

भारत की भाषा-समस्या

रामविलास शर्मा



राजकमल प्रकाशन

नयी दिल्ली पटना - - - /

भारत सरकार द्वारा अपेक्षाकृत सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराये गये कागज पर मुद्रित।

प्रथम संस्करण की भूमिका

भाषा की समस्या मूलतः जातीय समस्या का ही एक अंग है। इस देश में अनेक भाषाएँ बोलनेवाली जातियाँ रहती हैं। इनसे मिलकर भारत राष्ट्र बना है। इस राष्ट्र में जातियों की सम्पर्क भाषा क्या हो, एक ही सम्पर्क भाषा हो या अनेक हो—यह समस्या का एक पक्ष है। कुछ लोग इस देश की उपमहाद्वीप कहते हैं, उनका मत है कि राष्ट्रीयता का भाव अंग्रेजों का विरोध करने से पैदा हुआ, वास्तव में यह देश राष्ट्र नहीं है क्योंकि यहाँ एक भाषा के बदले अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। इस तरह राष्ट्रभाषा की समस्या का विवेचन करते हुए राष्ट्र की व्याख्या करना आवश्यक हो जाता है, विशेषकर भारतीय राष्ट्रीयता के ऐतिहासिक विकास पर कुछ कहना आवश्यक हो जाता है। राष्ट्रभाषा की समस्या विशुद्ध भाषा-विज्ञान की समस्या न होकर बहुजातीय राष्ट्र के गठन और विकास की ऐतिहासिक-राजनीतिक समस्या बन जाती है।

भारत की जातियों में हिन्दी-भाषी जाति समस्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है। कुछ लोग इस जाति के अस्तित्व से ही इन्कार करते हैं। वे कहते हैं कि उत्तर भारत के पुराने जनपदों में रहनेवाले तीन स्वतन्त्र जातियाँ हैं; बुन्देलखण्ड, अवधी, अजभाषा आदि हिन्दी की बोलियाँ नहीं हैं, वे हिन्दी से स्वतन्त्र भाषाएँ हैं। हिन्दी क्षेत्र में भाषा और बोलियों की यह समस्या हिन्दी-भाषी जाति के विकास की समस्या बन जाती है। इस विकास को समझे बिना भाषा और बोली के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। भाषा-समस्या का यह दूसरा पक्ष है।

इसी हिन्दी प्रदेश में बोलचाल की भाषा के आधार पर माहितीय भाषा के दो रूप—हिन्दी और उर्दू—विकसित हुए। उर्दू मुसलमानों की भाषा है या हिन्दुओं और मुसलमानों के मिलने में बनी, भारत में जो मुसलमान आये वे एक कौम के थे या कई कौमों के, उनकी एक भाषा थी या वे कई भाषाएँ बोलते थे, क्या हिन्दी का विकास हिन्दू राष्ट्रवाद के अभ्युत्थान के कारण हुआ, क्या मुसलमानों की प्रलय कौम है, उर्दू को क्षेत्रीय भाषा बनाया जा ~~नहीं~~ नहीं—

ये सभी प्रदन हिन्दी-भाषी जाति के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ जुड़े हुए हैं। भाषा-समस्या का यह तीमरा पक्ष हुआ।

भारतीय जनता के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने बहुजातीय राष्ट्र की विशेषताएँ पहचानें, इस राष्ट्र में हिन्दी-भाषी जाति की भूमिका पहचानें। इस दृष्टि से भारत की भाषा-समस्या का व्यापक महत्व है, इसमें किसी को सन्देह न होना चाहिए।

इस पुस्तक में पिछले तीस वर्षों में भाषा-समस्या पर लिखे हुए मेरे अधिकांश निबन्धों का संग्रह है। इससे पाठक देख सकेंगे कि इस अवधि में भाषा-समस्या के कौन से पक्ष, किस समय एक हिन्दी लेखक के मन को आन्दोलित करते रहे। इन वर्षों में मेरे विचार बदले हैं। लेखों में समस्या के विभिन्न पक्षों पर, प्रलग-प्रलग समय पर कम-ब्यादा जोर दिया गया है किन्तु मेरी तीन बुनियादी मान्यताओं में कोई अन्तर नहीं आया। पहली यह कि अंग्रेजी भारत की सभी भाषाओं पर साम्राज्यवादियों द्वारा लादी हुई भाषा है और उसका प्रमुख जल्दी-से-जल्दी अन्त करना चाहिए। दूसरी यह कि हिन्दी और उर्दू मूलतः एक ही भाषा हैं और आगे चलकर दोनों घुल-मिलकर एक होगी, बोल-बाल की भाषा के आधार पर एक ही साहित्यिक भाषा का विकास होगा। तीसरी यह कि बुन्देलखण्डी, ब्रज, अवधी आदि हिन्दी की बोलियाँ हैं, स्वतन्त्र भाषाएँ नहीं हैं।

भारत की बहुजातीय राष्ट्रियता के बारे में, हिन्दी-भाषी जाति के विकास के बारे में, हिन्दी-उर्दू की बुनियादी एकता और हिन्दी की जनपदीय बोलियों के परस्पर सम्बन्ध के बारे में मेरी मान्यताओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

भारतीय संविधान के अनुसार सन् '६५ में केन्द्र के राजकीय काम-काज में अंग्रेजी का व्यवहार समाप्त हो जाना चाहिए था। स्वभावतः इस वर्ष मैंने जो लेख लिखे हैं उनका सम्बन्ध अंग्रेजी-हिन्दी अथवा अंग्रेजी बनाम भारतीय भाषाओं वाले विवाद से अधिक है। मेरे कुछ मित्रों ने मुझे याद दिलाया है कि सन् '४६ में मैं अनिवार्य राजभाषा का विरोधी था; अब हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनवाने के लिए अन्ध राष्ट्रवादियों की तरह दूसरों पर जोर-जबर्दस्ती से हिन्दी लादने का आन्दोलन कर रहा हूँ।

इन मित्रों की सेवा में निवेदन है कि जैसे मैं अनिवार्य राजभाषा का विरोधी सन् '४६ में था, वैसे ही आज भी हूँ। मैं किसी भी भाषा पर हिन्दी लादने का विरोध करता हूँ। मैं हिन्दी को सम्पर्क-भाषा बनाने के पक्ष हूँ, दूसरी भाषाओं के क्षेत्र में राजकीय और शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों में हिन्दी के व्यवहार के पक्ष में नहीं हूँ। सम्पर्क-भाषा को भी कुछ लोग हिन्दी का लादा जाना सम्मते हैं। मैं किसी भी प्रदेश की इच्छा के विरुद्ध उसके लिए हिन्दी को सम्पर्क भाषा बनाने का भी समर्थन नहीं करता। लेकिन मैं यह भी कहता हूँ, अंग्रेजी-प्रेमियों को हिन्दीभाषी प्रदेशों पर अंग्रेजी लादने का कोई अधिकार

नहीं है। महिन्दी-भाषी प्रदेशों के नेता नहीं चाहते कि केन्द्र में अंग्रेजी की जगह हिन्दी का चलन हो, उनकी इच्छा। वे केन्द्र में हिन्दी के अलावा अन्य भाषाओं का चलन कर सकते हैं। इसमें उन्हें अराजकता दिखायी देती हो तो अंग्रेजी ही चलायें लेकिन वे हिन्दीभाषियों को बाध्य नहीं कर सकते कि लोकसभा, राज्यसभा तथा केन्द्रीय राजकाज में वे भी अंग्रेजी का व्यवहार करें।

हिन्दी-भाषी जाति भारत की सबसे बड़ी जाति है। वह केन्द्र में अपने प्रतिनिधियों को हिन्दी लिखने-बोलने के लिए बाध्य करके अंग्रेजी का प्रभुत्व खत्म कर सकती है। १४ मार्च, सन् '६५ के 'धर्मयुग' में इस घाशय का मुभाव देखकर कम्युनिस्ट नेता श्री योगीन्द्र शर्मा ने लिखा था कि यह गृहयुद्ध की सलकार है।

मई, सन् '५८ के 'समालोचक' में मैंने लिखा था, "यदि हिन्दी-भाषी जनता संगठित हो, यदि वह अपने प्रदेश में हिन्दी को पूर्ण रूप में राजकाज की भाषा बनाये तो यह असम्भव है कि यह विशाल प्रदेश और बहुसंख्यक जनता सारे देश को अपने साथ खींचकर न ले चल सके।"

६ जनवरी, सन् '६३ के 'धर्मयुग' में मैंने लिखा था, "यदि समस्त हिन्दी-भाषी प्रदेश में शिक्षा-संस्थाओं, न्यायालयों, राजकीय कार्यों में हर स्तर पर हिन्दी का व्यवहार हान लगे, यदि विधान परिषदों के सदस्य प्रतिज्ञा करें कि वे अपना सार्वजनिक कार्य हिन्दी में ही करेंगे, यदि लोकसभा के सदस्य तय कर लें कि वे राजभाषा के रूप में हिन्दी का ही व्यवहार करेंगे, तो क्या इसमें किसी का सन्देह हो सकता है कि मजूचे राष्ट्र का वातावरण बदल जायेगा और हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाते जरा भी देर न लगेगी।"

योगीन्द्र शर्माजी नोट कर लें, जिसे वह गृहयुद्ध की सलकार कहते हैं, वह बात काफी पुरानी है।

इस सपह में काफी लेख ऐसे हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों और भाषावादियों के लेखकों में घावमी बहस के लिए लिखे गये थे। सन् '४६ में जो लेख 'कम्युनिस्ट' पत्रिका में छपा था, उसके ऊपर लिखा था, 'बहस के लिए लेख'। मितम्बर, '६४ के 'न्यू एज' (मासिक) में हिन्दी और राष्ट्रीय एकरूपता पर मेरा जो लेख छपा था, उस पर भी लिखा था, 'बहस के लिए लेख'। यह बताना इसलिए आवश्यक है कि पाठकों को यह भ्रम न हो कि मैंने अपने लेखों में जो दावे किये हैं, वे कम्युनिस्ट पार्टी की स्वीकृत मान्यताएँ हैं।

यद्यपि मैंने हिन्दी-उर्दू समस्या तथा हिन्दी क्षेत्र में भाषा और बोलियों के प्रश्न पर अनेक बार और काफी विस्तार में लिखा है, किन्तु मेरी स्थापनाओं का विरोध करनेवालों ने कभी भी मेरे तर्कों का खण्डन नहीं किया। इसके बदले वे मुँहजबानी मेरे बारे में छपवाहूँ फैलाते रहे हैं। इधर जव से अंग्रेजी का लेकर सपने तब टूटा है, वे उन छपवाहूँ को छापें के पृष्ठों में प्रकाशित भी करन लगे हैं। इन मित्रों में निवेदन है कि पतवे देन में भाषा समस्या का समाधान नहीं

हा मधला । त्वं वा तुल्य मत्तं मे ही मीशिन ।

माया-ममत्वा का घनिष्ठ सम्बन्ध राष्ट्रीय एकता से है, यह बात हिन्दी में छिपी नहीं है। जिस राष्ट्र में जिनकी ही धार्मिक दृष्टि होगी वृत्ता ही वह हर तरह का तनाव और बीच में के बीच की स्थिति में होगा। जिस देश की ओर धीरे धीरे जा रहा है, जिस ओर में जा रहे हैं और मंजिलों के बीच दृढ़ भावना होगी है जिस देश की राजमन्त्र के पीछे भावना जनता की गति होगी है वह देश अवश्य ही होगा है। माया-ममत्वा का सही समाधान राष्ट्रीय एकता की दृष्टि करके उस धर्म बना सकता है, माया-ममत्वा का सही समाधान लाया में धर्मनाथ पैदा करके राष्ट्रीय एकता की बहाली कर सकता है। इस तरह का धर्मनाथ हर अवस्था में विपन्नकारी होगा है; दीर्घकालीन युद्ध की परिस्थितियों में वह विशेष रूप में अनुपम सहायक हो सकता है। हमारी राष्ट्रीय एकता हर परिस्थिति में इस तरह का तनाव बर्दाश्त करके घटित बनी रहे, हमें इसी प्रयत्न करना चाहिए।

इस मस्यह के कुछ लेख अखंडो मे प्रकाशित हुए थे; उनका यही अनुवाद दिया गया है। 'भाषा और साहित्य मे पाकिस्तान' मसलत की एक बेहतर पत्रिका मे प्रकाशित हुआ था, उसका भी अनुवाद दिया गया है। अधिकांश लेख हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं मे प्रकाशित हो चुके हैं और यहाँ पन्नी बार सन्निहित किये गये हैं। कुछ लेख मेरे अन्य निबन्ध-मसलों मे द्या चुके हैं। अन्तिम तीन लेख इस मसल मे पन्नी बार प्रकाशित हो रहे हैं। कुछ लेखों के अनावश्यक अंश काट दिए गये हैं, किन्तु उनकी बार्द मुख्य स्थापना न बदले, मेरी दृष्टि मे आज वह नहीं हो या अवन, इसका मैंने ध्यान रखा है। सन् '४६ बाने निबन्ध मे मैंने अविवायं केन्द्रीय राजभाषा का विरोध किया था और कहा था कि हिन्दी को केन्द्रीय राजभाषा बनाने मे बड़े पूँजीपतियों को लाभ होगा। यह स्थापना उस निबन्ध मे रहने दी है यद्यपि बड़े पूँजीपतियों की भूमिका और केन्द्रीय राजभाषा के बार मे मेरे विचार बहो नहीं हैं। मैं केन्द्रीय राजभाषा को अविवायं बना देने, यानी हमरों की इच्छा के विरुद्ध उन पर लादने का विरोध हूँ किन्तु इस बात को धारदार और बाछनीय नमस्कार हूँ कि भारत के विभिन्न दल हिन्दी को केन्द्रीय राजभाषा बनान के लिए प्रयत्न करें, इन दलों के नेता ही जनमत के प्रतिनिधि बनते हैं, वे अपनी पार्टीओ के केन्द्रीय दपनरों मे अग्रेशी निकालें तो उन्हें अखिल भारतीय सम्पर्क के लिए पहले अपनी पार्टी मे, फिर शासन-व्यवस्था मे हिन्दी के व्यवहार की उपयोगिता दिखायी देने लगे।

भारत की राजनीतिक पार्टियों में मेरा सम्बन्ध कम्युनिस्ट पार्टी में रहा है। मैंने यह आशयक समझा कि खुद कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर अश्रेष्ठों का व्यवहार सस्म करने के लिए आन्दोलन किया जाय। इस आशय से कुछ बातें मैंने मित्रम्बर, सन् '६४ की 'न्यू एज' पत्रिका में लिखी थीं। यह पत्रिका भारतीय कम्युनिस्ट

पार्टी का मुखपत्र है। 'भाषा की समस्या—प्रति आवश्यक' और 'भाषा की समस्या और राष्ट्रीय विषय' लेख 'जनशक्ति' में प्रकाशित हुए। 'जनशक्ति' भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बिहार शाखा का मुखपत्र है। इसमें श्री योगीन्द्र शर्मा ने मेरी मान्यताओं का खण्डन करते हुए दो लेख लिखे। 'भाषा की समस्या और मजदूर वर्ग' तथा 'भारत की राजभाषा अंग्रेजी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा' उनके लेखों में प्रत्युत्तर हैं। ये भी 'जनशक्ति' में प्रकाशित हुए थे।

मैं 'जनशक्ति' के सम्पादक का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रमुख भारतीय नेता के विरुद्ध मेरे तीव्र खण्डनात्मक लेख छापे।

मेरे अनेक भाषा सम्बन्धी लेख 'धर्मयुग' में प्रकाशित हुए हैं जिससे मेरी बात हज़ारों ऐसे पाठकों तक पहुँची है जो मेरी पुस्तकों और लेखों से एकदम अपरिचित थे। इसके लिए मैं 'धर्मयुग' के सम्पादकों का कृतज्ञ हूँ। 'धर्मयुग' ने अंग्रेजी-विरोधी मान्दोलन में सशिव माय लेकर सराहनीय कार्य किया है। उसका बीटनिक प्रेम थोड़ा कम हो जाय तो वह हिन्दी भाषा और साहित्य की और भी सेवा करे।

५ अक्टूबर, '६५

रामविलास शर्मा

दूसरे संस्करण की भूमिका

१९६५ में राष्ट्रभाषा की समस्या नाम से मेरी एक पुस्तक छपी थी। बहुत दिन से यह अप्राप्य है। उसी का दूसरा संस्करण 'भारत की भाषा-समस्या' नाम में अब प्रकाशित हो रहा है। पुस्तक में भाषा-समस्या के अनेक पक्ष हैं। राष्ट्र भाषा की समस्या बाना पक्ष उनमें से एक है। पुस्तक का पुराना नाम प्रकाशक का दिया हुआ था। उसे बदलना मैंने जरूरी समझा।

भारत में विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले भाषम में सम्पर्क के लिए किसी एक भाषा का व्यवहार करें, यह समस्या का एक पक्ष है। हिन्दी-भाषी प्रदेश में हिन्दी और उर्दू दो भाषाओं के रूप में स्वीकृत न की जायें, हिन्दी प्रदेश की एक ही जातीय भाषा स्वीकार की जाय, विभिन्न जनपदों की उपभाषाएँ जातीय भाषा हिन्दी की तुलना में गौण स्थान पावेंगी, यह भाषा-समस्या का दूसरा पक्ष है। सारे देश के लिए हिन्दी को ही सम्पर्क भाषा बनाने की बात होती है और यही हमारी—हिन्दी प्रदेशवासियों की—जातीय भाषा भी है, इसलिए समस्या के ये दोनों पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्हीं दो पक्षों पर इस पुस्तक के अधिकांश निबन्ध लिखे गए हैं। इन दो पक्षों के मिलावा तीसरा पक्ष उन भाषाओं का है जिन्हें जातीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हुई अथवा जो राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए व्यवहार में नहीं आती। भारत में चार मुख्य भाषा-परिवार हैं, आर्य, द्रविड, कोल और नाग।

सभी परिवारों में कुछ भाषाएँ ऐसी हैं जिन्हें अपना उपयुक्त स्थान नहीं मिला। आर्य भाषा-परिवार में ऐसी भाषाओं की संख्या कम है। इससे अधिक संख्या द्रविड भाषाओं की है और इनमें से अधिकांश द्रविड भाषाएँ ऐसी हैं जो अन्य द्रविड भाषा-क्षेत्रों से ही घिरी हुई हैं। ऊपर से देखने में लगता है कि विंध्याचल के दक्षिण में चार मुख्य द्रविड भाषाएँ हैं—तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़। प्रचार यह किया जाता है कि आर्यों ने उत्तर भारत जीतकर द्रविड़ों को दक्षिण भारत में ठेल दिया, द्रविड़ भाषाओं के क्षेत्र में इन भाषाओं की कोई अपनी समस्या नहीं है। किन्तु अधिकांश पिछड़ी हुई जातियों और कबीलों की द्रविड़ भाषाएँ आर्य-भाषा क्षेत्रों में नहीं हैं, वे द्रविड़ भाषा-क्षेत्रों में हैं। दक्षिण भारत के चार द्रविड़ भाषा-भाषी राज्यों में पच्चीसो द्रविड़ भाषाएँ ऐसी हैं जो चार प्रमुख द्रविड़ भाषाओं से भिन्न हैं। भाषाविज्ञानी इनका अस्तित्व स्वीकार करते हैं, उनपर शोध कार्य किया जाता है, किन्तु उन्हें राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए मान्यता प्रदान नहीं की जाती। इन भाषाओं का व्यवहार करने वालों का जातीय जीवन पुनर्गठित करना आवश्यक है। जहाँ आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर इकाई बन सके, वहाँ उनका राज्य बनाना चाहिए। जहाँ ऐसा संभव न हो, वहाँ बृहद् राज्यों के अन्तर्गत उनके स्वायत्त क्षेत्र कायम करने चाहिए।

कोल भाषा परिवार भारत का अत्यन्त प्राचीन भाषा परिवार है। यही एक ऐसा परिवार है जिसकी भाषाएँ बोलने वालों का भारत में कोई अपना राज्य नहीं है। इस परिवार की भाषाएँ बोलने वाले अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता-संग्राम में लड़ चुके हैं। इनमें सन्थालों का वीरतापूर्ण संग्राम विशेष रूप से स्मरणीय है। ये लोग पश्चिम से पूर्व तक पूरे मध्यभारत में फैले हुए हैं। यदि आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर इनका राज्य बन सके तो उसे अवश्य बनाना चाहिए, न बन सके तो बिहार, उड़ीसा और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में इनके स्वायत्त क्षेत्र कायम करने चाहिए। कोल भाषाएँ बोलने वाले लोग जातीय निर्माण की विभिन्न मञ्जिलों में हैं। इनके सामाजिक विकास की विविधता का विस्तृत अध्ययन करके इनकी भाषा-समस्या सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ कोल शब्द के व्यवहार के बारे में दो बातें कहना आवश्यक है। इस शब्द का एक अर्थ सूअर होना है। इस कारण कुछ लोग इस शब्द को अपमान-जनक समझते हैं। इसके बदले वे मुण्डा शब्द का व्यवहार करना पसंद करते हैं। जिस कोल शब्द का अर्थ सूअर है वह कोल भाषा परिवार का ही है, इसमें मुझे सन्देह है। यह शब्द यूरुप की लियुआनियन भाषा में भी है और वहाँ भी उसका अर्थ सूअर है। इस लियुआनियन भाषा के लिए कहा जाता है कि इसमें इण्डोयूरोपियन परिवार के प्राचीन लक्षण अधिक सुरक्षित हैं।

जो सूअर के पर्यायवाची कोल शब्द को इण्डोयूरोपियन परिवार का प्राचीन माना जा सकता है। इससे भिन्न है दूसरा कोल शब्द जिसका अर्थ है

वीर पुरुष या वीरजवान । गण समाजों की यह परम्परा रही है कि उनकी भाषा में जो शब्द पुरुषत्व-सूचक होता है, उसी को गणसमाज का नाम मान लेते हैं । उत्तर भारत का पुरु वंश प्रसिद्ध है । पुरुष शब्द उसी पुरु से बना है । नाग भाषा परिवार में नाग या नगा मूलतः नग शब्द है जिसका अर्थ है पुरुष । कश्मीरी, हिन्दी आदि भाषाओं में अब भी एक नग, दो नग का अर्थ होगा, एक आदमी, दो आदमी । कबीले का नाम बताने वाले कोल शब्द का अर्थ गौरव-पूर्ण है । उसे हीन समझकर छोड़ना न चाहिए । पर कोल शब्द के लिए मेरे आग्रह का मुख्य कारण इसका है । अवध से लेकर छोटा नागपुर तक जहाँ भी कोल जनो की वस्तिर्या रही है, वहाँ स्थानों के साथ यह नाम जुड़ गया है और उसका ऐतिहासिक महत्व है । बैसवाडे में एक गाँव कुलहा है । स्पष्ट ही इसका सम्बन्ध कोल जनो से है । छोटा नागपुर में हमने ठीक मिलता-जुलता एक स्थान है कोलहा । मेरा अनुमान है कि गढा-कोला जैसे स्थानवाचक नामों में भी गढ के साथ दूसरा शब्द विशेष जनसमुदाय अर्थात् कोल जनो का सूचक है । कोल शब्द के सहारे भाषा-विज्ञान, समाजशास्त्र और इतिहास को घनेक गुणियाँ सुलझाई जा सकती हैं । हमें इसी शब्द का व्यवहार करता हूँ ।

✓ भारत में नागभाषा परिवार ही एक ऐसा परिवार है जिसकी भाषाएँ बोलने जाने लोगो ने अपने राज्य की भाषा को अंग्रेजी बताया है । अगामि, सेमा आदि गण अपने दैनिक जीवन में अपनी-अपनी गण भाषाओं का व्यवहार करते हैं । आपस में और दूसरों से सम्पर्क में आने पर वे एक प्रकार की हिन्दी का व्यवहार करते हैं जिसमें अनेक भाषाओं के तत्त्व आकर घुलमिल गये हैं । अंग्रेजी बहुत थोड़े लोग जानते हैं किन्तु ईमाई धर्म-प्रचारकों के प्रभाव से इनके राज्य का नाम नागालैण्ड है और इस राज्य की भाषा अंग्रेजी है । अन्य प्रदेशों की तरह यहाँ भी यह सत्य है कि जब नाग भाषाओं का अपना स्वत्व प्राप्त होगा, तब अंग्रेजी की स्थिति कमजोर होगी और वे लोग जो टूटी-फूटी मिश्रित हिन्दी का व्यवहार करते हैं, उन्हें इस सम्पर्क भाषा को सुदृढ़ करने का अवसर मिलेगा । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि छोटा नागपुर में कोल और द्रविड जन इसी प्रकार की टूटी फूटी मिश्रित हिन्दी का व्यवहार करते हैं । कोल भाषाओं को उनका स्वत्व प्राप्त होने के साथ साथ यह टूटी-फूटी हिन्दी भी सुदृढ़ सम्पर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होगी ।

यहाँ परिनिष्ठित भाषा और उसके अपरिनिष्ठित रूपों की चर्चा करना आवश्यक है । नागालैण्ड और छोटा नागपुर केवल दो ऐसे प्रदेश नहीं हैं जहाँ हिन्दी के अपरिनिष्ठित रूपों का चलन है । डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या सन् १९२८ से बलकल की हिन्दी की बकालत करते रहे हैं । १८वीं सदी के अन्त में अंग्रेज तथा यूरोप के अन्य व्यापारी, उत्तर भारत और बंगाल के विभिन्न पक्षों के लोग, इसी हिन्दी से काम चलाने लगे । दक्षिण भारत में एकनी नाग से हिन्दी का एक रूप विख्यात है । वहाँ निश्चित लोग साहित्य में परिनिष्ठित

स्तर पर अंग्रेजी का स्थान लेती है या नहीं। १९४८ में पेरिस की एक सभा में डॉक्टर सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ने भी हिन्दी को राष्ट्र सभ में स्थान देने की बात कही थी। किन्तु जब हिन्दी को केन्द्रीय राज्यभाषा बनाने का प्रश्न सामने आया, तो उन्होंने भाषा-आयोग के बहुमत से असंग अपनी विरोधी राय प्रकट की। यदि, भारत के प्रतिनिधि राष्ट्र सभ में हिन्दी का व्यवहार करें या किसी अन्य भारतीय भाषा में अपने विचार प्रकट करें तो सत्तार को पता चल जाए कि भारत अब अंग्रेजी और अंग्रेजों का अर्थ उपनिवेश नहीं रहा। तब राष्ट्र सभ की एक भाषा हिन्दी हो, यह माँग करत हुए अच्छा भी लगेगा। पर अभी तो भारत की लोक सभा में अंग्रेजी का बोलबाला है। जब भारत की लोक सभा में अंग्रेजी छापी हुई है, तब विश्वसंस्था राष्ट्रसभ में हिन्दी को स्थान देने की माँग कम किम मुँह से कर सकते हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दी को विश्वभाषा बनाने के प्रति राजनीतिज्ञों में जो गहरी दिलचस्पी पैदा हो गयी है, उसका कारण ही यह है कि लोग यह न पूछें कि लोकसभा में और अखिल भारतीय सेवाओं में अंग्रेजी का चलन क्यों है।

भाषा की समस्या मात्र प्रशासन-सम्बन्धी समस्या नहीं है। इसका गहरा सम्बन्ध देश के जनतान्त्रिक आन्दोलन और देश की सुरक्षा से है। जनतन्त्र से जितना लाभ या हानि सम्पत्तिशाली लोगों को होती है, उससे अधिक लाभ या हानि श्रमिक जनता को होती है। भारत के सामाजिक विकास का यह अन्वयार्थ तथ्य है कि हिन्दी प्रदेश से असंग, भिन्न प्रदेशों में, हिन्दी भाषी मजदूरों की संख्या बहुत बड़ी है। जिन कारणों से हिन्दी प्रदेश के गरीब और मुफलिम किसान अपना देश छोड़कर अफ्रीका, फीजी, मारीशस आदि द्वीपों, महाद्वीपों में कुलीगरी करने गये थे, उन्हीं कारणों से इनके भाई बंधु अपना प्रदेश छोड़कर बम्बई कसकसा जैसे बड़े नगरों में मजदूरी करने गये थे। कलकत्ते के मजदूरों में आधे से कुछ ज्यादा ही हिन्दीभाषी होंगे। इसी तरह बम्बई के मजदूरों में एक बहुत बड़ा हिस्सा हिन्दी मजदूरों का है। जिस तरह देश छोड़कर जाने वाले हिन्दी मजदूरों ने अपनी भाषा को विश्वभाषा बनाया है, उसी तरह अपना प्रदेश छोड़कर जाने वाले, बंगाल महाराष्ट्र आदि में मजदूरी करने वाले, हिन्दी श्रमिकों ने अपनी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया है। हिन्दी के बिना अखिल भारतीय स्तर पर मजदूरों का संगठन हो ही नहीं सकता। जनतन्त्र की एक अत्यन्त जागरूक शक्ति मजदूर है, इसलिए जो लोग जनतन्त्र की रक्षा की बातें करते हैं, उन्हें अविविम्ब भारत के सामाजिक जीवन में अंग्रेजी के व्यवहार को निकाल बाहर करना चाहिए।

दूसरी बात सुरक्षा की है। स्वाधीन भारत ने अभी किसी बड़े युद्ध का सामना नहीं किया, पर हो सकता है, निकट भविष्य में उसे ऐसे युद्ध का सामना करना पड़े। आधुनिक युद्ध की विशेषता यह है कि वह सैनिकों और असैनिक जनता में विशेष भेद नहीं करता। सैनिकों और असैनिक जनता

के सहयोग से ही युद्ध में सफलता मिलती है। युद्ध के मोर्चे पर चाहे घागे बढ़ना हो, चाहे सैनिक कारणों से पीछे हटना हो, दोनों स्थितियों में परस्पर सहयोग अपेक्षित होता है। यदि युद्ध दीर्घकाल तक चला या छापमार लड़ाई चलाने की नीयत आयी, तो जनता का सम्पर्क और सहयोग और भी अधिक अपेक्षित होगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जनता और सेना, दोनों किसी एक भाषा का व्यवहार करके एक दूसरे की बात समझ सकें मने ही यह भाषा टूटी-फूटी हो, अपरिनिष्ठित हो, पर उसका कामचलाऊ होना बहुत जरूरी है। जनता के अलावा स्वयं सेना के भीतर अफसर और सिपाही के बीच जितना फासला कम होता है, उतना ही फौज भीतर में मजबूत होती है। यदि अफसर अंग्रेजी के रम में रंगे होंगे तो उनके और साधारण सैनिकों के बीच में फासला ज्यादा होगा और उतना ही सेना की जुभाहू शक्ति कम होगी। इसलिए अंग्रेजी का प्रमुख समाप्त करना और उसकी जगह काम-चलाऊ हिन्दी का व्यापक प्रसार करना राष्ट्र के जीवन-मरण का प्रश्न है।

निस्सन्देह जो लोग अंग्रेजी के व्यवहार के भादी हैं, उन्हें इस भाषा का मोह छोड़ते थोड़ा कष्ट होगा। अपने दिल को हिम्मत बंधाने के लिए उन्हें यह बात याद कर लेना चाहिए कि १९वीं सदी में 'राजपूताना' में स्थित अंग्रेज अफसर वहाँ के राजाओं से हिन्दी में ही पत्र-व्यवहार करते थे। राजा बलवंतसिंह कालेज के हिन्दी अध्यापक डॉ० श्री मोहन द्विवेदी की देख-रेख में महेशचन्द्र गुप्त राजस्थान के प्रशासनिक 'कार्यों में हिन्दी का प्रयोग' (१८५७-१९७४) विषय पर शोध कार्य कर रहे हैं। उन्होंने १८५७ से पहले के और उसके बाद के भी काफी दस्तावेज इकट्ठे किए हैं। इन दस्तावेजों में वे पत्र हैं जो अंग्रेजों ने राजाओं को लिखे, इनके अतिरिक्त वे पत्र हैं जो राजाओं ने अंग्रेजों को लिखे, साथ ही ऐसे पत्र हैं जो राजाओं ने एक दूसरे को लिखे। यदि राजस्थान में १९वीं सदी में हिन्दी राजभाषा के रूप में काम आती थी और उसका व्यवहार हिन्दुस्तान के लोग ही नहीं, अंग्रेज भी करते थे, तो कोई कारण नहीं कि २०वीं सदी के अन्तिम चरण में अंग्रेजी प्रेमी भारतवासी अपना अंग्रेजी मोह त्यागकर हिन्दी का उपयोग न कर सकें।

राष्ट्रीय सुरक्षा के माध्यम राष्ट्रिय एकता का प्रश्न जुड़ा हुआ है। राष्ट्रिय एकता केवल हिन्दुओं और मुसलमानों की एकता नहीं है। पश्चिमी पाकिस्तान के धर्मान्ध लोगों ने पूर्वी बंगाल के लोगों की भाषा और जातीय सस्कृति की अवहेलना करके धर्म के नाम पर उन्हें दबाकर रखने का प्रयत्न किया। इसमें उन्हें सफलता न मिली। बचे हुए पाकिस्तान में आन्तरिक संघर्ष विकट रूप धारण कर रहा है और धर्म के नाम पर अपीलें जारी करके उस शान्त करना असम्भव हो गया है। यदि भारत में भूल सामाजिक समस्याएँ हल न की गईं, तो यहाँ भी भयानक अशान्ति फैल सकती है। राष्ट्रिय एकता विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले समुदायों की एकता भी है। इंग्लैण्ड की अंग्रेजी-भाषी जाति का

दो राज्यों में बाँट दीजिए तो क्या इससे इंग्लैंड की राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी ? विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले मिलकर राष्ट्रीय एकता मजबूत करें, इसके लिए जरूरी है कि कोई एक भाषा बोलने वाला समुदाय भी विभाजित न हो, वरन् धार्मिक रूप से मजबूत हो। महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, केरल, गुजरात आदि प्रदेशों के लोगों ने भाषा व आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग की। केन्द्रीय सत्ता ने यह विरोध किया, फिर वही माँग स्वीकार की। अंग्रेजों ने बम्बई और मद्रास प्रेसीडेन्सी नाम से जो बड़े-बड़े सूबे बनाये थे, उन्हें तोड़कर नये राज्य गठित किए गए। हिन्दी प्रदेश में इससे उल्टी स्थिति है। यहाँ प्रान्त बड़े राज्यों को तोड़कर छोटे राज्य बनाने का नहीं है। प्रान्त है अनेक हिन्दी-भाषी राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बनाने का। प्रान्त प्रशासन विशाल आपत्ति करता है कि इसने बड़े राज्य का शासन चलाना बहुत कठिन होगा, इसलिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को भी दो-तीन टुकड़ों में बाँटना उचित होगा। जहाँ तक शासन चलाने का सम्बन्ध है, आगरा नगर-महापालिका एक शहर की नालियों की ही सफाई नहीं करा पाती, यदि हर मुहल्ले की एक-एक पालिका बना दी जाय, तो शायद यह शहर आदमियों के रहने लायक हो जाय। पर विश्वास नहीं है कि मुहल्ला पालिका भी मुहल्ले की सफाई करा सकेगी क्योंकि आदत यह है कि अपने घर का कूड़ा दूसरे के घर के सामने डालो और हाजत रफा करने के लिए नालियाँ हैं—जिनमें गहराई बहुत ही कम है क्योंकि ठेकेदार कहता था, नालियाँ गहरी करें तो डजीनियर को पैसा वहाँ से देंगे। जनसत्ता की रक्षा करना, शासन सत्ता चलाना नये सिरे से सीखना है। प्रान्त छोटे-बड़े राज्यों का नहीं है। प्रान्त है शासन चलाने की योग्यता का। प्राजक्त विकेन्द्रीकरण की काफी चर्चा है। केन्द्रव्यवस्था और शक्ति का विकेन्द्रीकरण परस्परविरोधी बातें नहीं हैं, वे एक-दूसरे की पूरक हैं। भारत जैसे विशाल देश में राष्ट्रीय योजनाएँ बनाना, राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना केन्द्रीय शक्ति का काम है। इस राष्ट्रीय ढाँचे के भीतर नीतियों को कार्यरूप में परिणत करना, आवश्यकता-नुसार उनमें परिवर्तन करना राज्यों का काम है। विकेन्द्रीकरण का एक स्तर राज्य है। पर विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया इसी स्तर पर समाप्त नहीं हो जाती। लोग गाँव, तालुका, तहसील, ब्लॉक आदि की बातें करते हैं। राज्य के बाद वाला स्तर जनपद का है। हिन्दी-भाषी प्रदेश में ब्रज, अवध, बुन्देलखण्ड, मिथिला, मगध आदि जनपद साफ पहचाने जाते हैं। मुख्य बोलियों के ऐसे विशेष क्षेत्र महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु आदि प्रदेशों में भी हैं। इन्हीं को शासन का मूल आधार बनाना चाहिए, यही विकेन्द्रीकरण का दूसरा स्तर है। हमारे यहाँ जो कमिश्नरियाँ बनी हैं, उनमें जनपदों की सीमाओं का ध्यान नहीं रखा गया। जैम भाजपुरी क्षेत्र आधा बिहार में है और आधा उत्तर प्रदेश में, जैसे ब्रज क्षेत्र कुछ उत्तर प्रदेश में है और कुछ राजस्थान में, जैम बुन्देलखण्ड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विभाजित है, वैसे ही कमिश्नरियाँ जनपदों की सीमाएँ तोड़ती

है। जब कोई एक जनपद दो प्रलग राज्यों में विभाजित होगा, तब किसी एक ही कमिश्नरी के अन्तर्गत वह समुक्त कैसे होगा ?

बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आदि हिन्दी राज्यों को मिलाकर एक विशाल राज्य बनाना चाहिए। इस राज्य की इकाईयाँ उसके जनपद होंगे, विशेष बोलियों के क्षेत्र होंगे। प्रत्येक जनपद में कम से कम एक विश्वविद्यालय, एक भाषाश्रमिका केन्द्र और उच्च न्यायालय की एक शाखा होनी चाहिए। सब हिन्दी प्रदेश का—देशी-विदेशी राजनीतिज्ञों द्वारा उलझाया हुआ—गोरखघन्ना कुछ सुलभ सबना है। अनेक राज्यों की विधान सभाओं पर जो बड़ोड़ो दपया लब्ध होता है, वह बचाकर विकास कार्यों में लगाया जा सकेगा। व्यापार के प्रसार में राज्य स्तर की चुनौती आदि की हवाबटें दूर की जा सकेंगी। हिन्दी-भाषा जनता अपनी शक्ति पहचानेगी और राष्ट्र के जीवन में अपनी भूमिका निभादेगी। विभिन्न राज्यों में बँटे होने से उसकी सांस्कृतिक एकता छिन्न भिन्न हो गयी है, वह फिर सुनबद्ध होगी। जनपद की राजकीय और सांस्कृतिक कार्यवाही की मूल इकाई बनाने से इस प्रदेश के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन को पुष्ट जनतांत्रिक आधार प्राप्त होगा। केन्द्रबद्ध शक्ति और विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्तों का समन्वय होगा। अभी जहाँ सिद्धान्त-हीनता और नियमविहीन अभ्यवस्था है, वहाँ सिद्धान्तिक आधार पर जातीय प्रदेश का पुनर्गठन होगा।

यह हिन्दी प्रदेश काफी बड़ा होगा किन्तु सोविषयत सध के कसी क्षेत्र से और चीनी गणतन्त्र के चीनी क्षेत्र में वह बड़ा न होगा।

असोक, समुद्रगुप्त, भगवत और औरगजेव के समय में इस देश के भीतर जितनी भी राजनीतिक एकता काममें हुई है, उसका आधार हिन्दी प्रदेश की एकता रही है। हिन्दी प्रदेश को विभाजित रखकर राष्ट्रीय एकता की बातें करना प्रलाप मात्र है। हिन्दी प्रदेश की एकता मरने पहले राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है।

इस पुस्तक के दूसरे संस्करण में दो निबन्ध और जोड़ दिए हैं। एक निबन्ध हिन्दी के भाषुनिक विकास-सन्दर्भ में बहुभाषा की भूमिका है, दूसरा निबन्ध हिन्दीभाषी प्रदेश के बहुभाषाभाषी होने की समस्या से सम्बन्धित है।

१४ जून, १९७७

रामविलास शर्मा

अनुक्रम

१. स्वदेशी भाषा और महासावादी साहित्य	२१
२. राजनीतिक नेता और हिन्दी	२४
✓ ३. भाषा और राष्ट्रीयता	२६
४. भाषा और साहित्य में पाकिस्तान	२७
५. हिन्दी गद्य-शैली पर कुछ विचार	३१
६. राष्ट्रभाषा हिन्दी और हिन्दू राष्ट्रवाद	३८
७. हिन्दी का 'संस्कृतीकरण'	४४
८. उर्दू-साहित्य की सांस्कृतिक परम्परा	५०
९. भारत की भाषा-समस्या	६६
१०. जातीय भाषा के रूप में हिन्दी का प्रसार	८४
११. हिन्दी-उर्दू समस्या	९२
१२. भाषा और प्रांतीयता	९९
१३. अनिवार्य राजभाषा का सवाल	१०२
१४. अंग्रेजी के हिमायती	१०८
१५. सोवियत क्रान्ति और भाषा-समस्या	११२
१६. अंग्रेजी-प्रेमी भारतवासी	११५
✓ १७. बहुजातीय राष्ट्रीयता और राष्ट्रभाषा हिन्दी	१२१
१८. हिन्दी की व्याकरण-सम्बन्धी कठिनाइयाँ	१२६
१९. उर्दू की समस्या	१३१
२०. जातीय प्रतिद्वन्द्विता और हिन्दी	१३८
२१. राष्ट्रभाषा अंग्रेजी	१४४
२२. सोवियत संघ में भाषा-समस्या-समाधान	१५०
२३. हिन्दी-उर्दू की बुनियादी एकता	१५३
२४. राष्ट्रीय एकता और अंग्रेजी	१५७
२५. राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय प्रभुत्व	१६२

२६	हिन्दीभाषी प्रदेश में हिन्दी प्रचार की आवश्यकता	१६६
२७	सरकारी बोशवार और राष्ट्रभाषा	१७४
२८	कामपची कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम का मसौदा	१८१
२९	राष्ट्र, जाति और मार्क्सवाद	१८५
३०	'अन्तर्राष्ट्रीय' वैज्ञानिक शब्दावली	१९२
✓ ३१	संस्कृति और भाषा	१९४
३२	भाषा की समस्या—अति आवश्यक	१९८
३३	अंग्रेजी की सुरक्षा के लिए सघर्ष	२००
३४	भाषा की समस्या और राष्ट्रीय विघटन	२०५
३५	भाषा की समस्या और मजदूर वर्ग	२१२
३६	भारत की राजभाषा अंग्रेजी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा	२२५
३७	देश का विघटन और अंग्रेजी	२४२
३८	प्रगतिशील साहित्यकार और भाषा-समस्या के जनतांत्रिक समाधान	२५१
३९	हिन्दी के आधुनिक विकास-सन्दर्भ में राजभाषा की भूमिका	२७७
४०	हिन्दीभाषी प्रदेश—बहुभाषाभाषी प्रदेश ?	२८६

परिशिष्ट—१

१	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और उन्नीसवीं सदी में हिन्दी-आन्दोलन	३०१
२	गांधीजी और भाषा समस्या	३१५

परिशिष्ट—२

१	प्रेमचन्द और भाषा-समस्या	३४५
२	उत्तर प्रदेश की सरकार और हिन्दी	३५३
३	भारत का भाषा-संकट	३५५

भारत की भाषा-समस्या

स्वदेशी भाषा और अहिंसावादी साहित्य

हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के अनेक पदाधिकारी इस बार अपनी असाहित्यिकता के कारण एक विशेषता लिये हैं। साहित्य में जितने भी जन अधिक संख्या में दिलचस्पी लें, हमें उससे प्रसन्न होना चाहिए। परन्तु ये मैधावी हिन्दी-साहित्य के पास विद्यार्थी के रूप में नहीं आए। उसे जानने-पहचानने की उन्होंने चेष्टा नहीं की। राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करनेवाली अपनी प्रकृति के अनुसार उन्होंने हिन्दी-साहित्यको जो तरह-तरह के उपदेश दिए हैं। यदि वे हमारे साहित्य का सहृदयतापूर्वक अनुशीलन कर उसकी त्रुटियाँ साहित्यिकों को बताते तो उनके कार्य पर सबको हर्ष होना। पर उनकी असाहित्यिकता और साहित्य के अज्ञान का घोष उनके उपदेश की मधुर वाणी से मेल नहीं खाता।

सम्मेलन के सभापति ने, शायद अपने पूर्व राष्ट्रपति होने का स्मरण कर, कहा है—“सुविधा के विचार से हिन्दी को राष्ट्रभाषा हमने माना है।” फिर इस सुविधा के मार्ग में जो अड़चनें आएँ, उन्हें क्यों न हटाया जाए? आप कहते हैं—“हिन्दुस्तान में हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, सिख बसते हैं और तो भी यह हिन्दुस्तान है। उसी प्रकार हिन्दी में सभी भाषाओं से उत्तम शब्द हम लेंगे और तो भी यह हिन्दी ही रहेगी।” जैस काप्रेस, राष्ट्र की एकता का प्रतीक, अपन भीतर सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि रखती है, वैसे हिन्दी सब सब राष्ट्रभाषा न होगी, जब तक उसमें सभी भाषाओं के प्रतिनिधि शब्द न होंगे। सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष श्री ब्रजलाल बिषाणी ने इस बात को भली-भाँति समझा है और उस सबसे अधिक स्पष्ट रूप में कहा है—“हिन्दी-भाषा के प्रकार तथा सर्वप्रियता के लिए आवश्यक है कि उसका शब्द-भण्डार सब भाषाओं से लिए हुए शब्दों से भरा हो। हरेक प्रान्तवासी में हिन्दी के लिए समतुल्य पैदा होने के लिए हिन्दी के शब्दकोश में उसका भी हिस्सा होना आवश्यक है।” जब तक यह शब्दकोश न बने, तब तक इस भाषा की कल्पना करना कठिन है। सभी अन्य प्रान्तों के विभिन्न भाषा भाषी हिन्दी ही सीखते थे, अब वे उसके साथ थोड़ी-थोड़ी सभी प्रान्तीय भाषाएँ सीखेंगे। हिन्दी बोलनेवाले, जिन्हें

तमिल, बन्नड, बँगला, मराठी, गुजराती आदि का ज्ञान नहीं—बीस देखकर शुद्ध हिन्दी बोलेंगे। यह भाषा हिन्दी होगी या और कुछ, इसे बाबा साहेब श्री कालेलकर ने अच्छी तरह समझा है। इस भाषा का अपना नामकरण करते हुए उन्होंने कहा है—‘स्वदेशी भाषा में हम बोलेंगे।’

भाषा-संस्कार के साथ इन हिन्दी के शुभेच्छुओं को हमारे साहित्य की उन्नति का भी ध्यान है। राजनीतिक सुविधाओं के लिए हिन्दी की आवश्यकता नहीं। बाबू राजेन्द्रप्रसाद के अनुसार “राष्ट्र का प्राण साहित्य होता है और उस साहित्य का निर्माण कला समाज का बहुत बड़ा सेवक होता है।” तब हिन्दी-साहित्य की त्रुटियाँ दूर होनी ही चाहिए। काका कालेलकर के अनुसार आधुनिक साहित्य का पूर्व भाग दूसरों की नकल का फल है। “इस जनाने का हमारा प्रारम्भिक साहित्य अनुकरण ही था और अनुकरण तो निष्प्राण ही हो सकता है।” ‘हमारे साहित्य’ में किन-किन साहित्यों की गणना है, नहीं मालूम, यदि हिन्दी की है तो उसके साथ अन्याय है। ‘इस जनाने का हमारा प्रारम्भिक साहित्य’ एक ऐसा गोल वाक्य है कि समय ठीक से निर्धारित नहीं हो सकता। फिर भी भारतेन्दु से लेकर आज तक जो नये युग का जीवन है, उसमें उत्पन्न किसी भाग के साहित्य पर ऊपर का आरोप लागू नहीं होता। अन्य साहित्यिक जागृतियों की भाँति हमारे यहाँ बाहरी साहित्यों के सम्पर्क से विचारों में नवीनता आई है, पुरानी रुढ़ियों का ध्वंस और नई धाराओं का निर्माण हुआ है। यदि यह अनुकरण है तो कोई भी जीवित साहित्य उससे नहीं बचा।

“पिछले थोड़े वर्षों में हिन्दी ने बँगला, मराठी, गुजराती आदि प्रांतीय साहित्यों से अपना साहित्य कम समृद्ध नहीं किया है। आदान प्रदान में हिन्दी सिद्ध हो चुकी है। हम हिन्दी को जो कुछ देते हैं, वह उसे सशोधित कर देश के कोने-कोने में पहुँचा देती है।” किसी नवजागत भाषा के साहित्य की ऊँचाई जल्दी आँकना आसान नहीं। जो कृतियाँ शीघ्र प्रसिद्धि पाती हैं, वे बहुधा पाठकों की पूर्व-निश्चित धारणाओं के बहुत-कुछ अनुकूल तथा कुछ-कुछ पुरानी रुढ़ियों का अवलम्ब लिये होती हैं। हिन्दी में अब भी इतने रुढ़िवादी हैं कि पक्के क्रान्ति-कारियों को उचित श्रेय या विज्ञापन नहीं मिला। जो हमारे यहाँ का वास्तविक मौलिक साहित्य है, उसकी समुचित छानबीन धीरे-धीरे ही सम्भव है। परन्तु वैसा करना उसकी ओर में आँस मूँदकर राम देने से सम्भव नहीं, उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा।

हिन्दी-भाषा में अरबी-फारसी के प्रचलित शब्दों के बहिष्कार के समान हमारे नेताओं ने हिन्दी साहित्य में अश्लीलता का दुःस्वप्न भी देखा है। गांधीजी का वश चले तो वह साहित्य-सम्मेलन से उस रस को त्याग्य ही मनवा दें। वश चले तो गांधीजी ब्रह्मचर्य द्वारा सबसे सन्तति-निग्रह करवा दें। परन्तु वश चले तो भी यह हानिकर होगा। समयानुकूल प्रकृति की पुकारों को न मानने से बुरा फल मिलता है। असाधारणों का नियम सब पर लागू नहीं हो सकता।

यदि साहित्य का सम्पर्क जीवन में रहेगा तो उसमें शृंगारी वर्णन अवश्य आएंगे । क्या हिन्दी, क्या संस्कृत, बड़े-बड़े सन्तो ने अपने साहित्य में जीवन का पूर्ण चित्र उतारने के लिए शृंगार का बहिष्कार नहीं किया । देखना केवल यह होता है कि यह शृंगार पवित्र मनोभावों का परिचायक तो नहीं है । हिन्दी के गुजरे साहित्य के लिए यह आक्षेप सही हो सकता है । तब यदि जिस रस का वर्णन करता था, चाहता था कि उसी के अनुकूल आचरण करने के भाव पाठक या श्रोता के मन में उत्पन्न हो । आधुनिक साहित्य में विलासित आनन्द की ओर अधिग्रह ध्यान है । किसी गूनी का चित्रण करके यदि हमें गूनी बनने के लिए नहीं कहता । ममार के बड़े-से-बड़े साहित्यिकों ने पाप को अपना विषय बनाकर अद्भुत कृतियों को जन्म दिया है । अतः, यदि स्त्री पुरुष के पारस्परिक मनोभावों और आकर्षण-प्रत्याकर्षण का स्वस्थ वर्णन हो तो वह साहित्य भी समाज को उठानेवाला होगा ।

बाबा कानेलकर को साहित्य-नियन्त्रण के सम्बन्ध में और किसी से कम चिन्ता नहीं । आज साहित्य पर न राजसत्ता का नियन्त्रण है, न धर्माचार्यों का । "जो लोग साहित्य का उस जानने हैं और समाज का स्ति चाहते हैं, इतिहास और आदर्श, दोनों की दृष्टि रखकर जो लोग समाज की प्रगति में मदद कर सकते हैं, ऐसे पुरुषों का ही नियन्त्रण साहित्य पर रहना चाहिए । दुःख के भाष कहना पड़ता है कि हमारे साहित्य-जगत में मनमानी मर्यादों की ठान ली है ।" हमें काका साहब से सहानुभूति प्रकट करने की आवश्यकता नहीं, हमारे यहाँ आचार्य लोग अब भी अधिकांश प्यूरिटन प्रवृत्ति के हैं । यह सभी जानते हैं कि अदलीलता का कहीं आभास पाते ही वे धरती मिर पर उठा लेते हैं । परन्तु काका साहब को इन पर विश्वास नहीं । उन्हें आभा है, एक दिन साहित्यिक शासन की यागडोर उनके हाथों में आएगी; तब वह इन उच्छृङ्खल व्यक्तियों को गिन-गिनकर पाँसी पर लटकाएंगे ।—“भारतीय साहित्य परिषद् जब पूर्ण रूप से विकसित होगी, तब साहित्य-शुद्धि संभालने की जिम्मेदारी बानून या धर्मतन्त्र के हाथों में नहीं रहेगी, साहित्य ही अपने क्षेत्र को संभाल लेगा ।”

आदर्श साहित्य-निर्माण के लिए गांधीजी, बाबू राजेन्द्रप्रसाद, बाबा साहब आदि सभी ने उपदेश दिए हैं । इन्हें देखकर कोई अपरिचित यही समझेगा कि हिन्दी में एकदम पतित और समाज का अहित करनेवाला साहित्य रचा जा रहा है । इसका उत्तर एक लेख में देना सम्भव नहीं । साहित्यिकों के नाम गिनाने की अपेक्षा उनकी कृतियों का सुचारु विवेचन अधिक श्रेयस्कर होगा । तब तब अपने नेताओं की सुझावनाओं के लिए अनुग्रहीत होते हुए हम यही आशा करते हैं कि यदि उनका हमारे साहित्य से कुछ दिनों और सम्पर्क रहा तो वे उसमें अपने अनेक सिद्धान्तों को कार्य-रूप में परिणत पाएँगे । (१९३६)

राजनीतिक नेता और हिन्दी

राजनीतिक नेता लोग साहित्य पढ़ेंगे, इसकी आशा करना व्यर्थ जान पड़ता है। फिर भी साहित्य राजनीति में असर नहीं किया जा सकता। नेताओं की राजनीति गंदली होने पर उसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ सकता है, विशेषकर जब थोड़ा-बहुत शासनाधिकार हाथ में होने से वे बालकों और नवयुवकों की शिक्षा के लिए उत्तरदायी भी हों। ऐसी दशा में शिक्षा और भाषा में हस्तक्षेप करने के पहले उन्हें साहित्य के विकास और उसकी मूलधारा का ज्ञान होना आवश्यक है। आज की भारतीय राजनीति समझौते पर निर्भर है। यह समझौता कभी 'इंडिया एक्ट' के लिए अंग्रेज सरकार से कुछ क्षणों मनवाकर होता है, कभी केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शासन में बंटवारा करने के लिए श्री जिन्ना से महात्मा गांधी और श्री जवाहरलाल नेहरू की बातचीत के रूप में प्रकट होता है। हमने हिन्दी-साहित्य में समझौता करना नहीं सीखा। हम समझौता नहीं, एका करते में विश्वास रखते हैं और यह एका एक स्वतन्त्र अविभाजित राष्ट्र की भूमि पर ही हो सकता है। जो प्रान्तीयता और साम्प्रदायिकता लेकर आगे बढ़ता है, वह राष्ट्रीयता का ब्रोही है, उससे एक राष्ट्र-प्रेमी समझौता कैसे कर सकता है? इस उग्र राष्ट्रीयता की भावना में राजनीतिज्ञ हिन्दी-साहित्य में शिक्षा ले सकते हैं। हमारे साहित्य का उद्भव ही एक विदेशी साम्राज्यवाद के प्रतिरोध से हुआ था और सदियों तक देश की भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे साहित्यिकों ने इस विदेशी साम्राज्यवाद से मोर्चा लिया है। यह मोर्चा नये ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भी जारी रहा है। इस दासता में भी हमने अंग्रेजी को क्यों नहीं अपनाया? इसलिए कि हमारी भाषा हमारी राष्ट्रीय चेतना की प्रतीक है। अरबी और फारसी के विरुद्ध इसी तरह तुलसीदास और भूपण ने हिन्दी की पनावा ऊँची रखी, इसलिए कि समाज के जीवित रहने का अर्थ हिन्दी का जीवित रहना भी था। यद्यपि हिन्दी का रूप बदलता रहा है, लेकिन उसकी एका नष्ट नहीं हुई। गुलाम देशों की यह मनोवृत्ति रही है कि वे विदेशी संस्कृति और भाषा को जल्दी अपना लेते हैं क्योंकि उनका अपना सामाजिक

जीवन नहीं के बराबर होता है। ज्ञान्ति के पूर्व के रूस में वहाँ के शिक्षित और धनी वर्गों में इसी प्रकार पेंच भाषा का बोलबाला था। रूसी भाषा को लोग गेंवारू और अयंगाम्भीर्य में हीन समझते थे। यदि वहाँ के साहित्यिक इस वृत्तित मनोवृत्ति के सामने सिर झुका देते तो आज का रूसी-साहित्य वहाँ होता ? हमारे देश में भी अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करने लोग अपनी शिक्षा का परिचय देना आवश्यक समझने हैं। जो बाबू वर्ग इंग्लिशतानी में बातचीत करता है, वह इसलिए कि अपनी भाषा में विचार करने की उसमें अक्षमता है। उसकी भाषा तीन कौड़ी की होती है और भाव दो कौड़ी के। हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कुछ लोगो ने अंग्रेजी, अरबी, फारसी—सभी से शब्द भर लेने की सलाह दी है। जहाँ नये नये शब्दों के शब्द खोजने पड़ें, वहाँ संस्कृत से न लेकर उन्होंने अंग्रेजी से लेने को कहा है। माना अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द खुद उसके घर के हों, उसने उन्हें लैटिन और ग्रीक से उधार न लिया हो। ग्रीक और लैटिन के शब्द अंग्रेजी की चलनी में छनते हुए हिन्दी में आएँ, उन्हें स्वीकार है, संस्कृत से हम शब्द लें, उन्हें स्वीकार नहीं।

जो भारत की जलवायु में पना है, उस भारत की भाषा और संस्कृति अपनाती होगी, उस भारत की ही महत्ता का स्वप्न देखना पड़ेगा। भारतीय भाषाओं को अन्तर्देशीय ढाँच में ढालने की चेष्टा पुरानी साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का एक अवशिष्ट चिह्न है, हम उससे किसी प्रकार सम्झौता नहीं कर सकते। जिस तरह हम भारत की भूमि में अन्न जल ग्रहण करते हैं, उसी तरह उगकी भाषा भी। जब हम देश-प्रेम करना सीखें, तब उसकी भाषा से भी प्रेम करेंगे। न हम देश-प्रेम में विगी में सम्झौता करना चाहते हैं, न भाषा प्रेम में। देश-प्रेम और भाषा प्रेम दो अलग वस्तुएँ नहीं, एक है। (१९३६)

भाषा और राष्ट्रियता

इसी साल अभी अगस्त के महीने में श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने बलबत्ता में महाजानि भवन का शिलान्यास करते हुए बताया है कि बंगाल ने भारतवर्ष के नये अभ्युत्थान में किस प्रकार योग दिया है। बंगाली भाषा, साहित्य, कला और संगीत—सभी का उन्होंने उल्लेख किया। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी अभिमान प्रकट किया कि विदेशी सभ्यता का स्वागत करने में बंगाल सर्वप्रथम था। अंग्रेजी समाचारपत्रों में उनका वाक्य इस प्रकार छपा था—
 "Bengal led India in welcoming European culture to her heart" यूरोप की सभ्यता अपनाते में बंगाल भारत का अग्रणी था। विदेशी सभ्यता विदेशी शासन के ही साथ हमारे देश में आई है। स्वाभाविक था कि राष्ट्र-प्रेमी व्यक्तियों ने विदेशी शासन के समान उस सभ्यता से भी अपने-आपको दूर रखा। परन्तु बंगाल में ऐम ह्यूमटनामा व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने उत्थान के लिए अंग्रेजी शिक्षा को आवश्यक समझा। उस शिक्षा के प्रसार के साथ बंगाल के नये साहित्य का उदभव भी हुआ। इसलिए अनेक बंगाली अपने साहित्य पर गर्व करते हुए उस शिक्षा पर भी गर्व करते हैं। फिर भी गुलामी गुलामी है, उस पर अभिमान करना किसी की शोभा नहीं देता।

बंगाली विद्वानों के हृदय में विदेशी शिक्षा और सभ्यता के प्रति यह भावना कितनी दृढ़ता से घर घर गई है, इसका एक और प्रमाण देखिए। बंग-साहित्य-सम्मेलन के सभापति सुप्रसिद्ध विद्वान् डा० सुनीतिकुमार चटर्जी ने इसी बात का उल्लेख कर कहा था—“ऊनविंश शतके इंग्लैंड अनुगामी बंगाली इंग्रेजी शिक्षा का भारतेर गुरुस्थानीय छिल।” और यही नहीं कि केवल घटनाचक्र में पड़कर अंग्रेज के अनुगामी बंगाली को अंग्रेजी शिक्षा लेनी पड़ी हो, बंगाल के अन्यतम भाषातत्त्वविद् डा० चटर्जी ने उसी शिक्षा की आवश्यकता बतलाते हुए कहा है—“इंग्रेजी के बाद दिया अन्य कौन भाषा के ताहार स्थाने बसाइते गेले ग्रामादेर मानसि” सति घटिबे।” इतना बड़ा चढ़ा अंग्रेजी के प्रति इनका प्रेम है कि उसके स्थान पर अन्य किसी भाषा को रखने से मानसिक क्षति की सम्भावना है। ऐम शब्द उसी व्यक्ति के मुँह में निजत सनते हैं जिसकी परमुखापेक्षिता चरम सीमा को पहुँच चुकी हो। (१९३६)

भाषा और साहित्य में पाकिस्तान

राष्ट्रभाषा को लेकर बहुत दिनों से विवाद चल रहा है। हिन्दीभाषी कहते हैं कि हिन्दी राष्ट्रभाषा होगी। उरदूभाषी लोग बंगला को राष्ट्रभाषा बनाने में लगे हुए हैं। उर्दू भाषी लोग उर्दू का भारत की 'आमफहम' और 'मुस्तर्जि जवान' मानते हैं। कांग्रेस के नेता कहते हैं, देश की 'कॉमन सेंसिबल' हिन्दुस्तानी है। हिन्दुस्तानी नाम की कोई भाषा है या उस भाषा को अभी जन्म लेना है, यह स्पष्ट नहीं है।

राष्ट्रभाषा के बारे में इनकी बातें सुनकर लगता है कि हमारा भी एक राष्ट्र है। राष्ट्र के गठन के समय में कोई अडचन नहीं है, इसीलिए राष्ट्रभाषा की समस्या उतनी महत्वपूर्ण हो गई है। किन्तु कुछ दिनों में देश में एक 'पाकिस्तान' की चर्चा होने लगी है। कांग्रेसी लोग देश में लगना है कि 'पाकिस्तान' हमारे परिहास का विषय बना हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि जिन्होंने देश के अन्दर एक नये पाकिस्तान की स्थापना की है, वे उर्दू की भी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

मुस्लिम लोग के नेता यह आन्दोलन करते हैं कि कांग्रेसी नेता उर्दू के धनु हैं और उनका उद्देश्य केवल हिन्दी-प्रचार करना है। दूसरे गहरे मुस्लिम लोग के यही नेता कहते हैं कि देश की राष्ट्रभाषा उर्दू है। यह उर्दू-प्रचार में अडचन देकर या अडचनो की कल्पना करके उन्होंने तय कर लिया है कि उनकी भाषा राष्ट्रभाषा न होगी, इसलिए राष्ट्र भी बायग न रहेगा। तब यह पाकिस्तान की चर्चा कोरा राजनीतिव आन्दोलन है या उसका और भी कोई आन्तरिक महत्व है? पाकिस्तान का 'मुल' विलेते देयर अनेर मुसलमानों का चिन्तन चल ही उठा है। इस भारत-उद्यान में यह 'मुल' क्या अत्यन्त तुच्छ और निरुपेक्षा साबित ही नहीं मिला है? साहित्य और भाषा में मुसलमानों ने जो आन्दोलन छेड़ दिया है, उसे देखकर लगता है कि इस विप्लव की जड़ें धरती में बहुत गहरी चली गई हैं।

मध्य भारत में बहुत दिनों से हिन्दी और उर्दू का विवाद चलता रहा है। लखनऊ और दिल्ली की मुस्लिम संस्कृति में केन्द्र कहा जाता है। इस कारण

देश के इस भाग में दरबारी सभ्यता के साथ भारत की एक अन्य व्यापक और अधिक प्राचीन सभ्यता का संघर्ष स्वाभाविक हो गया। विन्तु हिन्दीभाषी समझते हैं कि इस तरह का संघर्ष उन्हीं के साहित्य में पाया जाता है, अन्य प्रांतों में भाषा-सम्बन्धी कोई समस्या है, ऐसा उन्हें नहीं मान्य होता। विन्तु वर्तमान काल में अन्य प्रांतों में भी भाषा को लेकर संघर्ष चल रहा है, वह संघर्ष चाह तोड़ हो, चाहे घीमा हो, उसके अस्तित्व से इन्कार नहीं किया जा सकता। बंगला के हास्य-रसात्मक पत्रों में भाषा को उर्दू का नया लिखास पहचानने की बात लेकर अनेक व्यंग्य प्रकाशित हुए हैं। विन्तु मौलवी फजलुलहक का मन्त्रि-मण्डल कायम होने के बाद बंगला भाषा को विवृण्वन की चेष्टा और जोरों से होने लगी है। अब वह चर्चा हास-परिहास का विषय नहीं रह गई। देश में आन्दोलन द्वारा उसका प्रतिकार आवश्यक हो गया है।

बंगाल-साहित्य-सम्मेलन में डॉ० मुनीतिकुमार चट्टोपाध्याय ने इस बारे में कई बातें कही हैं। उन सब पर विचार करने से भाषा समस्या की गम्भीरता समझ में आ जाती है। आजकल के अरबी फारसी प्रेमी अनेक मुस्लिम नेताओं की तुलना में भारत के आदि मुस्लिम आक्रमणकारी भी इतने साम्प्रदायिक नहीं थे। डॉ० चट्टोपाध्याय ने कहा है, "वे बुतनिकन या मूर्तिध्वसी थे, विन्तु खान-शिकन या भाषा-ध्वसी वे नहीं थे।" उन्होंने कलमा मूल भाषा में प्रकाशित न करके उसका अनुवाद देशी भाषाओं में प्रकाशित किया था। विन्तु आज साम्प्रदायिकता इतनी प्रबल हो गई है कि कलमा से दूरिनार, साहित्य को कलमे की भाषा में लिखने का प्रयत्न हो रहा है।

तुर्की में अरबी फारसी शब्दों का बहिष्कार हुआ, फारसी से अरबी शब्दों का बहिष्कार हुआ, यह सब साम्प्रदायिक मुस्लिम नेताओं को दिखाई नहीं देता। वे 'पैन इस्लामिज्म' की बातें करते हैं। विन्तु अन्य मुस्लिम देशों की राह छोड़कर उन्होंने अपनी नई राह पकड़ी है, यह बात वे भूल जाते हैं। भाषा के अलावा भावों में भी साम्य होता है। भारत के साम्प्रदायिक नेता, भाषा और भाषा बोना ही क्षेत्रों में, अन्य स्वाधीन मुस्लिम राष्ट्रों से एकदम अपरिचित हैं। डॉ० चट्टोपाध्याय ने बंगाल में यह भाषा-ध्वसी कुचेष्टा देखकर सखेद कहा है, 'पश्चिम के मुसलमान लेखकों में अन्धाधुन्ध भाषा में अरबी फारसी शब्द भरने की प्रवृत्ति को रोकने की बात चली है। क्या केवल बंगला भाषा में उस रीति को नया रूप देकर ग्रहण किया जायगा और पाँच करोड़ से ऊपर जनता की दुर्लभ भाषागत एकता को स्वेच्छा से विनष्ट कर दिया जायगा?' "

मध्य भारत में उर्दू को सहज और सरल बनाने के लिए उम अरबी फारसी के शब्द जाल में मुक्त करने के लिए आन्दोलन हो रहा है। इस आन्दोलन के सूत्रधारों में अनेक प्रगतिशील लेखक हैं। वे कोशिश कर रहे हैं कि साहित्य यथाम्भव जन-साधारण के लिए बोधगम्य हो। लाक्षणिक सुबाध साहित्य रचने के लिए उम अरबी फारसी के कठिन शब्द जाल से मुक्त करना ही होगा।

सभी लोग प्रयत्न करते हैं कि उनकी भाषा का प्रसार हो। किन्तु अन्य साम्प्रदायिकता का जाल अरबी फारसी के शब्द समेटकर बहुसंख्यक जनता के लिए भाषा को दुर्बोध बना देता है। इस तरह का प्रयत्न मुस्लिम साम्राज्य के वैभव के दिनों में न हुआ था। आज वह प्रयत्न इतना समर्थ क्यों हो गया है ?

मुस्लिम साम्राज्य में पुराने हिन्दी-साहित्य का चरम विकास हुआ था। तुलसीदास, सूरदास आदि कवि उसी युग में हुए थे। और उस युग के साहित्यिक थे रहीम, रसखान जैसे मुसलमान कवि। वे हमारे देश के, हमारी भाषा के कवि हैं। क्या उनकी स्थाति किसी भी मुसलमान लेखक के चाहने योग्य नहीं है ? सर इकबाल का हम नाम सुनते हैं। रहीम के दोहे और रसखान के छन्द गाँवों के हिन्दू और मुसलमान दोनों के ही कंठ में बसे हुए हैं। क्या वह लोकप्रियता पाकिस्तान के जन्मदाता के लिए दुःप्राप्य नहीं है ? मुस्लिम साम्राज्यकाल में मुस्लिम साहित्यकार अपनी भाषा में अपना कोई स्मृतिचिह्न न चाहते थे। साम्राज्य का नाश होने पर अनेक लोगों के हृदय में यह इच्छा हुई कि बीते वैभव का एक सांस्कृतिक चिह्न सुरक्षित कर लिया जाय। उर्दू भाषा का विकास तभी सम्भव हुआ जब मुस्लिम साम्राज्य का अन्त पतन आरम्भ हो गया। उस युग के साहित्य में सामाजिक और राजनीतिक पतन के अनेक लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। जन-साधारण की भाषा छोड़कर दरबारी साहित्यकारों ने एक नई दरबारी भाषा का आविष्कार किया। उसे खूब मार्जित करके उन्होंने उसे अपना सांस्कृतिक चिह्न मान लिया। भाषा में ऊपरी चमक दमक थी। किन्तु उस भाषा में देश के प्राणों की गूँज नहीं थी। कविता का प्रधान गुण हो गया चमत्कार-प्रदर्शन। उस चमत्कार-प्रदर्शन की भाषा हुई उर्दू। इस चमत्कार-प्रियता ने ही सर्वनाश की राह दिखाई। इस सर्वनाश से कोई भी 'चमत्कार' उनका उद्धार न करेगा, यह बात उनके दिमाग में नहीं आई। ईरान की पतनकालीन साहित्यिक परम्परा को अपनाकर मुसलमान दरबारी कवियों ने अपने साहित्य का विकास किया। आज अरबी फारसी शब्दों का मोह त्यागने की बात घाने पर उन्हें लगता है कि उनके गौरव का इतिहास नष्ट हो जायगा। मुस्लिम साम्राज्य के वैभवकाल में मुसलमान साहित्यकारों ने लोकभाषा का व्यवहार करके कितनी शक्ति प्राप्त की, यह बात इनके दिमाग में पँटती ही नहीं।

देश में जो लोग पाकिस्तान चाहते हैं, वे पाकिस्तान लेकर भी सन्तुष्ट न होंगे। वे अब भी विगत साम्राज्य की मधुर स्मृति में निमग्न हैं। उनकी समझ में उस स्मृति के साथ अरबी-फारसी शब्दों से लदी हुई भाषा का कोई आध्यात्मिक सम्बन्ध है। इसलिए राजनीति में जो पाकिस्तान के समर्थक हैं, वे भाषा का भी विभाजन करने को तैयार हैं। वे सोचते हैं कि उनकी नई भाषा समय बीतने पर देश की अन्य भाषाओं पर अपना आधिपत्य कायम कर लेगी। इसीलिए अरबी-फारसी सस्मृति को आधार बनाकर उन्होंने भारत की अनेक भाषाओं में विघ्नसर्प आरम्भ कर दिया है।

हमने अरबी, फारसी या अन्य विदेशी शब्दों का बहिष्कार किया हो, ऐसा नहीं है। हिन्दी-साहित्य की लावप्रिय और घमँघम्य के समान पूजनीय पुस्तक रामायण में अनेक विदेशी शब्द हैं। हिन्दी के किसी भी उत्तरदायी साहित्यकार ने कभी यह नहीं कहा कि हमारी भाषा केवल ससृजित शब्द मात्र समर्थ बनेंगी। लेकिन अस्वाभाविक रूप से हिन्दी में अपरिचित शब्द भरने में विनामयम भग होगा, यह बात भूलना न चाहिए। भारत की अधिकांश भाषाओं का एक सामान्य सांस्कृतिक आधार है। चाहे पश्चिम में लोग हिंदी, बँगला, मराठी आदि भाषाएँ समझ लेते हैं, कारण यह कि इन भाषाओं में बहुत से शब्द सामान्य हैं। देश की एकाता के सूत्र में बाँधने के लिए भाषा की यह एकता प्रधान माध्यम है। अपनी बुद्धि से अनेक जन इस एकाता पर आधारित कर रहे हैं किन्तु जितना आधार करेगा, उतना ही देश की भाषाओं का परस्पर साम्य-बोध और भी दृढ़ होगा। सभी देशवासी इस राष्ट्रघातक प्रयत्न को समूल नष्ट कर देंगे। (१९४१)

हिन्दी गद्य-शैली पर कुछ विचार

आज से लगभग सत्तर वर्ष पहले भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने नये हिन्दी गद्य की व डाली थी। वैसे अजभाषा से भिन्न नई हिन्दी लिखने का प्रयास और भी हुले आरम्भ हो गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि अब तक नये हिन्दी गद्य सौ वर्ष बीत चुके हैं और अब इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि आरण गद्य के लिए हम एक साफ-सुथरी नौली बना सके हैं या नहीं। हिन्दी गद्य विकास में जो दो-तीन मार्ग-चिह्न स्पष्ट दिखाई देते हैं, उनमें सबसे पहले तो आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र और उनके सहयोगियों ने हिन्दी गद्य-शैली पर एक अमिट छाप डाली है। इन शैली पर विचार करते हुए हमें सभी आलोचना माननी है। पहली तो यह कि इसमें एक ऐसी जिन्दादिली का बाद के गद्य में प्रायः नहीं मिलती। दूसरी यह कि इस भाषा में परिष्कार की जरूरत है और अपने तात्कालिक रूप में वह शैली आज ग्रहण नहीं की जा सकती।

इन दोनों बातों में कुछ ठहरकर विचार करना आवश्यक है। भारतन्दु-युग के लेखकों की शैली में जिन्दादिली क्या है और बाद के गद्य में वह लोप क्यों हुआ है? इसका कारण कुछ लोग यह बताते हैं कि भारतेन्दु और उनके सहयोगी गहन गम्भीर चीजें न लिखते थे। इसलिए उनकी शैली में हँसी-मजाक की आवाज ज्यादा रहती थी। आगे चलकर हमारी शैली में भाव-गाम्भीर्य आया और इसलिए यह जरूरी हो गया कि इस गहराई में जिन्दादिली डूब जाय। एक बात ध्यान देने की यह है कि भारतन्दु-युग के लेखक इस पीढ़ी के लेखकों की तुलना में सस्तर के अधिक निकट थे। उनके सामने हिन्दी गद्य की कोई विविध परम्परा न थी और इसलिए होना तो यह चाहिए था, कि संस्कृत के शब्दों का भरमार से उनकी शैली में भिन्न बन जाती, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। इसके सिवा यह बात भी सही नहीं है कि उस युग में गम्भीर आलोचना नहीं लिखी गई। उस युग के मासिक पत्रों की जितनी में सैकड़ों सुन्दर आलोचनात्मक निबन्ध आज भी सुरक्षित हैं। (यानी जहाँ उन्हें रहीं में बेच नहीं डाला गया था जिन्दा में दीमक नहीं लग गया।) उनका मनन करने का नया विधी ने उन्हें प्रशिक्षित

नहीं बिया, इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे प्रवासकों को है। उन निबन्धों में भाज के बहुत ही मामूली आलोचनात्मक निबन्धों की तुलना की जाय तो दोनों की शैली का भेद मालूम हो जायगा। उस समय के अधिवक्तर लेखक यह कोशिश करते थे कि कठिन और दुरूह बातों को भी आमानी में समझा दें। भाज के काफी लेखकों की यह कोशिश होनी है कि साधारण बातों को भी असाधारण शब्दावली में प्रस्तुत करके अपने निबन्धों को गम्भीर बना दें।

यह सही है कि भारतेन्दु-युग की गद्य-शैली में परिष्कार की जरूरत थी। लेकिन यह जरूरत इतनी बड़ी नहीं जिनकी कि लोग समझते हैं। बालकृष्णभट्ट के निबन्ध, भारतेन्दु के नाटकों में वातालाप, राधाचरण गोस्वामी के ग्रहमन—इनमें बहुत परिष्कार की गुंजाइश नहीं है। उसके अलावा जो परिष्कार प्राप्त करेंगे, वह कुछ शब्दों को लेकर होगा, वाक्यरचना, पंक्तियों के चुनाव, शैली के प्रवाह आदि में इसमें ज्यादा अन्तर न पड़ेगा। यानी भारतेन्दु-युग का कोई सचेत लेखक व्याकरण की दो-चार अनुद्विधा बराता हुआ गद्य लिखता तो उसकी जिन्दादिली में ज्यादा पर्य न पड़ता। इसलिए जिन्दादिली का सबसे साहित्य का हल्कापन नहीं है। अगर ऐसा हो तो हल्केपन के डर से कोई भी जिन्दादिलि लेखक साहित्य की दुनिया में पैर ही न रखे।

भारतेन्दु-युग की गद्य-शैली पर थोड़ा और विचार करने में उसकी कुछ ऐसी विशेषताएँ सामने आती हैं जो बाद के गद्य में, विशेषकर सन् '२० से सन् '४० तक के गद्य में, कम मिलती हैं। पहली विशेषता यह है कि इन लेखकों के मन में शब्दों का चुनाव करते हुए किसी तरह के निषेध का विचार आये नहीं आता। द्विवेदा-युग में हमारे भीतर एक निषेध-भावना घर कर गई थी—एक शब्द को हम जानते हैं, बातचीत में उसका प्रयोग भी करते हैं लेकिन गद्य में उसे लिखें या न लिखें, यह प्रश्न बार-बार लेखकों के सामने आता था। भारतेन्दु-युग के लेखकों में नई हिन्दी का रूप संसारते हुए बँगला और संस्कृत की ओर भी ध्यान दिया, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उन्होंने उस बोलचाल की भाषा पर दिया जो नित्य ही उनके कानों में पड़ती थी। भारतेन्दु-युग की गद्य-शैली का आधार बोलचाल की भाषा है। उस समय के निबन्धों को पढ़िये तो यह नहीं लगता कि उन्हें किसी ने लिखा है। ऐसा मालूम होता है कि लेखक हमसे बातें कर रहा है और हम छापे के अधरो में भी उसकी आवाज सुनते जाते हैं। द्विवेदी-युग में परिष्कार के बहाने गद्य-शैली का आधार बदल दिया गया। अनेक लेखकों ने बोलचाल की भाषा से बार-बार बचने की कोशिश करते हुए शुद्ध साहित्यिक हिन्दी को अपनी शैली का आधार बनाया।

बोलचाल की भाषा को आधार बनाने से ही भारतेन्दु-युग के लेखक अपनी शैली में एक बहुत ही बलवती आहिवा शक्ति पैदा कर सके थे। वे जिस शब्द को भी चाहते थे, उसे हिन्दी में पचा लेते थे। इस तरह वे फारसी, अरबी और अंग्रेजी के शब्दों का ही एगान्तर न कर लेते थे बल्कि हिन्दी और संस्कृत का भेद मानते

हुए संस्कृत शब्दों का रूपान्तर भी कर लेते थे। हमारी ग्रामीण भाषाओं में यह प्रवृत्ति है कि संस्कृत के शब्द अपने सरल तद्भव रूप में वाम में लाये जाते हैं। भारतेन्दु-युग के लेखकों ने अपनी शैली में इस प्रवृत्ति को उभारा। उन्होंने तद्भव शब्दों का बहुलापन में प्रयोग किया, इसके अनावा ग्राम-भाषाओं से भी जहाँ तक हो सके शब्द लीचे और इस तरह नई हिन्दी को समृद्ध किया। आगे चलकर यह प्रवृत्ति बदल गई। संस्कृत शब्दों के तद्भव रूप पर जोर देने के बदे हम तद्भव शब्दों को भी तत्सम रूप देने लगे।

यहाँ पर हिन्दी-भाषा के भौतिक विकास पर दो शब्द कहना अमगत न होगा। ५० अक्षरनाथ भा अक्षर कहते सुने जाते हैं—“मेरी मातृभाषा हिन्दी नहीं है परन्तु संस्कृत-प्रभित होने के कारण हिन्दी देश के अधिकांश भाग में बोली और समझी जाती है।” इस तरह की बातें मभा-ममाज में आये दिन हम दूसरों के मुँह से भी सुना करते हैं। यह बिल्कुल सही है कि हिन्दुस्तान के अधिकांश भाग में हिन्दी बोली और समझी जाती है। देश की और किसी भाषा को यह गौरव प्राप्त नहीं है। लेकिन ‘शाय कबल को भारसी क्या?’ बलकृष्ण की हरीसन गोड या बम्बई के परेल में उन लोगों की बोली मुनिशे जिन्होंने हिन्दी को वास्तव में यह गौरव दिया है। इनकी बोली हुई हिन्दी का रूप ५० अक्षरनाथ भा की संस्कृत-प्रभित अ-मातृभाषा हिन्दी से बहुत भिन्न है। भा महोदय के लिए क्षम्य है कि मातृभाषा न होते हुए भी वह हिन्दी को उसके किसी भी रूप में बोल लेते हैं लेकिन जो लोग हिन्दी को मातृभाषा मानते हैं, उन्हें तो अपनी भाषा के उस रूप की रक्षा करनी चाहिए जो सचमुच उनके आये दिन के व्यवहार में प्रकट होता है।

संवत् २०० से लेकर संवत् २००० तक हिन्दी का विकास किम पार हुआ है? हिन्दी-भाषा की भागीरथी हिमालय में समुद्र की ओर बही है या समुद्र से हिमालय की ओर? गोस्वामी तुलसीदास, भारतेन्दु और प्रेमचन्द ने हिन्दी के संस्कृत रूप को संवारा है या उसके प्राकृत रूप को? यदि यह दावा सच होता कि भारतीय भाषाओं की एकता का आधार संस्कृत के तत्सम शब्दों का समान रूप से प्रयोग है तो बँगला, गुजराती, हिन्दी, मराठी आदि-आदि भाषाओं का अलग-अलग विकास बिल्कुल अस्वाभाविक होता। इतिहास की मीग कुछ और थी, भाषा विज्ञान के प्राचार्यों की मीग कुछ दूसरी है। गुजराती, मराठी, बँगला, हिन्दी आदि भाषाओं का अलग-अलग विकास इसलिए हुआ है कि इन भाषाओं में अपने प्राकृत रूप को संवारा है। उन्होंने तत्सम शब्द भी लिए हैं और साहित्य-रचना में विशेष रूप से लिये हैं लेकिन बँगला, हिन्दी या मराठी की जानीयता, उसका विशेष रूप, उसका बोधन या वह भेदगपन जिसका उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास ने किया था, संस्कृत शब्दों के प्रयोग के कारण नहीं है। भाषा की भागीरथी प्राकृत रूप समुद्र की ओर ही बह रही है, संस्कृत रूप हिमालय की ओर नहीं। हिमालय की बर्फें धूल-धूलकर अब सजल बन

"घातिर आप रमणी हैं न ? जिम दिन आप कमल-नृमुग के समान यत्न-मान सामाजिक पानी की तरह से ऊपर उठ आएंगी, जग दिन यह कह देगी कि त्यागवाद महान् नहीं हो सकता । जिम त्याग का खिड़ोरा पीटा जा रहा है वह या तो समाज में इस समय जो धर्म प्रचलित है उस धर्म के भय से बिया जा रहा है या वह समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने के लिए बिया जाता है । सारे दान पुण्य, सत्कर्म बड़े जानेवाले वार्य दन्ती दो कारणों के परिणाम हैं । सारा सामाजिक संगठन अर्धज्ञानिक नहीं है । जो चीख वैज्ञानिक नहीं है, वह महान् हा ही नहीं सकती । मिस विमना, इस युग के दो सबसे बड़े तत्त्ववेत्ता हैं—कारबिन और वाल्स मार्क्स । दोनों ग्रहणवादी हैं ।"

घाईस साल की लड़की के धीरज की प्रशंसा करनी होगी । लगभग पूरा पृष्ठ सुन जाती है और एक बार भी उस चौबीस साल के युवक को नहीं टोरती । नीतिराज ने भी, मालूम होता है, कालेज में हिन्दी के नाटक ही पढ़े हैं । इसलिए विमना से कहता है—"घातिर आप रमणी हैं न ।" क्या ही अच्छा हो कि कालेज के लड़के सहपाठिनी विद्यार्थिनी के लिए ऐसे ही सुन्दर शब्दों का प्रयोग किया करें । 'सामाजिक पानी की तरह' से ऊपर उठाना भी बर्मात है । एक वाक्य में नीतिराज सर्वनामों का प्रयोग भूल गया है इसलिए 'जो धर्म प्रचलित है उस धर्म के भय से,'—बार-बार धर्म की दुहाई देने लगता है । 'समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करना' आदि ऐसे दुकड़े हैं जो नाटक की वाक्य रचना में ठूँठ-जैसे लगे हैं । नीतिराज ने कारबिन और वाल्स मार्क्स को ही पानी नहीं दिया, बोल्शाल की हिन्दी पर भी पानी फेर दिया है ।

नाटकों में इस तरह की सौली ज्यादा दिन नहीं चल सकती । पाठ्य-क्रम में शामिल करने पर भी इस तरह के नाटक हिन्दी के रणमंच का उद्धार नहीं कर सकते ।

मालोचना में गम्भीर चिन्तन के नाम पर हर तरह की वाक्य-रचना क्षम्य समझी जाती है । एक उदाहरण देना ही काफी होगा । 'सामाजिक शक्ति के संगठन में परस्पर-विरोधी शक्तियों का संघर्ष होता है, साहित्य उसका सजीव चित्रण कर यह स्पष्ट कर देता है कि उसमें वह सक्रिय रूप से भाग ल रहा है और यह कि वह सामाजिक संगठन एक स्थिर वस्तु नहीं है, बल्कि गतिमान और परिवर्तनशील है ।' इस बात को और भी सन्न ढंग से कहा जा सकता था और इस तरह का वाक्य रचने के लिए गम्भीर चिन्तन की दुहाई नहीं दी जा सकती । वाक्य के वेदोपेन का कारण गम्भीर चिन्तन नहीं, अंग्रेजी के 'that' का भद्दा अनुवाद है 'यह कि वह' ।

संक्षेप में हिन्दी की गद्य शैली को संवारने के लिए वाक्य-रचना पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है । लिखते समय हम वाक्यों का सुनते भी जाएँ या निस जाने पर उन्हें जोर से पढ़कर सुनें सुनाएँ जिससे कि उनका अस्वाभाविक प्रवाह तुरन्त मालूम हो जाय और हम उनमें आवश्यक सुधार कर सकें । इसके

मिलावा मसार की हर भाषा के पुष्ट गद्य का आधार ग्राम जनता की बोलचाल की भाषा रही है। हमें अपनी गद्य शैली को सबल और समर्थ बनाने के लिए फिर यही आधार कायम करना है। ऐसा करने से हिन्दी भारत की दूसरी भाषाओं से दूर न जा पड़ेगी। यह भय इसलिए पैदा होता है कि हम भारतीय भाषाओं के विकास को ही गलत समझ बैठते हैं। यह विकास संस्कृत की ओर नहीं लौट रहा है बल्कि तद्भव रूपों को अपनाता हुआ भाषा के प्राकृत रूप की ओर बढ़ रहा है—प्राकृत, अपने मौलिक और व्यापक अर्थ में। भारतन्दु और प्रेमचन्द की शैली इसी विकास की ओर संकेत करती है। हिन्दुस्तान की अधिकांश जनता हिन्दी बोलती है या उसे समझती है। लेकिन हम अपनी गद्य-शैली को उस जनता के बोलने समझनेवाले रूप से बहुत दूर ले गए हैं। इस तरह हिन्दी लोकप्रिय नहीं बन सकती। मादरता फैलाने पर यह गद्य शैली बदलेगी। नई पीढ़ी के लेखकों पर विशेष रूप से यह भार है कि वे अपनी शैली को इस तरह गढ़ें कि शिक्षा-प्रसार में उसमें सहायता मिले और देश की कोटि-कोटि जनता के सम्पर्क से वे स्वयं भी अपनी भाषा और साहित्य को समृद्ध बनाएँ।

(१९४७)

राष्ट्रभाषा हिन्दी और हिन्दू राष्ट्रवाद

हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की माँग कुछ नई नहीं है। भारतेन्दु में नेकर मय तक इस माँग का आधार यही रहा है कि हिन्दी जनता की भाषा है; बोलने, लिखने और समझने में यह सर्व है, हिन्दुस्तान की अधिराज्य जनता सभी भी उसे बोलती और समझती है। अपनी माँग को पुष्ट करने के लिए हिन्दी-भाषियों ने जनता को अपनी बसोटी बनाया था। उन्होंने राष्ट्रभाषा की समस्या का जनतात्रिक ढंग से ही सुलभाने का प्रयत्न किया था। लेकिन पछर कुछ वर्षों में यह परिस्थिति बदल रही है। साहित्य-सम्मेलन के मय में हिन्दी-हिन्दुस्तान का नाम लगाकर अपनी भाषा के प्रसार का गवुचित करने और उसके राष्ट्र विकास को रोवने का प्रयाग किया गया है। एक तरफ तो हम गव के साथ कहते रहे हैं कि हिन्दी आम जनता की भाषा है जिसके बालने-बाले सभी जातियों और धर्मों के लोग हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रीयता के नाम पर साम्प्रदायिकता का जहर फैलानेवाला यह नया हिन्दू राष्ट्रवादी दल भाषा को धर्म के साथ जोड़कर हिन्दी को जनता की भाषा के पद में हटा दना चाहता है। ऊपर से देखने में मालूम होता है कि ये हिन्दू राष्ट्रवादी हिन्दी के समर्थक हैं, जो उसका प्रसार और विकास चाहते हैं, बास्तव में इनके बडा शत्रु हिन्दी का कोई दूसरा नहीं हो सकता। राष्ट्र की तरह भाषा का विकास भी जनतात्रिक आधार पर होता है, जनता की उपेक्षा करने कासिस्म को आधार बनाने पर राष्ट्र की तरह भाषा का भी सत्यानाश होना अनिवार्य है। हिन्दी का सत्यानाश करना तो विघाता के लिए भी कठिन होगा। विघाता की इच्छाओं के एवमात्र टीकाकार ये हिन्दू-राष्ट्रवादी उनके विकास में कुछ देर के लिए बाधा जहर डाल सकते हैं।

राष्ट्रभाषा के साथ हिन्दू-राष्ट्रवाद के गठबन्धन को सबसे ताजी मिसाल थी रविशकर शुक्ल की लिखी हुई एक पुस्तक है जिसका नाम है—‘हिन्दीवालो, सावधान !’ ‘इस्लाम खतरे में है’ की तरह लेखक ने हिन्दू-धर्म खतरे में है, कहकर हिन्दीवालो को सावधान करने की चेष्टा की है। जहाँ-जहाँ ‘इस्लाम

तनूरे में है' का नारा लगाया गया है, वही-वही गाबिन हो चुका है कि इस्लाम
 बदले किसी की जमीन-जायदाद ही गतरे में यो जिंगे बचाने के लिए यह
 तनूरे की घटी बजाई गई थी। इस बहाने जायदाद की रिपाजत हा नहीं पाती
 और जनता इस ठग विद्या को पहचानकर जायदाद की जवाब करके ही इस सेनो
 । सेनान ने इस्लाम की गांधी न मानकर मुस्लिम धर्मान्धता की धादन
 मानकर उगरे पीछे चलने की सिफारिश की है। प्रत्येक हिन्दू-राष्ट्रवादी ऊपर
 स जिन्ना का विरोधी होने हुए भी हृदय में उनकी को अपना धादन मानता है।
 पाँचवाँ और देश के स्वाधीनता सधाम के द्वारे में यह धीम के प्रतिनिधवादी
 नेनाधो के समान ही भूठा प्रचार करता है। रविनर पुस्तक का अभियोग है
 कि कांग्रेस ने हिन्दुओं के साथ 'घोर विस्वामपात्र किया है।' (हिन्दीभाषा,
 माधवान'; परिशिष्ट, पृ० ६७)। हिन्दुओं का विस्वासापात्रता कोई हिन्दू
 जिन्ना ही हो गाता था लेकिन सेनान के दुर्भाग्य से 'हिन्दुओं का ऐसा कोई नेता
 नहीं है जो मि० जिन्ना से टकरा सके।' (उप०) हिन्दुओं में ऐसा नेता पैदा
 करने के लिए जरूरी है कि हर हिन्दू के हृदय में राष्ट्रियता की परम्परा को
 निमल कर दिया जाए। इसलिये कांग्रेसी नेताओं के लिए सेनान ने यह दावा किया
 है कि उन्होंने 'जन्म-भर मनसा, बाधा और कर्मणा यह सिद्ध करने की चेष्टा
 की है, और घर भी कर रहे हैं, कि वे हिन्दू नहीं हैं।' (उप०) कांग्रेस पर
 अहिन्दू होने का अभियोग लगाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि कांग्रेस की प्रेरणा
 से जो जनवादी परम्परा कायम हुई है, उसमें निहित स्त्राघों की रक्षा की जाए।
 इस हिन्दू प्रेम के पीछे पूँजीवाद और उमीदारी प्रथा का प्रेम छिपा हुआ है जो
 लेखक ने इस तरह की दलीलें देना कराता है—प० नेहरू को हिन्दुस्तान के नाम
 से बिड़ है यशोवि उसमें हिन्दू नाम जुड़ा हुआ है। इसलिये वह चाहते हैं कि
 देश को 'इंडिया' ही कहा जाए और इस मामले में गांधीजी 'उनकी पीठ धपपपा
 रहे हैं' (परिशिष्ट, पृ० ६८)। प० नेहरू के भाषणों की जनता भी सुनती है
 और वह अच्छी तरह जानती है कि वे इंडिया शब्द का प्रयोग क्यों हैं या
 हिन्दुस्तान का। लेकिन फागिश्म का आधार झूठ होता है और हिन्दू-राष्ट्रवाद
 एक फागिस्ट विचारधारा है।

हिन्दू और मुस्लिम प्रतिप्रियावादी एक-दूसरे के बितने निबट हैं, इसकी
 एक मिमाल देखिए। दोनों ही नेहरू-सरकार की एक हिन्दू सम्प्रदायवादी सरकार
 के रूप में चलना करते हैं। वरुं इतना ही है कि मुस्लिम प्रतिप्रियावादी उसे
 हिन्दू सरकार पहने से ही मानते हैं और उनके हिन्दू भाई उगे ऐसी बनाना
 चाहते हैं। पुक्कनी कहते हैं कि 'हमारा सत्तार नेहरू सरकार को हिन्दू सरकार
 बनाना और गमभता है—जबकि वास्तव में अर्थात् अमन में वह हिन्दू सरकार
 नहीं है। ऐसी भाति का कारण नहीं रहने या भविष्य में उत्पन्न होने दिया जा
 सकता। (उप०) सारे सत्तार में जबकि और उनके पिछू ही ऐसा प्रचार
 करते हैं और धी० धी० धी० दुनिया-भर में विज्ञापित करती है कि प० नेहरू

को हिन्दू सरकार मुसलमानों का नाश कर देना चाहती है। लेकिन मसाल में सब चर्चित, पीरोज खाँ नून या उनके हिन्दू नन्हाल (रविशंकर शुक्ल जैम) ही नहीं है। दुनिया का हर जनतन्त्रवादी न तो नेहरू सरकार को एक हिन्दू सम्प्रदायवादी सरकार मानता है और न उसे होना देना चाहता है।

हिन्दू राष्ट्रवाद की खुली घोषणा इस प्रकार है—

‘हिन्दुस्तान एक हिन्दू राष्ट्र हो जिसका राज-धर्म हिन्दू धर्म हो और जिसमें सब प्रमुख पदों पर हिन्दुओं और प्रमुस्लिमों की नियुक्ति हो। ऐसा कोई व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से हिन्दू धर्म न मानता हो, हिन्दुस्तान सरकार का प्रधान नहीं हो सकता।’ (पृ०) स्पष्ट रूप से हिन्दू धर्म मानने का मतलब क्या है? यह कि जो मुसलमानों को हिन्दुस्तान में रहने दे, वह पूरा हिन्दू नहीं है। “इस्लाम धर्म के किसी अनुयायी को हिन्दुस्तान में नागरिकता के अधिकार नहीं मिल सकते” और “अल्पसंख्यक के किसी भेद नाम पर पाकिस्तान के फिफथ कॉलम को स्वच्छन्द नहीं छोड़ा जा सकता” (पृ० ६६)। यह है सच्चे हिन्दूपन की कमीटी! अगर सीधी नीति धर्मान्ध है तो क्या हम नहीं हो सकते? अगर वे एक बार मुँह में गिरे हैं तो हम सौ बार गिरेंगे। हिन्दू राष्ट्रवाद की बीरता इसी प्रकार की है।

इस हिन्दू राष्ट्रवाद की भाषा के क्षेत्र में सागू करना मुश्किल नहीं है। जैसे हिन्दुस्तान का हर मुसलमान पाकिस्तान का फिफथ कॉलम है, वैसे ही हिन्दी में आया हुआ अरबी-फारसी का हर शब्द फिफथ कॉलम है, जिसे निकाल बाहर करना चाहिए। बात कुछ बहुत मौलिक नहीं है क्योंकि मराठी में भी सावरकर भी यह काम कर चुके हैं। उन्हें सफलता कितनी मिली है, यह मराठी का कोई अक्षर उठाकर देख लीजिए।

कठिनाई तब पैदा होती है जब जनता के व्यवहार का प्रश्न सामने आ जाता है। हिन्दू राष्ट्रवादियों के दुर्भाग्य से इस देश की जनता हिन्दू-मुसलमान शब्दों की पहचान नहीं कर पाती। फल यह होता है कि इस जनता से प्रेरणा पाने वाले कवि और लेखक भी हिन्दू-मुस्लिम शब्दों का भेदभाव भूल जाते हैं। इसलिए हिन्दू राष्ट्रवाद के इन आचार्य ने जनता का भगडा ही खरम कर दिया है। आपने लिखा है—‘जनता तो मेड़ों के झुण्ड के समान है, उसे नेताओं ने जिधर हाँक दिया उधर चल दी’—‘जनता को पेटभर खाने और तनभर कपड़े के सिवाय किसी और चीज की चिन्ता नहीं होती।’ (मूल पुस्तक, पृ० ८५)।

यह तर्क भी अधिक मौलिक नहीं है। जब हिन्दुस्तान में आजादी का आन्दोलन चला, तब अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने भी यही दलील पेश की थी कि हिन्दुस्तान की आम जनता को तो खाने-पहनने से मतलब है, कुछ थोड़े से असन्तुष्ट लोगो ने उसे आजादी का नाम लेना सिखा दिया है। अगर उन्हें पकड़कर जेल में बन्द कर दिया जाय तो वह आजादी का हल्ला भी एक दिन में खत्म हो जाएगा, इस विचार के अनुसार जनता को भेद और घनने

को मेडिया समझनेवालों ने काम भी किया लेकिन उमरा फन क्या हुआ, इसे सारी दुनिया जानती है। श्रीमान् रविवर शुक्ल जनता को 'लंग्वेज कांग्रेस' करने के फेर में स्वयं जनता की शक्ति से 'मनवान्नास' हो गये हैं। लेकिन लंग्वेज महादुर की शक्ति पर आपका विश्वास झटका है। भारतीय जनता तो अपनी भाषा के प्रति कभी जागरूक नहीं रही लेकिन 'भला हो लंग्वेज महादुर का ज़िन्ने फारसी को हटाकर प्रांतीय भाषाओं को प्रतिष्ठित किया' (पृ० ५८)। गोया साहें मँवाले ने हिन्दी का सर्वनाश करने के लिए कुछ उठा रखा था और उनकी चलाई हुई शिक्षा-प्रणाली के लिए हिन्दुस्तानियों को उनका श्रुतज्ञ होना चाहिए। अपनी जनता को माली कि वह भट है और लंग्वेज के उठा लिए शाबाशी कि वह इम्मापसन्द है—यह है हिन्दू राष्ट्रवाद का सच्चा रूप।

हिन्दी-भाषी जनता को मेडियाप्रदान बनारस इस लेखक ने हिन्दी के बड़े-बड़े साहित्यिकों को भी उसमें शामिल कर लिया है। यह हिन्दी के लिए गर्व की बात है कि उनके बड़े-बड़े साहित्यकारों ने बोलचाल की भाषा को अपना आधार बनाया है। रविवर शुक्ल की भूमिका में इस बोलचाल की भाषा को अपनाने का मतनय है उर्दू कोष को अपनाना। लिखा है—“उर्दू कोष बेचल हिन्दी शब्द-सागर में ही नहीं गमाया हुआ है, यह व्यवहार में भी बहुत हद तक हिन्दी पत्रों और पुस्तकों के पन्नों पर विद्यमान है, और हिन्दी के बड़े-बड़े साहित्यिकों की बोलचाल में भी विद्यमान है, यस्कि यो कहिए, बोलचाल में और भी अधिक प्रचल रूप से विद्यमान है” (पृ० ३)। इस बोलचाल के खतरे से बचने के लिए आपने यह बाबा-बाक्य प्रमाण रूप में रखा है—‘कण्ठगतैऽपि प्राणं यावन्ती न मदेत्।’ और टीका की है—‘संस्कृत की इस अक्षर्य पीढ़ी में आज हिन्दी है। आज हिन्दी को वही काम करना है जो संस्कृत ने, पाली ने और अपभ्रंश ने किया है’ (पृ० ६)। संस्कृत की अक्षर्यता से अपभ्रंश कैसे पैदा हो गई, अपने अद्भुत भाषा विज्ञान का प्रकाश हम प्रश्न पर भी डाल देते तो हिन्दीवाले और सावधान हो जाते।

लेखक को हर जगह हिन्दी हारती हुई और उर्दू जीतती हुई दिखाई देती है। उर्दू की जीत का कारण उसका विमुक्ततावाद यानी हिन्दी शब्दों के बहिष्कार की प्रवृत्ति बताई गई है। जब उस विमुक्ततावाद को हिन्दी में लागू करने का हठ किया गया है। वास्तव में हार न हिन्दी रही है, न उर्दू, हार रहे हैं दोनों तरफ के विमुक्ततावादी जो दोनों की बोलचाल के अस्सी फीसदी शब्दों के आधार पर नज़दीक आते देखकर हाथ हाथ करके छाती पीट रहे हैं। उनका यह काम उचित भी है क्योंकि दोनों के पास आने को वे बिसकुल नहीं रोक पाते। लेखक ने कई जगह ऐसे शब्दों की सूची बनाई है जिन्हें वह हिन्दी से निवाल देना चाहता है। पृ० २२-२३ पर ऐसे शब्दों की सूची देखने लायक है। इसमें तलाश, मूराख, बजन, शोरगुल, पैदावार, दाग, दर्द, रोशनी, हजम करना, सख्त, नज़दीक, मेहमान, कमरबन्द, बीबी, दिल, बिताब, अन्दर, तरफ, इन्कार,

खरीदना, आवाज देना, खून जैसे शब्द हैं जिन्हें हिन्दू संस्कृति के लिए घातक बताया गया है। पाठक स्वयं सोचें कि हिन्दी भाषा को इन शब्दों से छतरा है या रविशंकर शुक्ल जैसे उसके समर्थकों से।

इन शब्दों के हिन्दी पर्यायवाची तो और भी मनोहर हैं ! जिताब के लिए केवल 'पोथी' लिखना चाहिए और बीबी के लिए 'बहू' ।

हिन्दीवालों को सावधान करनेवाले इन सज्जन से अगर कोई पूछे कि क्या आपने यह 'पोथी' अभीम खाकर लिखी थी तो कोई बेजा सवाल न होगा। ऐसे एक-दो नहीं पचीसो शब्द हैं जिन्हें आपने हिन्दी से निकालने की सलाह दी है लेकिन जो दूसरी जगह आपके 'लैंग्वेज कान्सेप्ट' दिमाग पर भी सवार हो गए हैं। मिसाल के लिए पृ० ३३ पर आप 'किसा' शब्द निकाल देने की सलाह देते हैं लेकिन पृ० १५६ पर हिन्दी शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए 'किने' की ही शरण ले बैठे हैं।

इसी सूची में आपने 'बच्चा' शब्द भी रखा है जिसे हिन्दी से आप विदेशी समझकर निकालना चाहते हैं। पाठकों को ऐसी अपार भूलतता पर विश्वास न हो तो इस पुस्तक के पृ० ३४ की दूसरी लाइन देख लें। लेकिन बाहू रे बच्चो, बाबाय ! पृ० १७६ पर जब लेखक महाशय हिन्दी रखा सघ स्थापित करने में लगे थे, तभी आठवी पंक्ति में तुम भी आ कूदे ('हिन्दी जनता में प्रबल आन्दोलन किया जाय कि वह अपने बच्चों को... ' इत्यादि)। इसी तरह 'आबादी' का आप विरोध करते हैं लेकिन पृ० २५ पर अवध को 'आबाद' करते हैं। आदत आपके पसन्द नहीं लेकिन पृ० २७ पर आप खुद उसके 'आदी' दिखाई देते हैं। जादू वह जो सिर पर चढ़कर खोने और वह आपके ही नहीं, हिन्दी-उर्दू दोनों के विशुद्धतावादियों के सिर पर चढ़कर बोलता है। जितना ही बोलचाल के शब्दों से पर भाड़ते हैं, उतना ही वे चिपकते जाते हैं।

पृ० ४०-४१ पर एक दूसरी सूची है, उन शब्दों की जो बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं। इनमें बगावन, कुर्बानी, गद्दार, हिमायत, उस्ताद, हमदर्दी, नाराज, नासुश, सर्दी जैसे शब्द भी हैं। पूछना चाहिए कि आप किस देश के रहने-वाने हैं जो इन शब्दों को बोलचाल का नहीं समझते। आपका दुराग्रह कितना बड़ा हुआ है, यह इस बात में जाहिर है कि आपने 'देशदूत' जैसे पत्र और वेदव बनारसी जैसे लेखक को भी—जिन पर हिन्दी उर्दू के मामले में उदार होने का कलक कभी नहीं लगाया जा सकता—उर्दू परस्तों की पांति में बिठा दिया है।

आप पर प्रतिक्रियावादी होने का आरोप लगाया जायगा, यह आप पहले से ही जानते हैं। इसलिए पृ० ८३ पर आपने गर्व से घोषणा की है—'हमें एक बार नहीं सौ बार प्रतिक्रियावादी कहलाना स्वीकार है।' उसके बाद यह भी मुक्तकठ से स्वीकार किया है कि 'ये सब बातें पुनरुत्थान की भावना से प्रेरित हैं।' (उप०) बोलचाल के शब्दों के आने से आप भाषा का कृत्रिम मानते हैं, अधिक संस्कृतनिष्ठ होने से हिन्दी स्वाभाविक हो जायगी। (पृ० ८८-८९)

एक सुभाव मार्क का है। अगले प्रांतीय चुनाव के लिए हिन्दी जनता को अभी से तैयार करना चाहिए। (पृ० १७६)। राष्ट्रवादी मुसलमानों और बाग्रेम के नेताओं पर यह विपक्षजन उस चुनाव की तैयारी का ही एक अंग है। ऐम लोगो की कमी नहीं है जो देश को जनतन्त्र की तरफ बढ़ने से रोककर साम्राज्यवाद की पाली-पोसी हुई व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं। इनके प्रचार में एक ऐसी हिन्दी की स्थान दिया गया है जिसका भारत की जनता से यथा-सम्भव कम सम्बन्ध है। जितना सम्बन्ध हिन्दू राष्ट्रवाद का हिन्दू जनता से है, उतना ही हिन्दी के इन समर्थकों का हिन्दी से है। कलम पकड़ते चार दिन नहीं हुए कि तुलसीदास, भारतन्दु और प्रेमचन्द—सभी की परम्पराएँ उलटने को तैयार है। मानो ईश्वर के यहाँ से हिन्दी की जायदाद का बँनामा कराके लौटे है। हिन्दी के उस एक बड़े लेखक का नाम बताइए जिसने इन सिद्धान्तों को मानकर रचना की हो। भाषा के निर्माता कुछ अन्धे प्रतिक्रियावादी नहीं हो सकते। उनके निर्माता हिन्दुस्तान के करोड़ों किसान, मजदूर और साधारण लोग हैं जिनकी बोलचाल की भाषा से आपको असली खतरा दिखाई देता है। हिन्दी बोलनेवालों ने जिन शब्दों को अपना लिया है, उन्हें तमाम मुसलमानों को कल करके भी हिन्दी से नहीं निकाला जा सकता। यह सस्कृति की राम-दुहाई जनता के मन से उत्पन्न हुई है क्योंकि एक बार अंग्रेजी से टक्कर लेने के बाद यह जनता उनके देसी नक्कासों से डरकर चुप रहनेवाली नहीं है। जिस समय हिन्दी-उर्दू के कथित हिमायती एक-दूसरे को कोसते रहे हैं, उस समय यही जनता खेतों, जलिहानों और नारखानों में एक मिली जुली भाषा गढ़ती रही है जिसकी उपेक्षा करना दोनों में से किसी के लिए भी सम्भव नहीं है। हिन्दी घमर है, इसलिए कि वह अपनी स्वाधीनता के लिए लड़नेवाली जनता की सजीव भाषा है।

(१९४८)

हिन्दी का 'संस्कृतीकरण'

बहुत से लोगो का विचार है कि संस्कृत ने मृत भाषा का रूप इसलिए ले लिया कि पंडिता ने उसे व्याकरण के नियमों से जकड़ दिया था। परन्तु व्याकरण और भाषा की सजीवता में कोई ऐसा अन्तर्विरोध नहीं दिखाई देता कि संस्कृत की मृत्यु के लिए व्याकरण की दोषी ठहराया जाए। अगर आज की जीवित भाषाओं को लें तो देखेंगे कि वे व्याकरण से कम अनुशासित नहीं हैं और किसी हद तक तो उनके व्याकरण में ऐसी विरोधताएँ मौजूद हैं जो सर्वसुद्धि को स्वीकार ही नहीं होतीं। कौन नहीं जानता कि अंग्रेजी-व्याकरण बारह साल पढ़ने के बाद भी भाषा में अशुद्धियाँ रह जाना एक साधारण बात है। फिर भी अंग्रेजी ससार की सबसे सजीव भाषाओं में है। संस्कृत की अपेक्षा उसमें स्वच्छन्दता यही कम है। संस्कृत वाक्य-रचना में आप शब्दों का हेर-फेर कर सकते हैं—'एतद् मम पुस्तकम्' को मम, पुस्तकम्, एतद् किसी भी शब्द से प्रारम्भ करके लिख सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी में 'दिस इज माई बुक' को 'इज दिस माई बुक' लिखकर देखिये, कितना अन्तर हो जाता है। और कही बुक माई इज दिस' लिख दीजिये, तब तो वाक्य का कचूमर ही निकल जायगा। छोटे बच्चे अंग्रेजी सीखते हुए अक्सर इस तरह की वाक्य-रचना करते हैं। और बच्चे ही क्या, बालिका भी हिन्दी से अंग्रेजी शुरू करते हैं, तो प्रारम्भ में यही गलती करते हैं। अगर कोई समझे कि 'राम रामी रामा' की रटन्त से अंग्रेजी ही अच्छी तो उसे हिन्दी के 'राम से, राम में, राम पर' आदि रूप याद रखने चाहिए और बिहारी भाइयों की 'ने' सम्बन्धी कठिनाई को न भूल जाना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों से सरल है और इसलिए उसे राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए। ऊपर की बातें कहने का उद्देश्य यह है कि संस्कृत के मृत भाषा बनने का कारण व्याकरण नहीं कुछ और है। दरअसल संस्कृत कुछ गिने-चुने शिक्षितों की भाषा रह गई थी और लोक-प्रचलित भाषा से इतनी दूर चली गई थी कि आम जनता के लिए वह दुर्लभ हो गई थी। उसका व्याकरण कितना भी सरल किया जाता, वह 'जीवित'

भाषा का पद न पा सकती थी। अक्सर अनेक ग्राम-भाषाओं का व्याकरण संस्कृत से कम कठिन नहीं होता, बल्कि उससे भी अधिक गहन और विस्तृत होता है, फिर भी ग्रामीण बच्चे बिना सूत्र घोड़े हुए ही व्याकरण के अनुसार नित्य वाक्यरचना करते रहते हैं। फ्रांस और स्पेन के कुछ भागों में 'वास्क' नाम की ऐसी बोली आज भी प्रचलित है। उसका व्याकरण लैटिन से भी कुछ बनया जाता है लेकिन लैटिन संस्कृत के पद को प्राप्त हुई और वास्क प्रब भी जीवित है। वास्क के लिए एक कहानी प्रचलित है कि मुदा ने शंतान पर पका होकर उसे वास्क-व्याकरण याद करने के लिए भेजा। सात साल तक परिश्रम करने के बाद भी शंतान कोरा-का-कोरा ही वापस लौटा।

व्याकरण की कठिनाई नहीं भाषा सीखनेवालों को महसूस होती है। जो उसे नित्य-प्रति बोलत हैं, उनके लिए व्याकरण 'सीखने' का प्रश्न नहीं उठता। इसी प्रकार बोश देखकर भी कोई हिन्दी, उर्दू या हिन्दुस्तानी में बातें नहीं करता। काफी दिन तक बोश-निर्माण में परिश्रम करने के बाद अधिकांश लोग यह समझ गये हैं कि हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी की समस्या का चाहे जो हल हो, वह कम से-कम बोश-निर्माण से हल नहीं हो सकती।

लेकिन बोशकार भला यह सब माननेवाले हैं। उनके लिए धमर-कोश पहले है, कालिदास बाद का। उनके लिए धमर-कोश उनकी बोश रचना पहले है। उनका क्या बोनेगी, वैज्ञानिक, डाक्टर, वकील, राजनीतिक नेता, आदि-आदि किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, इस प्रदेश से दुबले बोशकार मोटे-मोटे बोना का निर्माण करने में लगे हैं। बोश-रचना में ऐसे शब्द नहीं रखे जाते जो व्यवहार में आते हैं बल्कि ऐसे शब्द गढ़कर रखे जाते हैं जो व्यवहार में लाय जायेंगे। अगर 'जनता' की समझ और व्यवहार का निवाल बाहर किया जाता है और कोशकार दत्तचित्त होकर फिर अपने शब्द-निर्माण में लग जाते हैं।

छोटे से बड़े तक अनेक पंडित-महापंडित कई वर्षों से इस कार्य में लगे हैं। हिन्दी में लगे हैं और उर्दू में लगे हैं और इनके साथ बंगला जैसी अन्य भाषाओं में भी लगे हैं। इस हिसाब से हम इसे 'भारतीय साहित्य का बोश-युग' कह सकते हैं।

बोशकार अपने निर्दोष कार्य में लगे रहते और उनके एवान्त चिन्तन में बाधा देने की कोई जरूरत नहीं अगर उनकी बोश-रचना आम जनता पर लादी जाने की नहीं होती। जब उनके इस कार्य को सरकारी या अर्द्ध-सरकारी सरक्षण मिल जाता है, तब यह सतरा पंदा हा जाता है कि कचहरी डाकखान में हमें ऐसे वागज-गत्र पढ़ने की मिलेंगे जिन्हें समझने के लिए भारी-भरकम वाक्य साथ लेकर चलना पड़ेगा।

बल्कि बोश, एक 'अपसंज्ञित' ध्वनित अपने 'अपसंज्ञक' पर अभिप्राय

लेगाता है और 'अपसर्जन' का मित्र 'अपचय' करता है। आप भदासत में 'प्रत्याख्यान' करते हैं। वकील 'अख्यय' की अभ्युक्ति करता है। इतने ही में एक 'अपनयन' का मुरदमा और पेन होता है लेकिन मुकदमे का 'लम्बन' हो जाता है या वह 'विवृष्ट' हो जाता है। आपका 'अभिवर्त्ता' 'अपय-पत्रक' देता है जिसमें फिर 'अप्ययन विवरण' होता है। इसके बाद 'पुनर्वाद के अख्यय' की नीयत प्राप्ति है और तब 'अपचारक' से कहा जाता है कि 'इस बाद का अप्यय बाद के परिणाम का अनुसरण करेगा।'

यदि आप हिन्दी-प्रेमी हैं, तो इन शब्दों पर कुछ देर तब विचार कीजिए। यदि अंग्रेजी और हिन्दी पर्यायवाची शब्दों के बिना आप इनका मतलब समझ लेंगे तो 'बीर सराही तोहि' हमें कहना पड़ेगा। ऊपर के शब्द उस बोझ में लिये गये हैं जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार और टिहरी राज्य की सहायता से नागरी प्रचारिणी सभा तैयार कर रही है। बानगी के तीर पर कुछ शब्द २ जून, १९४८ की 'अमृत बाजार पत्रिका' में छपे हैं। यदि नागरी-प्रचारिणी सभा ऐसी ही हिन्दी का प्रचार करना चाहती है तो उसे लोगों की धोखे में न डालकर अपना नाम बदल डालना चाहिए।

इसमें शक्य है कि ये शब्द संस्कृत में भी उसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं जो कोशकारी की अंग्रेजी के आधार पर अभीष्ट हैं। यह संस्कृत और हिन्दी दोनों के माय अन्वय है। इस तरह की भाषा को यू० पी० सरकार, टिहरी राज्य और नागरी-प्रचारिणी सभा तीनों मिलकर और उन-जैसे दस पाँच नहीं चला सकते, क्योंकि ये शब्द जनता के गले से उतरेंगे नहीं। कोशकार भले ही आज जनता को अशिक्षित कहकर उसकी बोलचाल की भाषा की उपेक्षा करें, लेकिन यह कोश-भाषा भाषांतर बुलवाना तो उसी जनता से है!

हिन्दी के इस 'संस्कृतीकरण' से हिन्दी का राष्ट्रभाषा बनना तो दूर, उसका प्रान्तीय भाषा के रूप में भी लोकप्रिय रहना कठिन हो जाएगा। यह हिन्दी की मजा करना नहीं, उसका गला घोटना है। हर हिन्दी-प्रेमी को इसका विरोध करना चाहिए।

यह बात नहीं है कि संस्कृत से शब्द लेना एकदम बन्द कर देना चाहिए। लेकिन शब्द लेना एक बात है, भाषा को संस्कृतमय बना देना दूसरी बात। इन कोशकारी की नज़र में हिन्दी का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। उसमें जो कुछ है और होना चाहिए, वह केवल संस्कृत का! इनके लिए मध्यकाल से लेकर अब तक केवल सांस्कृतिक पतन ही होता आया है और जितनी जल्दी सप्तपुत्र की ओर लौट चलें, उतना ही अच्छा। यह हठधर्म कुछ नया नहीं है। जब गोस्वामी तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' रचा था और पंडितगण उनकी रचना को 'भदेस' कहकर हँसते थे, तब से यह क्रम चला आ रहा है। यूरोप में इस प्रकार लैटिन के आगे 'क्लर टर्ग' का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन वही 'भदेस' भाषाई समार की सबसे समृद्ध भाषाएँ बन गईं। वह पद हिन्दी भी प्राप्त

करेगी, लेकिन बोल-रचना और संस्कृतीकरण के रास्ते पर चलकर नहीं।
ऊपर की बोल-रचना निमित्त शब्दावली सरल शब्दों में भी लिखी जा सकती है।
लेकिन बोल-प्रेमियों का कहना है कि सरल शब्दावली पारिभाषिक कहाँ हुई !
इस तरह हिन्दी को इतना पारिभाषिक बनाया जाएगा कि वह 'भाषा' न रहकर
बेवल 'परिभाषा' रह जाएगी !

हैदराबाद के स्वनामधन्य निजाम साहब उर्दू के लिए ऐसे ही बोल बनवा
चुने हैं। उनसे उर्दू कितनी लोकप्रिय हुई है, इस बात पर हिन्दी-प्रेमियों को
विचार करना चाहिए।

'सारे देश में समझी जाए'—इस बहाने हर भाषा के बटमुल्ले अपनी भाषा
को जान लेने पर तुले हुए हैं।

पश्चिमी बंगाल की अत्यन्त प्रगतिशील सरकार के 'स्वायत्त विभाग' ने
गरपारी कामों के लिए 'व्यवहार्य परिभाषा' का पहला भाग प्रकाशित किया
है। सरकार की तरफ से छपी हुई चीज है, इसलिए उसमें गुप्तताचीनी की
गुजाहरी भी कम है। आप 'परिभाषा' का जो मतलब लगाते हो, बग सरकार
ने उसका अर्थ 'शब्दावली' लिया है, यह याद रखें।

इसके रचयिताओं में डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी का प्रसिद्ध नाम भी है।
भूमिका में बताया गया है कि 'हिस्साब' शब्द प्रचलित होते हुए भी उसकी जगह
गणन' और 'गणन' से 'गणनिक' और 'महागणनिक' शब्द रहे गये हैं। रवीन्द्र-
नाथ के बंगाल में यह सलित पदावली रची जा रही है। इसी प्रकार 'प्रदालत'
शब्द काफी सम्मानपूर्ण नहीं, 'not dignified enough' समझा गया है। इस-
लिए उसकी जगह 'धर्माधिकरण' सजाया गया है, जिसका नाम सुनते ही
मपर्यायियों के छक्के छूट जाएँ।

भूमिका में भाषा विज्ञान की यह अपूर्व बात भी कही गई है—'Bengali,
Hindi, Marathi and the rest now depend upon Sanskrit—they
are not free to utilise their own basic elements' यानी बँगला,
हिन्दी, मराठी वगैरह को खुद अपने भीतर से शब्द निर्माण करने की छूट नहीं
है। उन्हें संस्कृत का ही मुँह जाहना पड़ेगा।

हिन्दुस्तान में भाषा विज्ञान में कितनी प्रगति की है, यह ऊपर के इस एक
वाक्य से प्रकट है, जिस पर डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी के हस्ताक्षर हैं।

नागरी प्रचारिणी के कासकारों की सेवा में हम इस बर्गीय 'परिभाषा' का
कुछ शब्द पेश करत हैं। आप लोग अलग-अलग न जाने क्यों परिश्रम कर रहे हैं,
हिन्दी बँगला जब दोनों सस्तर से लेती है, तब उनमें भेद कहाँ रहा ? घाटे के
हिन्दी-बँगला का ही मुँह जाहना पड़ेगा।
शब्द-कोष पर हिन्दी, बँगला लिखकर क्यों नहीं बानू कर देते ? बानगी दक्षिण
न्यासपाल, महा व्यावहारिक (सज्ञा है, विशेषण न समझ लीजिएगा !),
स्थपति, भाविनार, कृषी धावक (यह बातल घोनेवाला है !), आत्ययिक,
चक्रचर नियामक, दोहवर्धन आधिकारिक (बेरी से सम्बन्ध है), दुष्कृति विमर्श

हिन्दी का संस्कृतीकरण /

विभाग, उप-आयुक्तक, उप-प्रादेशिक परिवहन महाध्यक्ष, उप-भारतयाध्यक्ष, एप-अधिकर्ता, साहित्य-उपदेष्टा, धूमोत्पात परिदसंब, साधित्र रक्षक, लेख्य-प्रापक, राजस्व-करणिक, विक्रयिक, विनिष्ट-मुद्रितक-उपदेष्टा, परियाण-करणिक अवर, अन्त शुक्ल श्रुत्यक, शिल्प व मभरण मन्त्रक, राष्ट्रमृत्यातियोगाधिकार, कन्या प्रणिधि, तूर्ण पत्र (एक्सप्रेस बिट्ठी) इत्यादि ।

इस शब्दावली के निर्माता जानते हैं कि उसे बंगाल में कोई न समझेगा । इसलिए जीववानों को आदेश दिया गया है कि जितना समय अंग्रेजी सीखने में लगाते हों, उसका चौथाई भी मातृभाषा (यानी संस्कृत) सीखने में लगायें तो वे अपरिचित शब्द उतने अपरिचित न रह आएंगे ।

इतने बोशकारों के लिए सबसे अच्छी मजा यही है कि इनसे इन्हीं के बनाये हुए कोश याद कराये जाएँ । जहाँ भूमें वहाँ फिर याद करने की ताकीद कर दी जाय । जब हिन्दी, बंगला आदि के बोशकार अपने अपने कोश या सम्मिलित महाकोश याद कर आलें तभी वह कोश जनता तक पहुँचे, उमके पहले नहीं ।

हिन्दी का संस्कृतीकरण पारिभाषिक शब्दों को लेकर ही नहीं है । साधारण साहित्य में, दैनिक और मासिक पत्रों आदि में भी तत्सम शब्दों को इसलिए भरा जाता है कि इससे हिन्दी सुबोध हो जाएगी—खुद हिन्दी बोलनेवालों के लिए नहीं बल्कि दूसरी भाषायों के बोलनेवालों के लिए । मिसाल के लिए, शायद बंगाल के लोग संस्कृत-बहुल हिन्दी को बोलचाल की खिचड़ी भाषा से ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे । देखना चाहिए कि बोलचाल की बंगला में तत्सम शब्दों का अनुपात कितना रहता है । इस पर डा० सुनीतिकुमार चटर्जी से ज्यादा कौन अधिकारी विद्वान राय दे सकता है ? बंगला भाषा की उत्पत्ति और विकास पर लिखे हुए अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ के पहले भाग में उन्होंने यह मत प्रकट किया है—

‘In Modern Bengali, the Colloquial has a surprisingly small ‘percentage of Sanskrit words’ (The Origin and Development of the Bengali Language, Vol 1, p 221) यानी बोलचाल की बंगला में संस्कृत शब्दों की तादाद असाधारण रूप से कम है ।

हिन्दी पाठक इस वाक्य पर कुछ देर तक विचार करें । जिन ग्रन्थ भाषा-भाषियों की दुहाई देकर हिन्दी को बिगाड़कर उसे संस्कृतमयी बनाया जा रहा है, वे स्वयं बंगाल जैसे प्रान्त में भी संस्कृत शब्दों का कम-से-कम प्रयोग करते हैं ।

पारिभाषिक शब्दों की समस्या बोलचाल की भाषा के नियमों को तोड़कर हल नहीं की जा सकती । बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी और फारसी के शब्द भी आते हैं और संस्कृत से भी आते हैं । लेकिन धार्य संस्कृति के जोन में शुद्धतावादी केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों को लेने पर तुले हुए हैं । वे यह भूल जाते हैं कि स्वयं संस्कृत दूसरी भाषायों से शब्द लेकर समृद्ध होती रही थी ।

इस बात को सुनीति बाबू भी मानते हैं। उपर्युक्त पुस्तक में लिखा है—“The Aryan speech has been borrowing words from the Dravidian ever since the former came to India”—(Ib, p. 178) अर्थात् “आर्यों की भाषा हिन्दुस्तान में आने के बाद से ही द्रविड भाषाओं से बग़र बग़र उधार लेती रही है।” लेकिन ‘देववाणी’ भन्ने शब्द लेती रही हो, देववाणी के बग़र ज़मीन समर्थक जोरो से हृदय-वपाट बन्द नये हैं कि वही विदेशी हवा लगने से उनका देवत्व मरित न हो जाय।

अगर कोई कहे कि इरम टैकम इन्फेक्टर, वारट, वर्रेमी, गात्रियन, रिपोर्ट, रिमीवर, ममन, सब-जज आदि अंग्रेज़ी के प्रचलित शब्दों को ग्रहण कर लेना चाश्चि और उनही जगह नये शब्द न करने चाश्चि तो यह राष्ट्रभाषा के प्रति झोट कहा जाएगा। लेकिन इन्हीं शब्दों को सुनीति बाबू ने अपनी पुस्तक में ‘typical naturalised English Words’ (पृ० ६४५-६८) कहा है। ये शब्द बँगला के अपने शब्द मान लिये गए हैं और यही नहीं, इनके साथ लज्ज-बीनन, वेटिंग-रम, पॉसिल, गिरीमेंट (ग्रीमेंट), नोटिंग, बर्ज़ाइस (बुर्ज़ुआ), मरगिज, रजिस्ट्री, निवर, हाफ साइड आदि शब्द भी बँगला की स्वीकृत सम्पत्ति माने गये हैं। लेकिन बँगला की ‘व्यवहार्य परिभाषा’ उठाकर देखिए तो इन्हीं शब्दों या इन जैसों के बदले हा० सुनीतिगुमार और उनके सहयोगी नये-नये भारी भरकम शब्द गढ़ते दिखाई देंगे और उनसे सहायियों की सम्झ में न आने पर उनसे कहेंगे कि अपनी मातृभाषा सीखने में कुछ समय लगाओ।

इसी तरह अपनी पुस्तक के पृ० २१७ (खंड १) पर उन्होंने बेंलेट, सेन्टरी, प्रिटर, गजट, टाइमटेबल, रोमास, रोमाटिक, बलासिक, ट्रेजिक, पॉमिन, फाट, पयूचरिजम, साइस, प्रोटोप्लाजम, प्लोस्टोसीन, लॉ, प्लॉट, कैमिस्ट्री, फिजिक्स आदि शब्दों के लिए लिखा है कि वे ‘are being bodily adopted at the present day,’ यानी वे जैसे-जैसे तैसे बँगला में अवतार ले रहे हैं। लेकिन मजाल क्या कि वही सुनीति बाबू अब इनके लिए ससृष्ट की किसी धातु से नया शब्द न गढ़ लें।

अपनी पुस्तक के पृ० २१२ (खंड १) पर उन्होंने यह भी लिखा था कि बँगला के मुसलमान लेखक ज्यादा सरवा में आगे आ रहे हैं, इसलिए फारसी, फ़ारसी के शब्दों का बँगला में आना बिल्कुल स्वाभाविक होगा (‘will be in the nature of things’) लेकिन ‘व्यवहार्य परिभाषा’ में इन स्वाभाविक रूप से आये हुए शब्दों को ढूँढ़ने के लिए अब आपकी खुदबीन की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह पूँजीवादी नेता चुनाव में लिये हुए वादों की जरूरत पड़ेगी। मूल जाते हैं, वैसे ही ‘रिवाइलरिजम’ के जोश में (‘आर्य सस्कृति के मोह में’) सुनीति बाबू जैसे भाषा वैज्ञानिक खुद अपने बनाये हुए सिद्धान्तों को मूल गए हैं। यह पूँजीवादी संस्कृति के हास का चिह्न है, उसने उत्थान का नहीं। यह रास्ता बँगला और हिन्दी की उन्नति नहीं, उनकी अवनति का है। (१९४८)

उर्दू-साहित्य की सांस्कृतिक परम्परा

हिन्दी उर्दू की समस्या का एक पटलू उनके साहित्य की परम्परा का भी है। हिन्दी और उर्दू एक भाषा हैं, या एक भाषा की दो शैलियाँ हैं वे आगे चलकर मिलेंगी या उनमें से एक ही रह जाएगी आदि मसला को पेश करते हुए और उनका हल खोजते हुए इन दोनों की सांस्कृतिक परम्परा का सवाल भी उठाया जाता है।

उर्दू की साहित्यिक और सांस्कृतिक परम्परा क्या है ? यह परम्परा हिन्दी की साहित्यिक और सांस्कृतिक परम्परा से कहाँ तक असंग है ? क्या दोनों की कोई सामान्य परम्परा भी है जिसे आगे विकसित किया जा सकता है ?

इन प्रश्नों का जवाब देने से हिन्दी उर्दू की समस्या को सही तौर से पेश करने और उसे हल करने में सहायता मिलेगी।

१

उर्दू की सांस्कृतिक परम्परा के बारे में एक मत यह है कि वह विदेशी है, उसी की यजह से देश के बँटवारे की नौबत आई (या वह परम्परा भी बँटवारे का एक कारण है), इस परम्परा से हिन्दी का कोई समझौता नहीं हो सकता और दरअसल उस परम्परा को, चूँकि वह राष्ट्रघोषी है जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए।

इस मत को हिन्दी साहित्य सम्मेलन के नये सभापति सेठ गोविन्ददास ने बड़ी धूमधाम से पेश किया है। इसी मत को श्री राहुल साहूत्यामन, श्री सम्पूर्णानन्द, श्री गुरुपोत्तमदास टडन आदि सज्जन भी पेश कर चुके हैं। सेठ गोविन्ददास ने उस पेश करने में धूमधाम के अलावा किसी मौनिकता का खिस्पा नहीं दिया। इसलिए यहाँ पर श्री गुरुपोत्तमदास टडन के शब्दों को उद्धृत करना ज्यादा अच्छा होगा। टडनजी सम्मेलन के प्राण हैं। सम्मेलन के सालाना सभापति जो मत प्रबल करते हैं उनमें इन प्राणों की ध्वनि ही गूँजती रहती है।

सम्मेलन के पैंतीसवें अधिवेशन में टडनजी ने उर्दू की सांस्कृतिक परम्परा

पर ये विचार प्रकट किये थे :

“उर्दू कवियों की जो कविताएँ हुईं, वे अरब और ईरान के सहजीव की प्रतीक थीं। उर्दू कविताएँ हमें अपने नगर, अपने देश, अपने गली-बूचों की ओर ले जाने के बजाय, ईरान और अरब के नगर तथा गली-बूचों की ओर ले जाती हैं। उसकी सांस्कृतिक परम्परा हमारे देश की, हमारी मिट्टी से निकली हुई जो सृष्टि है, उसके विपरीत है।

“उर्दू कवियों के रूपों में उर्दू कविता का सांस्कृतिक प्रयत्न स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उनकी कविताओं में यदि बीर की उपमा दी जाती है तो हस्तम, सोहराब, अफ़सियाब की याद किया जाता है, वही पर आपको भीम, भर्जुन, आदि की उपमा नहीं मिलेगी। नदी की उपमा जब आती है तो उन्हें अरब की, मेसोपोटामिया की और ईरान की नदियाँ याद आती हैं। पर्वत की याद होती है तो उन्हें ईरान के पहाड़ों की याद आती है, हिमालय पर्वत की याद नहीं आती। फलों में उनको ‘नगिस’ की याद आती है। पक्षियों में उनको बुलबुल दिखाई पड़ता है, अपने देश के जो सुन्दर और अच्छे पक्षी हैं, उनकी चर्चा नहीं करते। उनका यह प्रयत्न था कि सखनऊ की गलियाँ ‘अश्वी’ बन जाएँ। ‘अश्वी’ ईरान का एक नगर है। सहर जो कि सखनऊ का कवि था उसका एक गौर ‘फसाना भजायब’ में यह है—‘बुलबुले शीराज को है रसक नासिख का धुर। अश्वी इसने किये हैं, लखनऊ के कूचे और गलियाँ’। कहने का तात्पर्य यह है कि उर्दू का सांस्कृतिक क्रम पृथक्वाद है और उसका परिणाम यह हुआ है कि जैसे-जैसे उर्दू का विकास हुआ, वैसे-वैसे सांस्कृतिक पृथक्ता बढ़ती गई। जहाँ-जहाँ उर्दू का साम्राज्य था, वहाँ वहाँ पृथक्वाद का विशेष बल था, जैसे उत्तर-प्रदेश और पंजाब में।”

(हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, पैंतीसवें अधिवेशन का विवरण, प्रयाग, पृ० ७१-८०)

यह सब कहने का सीधा मतलब यह है कि उर्दू की सांस्कृतिक परम्परा अलग-अलग पैदा करती रही है, इसलिए उसे खत्म कर देना चाहिए। आगे जब टबन जी कहते हैं कि “मुझे उर्दू कविता अच्छी लगती है” तब उनसे पूछा जा सकता है कि इस राष्ट्र विरोधी कविता के अच्छा लगने का पाप आप जैसे विशुद्ध भारतीयता प्रेमी से कैसे हो गया? अगर उर्दू की सांस्कृतिक परम्परा हिन्दुओं और मुसलमानों में फूट डालती है तो इस बारे में दो मत नहीं हो सकते कि ऐसी परम्परा को खत्म कर देना चाहिए। ऐसी परम्परा तो फूटपरस्तों की ही अच्छी लग सकती है।

२

उर्दू साहित्य के इतिहास पर दृष्टि डालने से पहली चीज यह दिखाई देती है कि उर्दू की सांस्कृतिक परम्परा परिवर्तनशील रही है। जो परम्परा जोक या दाग की थी, वही परम्परा ज्यो-की-त्या जोश या क़ुशान चन्दर की नहीं हैं। हमें

देखना चाहिए कि यह परम्परा पहले क्या थी और उसमें कौन-कौन-सी खास तब्दीलियाँ हुई हैं ।

जिस तरह हम भारतेन्दु के पहले की हिन्दी कविता को मोटे तौर पर रीति-कालीन कविता कहते हैं, उसी तरह हाली के पहले की उर्दू कविता को मोटे तौर पर हम रीतिकालीन कविता कह सकते हैं ।

इस ज़माने की उर्दू कविता पर दरबारी मस्बूति की जबर्दस्त छाप है । उसके भावों और भाषा पर सामन्ती मस्कृति की छाप है । यह सामन्ती साहित्य में ईरानी साहित्य की परम्परा की अप्रगता थी । उसने ईरानी साहित्य में प्रचलित उपमाओं, रूपकों वगैरह को अपने साहित्य में सजाने की कोशिश की ।

हर देश के रीतिकालीन साहित्य में—उम समय के साहित्य में जब उद्योग-धन्यो के विकास में सामन्ती ढाँचा खत्म नहीं हुआ—बात कहने के ढंग पर ज्यादा जोर दिया जाता है, भावों और विचारों की मौलिकता पर कम जोर दिया जाता है । हिन्दी की रीतिकालीन कविता, विहारो और देव की रचनाओं में यह शैली हम देख सकते हैं । यही बात उर्दू की रीतिकालीन कविता पर भी लागू होती है ।

आगे चलकर रीतिकालीन परम्परा ज्यादा साथ नहीं देती । उसमें चाह भीम और अर्जुन का गुणगान हा, चाहे सोहराब और अफ़सियाब का, उस परम्परा से नाता तोड़ना ही होता है । हिन्दी की रीतिकालीन परम्परा में रामायण और महाभारत के वीरों की कमी नहीं थी, फिर भी खड़ी बोली के कवियों ने उस परम्परा का जोरों में विरोध किया और छायावादी कवियों ने उससे नाता तोड़कर एक नई परम्परा को जन्म दिया । उर्दू साहित्य में भी उसकी रीतिकालीन परम्परा एक निर्जीव परम्परा हो गई है । उर्दू-साहित्य उससे बहुत आगे बढ़ चुका है । रीतिकालीन परम्परा का विरोध करने और उससे नाता तोड़ने पर खुद उर्दू के लेखकों और कवियों ने ज़ार दिया है ।

जैसे हिन्दी में भारतेन्दु से पहले की सभी रीतिकालीन कविता ऐसी नहीं है, जिसे उठाकर रही की टोकरी में फेंक दिया जाय, उसी तरह उर्दू की रीतिकालीन कविताओं में बहुत-सा हिस्सा सांस्कृतिक परम्परा का अंग बनकर सुरक्षित रहेगा । उर्दू के बहुत-से पुराने कवियों की ऐसी संकड़ो पक्तियाँ हैं जो अपनी उक्ति चातुरी की वजह से बार-बार उद्धृत की जाती हैं और अब उन्होंने बोलचाल में कहावती की जगह ले ली है । मसलन—

बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का
जा चोरा तो इक कतरए खूँ न निक्ला ।

• • •

जमीनें चमन गुल खिलाती है क्या-क्या,
बदलता है रंग आस्माँ कैसे-कैसे ।

• • •

न जोरे सिकन्दर न है कग्र दारा,
मिटे नामियो के निर्शा कैसे-कैसे।

• • •
अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाँगे,
मर के भी चैन न पाया तो क्रियर जाएँगे।

• • •
हज़रते दाग जहाँ बँठ गये बँठ गये
और होंगे तेरी महफिन से उमरनेवाले।

इस तरह की पक्तियाँ बोलचाल में इस तरह आती हैं कि उन्ह हिन्दुस्तानी (खड़ी बोली) बोलनेवाली जनता की सांस्कृतिक परम्परा का एक भ्रग कहा जा सकता है।

हाली से पहले की उर्दू कविता की देन इतनी ही नहीं है। हाली से पहले भी बहुत-से कवियों ने रीतिकालीन परम्परा से बँधे न रहकर अपना नया रास्ता बनाया था। इन कवियों में गालिव का नाम सबसे पहले आता है जिनके व्यक्तित्व की छाप उनकी रचनाओं पर इस तरह पड़ी है जिस तरह अपने व्यक्तित्व की छाप डालना किसी भी रीतिकालीन कवि के लिए मुमकिन नहीं है। गालिव ने अपने जीवन के घारे में बड़े दर्द से लिखा है। इस तरह का दर्द दूसरी की रचनाओं की नकल करने से नहीं पैदा होता। इटली के महान् कवि दान्ते ने जिस तरह अपने जीवन की अपार वेदना अपने महाकाव्य में उडेल दी थी, उसी तरह गालिव के शेर उस जमाने के वातावरण के प्रति शोभ, ख्याति और वेदना में डूबे हुए हैं।

गालिव के जमाने में बहुत-से लोग इल्म की धायरी करते थे। वे फारसी साहित्य की उपमाएँ और रूपक लेकर अपनी रचनाओं को संवारने की कोशिश करते थे। इन सब में फारसी साहित्य से प्रभावित होते हुए भी गालिव एक महान् प्रतिभाशाली कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं।

गालिव की पच्चीसों पक्तियाँ साधारण बोलचाल में बराबर उद्धृत की जाती हैं। मिसाल के लिए—

• • •
हमको भालूम है जन्नन की हकीकत लेकिन,
दिल के खुश करने को गालिव य' खयाल अच्छा है।

• • •
उनको देखे से आ आ जाती है मुँह पर रीनक,
वो समझते हैं कि बीमार था हाल अच्छा है।

• • •
बर्ज की पीते थे मय लेकिन समझते थे कि हाँ,
रग लायेगी हमारी फाकामस्ती एक दिन।

रगो मे दीडने फिरने के हम नही कायल,
जो भाँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है ।

न था कुछ तो खुदा था कुछ न होता तो खुदा होता,
हुबोया मुझको होने ने न होता मैं ता क्या होता ।

मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि भासाँ हो गईं ।

ददं का हृद स गुजरना है दवा हो जाना ।

है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ,
बरना क्या बात कर नही आती ।

अनेक हिन्दी लेखकों की रचनाओं में गालिब के घेर उद्धृत किये जाते हैं । उम्रजी की शायद ही कोई पुस्तक, शायद ही कोई लेख हो जिममें गालिब के घेर उद्धृत न किये गये हों । निरालाजी ने जहाँ-तहाँ गालिब के घेर उद्धृत ही नहीं किये, उन पर 'प्रबन्ध पद्य' में लिखा भी है । गालिब की रचनाएँ किस तरह हिन्दी लेखकों की सांस्कृतिक परम्परा बन गई हैं, इसकी एक मिसाल निरालाजी के जीवन में मिलती है । निरालाजी को अपने जीवन में जो मुसीबतें उठानी पड़ी हैं, जो अपमान सहने पड़े हैं और जिस तरह विरोधियों के मुकाबले में अपने आत्मविश्वास को अडिग रखना पड़ा है, उससे गालिब की रचनाओं से उन्हें एक आन्तरिक सहानुभूति पैदा हो गई थी । मैंने उन्हें पचीसो बार इन पक्तियों को गाते सुना है और आखिरी बार अभी पिछले साल बनारस में जब वह काफी अस्वस्थ थे, उन्हें फिर गालिब के घेर गुनगुनाते सुनकर काफी ताज्जुब भी हुआ कि इनके मन की दुनिया में और बहुत-से उलटफेर हुए, लेकिन गालिब, रवीन्द्रनाथ और तुलसीदास—ये तीन महाकवि अपनी जगह अब भी कायम हैं ।

रहिये अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो,
हमसखुन कोई न हो और हमजवाँ कोई न हो ।
वेदरो दीवार-सा इक धर बनाना चाहिए,
कोई हमसाया न हो और पासवाँ कोई न हो ।
पड़िये गर बीमार तो कोई न हो तीमारदार
और अगर मर जाइये तो नौहरवाँ कोई न हो ।

जब श्री पुरपोषमदास टंडन जर्दू की सांस्कृतिक परम्परा को विदेशी और राष्ट्र-विरोधी कहकर उस पर हमला करते हैं, तब हम यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि हिन्दी की सांस्कृतिक परम्परा को 'निराला' की देन महान् है या श्री टंडन की । निराला की देन महान् है और इसीलिए महान् है

कि उनके हृदय में वह सकीर्ण साम्प्रदायिकता नहीं थी जिसका परिचय श्री टडन ने बार बार दिया है। सकीर्ण हृदय से महान् सांस्कृतिक परम्परा का कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता।

मालिव के बाद पुरानी उर्दू कविता में दूसरे महान् रचनाकार मीर हैं। मीर की बहुत सी रचनाओं में ऐतिहासिक परम्परा से साफ नाता टूटा हुआ दिखाई देता है। वीर सा ऐतिहासिक कवि अपने घर का इस यथार्थ ढंग से विर्णन करेगा।—

लोनी लग लग के झड़ती है माटी,
माह क्या उम्र वेमजा काटी।
भाड़ बाँधा है मेह ने दिन रात,
घर की दीवारें हैंगी जैसे पात।
घाउ में काँपते हैं ओ थरथर,
उन पर रहा रखे कोई क्योकर।

मीर की भी अनेक पक्तियाँ कहावतों का दर्जा पा चुकी हैं, जैसे ये—

ग्राम से कुछ बुझा सा रहता है,
दिल हुआ है चिराग मुफलिस का।

हाली से पहले जिन लोगों ने ऐतिहासिक परम्परा से नाता तोड़ा, उनमें नजीर का नाम महत्वपूर्ण है। नजीर के काव्य में लोक-गीता, कहावतों और लोक-संस्कृति की जो स्थान दिया गया है उससे आज भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नजीर जनता के कवि थे। इन्होंने ग्राम जनता की जिन्दगी के बारे में घड़ी सजीव रचनाएँ की हैं। इनकी भाषा के बारे में श्री अजरतनदास ने लिखा है

‘इनकी भाषा दली थी और उसे विलायती बनाने का कभी इन्होंने प्रयत्न नहीं किया। इनका चलती भाषा पर पूरा अधिकार था और फारसी तथा अरबी के कोशों से चुन चुनकर अपनी भाषा को सद्गु बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसा विषय चुना, वैसी ही भाषा ली और वैसे ही वास्तविकता से उसका चित्रण भी कर डाला।

(उर्दू साहित्य का इतिहास, बनारस, स० १९६१, पृ० १५२)

नजीर की बहुत सी रचनाओं पर सूफीपन का रंग है। दरअसल उनकी कविता की जड़ें उस जमाने के समाज में दूर तक खली गई थी। वह आदर्शवादी कवियों की तरह गरीबी का गुणगान नहीं करते बल्कि इन्सान की वे सुसीखें बयान करते हैं जो गरीबी के सबब से उस पर आती हैं। लिखा है—

जब आदमी के हाल पर आती है मुफलिसी,
बिस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी
प्यासा तमाम रोज बिठाती है मुफलिसी

उर्दू साहित्य की सांस्कृतिक

भूला तमाम रात सुलाती है मुफलिसी,
ये दुख वो जाने जिस पे कि आती है मुफलिसी ।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में देश के अन्दर नई राष्ट्रीय चेतना विकसित होने लगी । हिन्दी-साहित्य में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने किस तरह देशभक्तिपूर्ण कविताओं की परम्परा चलाई, इसे सभी लोग जानते हैं । उस समय की राष्ट्रीय चेतना पर पुनस्त्यानवाद का भी रंग चढ़ा हुआ था । भारतेन्दु बाबू ने धर्म जाति के प्राचीन गौरव के गीत गाये । हाली ने मुसलमानों के बीते वैभव के स्वप्न देखे । फिर भी हाली और भारतेन्दु—दोनों ने ही यह अनुभव कर लिया था कि देश की उन्नति हिन्दू-मुसलमानों के मेल से और उनकी मिली-जुली राष्ट्रीय चेतना से ही हो सकती है । हाली ने देश पर लिखा था—

ऐ वतन ऐ मेरे बहिष्ते बरी
बया हुए तेरे आसमाँ धी जमी
रात और दिन का वो समाँ न रहा
वो जमी और वो आसमाँ न रहा ।

हिन्दू मुस्लिम-एकता पर लिखा था—

तुम भ्रगर चाहत हो मुत्क की खैर,
न किसी हमवतन को समझो गैर ।
हो मुमल्गी इसमे या हिन्दू
बीड मजहब हो कि या ब्राह्मो,
सबको भीठी निगाह से देखो ।
समझो आँखो की पुतलियाँ सबको ।
हिन्द में इत्तफाक होता भ्रगर
साते गैरो की ठोकरें क्योंकर ?

प्राधुनिक हिन्दी साहित्य के आरम्भ-काल में जैसे सामाजिक कुरीतियों पर बहुत सी रचनाएँ की गईं, उसी तरह उर्दू-साहित्य में भी समाज-सुधार पर बहुत-सी चीजें लिखी गईं । बीसवीं सदी में आकर साहित्य का मतलब मुख्य रूप से कविता नहीं रहता; उसके दूसरे रूप कहानी, उपन्यास आलोचना वगैरह भी फलने-फूलने लगते हैं । इस नए जमाने का हिन्दी-उर्दू साहित्य और भी नजदीकी सांस्कृतिक परम्पराएँ बनाता हुआ चलता है ।

हिन्दी उपन्यासों में देवकीनन्दन खत्री के ऐयारी उपन्यासों के बाद हम प्रेमचन्द के सामाजिक समस्याओं वाले उपन्यासों तक पहुँचते हैं । उर्दू में प० रतननाथ सरनार के 'फिमान-ए-आजाद' में आगे बढ़ते हुए हम फिर प्रेमचन्द तक पहुँचते हैं । प्रेमचन्द ने उर्दू और हिन्दी में सामाजिक समस्याओं वाले उपन्यासों की नींव डाली । प्रेमचन्द ने हिन्दी-उर्दू की सांस्कृतिक परम्पराओं का मिलकर एक होना साहित्य की बड़ी महत्वपूर्ण घटना है । उससे जाहिर होता है कि सांस्कृतिक परम्परा की जड़ें सामन्ती साहित्य से क्यादा मौजूदा सामाजिक

जिन्दगी में धँसी होती है। प्रेमचन्द के जमाने में एक नई परम्परा गढ़ी जा रही थी जिसके तत्त्व इस्लाम या हिन्दू-धर्म से न लिये जाकर देश के सामाजिक और राजनीतिक आन्दोलनों से, समाज की नई प्रगति से, वहाँ के नये सम्बन्धों से लिये जा रहे थे। प्रेमचन्द ने हिन्दी और उर्दू में जो नई परम्परा डाली, वह गुणात्मक रूप से साहित्य की पुरानी परम्परा से भिन्न थी। वह दाग, जीव, बिहारी, पद्मावर की परम्परा से ही भिन्न न थी, वह हात्ती घोर भारतेन्दु की परम्परा से भी बाकी अलग थी। प्रेमचन्द साहित्य के विकास की वह मजिल से जो अपने में सुधारवादी राष्ट्रीयता अन्तर्भूत करने नये प्रगतिशील साहित्य की तरफ इशारा करती है।

प्रेमचन्द एक नई परम्परा को इसलिए जन्म दे सके कि हमारे समाज में नये परिवर्तन हो रहे थे, उसमें नई आसएँ, नये उद्देश्य लेकर नये आन्दोलन चल रहे थे।

हिन्दी-उर्दू साहित्य में प्रेमचन्द की परम्परा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सृष्टि रचने का काम मनुष्य का सामाजिक जीवन करता है। यह सामाजिक जीवन बदलता रहता है, इसलिए सृष्टि की धारा भी बदलती रहती है। सामाजिक जीवन के मुजावले में धर्म-सम्प्रदाय, मत मतान्तरों के संस्कार बहुत ही कमजोर साबित होते हैं, और सृष्टि पर उनका असर कम-से कम होता जाता है।

प्रेमचन्द खुद इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि सामन्त-मान की सांस्कृतिक परम्परा खत्म हो रही है और नये जमाने की एक नई परम्परा कायम हो रही है। वह जानते थे कि दोनों के उद्देश्य, दोनों के साहित्यिक रूप, दोनों के सौन्दर्य-सम्बन्धी मानदण्ड अलग-अलग हैं।

पुरानी साहित्यिक परम्परा के बारे में उन्होंने लिखा था—

“हमारे साहित्यकार कल्पना की एक सृष्टि खड़ी करके उसमें मनमाने तिलिम्म बाँधा करते थे। वही किसान-ए-अजायब की दास्तान थी, कहीं बीस्ताने खयाल की और कहीं चन्द्रकान्ता सन्तति की। इन आख्यानों का उद्देश्य केवल मनोरंजन था और हमारे भद्रमुत्त रस—प्रेम की तृप्ति...”

“क्या हिन्दी और क्या उर्दू—कविता में दोनों की एक ही हालत थी...ऐसे पतन के काल में लोग या तो धांसिकी करते हैं या अध्यात्म और वैराग्य में मन रमाते हैं।

“कला का नाम था और सब भी है, सङ्कुचित हृदय-युवा का, सद्द योजना का, भाव-निबन्धन का। उसने लिए कोई घादमं नही है, जीवन का कोई ऊँचा उद्देश्य नहीं है—भक्ति, वैराग्य, अध्यात्म और दुनिया से विनारावशी उसकी सबसे ऊँची रूपनाएँ हैं। हमारे उस कलाकार के विचार से जीवन का चरम सत्य वही है। उसकी दृष्टि अभी इतनी व्यापक नहीं कि जीवन-भ्रम में वह सौन्दर्य का परमोत्कर्ष देखे।”

(लखनऊ, प्रगतिशील लेखक सम्मेलन में समापति पद से दिये गये भाषण से)
 इस परम्परा को प्रेमचन्द खत्म कर रहे थे। उन्होंने माफ़ माँग की थी कि
 साहित्य के पुराने मानदण्डों को बदला जाय। उन्होंने कहा था—

“हमें सुन्दरता की कसीटी बदलनी होगी। अभी तक यह कसीटी धमीरो
 और बिनासिता के डग की थी। हमारा कलाकार धमीरों का पल्ला पकड़े रहना
 चाहता था— उसकी निगाह अन्त गुर और बँगलों की ओर उठती थी। भोपड़े
 और खंडहर उसके ध्यान के अधिकारी न थे। उन्हें वह मनुष्यता की परिधि
 के बाहर समझता था। कभी उनकी चर्चा करता भी था तो उनका मजाक
 उड़ाने के लिए।” (उप०)

प्रेमचन्द का हर शब्द उनके सच्चे जनवादी हृदय से निकला है, जो समाज
 के नये विकास के लिए, साहित्य की परम्परा बदलने के लिए जोर से ललकारता
 है।

“यदि साहित्य ने धमीरो के याचक बनने को जीवन का सहारा बना लिया हो,
 और उन भ्रान्दोलनों, हलचलों और क्रान्तियों से बेखबर हो जो समाज में हो
 रही हैं— अपनी ही दुनिया बनाकर उसमें रोता और हँसता हो तो इस दुनिया
 में उसके लिए जगह न होने में कोई अन्धाय नहीं है।” (उप०)

प्रेमचन्द के ये प्रभावशाली शब्द— उनके हृदय के ये सच्चे उद्गार— बतलाते
 हैं कि साहित्य की जो परम्परा धार्मिक अन्धविश्वासों, साम्प्रदायिक विद्वेष
 और भेदभाव, सामन्ती रुढ़ियों और प्राचीनतावाद को अपना आधार बनाती
 है, वह खत्म हो जाती है। साहित्य की वह परम्परा जो समाज के गतिशील
 जीवन को, उसके क्रान्तिकारी वर्ग को, जनता के सघर्ष को अपना आधार
 बनाती है, वह जीवित रहती है और वही परम्परा जीवित रह सकती है।
 प्रेमचन्द ने हिन्दी-उर्दू में इसी परम्परा को जन्म दिया था।

कुछ लोगों के मन में शका पैदा हो सकती है कि प्रेमचन्द ने तो यह सब
 काम हिन्दी में किया था, उसका जिक्र उर्दू साहित्य के सिलसिले में क्यों किया
 जा रहा है? ऐसे पाठकों की सेवा में प्रेमचन्द के ये शब्द अर्पित हैं—

“मेरा सारा जीवन उर्दू की सेवकाई करते गुजरा है और आज भी मैं
 जितनी उर्दू लिखता हूँ, उतनी हिन्दी नहीं लिखता।”

(प्रेमचन्द कुछ विचार, पृ० १६१)

हिन्दी-उर्दू के लिखनेवालों का सामाजिक वातावरण धाम तोर से एक-सा
 रहा है, इसलिए उनकी साहित्यिक परम्परा के उतार-चढ़ाव उसके मोड़ और
 नई दिशा में प्रवाह भी मिलते-जुलते रहे हैं। हिन्दी में ऐतिहासिक परम्परा
 का विरोध किया गया। उर्दू में भी उस परम्परा का विरोध किया गया। हिन्दी
 में राष्ट्रीय कविता का युग आया, चक्कस्त और इकबाल यह युग उर्दू कविता
 में भी लाये।

हिन्दी-कविता में छायावाद के नाम से नई रोगाटिक कविता का युग

भाया। इस तरह की रोमांटिक कविता का युग उर्दू में भी था।

मुन्जहार में कोयल की गदा गूँज रही है,
बोहसार में पुरखोर हवा गूँज रही है,
कुनबुल में जुनूखेज फजा गूँज रही है,
मैदान में घनघार घटा गूँज रही है,
बरसात है, बरसात है, बरसात है,
बरसात !

छायावादो कविता के उत्तरकान में जैसे हिन्दी में कुछ कवियों ने निराशा
ऊँच और प्रवेलेपन के गीत गाये, वैसे ही उर्दू में—

राह की रात और मैं नाशाद ओ नाशारा फिर्ह,
जगमगासी जागती सड़कों पे आबारा फिर्ह,
गैर की बस्ती है बब तक दरबदर मारा फिर्ह,
ऐ गमे दिल क्या कहूँ, ऐ बहसते दिल क्या कहूँ।
यह रूपहनी छाँव यह आवाश पर तारों का जाल,
जैसे सूफी का तमध्वर, जैसे आसिब का खयाल,
आह लेकिन वीन जाने वीन समझे जी का हाल,
ऐ गमे दिल क्या कहूँ, ऐ बहसते दिल क्या कहूँ।

हिन्दी में जैसे कुछ कवियों ने प्राचीनतावाद की ऐसा साधन बनाया है कि
साहित्य का पानी उतर जाय, उसी तरह उर्दू में भी असमाव और फूट पैदा
करनेवाले, इस्लाम में उर्दू का नाता जोड़नेवाले, मुसलमानों की प्रलग जाति
और उर्दू को प्रत्य और ईरान की सभ्यति में मिलावेवाले धायर भी हुए हैं।
लेकिन उनकी वजह में उर्दू साहित्य की साम्प्रदायिक समझना उतनी ही बड़ी
प्रकलमन्दी होगी, जितनी विभिन्न की वजह से अंग्रेजी साहित्य की साम्राज्य-
वादी समझना।

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन का कहना है कि उर्दूवाले राम, कृष्ण, अर्जुन वगैरह
का नाम लेना अपनी सभ्यति के खिलाफ समझते हैं। अगर ऐसा है तो नजीर
ने 'बन्हेया का बालपन' क्यों लिखा? और लिखा तो ऐसी की जाति-बाहर क्यों
नहीं कर दिया गया? नजीर ने लिखा है—

मारी मुनो ये दधि के सुट्टया का बालपन,
श्री मधुपुरी नगर के बर्नया का बालपन,
मोहन-स्वरूप नृत्य चरैया का बालपन,
घन-जन के ग्वाल गोर्ण चरैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण बन्हेया का बालपन।

नजीर ने दीवाली पर लिखा था—

हर इक मकान में जला फिर दिया दिवाली का,
हर इक तरफ को उजाला हुआ दिवाली का,

मभी के दिल मे समा भा गया दिवाली का,
 किसी के दिल को मजा खुश लगा दिवाली का,
 भजब बहार का है दिन बना दिवाली का ।

होली पर दूसरे सुर-ताल मे लिखा था—

जब फागुन रंग भूमवते हो तब देख बहारें होली की,
 और रफ के शोर खड़कते हो तब देख बहारें होली की ।

नये युग ने कवियों मे सागर निजामी ने वृष्ण के वासुरी बजाने इत्यादि
 पर लिखा है—

भय गोपाल भूमवर बसरी बजामो फिर ।
 बसरी के कंफ से दिल को गुदगुदामो फिर,
 प्रेम और प्रीति की, रीति को जगामो फिर

खुद ही तुम कमल बनो, खुद ही मुसकरामो फिर,
 बूयगुल के रूप मे, सबके पास जाओ फिर,
 बसरी बजामो फिर दो जहाँ मैं छाओ फिर,
 भय गोपाल भूमकर बसरी बजामो फिर ।

यहाँ पर भववर इलाहाबादी का जिक्र करना उचित होगा, जिनके डेरों
 घेर घनेक हिन्दी लेखकों की रचनाओं मे उद्धृत किये हुए मिलेंगे । उनके बहुत-से
 शेर वहावतो का दर्जा पा गये हैं—

खीचो न कमानो की न तलवार निकालो,
 जब तोप मुकाबिल हो तो भलवार निकाली ।

कौम के गम मे डिनर खाते है हुक्काम के साथ,
 रज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ ।

भकवर की मज्जर भक्तर धार्मिक आस्था और पुरानी तहजीब पर रहती
 है । वह प्रग्रेजियत के खिलाफ हैं लेकिन उसके बंदने एक नई जनवादी संस्कृति
 का नक्शा उनके सामने नहीं है । उनके जमाने की सीमाएँ भी थी । फिर भी
 प्राचीनतावादियों पर कैसा व्यर्थ किया है । —

पेट भसकफ है किलकीं मे
 दिल है ईरान और टर्की मे ।

प्राचीनतावाद और कट्टरतावाद के खिलाफ बहुत-से उर्दू कवियों ने लिखा
 है । यही सबब है कि वह अपने यहाँ एक जनवादी और प्रगतिशील परम्परा
 कायम कर सके हैं ।

मुस्लिम प्राचीनतावादियों पर व्यर्थ करते हुए जोश ने लिखा है—

भा ही नहीं सकता मेरे मुँह सालाए बुझदिल । (यानी बुझदिल साला मेरी
 बराबरी नहीं कर सकता ।)

मैं पाक, वो नापाक, मैं गोरा हूँ, वो काला,
वया उसका मेरा जिक्र, वो देशी मैं विदेशी,
मैं मिस्र की मस्जिद, वो बनारस का शिवाला,
गंगा की हर इक लहर में गल्लीदा है पस्ती,
दजले की हर एव मौज में खसा है हिमाला ।

(प्राचीनतावादी मोलाना फर्माते हैं कि गंगा की लहरों में पस्ती है और
दजला की मौजों में हिमालय का नजारा है ।)

जोश ने लिखा है कि सैतान मोलवी को यो फंसा लेता है—

यही कह कह के राह करता है गुम
कि खुदा ने हो खानदान से तुम ।

प्राचीनतावाद के विरोध के फलस्वरूप हिन्दू-मुस्लिम-एकता पर उर्दू कवियों
ने बहुत सुन्दर रचनाएँ की हैं ।

इकबाल ने लिखा था—

मा गैरियत के पर्दे इक बार फिर उठा दें,
बिछुड़ों की फिर मिला दें, नक्ते दुई मिटा दें ।
सूनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती
मा इक नया शिवाला, इस देश में बसा दें ।
दुनिया के तीरथों में ऊँचा हो अपना तीरथ,
वामाने आसमाँ में उसका कसस मिला दें ।
हर सुबह उठके गाएँ मत्तर वो भीठे-भीठे,
सारे पुजारियों को मय पीत की पिला दें ।
शक्ती भी शान्ती भी भक्तों के गीत में है
घरती के बासियों की मुक्ती पिंगीत में है ।

यह याद रखना चाहिए कि हिन्दू-मुस्लिम-एकता की अभिगम और पक्की
नींव जनतथ्य ही है, भावुकता के आधार पर कायम की हुई एकता, सिर्फ
ईश्वर-भरला का नाम लेकर कायम की हुई एकता टिकाऊ नहीं हो सकती ।
बहुत कांग्रेसी नेता एकता का दम भरते थे, आज वे प्राचीनतावाद और हिन्दू
सम्प्रदायवाद के भक्त नजर आते हैं । कारण यह है कि किसान मजदूरों के
आन्दोलन का विरोध करके, उनके सवर्ण को अपने लिए काल समझकर कोई
भी एकता का हिमायती नहीं हो सकता । उसे एकता अपने लिए एक खतरा
मालूम होने लगती है । इकबाल भी इस एकता को छोड़कर सम्प्रदायवाद की
तरफ झुक गये थे ।

उर्दू में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ बहुत काफी और बहुत जोरदार
कविताएँ लिखी गई हैं । इन पर एक नजर डालने से ही जाहिर हो जाता है
कि यह आरोप कितना झूठा है कि उर्दू के कवियों को अपने देश से प्रेम नहीं
है । जोश ने खास तौर से साम्राज्य विरोधी आन्दोलन पर बहुत सुन्दर पक्तियाँ

लिखी हैं।

सन्दन मे बादशाह मगामत के राजगद्दी पाने पर जोश ने हिन्दुस्तान के बारे मे लिखा था—

विश्वरे हिन्दोस्ताँ मे रात को हगामे गाव,
करवटें रह-रह बे लेता है फज्जा मे इनवलाव,
गर्म है सोजे बगावत मे जवानों का दिमाग,
घाँधियाँ भाने को है ऐ बादशाही के विराग

° ° °

आपणे ऐवान मे रक्ताँ हैं सपटें ऊद की,
झिन्दियो की माँस से आती है बू बारुद की।

साम्राज्यविरोधी आन्दोलन पर जोश ने लिखा था—

क्या हिन्द का जिन्दा काँप रहा है गूँज रही हैं सब्धीरें,
उकताग है शायद कुछ कंदी और तोड़ रहे हैं जजीरें।

° ° °

क्या उनको लबर थी, ओठों पर जो कुपल लगाया करते थे,
एक रोज़ इसी लामोसी मे टपकेंगी दहकती सब्धीरें,
सँभलो कि वो जिन्दा गूँज उठा, भपटो कि वो कंदी छूट गये,
उठठो कि वो बैठी दीवारें, दीडो कि वो टूटी जजीरें।

ईस्ट इंडिया कम्पनी के फर्जंदो से कहा था—

इक बहानी बकत लिखेगा नये मजमून की
जिसकी भुर्खी को जरूरत है तुम्हारे खून की।

जोश का साम्राज्य-विरोध १५ अगस्त, सन् '४७ के बाद गुमराह हो गया है। आजकल वह 'आजकल' के संपादक है। वह उन लोगो मे है जो अपनी जनता का साथ छोड़कर उस दल के साथ जा मिले हैं जो हिन्दुस्तान को साम्राज्यवादी खेमे के साथ बाँचे हुए है।

३

उर्दू पर यह दोष लगाया जाता है कि उसमे फारसी की दस पाँच बहरें ही काम मे लाई जाती है और हिन्दी के हजारो छन्दो के भण्डार को अछूता छोड़ दिया गया है।

यहाँ पर पहले तो यह याद रखना चाहिए कि उर्दू की बहरें अब सिर्फ उर्दू तक सीमित नहीं रही। हिन्दी मे बहुत-से कवियो ने उन्हे अपना लिया है और उनमे बरोक रचनाएँ करते है। इस तरह की रचनाएँ वे कवि भी करते है, जो प्राचीनतावाद के उपासक हैं, जैसे दिनकर।

धुँधली हुई दिशाएँ, छाने लगा बुझासा,
बुझनी हुई शिक्षा ने, भ्राने लगा धुँधलासा,

कोई मुँह बता दे, क्या आज हो रहा है,

मुँह को छिपा निमिर मे, क्यों तेज रो रहा है ।

इसके अलावा फारसी की बहरो और हिन्दी के छन्दो म उठना फर्क नहीं है जितना कुछ लोग समझते हैं । श्री हरिदासर शर्मा ने अपने 'उर्दू साहित्य के इतिहास' (पृ० १९) में लिखा है—“उर्दू म इस्तेमाल होनेवाले कुछ छंदों के नाम ये हैं—मुमैर, विधाता, विहारी, शास्त्र, भीमपवर्षा, भुजंगप्रयात, परारो, हरिगीतिका, आनन्दवद्वंक, दिग्पाल, भुजगी, चौपाई आदि । इससे यह तो बाहिर हो जाता है कि छन्दों के लिहाज से हिन्दी-उर्दू की सांस्कृतिक परम्पराओं के बीच कोई गहरी न पट सवनेवासी खाई नहीं है ।

छायावादी कवियों ने—खासकर निरालाजी ने—जिम तरह मुक्तछन्द लिखने की प्रथा डाली थी, उसी तरह उर्दू में बहुत से कवियों ने भी मुक्तछन्द में रचनाएँ की । लेकिन जो चीज हिन्दी उर्दू कवियों को सबसे ज्यादा नजदीक लाती है, वह उनके गीत हैं । उर्दू कवि एक अरसे में गीत लिखते आये हैं । प्रगतिशील कवियों ने जो गीत लिखे हैं वे रोमांटिक गीतों के लग दापरे से निकलकर आम जनता के गले में रम चुके हैं । ऐसे गीत एक दो नहीं, सँकड़ो हैं । उर्दू साहित्य का यह पहलू उसका सबसे लोकप्रिय और जनवादी रूप हमारे सामने लाता है । इन गीतों की सांस्कृतिक परम्परा एक ऐसी शक्तिशाली और प्रगतिशील परम्परा है जो हिन्दी-उर्दू के बाकी भेदभाव को दूर करने में बहुत बड़ी मदद करेगी । इन गीतों की देखने से पता चलता है कि जब हम जनता के सर्वप, उसकी मुसीबतों, आशाओं और आदरों का लेकर साहित्य रचते हैं तब प्राचीनतावाद के तमाम अलगाव पैदा करनेवाले रूप आप स आप खत्म हो जाते हैं । हमारी जनता की संस्कृति एक है । हमारा साहित्य जितना ही जनता के नजदीक आता है, उतना ही उसकी सांस्कृतिक परम्परा प्राचीनता ॥ मुँह मोड़कर अपने निचे मौजूदा जमाने स तस्व चुनती है । जनता की यह सबल सांस्कृतिक परम्परा पुरान जमाने की मस्ति से निक ब चीजें लती है जो उसमें धार्मिक अन्धविश्वास और भेदभाव पैदा करने के बदले उसे एतता, आजादी और जनतन्त्र के नजदीक ले जाती हैं और जनवादी भावनाओं का मजबूत करती हैं ।

उर्दू के कविम ने हमारे जन-आन्दोलन की जो गीत दिये हैं उनमें मखदूम मुहीउद्दीन का गीत— यह जग है जगे आजादी आजादी के परचम के तले मजदूर वर्ग का अपना गीत है । बंगाल के अकाल पर चामिक का यह गीत मोवप्रिय हो चुका है—

पूरब देस म दुग्गी बाजी फँसा दुख का जाल,
दुख की धमनी कीन बुझाये सूख गये सब ताल,
जिन हाथों ने माती रोते आज वही कणाल,
रे माथी आज वही कणाल !

भूखा है बगाल ।

भूखा है बगाल रे साथी, भूखा है बगाल ।

इसी तरह मजाज का गीत 'बोल भरी ओ घरती, बोल, राजसिंहासन डाँवाडोल' मली सरदार जाफरी के कई गीत, प्रेम धवन का 'घरे भब भागे, लन्दन जाओ' उर्दू में एक ऐसी परम्परा की नींव डाल चुने हैं जिसे हम हिन्दी-उर्दू की मिली-जुली परम्परा कह सकते हैं।

प्राधुनिक उर्दू कविता उन तमाम रूपों और कल्पनाओं से पीछा छुड़ा चुकी है जिन्हें श्री रघुपतिसहाय फिराक ने 'सदा बहार और सदा सोहाग' कहा था। उन्होंने भारतेन्दु से लेकर निराला तक हिन्दी-साहित्य के तमाम विकास पर जो बुहारी फेर दी थी, उससे हिन्दी को उर्दू के नजदीक साने में मदद न मिल सकती थी। इसके अलावा हिन्दी के तमाम विकास पर कीचड़ उछालने के बाद उन्होंने आदर्श रूप से जो दोर पेश किये थे और पुराने रूपों के शाश्वत सौन्दर्य की जो व्याख्या की थी, वह एक प्रतिनिधावादी काम था, जिसका विरोध करना जरूरी था। पुराने रूपों और प्राचीनतावाद का विरोध जिस तरह उर्दू के नये कवियों ने—खास तौर से प्रगतिशील कवियों ने—किया है, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाय, थोड़ी है। इस सिलसिले में मिर्ते हुसैन का लेख विशेष ध्यान देने योग्य है जिसमें उन्होंने इकबाल की जनतन्त्र-विरोधी धारणाओं की आलोचना की थी। यह लेख 'नया अदब' में छपा था (जब 'नया अदब' ललनऊ से निकलता था)। जिस तरह हिन्दी की प्रगतिशील कविता पर यह तोहमत लगाई जाती है कि उसने प्राचीन संस्कृति से नाता तोड़ लिया है, वह छिछली राजनीतिक और प्रचारात्मक हो गई है वगैरह, उसी तरह उर्दू की प्रगतिशील कविता पर भी आरोप लगाए जाते रहे हैं। इनका जवाब देते हुए एहतेशाम हुसैन ने बहुत-कुछ लिखा है और उन्होंने उर्दू में नई तरह की आलोचना को आगे बढ़ाया है। उर्दू की आलोचना, उसके नाटक, कहानियाँ, उपन्यास आज उसी तरह नये रास्ते पर चल रहे हैं जिस तरह हिन्दी-साहित्य के में रूप। उपन्यासों और कहानियों का सम्बन्ध अरबाम की जिन्दगी से होता है, इसलिए इनमें प्राचीन रूपों, अलंकारों वगैरह का असर नहीं के बराबर होता है। हिन्दी के बहुत से पाठक 'हंस' में कृशनचन्दर की कहानियाँ, स्केच पढ़ चुके होंगे। खास तौर से रुद्रदत्त भारद्वाज पर उनका स्केच, 'तीन गुडे' नाम की कहानी यह जाहिर करती है कि उर्दू-साहित्य मौजूदा जिन्दगी से अपनी विषयवस्तु चुनकर एक मिली-जुली जनवादी परम्परा गढ़ रहा है।

उर्दू की नई कविता में पुरानी व्यवस्था का विरोध और जनतन्त्र की तरफ बढ़ने की स्वाहित्श पग-पग पर मिलती है। उर्दू कविता में देश-विदेश की महत्वपूर्ण घटनाओं, जन आन्दोलनों की गहरी छाप है। रूस पर हिटलर की हमला, लाल फौज का वीरतापूर्ण सभ्राम, बर्लिन की जीत, हिन्दुस्तान में क्रिप्स-

मिशन का प्राना, देश का बँटवारा, साम्प्रदायिक दंगे, गांधीजी की हत्या, आज़ाद हिन्दुस्तान में जनता के आन्दोलनों का दमन, नये जन सघर्ष, इन सभी की तसवीरें उर्दू कविता में मिलेंगी। इनसे स्पष्ट हो जाता है कि उर्दू की सांस्कृतिक परम्परा को आज वही घटना-क्रम, वही सामाजिक परिस्थितियाँ, वही जन-सघर्ष रच रहे हैं जो हिन्दी की सांस्कृतिक परम्परा रच रहे हैं। (१९४६)

भारत की भाषा-समस्या

भाषा-समस्या का सामान्य महत्व

भाषा-समस्या मजदूर वर्ग, उसकी पार्टों, तमाम श्रमिक जनता और प्रगतिशील बुद्धिजीवियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लेनिन के शब्दों में, "भाषा मानवीय सम्पर्क का सबसे महत्वपूर्ण साधन है" (जातियों के आत्मनिर्णय का अधिकार)।

भाषा-समस्या का महत्व सामाजिक विकास की मशिनो में अलग-अलग होता है।

पूँजीवाद से पहले सामन्ती और कभीलाई सामाजिक सम्बन्ध विभिन्न जनसमूहों को एक ही जाति (नेशन) में संगठित होने से रोकते हैं, इसलिए वे प्राधुनिक भाषाओं के विकास में भी बाधा डालते हैं। वस्तुगत रूप से पूँजीवाद किसी जाति के गठन में प्रगतिशील भूमिका पूरी करता है, इस तरह वह प्राधुनिक भाषाओं के विकास में भी प्रगतिशील भूमिका पूरी करता है।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि जातीय समस्या और भाषा-समस्या में बड़ा गहरा सम्बन्ध है, किसी जाति के सामाजिक विकास तथा उस विकास के सांस्कृतिक प्रतिबिम्ब में गहरा सम्बन्ध है। यह सांस्कृतिक प्रतिबिम्ब सामाजिक विकास को भी प्रभावित करता है।

लेनिन के अनुसार "समस्त संसार में सामन्तवाद पर पूँजीवाद की अन्तिम विजय का युग जातीय आन्दोलनों के साथ जुड़ा रहा है। इन आन्दोलनों का प्राथमिक आधार यह है कि बिकाऊ माल की पैदावार को पूर्ण विजयी बनाने के लिए पूँजीपतियों के हाथ में घरेलू बाजार आ जाना चाहिए, उनके अधिकार में राजनीतिक रूप से एकताबद्ध प्रदेश होने चाहिए जहाँ के लोग एक ही भाषा बोलते हों, इस भाषा के विकास में और साहित्य में उसके व्यवहार को सुनिश्चित करने में जो भी अड़चनें आती हैं, उन्हें दूर करना होता है।"

पूँजीवादी सामाजिक विकास की आवश्यकताएँ, बड़े पैमाने पर जातियों के आत्मनिर्णय का अधिकार, व्यापार-सम्बन्ध कायम करने की आवश्यकताएँ,

परलू वाजार को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकताएँ सक्षेप में यह कि जातीय पैमाने पर पूँजीवादी सामाजिक सम्बन्धों के गठन की आवश्यकताएँ भाषा की एकमूर्तता और उसके विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती हैं। भाषा की एकता और विकास के बिना आधुनिक जानियों का विकास असम्भव है।

'मार्क्सवाद तथा जातीय और औपनिवेशिक समस्या' नाम की पुस्तक में स्तालिन ने बताया है कि जो जातियाँ पूँजीवादी विकास में पिछड़ गईं, जिन्हें बहुजातीय पूँजीवादी राष्ट्र में राज्य बनाने के अधिकार नहीं मिले, उनका उत्पीड़न उन बड़ी जातियों के पूँजीपतियों ने किया जो पूँजीवादी विकास में आगे रही थी। ज़ारशाही रूस में गैर रूसी जातियों की भाषाओं का दमन किया गया। अपनी भाषा का व्यवहार करने के लिए सघर्ष जातीय आन्दोलन का मुख्य प्रगमन गया। उत्पीड़ित जाति के पूँजीपति सभी वर्गों को अपने हितों के लिए एकजुट करने का प्रयत्न करते हैं। भाषा-समस्या को लेकर भी उनकी यही नीति रहती है। किन्तु भाषा की समस्या उत्पीड़ित जाति के मजदूर वर्ग के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्तालिन के अनुसार "तातार या यज़्दी मजदूर को सभा और भाषाओं में अपनी भाषा का व्यवहार करने की सुविधा न दी जाय, यदि उसके स्कूल बन्द कर दिए जाएँ तो उसके बौद्धिक विकास की कोई सम्भावना न रहेगी," (मार्क्सवाद तथा जातीय और औपनिवेशिक समस्या)। मजदूर वर्ग के हित में है कि वह स्कूलों, भाषणों, मखमरों आदि में अपनी भाषा के व्यवहार के लिए लड़े।

स्तालिन ने यह भी बताया है कि उत्पीड़न से पूँजीपतियों के लिए यह आसान हो जाता है कि मजदूर वर्ग को यह भुलावा दें कि उसके और पूँजीपतियों के हित एक हैं। जातीय समस्या मुख्य सामाजिक प्रश्नों में लोगों का ध्यान हटा देती है। भाषा-समस्या से भी पूँजीपति इस प्रकार लाभ उठाते हैं और लोगों को क्रान्ति के रास्ते से हटा देते हैं।

समाजवादी क्रान्ति के बाद जातियों का नया स्वाधीन विकास आरम्भ हुआ। सोवियत संघ में जातियाँ स्वायत्त सत्ता के अधिकार को व्यवहार में ला सकें, इसके लिए अपनी भाषा के विकास और व्यवहार का प्रश्न फिर सामने आया। स्कूलों, मखमरों, मखमरी संस्थाओं आदि में अपनी भाषा के व्यवहार के बिना कोई भी जाति सोवियत स्वायत्त शासन को अपनी रूप नहीं दे सकती।

समाजवादी क्रान्ति के बाद भी सोवियत संघ में पूँजीवाद के प्रवेश के रहे। यह अवरोध इस बात से बाहर हुए कि जातीय समस्या को लेकर छोटी और बड़ी दोनों ही तरह की जातियों में घट-राष्ट्रवाद के रुझान दिखाई दिये। एक तरफ तो सोवियत संघ में ऐसे लोग थे जो कहते थे कि उर्बेनी नाम की कोई जाति ही नहीं है; दूसरे लोग का विचार था कि बोल्शेविक पार्टी वृत्रिम रूप से इस जाति को गढ़कर खड़ा कर रही है। दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो कहते थे कि समाजवाद की जीत के बाद सब जातियाँ मिलकर एक ही राष्ट्र बनेंगी,

भारत की भाषा-समस्या

भाषा-समस्या का सामान्य महत्व

भाषा-समस्या मजदूर वर्गों, उसकी पार्टों, समाज श्रमिक जनता और प्रगतिशील बुद्धिजीवियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लेनिन के शब्दों में, "भाषा मानवीय सम्पर्क का सबसे महत्वपूर्ण साधन है" (जातियों के आत्मनिर्णय का अधिकार)।

भाषा-समस्या का महत्व सामाजिक विकास की दृष्टि से अलग-अलग होता है।

पूँजीवाद से पहले सामन्ती और कबीलाई सामाजिक सम्बन्ध विभिन्न जनसमूहों को एक ही जाति (नेशन) में संगठित होने से रोकते हैं, इसलिए वे प्राधुनिक भाषाओं के विकास में भी बाधा डालते हैं। वस्तुगत रूप से पूँजीवाद किसी जाति के गठन में प्रगतिशील भूमिका पूरी करता है, इस तरह वह प्राधुनिक भाषाओं के विकास में भी प्रगतिशील भूमिका पूरी करता है।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि जातीय समस्या और भाषा-समस्या में बड़ा गहरा सम्बन्ध है, किसी जाति के सामाजिक विकास तथा उस विकास के सांस्कृतिक प्रतिबिम्ब में गहरा सम्बन्ध है। यह सांस्कृतिक प्रतिबिम्ब सामाजिक विकास को भी प्रभावित करता है।

लेनिन के अनुसार "समस्त ससार में सामन्तवाद पर पूँजीवाद की अन्तिम विजय का युग जातीय आन्दोलनों के साथ जुड़ा रहा है। इन आन्दोलनों का आर्थिक आधार यह है कि बिकाऊ माल की पैदावार को पूर्ण विजयी बनाने के लिए पूँजीपतियों के हाथ में घरेलू बाजार आ जाना चाहिए, उनके अधिकार में राजनीतिक रूप से एकताबद्ध प्रदेश होने चाहिए जहाँ के लोग एक ही भाषा बोलते हों, इस भाषा के विकास में और साहित्य में उसके व्यवहार को सुनिश्चित करने में जो भी अड़चनें आती हैं, उन्हें दूर करना होता है।"

पूँजीवादी सामाजिक विकास की आवश्यकताएँ, बड़े पैमाने पर जातियों के आत्मनिर्णय का अधिकार, व्यापार-सम्बन्ध तायम करने की आवश्यकताएँ,

धरलू बाजार को मुख्यस्थित करने की आवश्यकताएँ सक्षम में यह कि
 जातीय पैमाने पर पंजीवादी सामाजिक सम्बन्धों में गठन की आवश्यकताएँ
 भाषा की एकमूर्तता और उसके विनाश की प्रक्रिया को धारण बढ़ाती हैं। भाषा
 की एकता और विकास के बिना आधुनिक जातियों का विकास असम्भव है।
 जातीय न्याय और औपनिवेशिक समस्या नाम की पुस्तक में
 जातीय और औपनिवेशिक विकास में पिछड़ गई, जिसे उन

नौ पंक्तियों पर पंजीयन का प्रयोग किया गया है।
 भाषा की एकमूर्तता और उसके विनाम का विकास ग्रन्थ में
 ही एकता और विकास के बिना प्राचिन जातियों का विकास ग्रन्थ में
 'माकर्मवाद तथा जातीय और औपनिवेशिक समस्या' नाम की पुस्तक में
 स्तानिन ने बताया है कि जो जातियाँ पूँजीवादी विकास में पिछड़ गईं, जिन्हें
 बहुजातीय पूँजीवादी राष्ट्र में राज्य बनाने के अधिकार नहीं मिले, उनका
 उत्पीड़न उन बड़ी जातियों के पूँजीपतियों ने किया। पूँजीवादी विकास में
 प्रागे रही थी। जारसाही इस में गैर हथी जातियों की भाषाओं का दमन
 किया गया। अपनी भाषा का व्यवहार करने के लिए सघर्ष जातीय आन्दोलन
 का मुख्य अंग बन गया। उत्पीड़ित जाति के पूँजीपति सभी वर्गों को अपने हितों
 के लिए एकजुट करने का प्रयत्न करते हैं। भाषा समस्या को लेकर भी उनकी
 यही नीति रहती है। विन्तु भाषा की समस्या उत्पीड़ित जाति के मजदूर वर्ग
 के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्तानिन के अनुसार "तातार या यहूदी मजदूर को
 नभा और भाषाओं में अपनी भाषा का व्यवहार करने की सुविधा न दी जाय,
 यदि उसके स्कूल बन्द कर दिए जायें तो उसके बौद्धिक विकास की कोई
 सम्भावना न रहेगी," (माकर्मवाद तथा जातीय और औपनिवेशिक समस्या)।
 मजदूर वर्ग के हित में है कि वह स्कूलों, भाषणों, प्रखण्डों आदि में अपनी
 भाषा के व्यवहार के लिए सचेत हो।
 निम्नलिखित भी बताया है कि उत्पीड़न में पूँजीपतियों के लिए या
 कि उनके गढ़ भी बताया है कि उत्पीड़न में पूँजीपतियों के लिए या
 कि उनके गढ़ भी बताया है कि उत्पीड़न में पूँजीपतियों के लिए या

मावना न रहना, जूटूर वर्ग के हित में है कि वह स्कूला, मापा के व्यवहार के लिए सहे।

स्तालिन ने यह भी बताया है कि उत्पीड़न में पूँजीपतियों के लिए यह प्रामाण हो जाता है कि मजदूर वर्ग को यह मुलावा दें कि उसके और पूँजीपतियों के हित एक हैं। जातीय समस्या मुख्य सामाजिक प्रश्न से लोगों का ध्यान हटा देती है। भाषा-समस्या से भी पूँजीपति इस प्रकार लाभ उठाते हैं और लोगों को शान्ति के रास्ते से हटा देते हैं।

शान्ति के बाद जातियाँ का नया स्वाधीन विकास प्रारम्भ होगी शान्ति के बाद जातियों का नया स्वाधीन विकास प्रारम्भ होगा। शान्ति के बाद जातियों का नया स्वाधीन विकास प्रारम्भ होगा।

नयी के हित एवं न. भाषा-समस्या से भी पूँजीवादी
 मान हटा देती है। भाषा-समस्या से भी पूँजीवादी
 और लोगों को श्रान्ति के रास्ते से हटा देते हैं।
 समाजवादी श्रान्ति के बाद जातिया का नया स्वाधीन विकास प्रारम्भ
 हुआ। सोवियत सभ में जातिया स्वायत्त सत्ता के अधिकार को व्यवहार में ला
 सके, इसके लिए अपनी भाषा के विकास और व्यवहार का प्रश्न फिर सामने
 आया। स्कूलों, अदालतों, सरकारी संस्थाओं आदि में अपनी भाषा के व्यवहार के
 बिना कोई भी जाति सोवियत स्वायत्त शासन को समझी रूप नहीं दे सकती।
 समाजवादी श्रान्ति के बाद भी सोवियत सभ में पूँजीवाद के प्रवेश को रोकने के
 लिए जातीय समस्या को लेकर छोटी प्र

यथा । स्कन्धो भद्रालतो, गरवारी सखायः ।
ननु कोई भी जाति सोवियत स्वायत्त नासन की समसती रूप नहीं है ।
समाजवादी प्रान्ति के बाद भी सोवियत सभ म पूंजीवाद के ध्वरो बने रहे ।
य समगप इस बात से जाहिर हुप कि जालीय गमन्या को लेकर छोटी प्रौर
यही दोनो ही तरह की जातियो म सभ राष्ट्रवाद के गमान दिखाई दिये । एव
तरफ तो सोवियत सभ मे ऐसे लोग थे जो बहते थे कि उर्जनी नाम की कोई
जाति ही नहीं है; इन लोगो का विचार था कि बोलेविक पार्टी शुद्ध रूप
से इस जाति को गढ़र सटा कर रही है । दूसरी तरफ ऐग लोग थे जो बहते
थे कि समाजवाद की जीत के बाद सब जातियो मित्रवर एव हो जाएँगी,
भारत की माया-गमस्या / ६७

उनकी भाषाएँ आपस में घुल-मिल जाएँगी और सबकी एक ही सामान्य भाषा होगी। गैर रूसी जातियों में कुछ लोग ऐसे थे जो यह माँग करते थे कि उनकी जाति के मजदूरों की सस्कृति को रूसी मजदूर वर्ग की सस्कृति के प्रभाव से मुक्त रखा जाय। इस प्रकार समाजवादी क्रान्ति के बाद भी विभिन्न रूपों में अध-राष्ट्रवाद का खतरा बना रहा।

मजदूर वर्ग को भाषा-समस्या का दोहरा महत्व समझना चाहिए। मजदूर-वर्ग के अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भाषा-समस्या का महत्व है, साथ ही क्रान्ति के विरुद्ध पूँजीपति वर्ग उभरा उपयोग मजदूरों को भटकाने के लिए भी करता है।

पूँजीवाद में पहले के समाज में मुख्य कर्तव्य यह होता है कि सामन्ती विघटन के खिलाफ भाषा की एकता के लिए संघर्ष किया जाय। भारी बड़ी हुई जातियों के सर्वहारा वर्ग का कर्तव्य है कि वह विछड़े लोगों को जातिरूप में सुगठित होने में मदद दे।

जहाँ जातियाँ औद्योगिक विकास की मजिलें पार कर चुकी हैं लेकिन जिन्हे अपनी भाषा का व्यवहार करने की आजादी नहीं है वहाँ उत्पीड़न और उत्पीड़ित दोनों ही तरह की जातियों के मजदूर वर्ग का कर्तव्य यह है कि जनवादी क्रान्ति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जातीय भाषा के व्यवहार के अधिकार के लिए संघर्ष करें। पूँजीवाद पर मजदूर वर्ग की विजय के पहुँचे और बाद को—दोनों ही स्थितियों में—इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाषा-समस्या को लेकर छोटी और बड़ी—दोनों ही तरह की—जातियों में अध-राष्ट्रवादी रुझान पैदा न हो।

यह हुआ भाषा समस्या का सामान्य महत्व।

भारत में भाषा-समस्या का विशेष महत्व

ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ भारत की तमाम जनता संघर्ष करती रही है—सबसे पहले भाषा-समस्या का महत्व इस संघर्ष के सन्दर्भ में है।

ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अंग्रेज़ी को अनिवार्य राजभाषा के रूप में भारत पर इसलिए लादा कि वह जनता का शोषण कर सके। इस प्रकार उसने भारत की अनेक जातियों की भाषाओं की प्रगति में बाधा डाली। स्वाधीनता-संग्राम के दौरान भारतीय जनता ने यह माँग बराबर पेश की कि शिक्षा-संस्थाओं, प्रदालतों, शासनतंत्र आदि में अंग्रेज़ी की जगह उसकी भाषा का चलन हो। जातीय प्रदेशों में अंग्रेज़ी की जगह वहाँ की भाषाओं का व्यवहार हो, जनता के लिए यह अब भी ज्वलन्त प्रश्न बना हुआ है और अगस्त, सन् १९४७ के राजनीतिक परिवर्तन के बाद यह समस्या अभी कही हल होती नहीं दिखाई देती।

हिन्दुस्तानी क्षेत्र तथा समस्त भारत की राजभाषा हिन्दी, उर्दू अथवा हिन्दुस्तानी हो—इस सन्दर्भ में भारत की भाषा समस्या विशेष महत्वपूर्ण हो

गई है। सबसे बड़ा विवाद समस्या के इसी पक्ष को लेकर हुए हैं। प्रमुख सामाजिक समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने में उच्च वर्गों के पास हिन्दी-उर्दू समस्या सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक साधन रही है। साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा करने के लिए इस समस्या का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। भारत और पाकिस्तान में चरम प्रतिक्रियावादी धारण हित साधने के लिए इस समस्या का उपयोग करते हैं।

भारत-जैसे बहुजातीय देश में प्रतिवार्य राजभाषा का प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुजातीय पूँजीवादी राज्यों से देखा जाता है कि इस तरह की प्रतिवार्य राजभाषा राजनीतिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में दूसरे भाषाओं के व्यवहार पर रोक लगाती है और कभी-कभी उनके इस अधिकारों को एकदम अस्वीकार करती है। भारत के बड़े पूँजीपतियों से अन्य जातियों और जनसमूहों का जो सम्बन्ध है, उसे देखते हुए राष्ट्रभाषा का प्रश्न अपना वर्ग-महत्व रखता है।

कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ लोग मिली-जुली बोनियाँ बोलते हैं। वहाँ सामन्ती सम्बन्ध प्रायः भी कायम हैं। वहाँ के जातीय प्रदेश में टकसाली जातीय भाषा का विकास अभी तक नहीं हो पाया। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जहाँ पहाड़ी बोनियाँ बोली जाती हैं ऐसे ही इलाके हैं।

भाषा-समस्या बचीली और पिछड़े हुए जातीय गुटों के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न पूँजीवादी गुट इनका शोषण करते हैं। उन्हें अपनी भाषाओं के व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। उनकी भाषाओं का अस्तित्व ही अस्वीकृत कर दिया जाता है।

इतनी बातों से ही स्पष्ट हो जाता है कि मजदूर वर्ग और उसकी पार्टियों को भाषा-समस्या पर बड़ी ध्यान देना चाहिए।

ब्रिटिश साम्राज्यवाद और राजभाषा के रूप में अंग्रेज़ी की भूमिका

शिक्षा और संस्कृति के मामलों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीति यह रही है कि ग्राम जनता की भ्रष्टाचार और पिछड़ेपन की दशा में रखा जाय। शासन-व्यवस्था के लिए क्लर्कों की फौज तैयार करने के लिए साम्राज्यवाद ने अंग्रेज़ी की पढ़ाई अनिवार्य कर दी और उसे शिक्षा का अनिवार्य माध्यम बनाया। ग़दरवाले विचारधारा के सम्पर्क से भारतीय भाषाओं और साहित्य को जो भी लाभ हुआ, वह अप्रत्यक्ष रूप से हुआ; वह लाभ साम्राज्यवादियों की भाषाओं के विपरीत था। इस बात का प्रचार वे बराबर करते रहे कि भारत भाषाओं का अजापबधर है और उसमें जो भी एजता है, वह इसलिए कि अंग्रेज़ी ने 'लिगुमा प्रादु' की भूमिका पूरी की है। यूरोप के अनेक प्रसिद्ध भाषाशास्त्रियों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की यह स्थापना मान ली, इसलिए भी कि अपने उपनिवेशों में वे भी यही खेल खेल रहे थे।

भारतीय जनता ने माना कि शिक्षा, घडातल, कचहरी, दामन इत्यादि

मे अंग्रेजी की जगह अपनी अपनी भाषा को । यह विमर्शपूर्ण व्यापार भी । राष्ट्रीय नेताओं ने ध्यानाधीन आती थी कि सन् १९४७ में आजादी पाने के बाद इस भाषा को वे पूरा करेंगे । लेकिन विभिन्न कारणों से वे उसे पूरा नहीं कर सके । सबसे पहला कारण तो यह है कि सरकार ने नेता स्वयं अंग्रेजी में डूबे हुए हैं । उन्हीं भारतीय भाषाओं के विचार के लिए प्रायः कुछ भी नहीं किया । दूसरा कारण यह है कि वे विभिन्न जातीय भाषाओं में संस्कृत के अर्थ में नीति पर चर्चा रहे हैं, जिससे कि आम जनता के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में भाग न ले सके । जब हम संस्कृत-विभागीय भाषा पर लगे हैं तो और उनकी होंसी उचित ही है, तब वे एक नई आवाज भरकर अंग्रेजी की शरण में लौट आते हैं और कहते हैं कि अंग्रेजी अभी पाँच या दस साल और चलाने दी जाय । इस समय तब उद्योग-धन्यों का राष्ट्रीयकरण आ होगा, जैसे ही पाँच या दस साल तक आम जनता की उच्च शिक्षा, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यवाही उसकी अपनी भाषा में न होगी ।

कुछ विद्वान् हिन्दी के ही संस्कृतीकरण की माँग नहीं कर रहे हैं । बँगला जैसी भाषा में भी वही विद्वान् उसी संस्कृतीकरण की माँग कर रहे हैं और उनका उद्देश्य भी वही है । कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल की सरकार ने उच्चकोटि के विद्वानों की एक समिति बनाई जिसमें प्रसिद्ध भाषाविद् डा० सुनीतिकुमार अटर्जी भी थे । इस समिति का यह काम मिला गया था कि वह शासन में व्यवहार के लिए बँगला में पारिभाषिक शब्दावली बनाए । इस शब्दावली की भूमिका में उन उच्चकोटि के विद्वानों ने कुछ प्रचलित शब्दों को संस्कृतिकृत कर दिया क्योंकि उनकी समझ में वे शब्द काफी गरिमायुक्त नहीं हैं । उनके मतों से उन्होंने ऐसा शब्द रखा है जो जन साधारण की समझ में नहीं आते, जो कभी-कभी समाधारण जनो की समझ में नहीं आते । इसलिए पारिभाषिकी निर्माताओं ने बंगाली जनता के देश-प्रेम को लक्ष्य रखा है कि जैसे वे अंग्रेजी का अध्ययन करते रहें हैं वैसे ही मातृभाषा के अध्ययन को भी अधिक समय दें ।

केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारें जनता की इस माँग को पूरा नहीं कर पा रही कि शिक्षा संस्थाओं में बच्चों, प्रदानत, सरकारी दफतरी आदि में जनता की भाषाओं का व्यवहार हो । शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की विरासत कायम है ।

पूँजीवादी सामन्ती औपनिवेशिक व्यवस्था भारतीय भाषाओं के पूर्ण विकास को रोकती है । शासक वर्ग जनता को या तो अंग्रेजी की शरण लेने को कहते हैं या भारतीय भाषाओं का ऐसा संस्कृतीकरण करते हैं कि वे लोगों को दुर्बोध हो जाएँ ।

अनिवार्य राजभाषा का सवाल

विभिन्न प्रदेशों में अंग्रेजी की जगह भारतीय भाषाओं का व्यवहार हो,

यह सही माँग है और मजदूर वर्ग को इसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी की जाह सारे देश में एक ही भाषा का चलन हो, यह माँग उस जनतांत्रिक माँग से भिन्न है। अंग्रेजों ने सारे भारत पर अंग्रेजी लादी—यह साम्राज्यवादी कार्य था। उसका स्थान एक भारतीय भाषा ले ले, यह बात जनतांत्रिक और न्यायपूर्ण न होगी। फिर भी पूँजीवादी नेता हिन्दी उर्दू या हिन्दुस्तानी और अंग्रेजी को भी अनिवार्य राजभाषा बनाने का कार्य करते रहे हैं।

भारत की एम्पुनिस्ट पार्टी के राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया है कि बड़े पूँजीपति महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु आदि प्रदेशों के आत्मनिर्णय के अधिकार को नहीं मान रहे। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' ने ६ दिसम्बर, १९४८ के एक म लिखा है कि ब्रिटिश 'सम्पर्क' की कुछ विरासत सुरक्षित रहनी चाहिए जैसे कि हार्दिकोटों में केन्द्रीय भाषा का ही चलन होना चाहिए और विभिन्न प्रान्तों में एक ही केन्द्रीय भाषा का चलन न होने से उच्च शिक्षा की प्रगति में बाधा पड़ेगी। इस प्रकार विभिन्न प्रदेशों के हार्दिकोटों और उच्च शिक्षा-मन्त्रालयों में एक ही केन्द्रीय भाषा के चलन की माँग करते बड़े पूँजीपति जातियों के पूर्ण राजनीतिक और आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं।

भारत के बड़े पूँजीपति चाहते हैं कि अंग्रेजों की जगह देश के शोषक बन जाएँ, यह सम्भव न हो तो विदेशी मालिकों के साथ मिलकर शोषण में हिस्सा बँटाएँ। जब तक साम्राज्यवाद में समझौता नहीं हुआ था, तब तक वे भाषायी झगड़ों—अर्थात् वहाँ के पूँजीपतियों—के आत्मनिर्णय का अधिकार मानते थे। विदेशी मालिकों की छत्रछाया में जहाँ एक धार उनका अधिकार राज्यसत्ता पर हो गया, वहाँ उन्होंने राष्ट्रवाद, एकता, बन्द आदि के नाम पर अपने बाड़े तोड़ना आरम्भ कर दिया। भारत के बड़े व्यापारी सारे भारत के लिए एक राष्ट्रभाषा या राजभाषा की वर्षा बरसकर करते रहे हैं क्योंकि इसके द्वारा वे अपने हित में बाजार को सुदृढ़ कर सकेंगे और दूसरी जातियों के पूँजीपतियों को निकाल सकेंगे।

जो लोग हिन्दी, उर्दू या हिन्दुस्तानी बोलते या लिखते हैं, उन्हें बड़े पूँजीपतियों की महत्वाकांक्षा से दिलचस्पी नहीं हो सकती। वे विस्मृत न चाहेंगे कि किसी भारतीय भाषा के पूर्ण और स्वतन्त्र विकास में बाधा डाली जाय। बड़े पूँजीपति उनकी साम्राज्य विरोधी भावना से लाभ उठाना चाहते हैं। वे पूछते हैं अंग्रेजी जाय, उसकी जगह कौन-सी भाषा ले?

भामनता प्रदश्य चाहती है कि अंग्रेजी उन पर न लदी रहे जैसे वह अब तक लदी रही है। बड़े पूँजीपति इस बात को जानते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि अंग्रेजी जाय। लेकिन वे लोगों को यह सोचने का मौका नहीं देते कि उसकी जगह कौन लेगा? बजाय यह कहने के कि जब अंग्रेजी जायगी तब प्रत्येक भारतीय भाषा को अपने स्वत्व प्राप्त होगी, वे पूछते हैं, कौन-सी एक भाषा अंग्रेजी की जगह लेगी। इस तरह सबान को पेदा करके वे जनता को

गुमराह करते हैं।

जो लोग चाहते हैं कि हम तरह के सबाल जनताधिकार ढंग से हल किये जाएँ, वे सच पहले हर जाति का यह हक मानेंगे कि हर स्तर पर वह अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यों में अपनी भाषा का व्यवहार कर सके और इस अधिकार पर कोई भी रोक न लगनी चाहिए।

रूस के पूँजीवादी-सामन्ती राज्य में बोल्शेविक पार्टी ने माँग की थी कि अनिवार्य राजभाषा का चलन बन्द किया जाय। उसने हर जाति को राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपनी भाषा के व्यवहार की पूरी छूट दी। बोल्शेविक पार्टी पर यह आरोप लगाया गया कि उसकी नीति व्यावहारिक है। लेनिन ने इस आरोप का उत्तर देते हुए लिखा, "हर जाति के राष्ट्रवादी पूँजीपतियों की दृष्टि में सर्वहारा का सारा काम जातीय समस्या के सन्दर्भ में हवाई होता है। सर्वहारा जन हर तरह के राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं, इसलिए वे 'हवाई' समानता की माँग करते हैं। वे माँग करते हैं कि सिद्धान्ततः किसी को थोड़े से भी विशेषाधिकार न मिलें।"

पूँजीपति भाषा समस्या का व्यावहारिक समाधान पेश करते हैं। वे कहते हैं कि इतनी भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकें छपवाने से व्यर्थ का खर्च होता है। तमाम उच्च न्यायालयों और विश्वविद्यालयों में एक ही केन्द्रीय भाषा का चलन होना चाहिए। मजदूर वर्ग हम तरह की व्यावहारिकता को स्वीकार नहीं कर सकता।

सोवियत संघ में इसी अनिवार्य राजभाषा नहीं है। प्रधान सोवियत में हर एक को अपनी भाषा में बोलने का अधिकार है और मध्य गैर-रूसी भाषाओं में दिये हुए भाषणों के अनुवाद की माँग कर सकते हैं। सोवियत संघ के प्रजातन्त्रों में इसी की पढाई स्कूलों और कालेजों में अनिवार्य है। इसमें कोई बुराई नहीं है। जातियों की मर्जी के खिलाफ रूसी की पढाई अनिवार्य नहीं की गई। भारत में यदि सभी जातियों से बराबर संख्या में जनवादी ढंग से चुने हुए प्रतिनिधि शिक्षाक्रम में किसी स्तर पर किसी एक भारतीय भाषा का अध्ययन अनिवार्य करना चाहे और किसी जाति के प्रतिनिधि इसका विरोध न करें तो इस तरह की अनिवार्य शिक्षा में कोई दोष नहीं है। मुख्य बात यह है कि कोई भाषा किसी जाति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध सादी न जानी जाए।

बहुजातीय पूँजीवादी राष्ट्र में जातियों का उत्पीड़न हाता है, उसमें अनिवार्य राजभाषा बड़े पूँजीपतियों के हित साधन का कारण बनती है। उससे विभिन्न जातियों की श्रमिक जनता में एकता नहीं पैदा होती बल्कि परस्पर वैर उत्पन्न होता है। हम नहीं चाहते कि कोई एक भाषा अंग्रेजी की जगह ले। विदेशी साम्राज्यवाद ने हमारे ऊपर अंग्रेजी सादी थी। हम नहीं चाहते कि किसी भारतीय भाषा के पूर्ण विकास पर कोई देशी साम्राज्यवादी रोक लगाएँ। बड़े पूँजीपति उन जातियों के अधिकार नियन्त्रित करते हैं जो कमोबेश

धार्मिक विकास कर चुकी है; जो जातियाँ पिछड़ी हुई हैं, उनके राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास को ये बड़े पूंजीपति धक्का दे रहे हैं। वे उनसे कहते हैं तुम्हारी अपनी कोई भाषा नहीं है; जो भाषा हम तुम पर ला दें वही तुम्हारी भाषा होगी। इस नीति का हम विरोध करेंगे।

बहुजातीय देश में समाजवादी सत्ता स्थापित होने पर उत्पीड़ित जातियों की भाषाओं को नया जीवन प्राप्त होता है। उनकी भाषाएँ और संस्कृतियाँ नई शक्ति पाकर लहलहा उठती हैं। समाजवाद आने पर विभिन्न जातियों की भाषाएँ मुरझाकर खरम न हो जाएँगी और बड़ी जाति की भाषा उनकी जगह न ले लेगी। इसलिए बहुजातीय समाजवादी राज्य में भी एकमात्र अनिवार्य राज-भाषा का चलन न होगा।

सोवियत संघ में रूसी भाषा सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती है। वह गैर-रूसी जातियों की मातृभाषा तभी बन सकती है, जब उनका रूसीकरण हो जाय। स्तालिन ने बताया है कि तमाम दुनिया में समाजवादी क्रान्ति की विजय हो जाने के बाद भी भाषा और संस्कृति के भेद रहेंगे। इससे स्पष्ट है कि भविष्य में जनता का राज कायम होने पर भी सारे देश में केवल एक ही भाषा बोली जाय, ऐसा न होगा। देश में जनता का राज कायम नहीं हुआ। इसलिए खतरा यह है कि जातियों की समानता का सिद्धान्त ऊपर से मान लिया जाय और प्रभुत्व में उसका उल्लंघन किया जाय। इसलिए भारत में अनिवार्य राज-भाषा के रूप में या सारे देश की एकमात्र सामान्य भाषा के रूप में हिन्दी स्वीकार न की जाएगी।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक प्रस्ताव में दूसरी पर हावी होने-वाले बड़े पूंजीपतियों का उल्लेख है जो केरल, महाराष्ट्र, आन्ध्र आदि के प्रात्म-निर्णय के अधिकार का विरोध करते हैं। ये बड़े पूंजीपति मुख्यतः मारवाडी हैं। बिड़ला, डालमिया, सिंघानिया, गोयन्का आदि जिन्होंने भारत में अपना जाल बिछा रखा है, इसी जाति के हैं। इनमें अन्य पूंजीपति भी शामिल हैं जो मारवाडी नहीं हैं। बिड़ला, गोयन्का आदि की मातृभाषा हिन्दी नहीं राजस्थानी है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने सामन्तवाद को सुरक्षित रखा। ये सत्तजन अपने घरेलू बाजार को सुगठित करके पूंजीपति नहीं बने; भारत से ही अपने व्यापार और उद्योग धंधों का प्रसार वे अन्य प्रदेशों में करते रहे, यही कारण है कि इन्होंने राजस्थानी के लिए कुछ नहीं किया लेकिन हिन्दी पत्र निकालने में वे पूंजी लगाते हैं। उनकी नीति में दक्षिण तथा अन्यत्र लोग हिन्दी को अपने ऊपर हावी होनेवाली जाति की भाषा समझने लगे हैं। अंग्रेज और उनके हाली-मवाली भाषा-समस्या को लेकर विभिन्न जातियों में द्वेष फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। जातीय विद्वेष की जो अग्नि वे भड़का रहे हैं, उससे इन भाषाओं में परस्पर आदान-प्रदान का क्रम भग होता है और बहुत-से अन्य हिन्दी राष्ट्र-वादी यह समझने लगे हैं कि और सब उनकी भाषा सीखेंगे, वे किसी की भाषा

बड़े पूंजीपतियों की नीति हिन्दी को अनिवार्य राजभाषा बनाने की है। इसके विपरीत प्रान्तीय पूंजीपति कहते हैं कि उनके विरोधी भाषायी साम्राज्यवाद कायम करना चाहते हैं। और वे अपनी जाति को आत्मनिर्णय का पूरा अधिकार देने की बात कहते हैं, बसते कि इस प्रश्न पर मजदूर वर्ग उनके झंडे के नीचे आ जाय। प्रान्तीय पूंजीपति जब इस तरह के दावे करते हैं, तब उनका पर्दाफाश करना चाहिए।

प्रान्तीय पूंजीपतियों की नजर पड़ोसी इलाकों पर है। बिहार के प्रादिशासी इलाकों के लिए बंगाल और बिहार के पूंजीपतियों में झगडा है। बम्बई और मद्रास किसके हिस्से में होंगे, इसको लेकर झगडे हैं। श्री पट्टाभि सीनारमैया भी ब० मा० मुंशी के भाषायी साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हैं दोनों एक ही पैली के बट्टे-बट्टे।

सभी जातियों की श्रमिक जनता मजदूर वर्ग के नेतृत्व में केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों तरह के पूंजीपतियों तथा जमींदारों के खिलाफ संघर्ष करके हारति के लिए स्वतन्त्रतापूर्वक राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास का अधिकार सुनिश्चित कर सकती है। यही तरीका है कि बड़े पूंजीपति दूसरा पर अनिवार्य राजभाषा न लाद सकेंगे और सभी जातियों की भाषाओं को विपणित होने का पूरा अवसर मिलेगा।

हिन्दी-उर्दू-हिन्दुस्तानी समस्या

समस्या यह है कि हिन्दुस्तानी प्रदेश की भाषा हिन्दी, उर्दू या हिन्दुस्तानी में बोल-सी है या तीनों हैं या इनमें कोई दो हैं।

हिन्दी केवल हिन्दुओं की भाषा नहीं है, मुस्लिम जनता भी हिन्दी बोलती है। उर्दू भी केवल मुसलमानों की भाषा नहीं है। बुनियादी तौर से हिन्दी-उर्दू एक ही भाषा हैं। दोनों का आधार जनसाधारण की बोलचाल की भाषा है। इस बोलचाल की भाषा के सहारे के बिना न तो हिन्दी का एक वाक्य लिखा जा सकता है, न उर्दू का। उर्दूवाले कहते हैं, उनकी भाषा आम जनता की जवान है। वे ठीक कहते हैं, इस अर्थ में कि जनता की भाषा के बिना उर्दू का एक वाक्य नहीं लिखा जा सकता। हिन्दी उर्दू में भेद उनके बोलचाल के रूप में नहीं है, भेद है उनकी उच्च स्तरीय शब्दावली में। बोलचाल की एक ही भाषा की दो शैलियाँ हैं। उनके भेद का कारण यह है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अन्तर्गत हमारे देश की जातियों का विकास विषम रूप में हुआ है।

विदेशी पूंजी ने भारतीय सामन्तवाद को अपना दोस्त बनाया। उसने भारतीय उद्योग धन्यों का विकास रोका, आम जनता का बुरी तरह शोषण किया और उसे अशिक्षित रखा, जमींदारों का वर्ग बनाकर अपने लिए सहायक तैयार किये, यहाँ की भाषाओं के विकास को भरसक रोका और जनता पर

विदेशी भाषा नादी और उड़े पूँजीपतियों ने सौदा पक्का किया कि मिलकर देश का शोषण करें।

इस कारण ग्राम जनता सस्कृति के क्षेत्र में अपनी एकता का प्रभाव पूरी तरह न डाल सकी। पाश्चात्य शिक्षा, भाषा और साहित्य में बुद्धिजीवियों को जो भी प्रेरणा मिली हो, ग्राम जनता अपने साम्राज्य विरोधी, सामन्त-विरोधी, पूँजीवाद विरोधी दृष्टिकोण का प्रभाव सस्कृति पर नहीं डाल पाई। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने रायगाहों, रायबहादुरों, खानबहादुरों आदि की सेना तैयार कर ली और ये हिन्दी-उर्दू के नेता बन गए। इनके साम्राज्य-भरस्त दृष्टिकोण का प्रभाव भाषा के विकास पर भी पड़ा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद प्रत्यक्ष रूप से तथा अपने सहायकों के जरिये अप्रत्यक्ष रूप से भाषा और सस्कृति के मामलों में दखल देता रहा। भाषा और साहित्य में वह धार्मिक विद्वेष भड़काता रहा। प्रियर्सन का मत था कि इस्लाम के साथ उर्दू दूर-दूर तक फैली, उन्हे इस बात का ध्यान न रहा कि भारत में इस्लाम के प्रवेश के बहुत दिनों बाद उर्दू का विकास आरम्भ हुआ। प्रियर्सन ने यह नहीं बताया कि इस्लाम के साथ उर्दू भारत में ही क्यों आई, मिर, अलजीरिया, तुर्की या इस्लाम के घर घर में क्यों नहीं पहुँची?

ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने सामन्तवाद का शोषण किया। सामन्ती वर्ग की विशेष विचारधारा है पुनरावस्थापनवाद। इसके प्रभाव से धार्मिक और साम्प्रदायिक विभाजन मजबूत हुए हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत की हर जाति को ब्रिटिश मूँवा और देशी राज्यों में बाँट दिया। इस कारण जातियों की सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता टूट करने में सफल हुई।

भारत के नेता जब दुर्लभ तरीके से साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे थे, तब वे भाषा और सस्कृति को धर्म से परे मानते थे। वे कहते थे कि नागरी और फारसी लिपि में लिखी जानेवाली हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा होगी। वे साम्राज्यवाद से समझौता करने और जनवादी प्रान्ति के विरोध के रास्ते पर चले। साम्राज्यवाद के खिलाफ जनता में जहाँ प्रान्तिकारी उभार आया, उन्होंने उसे दबाया। उन्हें भय था कि विदेश साम्राज्य के स्वार्थ के साथ वही उनकी शोषण-व्यवस्था भी खत्म न हो जाय। कांग्रेस के भीतर और बाहर उन्होंने किसानों और मजदूरों के वर्ग संगठन बनाने का विरोध किया। किसानों और मजदूरों की एकता ही राष्ट्र की एकता को मजबूत कर सकती है, देश की हर जाति की भाषा और सस्कृति की एकता को मजबूत कर सकती है।

इस नीति के कारण राष्ट्रीय नेता राष्ट्र के साम्राज्यवादी विभाजन में ही समझौदार नहीं हुए, वे अपने अन्दर भी अन्ध राष्ट्रवादी रुझान पालते रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी फागिस्ट संस्थाओं से सहपं करने का दिखावा करते हुए वे उस तरह की प्रवृत्तियों को कांग्रेस के अन्दर ही पुष्ट करते रहे हैं। वे सामान्य सस्कृति और सामान्य भाषा की मीठी मीठी बातें मूल रूप से

चरम साम्प्रदायिक दृष्टान्तों का समर्थन करने लगे हैं। वे भाषा-विवाद जैसी चीजों का उपयोग इसलिए कर रहे हैं कि जनता जनतन्त्र और समाजवाद के लिए सघर्ष करना बन्द कर दे। भाषा-विवाद और प्रान्तों के विभाजन से सम्बन्धित झगड़े उनके हाथ में ऐसे अस्त्र हैं जिनसे जनता का ध्यान मुख्य सामाजिक समस्याओं से हटा दिया जाय। सामन्ती-पूँजीवादी शोषण कायम रखने के लिए वे जनता में फूट डालनेवाले साम्राज्यवाद के तमाम दाँव-पेंच इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए यह आशा करना व्यर्थ है कि वे इन समस्याओं को हल करने में रतीभर सहायता करेंगे। भारत में मजदूर वर्ग और उसके साथी किसान और मध्य वर्ग के लोग हर जाति की सामान्य सस्कृति और सामान्य भाषा का निर्माण करेंगे।

कानपुर या आगरा की एक ही मिल में काम करनेवाले हिन्दू और मुसलमान मजदूर क्या दो भाषाएँ बोलते हैं? उनकी भाषा एक है। उत्तर प्रदेश के किसान भी एक ही भाषा बोलते हैं और एक दूसरे की बात समझते हैं। अपने दफतरी और मुहल्लों में मध्यमवर्गीय कामकाजी लोग आपस में एक ही भाषा बोलते हैं। हर प्रदेश में हिन्दू और मुसलमान मजदूरों की भाषा एक है, हिन्दू और मुसलमान किसानों की भाषा एक है, मध्य वर्ग के कामकाजी हिन्दुओं और मुसलमानों की भाषा एक है। इस भाषा में स्वामीय भेद होते हैं किन्तु धर्म के आधार पर भेद नहीं पैदा होता। जब बोलचाल की भाषा साहित्य और उच्च सांस्कृतिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, तब उसकी शब्दावली में भेद पैदा हो जाता है।

हिन्दी-उर्दू विनिर्वादी तौर से एक हैं किन्तु अपने साहित्यिक रूपों में भिन्न हैं, यह अन्तर्विरोध सामाजिक अन्तर्विरोध का ही परिणाम है। साम्राज्यवाद ने सामन्तवाद कायम रखा और पूँजीवादी वर्ग में हिन्दू-मुस्लिम आधार पर भेद डाला। पूँजीवादी नेताओं की समझौतापरस्ती के कारण साम्राज्यवादी नीति सफल हुई। यह कहना कि बोलचाल की भाषा से उच्च शिक्षा और सस्कृति के सभी कार्य सम्पन्न किए जा सकते हैं, सामाजिक विकास के वास्तविक अन्तर्विरोध को अँधेरे में डूब लेना है।

हिन्दी और उर्दू को हिन्दू धर्म और इस्लाम से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता। उर्दू में ईरान और अरब की साहित्यिक परम्परा का अनुसरण है, उसकी साहित्यिक शब्दावली अरबी और फारसी के आधार पर रची गई है। हिन्दी की साहित्यिक शब्दावली का आधार संस्कृत है और वह भारत की साहित्यिक परम्परा का अनुसरण करती है। दोनों की ही साहित्यिक परम्परा में सामान्य जनवादी तत्व विद्यमान हैं और इन्हीं के आधार पर भविष्य में सामान्य साहित्यिक भाषा का विकास होगा। जो विशुद्ध धार्मिक तत्व हैं, वे विलीन हो जाएँगे, पुरानी गथाएँ, वेद-कथाएँ आदि सामान्य सांस्कृतिक परम्परा का अंग बन जाएँगी। हिन्दी और उर्दू में आज जो परस्पर-भिन्न साहित्यिक परम्पराएँ

दिखाई देती है, वे एक ही साहित्यिक भाषा और सामान्य साहित्यिक परम्परा के विकास में दुर्लभ्य भाषा नहीं हैं। जनसाधारण की उच्च सांस्कृतिक आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए (अर्थात् उन्हें दर्शन, राजनीति, धर्मशास्त्र आदि की शिक्षा देने के लिए) जनवादी आन्दोलन की बढ़ती के साथ दोनों के बीच का फासला दूर होगा।

बोलचाल की भाषा में केवल संस्कृत के या केवल धरवी फारसी के शब्द नहीं होते। साहित्यिक शब्दावली में शुद्धता की रक्षा न की जा सकेगी। राष्ट्रलजी ने सविधान का 'मसौदा' लिखा है जबकि डॉ० रघुवीर ने मसौदे के लिए 'प्राक्ष' लिखा है। कुछ लोग कहते हैं कि साहित्य की भाषा और जनता की भाषा में भेद अन्तर रहेगा। यह भेद उच्च वर्गों और जनसाधारण की संस्कृति का भेद प्रकट करता है। जनतन्त्र और समाजवाद की और प्रगति के साथ यह भेद भी मिट जाएगा। प्रगतिशील लेखक अब जन-सघर्षों को धामे बढ़ाने के लिए साहित्य रचते हैं, तब यह भेद खत्म हो जाता है या कम हो जाता है।

उदारपथी पूँजीवादी नेता हिन्दी-उर्दू को मिलाने में असफल हुए। वे यह न जानते थे कि दोनों में भेद क्या है। उन्होंने इस समस्या का सम्बन्ध आम जनता की सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रगति से नहीं जोड़ा, उन्होंने यह नहीं देखा कि इस समस्या का सम्बन्ध जनता की निरक्षरता दूर करने से है, जनसाधारण के लिए साहित्य और संस्कृति सुलभ करने से है, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के सहयोगियों ने बुद्धिजीवियों में जो पुनरुत्थानवादी कल्पना पैदा किये हैं, उनसे सघर्ष करने से हैं।

साम्प्रदायिक अनुपात लागू करने से (अर्थात् मुसलमानों आदि के जितने एम० एल० ए० होंगे, यह निश्चित करने में) हिन्दू-मुस्लिम समस्या हल न हो सकती थी। इसी तरह फारसी और संस्कृत के कोशों से किसी निश्चित अनुपात के अनुसार शब्द लेकर मिलाने से सामान्य साहित्यिक भाषा का विकास न हो सकता था।

दो लिपियों में लिखी जानेवाली हिन्दुस्तानी भाषा समस्या का कोई हल प्रस्तुत नहीं करती। दोनों लिपियों में यदि शब्दावली भिन्न है, तो हिन्दुस्तानी नाम देने से बेहिसाब भगड़े बढ़ते हैं। हिन्दी और उर्दू में धातु वास्तविक भेद है। यह भेद खत्म करके तुरन्त हिन्दुस्तानी नहीं बनी जा सकती। इसलिए अभी कुछ समय तक हिन्दी और उर्दू दोनों का चलन स्वीकार करना चाहिए जिससे कि स्वाभाविक रीति से दोनों मिलकर एक हो जाएँ।

पारिभाषिक शब्दावली की समस्या

लोग कहते हैं कि भारतीय भाषाएँ संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं। इसलिए हिन्दी का जितना ही संस्कृतीकरण होगा, वह सारे भारत में उतनी ही सुबोध और लोकप्रिय होगी। पिछले पाँच बी वर्षों का इतिहास बतलाता है कि भार-

तीय भाषाओं में असंस्कृत रूप निरन्तर विकसित होते गये हैं। ये रूप लोकप्रिय हैं, इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं। कहा जाता है कि बँगला में संस्कृत शब्द सबसे ज्यादा हैं। 'बँगला भाषा का उद्भव और विकास' नामक ग्रन्थ में डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी ने लिखा था, "आधुनिक बँगला के बोलचाल वाले रूप में संस्कृत शब्दों का अनुपात आश्चर्यजनक रूप से कम है" (गण्ड १, पृ० २२१)। कारण यह है कि "तद्भव शब्दों का सम्बन्ध दायें दिन के जीवन से है और भाषा में, कहना चाहिए, सबसे ज्यादा थम इन्हीं को बरन्ना पड़ता है।" (उप०, पृ० १६७-६८)

संस्कृत के शब्द अपने तद्भव रूप में सुरक्षित रहते हैं। दुरुतावादों के लिए ये शब्द प्रशुद्ध हो जाते हैं। न केवल बँगला में बरन् उन तमाम भारतीय भाषाओं में, जो संस्कृत से सम्बद्ध हैं, तत्सम शब्दों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से कम है। गम्भीरकरण द्वारा हिन्दी को लोकप्रिय बनाने की माँग मजबूत है और लोगों को उसका विरोध करना चाहिए। उर्दू को फारसी-गमित करना उर्दू के लिए हानिकारक है और उर्दू-प्रेमियों को उसका विरोध करना चाहिए।

इसका यह अर्थ नहीं है कि हिन्दी-उर्दू संस्कृत-फारसी से शब्द न लें। यह कार्य विवेक से, बोलचाल की भाषा की प्रकृति पहचानते हुए करना चाहिए। इसमें भाषा समृद्ध होगी और उसका लोकप्रिय रूप नष्ट न होगा। नये शब्द मढ़ने और उधार लेने के अलावा, बोलचाल की भाषा की रचनात्मक क्षमता को भूल न जाना चाहिए। हिन्दी-उर्दू की उच्च शब्दावली में अंग्रेजी शब्दों का प्रवेश भी बिलकुल बन्द न करना चाहिए।

कई लोग पारिभाषिक शब्दों के छोटे-बड़े कोश बना रहे हैं। वे कहते हैं कि जो शब्द प्रचलित है, वह पारिभाषिक नहीं हो सकता। सविधान के अनुवादक श्री धनश्याम सिंह गुप्त ने लिखा है, "सभी भाषाओं में लोक-प्रचलित शब्द अर्थ की दृष्टि से सिधिल और अनिश्चित होते हैं" "हर विशेष विषय की अपनी विशेष शब्दावली होती है और लोक-प्रचलित भाषा से यह उद्देश्य सिद्ध नहीं होता।" (भारतीय संविधान का प्रारूप, १९४८)

अज्ञानी हिन्दी पाठक की सहायता के लिए डॉ० रघुवीर ने सविधान के मसौदे के अन्त में शब्द-सूची दे दी है। इस सूची से बहुत अच्छी तरह पता चल जाता है कि पारिभाषिक तथा लोक-प्रचलित शब्दावली में किस तरह का सम्बन्ध है। शब्द-सूची के पहले तीन पृष्ठों में इस तरह के अंग्रेजी शब्द दिये हुए हैं—

ओपन, फायर-आर्म, प्रॉबिट, अलाउस, ऐक्ट, वारंट, ऐडवोकेट, मीटिंग, सीट, क्लेम, आर्टीनेन्स, आर्टीकल, नाइसेम, ग्रांट, प्रैक्टिस, फ्री, मेपटी, एजेण्ट, इंजीनियरिंग, रेलवे, भाइनर इत्यादि। ये शब्द अंग्रेजी में ही लोक-प्रचलित नहीं, उनमें से बहुतों को इस देश के अशिक्षित लोग भी समझते हैं। अधिपत्र, अधिष्ठान, अयोमार्ग क्या हैं? वारंट, सीट और रेलवे!

• यदि अंग्रेजी के लोक-प्रचलित शब्द उस भाषा में पारिभाषिक माने जा सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि उस नियम का पालन हिन्दी में न किया जाय। कठिन शब्दावली का फल यह होगा कि जनसाधारण शिक्षा और सस्कृति से दूर रहेंगे। दुख की बात यह है कि डॉ० रघुवीर के बनाये हुए बहुत-से शब्दों को उच्च शिक्षा पाये हुए लोग भी नहीं समझते। इस जड़ता को भारत के प्राचीन गौरव और राष्ट्रीय एवता के नाम पर न्यायपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। अपनी शब्द-सूची की भूमिका में डॉ० रघुवीर ने लिखा था, “हमने भौगोलिक ही नहीं, ऐतिहासिक दृष्टि से भी भारत की एकता का ध्यान रखा है। भारत के दीर्घकालीन गौरवमय अतीत में जो कुछ उपयोग्य था, उसे हमने प्राप्तसात् कर लिया है।”

वास्तव में उन्होंने जो कुछ किया है, वह इसका ठीक उलटा है। उन्होंने वे तमाम शब्द छोड़ दिये हैं, जो न केवल हिन्दी-भाषी प्रांतों में बरन् दक्षिण भारत तथा अन्यत्र समझे जाते हैं। ये शब्द उनके लिए पारिभाषिक नहीं हो सकते क्योंकि इनमें लोकप्रियता का दाग लग गया है। उन्होंने वे तमाम शब्द छोड़ दिये हैं जो अतीत में जनता के परस्पर सम्पर्क के कारण प्रचलित हो गये हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने डॉ० रघुवीर की झालोचना की है और उनके अनुवाद के बदले अपना अनुवाद प्रस्तुत किया है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि नये शब्द आवश्यक हैं और वे या तो दूसरी भाषाओं से लिये जायेंगे या प्राचीन भाषाओं के शब्दों, धातुओं के आधार पर गढ़े जायेंगे। जो लोग इन शब्दों का व्यवहार करेंगे, उनकी आवश्यकताएँ ध्यान में रखी जायें तो यह कार्य ज्यादा सन्तोषजनक ढंग से सम्पन्न होगा। सबसे पहले उन शब्दों का संग्रह करना चाहिए जिनका व्यवहार विभिन्न देशों के लोग पहले से ही कर रहे हैं। इसके बाद सस्कृत, फारसी या अंग्रेजी से झाल मँदकर शब्द न लेने चाहिए वरन् इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे बोलचाल की भाषा की प्रकृति के अनुकूल हैं या नहीं। ग्रीक और लैटिन के आधार पर बनाये हुए जो अंग्रेजी के शब्द यूरोप की अन्य भाषाओं में प्रचलित हैं, उन्हें विदेशी होने के कारण ही न छोड़ देना चाहिए। आवश्यकतानुसार उनकी जगह लोकप्रिय हिन्दुस्तानी शब्दों को दी जा सकती है।

हिन्दी-उर्दू की उच्च स्तरीय सांस्कृतिक शब्दावली देर में घुल-मिलकर एक होगी, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा की तरह हिन्दी-उर्दू की पारिभाषिक शब्दावली भी एक दिन मिलकर एक होगी, इसमें खरा भी सन्देह नहीं है।

लिपि का प्रश्न

लिपि भाषा का अभिन्न अंग नहीं है। यूरोप की अनेक भाषाएँ लैटिन वर्णमाला का व्यवहार करती हैं। निन्तु इससे वे मिलकर एक नहीं हो जाती। भारत में हिन्दी और मराठी की लिपि प्रायः एक-सी है, फिर भी दोनों भाषाओं

मे बहुत अन्तर है। इस दृष्टि से लिपि का प्रश्न गौण है। फिर भी लिपि-भेद होने से हिन्दी-उर्दू के बीच का फासला बड़ा है। यदि हिन्दी के पाठक उर्दू से और उर्दू के पाठक हिन्दी से परिचित होते तो यह फासला इतना न बड़ा होता। एक लिपि होने से उन्हें निकट लाने और मिलाने में सुविधा होगी।

एक लिपि की स्वीकृति स्वेच्छा में ही हो सकती है। फिर भी मजदूर वर्ग को आन्दोलन करना चाहिए कि एक ही लिपि का चलन हो जिसमें हिन्दी-उर्दू जल्दी-स-जल्दी घुल-मिलकर एक हो सकें। यह लिपि कुछ संशोधनों के साथ देवनागरी ही हो सकती है।

पिछड़ी हुई जातियों की भाषाओं का प्रश्न

भारत में मराठी, बंगला, तमिल, तेलुगु आदि सुविकसित भाषाओं के अलावा बालिया के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ किसी बोली ने विकसित होकर अभी भाषा का रूप नहीं लिया। इस तरह के क्षेत्रों में राजस्थान है। कुछ इलाक़ों में भी हैं जिनके लिए मड़ोमी प्रान्तों के पूँजीपतियों में आपस में झगडा है। बिहार के आदिवासी इलाक़ों के लिए बगाली और बिहारी पूँजीपतियों में झगडा है। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ लोग अभी आदिम समाज-व्यवस्था में ही रह रहे हैं। मध्यप्रदेश और राजस्थान के आदिवासी न अपना, न अपनी भाषाओं का विकास कर पा रहे हैं। इनकी भाषाओं के विकास की बात कोई हवाई सैद्धान्तिक प्रश्न नहीं है। यह उनके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का प्रश्न है। जनवादी आन्दोलन और मजदूर वर्ग को उनके राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए।

हर बोली या भाषा के लिए एक प्रजातन्त्र का सवाल

महापंडित राहुल सांकृत्यायन कुछ समय पहले तक यह माँग करते रहे हैं कि उन प्रदेशों में प्रजातन्त्र कायम किया जाय जहाँ भवधी, ब्रजभाषा, बुन्देलखण्डी आदि का चलन है। उनके चरणचिह्नो पर श्री शिवदानसिंह बले (देखिए उनकी पुस्तक 'प्रगतिवाद' में 'जनपद आन्दोलन' नामक निबन्ध), श्री व्योहार राजेन्द्र सिंह, श्री बनारसीदास चतुर्वेदी आदि जनपद-आन्दोलनों में योग देते रहे हैं। प्रश्न यह है कि भवधी, ब्रजभाषा बुन्देलखण्डी आदि बोलियाँ हैं या भाषाएँ, उनके बोलनेवाले हिन्दुस्तानी जाति के अन्तर्गत हैं या भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र जातियों के रूप में विकसित होंगे। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इनमें से हरेक के लिए प्रजातन्त्र या प्रान्त बनना चाहिए।

गाँवों में किसान भवधी, ब्रज आदि का व्यवहार करते हैं। शहरों के मजदूर, खास तौर से मिल्स और कारखानों के श्रमिक आपस में खड़ी बोली का व्यवहार करते हैं। बानपुर में उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, मोंडा और छपरा तक से मजदूर आते हैं। लखनऊ, आगरा और झाँसी के लोका वर्कशॉप, कार-

सानी भादि में इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों के मजदूर काम करते हैं। जो किसान सीधा गाँव से आकर मजदूर बना है, वह अपनी गाँव की बोली बोलता है और उसके साथी उसकी बात समझ लेते हैं। कुछ समय बाद वह शहर की बोली—खड़ी बोली—सीख लेता है और अपने साथियों से इसी में बात करता है, यद्यपि घर पर वह अपनी गाँव की बोली का ही व्यवहार करता है।

हिन्दुस्तानी प्रदेश के मजदूर वर्ग में अवधी, ब्रज भादि बोलनेवाले लोग हैं। इनका सामान्य परिवेश और सामान्य प्रायिक सम्बन्ध उन्हें एक सामान्य भाषा बोलने पर मजबूर करते हैं। यह भाषा खड़ी बोली या हिन्दुस्तानी होती है। अखबारों में पढ़ी लिखने के लिए, इस्तहारों के लिए भाँसी, आगरा, कानपुर और लखनऊ के मजदूर बुन्देलखण्डी, ब्रजभाषा या अवधी का व्यवहार नहीं करते। ये मजदूर हिन्दी-उर्दू का ही व्यवहार करते हैं और उनकी बोल्बोल में कोई भेद नहीं होता। शहरों के मध्यवर्ग का भी यही हाल है।

खड़ी बोली और फारसी के सघर्ष में खड़ी बोली (उर्दू) की विजय हुई। कविता में ब्रजभाषा का व्यवहार हो या खड़ी बोली का, इस सघर्ष में खड़ी बोली (हिन्दी) की विजय हुई। भारतेन्दु भोजपुरी क्षेत्र के थे, प्रतापनारायण मिश्र अवध के, राधाचरण गोस्वामी ब्रज के, इन सबने यक्ष के लिए खड़ी बोली को अपनाया। यह विकास उन्नीसवीं सदी में हुआ किन्तु उसका आरम्भ पहले ही चुका था। इस विकास का कारण या पूँजीवाद का विकास। भारत में पूँजीवाद उन्नीसवीं सदी में आरम्भ नहीं हुआ। व्यापारी पूँजीवाद उन सीधे-गरी के साथ शुरू हुआ जो अपने साथ खड़ी बोली मुदूर हैदराबाद ले गये। ब्रिटिश पूँजीवाद में टक्कर होने पर भारतीय पूँजीवाद के सहज विकास में बाधा पड़ी लेकिन यह रुक नहीं गया। पूँजीवाद के विकास के साथ हम मिलते और कारखानों में मजदूरों की खड़ी बोली बोलते देखते हैं। बेहात में जहाँ सामन्ती सम्बन्ध अब भी दृढ़ हैं, वहाँ भाषायी एकीकरण का यह काम पूरा नहीं हुआ। मध्यवर्ग पूँजीवादी विकास का ही परिणाम है और किसानों की अपेक्षा यह वर्ग खड़ी बोली को अधिक अपनाता है। इसी कारण हिन्दी-उर्दू लिखने में ऐसे लोग हैं जो घर में खड़ी बोली में घसम भन्म कोई बोली भी बोलते हैं। श्री मैथिलीशरण गुप्त घर में बुन्देलखण्डी, श्री राहुल साहू रायन भोजपुरी, श्री शिवमगसिंह 'सुमन' और अली सरदार जाफरी अवधी बोलते हैं, या पहले बोलते थे।

इसका अर्थ यह है कि उपर्युक्त बोलियों के बोलनेवाले पूँजीवाद के विरास के साथ एक ही जाति में संघटित हुए हैं, एक ऐसे स्थायी जन समुदाय के रूप में गठित हुए हैं जिसकी सामान्य भाषा है और सामान्य प्रायिक जीवन है। यह विकास पूरा नहीं हुआ। सामन्ती सम्बन्ध अभी बने हुए हैं। इसीलिए हिन्दुस्तानी प्रदेश में भाषा और बोली का प्रश्न भी हमारे सामने आता है। खड़ी बोली

‘भाषा’ बनी, ब्रज, अवधी आदि ‘बोलियाँ’ रही। यह प्रक्रिया अनोखी नहीं है। जिन देशों में भी सामन्ती सम्बन्धों की जगह पूँजीवादी सम्बन्ध विकसित हुए हैं, वहाँ इसमें मिनती-जुलती प्रक्रिया देखने को मिली है। लन्दन के आस-पास की अंग्रेजी, पेरिस के आस-पास की फ्रांसीसी, मास्को के आस-पास की रूसी सामाजिक सम्पर्क और मादरिण की भाषा बनी। ब्रिटेन में वेल्श जैसी भाषा अंग्रेज़ी के मुकाबले और फ्रांस में प्रोवांसाल जैसी समृद्ध साहित्यिक भाषा फ्रांसीसी के मुकाबले बोली की हैसियत हो पा सकी।

समाज में किसान या मजदूर वर्ग के कुछ हिस्से अपनी बोली छोड़ते नहीं हैं या टकसाली भाषा के साथ उमका भी व्यवहार करते हैं, तो यह भारत में होनेवाली कोई अद्भुत क्रिया नहीं है। फ्रांस जैसे विकसित पूँजीवादी देश में भी बोलियों का अस्तित्व है। भाषाविद वान्द्राई ने अंतों बोली के बारे में लिखा है “मछुप्रो में, तराई के नमक बनानेवालों में, स्टेट-मजदूरों और घुमन्तू सीदागरो में वे लोग का व्यवहार अब भी होता है और कोई नहीं कह सकता कि कब तक होता रहेगा” (वान्द्राई, भाषा, लन्दन, १९३१, पृ० २८६)। मेइये के अनुसार इसी प्रकार फ्रांस और स्पेन में वास्क का व्यवहार होता है। इसलिए इसमें आश्चर्य न होना चाहिए कि हिन्दुस्तानी प्रदेश में टकसाली भाषा के अलावा भी अनेक बोलियों का चलन बना हुआ है।

भाषा और बोली का भेद केवल भाषागत भेद नहीं है, वह सामाजिक भेद भी है। किसी समय हमारे यहाँ ग्रजभाषा और फ्रांस में प्रावांसाल समृद्ध साहित्यिक भाषाएँ थी। पूँजीवाद के विकास के साथ दिल्ली, मेरठ तथा पेरिस के आस-पास की बोलियों को व्यापारी दूर-दूर तक ले गये। बोलियों ने भाषा का रूप लिया। जिन क्षेत्रों में अवधी, ब्रज आदि बोलियाँ अभी बोली जाती हैं, उनकी टकसाली भाषा खड़ी बोली है। इस टकसाली भाषा के कारण—साम्राज्यवाद और पूँजीवाद के बावजूद—यहाँ की जनता सीमित विकास कर सकी है। इन क्षेत्रों के मजदूर टकसाली भाषा यानी खड़ी बोली के जरिये एक-दूसरे के निकट आते हैं। इस तरह इस टकसाली भाषा का विकास जनवादी क्रान्ति की विजय के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है ‘जनयुग’ और ‘नया जमाना’ अवधी, ब्रजभाषा आदि में निकाले जाएँ तो इससे मजदूरों की एकता दृढ़ न होगी। मैंने ‘जनयुग’ के लेख अवधी में उल्था करके उन्नाव और रायबरेली के किसानों को सुनाये हैं, यह देखने के लिए कि उनकी शब्दावली में कितना परिवर्तन करना पड़ता है। व्याकरण-रूपों को छोड़कर ६८ फीसदी शब्दावली वही रहती है। ये बोलियाँ एक-दूसरे के इतना निकट हैं कि यदि एक ही लेख—खास तौर से अक्षवारी लेख—का उल्था उनमें करें तो ६८ फीसदी इबारत एक-सी होगी। ये बोलियाँ मुहावरों, सुन्दर अर्थ-व्यञ्जक शब्दावली और अलंकृत वचनों में समृद्ध हैं। टकसाली भाषा के लेखक इनसे बहुत-कुछ सीख सकते हैं। इनमें अछूता खजाना है जिसे अपनाने से टकसाली भाषा की

व्यंजना-शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ेगी । लेकिन इसका यह अर्थ विलुप्त नहीं है कि इनका व्यवहार करनेवालों को हम स्वतन्त्र जातियाँ मान लें ।

श्री राहुत साहूत्यायन तथा अन्य लोगों की यह माँग कि धवधी, ब्रज, मुन्देलखण्डी आदि को विभिन्न जातियों की टक्काली भाषा माना जाय, प्रति-क्रियावादी माँग है । यह माँग केवल सामन्ती वर्गों के हित में है जो इस तरह एक पतनशील व्यवस्था की रक्षा करना चाहते हैं । इस माँग से हिन्दुस्तानी प्रदेश के मजदूरों की एकाग्रता में बाधा पड़ती है ।

हर बोली के लिए एक प्रजातन्त्र या प्रान्त बनाने का मकान नहीं है । सोवियत संघ में ६० से ऊपर भाषाएँ हैं, प्रजातन्त्र इनसे बहुत कम है । धवधी, ब्रज आदि विभिन्न जातियों की भाषाएँ होती, तो भी उनके लिए हर जगह प्रजातन्त्र कायम न किये जाते । वे बोनियाँ हैं, इसलिए उनमें से हरेक के लिए प्रजातन्त्र बनाने की माँग विशेष रूप से हास्यास्पद है । औरछा के महाराज जनपद आन्दोलन में खास दिलचस्पी लेते रहे हैं, यह बात आकस्मिक नहीं है ।

भारत में भाषा समस्या के ये कुछ मुख्य पहलू हैं । (१९४६)

जातीय भाषा के रूप में हिन्दी का प्रसार

जातीय भाषा बनने से पहले हिन्दी या खड़ी बोली एक जनपद की भाषा थी। ब्रज, अवध, बुन्देलखण्ड आदि जनपदों में ब्रज, अवधी, बुन्देलखण्डी आदि भाषाएँ बोली जाती थी। इन जनपदों में रहनेवाले छोटी-बड़ी रियासतों में बैठे हुए थे। वे सब किसी जाति में संगठित न हुए थे और इसीलिए एक जातीय भाषा के रूप में उनके पास भाषा की व्यवहार की कोई भाषा न थी। कुछ पढ़े-लिखे लोग सस्कृत से काम चलाते थे लेकिन उसे आम जनता न तो समझती थी, न बोलती थी।

सब के समाज की दो विशेषताएँ ध्यान देने योग्य हैं। एक तो यह कि समाज चार वर्गों में बँटा हुआ था जिनके अन्तर्गत सैकड़ों जात-विरादरियाँ थी। दूसरी यह कि गाँव बहुत-कुछ खुदगुस्तार थे, ऊपर से आधी तूफान निकलते रहें, ये छोटे-छोटे पंचायती राज अपनी जगह बंदस्तूर कायम रहते थे।

तेरहवीं-चौदहवीं सदी में सामन्ती समाज का यह ढाँचा ढीला पड़ने लगा था, वर्णव्यवस्था शिथिल हो रही थी और लोग अपने खानदानी पेशे छोड़कर नये पेशे अपनाने लगे थे। तुर्कों के हमलों से यह ढाँचा और कमजोर पड़ा हालाँकि उसे तोड़नेवाली ताकतें उसके भीतर ही पैदा हो रही थी। तिलक जो हिन्दी और फारसी दोनों जानता था और अबुलहसन और महमूद गजनवी की सेवा में रहा था, एक नाई का सडका था। ग़ुलाम नाम का एक बनिया परिवार राजा से किला छीनकर इल्तमश से लड़ा था (कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, खण्ड ३, पृ० ५३)। गुजरात में तगी चमार ने दिल्ली के बादशाह के खिलाफ विद्रोह की अगुआई की। हेमू, जिसने अकबर का मुकाबला किया था, बनिया था। अकबर का चित्रकार दसवन्त बह्दार था। रामानन्द के शिष्यों में कबीर जुलाहा, रंदास चमार और सेना नाई थे। कबीर के उत्तराधिकारी धरमदास बनिया थे। दादू के लिए कहा जाता है कि वह मोची थे। उनके शिष्य सुन्दरदास बनिया थे और मलूवदास खत्री थे। इस तरह की और भी मिसालें दी जा सकती हैं। इससे नतीजा यही निकलता है कि सस्कृति पर अब ब्राह्मण-

पुरोहिताँ का इजारा टूट रहा था, राज्य और धरती पर क्षत्रियो का अधिकार ढीला पड़ रहा था ।

तुर्क बादशाहों ने बाजार, तोलने के बाँट, सिक्को आदि के बारे में जो सुधार किये, उनसे सौदागरों को फायदा पहुँचा । इस ज़माने में नई-नई महियाँ और नये-नये शहर आबाद हुए । फीरोज तुगलक के लिए बहा जाता है कि उसने फीरोज़ाबाद, फतहाबाद, फीरोज़पुर, बदायूँ, जौनपुर आदि शहर बसाये । शेरशाह के ज़माने में पटना शहर फिर व्यापार का केन्द्र बना । उसने समय में जो सबकुँ और नहरें तैयार हुईं, उनसे व्यापार बढ़ा । शेरशाह ने सराएँ बनवाई धार्मिक उदारता की नीति धरती, और खास बात यह कि राज्य और किसान के बीच सीधा सम्बन्ध कायम किया । पहले गाँव का मुखिया मालगुजारी तय करता था, उसका वह हक छिन गया । इस तरह एक तरफ तो सौदागरी और व्यापार के केन्द्रों के तौर पर शहर बढ़ती पर थे, दूसरी तरफ गाँवों की खुद-मुस्तारी पर पाबन्दी लगी । अकबर ने बालूद का महत्व समझा । राज्य में शान्ति कायम रखने के लिए, अपने खाय तौर से बालूद का भरोसा किया । सामन्ती युग के तीर-कमान और तलवार पुरानी चीजें बनत जा रह थे । अकबर ने सारे राज्य में एक-सी मुद्रा-व्यवस्था चलाकर व्यापार की बढ़ती में मदद की । तन्मवाह के लिए जागीरों की लेकिन मालगुजारी बगैरह तय करने का हक जागीरदारों को नहीं दिया । कभी-कभी उन्हें जागीर से दूर भी तैनात कर दिया जाता था । इस तरह सामन्तों और जागीरदारों की ताबत कम हुई । धार्मिक मामलों में अकबर ने उदार नीति धरती ।

मुगल बादशाहों को खुद भी व्यापार से दिलचस्पी थी । अकबर खुद व्यापार करता था । लखनऊ यूनिवर्सिटी के डॉ॰ पत के अनुसार गुजरात, आगरा और कश्मीर के बढिया उद्योगों का इजारा उसके हाथ में था । शाहजहाँ ने नील का व्यापार अपने हाथ में रखा था और मनोहरदास की राज्य से उधार रकम देकर व्यापार करने की आज्ञा दी थी और मुनाफे में हिस्सा लेता था । नूरजहाँ को भी नील और जरी के बस्तियों के व्यापार में दिलचस्पी थी । बादशाहों के भाई-भतीजे सौदागरी से धन कमाते थे । मुगल राज्यसत्ता की घामदनी का जरिया सिर्फ़ जमीन न थी, बल्कि व्यापार भी था ।

व्यापार की उन्नति से पुराने जनपदों का घलगाव दूर हुआ । पटना, बनारस, इनाहाबाद, आगरा और दिल्ली ऐसे केन्द्र बन गये जिनके चारों तरफ एक बीसी बाजार कायम हुआ । यात्री मानरीवे के अनुसार सन् १६४० में आगरा की आबादी छ. लाख थी । मार्क्स ने भारतीय इतिहास पर अपनी पुस्तक में लिखा है कि अकबर के ज़माने में दिल्ली दुनिया का सबसे बड़ा शहर था । जो नया बाजार कायम हुआ, उसके सबसे बड़े केन्द्र आगरा और दिल्ली ही थे ।

ब्रिटेन में हिन्दुस्तानी बपड़े की माँग बढ़ने से यहाँ का रोजगार और कमरा । सत्रहवीं सदी के पहले हिस्से में आगरा से विलायत बपड़ा भेजा जाता

था और यह कपड़ा भवध से बनकर आता था। इस तरह बज और भवध एक बाजार में संगठित हुए। खुद भवध में दरियावाद और खैराबाद अपने उद्योगों के लिए मशहूर हुए। इसी तरह पटना, बनारस, लखनऊ बगैरह ने घास-पास के देहात को अपनी तरफ ममेटा और उनका पुराना अलगाव बहुत-कुछ दूर किया। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने जिन मुगल कारखानों का जिक्र किया है, मुमकिन है कि वे पूंजीवादी पैदावार की पहली मजिल रहे हों। बहरहाल जुलाहा को सौदागर पेशगी रुपया देते थे और उनसे तैयार माल लेते थे। पेशगी लेने पर जुलाहा अपने माल पर अधिकार खो देता था। पेशगी के जरिये सौदागर उसकी श्रमशक्ति खरीद लेता था। यह पैदावार का पूंजीवादी तरीका था। सन् १८४४ में एंगेल्स ने अपनी पुस्तक 'इंग्लैंड के मजदूर वर्ग की दशा' में लिखा था "मशीनें चालू होने से पहले कच्चे माल को काटने और बुनने का काम मजदूर के घर पर होता था।" सत्रहवीं सदी में यह सिलसिला यहाँ भी कायम था। लेनिन ने मिखाइलोव्स्की को जवाब देते हुए बतलाया था कि सत्रहवीं सदी में आपसी विनिमय की बढ़ती से, बिकाऊ माल के चलन के धीरे-धीरे तेज होने से, और छोटे-छाटे बाजारों के एक बड़े बाजार में सिमटने से इसी जाति का निर्माण हुआ। सत्रहवीं सदी में इसी तरह हमारे यहाँ भी हिन्दुस्तानी जाति का निर्माण शुरू हुआ था।

भाषा और साहित्य के क्षेत्र में हम जनपदों का एक-दूसरे के नजदीक आना और उनका अलगाव दूर होना देखते हैं। 'रामचरितमानस' भवधी में लिखा गया है, लेकिन ब्रज, भोजपुरी आदि के इलाकों में भी वह अपनाया जाता है। यही नहीं, गोस्वामीजी ब्रज और भवधी दोनों में कविता करते हैं और उनकी भाषा में एक से अधिका बोलियों के शब्द और प्रयोग देखे जा सकते हैं। उधर ब्रजभाषा की कविताएँ—भीरा, मूर, रसखान और रहीम की रचनाएँ दूर देहात तक पहुँच रही थीं। खड़ी बोली में भी खुसरो, कबीर आदि रचनाएँ करने लगे थे। रहीम ने किसी की खड़ी बोली में ही पाँच मंजर लिखा था—भुक्-भुक् मतधाना गावना रेवता था।

दक्कन में खड़ी बोली का अलग विकास हुआ, गद्य और पद्य दोनों में यह प्रदेश मुख्यतः तेलुगुभाषी था और खड़ी बोली यहाँ कम तादाद के लोगो की भाषा थी। उत्तर की भाषा पर उसका असर कुछ देर से पड़ा।

दार्जिलिंग में व्यापार और विनिमय के लिए जिस भाषा का उपयोग होता था, वह भाषा खड़ी बोली या हिन्दी थी। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि देश-विदेश के जो लोग काम-काज के लिए दिल्ली या आगरा आते थे, वे यही भाषा सीखते थे। ग्रियर्सन ने लिखा है कि "उन दिनों के कुछ अंग्रेज सौदागर नि सन्देह घडल्ले से हिन्दुस्तानी बोल सकते थे..." (लिम्बिस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, सप्ट १, पृ० २)। और इतिहासकार सरदेसाई ने लिखा है कि इतालवी यात्री मनुन्ची ने शिवाजी में, बिना किसी दम्पिये की मदद के, उर्दू में

वातचीत की। फारसी के दबाव की वजह से यह भाषा पहले-पहल दक्खिन में फूली-फली।

हिन्दुस्तान में जो तुर्क, पठान, ईरानी, उजबक आदि जातियों के लोग आये, वे यहाँ किसी नई भाषा की जन्म न दे सके। उनके बहुत-से शब्द यहाँ वालों ने ले लिये, उनके प्रत्यय लगाकर कुछ नये शब्द भी गढ़े—जैसे पागलताना, झफीमची (घोर पिछले दिनों जगवाड़) बगैरह। लेकिन हमारी भाषा की व्याकरण व्यवस्था, उसके मूल शब्द-भण्डार में कोई भारी तबदीली नहीं हुई। तुर्कों, पठानों, ईरानियों, उजबकों आदि के आने ॥ पहले भी हिन्दी भाषा थी, उसके हिन्दुस्तानी बन जाने के बाद भी रही। इसलिख बाइसाहा के लम्बे-रो में नई जवानों गढ़न की कल्पना भ्रामक है।

बाहर से आनेवाले लोगों के शब्दों से हमारी भाषा और समृद्ध हुई लेकिन उसने अपने जातीय रूप की रक्षा की। भाषा के बारे में शेरशाह और अकबर की नीति अंग्रेजों की तरह अनुदार नहीं थी। शेरशाह ने तो फारसी के साथ हिन्दी में काम बज करने की हिदायत दे रखी थी।

प्रजभाषा अरबी, खड़ी बोली आदि सभी न हिन्दुस्तानी जाति के निर्माण में मदद दी। हमारी जाति का चरित्र सषणों द्वारा और पक्का हुमा। इन सषणों के दो पहलू थे, एक तो जातीय, दूसरा जनवादी। यानी एक तरफ तो यहाँ के लोग बिदनी आततायियों के खिलाफ लड़े, दूसरी तरफ वे सामन्ती उत्पीड़न के खिलाफ, वण व्यवस्था और पुरोहिता-सामन्ती के विषय अधिकारों के खिलाफ भी लड़े। भास्त आन्दोलन में ये दोनों पहलू मौजूद हैं। जुलाह और किसान इस आन्दोलन की शक्ति देनेवाले हैं। सोदागर उसके सहायक हैं, हिन्दू और मुसलमान, सूफी और मत दानों उसमें शामिल हैं। भक्ति-आन्दोलन एक जातीय और जनवादी आन्दोलन है। क्या उस समय हिन्दुओं और मुसलमानों की दो संस्कृतियाँ थीं? कुछ धार्मिक भेदभाव जरूर था लेकिन दो संस्कृतियाँ नहीं थी। जायसी, रसमान, रहीम, आलम, शेख, पजनेस बगैरह की वही संस्कृति थी जो गूर, मीरा, तुलसी, नन्ददाम, दादू, रैदास आदि की थी। यह संस्कृति जातीय और जनवादी थी, इसीलिए बबीर को हिन्दू और मुसलमान दोनों अपनाते के लिए तैयार थे। दरबारा की संस्कृति अलग थी। मुगल राज्यसत्ता इस जनवादी संस्कृति को आश्रय देनेवाली न थी।

हिन्दुस्तान के लोग सामन्ती डाँचा लम्ब करके अपनी जातीय राज्यसत्ता कायम कर रहे लेकिन तभी अंग्रेजों की दखलबन्दाजी से उनकी ऐतिहासिक प्रगति में बाधा पड़ी।

उन्तीसवीं सदी में अंग्रेजों ने हिन्द प्रदेस को अपने अधिकार में लिया। हिन्दुस्तान में ऐसी परिस्थितियाँ थी जिनसे फायदा उठाकर उन्होंने भाषा और संस्कृति के मामलों में दखल देना और यहाँ के लोगों में फूट डालना शुरू किया।

महाराष्ट्र, आन्ध्र, बंगाल, पंजाब आदि में वे परिस्थितियाँ न थीं जो हिन्दी-भाषी इलाके में थी। महाराष्ट्र में शिवाजी एक जातीय रियासत कायम कर चुके थे। वैसे कोई कोशिश यहाँ न हुई थी। शिक्षा का कोई मिला-जुला जातीय क्रम निश्चित न था, मुस्ला-पंडितों के हाथ में अब भी शिक्षा की जिम्मेदारी थी। इस धार्मिक शिक्षा की वजह से दो लिपियों का प्रयोग होता था और भाषा की एकता के हिसाब से सब जगह एक ही लिपि का चलन न था। मुगल साम्राज्य के उखड़ने के बाद नवाबों के अड़्डे ज्यादातर हमारे इलाके में रहे। बंगाल, महाराष्ट्र, आन्ध्र, बंगौरह इनसे अपेक्षाकृत मुक्त रहे। हैदराबाद में उर्दू के प्रसर से तेलुगु भाषा में कुछ तबदीली हुई, लेकिन उस हद तक नहीं कि तेलुगु में हिन्दी उर्दू की तरह दो धाराएँ चल पड़ें।

अंग्रेजों ने जिस चलन से फायदा उठाया और उसे गहरा बनाया, वह यहाँ की धार्मिक शिक्षा और सामन्ती पिछड़ेपन की वजह से था। बहुत-से राज-दरबारों में ब्रज भाषा के आगे नयी जातीय भाषा हिन्दी की पूछ न थी, नवाबों के यहाँ खड़ी बोली के लोकप्रिय रूप और जनवादी कविता की कद्र न थी। इस तरह खड़ी बोली में दो धाराएँ चल निकली—एक तो लोकप्रिय धारा, दूसरी सामन्ती के आश्रयवाली धारा। कुछ कवियों ने साधारण भाषा के शब्दों के बहिष्कार की नीति अपनायी जिससे उनकी शैली बोलचाल की भाषा से अलग मालूम होने लगी।

अंग्रेजी ने इस भेद को और गहरा किया। गिलग्राइस्ट ने हिन्दुओं और मुसलमानों की अलग भाषाओं के सिद्धान्त की रचना की। रिजले न धर्म के आधार पर दो कौमों की और ग्रियर्सन ने भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में फूट के उसूल की धार्मिक रूप दिया। सर सैयद ने लश्करो में नयी भाषा बनने की तजवीज पेश की। इकबाल ने मुस्लिम कौम और मुस्लिम संस्कृति का नारा लगाया। ये सब साम्राज्यवादी विषयों के फल थे।

अंग्रेजों के राज में गाँवों की पुरानी व्यवस्था तो टूटी लेकिन उन्होंने सामन्तवाद और सामन्ती संस्कृति को मजबूत भी किया। इसी अर्जर सामन्ती संस्कृति पर उन्होंने अपनी तहजीब का ताज रखा। हिन्दीभाषी इलाके की उन्होंने कई सुबों में बीटा, यहाँ ताल्लुकदारों और नवाबों को पाला-पोसा, और भाषा के मामले में जातीय उत्पीड़न का एक नया तरीका निकाला। कभी हिन्दुओं को दबाया, मुसलमानों को उभारा, कभी हिन्दुओं को उभारा और मुसलमानों को दबाया। कचहरी, अदालत और पुलिस में वह जवान चलाई कि किसान कभी मगझ ही न सके और उसे ठगने और लूटने में उन्हें आसानी हो। इस तरह एक तरफ उर्दू की धारा बही, दूसरी तरफ हिन्दी की। फिर भी भाषा के बुनियादी शब्दों और मूल व्याकरण-व्यवस्था के बिना कोई भी धारा आगे न बढ़ सकती थी।

हिन्दी उर्दू का भेद उन्नीसवीं सदी में पहले नगण्य है। उन्नीसवीं सदी में

अंग्रेजी राज कायम होता है और सभी यह भेद गहरा होता है। इसलिए उस भेद के लिए सबसे ज्यादा अंग्रेज ही जिम्मेदार हैं। अगर सूफियो और सन्तो की परम्परा जिम्मेदार होती तो इस तरह की दो धाराएँ बगल, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह में भी बहती दिखाई देती। वहाँ नहीं दिखाई देती, यह इस बात का प्रमाण है कि हिन्दी-उर्दू का भेद अस्थायी है, जो जनता के स्वाधीनता-आन्दोलन की बढ़ती के साथ कम होते-होते मिट जाएगा। आखिर अभी तो साल भी तो दस पाई की नहीं हुए।

हिन्दीभाषी इनाके में सामन्ती अवशेष कायम रखकर, हिन्दी-उर्दू के सवाल में साम्प्रदायिता उभारकर, एव ही भाषा की दो धाराएँ बहाकर और दोनों पर अंग्रेजी लाइन, आम जनता को अशिक्षित रखकर अंग्रेजों ने हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को भारी नुकसान पहुँचाया है।

फिर भी हर जगह उनकी मनचीती नहीं हुई। हिन्दुस्तानी जनता ने आमानी में उनका जुगा स्वीकार नहीं किया। १८५७ में दिल्ली, मेरठ, बानपुर, भौंसी आदि शहरों में और अवध, भोजपुरी, बुन्देलखण्ड आदि जनपदों के वीरों ने अंग्रेजों के दाँत खट्टे कर दिए। अगर अंग्रेजों को हिन्दुस्तानियों से ही मदद न मिलती तो देश का इतिहास ही दूसरा होता। हमारे साहित्यकारों ने जनवादी सस्कृति की परम्परा को निवाहा। हिन्दी उर्दू के लेखकों के सहयोग की अंग्रेज खतम नहीं कर पाए। भारतेन्दु, प्रतापनारायण मिश्र, बालमुकुन्द गुप्त, जो आधुनिक हिन्दी के निर्माता हैं उर्दू के भी लेखक थे। प्रेमचन्द ने उस परम्परा को और आगे बढ़ाया।

कांग्रेस और लीग के नेताओं ने कान्तिरारी जन-आन्दोलन का तो विरोध किया, लेकिन साम्राज्यवादियों की स्वाधीनता-योजना स्वीकार की। भारतीय जनता से भय खाकर अंग्रेजों ने अपना झंडा और अपनी कौज तो हटा ली लेकिन अपने पूँजीवादी पजे देश में और भी गढ़ा दिए।

अंग्रेजी पूँजी का हित इस बात में है कि बँटवारे के बाद कायम की हुई दोनों रियासतें आपस में लड़ें या उनमें तनातनी रहे जिससे कि लोगों का ध्यान छिपे हुए मुठेरों की तरफ न जाय। इसके लिए उन्होंने दंगे कराए, कश्मीर को लड़ाई कराई और साम्प्रदायिक दलों के जरिए तनातनी कायम रखी।

साम्प्रदायिकता से फायदा उठाकर पाकिस्तान के शासकों ने वहाँ की भाषाओं को दबाया और उन पर उर्दू लादी। हिन्दुस्तान के साम्प्रदायिकों ने कहा कि अब तो उर्दू पाकिस्तान गई और यहाँ उसकी बात करना भी राष्ट्र-द्रोह है। राजपि टडन और महाशक्ति राहुन ने इस विपक्षे प्रचार का नेतृत्व किया। उत्तर भारत के सूबों में हिन्दी ठीक ही, राजभाषा घोषित की गई, लेकिन उर्दू के व्यवहार और शिक्षा आदि में तरह-तरह के झड़गे लगाये गए।

हिन्दी के कुछ लेखक इस परिस्थिति को सन्तोषजनक समझते हैं। लेकिन उर्दू को दबाने से हमारी जातीय भाषा के विकास में बाधा पड़ती है, इसलिए

इस परिस्थिति को संतोषजनक कैसे कहा जा सकता है? उर्दू में पौत्रप्रिय साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है। उसमें बोलचाल के मुहावरों का निबन्धन हमारा रूप ही नहीं है, हमारी भाषा और साहित्य का इतिहास उसके बिना अधूरा रहेगा। इसलिए अपनी जानि के सांस्कृतिक इतिहास के लिए, अपनी जातीय भाषा के विवास के लिए मैं उर्दू के दवाने का विरोध करता हूँ।

कांग्रेसी नीति के खिलाफ उर्दू के कुछ सेपरातो ने विधान की सहायता लेते हुए इलाहाबाद खान का सवाल उठाया है। हिन्दी में अलग उर्दू का कोई अलग इलाका नहीं है हालाँकि उर्दू या हिन्दी को अपनी एकमात्र साहित्यिक भाषा समझनेवाले लोग हैं। इसलिए उर्दू के पढ़ने-पढ़ाने और उसे व्यवहार में लाने में जो भी बाधाएँ आती हैं, उन्हें दूर करने के लिए आवाज बुलन्द करना सभी जनवादियों का कर्तव्य है। उसे अलग इलाहाबाद खान मानना गलत है।

हिन्दीभाषी इलाके की जनता के लिए किसानों में शिक्षा का सवाल भाषा की समस्या के साथ जुड़ा है। किसानों को ग्राम शिक्षा किस लिपि में दी जाय? अगर किसानों को एकजुट करना है, उनकी राजनीतिक चेतना को विकसित करना है, उनके आन्दोलन को राष्ट्रीय आन्दोलन की धुरी बना देना है तो ग्राम शिक्षा के लिए दो लिपियाँ रखना हाज़िराव होगा। इसलिए मेरी राय है कि देवनागरी लिपि के जरिये ग्राम जनता में शिक्षा के प्रचार पर जोर देना चाहिए।

अंग्रेजों ने १८५७ से सबर तोवर हमारे इलाके को सबसे ज्यादा दुकड़ों में बाँटा है। सदियों से एक साथ रहनेवाले आगरा और दिल्ली भी अलग हो गए। हिन्दीभाषी इलाका एक होना चाहिए। इसके बारे में यह कहना भी नहीं चल सकता कि बड़े सूबे का छोटे सूबों में हम बाँटना चाहते हैं। यहाँ सवाल छोटे दुकड़ों को मिलाकर बड़ा सूबा बनाने का है। अलग-अलग प्रांतीय सभाएँ और हुकूमतें चलाने का खर्च बचेगा, व्यापार और उद्योग अन्धों की तरफ़ी में मदद मिलेगी। हमारा सांस्कृतिक आन्दोलन पूरे प्रदेश में जातीय पैमाने पर चलेगा और भाषा भी अपना जातीय रूप निखार सकेगी।

किसान-आन्दोलन की बढ़ती के लिए यह आवश्यक है कि शोलियों में साहित्य रचा जाय; अभी भी यह रचा जा रहा है। लेकिन हर जनपद के लिए अलग सूबा या प्रजातन्त्र बनाने की माँग करना जातीय प्रदेश के बाँटवारे को दूसरे रूप में कायम रखना है। इससे सावधान रहना चाहिए।

हिन्दीभाषी लेखकों का हित इस बात में है कि वे भाषावार प्रान्त-निर्माण के आन्दोलन का समर्थन करें, दूसरों की गर्जों के खिलाफ़ उन पर हिन्दी भाषा लादने का विरोध करें। इससे दूसरी भाषाओं के लोग उनकी जातीय एकता के आन्दोलन का समर्थन करेंगे। उन्हें इस भ्रम में कि संस्कृत-गर्भित होने से हिन्दी दक्षिण में ज्यादा समझी जाएगी, अपनी भाषा को बिगड़ने न देना चाहिए। संस्कृत-गर्भित हिन्दी के पक्षपाती साहित्य-सम्मेलन ने दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार का काफ़ी अहित किया है। वहाँ पर हिन्दी का प्रचार किया है

‘दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा’ ने जिसकी नीति सम्मेलन में भिन्न है।

हिन्दीभाषी इलाका भारत का सबसे बड़ा ज्ञानीय इलाका है। सत्या के विचार से हिन्दुस्तानी जाति दुनिया की तीन-चार सबसे बड़ी जानियों में गिनी जाएगी। ऋग्वेद और महाभारत की रचना इसी प्रदेश में हुई है। यही की नदियों के किनारे वाल्मीकि और तुलसी ने अपने अनुष्टुप और चौपाइयाँ गाई हैं। तानसेन और ययाज राी, हाली, भीर, अकबर, गालिब, भारतेन्दु, प्रेमचन्द, निराला यही के रत्न हैं। ताजमहल और विद्वनाथ के मन्दिर यही के हाथों ने गढ़े हैं। आल्हा और बजली ने सैकड़ों साल तक यहीं का आवाज गुंजाया है। पठारह सौ सत्तावन में यही की धरती हिन्दुओं और मुसलमानों के खून से सींची गई है। जिन दिन यह विशाल हिन्दी प्रदेश एक होकर नये स्वाधीन जनजीवन का निर्माण करेगा, उस दिन इसकी मस्जिदें एशिया का मुख उज्ज्वल करेगी। किसानों और मजदूरों की एकता जा जाता की एकता की घुरी है, वह दिन निकट लाएगी। हिन्दी और उर्दू के लेखकों को इस जनता के हितों को ध्यान में रखकर अपनी जातीय परम्परा के अनुसार लोकप्रिय भाषा और जनवादी साहित्य के विकास में योग देना चाहिए।

(१९५३)

हिन्दी-उर्दू समस्या

अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का तनाव दूर करने के लिए शान्ति प्रेमी जनता जोर-जबर्दस्ती के बदले समझौते की बातचीत का रास्ता पसन्द करती है। भारतीय शान्ति-प्रान्दोलन के नेताओं ने भी तीसर महायुद्ध की तैयारियाँ रोकने के लिए समझौते की बातचीत चयन पर जोर दिया है।

मेरा विचार है हिन्दी-उर्दू समस्या को लेकर जो तनाव पैदा किया गया है, उसे दूर करने के लिए भी समझौते की बातचीत चयन और छुरेबाजी को प्रोत्साहन न देना श्रेयस्वर हो सकता है।

पिछले दिनों उर्दू प्रेमियों की तरफ से उर्दू को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मानने और उसने लिए क्षेत्रीय भाषा के अधिकार माँगने के बारे में आन्दोलन हुआ था। उस आन्दोलन के जवाब में कुछ हिन्दी प्रेमियों की तरफ से भी आन्दोलन हुआ और सलाह में उर्दू प्रेमियों के सम्मेलन के अवसर पर एक उर्दू-प्रेमी को एक हिन्दी प्रेमी ने छुरा मारकर उस अस्पताल भेज दिया।

आप मानेंगे कि टैंक और ऐटम बम का खतरा न होने पर भी सखनऊ जैसे शान्तिप्रेमी नगर में यह काह्र होना जाहिर करना है कि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय तनाव दूर करने के लिए वमबाजी का रास्ता बुरा बताया जाता है, वैसे ही भाषा की समस्या हल करने के लिए छुरेबाजी का रास्ता भी बुरा समझा जाना चाहिए।

उत्साह पैदा करनेवाले आन्दोलन अक्सर अर्द्धसत्यो को लेकर चलते हैं। इसमें शक नहीं कि बहुत-से उर्दू-प्रेमियों में सम्प्रदायवादी भी हैं, और पहले भी रहे हैं। लेकिन इस बात को लेकर अर्द्ध सत्यप्रेमी सज्जन यह नतीजा निकालते हैं कि सभी उर्दूवाले सम्प्रदायवादी हैं, उर्दू का जन्म ही सम्प्रदायवाद से हुआ है पाकिस्तान का जन्म भी उर्दू के कारण हुआ है (भले ही पूर्वी पाकिस्तान के लोग उर्दू को राजभाषा बनाने के खिलाफ लड़े हों) और इसलिए जितना ही जल्दी उर्दू को मिटाया जाय, उतना ही अच्छा।

इसमें भी शक नहीं कि हिन्दी प्रेमियों में बहुत से सम्प्रदायवादी हैं और पहले भी रहे हैं। ये, वन इस बात से उर्दू-खेमे के अर्द्ध सत्यप्रेमी यह नतीजा निकालते

है कि सभी हिन्दी प्रेमी सम्प्रदायवादी हैं, हिन्दी का जन्म ही सम्प्रदायवाद से उर्दू के मोठे सरल शब्दों को निवालकर उनको जगह सस्कृत के कवच-पत्थर भरकर हुआ है। हिन्दी को बिहार या उत्तर प्रदेश की राजभाषा बना दिया गया है, यह हिन्दी प्रेमियों की साम्प्रदायिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है।

इसी तरह हिन्दी-सेमे के अर्द्ध सत्यप्रेमी उर्दू-विरोध को राष्ट्रीयता की पहली पातें मानते हैं। यह उर्दू-विरोध जल्द ही मुस्लिम-विरोध का रूप ले लेता है और उकसावा पैदा करनेवाली 'दलीलें' दी जाती हैं जिन्हें सुनकर मालूम होने लगता है कि जनता की भूलमारी, भ्रष्टिदा, भ्रकात और भहामारी का एकमात्र कारण उर्दू है।

उधर उर्दू-सेमे के अर्द्ध-सत्यप्रेमी उर्दू को हिन्दी से और दूर लोचकर, हिन्दुस्तानी जनता के सांस्कृतिक इतिहास से और दूर ले जाकर, इस्लाम से उर्दू का सम्बन्ध अपनी समझ में और पक्का करके, भलगाव की भावना को और मजबूत करते हैं। समूची हिन्दुस्तानी जनता कैसे साधारण होकर अपनी मिली-जुली संस्कृति, अपना मिला-जुला लिखित साहित्य अपने बठाएगी, अवधी, ब्रज, बुन्देलखण्डी, भोजपुरी आदि से हम अपनी भाषा के लिए क्या लेंगे, कैसे उसे सोलह करोड़ के लिए सुलभ बनाएंगे ये समस्याएँ उनके लिए हैं ही नहीं। उल्टा वे किसी महा अश्लील पत्रिका की बिन्नी का हवाला देकर पूछेंगे, 'कहिए, आपके यहाँ कोई पत्रिका इतनी बिबती है?' या अपने बड़प्पन की डींग हाँकेंगे, 'हमने जितना बमाव हासिल किया है उतना किसी ने किया ही नहीं है।'।

उर्दू सेमे के ये अर्द्ध-सत्यप्रेमी भाषा और निराशा के बीच झूलते खाते हैं। कभी तो वे उर्दू के अजर-अमर होने की बात सोचकर गद्गद् हो उठते हैं और कभी उसका विनाश निश्चित समझकर बैसे ही उदास और परेछान हो जाते हैं।

किसी जिले या सूबे की ध्यान में रखकर हिन्दी-उर्दू की समस्या स्थायी रूप से हल नहीं की जा सकती। यह समस्या सभी हल होगी जब हम हिन्दी प्रेमी और उर्दू-प्रेमी दोनों समूची हिन्दुस्तानी जाति के राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनर्गठन की समस्या के सन्दर्भ में उस पर विचार करेंगे। सवाल यह है कि जैसे तेलुगू, मराठी, तमिल या बन्नड़ भाषाएँ बोलनेवाले अपने अपने प्रदेश में अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनर्गठन करने के लिए उठ खड़े हुए हैं या उठ खड़े हो रहे हैं, वैसे ही क्या हिन्दुस्तानी लोग भी मुगल और ब्रिटिश राज के अपने भलगाव को खत्म करके एक जातीय प्रदेश में अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनर्गठन के लिए उठेंगे? या वे अपनी सामान्य समस्याएँ भलग-भलग अपने जिले और सूबो में ही उलझाते-मुलझाते रहेंगे?

अभी पिछले दिनों भाषावार प्रान्त बनाने के सितसिक्के में जो सम्मेलन हुआ, उसमें और भाषाओं के प्रतिनिधियों ने तो अपने जातीय झगड़ों के पुनर्गठन की बात उठाई लेकिन हिन्दुस्तानी प्रदेश का सवाल वहाँ उठा ही नहीं। इसका सवय यह है कि हिन्दुस्तानी जनता का प्रदेश और जातियों के प्रदेश से बड़ी ज्यादा

बैठा हुआ है, यहाँ भी जातीय चेतना ४१ वभी हिन्दी-उर्दू विवाद से, कभी भोज-पुरी या मैथिली प्रान्त के आन्दोलन से, वभी बिहारी-बंगाली फसाद से सही रूप में विकसित होने नहीं दिया गया।

हिन्दी-उर्दू समस्या को लेकर जो लोग साम्प्रदायिक प्रचार करते हैं, वे हिन्दुस्तानी जनता की जातीय चेतना पर सबसे पहले प्रहार करते हैं।

हिन्दी-उर्दू के अर्द्ध-सत्यप्रेमी हिन्दुस्तानी जाति के प्रदेश का सवाल, उसके राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनर्गठन का सवाल नहीं उठाते, यह बात आकस्मिक नहीं है। वे सारे हिन्दुस्तान में हिन्दी फैलाने के लिए कटिबद्ध हैं, लेकिन जब दक्षिण के लोग उनसे पूछते हैं—हिन्दी किस प्रदेश की भाषा है, तो वे बगलें भाँकने लगते हैं।

यह बात आकस्मिक नहीं है कि हिन्दी खेमे के कुछ अर्द्ध-सत्यप्रेमी हिन्दुस्तानी जाति के इलाके को 'बोलियों के आधार पर ग्यारह हिस्सों में बाँट देने का प्रचार करते हैं। 'भाषा' के आधार पर वे प्रान्त-निर्माण की बात नहीं करते वरन् 'बोली' के आधार पर एक जातीय प्रदेश के बटुत-से टुकड़े करने की बात करते हैं।

समूचे हिन्दुस्तानी प्रदेश को ध्यान में रखते हुए हिन्दी-उर्दू समस्या पर विचार किया जाय, तो ये परिणाम निकलते हैं—

१. जहाँ तक साधारण जनता की बोसधाग का सम्बन्ध है, हिन्दी-उर्दू का कोई भेद नहीं है।

२. हिन्दी-उर्दू का भेद लिखित भाषा के मासिले में उठता है।

३. उर्दू को लिखित भाषा के रूप में काम में लानेवाले लोग ग्राम तौर से सम्प्रदायवादी नहीं हैं। वास्तव में कुछ हिन्दू सम्प्रदायवादी भी लिखित भाषा के रूप में उर्दू का प्रयोग करते हैं। उर्दू का प्रयोग करनेवाले सब मुसलमान ही नहीं, गैर मुसलमान भी हैं।

४. लिखित भाषा के लिए जो लोग हिन्दी का प्रयोग करते हैं, उनकी सख्या उर्दू का प्रयोग करनेवालों से ज्यादा है। इससे नतीजा यह निकलता है कि हिन्दुस्तानी प्रदेश में एक 'सांस्कृतिक अल्पमत' लिखित उर्दू का प्रयोग करता है।

५. व्यवहार में इस सांस्कृतिक अल्पमत की जरूरतों का ध्यान रखा जाता रहा है, जैसे फिल्मों में हिन्दी लिपि के साथ उर्दू का प्रयोग, अनेक गैर-साम्प्रदायिक संगठनों का उर्दू पत्र निकालना (जिनमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल है)।

हिन्दी खेमे के अर्द्ध-सत्यप्रेमी यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि उर्दू एक सांस्कृतिक अल्पमत के काम में आनेवाली लिखित भाषा है। वे इस सत्य को दोहराकर कि जनता की भाषा यानी 'बोलचान की भाषा' एक है, इस बात से इन्कार करते हैं कि लिखित भाषा में आज भेद है और उर्दू एक सांस्कृतिक अल्पमत की जरूरतें पूरी करती है।

इमलिए वे हिन्दी को राजभाषा बनाकर उर्दू के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहते हैं जिससे लिखित भाषा के एकीकरण का सवाल एक दूसरे से सीखकर, कुछ आपस में आदान प्रदान करके हल न हो, बल्कि एक लिखित रूप को दबाकर हो।

उर्दू खेमे के अर्द्ध-सत्यप्रेमी यह मानने में इन्कार करते हैं कि समूचे हिन्दूस्तानी प्रदेश में उर्दू का व्यवहार एक लिखित भाषा के रूप में एक सांस्कृतिक अल्पमत करता है। वे यह मानने से इन्कार करते हैं कि सवाल सांस्कृतिक अल्पमत की लिखित भाषा की रक्षा करने, उसमें उपयोग की सुविधाएँ देने का है। वे सभी राजराज के लिए दोनों लिपियों के चलन की बात कहते हैं, कभी उसे क्षेत्रीय भाषा मानकर उसमें लिए दिल्ली, भोपाल और लखनऊ का 'क्षेत्र' बूढ़ने लगते हैं।

उर्दू खेमे के ये दोस्त हवीजन पहचानने में गलती करते हैं, जिससे हिन्दी-खेमे के सम्प्रदायवादी ही मजबूत होते हैं, उर्दू की रक्षा और उसके व्यवहार की सुविधा देने का असली प्रश्न टल जाता है।

लिखित भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग हमारे प्रदेश में बहुसंख्यक लोग करते हैं। इमलिए उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है कि एक ही लिखित भाषा के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार करने में मदद दें। इस काम में एक बाधा यह प्रचार है कि लिखित भाषा के रूप में उर्दू को दबाने में हमारी भाषा-समस्या सुलझ जाएगी। जो लोग इस तरह का प्रचार करते हैं, वे अर्द्ध-सत्य का सहारा लेकर लिखित उर्दू के सामन्ती साहित्य, उसकी ईरानी परम्पराओं का हुवाला तो देते हैं लेकिन निम्नलिखित उर्दू के जनवादी और लोकप्रिय साहित्य के बारे में खामोश रहते हैं या मरामर झूठा प्रचार करते हैं।

सन् '४७ के बाद हिन्दी खेमे के सम्प्रदायवादियों ने नये सिरे से जोर मारा है। राजनीतिक जीवन से उससे होने पर कुछ सज्जन भाषा को लेकर सम्प्रदायवाद का प्रचार करने लगे। कुछ मित्रों की यह भ्रम है कि ऐसे लोग केवल भाषा के मामले में सम्प्रदायवादी हैं, बाकी मामलों में असाम्प्रदायिक और जनवादी हैं।

इस तरह की धारणा बनाते हुए बहुत सतर्क रहना जरूरी है।

सन् '४७ में—भारत विभाजन के बाद—राहुलजी ने हिन्दी-उर्दू समस्या के सिलसिले में ही कहा था—

“इस्लाम को भारतीय बनना चाहिए—उनका भारतीयता के प्रति यह विद्वेप सदियों से चला आया है सही, किन्तु नवीन भारत में कोई भी धर्म भारतीयता को पूर्णतया स्वीकार किये बिना फल-फूल नहीं सकता।”

बात थी उर्दू की, नतीजा निकला कि “उनका भारतीयता के प्रति यह विद्वेप सदियों से चला आया है,” यानी मुसलमान मूलतः राष्ट्र-विरोधी हैं।

और 'आज की राजनीति (१९५०) में राहुलजी ने हिन्दी-उर्दू समस्या

के सिलसिले में ही लिखा था—

“इस्लाम ने जो भी कहा हो किन्तु मुसलमानों ने अपने को देश की धारा का अंग मानने से सदा इन्कार किया।”

बात थी उर्दू की, नतीजा निरला कि मुसलमानों ने अपने को इस देश की धारा का अंग ही न समझा।

घोर भी, उसी पुस्तक में राहुलजी कहते हैं—

“इस्लाम का भारतीयकरण करना ही हितकर होगा। मौलाना आजाद की यह मनोवृत्ति यदि भारतीय मुसलमानों में रही, तो उनकी भविष्य तथा महानुभूति हमेशा भारत की अपेक्षा पाकिस्तान के साथ रहेगी। यह भावना भारतीय मुसलमानों को छिपा पचमागी बनाकर छोड़ेगी।

यदि मुसलमान पचमागी बन रहे हैं तो उनके साथ व्यवहार भी वही होगा जो देशद्रोहियों के साथ होता है। हिन्दू मुस्लिम दंगे कराने के लिए इसमें क्या-क्या कहा जा सकता है? आप कहेंगे, यह तो आपा-सम्बन्धी मनोवृत्ति को लेकर लिखा गया है।

मान लिया, आपा-सम्बन्धी मनोवृत्ति को तोवर लिया गया है, लेकिन इस किताब में युधिष्ठिर नाम का पात्र—जो राहुल उवाच की जगह सूत्रधार का काम करता है—कहता है, आप कुरान को उठाकर किसी धर्म के प्रमुख ग्रन्थ से मिलाकर देख लीजिए, वह हर तरह से मित्रकोटि का जैचेगा।”

अब आप पता लगाएँ कि दुनिया के तमाम मुसलमानों के धर्मग्रन्थ से हिन्दी उर्दू समस्या का क्या सम्बन्ध है।

देलिए, राहुलजी का केवल भाषा के मवाल पर सम्प्रदायवादी होना अक्स ठीक करने के कैंस मुन्दर नतीजे तक पहुँचता है।

हमारे अनेक शुभ विचार रखनेवाले भाइयों ने राहुलजी का विरोध करना तो दूर उनकी पीठ थपथपाई कि आप वास्तव में प्रगतिशील विचारक हैं। उनका खयाल था कि राहुलजी का पर्दाफाश करने में सयुक्त मोर्चा टूट जाएगा (राहुलजी की नीति से उन्हें सयुक्त मोर्चे के लिए कोई भय न था), इसलिए कभी तो वे उनके भाषा सम्बन्धी प्रचार को आदर्श कहते रहे, कभी चुप रहे और कभी घेरे जाने पर बाल कि राहुलजी को सम्प्रदायवादी कहने से क्या होता है, सभी हिन्दी लेखक जैसा ही सोचते हैं।।।

इस अवसरवादी नीति को, साम्प्रदायिकता को, तरह-देन का नतीजा यह हुआ कि राहुल जी के चरणचिह्न पर चलनेवाले और ‘प्रगतिशील’ लेखक भी आगे आ रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में उर्दू को क्षेत्रीय भाषा बनाने के आन्दोलन के सिलसिले में ‘उत्तर प्रदेश भाषा समिति’ लखनऊ ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के नाम एक आवेदन पत्र छपवाया था। इसमें कहा गया था—

"हम इस प्रदेश की भाषा के बंटवारे और भाषा की बाँटार जनता में फूट डालन की विपत्ती साम्प्रदायिक नीति का घोर विरोध करते हैं। यह प्रवृत्ति जन विरोधी, राष्ट्रीयता-विरोधी और देशद्रोही है।"

जब कोई प्रवृत्ति 'देशद्रोही' बरार दी जाएगी, तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा ? भाषेदन-पत्र न ऐसा वातावरण तैयार करने की कोशिश न की जिससे हिन्दी-उर्दू लेखक बैठकर समस्या पर विचार करते और उसे सुलभाने की कोशिश करते। उर्दू-प्रेमियों न क्षेत्रीय भाषा के लिए जैसे हिन्दी लेखकों से सलाह माँगी कि वे बिना भाषा-दोलन छेड़ दिया था और उर्दू की रक्षा की सही माँग का क्षेत्रीय भाषा की गलत माँग से उलझा दिया था, वैसे ही और उससे पचास बरस पहले वदर उत्तर प्रदेश भाषा समिति ने इन उर्दू प्रेमियों की कोशिश का देशद्रोह करार दे दिया।

इससे खुले सम्प्रदायवादियों ने फायदा उठाया और छुरेबाजी के लिए वातावरण पैदा कर लिया।

अब यह स्पष्ट हो गया होना कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की तरह भाषा-सम्बन्धी मामलों में भी उगसावे की नीति के वदन सुनह-समझौते की बातचीत चलाना क्यों जरूरी है।

भाषेदन-पत्र पर भाषा समिति के मन्त्री की हैसियत से सुप्रसिद्ध प्रगतिशील बलाकार मन्थाल के दस्तखत हैं।

मन्थालजी यह प्रद-गत्य मानकर कि हिन्दुस्तानी जनता की एक भाषा है, उसके दो लिखित रूपों की प्राज्ञ की आवश्यकता को सिर्फ एक लिपि-रूप रख-कर तुरन्त खत्म कर देना चाहते हैं। उनके विचार से हिन्दी-उर्दू के प्रादान-प्रदान का सवाल नहीं है। समझा-बुझाकर एक लिपि चलाने का सवाल नहीं है। सवाल है दो में से एक ही रूप रखकर समस्या को हल करने का। हिन्दी-उर्दू की समस्या को जोर-बदवन्ती से हल करने का समर्थन करते हुए मन्थालजी कहते हैं—

"दमन और जबरन यके अप्रिय शब्द हैं। हम इन शब्दों को सदा ही अपने विरोधियों के गले मर्दते हैं। लेकिन किसी भी नियम या अनुशासन को दमन और जबरन बह दिया जा सकता है। अनिवार्य शिक्षा भी एक प्रकार का दमन और जबरन है और पैदावार के गायनों का राष्ट्रीयकरण तो बहुत बड़ा दमन और जबरन बताया जाएगा।"

(‘नया पथ’—सितम्बर, १९५३)

वहाँ राष्ट्रीयकरण, वहाँ हिन्दी-उर्दू समस्या। पहले तो भारत में पैदावार के साधनों के राष्ट्रीयकरण का सवाल ही नहीं उठता और जहाँ उठता है या उठा है, वहाँ कामचोर वर्गों की मिलियत खत्म करने को उठा है। क्या जो लोग लिखित भाषा के लिए उर्दू काम में लाते हैं, कामचोर वर्गों के लोग हैं ? मन्थालजी की उपमा ही जाहिर करती है कि उन्होंने कामचोर वर्गों की वास्त-

हिन्दी उर्दू

विक्रम समरया मुलावर (और ये वर्ग मिलित भाषा के लिए हिन्दी-उर्दू दोनों का प्रयोग करते हैं ।) तमाम उर्दू-प्रेमियों को—या लिखित भाषा के लिए उर्दू-प्रयोग की मुविधा चाहनेवालों को—कामचोर-वर्ग बना दिया है और उन्हें अधिकारहीन करने का फैसला कर लिया है ।

अनिवार्य शिक्षा का चलन करने पर दमन और जबर जनता पर नहीं होता बल्कि उन कामचोर वर्गों पर होता है जो जनता को निरक्षर रखते हैं । राष्ट्रीयकरण में जो व्यवहार कामचोर वर्गों के साथ होता है, उसकी तुलना जनता को अनिवार्य शिक्षा देने से बरके यशपालजी ने जनता और शोषक वर्गों का भेद मूला दिया है ।

जब तक हमारे कुछ लेखक यह प्रचार करते रहेंगे कि जोर-जबर्दस्ती से हल करने पर लिखित भाषा की एकता कायम हो जाएगी, तब तक वह एकता उतनी ही दूर चली जाएगी, जनता में फूट डालनेवाले भाषा के सबाल को प्रेम से इस्तेमाल करेंगे और इस सबसे हिन्दुस्तानी जनता के राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनर्गठन का मयाल—हिन्दी प्रदेश के एकीकरण का सवाल—खटाई में पड़ा रहगा ।

यह समझना भूल होगी कि सभी हिन्दी-लेखक राहुलजी या यशपालजी की तरह सोचते हैं ।

अगस्त, १९५३ की 'अवन्तिका' ने सम्पादकीय नोट में इस बारे में लिखा है ।

'अवन्तिका' उर्दू को किसी क्षेत्र की अलग भाषा नहीं मानती । लेकिन वह उस स्वदेशी भाषा मानती है, राहुलजी की तरह अरब जेहादियों का कीर्ति-स्तम्भ नहीं । वह उसके विकास में बाधा देने का विरोध करती है, जोर जबर्दस्ती से राष्ट्रीयकरण या इस्लाम के भारतीयकरण का सवाल नहीं उठाती ।

इससे यह परिणाम निकलता है कि उक्तावा पैदा करनेवाला वातावरण खरम करके अगर हिन्दी-उर्दू के जनवादी लेखक इस समस्या को सुलझाने बैठें तो ऐसा हल निकल सकता है, जिसमें किसी के साथ जबर भी न हो और क्रमशः हमारे हिन्दुस्तानी प्रदेश में एक लिखित भाषा के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ भी तैयार हो जाएँ ।

(१९५३)

भाषा और प्रान्तीयता

इस बार ममियों में जब कलकत्ता गया तो लगा, शहर कुछ बदला-सा है। बँगला-भाषी मित्र बँगला छोड़कर ग्राम तीर से दूसरी भाषा में बात न करते थे। कुछ लोगों ने यह शिष्यायत भी की कि बस या ट्राम में किसी बंगाली बडकटर से हिन्दी में टिकट माँगे तो वह टिकट न देगा या उपेक्षा दिखलाएगा, दफतरो में हिन्दी बोलकर काम बनाने जाओ तो बीस बिगुवे काम होगा नहीं। एक साहित्य प्रेमी ने कहा, “भाष जो कुछ हिन्दी भाषण में कहते हैं, उसे प्रेमी भी कहें, हम उसमें बँगला साहित्यकारी और प्रोफेसरों को भी बुलाएँगे, उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि हिन्दी में क्या है।”

एक बँगला भाषी हिन्दी-प्रचारक मित्र ने कहा, “भाषके यहाँ से कुछ लोग आकर हमारा काम चौपट कर जाते हैं। यहाँ आकर रहते हैं, ‘बँगला में है क्या ? रबीन्द्रनाथ ने जो कुछ लिखा है, पबीर से।’ घरे बाबा, भाष लोग हिन्दी हिन्दी क्या चिल्लाते हो ? है क्या आपकी हिन्दी में ? और हिन्दी-प्रचार तो हम राजा राममोहन राय के समय से कर रहे हैं जब आपने यहाँ लोग हिन्दी-प्रचार का नाम भी न जानते थे।”

एक चौहत्तर वर्ष के प्रान्तिकारी, विचारक और लेखक न पूछा, “हिन्दुस्तान के भविष्य के बारे में क्या सोचते हो ?” मैंने कहा, “इस प्रश्न का उत्तर तो मुझसे अच्छा आप दे सकते हैं। मेरी समझ में हमारा भविष्य उज्ज्वल है।” उन्होंने कहा, “गृह-युद्ध होवाला है।” पूछा, “किसमें ?” मेरे मन में आया, धायद मजदूर-पूँजीपतियों की लड़ाई की बात सोचते होंगे। लेकिन वह बोले, “हिन्दुस्तानियों और बंगालियों में युद्ध होगा।” सुना था, कुछ दिन पहले बंगाली और हिन्दुस्तानी ट्राम-मजदूरों में झगड़ा हो चुका था। प्रत्यक्ष में प्रेमियों और बंगालियों के दर्शों की बात भी पढ़ चुका था। इसलिए गृह-युद्धवाली बात मैं हँसकर टाल न सका।

कलकत्ता की लगभग आधी जनता हिन्दुस्तानी है। यहाँ के मागवाही व्यापारी आपस में राजस्थानी बोलते हैं लेकिन शिक्षा, भाषण, प्रकाशन आदि

के लिए हिन्दी ही काम में लाते हैं। एक ओर तो ये बड़े बड़े व्यापारी हैं, दूसरी ओर अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि बोलनेवाले पूर्वी हिन्दीभाषी प्रदेश के लोग हैं जो ज्यादातर मेहनत-मजदूरी के सहारे जिन्दगी बसर करते हैं। शाम को अपने डेरो पर ढोल-मंजीरा या खंजरी या हुड्डुवा लेकर ये अपने लोकगीत गाते हैं। बंगला और हिन्दीभाषी भद्रजन समान रूप में इन्हे असम्भ्य और असंस्कृत समझकर इनसे प्रायः घृणा करते हैं। इनके अलावा बहुत-से अध्यापक और लेखक हैं, जिनमें से अधिकांश का उद्देश्य बलवत्ता आकर पैसा कमाना है, साहित्य-सेवा करना नहीं।

ऐसी स्थिति में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, यह भाषा लोगो के मन में बड़ी जल्दी पैदा होता है। इसका नतीजा यह होता है कि देश की विभिन्न जातियाँ आपस में मिश्रता बरतने के बदले एक-दूसरे से बैर मानने लगती हैं, एक-दूसरे से सीखने के बदले अपने बड़प्पन की झींग हाँकने में सारा समय लगा देती हैं। जहाँ तक साहित्य का सम्बन्ध है, यहाँ की जातियाँ एक-दूसरे से सहयोग बरके ही उसे सँवारती रही हैं और आगे भी उसे सँवार सकती हैं। सूर और तुलसी के युग में यहाँ के सांस्कृतिक आन्दोलन बराबर एक प्रदेश के बाहर के लोगो को भी प्रभावित करते रहे हैं। यदि ये व्यापक आन्दोलन न होते तो न सूर के पद रचे जाते, न चण्डीदास के। इसी तरह आधुनिक काल में देशभक्ति की जो लहर सारे देश में फैल गई, उसमें अनेक जातियो के लेखको का हाथ था। इसलिए किसी भी भाषा के साहित्य पर गर्व करते हुए उसके प्रेमियो को यह न भूल जाना चाहिए कि उसका विकास दूसरो के सहयोग से ही सम्भव हुआ है और उसमें मिलती-जुलती विशेषताएँ दूसरो के साहित्य में भी हैं।

जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध है, वास्तविक स्थिति यह है कि बंगाल आदि राज्यों में बँगला-जैसी समृद्ध भाषाएँ भी वहाँ के राजकाज की भाषाएँ नहीं बनीं। अंग्रेजी का बोलबाला अब भी है और तनाव अंग्रेजी और देशी भाषाओं के बीच नहीं, हिन्दी और यही की दूसरी भाषाओं के बीच है। हिन्दी-प्रेमियों का हित इस बात में है कि बँगला आदि भाषाएँ राजकाज के लिए अपने देश में पूरी तरह काम में लाई जाएँ। जब तक अहिन्दी-भाषी प्रदेशों में वहाँ की भाषाएँ अपने पूर्ण अधिकार नहीं पाती तब तक उनके बीच हिन्दी भी पूरी तरह परस्पर व्यवहार का माध्यम नहीं बन सकती। इससे विपरीत उन्हें डर रहेगा कि हिन्दी हमारी जगह छीनना चाहती है।

इधर शिक्षा के माध्यम को लेकर जो विवाद चल पड़े हैं, उनसे परिस्थिति और बिगड़ गई है। कई जगह यह प्रचार किया गया है कि किसी भाषा-विशेष के बदले हिन्दी ही शिक्षा का माध्यम बनेगी। तर्क यह होता है, हर जगह हिन्दी शिक्षा का माध्यम न होगी तो विश्वविद्यालय आपस में ज्ञान विनिमय न कर सकेंगे, विज्ञान की उन्नति न हो सकेगी, देश की सांस्कृतिक एकता टूट जायगी, इत्यादि। इस स्थिति से लाभ उठाकर अंग्रेजी-भक्त कहते हैं—“यह सब बहस

वेकार है, सबसे भली भयेंजी, इसने नया ज्ञान भी मिलेगा, पारिभाषिक शब्द
 गढ़ने की समस्या भी न रहेगी और भारत की एकता भी बनी रहेगी ।” इसपर
 कुछ विश्वविद्यालय इस और बाकी सरकरमी दिमा रहे हैं । विभिन्न भाषा-
 सेवों में जितना ही यहाँ की भाषाओं के हक मारे जाएँगे, उतना ही भयेंजी
 उनके मिर पर सवार रहेगी, यह बात असंदिग्ध है । आवश्यकता इस बात की
 है कि देश की भाषाएँ समान अधिवार पाकर बिगड़ित हो और इनके बोलन-
 वाले धनार्जनीय व्यवहार के लिए हिन्दी अपनाएँ, मादित्य के क्षेत्र में बढप्पन
 की झोड लगाने के बदले भारतीय साहित्य की सामान्य विशेषताओं को भी
 पहचानें और एक-दूसरे से सीखने की बात मोखें । यद्यपि कुछ पढ़े-लिखे लोगो
 और घनी जनो में जातीय द्वेषभाव बाकी बड़ा हुआ है, तथापि जनसाधारण
 में परस्पर प्रेम और देशभक्ति के भाव कितने दृढ़ हैं, इसका एक प्रमाण गोसा
 का सत्याग्रह है । इस छोटे-से प्रदेश को मुक्त कराने के लिए बंगला, मराठी,
 पंजाबी, हिन्दी आदि अनेक भाषाएँ बोलनेवाले नौजवानों ने अपने प्राणों की
 बाजी लगा दी । किसी ने यह सोचकर भाषा-पीछा नहीं किया कि गोसा के
 लोगो की भाषा तो कोकणी या मराठी है, हम उनके लिए क्यों जान दें । पन्द्रह
 अगस्त के बाद देश में जो व्यापन प्रदर्शन हुए वे भी इसी जातीय सहयोग और
 देश-प्रेम के सूचक हैं । जनसाधारण में यह भाईचारे का भाव देश की बहुत बड़ी
 सांस्कृतिक निधि है । यही वह शक्ति है जो देश को जातीय द्वेष के मार्ग से
 हटाकर प्रेम, समानता और सहयोग के मार्ग पर ले जायगी । इसके बिना न
 तो समूचे देश का विकास सम्भव है, न किसी जाति-विशेष का । (१९५५)

अनिवार्य राजभाषा का सवाल

भारत के संविधान में राजभाषा से सम्बन्धित धाराओं को स्वीकृत हुए चार वर्ष से ऊपर हो गए । जो कमीशन हिन्दी के व्यवहार के बारे में राष्ट्रपति के सामने अपने सुझाव रखेगा, वह भविष्य में बनेगा । किन्तु कुछ विद्वान् राजनीतिज्ञ उस भाषायी क्रांति की सम्भावना से घबरा उठे हैं जिसके जनक वे स्वयं थे । उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने पटना में भारतीय हिन्दी परिषद् के अधिवेशन में कहा था “अगर अंग्रेजी हटाने पर बहुत जोर दिया जायगा तो इसमें हिन्दी को लाभ नहीं हानि होगी, राष्ट्रीयता लुप्त हो जायगी, प्रादेशिक भावनाएँ प्रबल होगी, भारत के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे ।” ऐसा लगता है कि अंग्रेजी की स्थिति को जरा-सा भी धक्का लगने पर देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है । एच अन्ध राज्यपाल, मद्रास में श्री श्रीप्रकाश ने संस्कृत को भारत की राजभाषा बनाने की बात कही है ।

स्पष्ट है कि संविधान की भाषा-सम्बन्धी धाराएँ स्वीकृत करने के बाद भी कांग्रेसी नेता भाषा समस्या का अन्तिम समाधान पेश नहीं कर चुके ।

सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में जनता की भाषाओं के व्यवहार के लिए सघर्ष स्वाधीनता और जनतन्त्र के लिए होनेवाले सघर्ष का ही एक अंग है । रबीन्द्रनाथ और भारती जैसे कवियों ने बंगला और तमिल के गौरव गीत गाये । जनता ने मैकाले की भाषा-नीति का विरोध किया, जिसका उद्देश्य विदेशी साम्राज्यवादियों की चाकरी करनेवाले बुद्धिजीवी तैयार करना था । ब्रिटिश शासकों ने कोशिश की कि जनता की भाषाएँ दबाई जाएँ, उन पर अंग्रेजी लादी जाय, और जनता की एकता नष्ट कर दी जाय । साम्राज्यवादियों का स्वप्न रिजले की पुस्तक ‘द पीपुल ऑफ इंडिया’ में इस तरह प्रकट हुआ है, “यह सम्भव है—यद्यपि सम्भावना दूर भविष्य की है—कि शायद अंग्रेजी ही भारत की राष्ट्रभाषा बनेगी ।”

प्रारम्भिक दिनों में कांग्रेस के नेताओं की भाषा अंग्रेजी थी । किन्तु १९२० के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन की प्रगति के बाद भारतीय भाषाएँ

राजनीतिक मंच पर अग्रसर होने लगी। लेकिन भारतीय भाषाओं की यह प्रगति नेताओं को हमेशा अच्छी नहीं लगी। उनमें से कुछ चक्रवर्ती सम्राटों के गौरव-मय इतिहास का स्वप्न देखते हैं जब पुरोहितों की सहायता से वर्ण-व्यवस्था वाले समाज में संस्कृत का बोलवाला था। कुछ अन्य नेता 'डूबते की तिनके का सहारा' की मसल चरितार्थ करते हुए अंग्रेजी का दागन धामे हुए हैं।

कांग्रेसी नेताओं ने जब हिन्दी को राजभाषा के लिए मान्य किया, तब तक सत्ता प्राप्त किये उन्हें चार वर्ष हो गए थे। लेकिन इस फैसले के साथ उन्होंने यह भी सुनिश्चित कर लिया कि सभी सरकारी कामों के लिए अगले पन्द्रह साल तक अंग्रेजी का व्यवहार होगा। इस प्रकार अंग्रेजी का चलन उन्होंने बीस साल के लिए पक्का कर लिया। संविधान की लागू हुए पाँच साल भी नहीं बीते कि हमें उपदेश सुनने को मिलने लगे हैं कि अंग्रेजी को हटाना खतरनाक है। पन्द्रह साल के बाद पार्लियामेंट रानून बनाकर अंग्रेजी का चलन बनाये रह सकती है। कांग्रेसी नेताओं की यह मशा नहीं थी कि अंग्रेजी हटाने के लिए जमकर जोशिल करें। उन्होंने स्पष्ट ही अपने सामने यह सम्भावना रखी थी कि पन्द्रह साल के बाद भी अंग्रेजी जारी रहेगी, शायद उसके अगले पन्द्रह साल तक भी जारी रहेगी, हो सकता है कि इसके आगे भी जारी रहे। संविधान-सभा में बहस की तमाम सरगमियों के पीछे यह निर्भय निश्चय साफ दिखाई देता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की हानि करते हुए अंग्रेजी को अनिवार्य राजभाषा के रूप में चालू रखा जाय। श्री नेहरू ने बड़ी स्पष्टता से कहा है कि "भाषा इस बात की प्रस्ताव में चाहे लिलें, चाहे न लिलें, अंग्रेजी नाज़मी तौर से भारत में बहुत महत्वपूर्ण भाषा बनकर रहेगी जिससे बहुत लोग सीखेंगे और शायद उन्हें उसे जबरन सीखना होगा।" लोग इन तमाम बर्षों में अंग्रेजी जबरन सीखते आये हैं। अब उनके सामने एकमात्र यह सम्भावना पेश की गई है कि अंग्रेजी के बिना हमारी कला और विज्ञान का पतन हो जायगा और देश का विघटन होगा, उसका नाश हो जायगा।

अंग्रेजी की विशेषाधिकार वाली स्थिति इस बात से और दृढ़ हो गई है कि उसका व्यवहार सुप्रीम कोर्ट और प्रत्येक हाईकोर्ट की कार्यवाही में, पार्लियामेंट या विधानसभाओं में पेश होनेवाले हर बिल के लिए होगा और बिल का अंग्रेजी रूप ही अधिकारी रूप माना जायगा। यदि राज्यपाल या राज्यप्रमुख की आज्ञा से किसी बिल, ऐक्ट या आर्डिनंस के लिए हिन्दी का व्यवहार किया जायगा तो अंग्रेजी रूप ही अधिकारी रूप माना जायगा। भारतीय जनता के लिए इससे अधिक अपमानजनक दूसरी बात हो नहीं सकती। अंग्रेजी के मुकाबले में तमाम भारतीय भाषाओं को नीचा दर्जा संविधान ने ही दे रखा है।

संविधान में यह लिख दिया गया है कि पन्द्रह वर्षों तक भारत की भाषा-नीति में कोई भी परिवर्तन न होगा। संविधान ने राज्यों को इसके लिए भी बाध्य किया है कि वे एक-दूसरे से केवल हिन्दी या अंग्रेजी में ही पत्र-व्यवहार

करें। अपनी सरकारी कायवाही में विशेष कानून बनाये बिना कोई राज्य अंग्रेजी की जगह अपनी भाषा का व्यवहार नहीं कर सकता। नतीजा यह है कि लगभग सभी राज्यों में सारा सरकारी काम अंग्रेजी में होता है। इस प्रकार यह विदेशी भाषा न केवल अखिल भारतीय स्तर पर अनिवार्य राजभाषा बनी हुई है वरन् विभिन्न राज्यों में भी अनिवार्य राजभाषा बनी हुई है।

भारत के कुछ ब्रिटिशोधी अनिवार्य राजभाषा के रूप में हिन्दी का ता विरोध करते हैं लेकिन अंग्रेजी जो सब पर हावी है और जिसे खास अधिकार मिले हुए है उससे बारे में चुप रहते हैं। ये लोग समझते हैं कि ग्राम जनता पिछड़ी हुई है, इसलिए अंग्रेजी पढ़े लोगो का काम है उस पर शासन करना और जनता का काम है साक्षित होना। कहा जाता है कि अंग्रेजी के बिना देश की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति बन्द हो जायगी। लेकिन ग्राम जनता के सहयोग के बिना किसी तरह की प्रगति नहीं हो सकती, न आर्थिक न सांस्कृतिक।

भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करने से अंग्रेजी का प्रभुत्व कायम रखने में मदद मिलती है। एव ही राज्य में अनेक जातियों के रहने से उनमें से कोई भी अपना राजकाज अपनी भाषा में नहीं कर सकती। जातीयता के आधार पर जब तक लोग अपने राज्यों में पुनर्गठित न होंगे, तब तक अंग्रेजी का प्रभुत्व समाप्त न होगा।

ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के मुखपत्र टाइम्स के इक्वैनीमिस्ट ने लिखा था "भारत की संविधान सभा ने गरम बहस के बाद तय किया है कि हिन्दी के राजभाषा बनने से पहले अभी पन्द्रह साल तक अंग्रेजी राजभाषा और बनी रहेगी। इससे पता चलता है कि भारत का राजनीतिज्ञ यथार्थ का सामना करने को तैयार हैं और समझौता स्वीकार करते हैं। उनके इस रवैये की बहुत सी मिसालें आजादी के बाद मिल चुकी हैं।"

इस साम्राज्यवादी पत्र और राज्यपाल श्री मुंशी के यथार्थ दर्शन में काफी समानता मालूम होती है।

जहाँ तक अंग्रेजी के प्रभुत्व का सवाल है, हम वहीं हैं, जहाँ सन् '४७ में थे। यह प्रभुत्व और दृढ़ ही हुआ है। इसकी यथार्थ यही है जिसका दर्शन ग्राम जनता आये दिन करती है, इस यथार्थ को बदलना है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, सुब्रह्मण्य भारती, वीरेशलिंगम वल्लत्तोल आदि महान् साहित्यकारों ने जो सघन प्रारम्भ किया था, उसे तब तक जारी रखना चाहिए जब तक अंग्रेजी को हटाकर भारतीय भाषाओं को उनके उचित अधिकार न दिला दिये जाएँ। यह सघर्ष हमारे राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय गौरव और आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए सघर्ष है, यह समानता और परस्पर सहयोग के आधार पर भारतीय जनता की एकता को दृढ़ करने के लिए सघर्ष है।

भारत में पूँजीवादी राष्ट्रवाद की लपटें उठ रही हैं। उत्तर दिशा के

लोग भीम और दुर्योधन के समान एक-दूसरे पर प्रहार करने को उद्यत दिखाई देते हैं। संविधान-सभा की बैठक में श्री एल० के० मैत्र, श्री गान्धिल, श्री रामलिंगम् चेट्टियार, श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी, श्री शंकरराव देव आदि ने हिन्दी के प्रभुत्व से भय की बात की। श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कहा था, “भारतीय संविधान में एक धारा बना देने से आप सब लोगो को बाध्य नहीं कर सकते कि वे एक ही भाषा को स्वीकार कर लें।” उन्होंने यह भी कहा था, “दुर्भाग्य से लोगों में यह भय है और कई जगह उस भय का भ्रमली रूप भी दिखाई देता है। इन जगहों में लोगों को अपनी भाषाओं के व्यवहार की उतनी सुविधा भी नहीं दी गई जितनी घुणित विदेशी राज्य में भी उन्हें प्राप्त थी।”

संविधान में हिन्दी को राजभाषा का पद दिया गया है, किन्तु इस राजभाषा का कार्यक्षेत्र क्या है? अंग्रेजी ने राजभाषा बनकर प्रादेशिक भाषाओं के बहुत-से अधिकार छीन लिये थे। विभिन्न राज्यों को स्वायत्त शासन के काफी अधिकार दिये बिना अंग्रेजी की जगह हिन्दी को देने का मतलब है, दूसरी भाषाओं के अधिकार निवन्धित करना। संविधान में हिन्दी के विकास की बात कही गई है, अन्य भाषाओं का उत्प्रेषण नहीं है। इस तरह की मनोवृत्ति से भारत की विभिन्न जातियों में बैनी और भाईचारा न बढेगा।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में कहा गया है, “देश की एकता के नाम पर एक प्रदेश की भाषा हिन्दी को सभी जातियों और राज्यों के लिए उनकी भाषाओं का अहित करते हुए, अनिवार्य राजभाषा बना दिया गया है, इसलिए अहिन्दी जातियाँ अनिवार्य राजभाषा के रूप में हिन्दी का विरोध करती हैं और माँग करती हैं कि उनकी भाषाओं को सभी सरकारी कामों में हस्तक्षेप किये जाने की सुविधा दी जाय।”

भाषावार राज्य-निर्माण का आन्दोलन जोर पकड़ रहा है। यह स्पष्ट है कि जातीयता के आधार पर जो नये राज्य गठित होंगे, उनमें राजकाज की भाषाएँ प्रादेशिक भाषाएँ होंगी। जो लोग दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार करते रहे हैं, वे इस बात को समझते हैं। उन्होंने कहा है कि अपने-अपने प्रान्तों में प्रादेशिक भाषाएँ ज्ञान विज्ञान और राजकाज की भाषाएँ बन जाएँगी, सभी हिन्दी सचमुच राष्ट्रभाषा बनेगी।

मानसवाद दूसरों की इच्छा के विरुद्ध किसी भाषा को अनिवार्य राजभाषा बनाने का विरोध हमेशा करता रहा है। लेकिन वह एक या अधिक भाषाओं के माध्यम द्वारा विभिन्न जातियों के परस्पर सम्पर्क कायम करने का समर्थक भी रहा है। लेनिन ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट में इटालियन भाषी प्रतिनिधि फ्रैंच बोलते हैं और कहा था, “ऐसा वे किसी बर्बर पुलिस बानून के कारण डढे के भय से नहीं करते (स्विट्जरलैंड में ऐसा कोई कानून नहीं है) बल्कि केवल इसलिए कि किसी भी जनतन्त्र के सम्य नागरिक उस भाषा का व्यवहार करना उचित समझते हैं जिसे बहु-

संस्कृत जनता सम्भती हो ।”

सोवियत संघ के राष्ट्रपति बानीनिन ने गैर-रूसी जातियों में राजनीतिक प्रचारको से कहा था, “यह बहुत जरूरी है कि गैर-रूसी जातियों के मूलिक रूसी भाषा सीखें। रूसी भाषा सीखे बिना फौज में काम नहीं चल सकता। हमारे फौजी कायदे-बानून रूसी में होते हैं। इसी भाषा में फौजी हुक्मनामे जारी किये जाते हैं और रूसी में ही सिपाहियों की बर्मान होती है। सोवियत संघ में रूसी सभी जनो की सम्पर्क-भाषा है।”

लेनिन ने जातीय समस्या पर लिखते हुए कहा था, “आर्थिक सम्पर्क की आवश्यकताएँ स्वयं बता देंगी कि किसी देश में बहु-मूल्यक लोगों को किस भाषा के सीखने से व्यापार आदि में सुविधा होगी।” अंग्रेजों के आने से पहले भारत में व्यापार का अभाव न था। अनुभव से साबित हो गया है कि चीन-सी भाषा सीखने से बहु-मूल्यक जनता को लाभ होता है। यह हिन्दुस्तानी जाति की भाषा है। सोलहवीं-नववीं सदियों में ही व्यापार की उन्नति होने पर यह भाषा देश के विभिन्न और सुदूर प्रदेशों तक पहुँच रही थी। न केवल भारत के व्यापारी यह भाषा सीखते थे बरन विदेशी सौदागर भी, अंग्रेजों की श्रेष्ठता पर ध्यान न देकर, यही भाषा सीखते थे। यही कारण है कि इटली के यात्री मनुष्यों ने शिवाजी से हिन्दुस्तानी में बातचीत की थी। महाराष्ट्र और तमिल में हिन्दी में कविता रचनेवालों का अस्तित्व इस भाषा की लोकप्रियता का प्रमाण है। इसलिए यह सम्भलता गलत है कि अंग्रेजों के बिना न राष्ट्रीय आन्दोलन होता, न राष्ट्रीय एकता होती। अंग्रेजों ने देश के एकीकरण में बाधा डाली, इस एकीकरण में हिन्दुस्तानी जाति की भाषा महत्वपूर्ण भूमिका पूरी कर रही थी। वैष्णव कवियों ने सांस्कृतिक स्तर पर जनता की एकता को दृढ़ किया। उन्नीसवीं शती के समाज सुधारकों और धर्म-प्रचारकों ने अपने कार्य के लिए इस भाषा को प्रयोज्य। यह स्वाभाविक था, क्योंकि संस्था की दृष्टि से सम्भवतः चीनी जाति को छोड़कर हिन्दुस्तानी जाति संसार की सबसे बड़ी जाति है। इस कारण भारत की विभिन्न जातियों में आर्थिक और सांस्कृतिक सम्पर्क के लिए उसका व्यापक व्यवहार हुआ।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी अनिवार्य राजभाषा का विरोध करती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह राष्ट्रीय एकता का मूल्य नहीं समझती, या उस एकता को दृढ़ नहीं करना चाहती। कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह अनुभव करती है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता की सुरक्षा और देश की आर्थिक प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न राज्यों और प्रदेशों की जनता की एकता और परस्पर भाईचारा दृढ़ किया जाय। स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि जिन लोगों की मातृ-भाषाएँ अलग-अलग हैं, वे किस भाषा में परस्पर बातचीत करें। भारत की ठोस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कहा जाएगा कि यह भाषा हिन्दी ही हो सकती है। यह प्रश्न अभी भी चालू है। इसलिए अपनी मदुरा कांग्रेस में

कम्युनिस्ट पार्टी ने यह स्पष्ट कहा है कि अनिवार्य राजभाषा को लागू करने का विरोध करते हुए भी पार्टी चाहती है कि हिन्दी विभिन्न राज्यों की जनता तथा उनकी सरकारों के बीच परस्पर सम्पर्क का साधन अधिकाधिक बने । (१९५४-५५)

अंग्रेजी के हिमायती

अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है और उसे इस पद पर बनाए रखने में भारत के राष्ट्रीय लेखकों ने काफी योग दिया है। उपन्यास, कविता, राजनीति, विज्ञान—किस पर वे नहीं लिखते? किस पर वे नहीं बोलते? अभी तक साहित्य और संस्कृति का अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास नहीं लिखा गया, लिखे गये हैं विश्व, महाद्वीपों, राष्ट्रों या जातियों के इतिहास। यदि कभी अंग्रेजों ने अपनी भाषा का महत्व पहचाना और उसका अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक इतिहास लिखा तो उन्हें इन भारत के अंग्रेज भदीबों को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा।

पिछले दिनों एक अंग्रेजी पत्र के 'कॉलमनिस्ट'—'भदीब'—ने भारतीय भाषाओं के बारे में रोचक विचार प्रकट किए हैं। उनका कहना है कि अंग्रेजी की सी व्यंजन शक्ति किसी भारतीय भाषा में नहीं है; इसलिए भावुकता छोड़कर अंग्रेजी की शरण जाना ही उचित है। यह बात कितनी सही है, इसे 'भदीब' के साथ इन पक्तियों का लेखक भी अनुभव कर रहा है। 'कॉलमनिस्ट' का पर्यायवाची हिन्दी में मिलता नहीं है, उधर अंग्रेजी शब्द को ज्यो-वा-र्यो लिखने में खतरा यह है कि अगठ हिन्दीभाषी उसे अपभ्रंश बनाकर 'कलमनष्ट' न कर दें। हिन्दी के पाठक ऐसे जाहिल हैं कि उनमें से कुछ 'भदीब' का अर्थ भदब लगा लें, तो भी आश्चर्य नहीं। लेकिन इतना तो उन्हें मालूम ही होना चाहिए कि भदीब अंग्रेजी का शब्द नहीं है, हिन्दुस्तान का न सही, एशिया का तो है। अंग्रेजी के लेखक होते हुए भी 'भदीब' ने अपने लिए एशियाई उपनाम चुना, इस पर दो महीने बाद दिल्ली में होनेवाले एशियाई लेखक-सम्मेलन को उन्हें बधाई देनी चाहिए।

हिन्दी की व्यञ्जना-शक्ति कितनी सीमित है, इसके उदाहरणस्वरूप 'भदीब' ने इलियट की दो पक्तियों का अनुवाद दिया है—

हम खोखले हैं।

हमारे अन्दर भूसा भरा हुआ है।

महाकवि इलियट को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब हिन्दी के पाठक

उनकी रचनाओं में ऐसे महान् विचार प्रकट होते देखकर आधुनिक अंग्रेजी कविता के बारे में क्या सोचेंगे, जो सोचेंगे, उससे भारत-ब्रिटेन-अंग्रेजी कैसे दूढ़ होगी और भारत में अंग्रेजी साहित्य-रचना का भविष्य क्या होगा, इस तरह की समस्याएँ सभी चिन्तकों को चिन्तित कर सकती हैं। इलियट की महान् कल्पना—हम सोचते हैं, हमारे अन्दर भूसा भरा हुआ है।—‘अदीब’ के अनुसार हिन्दी के अनुवाद में सत्य बात कहते हुए भी हास्यास्पद हो जाती है। वास्तव में सत्य कभी-कभी हास्यास्पद हो ही जाता है, यद्यपि हिन्दी में हास्य रस को उतना ही उच्च स्थान दिया गया है जितना अन्य रसों को। सहृदयों को तो साधारणोत्तरण द्वारा यहाँ भी रस निष्पत्ति में आपत्ति न होगी।

इलियट-जैसे कवियों का उल्लेख करते हुए ‘अदीब’ ने पूछा है कि इनसे हिन्दी, बँगला या तमिल कैसे चुनवाएँ ? बहुत ही मदद से कहना चाहता हूँ कि बँगला या तमिल में चुनवाने की जरूरत क्या है। राष्ट्रभाषा हिन्दी ही उन सब की बोलियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए काफी है। फिर आपने हमारे प्रयोगवादियों की बोली नहीं सुनी ? इतने दिन इलियट के भूँस में हिस्सा बँटाकर जो बस आनन्दमय स्वर में रँभाते रहे हैं, उनकी रागिनी पर आपने कान नहीं दिया ? माना कि ‘हम सोचते हैं’ और अंग्रेजी की मूल पक्तियों का अनुवाद करना कठिन है, लेकिन उसी काव्य-परम्परा की इस एक पक्ति का भाव ही अंग्रेजी में अनुवाद कर डालिए—“मैं ही मरघट का बहु रिरियाता हुआ।”

‘अदीब’ ने क्या ही सुन्दर विचार प्रकट किया है—

A language is not a donkey । भाषा गधा नहीं है। यद्ये तो भाषा के बोलने और लिखनेवालों में होते हैं। भाषा को ठोकर मारो, चाहें पुचकारो, कोई लाभ न होगा। लेकिन यह जिया भाषा के बोलने या लिखनेवालों के साथ करो, अवश्य फल देगी। मेरी समझ में भारत में अंग्रेजी के लेखकों के प्रति हमारी राष्ट्रीय नीति पुचकारने की है और भारतीय भाषाओं के लेखकों को ठोकर मारने की। मैं इस नीति की सफलता चाहता हूँ।

और इस नीति में बुरा क्या है ? भारत के लोगो ने अपनी भाषाएँ छोड़कर सभी तक अंग्रेजी नहीं अपना ली—जैसे कि जारसाही रूस के अभिजात वर्ग ने फ्रांसीसी भाषा अपना ली थी—इस सबीर्णता को क्या कभी धमा किया जा सकता है ? रूसी लेखक गोगल ने एक नगर की सम्प्रान्त महिलाओं के बारे में लिखा था—“रूसी भाषा का संस्कार करने और उसे ऊँचा उठाने के लिए उन्होंने अपने शब्द मण्डार के साथे शब्द महिषूत करके उनकी जगह फ्रांसीसी शब्द रख लिये थे।”

आप स्वीकार करेंगे कि दिल्ली और बम्बई—जैसे नगरों के सज्जन—अर्थात् वास्तव में शिक्षित सज्जन—उन रूसी महिलाओं से बाजी मार ले गए हैं।

सम्प्रान्त रूसी समाज के पाठकों के लिए गोगल ने लिखा था—“इनके”

मुँह से कभी कोई सभ्य रूसी शब्द सुनने को नहीं मिलता। फ्रांसीसी, जर्मन और अंग्रेजी शब्दावली का प्रवाह उनके मुँह से फूट पड़ता है। उनका उच्चारण भी तरह-तरह का होता है। वे फ्रांसीसी बोलते हैं तो नाक से, और थोड़ा तुतलाते हुए। अंग्रेजी बोलते हैं तो चिड़ियों की तरह, दुरुस्त बहबहाते हुए। और जब बोलते हैं तब चिड़ियों-जैसे दिखाई भी देते हैं। वे उन पर हँसते हैं, जो चिड़ियों-जैसा मुँह नहीं बना पाते। वे रूसी में कुछ नहीं लिखते। उनकी देशभक्ति इसमें प्रकट होती है कि वे ग्रीष्म-निवास के लिए रूसी शैली में भोपड़ी बनवा लें।”

लेकिन ग्राम शिमला, मसूरी, नैनीताल आदि में अंग्रेजी शैली के ‘कॉटेज’ होने के कारण भारत के अन्तर्राष्ट्रीयतावादियों के लिए हिन्दुस्तानी ढंग की भोपड़ी बनाना भी आवश्यक नहीं। यहाँ भी वे रूसियों से प्रागे हैं।

गोगल की शिष्यायत है कि उस समय के सम्मानित विद्वान् रूसी भाषा के लिए स्वयं तो कुछ न करते थे, लेकिन यह माँग अवश्य करते थे कि रूसी भाषा परिष्कृत और समृद्ध हो जाय, वह अपने परिष्कृत और समृद्ध रूप में आसमान से उतरे और उनका काम इतना ही हो कि जीम निवासकर उसे गप कर लें।

लेकिन ‘अदीब’ की यह माँग नहीं है कि हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं को समृद्ध किया जाय। उनकी माँग यह है कि भारतीय भाषाओं के बहले अंग्रेजी में ही सारा काम होता रहे। यहाँ भी भारत के सम्मानित विद्वानों ने जारघाही रूस के सम्मानित विद्वानों को पीछे छोड़ दिया है।

‘अदीब’ ने चेतावनी दी है कि अंग्रेजी का सहारा न लिया तो पुल टूटने लगेंगे और दूसरी-तीसरी-चौथी पंचवर्षीय योजनाएँ असफल हो जाएँगी। यह चेतावनी एकदम सामयिक है। अभी हिन्दी को केन्द्रीय राजकाज की भाषा बनाने की बात ही चली है कि हैदराबाद राज्य में दो बार पुल टूट चुके हैं और जनता की भारी क्षति हुई है। जब चर्चा का ही यह फल है, तब व्यवहार में आने पर हिन्दी से कौन-सी छति न होगी, आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। इसी तरह योजनाओं के सम्बन्ध में भी। घूस और रिश्वत का बाजार गर्म है। योजना पूरी हो नहीं पाती कि घूस-गबन की जाँच के लिए समिति बैठाना आवश्यक हो जाता है। जब तक हिन्दी का पूर्ण बहिष्कार नहीं हो जाता, तब तक हर योजना को व्यवहार में लाने के साथ साथ घूस और रिश्वत की जाँच के लिए पहले से ही एक समिति बना देनी चाहिए। इससे सिद्ध हो जाएगा कि योजनाओं द्वारा पैसा खानेवालों का हिन्दी से कितना गहरा सम्बन्ध है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। राष्ट्रीय जीवन में भी अंग्रेजी का वैसा ही प्रभुत्व रहे तो अशिक्षा, बेकारी, बाढ़, मूसमरी आदि की समस्याएँ तुरन्त हल हो जाएँ और ५० नेहरू की गृहनीति में भी चार चाँद लग जाएँ। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ‘पंचशील’ का शब्द जरूर चल पड़ा है। यह ‘पंचशील’ या और किसी तरह का नील उन अंग्रेजो-अमरीकियों को पसन्द नहीं

सोवियत क्रान्ति और भाषा-समस्या

आज से चालीस साल पहले ससार की महान् समाजवादी क्रान्ति की विजय ने पिछड़े हुए बहुजातीय देशों के सामने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का एक नया आदर्श रखा। यह विकास पिछड़ी हुई जातियों की भाषाओं के माध्यम से ही सम्भव था। इसलिए सामाजिक विकास की समस्याओं के साथ समाजवादी क्रान्ति ने भाषा-समस्या हल करने का भी एक नया मार्ग हमें दिखाया।

अभी सी साल न बीते थे जब रूस का प्रभिजात वर्ग रूसी को पिछड़ी हुई भाषा मानता था; वह अपने सांस्कृतिक जीवन में अधिकतर फ्रांसीसी भाषा का व्यवहार करता था। हमारे देश में भी अनेक विद्वान् हिन्दी ही नहीं, भारत की सभी भाषाओं को पिछड़ी हुई मानते हैं। इसलिए केन्द्रीय राजकाज के लिए वे बहुत दिनों तक अंग्रेजी का व्यवहार उचित समझते हैं। रूस के नेताओं ने अपने राजनीतिक पत्र फ्रांसीसी के बदले रूसी में ही प्रकाशित किये थे; रूसी उनके राजनीतिक जीवन की भाषा थी। गैर-रूसी इलाकों के नेता वहाँ की भाषाओं का व्यवहार करते थे। इसलिए रूसी को पिछड़ी हुई भाषा मानकर सत्रमण साल के लिए अनेक वर्षों तक फ्रांसीसी भाषा के व्यवहार का प्रस्ताव उन्होंने नहीं रखा। रूसी जनता के लिए उन्होंने तुरन्त रूसी भाषा को राजकाज की भाषा घोषित कर दिया। आज तो लोग मानते हैं कि रूसी ससार की समृद्ध भाषाओं में है लेकिन यह स्थिति १९१७ में न थी। तोल्स्तोय, चेखव, गोर्की आदि कुछ उपन्यासकार अवश्य हो गए थे, जैसे भारत में रवीन्द्रनाथ, भारती, प्रेमचन्द, शरत्चन्द्र, इकबाल आदि कवि और कथाकार हो गए हैं। लेकिन फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की तुलना में वैज्ञानिक शिक्षा की पुस्तकें उसमें कहीं थी ? यह तर्क दिया जा सकता था कि किसी भी विषय की समुचित शिक्षा के लिए रूसी भाषा पर्याप्त नहीं है, इसलिए जब तक वह समृद्ध न हो जाय तब तक केन्द्रीय राजकाज फ्रांसीसी में होना चाहिए। लेनिन के नेतृत्व में स्वाभि-मानी रूसी जनता ने अपनी पिछड़ी कहलानेवाली, प्रभिजात वर्ग द्वारा उपेक्षित

भाषा में ही अपना गारा राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्य प्रारम्भ किया। भारत में जहाँ भाषा और शिक्षा की हज़ारों वर्ष पुरानी परम्परा है (सिन्धु घाटी के जन भी लिखना-पढ़ना जानते थे) वहाँ आज यह दयनीय स्थिति है कि देश की सभी भाषाओं को पिछड़ा हुआ मानकर अनेक वर्षों के लिए अंग्रेज़ी के व्यवहार का समर्थन किया जाता है।

खैर, रूसी में तो रवीन्द्रनाथ, प्रेमचन्द की तरह तोल्स्तोय और गोर्की जैसे विश्वविख्यात लेखक थे। वैज्ञानिक शब्दावली में प्रॉव के मुवाबसे में रूसी भले ही पिछड़ी रही हो, कथा-साहित्य में हिन्दी और बंगला की तरह रूसी समृद्ध थी। किन्तु बेलोर्ूसी, उक्रेनी, जाज़ियाई आदि भाषाओं में तो इतने बड़े नाम न थे। सोवियत राज्यसत्ता ने उन्हें भी अपने-अपने क्षेत्र में राजकाज की भाषा बनाया। इनसे भी गर्द-गुहरी मज़रबंजानी, ताज़िक, कज़ाक आदि भाषाएँ थी जिनमें मौखिक साहित्य ही अधिक प्रचुर था। ये भी राजकाज की भाषा बनी। इनसे भी 'पिछड़ी हुई' बकुचो, बुर्यात, मंगोल, चेचकास, समोयेद आदि भाषाएँ थीं जिनकी स्थिति भारत के अनेक आदिवासी जनो की भाषाओं से भी गर्द-भीती थी। इनको भी विकसित होने का मौका मिला। आज उनमें व्याकरण, बोध, विज्ञान, कथा-साहित्य, काव्य—सभी-कुछ है। हमारे देश में भाषा-समस्या के विवेचन में आदिवासियों की भाषाओं की चर्चा करने का अभी चलन नहीं है।

सोवियत सप न वही भी यह दलील नहीं दी गई कि भाषाएँ पिछड़ी हुई हैं, इसलिए चालीस साल तक, उनके व्याकरण और शब्दकोश तैयार होने तक, उनकी जगह रूसी भाषा का व्यवहार होगा। भाषा जनता के लिए है, जनता भाषा के लिए नहीं है। हमारे देश में जनता की आवश्यकताओं को देखकर भाषा-समस्या हल नहीं की जाती, अंग्रेज़ी से हमारे जो काम हो जाते हैं, वे भारतीय भाषाओं से होंगे या नहीं, यह समस्या पहले आती है। पारिभाषिक शब्दावली इस तरह गढ़ी जाती है मानो वह जनता के काम आने के लिए नहीं, उसकी जीभ और तालू का व्यायाम कराने के लिए है! पूँजीवादी और समाजवादी दृष्टिकोणों में यही अन्तर है। यदि भारत में साधारण जनता घामन के कामों में भाग ले, यदि उसके अपने जन-समूह राज्यसत्ता का वास्तविक आधार हो, अर्थात् यदि इस जनवादी देश में जनता का राज सचमुच हो तो क्या यह कल्पना की जा सकती है कि एक दिन भी यहाँ अंग्रेज़ी से काम चलेगा?

नवम्बर क्रान्ति ने मानवता के उद्धार और विकास का नया मार्ग दिखाया, उस मार्ग पर चलकर नवनिर्माण का आदर्श हमारे सामने रखा। इस निर्माण में एक वर्ग दूसरे का शोषण और उत्पीड़न नहीं करता; उसमें एक जाति 'फ्री वर्ल्ड' के लुटेरों की तरह दूसरी जाति को दबाकर उसकी भाषा और सभ्यता की पैरो तले नहीं रौंदती। मानव-समाज जाति और वर्गों के रूप में ही संगठित हुआ है। वर्ग मिट जाने पर भी जाति बनी रहती है, इस-

समृद्ध थी। इंग्लैंड में ऐमे साहित्यकार भी ये जो फ्रांसीसी में रचना करके प्रसार देना चाहते थे। किन्तु इतिहास ने लैटिन और फ्रांसीसी में लिखे हुए इनके न्यों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया जहाँ वे अब केवल अनुसन्धानकर्ताओं के काम आते हैं।

अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान पर शासन किया, अंग्रेजों के देश पर भी रोमनों और ग्रीकों ने शासन किया था। किसी समय इंग्लैंड के अभिजात वर्ग पर फ्रांसीसी भाषा का वैसा ही रौब गालिब था जैसा आज के समस्त-गोत्रीय भारतवासियों पर अंग्रेजी का है। किन्तु लैटिन या फ्रांसीसी को अधिक समृद्ध मानकर अंग्रेज जनता ने उस राष्ट्रभाषा न मान लिया। उसने साहित्यकारों को अपनी भाषा का समृद्ध किया और उसे यूरोप की नवीन और प्राचीन भाषाओं की पाँति में सम्मानप्रद स्थान दिलाया। अंग्रेजी समृद्ध होने के बाद राजभाषा नहीं बनी, राजभाषा होने के बाद वह समृद्ध हुई। वह लैटिन और फ्रांसीसी भाषाओं की तुलना में समृद्ध हुई जिनके हिमायती उसके अधिक स्थान से उसे हटाना चाहते थे।

अंग्रेज शासकों ने यहाँ की जनता के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास को रोक दिया। उन्होंने यहाँ की भाषा के ऊपर साम्राज्य की तरह अंग्रेजी को प्रतिष्ठित किया। अंग्रेजी भाषा को अंग्रेज-प्रेमी भारतवासियों के पूर्वजों ने विधान-सभा में प्रस्ताव पारित करके स्वीकार न किया था। वह अंग्रेज शासक-वासियों द्वारा लादी हुई भाषा थी। ससार में अंग्रेजी का बोलबाला मिल्टन और शेक्सपियर के कारण नहीं हुआ, उसका प्रसार करनेवाले क्लाइव और डलहौजी की विरादरी के थे। उत्तरी अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में अंग्रेजी का प्रसार करनेवाले वे आक्रमणकारी थे जिन्होंने वहाँ के आदिवासियों के नरमेघ रचाये थे, जिनका मिल्टन और शेक्सपियर से इतना ही सम्बन्ध था कि दोनों ही अंग्रेजी बोलते थे (कौसी अंग्रेजी बोलते थे, यह प्रश्न छोड़ दीजिए)। यदि समृद्धि के बल पर कोई भाषा अंग्रेजी की तरह 'विश्वभाषा' बनती तो पाणिनि और कालिदास की भाषा मृत भाषा न कहलाती, दान्ते, गेटे, तोल्स्टोय की भाषाएँ भी विश्वभाषा बन जातीं। अंग्रेजी के समर्थक उसके प्रसार के लिए मिल्टन और शेक्सपियर का नाम लेते हैं, उस ब्रिटिश साम्राज्य की कहानी भूल जाते हैं जिसमें कभी सूर्यास्त न होता था और अर्नेस्ट जोन्स के शब्दों में जिसकी घरती पर कभी रक्त न मूसला था।

अंग्रेजी-प्रेमी भारतवासी अपनी प्रिय विश्वभाषा के पक्ष में जितनी दलील देते हैं उनमें एक भी ऐसी नहीं है जो पहले 'लिबरल' राजनीति-विचारकों ने न दी हो। ये 'लिबरल' मद्द्बजन अंग्रेजी राज और अंग्रेजी भाषा के मामले में अत्यन्त उदार थे, हिन्दुस्तानी जनता के राज और हिन्दी भाषा के बारे में अत्यन्त अनुदार थे। वे अंग्रेजी राज को प्रगतिशील मानते थे, अंग्रेजी को भारतीय अराजकता दूर करके यहाँ न्याय और शान्ति की व्यवस्था कायम करनेवाला

मानते थे। कभी हतनी ही थी कि अंग्रेज उच्च पदों पर इन्हें नियुक्त न करते थे। भारतीय जनता के आन्तिकारी आन्दोलन से तब्त ये उदारपन्थी महानुभाव नौकरियों में रियायतें पाने के लिए परम प्रयत्नशील अंग्रेज शासकों के सामने प्रार्थना-मन्त्र पेश करने में महान् योग्य अनुभव करते थे। उन्हीं की परम्परा निवाहनेवाले थे वर्तमान 'निबरल' हैं जिनके लिए अंग्रेजी के राजभाषा न रहने में राष्ट्र छिन्न-भिन्न हो जाएगा, देश में गृहयुद्ध छिड़ जाएगा, हिन्दीवाले सब नौकरियाँ हथिया लेंगे, विद्वत् सभ्यता से धादान प्रदान के द्वार बन्द हो जाएँगे, इत्यादि। अंग्रेजी के चले जाने से बहुसंख्य हिन्दू अल्पसंख्य मुसलमानी और अछूतों को ला दालेंगे—राउड डेबुल काँफ़ेसों में जैने प्रिटिप्त प्रधानमन्त्री यह दलील पेश करते थे, वैसे ही स्वाधीन भारत के ये 'निबरल' अंग्रेजी के बारे में कहते हैं, अंग्रेजी गई नहीं कि हिन्दीवाले सारी नौकरियाँ हथिया लेंगे, उत्तरवाले दक्षिण पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे, अहिन्दी भाषाओं का नाम-निशान मिट जायगा। यह बात नहीं है कि राउड डेबुल काँफ़ेसों के दिनों में सम्प्रदायवादी रुढ़िवादी हिन्दू नहीं थे जो अछूतों को गुलाम बनाकर रखना चाहते, जो मुसलमानों को अपना दागु समझते थे। किन्तु इनसे अछूतों और मुसलमानों की रक्षा करने के लिए यह आवश्यक न था कि हिन्दू-अहिन्दू सभी अंग्रेजों की शरण जाते। आज भी ऐसे हिन्दी प्रेमी हैं जो अहिन्दी भाषाओं को दबाकर हिन्दी को वही स्थान देना चाहते हैं जो अंग्रेजी को प्राप्त था। इनसे अहिन्दी भाषाओं की रक्षा करने का मार्ग यह नहीं है कि हम अंग्रेजी की शरण में जाएँ।

अंग्रेजी को राजभाषा बनाये रखने के पक्ष में उदारपन्थियों की दलीलों का खडन देशभक्त भारतवासियों ने ही न किया था, वरन् उनका खडन भारत प्रेमी अंग्रेजों ने भी किया था। उदाहरण के लिए उदार-हृदय सी० एफ० ऐण्ड्रूज ने 'द टू इंडिया' नाम की अपनी पुस्तक में लिखा था—“अभी तक अंग्रेजी भाषा की समझनेवाले मुट्ठी-भर बुद्धिजीवी ही हैं किन्तु यह उभरती हुई साधारण भाषा जो हिन्दुस्तानी कहलाती है, उत्तर और मध्यभारत में पचीस करोड़ जनता द्वारा आसानी से समझी जाती है, दक्षिण में भी जहाँ द्रविड भाषाएँ बोली जाती हैं, उत्तर की इस भाषा से लोग थोड़ा-थोड़ा परिचित हो गए हैं। यहाँ मद्रास प्रेसीडेन्सी के इस तिरुपत्तूर ग्राम में जब मैं लोगों की बातचीत सुनता हूँ तो उत्तर के उन संस्कृत शब्दों को पहचान लेता हूँ जो तमिल में घुल मिल गए हैं। कल एन व्यक्ति मुझसे मिलने आया था, उससे जब मैंने अंग्रेजी में बातचीत करने की कोशिश की तो उसने कहा, 'जुपा करके हिन्दुस्तानी में बातचीत कीजिए'। और जब मैं उस भाषा में बोला तो वह मेरी बात आसानी से समझ गया।”

सी० एफ० ऐण्ड्रूज की यह पुस्तक १९३६ में प्रकाशित हुई थी, तब से दक्षिण में हिन्दी पढ़नेवालों और हिन्दी समझनेवालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अंग्रेजी पढ़नेवालों और अंग्रेजी समझनेवालों की संख्या उसी अनुपात में नहीं

बढी। अंग्रेजी के समर्थक अब भी मुट्ठी-भर बुद्धिजीवी ही हैं।

भारत प्रेमी ब्रिटिश महिला ऐनी बेसेंट ने 'इंडिया वाउण्ड और फ्री' में राजभाषा अंग्रेजी के विरुद्ध अपनी अन्य किसी रचना से यह कथन उद्धृत किया था—“जब मैंवाले ने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया था, तब वह भारत के महान् साहित्य को घृणा की दृष्टि से देख रहा था। उसने यह अनुभव किया था कि अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देकर वह विशाल जनता को अज्ञान के हवाले कर रहा था। रोटी के बदले वह पत्थर दे रहा था। सड़के शिक्षा पाते थे और अपने देश की थोड़ी कृतियों से अपरिचित रहते थे। वे अंग्रेजी में बखूबी भाव सकते थे अपनी मातृभाषा में नहीं। किसी देश में राष्ट्रीयता के भाव नष्ट करने का इससे अधिक कुशल उपाय नहीं है कि एक विदेशी भाषा को उच्च वर्गों की भाषा, कानून और अदालतों की, बँनेजों की भाषा बना दिया जाय और सरकारी नौकरियों के लिए उस विदेशी भाषा की जानकारी आवश्यक कर दी जाय।”

ऐनी बेसेंट का कथन जितना युक्तिपूर्ण तब था, उतना ही आज भी है। अंग्रेजी के जाने के बाद साम्राज्यवाद से भारतीय जनता का अन्तर्विरोध समाप्त नहीं हो गया। इन्दोनेशिया, पाकिस्तान, मिस्र, सीरिया आदि एशिया के देशों में साम्राज्यवाद अपने मित्रों की तलाश में है जिनकी सहायता से वह इन देशों के आन्तरिक जीवन में हस्तक्षेप करे। इसलिए भारतीय जनता की राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करने की ओर हमें सचेत रहना चाहिए।

ऐनी बेसेंट ने 'इंडिया वाउण्ड और फ्री' में उपर्युक्त कथन उद्धृत करने के बाद लिखा था, “मैं यही कहना चाहूँगी कि इंग्लैंड ने बहुत-कुछ, यद्यपि पूरी तरह नहीं, उसी शिक्षा नीति का अनुसरण किया था जिसे पोलैंड में रुस ने लागू किया था। स्कूलों में पोलिश भाषा में शिक्षा देना बन्द करा दिया गया था और वहाँ रुसी का ब्रँसे ही प्रयोग होता था जैसे वहाँ अंग्रेजी का। सभी देशों के तानाशाह एक-दूसरे से मिलते जुलते हैं।”

आज उसी तरह कुछ अंग्रेजी प्रेमी सज्जन शिक्षा संस्थाओं में भारतीय भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी को उच्चतर स्थान देना चाहते हैं। इससे भारतीय भाषाओं की कितनी क्षति होती है, इसकी ओर वे ध्यान नहीं देते। अंग्रेजी भाषा के आधुनिक 'लिबरल' हिमायतियों से एण्ड्रू जे और बेसेंट के विचारों की तुलना कीजिए तो पता चल जायगा कि इन भद्रजनों का दृष्टिकोण कितना प्रतिक्रियावादी है। राज्यसत्ता जनता के लिए है, जनता राज्यसत्ता के लिए नहीं है, यह सत्य उनकी समझ से परे है। वे राज्यतन्त्र को उसी पुराने नौकर-शाही ढंग से चलाना चाहते हैं जिसमें नौकरशाह जनता के नौकर न होकर उसके शाह होते थे। यह युग जनतन्त्र का है, जनता अधिक-से-अधिक शासन-तन्त्र में भाग लेगी। शासनतन्त्र जनता के उत्पीड़न का यन्त्र न होकर उसकी सेवा का माध्यम बनेगा। इस शासनतन्त्र में जनता अपनी भाषाओं द्वारा और केन्द्रीय

राजकाज में हिन्दी द्वारा ही भान ले सकती है। अंग्रेजी चाहे जितनी समृद्ध हो और हिन्दी चाहे जितनी दरिद्र हो, राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का भविष्य अन्ध-कारमय है हिन्दी का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल। अंग्रेजी के समर्थन इतिहास की प्रगति से युद्ध कर रहे हैं, इसलिए उनकी पराजय निश्चिन्त है।

राजभाषा की समस्या किसी भाषा के समृद्ध होने की कसौटी पर न तो अन्धधूल हल हुई है, न यहाँ होगी। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की आवश्यकताओं ने अनेक बुद्धिजीवियों को भारतीय भाषाएँ अपनाने पर पहले भी बाध्य किया था, प्रागे भी करेंगी। इन आवश्यकताओं में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं ने इजाफा किया है। राष्ट्रीय आत्म सम्मान का निर्वाह धायद देश में इतना आवश्यक नहीं होता जितना विदेश में। अखबारों के अनुसार स्वाधीन भारत के प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने जनवरी में प्राग्गोतिपपुर में कहा था, "मैं अंग्रेजी का पक्षपाती हूँ। मैं चाहता हूँ कि न केवल भारत में अंग्रेजी पढ़ी जाय बल्कि उसकी शिक्षा का और भी प्रसार हो। लेकिन मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता कि कोई अंग्रेजी को भारत की राष्ट्रभाषा बहे। मैं चाहता हूँ कि लोग इस बात पर ध्यान दें। यह कहना कि अंग्रेजी एक राष्ट्रीय भाषा है, सत्य के विरुद्ध है। यह झूठ है। मैं नहीं समझता कि यह दलील कैसे दी जा सकती है। यह बात विचारणीय है कि हम क्या सब अंग्रेजी का व्यवहार करते हैं या व्यावहारिक कारणों से अंग्रेजी और हिन्दी दोनों को काम में लाते हैं।"

इसके बाद अखबारी विवरण के अनुसार "श्री नेहरू ने कहा कि विदेश मन्त्री की हैसियत से अंग्रेजी देशों को कागज पत्र भेजते हुए वह बड़े असमंजस में पड़े कि जिन देशों में अंग्रेजी नहीं बोली जाती, उन्हें अंग्रेजी में लिखे हुए कागज पत्र कैसे भेजे जाएँ। दुनिया अंग्रेजी बोलनेवाले देशों से बड़ी है। बड़े असमंजस की बात थी। उन्होंने अंग्रेजी में कागज भेजना बन्द कर दिया। अब वह सब उन्हें हिन्दी में भेजते थे, उनकी सुविधा के लिए अंग्रेजी में अनुवाद साथ रहता था लेकिन मूल हिन्दी में होता था। जब उन्हें रूस या चीन से कोई खरीद मिलता था, तो वह हमेशा रूसी या चीनी में होता था। हो सकता है, साथ में अंग्रेजी में अनुवाद भी रहता हो। कुछ भी हो वह वह यह रहे थे कि दुनिया के सामने भारत में यह घोषित करना बड़ी अजीब बात थी कि भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है। इस 'कल्पना से ही मेरा सिर चकरा उठता है'।"

अंग्रेजी प्रेमियों के दुर्भाग्य से दुनिया अंग्रेजी-भाषी देशों से बहुत बड़ी है। इस अंग्रेजी विहीन दुनिया में साथ बरोड़ आनादी का महादेश चीन है। इसमें समार के छठे भाग में फैला हुआ समाजवादी सोवियत देश है। सोवियत संघ, चीन और भारत में जो भाषा न चले, उसे विश्वभाषा नहीं कहा जा सकता। इन तीन देशों से एशिया और यूरोप का अधिकांश भाग घिरा हुआ है। इनके साथ अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को मिला लीजिये, यूरोप से जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन

और पूर्वी यूरोप के देशों को भी गिन लीजिये तो पता चल जाएगा कि अंग्रेजी का विश्वभाषा होना कितना सार्थक है ।

अस्तु, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही कारणों से अंग्रेजी को राजभाषा का पद छोड़ना होगा । जो लोग भारतीय जीवन के कल्पित या वास्तविक अन्तर्विरोधों के कारण अंग्रेजी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित रखना चाहते हैं, वे लिबरलो, अंग्रेज-भक्तों, अल्पसंख्यकों के उन तथ्यावधित प्रतिनिधियों का अनुसरण करते हैं जो अंग्रेजी राज को आवश्यक बताकर, अंग्रेजों को न्यायवर्ता बनाकर पराधीनता के बन्धनों को दृढ़ करते रहे थे । भारतीय जनता की राष्ट्रीय भावना इन भारतवासियों के अंग्रेजी-प्रेम पर अवश्य विजय पायेगी । (१९५८)

बहुजातीय राष्ट्रीयता और राष्ट्रभाषा हिन्दी

विश्वविद्यालयों की शिला और राष्ट्रीय एकता के सम्बन्ध में भाषण करते हुए समाचारपत्रों के अनुसार दिल्ली में श्री हुमायूँ खबीर ने कहा कि हिन्दी-भाषी लोग जब हिन्दी को राजभाषा बनाने पर जोर देते हैं, तब कम-से-कम अगस्त उनके मन में यह कामना रहती है कि वे सार्वजनिक जीवन और नौकरियों के मामले में अहिन्दी-भाषियों के मुकाबले में फायदे में रहेंगे।

देश में जब इतनी प्रगति कर ली है कि कोई भी माँग जातीय स्वार्थ से परे नहीं समझी जा सकती। हिन्दीभाषी जनता हिन्दी को राजभाषा बनाने की माँग करती है तो यह भी नौकरियाँ पाने के लिए। अहिन्दी लोगों में हिन्दी के एक प्रचारक महारमा गांधी भी थे। पता नहीं, नौकरी पाने की किस छिपी हुई कामना से उन्होंने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रचार किया था।

श्री खबीर ने कहा कि देश की सभी मुख्य भाषाओं को समानता का दर्जा मिले तो परस्पर शका और संघर्ष की भावना दूर हो जाय। यह बहुत नेक सलाह है और हम उसका समर्थन करते हैं। किन्तु विभिन्न भाषाओं के बोलनेवालों में जो संघर्ष और मतभेद दिखाई देता है, उसका कारण भाषा ही नहीं है, हिन्दी भाषा तो और भी नहीं। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में जानीय एकीकरण के लिए प्रबल आन्दोलन उठा। इसका कारण भाषा न थी; हिन्दी भाषा और भी नहीं। बम्बई को लेकर गुजरात-महाराष्ट्र में, अलग राज्य (अथवा प्रान्त) बनाने की माँग को लेकर केन्द्रीय सत्ता और इन प्रदेशों की जनता में जो तनावतनी अभी तन बनी हुई है, उसका कारण हिन्दी नहीं है। इस तरह के और बहुत-से सगड़े हैं जिनका सम्बन्ध जातीय प्रदेशों के एकीकरण, सीमा निर्धारण, उद्योगीकरण आदि से है। इन सारे मतभेदों को भाषा-सम्बन्धी विवाद के धाते में नहीं ढाला जा सकता। इनसे स्पष्ट है कि देश में राष्ट्रीय एकता को बमजोर करनेवाले जातीय मतभेद के जो चक्र चल रहे हैं, उनसे हिन्दी का उन्नत कम सम्बन्ध है। राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा हिन्दी से नहीं है बल्कि इस जातीय विद्वेष और अलगवाय की भावना से है। तमिलनाडु में तमिल राजभाषा है किन्तु वहाँ ना एक दिन इस प्रदेश को भारत से

बहुजातीय राष्ट्रीयता और राष्ट्रभाषा हिन्दी / १२१

अलग करने की माँग करता है। उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में तमिलनाडु—इन दो प्रदेशों में कुछ दलों का भारत से अलगाव के नारे लगाना परिस्थिति की गम्भीरता की सूचना देता है।

यह बात सही है कि एक आदर्श अनन्त में किसी भाषा को विशेषाधिकार न मिलने चाहिए। किन्तु यह बात सही नहीं है कि हिन्दी को राजभाषा बनाने के विरोधी अंग्रेजी के विशेषाधिकारों के बारे में घुप रहे, उन्हें सिर झुकाकर स्वीकार कर लें, अंग्रेजी को अन्तर्राष्ट्रीय और विश्व-भाषा कहकर उन विशेषाधिकारों की रक्षा करें, इससे उनके अनुवादी अन्तःकरण को ज़रा भी कष्ट न हो, किन्तु हिन्दी के विशेषाधिकार प्राप्त करने की सम्भावना मात्र से वे आसमान सिर पर उठ लें। यह मनोवृत्ति मुस्लिम लीग के उन नेताओं की याद दिलाती है जो बहुसंख्यक हिन्दुओं के शासन-भय से अंग्रेजी राज की शरण लेते थे।

भारत एक बहुजातीय राष्ट्र है। राष्ट्रीयता और बहुजातीयता—इन दो पक्षों में से एक को भी भुलाना घातक होगा। जो लीग राष्ट्र का यह अर्थ लगाते हैं कि उसमें एक ही भाषा बोलनेवाले रहें, वे भारतीय राष्ट्रीयता के विकास को आँखों से ओझल कर देते हैं। छत्तान्दियों से यहाँ विभिन्न भाषाएँ बोलनेवाले लोग रहते आये हैं। आज यह तथ्य और भी स्पष्ट है—प्राचीन अतीत की समस्याओं की तरह अस्पष्ट और विषादास्पद नहीं, वर्तमान के उद्वलित सत्य के समान असदिग्ध है। इन जातियों की सीमारेखाएँ कोई मिटाना भी चाहे तो वह सफल न होगा। उनकी समानता, भाईचार, परस्पर सहयोग और एकता के बल पर ही राष्ट्रीय एकता दृढ़ हो सकती है।

साथ ही भारत देश एक राष्ट्र है, 'सब नॉन्टीनेन्ट' (उप-महाद्वीप) नहीं है। यहाँ सोवियत देश की तरह मजदूर वर्ग द्वारा सत्ता प्राप्त करने के बाद विभिन्न जातियों द्वारा स्वेच्छा से संघ बनाने का प्रश्न नहीं उठता। भारत विभिन्न जातियों द्वारा निर्मित संघ नहीं है, वह ऐतिहासिक विकासक्रम में संगठित एक राष्ट्र है। भारतीय जनता में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास विश्व इतिहास की अभूतपूर्व घटना है। समाजवादी सत्ता कायम होने से पहले इस तरह की बहुजातीय राष्ट्रीयता का विकास किसी देश में नहीं देखा गया। चीन में गैर-चीनी जातियों की स्थिति हमारे यहाँ के कोल-भिलों की दशा से मिलती जुलती थी। वहाँ उस तरह की बहुसंख्यक गैर-विकसित गैर-चीनी जातियाँ नहीं रही जैसी भारत में गैर-हिन्दी जातियाँ हैं। यूरोप के पूँजीवादी देशों ने जो बहुजातीय राष्ट्र कायम किये, उनमें धार्मिक जाति समूह सभी जातियों दासों की स्थिति में होती थी।

भारतीय राष्ट्र की एकरा की भावना अंग्रेजों की देन नहीं है, वह अंग्रेजों के आने से बहुत पहले की है। यह धार्मिक भावना माल नहीं है क्योंकि इसका सम्बन्ध एक ही धर्म से नहीं रहा। धार्मिक सहनशीलता और उदारता के कारण यहाँ प्राचीन काल से अनेक धर्म—अनीश्वरवादी धर्म तक—पल्लवित होते रहे

किन्तु यह देश बौद्धो, जैनो या हिन्दुओं का राष्ट्र नहीं माना गया। यह एकता केवल भौगोलिक नहीं है। यहाँ के राज्यों की, विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों की सीमाएँ देश से बाहर उत्तर-पश्चिम में दूर तक फैली रही हैं। यदि भौगोलिक एकता नियामक कारण होती तो भारत-विभाजन की नीबट न आती। भौगोलिक और धार्मिक कारण भी रहे हैं किन्तु मुख्य कारण है यहाँ की जातियों का सामान्य इतिहास, उनकी सांस्कृतिक समानताएँ, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उनका परस्पर सम्बद्ध और मिला-जुला विकास। इस ऐतिहासिक आधार पर ही यहाँ की राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ है।

मार्क्सवाद ने जानियों के विकास पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया है। लेनिन और स्तालिन के अनुसार जातियाँ पूँजीवाद के अन्त्युदय-काल की देन हैं। किन्तु मार्क्सवाद की किसी पुस्तक में भारत-जैसी बहुजातीय राष्ट्रीयता के विकास की व्याख्या नहीं मिलती। कुछ लोग यात्रिक ठग स यहाँ की परिस्थितियों पर मार्क्सवाद लागू करते हुए इस परिणाम पर पहुँचे थे कि यहाँ हर जाति अपनी सम्पूर्ण प्रमुख सम्पन्न विधान समा बनाये, फिर ये विधान समाएँ यहाँ अपना सघ निर्मित करें। इस तरह के विचारको के अनुसार सन् सत्तावन की राज्यक्रान्ति में राष्ट्रीय चेतना का अभाव था, कारण यह कि राष्ट्रीयता का आधार रेल-तार थे जिनका पूरी तरह चलन न हुआ था। भारतीय इतिहास की वास्तविकता पर ध्यान दिए बिना यह कभी समझ में न आयेगा कि माधवजी सिन्धिया ने पेशवा को मुगल बादशाह का नायब क्यो घोषित किया, १८५७-५८ में देश के विशाल भाग की जनता शाही झण्डे के नीचे क्यों सड़ी, साँसी में 'मुल्क बादशाह का, अमल रानी लक्ष्मीबाई का' की डुगगी क्यों पीटी गई। सी० एफ० ऐण्ड्रुज जैसे विदेशी लेखको ने ज्यादा सचाई से लिखा था कि अंग्रेजों ने आने के बाद राष्ट्रीय चेतना दृढ़ भले हुई हो, वह विद्यमान पहले से थी।

वर्तमान काल में जातियों की एकता और समानता की जो समस्या हमारे सामने है, उसका घनिष्ठ सम्बन्ध इस राष्ट्रीय चेतना के ऐतिहासिक विकास से है। हम जातीय समस्या और भाषा की समस्या को अपना इतिहास भुलाकर हल करेंगे या उसे राष्ट्रीयता के सन्दर्भ में हल करेंगे? राष्ट्रीयता के सन्दर्भ को भुलाकर जब हम उसे हल करते हैं, तब सीमान्त पर साम्राज्यवादी अड्डे कायम होते हैं। दस साल में एक बार भी आम चुनाव नहीं होता, जनतन्त्र के बदले धर्म-विशेष का राज्य कायम किया जाता है। साखों की तादाद में नर-नारी बेघर-बार होकर खुद तबाह होते हैं और देश के अर्थतन्त्र का सकट में डाल देते हैं। यह जातीय असंगत बहुत जल्दी साम्राज्यवादी गह्यन्त्र का अंग बन जाता है। त्रिन उप-निवेशों पर साम्राज्यवाद ने शासन किया है, उन्हें वह स्वाधीन नहीं देखना चाहता। एक साम्राज्यवादी ताकत गई तो दूसरी उसे हड़पने को तैयार रहती है। असंगत का नारा राष्ट्रीय एकता को कमजोर करनेवाला और साम्राज्यवाद तथा मुद्र की ताकतों को शहजोर करनेवाला है।

इसलिए जातीय समस्या और भाषाओं के समान अधिकारों की समस्या राष्ट्रीय एकता के सन्दर्भ में हल करनी होगी ।

भारत में प्रत्येक भाषा को अपने क्षेत्र में राजकीय और सांस्कृतिक कार्यों में पूर्ण अधिकार प्राप्त होने चाहिए । साधारण हिन्दी जनता, हिन्दी का शिक्षित वर्ग और लेखक इस स्थिति में पक्ष में हैं । हिन्दी-पत्रों में यह बार-बार कहा गया है कि हिन्दी किसी भाषा के अधिकार नहीं छीनना चाहती; अहिन्दी-भाषी जातियों के परस्पर व्यवहार के लिए अंग्रेजी की जगह हिन्दी होनी चाहिए ।

कई शताब्दियों से देश की विशेष परिस्थितियों के कारण हिन्दी अन्तर्जातीय व्यवहार की भाषा बनती रही है । उत्तर भारत में केन्द्रबद्ध मुगल शासन का होना, यहाँ आगरा जैसे व्यापार के बड़े-बड़े केन्द्रों का निर्माण, उन्नीसवीं सदी से पूर्व ही यहाँ के लोगों का विभिन्न प्रदेशों में फैलना ऐसे ही कारण थे । अंग्रेज व्यापारी भी उस समय अपनी सुविधा के लिए हिन्दी सीखते थे । वर्तमान काल में दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सर्वत्र ऐसे व्यापारी और पूँजीपति मिलेंगे जिनकी सांस्कृतिक भाषा हिन्दी है । हिन्दी ने प्रसार का एक बहुत बड़ा कारण कलकत्ता-बम्बई जैसे केन्द्रों में लाखों 'हिन्दुस्तानी' मजदूरों का निवास है । इन बड़े-बड़े नगरों के अतिरिक्त प्रत्येक जातीय प्रदेश में अल्पसंख्यकों के रूप में हिन्दुस्तानी मिलेंगे । विशाल आंध्र में हैदराबाद और उसके आस-पास हिन्दुस्तानियों का भारी जमघट है । अहिन्दी प्रदेशों में इस प्रकार हिन्दी को अन्तर्जातीय व्यवहार की भाषा बनाने में सुविधा मिली है ।

इसके अतिरिक्त सीलोन रेडियो और विविध भारती (और पाकिस्तान रेडियो भी) की कृपा से फिल्मी संगीत द्वारा देश के चारों कोनों तक रोज शाम-सबेरे हिन्दी गूँजती रहती है । कभी इन फिल्मी गानों की फरमाइश करनेवालों के नाम सुनिए । जितने हिन्दी-भाषी प्रदेशों के होते हैं, उतने ही अहिन्दी-भाषी प्रदेशों के । स्वयं गायकों और गायिकाओं में एक अच्छी संख्या अहिन्दी कलाकारों की रहती है । विनाश हिन्दी-भाषी प्रदेशों के लिए सबसे अच्छा बाजार है । ये व्यावसायिक परिस्थितियाँ बृहत्तों के न चाहने पर—और शायद उनके न जानने पर भी—हिन्दी को राष्ट्रभाषा बना रही हैं ।

इनके सिवा हिन्दी भाषा, लिपि और साहित्य की कुछ विशेषताएँ हैं जो इस कार्य में सहायता करती हैं । हम यहाँ उनका उल्लेख नहीं करते ।

हिन्दी अन्तर्जातीय व्यवहार की भाषा बन रही है, जनसाधारण के लिए अभी भी वह ऐसी भाषा है । वह केन्द्रीय राजकाज की भाषा भी जल्दी बन सकती है । इसमें एक बाधा है हिन्दी-भाषियों का असंगठन, उनमें जातीय चेतना की कमी । हिन्दी-भाषी प्रदेशों के राज्यों में भी हिन्दी अभी पूरी तरह राजकाज की भाषा नहीं बननी है । दक्षिण के लोगों की यह आपत्ति अनुचित नहीं है कि पहले अपने घर में हिन्दी को राजभाषा बना लो, फिर उसे सारे देश की राष्ट्रभाषा बनाना । यदि हिन्दी भाषी जनता समीकृत हो, यदि वह अपने प्रदेश में हिन्दी

हिन्दी की व्याकरण-सम्बन्धी कठिनाइयाँ

हिन्दी की व्याकरण-सम्बन्धी कठिनाइयों से कुछ अंग्रेजी-प्रेमी भारतवासी इतना परेशान हैं कि वे कभी कभी उसके चलरत्ता-बम्बई जैसे नगरी में कुछ अहिन्दी-भाषियों द्वारा व्यवहृत रूप को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की बात करते हैं। इनमें राजनीतिक नेताओं के अलावा कुछ प्रसिद्ध भाषा-वैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने यथेष्ट गम्भीरता से यह प्रस्ताव रखा है। अंग्रेजी के सम्पर्क में आने-वाले हिन्दुस्तानी खानसामा भी अंग्रेजी का एक सरल रूप काम में लाते थे जो साहब और उनके बीच की सांस्कृतिक आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए पर्याप्त होता था। कुछ देशों के पुलियो आदि ने इसी तरह अंग्रेजी को सरल करके अपना काम निवासा है। लेकिन हम देश में न तो हिन्दी भाषी जनता अंग्रेज साहबों की स्थिति में है, न अहिन्दी-भाषी जनता पुलियो और खानसामाओं की। इस कारण जो लोग हिन्दी के लघुलिपि सरल व्याकरण विहीन रूप को अपनाने की बात करते हैं, वे अपने और हिन्दी-भाषियों के प्रति अन्याय ही करते हैं। वहना न होगा कि खानसामा-अंग्रेजी को भारत की लिगुआ-फाङ्का या विश्वभाषा बनाने की बात नहीं की जाती। इसके विपरीत इस कोटि के राष्ट्रभाषा-प्रेमी अंग्रेजी-शिक्षा का स्तर गिरने से निरन्तर घबराते रहते हैं और आए दिन इस स्तर को उठाने के लिए नये-नये उपाय भी सुझावा करते हैं। यह बात भी कम मनोरंजक नहीं है कि एक ओर वे हिन्दी के दरिद्र होने की, उसमें उच्च कोटि के साहित्य के अभाव की घोषणा करते हैं, दूसरी ओर व्याकरण की कठिनाइयों से मुक्त हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाने का 'जनतांत्रिक' सुझाव भी देते हैं।

अंग्रेजी भाषा में व्याकरण-सम्बन्धी कठिनाइयाँ कम नहीं हैं। डेढ़ सौ साल से लगातार अंग्रेजी पढ़ने के बाद भी इस भाषा की सीखने का स्तर जो गिरता नज़र आ रहा है, उसका कारण विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिभा के अलावा उस भाषा की खूबियाँ भी हैं। किन्तु अंग्रेजी-प्रेमी देशभक्त अपनी प्रिय भाषा की व्याकरणगत कठिनाइयों से जरा भी विचलित नहीं होते, उन्हें शिकायत है हिन्दी की कठिनाइयों से। इनमें भी सारे फसाद की जड़ उनकी समझ में हिन्दी का लिग-

भेद है ।

हिन्दी शब्दों की लिंग-सम्बन्धी कठिनाई वास्तविक है । यह कठिनाई आहन्दी-भाषियों के लिए ही नहीं है, भोजपुरी आदि पूर्वी बोलियों के क्षेत्रों में हिन्दी बोलने-वालों के लिए भी यह कठिनाई विद्यमान है । इतिहासकारों का कहना है कि एक बार दिल्ली के क्लेग्राम में 'खारा पानी' कहनेवालों को पछाँह का समझकर छोड़ दिया गया, 'खारी पानी' कहनेवालों को पूरब का मानकर उन्हें तलवार के घाट उतार दिया गया । इस कठिनाई में ऐसे नतीजे भी निकल सकते हैं ।

भाषा का निर्माण किसी अकादमी में नहीं होता, न उसका व्याकरण बनाने का काम राजनीति विचारद्वय करते हैं, वरना यह कठिनाई दूर हो जाती । सस्कृत के महान् व्याकरण भी, जो भाषा को व्यवस्थित करने में अपना सानी नहीं रखते, इस कठिनाई से पार न पा सके । चन्द्र पुल्लिङ्ग, मित्र नपुंसक लिंग । वृक्ष जैसा जड़ पदार्थ पुल्लिङ्ग, हृदय प्रेमा सरल और अनिशील पदार्थ नपुंसक लिंग । पासु (घृन), परशु, इषु (बाण) जैसे निर्जीव पदार्थ पुल्लिङ्ग हैं, शरीर और शीर्ष जैसे मजीव पदार्थ नपुंसक लिंग हैं ।

इस देश के सांस्कृतिक इतिहास में सस्कृत का जो महत्त्व रहा है, उसे सभी लोग जानते हैं । भारत की भाषाओं पर उसका जो व्यापक प्रभाव पड़ा है, वह भी किसी ने छिपा नहीं है । सस्कृत शब्दों की लिंग-सम्बन्धी कठिनाई से उसके प्रसार में कोई बाधा नहीं पड़ी । सम्भव है, कुछ सज्जन कहें कि इस कठिनाई के कारण ही वह मृत भाषा हुई । यदि ऐसा होता तो सस्कृत भाषी प्रदेश की भाषाएँ—जिनमें हिन्दी सर्वोपरि है—इस कठिनाई से मुक्त होती ।

सस्कृत के समान यूरोप की भाषाओं और सस्कृति पर प्राचीन यूनान की भाषा—वहाँ अनेक भाषाएँ थी, हमारा तात्पर्य एथेन्स की भाषा से है—का प्रभाव पड़ा । किसी समय वह भूमध्य सागर के तट पर फैले हुए अनेक यूनानी उपनिवेशों के कारण एक विशाल भूभाग में फैल गई थी । इस भाषा में अरस्तू और अफला-तून जैसे विचारकों ने, सोफोक्लीज, यूरिपिदीज जैसे नाटककारों ने, हेराक्लितस जैसे दार्शनिकों ने अपनी रचनाएँ की जिनके आधार पर यूरोप की सस्कृति का प्रासाद निम्न हुआ । इस भाषा में जनैस (सस्कृत जन) नपुंसक है किन्तु दिमोस (जनता) पुल्लिङ्ग है । घूरा (घार), मातइय (तलवार), अकन्था (बाँटा) जैसी वेश्मन चीजें स्त्रीलिंग हैं । यदि आप कहें ये आकारान्त हैं, इसलिए स्त्रीलिंग हैं तो देखिए म्नीमा (समाधि), ओइको दोइमा (भवन) आदि नपुंसक लिंग हैं । नेत्रोस् (शव) तो पुल्लिङ्ग है, पाइदिओन् (मिथु) नपुंसक लिंग है ।

प्राचीन यूनानी के समान और भी बड़े पैमाने पर लैटिन व्यवहार में आई । वह शताब्दियों तक इटली ही नहीं, यूरोप की धार्मिक और सांस्कृतिक भाषा रही । इसमें भी यूनानी भाषा की तरह लिंगभेद वर्तमान था । अग्नि के लिए दो शब्द हैं, 'इन्केण्डियम्' और 'इग्निस', पहला नपुंसक, दूसरा पुल्लिङ्ग है । जनता के लिए दो शब्द हैं, गेन्स (जन) और पोपुलुम्; पहला स्त्रीलिंग है, दूसरा पुल्लिङ्ग । इम्पेर

(वर्षा), टूरिस् (मीनार), मारे (मगुद्र) तीनों को स्वभावतः नपुंसक लिंग होना चाहिए किन्तु ये अमश पुंलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग हैं। अकीला (बाज) और अग्रिबोला (वृषक) देखने में एक-से आकारान्त शब्द हैं किन्तु पहला स्त्रीलिंग है, दूसरा पुल्लिंग।

लैटिन की उत्तराधिकारिणी भाषाओं में फ्रांसीसी भाषा भी है। वह यूरोप में अन्तर्जातीय व्यवहार की भाषा रही है। उसमें घर के लिए दो शब्द हैं, मँजों, बातीमाँ, पहला स्त्रीलिंग है, दूसरा पुल्लिंग। इसी प्रकार घरती के लिए लैयर और पेयी, मार्ग के लिए रूत और शर्म शब्दों में पहला स्त्रीलिंग है, दूसरा पुल्लिंग। फ्रांसीसी लोग पर्वत जैसी विशाल वस्तु (मोताञ्ज) को स्त्रीलिंग विशापित करते हैं, पुस्तक जैसी छोटी चीज (लीव्र) को पुल्लिंग।

यूरोप के एक विशाल प्रदेश में व्यवहृत फ्रांसीसी की तरह एक हृद तक अन्तर्जातीय व्यवहार की भाषा जर्मन है। उसमें संस्कृत के समान ही लिंगभेद है। परधर (पटाइन), वृक्ष (बाउम), जूता (शू) जैसे निर्जीव पदार्थ पुल्लिंग हैं, जनता (फोल्क), नारी (इसके लिए एक शब्द क्लाइप भी है), सड़की (मैइडेन) आदि सजीव वस्तुएँ नपुंसक लिंग हैं। संस्कृत के समान जर्मन में तीनों लिंग विद्यमान हैं और शब्द के अर्थ या रूप से उन्हें पहचानना आसान नहीं है।

संसार के छोटे भाग में फैले हुए सोवियत संघ की अन्तर्जातीय व्यवहार की भाषा रूसी है। इसमें भी संस्कृत और जर्मन की तरह तीनों ही लिंग हैं। अधिकतर निर्जीव पदार्थ नपुंसक लिंग होते हैं किन्तु पुस्तक (क्नीगा), होटल (गस्ती-निस्ता), पुस्तकालय (बिब्लियोतेका) आदि शब्द स्त्रीलिंग हैं। यद्यपि शब्दों के रूप से उनका लिंग पहचाना जा सकता है, फिर भी इस विषय में नियमों के अनेक अपवाद हैं।

प्राचीन काल से आज तक संसार की अनेक और प्रमुख भाषाएँ शब्दों में लिंगभेद करती रही हैं। यह भेद वास्तविक न होकर—शब्दों द्वारा विशापित वस्तु के लिंग का अनुसरण करके—बहुधा शब्दों के रूप के अनुसार होता है। शब्दों का रूप देखकर उसका लिंग निश्चित करना सदा सरल नहीं होता। इस सम्बन्ध में कुछ मोटे नियमों का पालन किया जाता है किन्तु उनके अपवादों की संख्या कम नहीं है। भाषा संसार के पदार्थों, मनुष्य के व्यवहार और चिन्तन की अभिव्यक्ति के लिए ही विकसित हुई है। वह इस भौतिक जगत् और मनुष्य के भौतिक जीवन से बिलग होकर विकसित नहीं हुई। उसकी जड़ें इसी भौतिक जीवन और जगत् में हैं। किन्तु भाषा भौतिक जगत् से मनुष्य का सम्बन्ध विशापित करने का साधन ही नहीं है। जैसे मगीत में विभिन्न प्रदेशों की जातियों को स्वरो का विशेष सामग्र्य, उनका विशेष आरोह-अवरोह पसन्द आता है, वैसे ही भाषा के क्षेत्र में विभिन्न जातियाँ शब्दों के साथ विशिष्ट रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करती हैं। एक ही वस्तु के लिए विभिन्न भाषाओं के पर्यायवाची शब्दों में लिंग-सम्बन्धी अन्तर होता है। एक ही भाषा में किसी वस्तु के लिए भिन्न लिंगवाले पर्याय-

वाची शब्दों का प्रयोग देखा जा सकता है। दूसरो ने लिए इस वैचित्र्य के कारण भाषा बठिन हो जाती है किन्तु उगने बोलनेवालों के लिए इस वैचित्र्य का रागात्मक मूल्य है। भाषा के समस्त ऐतिहासिक विकास के फलस्वरूप यह विभिन्नता उत्पन्न होती है। यह भाषा की सजीव परम्परा न अग होनी है। उसे समाप्त करना वैसे ही असम्भव है जैसे मुहावरों का समाप्त करना। मुहावरों की तरह लिए भेद सीखना होता है। अन्तर्जातीय व्यवहार की कठिनाइयाँ दूर करने के लिए भाषा के रूप को न तो आज तक कहीं बदला गया है, न अब बदला जा सकता है। अन्य भाषाओं और जातियों के सम्पर्क में आने से भाषा में परिवर्तन होते हैं। किन्तु इन परिवर्तनों का सम्बन्ध व्याकरण से सबसे कम होता है। ग्रन्थी ने ससार की अनेक भाषाओं में शब्द लिये हैं—वास्तव में जर्मन या रूसी की तुलना में उसकी अपनी पूँजी नगण्य है—किन्तु उसके व्याकरण में कितना परिवर्तन हुआ है? उसने शब्द दूसरो के लिये किन्तु व्याकरण के रूप अपने रखे। उसका शब्द-भण्डार जितना मिश्रित है, उसका व्याकरण उतना ही अपेक्षाकृत विमुक्त।

खड़ी बोली ने अरबी-फारसी में संकड़ो शब्द लिये, उसका उर्दू रूप विकसित हुआ। कुछ विद्वानों का विचार है कि बाहर से आनेवाले मुसलमान यहाँ की भाषा समझते न थे, उनकी अपनी भाषाओं और यहाँ की बोलियों—अथवा खड़ी बोली और फारसी—के मिश्रण से फोजी बोलों और बाजारा में उर्दू का जन्म हुआ। बाहर से आनेवाले गुगनमानों की भाषा क्या थी, एब थी या एक से अधिक थी, बंगाल, ब्रह्मी, पंजाब, केरल आदि प्रदेशों में मुसलमान यहाँ की भाषा वैसे समझते लगे, इन प्रश्नों का विवेचन न करके हम केवल इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे कि उर्दू की जन्म देनेवाले मुसलमानों की व्याकरण-रूपों को स्वीकार करने में चाहे जो कठिनाई हुई हो, खड़ी बोली के व्याकरण-रूपों को उन्होंने सप्रम स्वीकार कर लिया। इन रूपों में लिए-भेद भी है। ऐसा नहीं हुआ कि लिए-सम्बन्धी कठिनाई दूर करके बाहर से आनेवाले मुसलमानों ने खड़ी बोली को अपनाया हो। उन्होंने यहाँ की व्याकरण-परम्परा को—जैसे सीपना शब्दों को ग्रहण करने से ज्यादा कठिन था—स्वीकार किया। भारत की अनेक भाषाएँ—जैसे बंगला—शब्द-भण्डार की दृष्टि से हिन्दी के जितना निरट हैं, उतना उर्दू नहीं है। यदि बाहर से आनेवाले मुसलमान यहाँ के लिए सम्बन्धी भेद सीख सकते थे तो शब्द-भण्डार की इतनी समानता रहने पर बंगाली भिन्न उनसे क्यों पार नहीं पा सकते? इस कारण 'भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी' में डॉ॰ सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित सुझाव अभी तक अप्राप्त रहा है 'परन्तु यदि ये व्याकरण-विषयक विनिष्टताएँ, जो बाकी के भारतवासियों के लिए वास्तविक कठिनाइयाँ बन रही हैं कम कर दी जायँ, जैसा कि पूर्वी हिन्दीवालों तथा विद्वारियों ने किया है (२१), तो संस्कृतनिष्ठ प्रचलित हिन्दुस्थानी, एब अत्यन्त सहज, सुबोध तथा ओजपूर्ण भाषा बन जाती है। इस सहज बनी हुई हिन्दुस्थानी का

हिन्दी की व्याकरण सम्बन्धी कठिनाइयाँ १

सारा व्याकरण एक पोस्टकार्ड पर लिखा जा सकता है। 'बाजारू हिन्दुस्थानी' के सदृश सुगठित तथा ओजपूर्ण भाषा को हाट बाजार से, जहाँ पर कि उसका स्वतन्त्र, अनवरुद्ध जीवन-प्रवाह पण्डितों की घृणा की परवाह न करते हुए अनवरत रूप से बहा चला जा रहा है, उठाने की आवश्यकता है। हमें उसे आदरपूर्ण आन्तर्जातिक या आन्तर्देशिक भाषा के इतने उच्च स्तर तक उठाना होगा कि वह कम-से-कम सार्वजनिक सभा-सम्मेलनों आदि में प्रयुक्त होने योग्य बन जाय। इसमें साहित्य का सृजन बाद में हो सकता है—आगे चलकर होगा ही (१)। परन्तु वह सारी भविष्य की बात है। अभी हाल के लिए हमें एक द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है, जिससे सर्वसाधारण को परिचित हो जाने के लिए कहा जा सकता है। यह उसी भाँति फारसी-युक्त उर्दू तथा नागरी-हिन्दी के साथ साथ प्रयुक्त होती रहेगी, जैसे आज होती है।”

अस्तु परिणाम यह निकला कि हिन्दी की सिंग-सम्बन्धी कठिनाइयाँ दूर करके उसे सरल नहीं बनाया जा सकता। जिस तरह खानसामा-अंग्रेजी को राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला उसी तरह अहिन्दी-भाषी प्रदेशों में कुछ लोगों द्वारा व्यवहृत हिन्दी के टूटे फूटे रूप को देश के राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवहार की भाषा नहीं बनाया जा सकता। यह सही है कि हिन्दी-भाषियों को दूसरों की त्रुटियों पर हँसना न चाहिए, वरन् भाषा-सम्बन्धी अपने प्रयोगों के प्रति उन्हें अधिक सचेत होना चाहिए। साथ ही यह भी सही है कि कुछ अहिन्दी-भाषी मिन हिन्दी की व्याकरण सम्बन्धी कठिनाइयों को दुर्लक्ष्य बतलाकर, उन्हें दूर करके भाषा को सरल करने का सुझाव देकर अन्तर्जातीय व्यवहार की भाषा-समस्या हल नहीं कर सकते। धैर्य, उदारता और परिश्रम से ही इस कठिनाई पर विजय प्राप्त हो सकती है।

(१९५८)

उर्दू की समस्या

प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस की कार्य-कारिणों तथा अन्य राजनीतिक सस्याओं ने पिछले दिनों उर्दू के संरक्षण की समस्या की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया है। उनके वक्तव्यों का यह मूल्य है कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण समस्या पर ध्यान केन्द्रित किया है जिसके प्रति साधारणतः हिन्दी-भाषी जनता उदासीन हो गई थी। इससे सिद्ध यह होता है कि भारत के साम्राज्यवादी विभाजन में जो अनेक समस्याएँ नहीं सुलझी, उनमें उर्दू की भी एक समस्या है। दुर्भाग्य से इन वक्तव्यों में यह नहीं बतलाया गया कि उर्दू के संरक्षण या दमन के लिए उत्तरदायी कौन है विभाजन के बाद यह समस्या अब भी क्यों बनी हुई है, उर्दू के संरक्षण के लिए कौन से उपाय किये जाने चाहिए, इत्यादि। संक्षेप में स्थिति यह है कि भावुकता के अलावा वैज्ञानिक स्तर पर इस समस्या के बारे में इन वक्तव्यों में कुछ नहीं कहा गया।

एक समय था जब कांग्रेस का नेतृत्व हिन्दी-उर्दू को मूलतः एक भाषा मानता था, उनमें अनावश्यक सस्कृत और अरबी शब्द भरने का विरोधी था, हिन्दुओं और मुसलमानों की मिली-जुली भाषा को कौमी जवान कहता था और उसे राजभाषा बनाने पर जोर देता था। आज स्थिति बदल गई है। कौमी जवान की बात करना तो महापाप है, जो सबके प्रगतिशील बात कही जा सकती है, वह यह कि उर्दू को दबाया न जाय। और कौमी जवान के राष्ट्रभाषा बनने का मकाल नहीं, शुद्ध राष्ट्रभाषा हिन्दी भी राजभाषा नहीं बन पाई, सारे देश में नहीं बन पाई, और अपनी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश—तथा अन्य हिन्दीभाषी राज्यों—में भी वह राजभाषा नहीं बन पाई।

देश के राष्ट्रीय नेताओं ने साम्प्रदायिक समस्या को हल किया साम्प्रदायिक माँगों को स्वीकार करके। साम्प्रदायिकता के आधार पर किये हुए समझौते के घूँस में राष्ट्रीयता के पत्र न लगे तो इसमें आश्चर्य क्या? उर्दू का नाम गुप्त ही बहुत-से हिन्दी-प्रेमी स्वभावतः परेगान हो उठते हैं। आखिर इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए तो पाकिस्तान बना और यह उर्दू का बसेड़ा अब भी बना हुआ है।

उर्दू-प्रेमियों ने अलग परेशान होकर बीभी जवान की इताबाई जवान बनाने के लिए दस्तखत टक्कठें किये। उन्होंने उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में अंग्रेजों की हड़ताने के लिए आन्दोलन करना जरूरी नहीं समझा। न उन्होंने इस आन्दोलन की नीति निर्धारित करने के लिए हिन्दी प्रेमियों में सलाह-मशविरा किया। इसलिए वैधानिकता का जामा पहनने पर भी यह एक सीमित साम्प्रदायिक आन्दोलन ही रहा।

उर्दू के सम्बन्ध में अनेक गलत धारणाएँ हिन्दी-प्रेमियों और उर्दू-प्रेमियों दोनों के मन में बनी हुई हैं। इन पर संक्षेप में विचार करना आवश्यक है।

एक धारणा यह है कि मुसलमानों ने यहाँ आकर उर्दू का एक प्रकार का धार्मिक प्रेम है, वे इसे अपने धर्म और विशेष सत्त्वृति की भाषा समझते हैं। बहुत-से हिन्दू इस धारणा को स्वीकार करते हैं। उनकी दृष्टि में मुसलमान सभी हिन्दुस्तानी नहीं बना, इसलिए उर्दू भी 'अरब जेहादियों का नीतिरत्न' है। हिन्दुओं और मुसलमानों में जो चरम साम्प्रदायिकतावादी हैं, वे उसके प्रति एक-सा ही प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। यहाँ दृढ़ बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि अनेक साम्प्रदायिकतावादी भाषा-वैज्ञानिकों का भी यह मत रहा है कि उर्दू इस्लाम की भाषा है।

यदि उर्दू इस्लाम की भाषा है तो पूर्वी बंगाल के मुसलमान अंगला क्यों बोलते हैं? उन्होंने उर्दू के एकमात्र राजभाषा बनाये जाने के विरुद्ध सपर्यं क्यों किया? बंगाल के अलावा बेरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, वज्मीर आदि प्रदेशों के मुसलमान घर में उर्दू क्यों नहीं बोलते? और हिन्दुस्तान-पाकिस्तान से बाहर तुर्की, ईरान, इराक आदि राष्ट्रों में उर्दू क्यों नहीं बोली जाती?

स्पष्ट है कि सत्सार में एक हिन्दुओं की भाषा, एक मुसलमानों की भाषा, एक बौद्धों या ईसाइयों की भाषा नहीं है। भाषाओं का निमाण और विकास धर्म के आधार पर नहीं हुआ। धार्मिक विचारधाराओं के कारण उनके लिखने-बोलने-वालों ने उनमें कुछ नई विशेषताएँ पैदा कीं, वह दूसरी बात है। भाषा का सम्बन्ध जातीयता से है, किसी जाति के सामाजिक और सांस्कृतिक विचार से है। जाति और धर्म एक वस्तु नहीं है। ईरानी, इर की, तुर्की जातियाँ इस्लाम धर्म मानती हैं किन्तु इनकी भाषाएँ अलग-अलग हैं। इसी प्रकार भारत की विभिन्न जातियों की अपनी-अपनी भाषाएँ हैं, उन जातियों के प्रदेशों में हिन्दू-मुसलमान दोनों ही उन भाषाओं को बोलते हैं, उनमें अपना सांस्कृतिक काम-काज करते हैं। उर्दू का व्यवहार कहीं के मुसलमान करते हैं? सबसे पहले हिन्दी-भाषी प्रदेश के, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्यप्रदेश आदि के। कारण यह कि उर्दू यदि कहीं की जातीय भाषा है तो हिन्दी भाषी प्रदेश की है। इसके बाद कलकत्ता, हैदराबाद, बम्बई जैसे नगरों में मुसलमानों की बस्तियाँ हैं जो अपने मूल प्रदेश से वहाँ पहुँचे हैं या जिनके पुरखे पहले वहाँ पहुँचे थे। इनके बाद

कश्मीर आदि प्रदेशों के मुसलमान हैं जिनकी मातृभाषा कश्मीरी है या अन्य कोई भाषा है और जो उर्दू भी जानते हैं और उसे काम में लाते हैं।

धर्म के आधार पर उर्दू की रक्षा की बात करना या उसे इस्लाम की भाषा समझकर उसका नाश करने की बात सोचना एक अवैज्ञानिक और प्रतिक्रियावादी कार्य है।

उर्दू इस्लाम की भाषा है, इस धारणा में भिन्न एक दूसरी स्थापना है जो प्रगतिशील और राष्ट्रीय समझी जाती है। वह यह है कि उर्दू हिन्दुओं और मुसलमानों के मेल से बनी है। दूसरे शब्दों में उर्दू केवल इस्लाम की भाषा नहीं, वह इस्लाम और हिन्दू धर्म दोनों की भाषा है। यह स्थापना देखने में प्रगतिशील मालूम होती है क्योंकि वह राष्ट्रीयता के लिए आवश्यक हिन्दू-मुस्लिम-एकता की ओर सचेत करती है। इस स्थापना का सहारा लेकर ही अनेक राष्ट्रीय नेताओं और विचारकों ने भाषा-समस्या को हल करने का प्रयत्न किया था और उसमें असफल भी हुए थे।

यदि हिन्दुओं और मुसलमानों के मिलने से उर्दू बनी होती तो बम्बई से बलुक्ता तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जातीय प्रदेश में उर्दू ही बोली जाती, बंगला, मराठी, कश्मीरी, मलयालम आदि भाषाओं का अस्तित्व ही न होता। उर्दू एक विशेष जातीय प्रदेश की भाषा है, भारत के सभी जातीय प्रदेशों की नहीं। उसे मातृभाषा के रूप में काम में लानेवाले वही लोग हैं जो हिन्दी-भाषी प्रदेश के निवासी हैं या वहाँ से जाकर दूसरे प्रदेशों में बस गए हैं। हिन्दी-उर्दू एक ही जातीय प्रदेश की भाषा है, इसीलिए उनका बोलचाल का रूप एक-सा है या प्रायः एक-सा है।

भारत में जो मुसलमान आये उनमें कोई पश्तो बोलता था, कोई तुर्की, कोई अरबी, कोई फारसी। उनकी भाषाएँ कम से कम तीन भिन्न परिवारों की हैं। तुर्की, अरबी, फारसी एक दूसरे से भिन्न भाषा-परिवारों की हैं। यदि उर्दू का निर्माण हिन्दुओं-मुसलमानों के मिलने से होता तो उसमें तुर्की के उतने ही शब्द होते जितने फारसी के। या इस्लाम धर्म का सम्बन्ध विशेष रूप से अरबी से जोड़ा जाय तो उर्दू में तुर्की फारसी का बहिष्कार और अरबी सस्कृत का बराबर सम्मिश्रण होना चाहिए था। बाहर से आनेवाले मुसलमानों ने राजभाषा के लिए अरबी नहीं, फारसी को चुना। उनका धर्मग्रन्थ अरबी में है, फारसी में नहीं। फारसी पर अरबी का प्रभाव है, फिर भी वह मूलतः भारत-यूरोपीय परिवार की भाषा है और अरबी की अपेक्षा वह सस्कृत के अधिक निकट है। मुसलमान सामन्तों ने अरबी को राजभाषा क्यों न बनाया? इस पद के लिए उन्होंने फारसी को क्यों चुना? इसलिए कि वे सामन्त अनेक वर्गों के बीच के बाधन मुस्लिम लोग के नेताओं से अधिक उदार थे। फारसी को चुनने में धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक कारण प्रधान थे। गान्धिविक दृष्टि से ईरान समृद्ध राष्ट्र था, मध्य एशिया और मध्यपूर्व के देशों पर ईरानी सत्त्व की छाप थी। बाहर से आनेवाले मुसलमान यह छाप

अपने साथ लाए थे। मुगल सम्राटों के यहाँ दरबारियों में काफी ईरानी होते थे; फारसी बोलचाल की भाषा थी। इस कारण मुगल राज्यसत्ता में फारसी का बोलबाला रहा।

मुसलमान सामन्तों ने राजभाषा में रचनाएँ की, अनेक सूफियों ने अवधी में काव्य लिखे, रमखान और रहीम जैसे कवियों ने ऐमी गरस कविताएँ लिखी कि वे आज भी गाँवों में लोगों की जवान पर रहे। हिन्दी भाषी प्रदेश स बाहर कश्मीरी, पंजाबी, बंगला आदि भाषाओं और उनके साहित्य के उत्थान और विकास में मुसलमानों ने महत्वपूर्ण योग दिया। बाजकल बहुत-से हिन्दू-मुसलमान इन बातों को याद करना पसन्द नहीं करते। उनसे एक अनचाहा परिणाम निकलता है कि मुगल शासनकाल में फारसी के राजभाषा रहते हुए भी यहाँ की जातीय भाषाओं ने अभूतपूर्व उन्नति की और इस उन्नति में मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ था। हिन्दू साम्प्रदायिकों को यह निष्कर्ष पसन्द नहीं है क्योंकि उनके अनुसार मुसलमानों ने भारत का कभी अपना देश नहीं समझा, फिर वे यहाँ की भाषाओं और उसके साहित्य की उन्नति में योग कैसे दे सकते थे? मुस्लिम साम्प्रदायिकों को यह निष्कर्ष पसन्द नहीं क्योंकि जातीय भाषाओं के विकास के इस चौखटे में उनकी उर्दू-मध्यस्थ धारणाएँ फिट नहीं होती।

तब उर्दू का विकास क्या साम्प्रदायिक कारणों से हुआ? या उर्दू हमारी जातीय भाषा थी और उसके मुजावले में हिन्दी का विकास साम्प्रदायिक कारणों से हुआ?

उर्दू का बोलचालबाना रूप वही या शायद वही है जो हिन्दी का है। इस रूप का एक नाम खड़ी बोली है। इस बोलनेवाले हिन्दू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, ईसाई अनेक धर्मों के लोग हैं। इस रूप को न तो मुसलमानों ने जन्म दिया, न उसे अवध और बिहार में फैलाने में एवमास उन्होंने भाग लिया। फारसी के राजभाषा रहने के कारण इस खड़ी बोली में फारसी के सैकड़ों शब्द आये। फारसी के माध्यम से सैकड़ों अरबी शब्द भी खड़ी बोली में आये। उर्दू के समर्थकों का कहना है कि उर्दू को संवारने और निखारनेवाले हिन्दू भी थे। यह बात सही है। इन मिस्रों को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि उर्दू को संवारने में हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों ने हिस्सा लिया, फिर भी खड़ी बोली का एक दूसरा रूप हिन्दी क्यों विकसित हुआ? प्रेमचन्द जैसे देशभक्त उर्दू प्रेमी लेखकों ने हिन्दी-सेवा क्यों की?

बहुत से उर्दू-प्रेमियों की यह धारणा है कि एक अच्छी खासी मुश्तक जवान बन गई थी, हिन्दीवालों ने एक साम्प्रदायिक आन्दोलन चलाया और अरबी-फारसी के मोठे शब्दों की जगह संस्कृत के भारी-भरकम शब्द रखकर एक नकली जवान गड़ती। उसी साम्प्रदायिक भाषा को अब लोग राष्ट्रभाषा कहने लगे हैं। हिन्दुओं की साम्प्रदायिकता और विश्वासघात के कारण उर्दू का गला घोंटा जा रहा है।

ये मिस्र दो चीजें बातें भूल जाते हैं। खड़ी बोली में अरबी फारसी के शब्दों की आमद हिन्दुओं और मुसलमानों के मिलन का परिणाम नहीं बरन् यहाँ फारसी

के राजभाषा बनाये जाने का परिणाम है। फारसी यहाँ के किसी प्रदेश की भाषा न थी, न वह बाहर से आनेवाले सभी मुसलमानों की भाषा थी, न वह भारत के हिन्दुओं और मुसलमानों के मेल से बनी हुई भाषा थी। ईरान के प्रति अपनी सांस्कृतिक गुलामी के कारण उन सामन्तों ने उसे राजभाषा बनाया जिनकी मातृ-भाषा तुर्की या कोई अन्य गैर-फारसी भाषा थी। फारसी को राजभाषा बनाना यहाँ की भाषाओं के साथ अन्याय करना था। इस अन्याय में मुसलमानों के साथ अनेक हिन्दू सामन्त और उनके आश्रित वर्गकारी भी शामिल थे। किसी विदेशी भाषा को राजभाषा बनाना जातीय उत्पीड़न का एक रूप है। इस तरह के जातीय उत्पीड़न में पूँजीपति ही नहीं, उनमें पहले सामन्त भी भाग ले चुके हैं। इस उत्पीड़न में बहुत-से हिन्दू शामिल हुए किन्तु इनके विपरीत बहुत-से हिन्दू अपनी पहचान से चलो आते हुई भाषा या भाषाओं के लिए सदैव भी। उन्होंने फारसी के बदले ब्रज या अवधी में रचनाएँ कीं। इन हिन्दुओं के साथ बहुत-से मुसलमान भी थे। सामन्त वर्ग और जनसाधारण—इन दोनों की सांस्कृतिक नीति अलग-अलग थी। सामन्त वर्ग मुख्यतः ईरानी सभ्यता का मूँह जोड़ता था, जनसाधारण अपनी भाषा और लोक सभ्यता के विकास में लगे हुआ था।

अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा को जातीय उत्पीड़न को और तीव्र किया। अंग्रेजी और फारसी राजभाषाएँ रहीं लेकिन दोनों के उत्पीड़न में अन्तर था। फारसी एशिया की ही और हमारे पड़ोस की एक भाषा थी। उसे राजभाषा बनानेवाले हिन्दी या ब्रज में कविताएँ करते थे, यहाँ की भाषाओं को प्रोत्साहन देते थे विशेष रूप से संगीत में उन्होंने यहाँ की समूची परम्परा को अपना लिया। उर्दू की तरह संगीत में अरबी-फारसी तानों से लदी हुई शैली का चलन न हुआ। राजभाषा अंग्रेजी की तुलना में राजभाषा फारसी का उत्पीड़न बहुत सीमित था।

सामन्तकाल में शिक्षा का काम पुरोहित वर्ग के हाथ में रहता है। इसलिए शिक्षा के नाम पर संस्कृत या अरबी-फारसी की पढ़ाई होती रही। इस कारण शिक्षित वर्ग में फारसी पढ़े साम दर्शन, साहित्य आदि की विशिष्ट शब्दावली के लिए फारसी से शब्द लेने लगे। नौकरी के लिए फारसी या उर्दू की जानकारी आवश्यक होती थी, इसलिए हिन्दू-मुसलमान दोनों काफी संख्या में फारसी-उर्दू सीखते थे। किन्तु यह हिन्दू-मुस्लिम-एकता विशेष आप्रिय और सामाजिक कारणों से पैदा हुई थी, इसलिए वह टिकाऊ न हुई।

उर्दू ने दर्शन, साहित्य, राजनीति आदि के लिए, या सभ्य व्यवहार के लिए केवल अरबी-फारसी शब्द लिये। उसके वोलचाल के रूप में तो हिन्दी शब्दों की भरमार थी लेकिन सभ्य व्यवहार के रूप में—‘तशरीफ लाइये, नोश परमाइये’ वाले रूप में—और साहित्य में जो नये शब्द आये, वे सब के-सब अरबी-फारसी थे। इस तरह उर्दू के वोलचाल के रूप में तो भाषा की जातीय परम्परा कायम रही लेकिन उसके सांस्कृतिक रूप में वह नष्ट हो गई।

उर्दू ने अपने इस नये विरचित रूप को दो धाराओं से अलग कर लिया।

एक तो वह हिन्दी की बोलियों—अवधी, ब्रज, बुन्देलखण्डी, भोजपुरी और खड़ी बोली के ही ग्रामीण रूप—से बहुत दूर चली गई। दूसरे, वह भारत की अन्य भाषाओं—बंगला, मराठी, गुजराती आदि—की सामान्य विशेषताओं से दूर जा रही। संस्कृत के कठिन शब्दों के नाम पर उसने उन तमाम शब्दों का बहिष्कार करना शुरू किया जो भारत की अन्य सभी भाषाओं की सामान्य निधि हैं। इस तरह उर्दू-प्रेमियों ने यहाँ के हिन्दी-भाषियों से ही अलग-अलग पैदा नहीं किया वरन् बंगला आदि भाषाएँ बोलनेवाले भुगलमानों से भी अलग-अलग पैदा कर लिया।

इसीलिए हिन्दी का आन्दोलन जोर पकड़ता गया, हिन्दू-मुस्लिम-एकता का सीमित आधार रहने पर भी उर्दू अपना स्थान सुरक्षित रखने में सफल न हुई और प्रेमचन्द, बालमुक्न्द गुप्त, प्रतापनारायण मिश्र, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, परसिंह शर्मा आदि अनेक लेखकों ने उर्दू से परिचय और प्रेम होते हुए भी हिन्दी की सेवा की। हिन्दी के प्रति गलत धारणाओं के कारण उर्दू प्रेमी सज्जन हिन्दी के सहयोग में कोई आन्दोलन नहीं चला सके। देश के विभाजन के बाद अब उनमें उर्दू को कौमी जवान बनाने का साहस नहीं रहा, उन्होंने पंथी के कारण उसे इलाकाई जवान बनाने का नारा दिया। उर्दू को पढ़ने-पढ़ाने और उसके व्यवहार के लिए सुविधाएँ होनी चाहिए, हम इस माँग का समर्थन करते हैं। किन्तु अपने बोलचाल के रूप में वह किसी विशेष इलाके की जवान नहीं है, इलाकाई जवान का नारा जातीय अलग-अलग और विघटन का नारा है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश और अन्य हिन्दी-भाषी राज्यों से अप्रैजी जाय, उसकी जगह हिन्दी को राज्यभाषा बनाया जाय, हिन्दी के साथ अल्पसंख्यकों—जिनमें मुसलमानों के साथ कुछ हिन्दू भी गिने आँगे—की भाषा के रूप में उर्दू का संरक्षण किया जाय, इस आधार पर हिन्दी-उर्दू-प्रेमी अब भी एक मंच पर संयुक्त आन्दोलन कर सकते हैं।

आगे चलकर क्या होगा ? उर्दू रहेगी या मिट जायगी ? उर्दू का बोलचाल वाला रूप मिट नहीं सकता, क्योंकि वह कुछ शिक्षित व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। यह रूप हिन्दी के बोलचाल वाले रूप जैसा है और हिन्दी-लेखक उसे अपनाकर हिन्दी को समर्थ बना सकते हैं। उर्दू का साहित्यिक रूप हिन्दी को काफी प्रभावित कर सकता है, अभी भी कर रहा है। अनेक हिन्दी-कवियों की छन्द-योजना और शैली पर उर्दू का प्रभाव देखा जा सकता है। यह प्रभाव कितना अधिक पड़ता है, यह उर्दू वालों पर भी निर्भर है। उर्दू-लेखक जितना हो अपना सीमित दायरा छोड़कर अपना साहित्य जनता के लिए लिखेंगे और देवनागरी के माध्यम से उस तक पहुँचायेंगे, उतना ही वे हिन्दी के विकास में प्रभावित कर सकेंगे।

हमारी ममक में उर्दू से प्रभावित होकर हिन्दी का बोलचाल वाला रूप पुष्ट होगा और हिन्दी में प्रभावित होकर उर्दू के 'सम्य' अरबी-फारसीवाले रूप में काफी परिवर्तन होगा। यह बहना आवश्यक है कि उर्दू में काफी देशभक्तिपूर्ण

और जनान्वित साहित्य है। शाश्वती के कारण साहित्य की विषयवस्तु नहीं बदल जाती। हिन्दी-प्रेमी काफी उर्दू-साहित्य पढ़ते हैं, उर्दू-प्रेमियों को इस विषय में उनमें होड़ करनी चाहिए।

उर्दू की रक्षा करना और उनकी स्वस्थ वियोज्यताओं से सीखना हिन्दी के हित में है। उसकी बोलचाल का रूप, कहावतें और मुहावरे हमारी भाषा की सम्पत्ति हैं। सैकड़ों शेर या उनमें टुकड़े कहावतों का रूप ले चुके हैं। वे हमारी सांस्कृतिक सम्पत्ति का अंग हैं। उर्दू में अरबी फारसी के शब्द होने से उनमें लिखने जोखने-वाले देशद्रोही नहीं हो जाते।

दरी दीवार पे हमरत से नजर बरते हैं।

खुश रहो अहनेवतन हम तो सफर बरते हैं ॥

इस तरह वे शेर उन लोग न गुनगुनाये थे जिन्होंने अपना रक्त देकर अपनी देशभक्ति प्रमाणित की थी। हमारा उद्देश्य हिन्दीभाषी प्रदेश की सांस्कृतिक एकरता को दृढ़ करना, उसके साहित्य को जनता के हित में विकसित करना है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हिन्दी-उर्दू प्रेमी एक दूसरे के निवृत्त आएँ, यहाँ अंग्रेजी की जगह अपनी भाषा प्रतिष्ठित करें और उसमें विकास में मिल-जुलकर योग दें।

स्वर्गीय पर्सीसह शर्मा ने अपने 'हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी' वाले प्रसिद्ध भाषण में हिन्दी उर्दू की एकरता के सम्बन्ध में कहा था, "कुटुम्ब के बँटवारे की तरह भाषा का यह बँटवारा भी कुटुम्ब-वत्सल और सम्पत्ति-विनाश का कारण है, बहुत-से सम्पन्न घराने बँटवारे की बदौलत टुकड़े-टुकड़े होकर बिगड़ गये, राज-परिवार भिखारी बन गये यदि हिन्दी-उर्दू दोनों समुक्त परिवार की दशा में आ जाएँ, तो फिर इसकी साहित्य सम्पत्ति का ससार की कोई भाषा मुकबला न कर सके।" इसमें सन्देह नहीं कि हमारे प्रदेश के हिन्दुओं, मुसलमानों तथा अन्य धर्मवालों में रचनात्मक प्रतिभा की कमी नहीं है। उर्दू किसकी सेवा करेगी? पाकिस्तान के पंजाबियों, बंगालियों, पठानों और सिंधियों की या अपने प्रदेश के लोगों की? यह युग जनतन्त्र का है। हिन्दी उर्दू एक ही जनता की सेवा करेंगी, इसलिए उनका समुक्त परिवार बनना अनिवार्य है। (१९५८)

जातीय प्रतिद्वन्द्विता और हिन्दी

देश के स्वाधीन होने के बाद जातीयता का भाव तेजी से बढ़ा है। हम गुजराती हैं, बंगाली हैं, मलयाली या आन्ध्र हैं—अपने प्रदेश, भाषा और सस्कृति से सम्बन्धित इस भाव को हम जातीयता का भाव कहते हैं। कुछ वर्ष पहले पढ़े-लिखे लोगों की बातचीत में एक शब्द अक्सर सुनाई देता था —‘प्रोविन्शियल’। जब हम किसी को अपनी भाषा और साहित्य की वेहद बड़ाई करते देखते थे तो कहते थे —‘ये लोग बड़े प्रोविन्शियल होते हैं’।

अपनी भाषा, जाति, प्रदेश, उसकी सस्कृति आदि पर गर्व करना बुरी बात नहीं है। इन अनेक जातियों से ही भारत राष्ट्र की रचना हुई है। इन प्रदेशों की विभिन्न सस्कृतियों से मिलकर ही भारतीय सस्कृति का निर्माण होता है। इसलिए अपने प्रदेश और उसकी सस्कृति को भुलाकर राष्ट्रीयता और भारतीय सस्कृति की बात करना सम्भव नहीं है।

इससे एक परिणाम यह भी निकलता है कि अपनी भाषा और उसके साहित्य को ही श्रेष्ठ समझने का फल देश की प्रगति के लिए हानिकार हो सकता है। हम एक दूसरे से सीखकर, मिल जुलकर आगे बढ़ने के बदले जातीय प्रतिद्वन्द्विता में फँस जाएँगे और अपनी शक्ति का काफी भाग अपनी जातीय श्रेष्ठता सिद्ध करने में व्यय करेंगे। अन्तर्जातीयता के इस खतरे को स्वीकार करते हुए यह मानना होगा कि उचित मात्रा में जातीयता की चेतना विकास के लिए आवश्यक है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि हिन्दी-भाषियों में—विशेषकर पढ़े-लिखे मध्यवर्ग के लोगों में—यह जातीयता का भाव उचित मात्रा में विद्यमान है या नहीं।

जातीयता की बात चलने पर कुछ भिन्न कहते हैं—हिन्दी राष्ट्रभाषा है, हम सारे राष्ट्र की बात सोचते हैं, किसी प्रदेश के बारे में सोचने की सकीर्णता क्यों दिखाएँ ?

देश की परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो हिन्दी-भाषियों में न चाहने पर भी जातीयता का भाव उभार रही हैं। इनमें एक उल्लेखनीय परिस्थिति अहिन्दी-भाषियों से हमारा सम्पर्क है। यातायात के साधनों के विकसित होने और आर्थिक कारणों

से हजारों आदिमियों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है या अपन प्रदेश में ही अन्य भाषाएँ बोलनेवालों से मिलना पड़ता है। इस जातीय प्रतिद्वन्द्विता का एक बहुत बड़ा केन्द्र बसकता है। इस नगर में हिन्दी का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। 'भारत मित्र' और 'मतवाला' जैसे पत्र यहीं से निकले हैं, निराला और उग्र जैसे लेखक यहीं अपनी साहित्य साधना कर चुके हैं। आज भी हिन्दी भाषा और साहित्य की प्रगति में बसकता की भूमिका नगण्य नहीं है। यहाँ आकर हिन्दी-भाषी व्यक्ति को यह बार-बार सुनने को मिलता है कि यह हिन्दुस्तानी है। हिन्दी-भाषी प्रदेश के लिए 'हिन्दुस्तान' शब्द का प्रयोग काफी पुराना है। हिन्दी-भाषियों की चेतना में यह शब्द हमारे देश का वाक्य ही रहा है। हिन्दी-भाषी प्रदेश का कोई विशेष नाम प्रचलित नहीं है। इन नाम के अभाव में हिन्दी-भाषी जाति का अस्तित्व मिट नहीं जाता। अन्य जातियों के सम्पर्क में आने से हिन्दी भाषी व्यक्ति को विषम होकर सोचना पड़ता है कि उनकी जाति क्या है। ऐसी परिस्थिति में अपनी जातीयता से सम्बन्धित कुछ बातें स्मरण रखना आवश्यक है।

सबसे पहले हिन्दी भाषी जनता में जातीय चेतना के अपेक्षाकृत अभाव पर ध्यान देना चाहिए। जिस समय हमारे देश में भाषा के आधार पर प्रान्त अथवा राज्य निर्माण की चर्चा चलती रही है, हमारे प्रदेश में अनेक राज्यों को मिलाकर विशाल हिन्द प्रदेश के गठन का आन्दोलन नहीं चला। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश को ही विभाजित करने का बात कुछ राजनीतिज्ञों में सुनाई दी। अल्प भाषाओं के आधार पर प्रान्त-निर्माण करने से—विशेषकर दक्षिण में—छोटे राज्यों का चित्र सामने आना था। किन्तु हिन्दी भाषियों को एक प्रदेश में संगठित करने से अनेक राज्यों में एक बड़ा राज्य बनता था। विभाजन के बदले स्पष्ट ही देश की एकता दृढ़ होती थी। किन्तु इस और किसी राजनीतिक दल ने ध्यान नहीं दिया। यह स्थिति हमारे प्रदेश में जातीय चेतना के अपेक्षाकृत अभाव का प्रमाण है।

इस स्थिति के अनेक कारण हैं। हिन्दी-भाषी प्रदेश असाधारण रूप में विशाल है। उसमें भारत के किसी भी भाषा-क्षेत्र की तुलना में बोलियों की सन्ख्या अधिक है। इस क्षेत्र में ब्रज, अवधी और मैथिली जैसी बोलियाँ हैं जिनका अपना विशाल साहित्य भण्डार है। अनेक लोगों के मन में अब भी यह दुविधा है कि ये बोलियाँ दरअसल बोलियाँ हैं या हिन्दी से स्वतन्त्र भाषाएँ हैं। यातायात के साधनों का समुचित विकास न होने और उद्योग धन्यो और व्यापार में हमारे प्रदेश के अनेक भागों के पिछड़े रहने से यह जातीय एकता का भाव विश्रुतल-सा रहा है। इन बोलियों की समस्या के अलावा हमारे यहाँ हिन्दी-उर्दू की विशेष समस्या रही है। बोलचाल की भाषा के दो शिष्ट या साहित्यिक रूप होने से जातीय गठन में बाधा पड़ती रही है। एक ही दिशा में बढ़ने के बदले सांस्कृतिक शक्तियाँ दो दिशाओं में बँट गई थी। ये परिस्थितियाँ अब धीरे धीरे बदल रही हैं।

इस प्रदेश के इतिहास के बारे में दो-चार बातें उल्लेखनीय हैं। मरकृत भाषा और साहित्य से हमारे प्रदेश का घनिष्ठ जातीय सम्बन्ध है। भाषाशास्त्र की दृष्टि

संस्कृत से जितना सम्बन्ध हिन्दी और उसकी बोलियों का है उतना अन्य भारतीय भाषाओं और उसकी बोलियों का नहीं। संस्कृत साहित्य के विशाल भण्डार में भारत के सभी प्रदेशों के विद्वानों ने अपनी ज्ञानराशि संचित की है। फिर भी इस साहित्य के अधिकांश भाग की रचना उन लोगों ने की है जो वर्तमान हिन्दी-प्रदेश के निवासी थे। पानी, प्राकृत और अपभ्रंस के साहित्य के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है।

आगे चलकर तुर्की बोलनेवाली अनेक जातियाँ यहाँ आईं। पश्तो, फारसी आदि अन्य विदेशी भाषाएँ बोलनेवाले जन भी यहाँ आये। एक-दो पीढ़ी के बाद वे अपनी पूर्व जातीयता खोकर यहाँ के लोगों में घुल मिल गए। इसका एक रोचक प्रमाण बाबर-वंश में तुर्की भाषा का गायब होना है। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी किन्तु उसके वंशज घर में तुर्की न बोलते थे। फारसी उनकी मातृभाषा नहीं, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में व्यवहार के लिए स्वीकार की हुई वह एक विदेशी भाषा थी—यद्यपि यह एशिया की ही भाषा थी और संस्कृत से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध था। सभी मुसलमानों की भाषा फारसी नहीं थी—यह तथ्य स्मरण रखना चाहिए। भारत के विभिन्न भाषा क्षेत्रों में मुसलमानों की वही भाषा थी जो वहाँ के हिन्दुओं या अन्य धर्मवालों की थी। इसलिए यह समझना कि हिन्द-प्रदेश के मुसलमान किसी फारसी बोलनेवाली जाति के थे अथवा उनकी मूलज जातीयता आज तक सुरक्षित है, मही नहीं है।

तीसरा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य १८५७ के स्वाधीनता संग्राम से सम्बन्धित है। भारतीय जातियों का परस्पर सम्बन्ध सौ वर्ष पहले आज से भिन्न था। १८५७ में आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से हिन्द-प्रदेश भारतीय जीवन की घुरी था। सन सत्तावन का स्वाधीनता-संग्राम हिन्द-प्रदेश तक सीमित नहीं था। पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, हैदराबाद आदि प्रदेशों में भी संघर्ष हुए किन्तु मुख्य समरभूमि दिल्ली, झाँसी और शाहाबाद के विशाल त्रिकोण से सम्बद्ध थी, इसमें संदेह नहीं। सन् सत्तावन के संग्राम की मुख्य शक्ति हिन्द-प्रदेश की हिन्दू-मुसलमान जनता थी। अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने यहाँ के नगरों को उजाड़ डाला, यहाँ का व्यापार भष्ट कर दिया, भयकर मरसहारा द्वारा उन्होंने यहाँ की जनता को त्रस्त और आतंकित करने में कुछ उठा न रखा। तब से जातीय सतुलन बदल गया। संस्था में विशाल होने पर भी आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हमारी जाति बहुत-बहुत पिछड़ी रही। यह स्थिति धीरे-धीरे बदल रही है।

भारत की अनेक समृद्ध भाषाओं की तुलना में हिन्दी गद्य का विकास विलम्ब से हुआ। खड़ी बोली का शिष्ट और सुसंस्कृत रूप पहले उर्दू के माध्यम से सामने आया। यदि हिन्दी गद्य का स्वतन्त्र विकास न होता, यदि उर्दू वास्तव में हमारी जातीय भाषा की भूमिका पूरी कर पाती तो हमारा गद्य-साहित्य आज बहुत समृद्ध होता। किन्तु हिन्दी शब्दों के बहिष्कार और फारसी-अरबी से ज्यादा शब्द उधार लेने के कारण उर्दू का विकास भारत की अन्य भाषाओं से अलग एक

निराली दिशा में हुआ। उर्दू में केवल दरबारी साहित्य नहीं है, खड़ी बोली के इस साहित्यिक रूप में राष्ट्रीय भावना और नये युग की चेतना प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। फिर भी शब्द-भण्डार की विशिष्टता के कारण वह हमारे जनपदों की बोलियों से दूर होती गई और हिन्दी गद्य का विकास अनिवार्य हो गया। यह प्रसन्नता की बात है कि उर्दू की बहुत सी पुस्तकें देवनागरी अक्षरों में छप रही हैं और हिन्दी साहित्य से सम्बन्धित बहुत सी पुस्तकें उर्दू में निकली हैं। इससे हमारी भाषा के दोनों साहित्यिक रूप एक-दूसरे के निकट आते हैं और एक मिली-जुली साहित्यिक भाषा की ओर बढ़ने की सम्भावनाएँ उत्पन्न होती हैं।

जातीय प्रतिद्वन्द्विता का सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि हिन्दी के सरल और मुहावरेदार रूप को ज्यादा-से-ज्यादा काम में लाया जाय। विशेष रूप से कथा साहित्य में भाषा का साफ-सुथरा रूप आना जरूरी है। हिन्दी कथाकार जान बूझकर कठिन भाषा नहीं लिखते। लेकिन सरसता ही काफी नहीं है। बाल-मुकुन्द गुप्त और प्रेमचन्द की शैली ही की तरह भाषा इतनी आकर्षक होनी चाहिए कि पाठक स्वयं उताही और लिखें। समृद्ध शब्दावली का प्रयोग करने से सारे भारत में हिन्दी लोकप्रिय हो जाएगी—यह धारणा कथा साहित्य पर निगाह डालने से मिथ्या साबित होती है। हिन्दी और अहिन्दी-प्रदेशों में उन्हीं कथाकारों की रचनाएँ अधिक पढ़ी जाती हैं जो सरल और मुहावरेदार भाषा लिखन में सबसे आगे हैं।

आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास विलम्ब से हुआ, फिर भी यह विकास असाधारण वेग से हुआ है। पिछले साठ-सत्तर वर्षों में हिन्दी ने प्रेमचन्द जैसे उपन्यासकार, निराला जैसे कवि, प्रसाद जैसे विचारक, कवि और नाटककार, बालमुकुन्द गुप्त जैसे व्यंग्य-लेखक, हरिविन्द और बालकृष्ण भट्ट जैसे पत्रकार, महावीरप्रसाद द्विवेदी जैसे आलोचक और सम्पादक, बृन्दावनलाल वर्मा जैसे ऐतिहासिक उपन्यासकार उत्पन्न किए हैं। इन सबकी रचनाएँ न केवल हिन्दी साहित्य घरेलू भारतीय साहित्य के इतिहास में उल्लेखनीय रहेगी। साठ-सत्तर वर्ष की छोटी अवधि में हिन्दी साहित्य की कुछ जातीय विशेषताएँ उभरकर सामने आती हैं। इनमें प्रमुख विशेषता है जिन्दादिली। भारतेन्दु युग के साहित्यकारों की जिन्दादिली का कहना ही क्या? भयानक कठिनाइयों का सामना करने पर भी वे अपनी विनोदप्रियता और उत्साह की रक्षा कर सके। कुछ लोग कहते हैं कि हिन्दी में हास्यरस का अभाव है लेकिन हिन्दी का शायद ही कोई लेखक हो जो व्यंग्य विनोद से पूरी तरह बचकर सदा गम्भीर बना रहा हो। गम्भीर आलोचक रामचन्द्र शुक्ल तक 'रीतिवादी कवियों की चर्चा होने पर अपनी विनोद-प्रियता का दमन न कर पाते थे। छायावादी लेखक निरालाजी के रेखाचित्रों—'देवी', 'चतुरी चमार' आदि—और अनेक आलोचनात्मक निबन्धों—'बला के विरह में जोशीवन्धु' आदि—में उनका व्यंग्य-विनोद देखते ही बनता है। प्रेमचन्द ने कथा साहित्य में—विशेषकर उनकी कहानियों में—उनका व्यंग्य अन्तर्धारा

रे समान प्रवाहित है। हम कह सकते हैं कि जिन्दादिली हिन्दी-साहित्य की एक जातीय विशेषता है।

दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता हिन्दी लेखकों का राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन से सम्बन्ध, विशेषकर ग्रामीण जीवन से उनका गहरा सम्बन्ध है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और उनके युग के अधिकांश लेखक देश में स्वाधीनता-प्रेम और नई राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करनेवाले थे। किसान-जीवन से प्रेमचन्द का कितना गहरा सम्बन्ध था, इसे सभी लोग जानते हैं। इसी कारण वे भारतीय साहित्य में एक नये यथार्थवाद की प्रतिष्ठा कर सके। प्रसाद जैसे साहित्यकार ने भी 'तितली' में प्रेमचन्द के समान किसानों का चित्रण किया। ऐतिहासिक उपन्यासकार वृन्दावनलाल वर्मा की रचनाओं में कुन्देलखण्ड की लोक-संस्कृति का वैभव देखने को मिलता है। नागार्जुन जैसे लेखकों ने इस परम्परा को सुरक्षित रखा है। अमृतलाल नागर ने निम्न मध्यवर्ग और घबस्त होती हुई सामन्ती संस्कृति के अनुपम चित्र देकर इस यथार्थवाद को व्यापक और प्रशस्त बनाया है। हिन्दी साहित्य की मुख्य धारा समाज निरपेक्ष न होकर समाज से पूर्णतः सम्बद्ध है। हिन्दी साहित्य का यह यथार्थवादी पक्ष उसका सबसे पक्ष है और हम उस पर उचित अभिमान कर सकते हैं।

हिन्दी साहित्य की इस प्रगति और जातीय प्रतिद्वन्द्विता में हिन्दी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नई कविता से सन्तोष नहीं किया जा सकता। यह धारा अन्तर्मुखी, सामाजिक जीवन की उपेक्षा करनेवाली और बसारमक सो-दय्य ॥ हीन है। हिन्दी को हास्यास्पद बनाने के लिए पाश्चात्यिक शब्दावली के कुछ नमूने और नई कविता की कुछ खडित पंक्तियाँ उद्धृत करना काफी होता है। नई कविता के समर्थक वर्तमान काल में हिन्दी के जातीय और राष्ट्रीय दायित्व को पहचानते हैं, यह नहीं कहा जा सकता। आधुनिक हिन्दी कविता को समृद्ध करने-वाले ऐसे बहुत-से कवि हैं जो नई कविता के रंग-रस से दूर हैं। फिर भी यह मानना होगा कि दिनकर, सुमन, नरेन्द्र के बाद के कवियों की पीढ़ी उसी समर्थ नहीं है। आधुनिक हिन्दी कविता की तुलना में हिन्दी कथा-साहित्य आगे बढ़ा आ है।

हिन्दी पढ़ने-लिखनेवाले अहिन्दी-भाषियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वे जब हिन्दी पढ़ते हैं तब अपनी भाषा के साहित्य से हठात् उसकी तुलना भी करते हैं। उनका दृष्टिकोण हमसे अधिक आलोचनात्मक होता है। ऐसे लोगों की संख्या निकट भविष्य में और भी बढ़ेगी। इसीलिए जातीय प्रतिद्वन्द्विता के इस युग में हिन्दी लेखकों का दायित्व बहुत बढ़ गया है। साहित्य के हर क्षेत्र में उनसे अपेक्षा-धारण परियम की अपेक्षा है। आधुनिक साहित्य के विकास में हम कुछ देर से शामिल हुए हैं। विलम्ब से होनेवाली क्षति पूरी करनी है। हमारी जाति संख्या में मारन की सभी जातियों से बड़ी है और विश्व की तीन-चार भाषाओं में—जिनके बोलनेवालों की संख्या सबसे अधिक है—हिन्दी भी है। परिमाण से

सन्तोष न करके उसे गुणात्मक रूप से समृद्ध करना हमारा कर्तव्य है। व्यापार के प्रसार से हिन्दी में पुस्तक प्रकाशन गूब बढ़ा है। शोध प्रवन्धों से लेकर उपन्यासों तक सैकड़ों पुस्तकें हर साल प्रकाशित होती हैं। जल्दी लिखने और पुस्तकें छापने का मोह अनेक लेखकों को मीबता है। साधना के बिना साहित्य का स्तर ऊँचा नहीं हो सकता। पुस्तकों की भारी सरया साहित्य की गरिमा का प्रमाण नहीं है। यदि सम्भव हो तो प्रत्येक हिन्दी लेखक को कुछ दिन के लिए अपना प्रदेश छोड़कर किसी अन्य भाषा क्षेत्र में जाना चाहिए। वहाँ की साहित्यिक गतिविधियों से परिचित होना चाहिए, छिटान्वेषण के बदले वहाँ की अच्छी बातें सीखने का प्रयत्न करना चाहिए और धैर्य से हिन्दी के सम्बन्ध में अहिन्दी भाषियों की राय सुननी चाहिए। इससे आत्मगन्तोष की शलत भावना कम होगी और नई लगन से साहित्य साधना करने की प्रेरणा मिलेगी। देश की वर्तमान परिस्थितियों में केवल हिन्दी भाषी प्रदेशों तक—उत्तर भी केवल बिहार या उत्तर प्रदेश तक और इनमें भी अक्सर इलाहाबाद, बनारस या पटना तक—अपना दृष्टिकोण सीमित करके साहित्यकार बिगेष प्रगति नहीं कर सकते। अपनी जातीय सत्कृति पर उचित गर्व करते हुए उस गर्व की अहंकार और दम्भ में परिवर्तित होने से बचाते हुए, भारत की सभी जातियों में सद्भावना और मैत्री को बढ़ाते हुए एक उदार दृष्टिकोण के आधार पर हम अपने प्रदेश के साथ समस्त देश की प्रगति में सहायक हो सकते हैं।

(१९५६)

राष्ट्रभाषा अंग्रेजी

सर्व-प्रभुत्व-सम्पन्न भारतीय गणराज्य की लोकसभा में पिछले महीने इस प्रश्न पर विलम्ब यहस हुई कि अंग्रेजी को भारत की एक राष्ट्रभाषा माना जाय या नहीं। हिन्दी में जब हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तब उसका अर्थ यह होता है कि सारे राष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों में परस्पर व्यवहार की भाषा। पहले अंग्रेजी भाषा के माध्यम में भारतीय समस्याओं पर विचार करनेवाले विद्वान् इसी अर्थ में (अथवा प्रायः इस अर्थ में) 'ए नैशनल लैंग्वेज' की चर्चा करते थे। लेकिन अब वही या उनमें से अनेक विद्वान् 'ए नैशनल लैंग्वेज' की बात करने लगे हैं अर्थात् भारत राष्ट्र में जितनी भाषाएँ बोली जाती हैं, वे सभी राष्ट्र के अन्दर ही बोली जाने से राष्ट्रभाषाएँ हैं।

एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकें मँगाने का काम अर्थशास्त्र के एक आचार्य को सौंपा गया। वह अंग्रेजी के लिए निर्धारित रकम भी अर्थशास्त्र की पुस्तकों के लिए खर्च कर देते थे। आपत्ति करने पर उन्होंने उत्तर दिया—आप देखते नहीं, ये अर्थशास्त्र की पुस्तकें भी तो अंग्रेजी में लिखी हुई हैं।

उसी तरह राष्ट्र में जो भाषा भी कही बोली जाय, वह राष्ट्रभाषा है।

वस्तुतः राष्ट्र के लिए अंग्रेजी में कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेशन और नैशनल के लिए राष्ट्र और राष्ट्रीय शब्दों का प्रयोग होता है किन्तु इस प्रयोग को उचित मानें तो 'मल्टीनैशनल कंट्री का अनुवाद बहुराष्ट्रीय राष्ट्र होगा (अर्थात् एक देश में अनेक राष्ट्र हैं)। हिन्दी में राष्ट्र शब्द देश के समवक्ष है, उससे घटकर नहीं है। वह भी हिन्दी का दोष है कि अंग्रेजी जैसी समृद्ध भाषा में हिन्दी जैसी दरिद्र भाषा के राष्ट्र शब्द का कोई नपा-तुला पर्याय नहीं है। और हो भी क्यों? राष्ट्र कहते ही कुछ दक्षिणानुसीपन की गन्ध नहीं आती क्या जैसे हिन्दी कहते ही देहातीपन की बू आने लगती है?

अंग्रेजी। इंग्लिश। नेशन। कितने साफ-सुधरे शब्द हैं। मुँह से निकलते ही चेहरा खिल उठता है। इसलिए अंग्रेजी 'ए नैशनल लैंग्वेज' भी है, 'द नैशनल लैंग्वेज' भी है। वह भारत राष्ट्र में बोली जानेवाली अनेक भाषाओं में एक है और

इन अनेक में एकमात्र नेव भाषा है।

ऐंग्लो इंडियन-कुल-कमल दिवाकर श्री फ्रैंक ऐन्टनी एम० पी० ने लोकसभा में कहा कि कुछ लोग अंग्रेजी का नाश करने पर तुले हुए हैं। इनमें अप्रगण्य वे हैं जिनकी मातृभाषा हिन्दी है। ये हिन्दी प्रेमी समझते हैं कि हिन्दी तब तक राज-राज की भाषा न बनेगी, जब तक अंग्रेजी का नाश न किया जाएगा।

श्री ऐन्टनी ने यह नहीं कहा कि अंग्रेजी को राजभाषा बनाये रखने के लिए हिन्दी का नाश करना जरूरी है। किन्तु इससे पहले अनेक अवसरों पर वह हिन्दी के लिए लोकसभा में जिन विशेषणा का प्रयोग कर चुके हैं, उनसे यही ध्वनि निवसती है।

श्री ऐन्टनी इतिहास में भी दखल रखते हैं। उन्होंने राष्ट्रभाषा-समस्या के दायरे से बाहर निरन्तर भारतीय इतिहास या विहंगावलोकन करते हुए घोषित किया, “द हिस्ट्री ऑफ इंडिया विफोर द ऐडवेंचर्ड ऑफ इम्पिरियल वाज द हिस्ट्री ऑफ ट्राइबलिज्म।” (६ अगस्त, १९५६ के टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित विवरण)। अर्थात् अंग्रेजों के आने से पहले भारत का इतिहास बर्लीन का इतिहास था।

कड़ीला को शिक्षित करने, उन्हें राष्ट्रीय एकरता का पाठ पढ़ाने, उनकी आदिम बर्बरता को दूर करने का काम अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजी शासकों को राष्ट्रीयता से डरना प्रेम था कि यहाँ से विदा होने समय वे एक के बदले दो राष्ट्र बना गए।

श्री फ्रैंक ऐन्टनी ने अपनी सहज बिनम्रता से यह नहीं कहा कि सम्प्रदाय के बाहन अंग्रेज शासकों के नामलवा और पानीदेवा ऐंग्लो-इंडियन सम्प्रदाय के ऐन्टनी जैम नेता अभी बचे रह गए हैं।

लेकिन ऐन्टनी महोदय देशभक्ति में किसी में पीछे नहीं। आज जब देश के अनेक वर्णधार जनता को यह समझाते नहीं बल्कि अंग्रेजों की पुरानी अत्याचार-गाथा भूल जाओ, नये सिरे से गत्य और अहिंसा के आधार पर उनमें मैत्री-सम्बन्ध कायम करो, तब भारतीय गणतन्त्र की लोकसभा में श्री फ्रैंक ऐन्टनी ने माननीय सदस्यों को सूचित किया कि वह ऐंग्लो इंडियन सम्प्रदाय का इतिहास लिख रहे हैं और वे ही जानते हैं (उनका दिल जानता है) कि अंग्रेजी राज ने जितना नुकसान ‘ऐंग्लो-इंडियन कम्युनिटी’ का किया है, उतना और किसी का नहीं। उन्होंने सख्त निवेदन किया कि १९०६ से पहले ऐंग्लो-इंडियन कम्युनिटी के सदस्य मैनिंग और थ्रॉप्टी (मर्चेंट प्रिसेज) होत थे (और इस रूप में भारत राष्ट्र की सेवा करते थे)। किन्तु १९०६ के बाद वे उस गोरबशाली स्थान पर हटा दिये गए। श्री ऐन्टनी के अनुसार अंग्रेज शासकों को सन्देह था कि वे हिन्दुस्तानियों में मिलकर किसी दिन विद्रोह कर देंगे।

उदारमना, मुमस्वृत अंग्रेज शासकों की राज्यसत्ता का आधार शायद इतना व्यापक था कि उन्हें भारतीय जनता से ही भय नहीं था, बल्कि उनमें भी सकट की

भाषका थीं जो अपने को अंग्रेजों का वशज मानने में गर्व और गौरव का अनुभव करते थे, भले ही अंग्रेज स्वतन्त्रता-सम्मिश्रण का सन्देह करके घृणा से मुँह फेर लेते हों। ऐंग्लो-इंडियनों से विद्रोह की शका निर्मूल थी। १८०६ के पचास साल बाद, सन् अठारह सौ सत्तावन के साल अनेक ऐंग्लो इंडियन देशभक्तों ने, हैदराबाद के निजाम और नेपाल के राना जगबहादुर जैसे दूरदर्शी राजनीतिज्ञों के समान ही, प्रगतिशील अंग्रेजों की राज्यसत्ता फिर से स्थापित कराने में एड़ी-चोटी का पसीना एक कर दिया। १९३२ में हर्बर्ट ऐस्किव स्टार्क नाम के एक ऐंग्लो-इंडियन सज्जन ने 'द काल ऑफ द ब्लड' (खून की पुकार) नाम की पुस्तक लिखी थी। उसमें उन्होंने १८५७ में ऐंग्लो-इंडियनों की राष्ट्र-सेवा का चित्रण किया था। इसकी भूमिका में उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया था कि १७८६ के बाद (श्री ऐन्टनी के दिए हुए सन् से कुछ वर्ष पहले) ऐंग्लो-इंडियनों को इस बात की मनाही कर दी गई थी कि वे जमीन सरीसैं या फौज और सिविल सर्विस में ऊँची जगह पाएँ। फिर भी खून की पुकार तो खून की ही है, विशुद्ध अंग्रेज उसे कँसा भी खून समझें। स्टार्क ने गर्व से लिखा है कि लामार्टीनियर बॉलिव, लखनऊ के (ऐंग्लो-इंडियन) छात्रों ने रेजीडेंसी के घरे के समय अंग्रेज सैनिकों के साथ रहकर उनकी अनुपम सेवा की, उनकी जूठी रवाबियाँ और गन्दे कपड़े धोय, चक्की पीसी, खाना पकाया और पला लीचा। इस सेवा का पुरस्कार छात्रों को क्या मिला, मालूम नहीं, लामार्टीनियर के प्रिंसिपल महोदय को ताल्लुकदार अवश्य बना दिया गया। १८५७ में भारतीय सेना के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़नेवाले कुछ गोरे अपसर भी थे। उनका उल्लेख करते हुए स्टार्क ने सगर्व लिखा है—अंग्रेजों से अंग्रेज तक लड़े, नहीं लड़े तो बेवस-ऐंग्लो इंडियन।

श्री फ्रैंक ऐन्टनी भी कह सकते हैं—अंग्रेजों ने भी चाहे हिन्दी को राजभाषा स्वीकार कर लिया हो, नहीं स्वीकार किया तो उन-जैसे ऐंग्लो-इंडियनों ने।

श्री ऐन्टनी के भाषण के समय चारों ओर से सदस्यों ने उस पर आपत्ति की और अपना तीव्र विरोध प्रकट किया। किन्तु प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों के भविष्य के सम्बन्ध में श्री ऐन्टनी को यथेष्ट आश्वासन दिया। कहना चाहिए, आश्वासन यथेष्ट से भी अधिक था क्योंकि प्रधानमन्त्री के भाषण के बाद श्री ऐन्टनी ने सन्तोष प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने जितने की आशा की थी, उससे भी अधिक प्रधान मन्त्री से उन्होंने पाया।

प्रधान मन्त्री अत्यन्त उदारचेता व्यक्ति हैं। सकीर्णता उनके स्वभाव के प्रतिफल है। उनका अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण जितना व्यापक है, उतना ही और उससे कुछ अधिक ही व्यापक उनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। विशेष रूप से उनका हिन्दी-सम्बन्धी दृष्टिकोण इतना व्यापक हो गया है कि अब वह कोण न रहकर रेखा बन गया है जिसमें चौड़ाई क्षीण होकर लम्बाई में परिवर्तित हो गई है।

भारत में कुछ लोग हिन्दी के हिमायती हैं, कुछ लोग अंग्रेजी के। पचशील का तकाजा है कि दोनों का शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व कायम रहे। जैसे भारत की

स्वाधीनता-रक्षा के साथ राष्ट्रीय सरकार ने देश में ब्रिटिश पूंजी के मुनाफे की रग्गा का भार भी लिया है, उसी तरह क्या अंग्रेजी का राजभाषा बना रहना हिन्दी के राष्ट्रभाषा बनने में सहायक नहीं हो सकता ? अगली चीज है दोनों के अलग-अलग क्षेत्रों को पहचानना। यह पहचान हासिल हो तो सघर्ष की नींव ही न आए। भाषाएँ 'ओवरलैप' करती हैं, ओवरलैप करने से प्रधान मन्त्री का आशय क्या है, यह जितना हम समझते हैं, उतना अखबार पढ़कर आप भी समझ सकते हैं। 'लैंग्वेजेंज डू ओवरलैप'—प्रधान मन्त्री के इस भाषाविज्ञानी मूख की व्याख्या करना हमारा काम नहीं।

प्रधान मन्त्री ने बताया कि पहले अंग्रेजी एक लाठी हुई भाषा थी। फिर भी उराने आधुनिक ज्ञान के द्वार खोल दिये। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्तमान समय में जो लोग उस लाठी हुई भाषा का लदाव अस्वीकार करके स्वेच्छा से उसे छोड़ते हैं, वे और भी जल्दी आधुनिक ज्ञान भण्डार तक पहुँच जाएंगे। उनके लिए द्वार खोलने का सवाल भी न उठेगा, वे लिटवी या रोजनदान से ज्ञान मन्दिर के आँगन में बृद्ध पड़ेंगे।

प्रधानमन्त्री न बता कि ऐंग्लो-इंडियन सम्प्रदाय को पूर्ण अधिकार है कि वह अंग्रेजी के माध्यम से ज्ञान पाये। इसके सिवा उन्होंने एक बात मार्क्स की और नहीं—“ऐंग्लो-इंडियन गूढ़ की गिविन एबी पॅसिबिलिटी टु डिलेप इग्लिश लैंग्वेज।” ऐंग्लो इंडियनों को वह पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए कि वे अंग्रेजी भाषा को विकसित कर सकें। अभी तक हम सुनते थे कि हिन्दी को ही भाषा-रूप में विकसित करना आवश्यक है, वह पिछड़ी हुई भाषा है, उसका भाषागत अथवा साहित्यिक महत्त्व नहीं है, महज सुविधा के लिए, बोलनेवालों की विद्याल सख्या के ही कारण उस राष्ट्रभाषा या राजभाषा बनाना है, इसलिए उस विकसित करना होगा। किन्तु सर्वज्ञान समृद्ध, आधुनिकता की खान, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महाभाषा अंग्रेजी को 'डिवेलप' कराना जरूरी है, और वह भी भारत के ऐंग्लो-इंडियन सम्प्रदाय द्वारा—इसमें बड़ी सूझ-बूझ की बात लोकसभा में स्वयं प्रधान मन्त्री भी आगे कहेंगे, इसमें सन्देह है।

प्रधान मन्त्री ने अपनी नीति के समर्थन में कहा कि पांडिचरी प्रदेश ('पांडि-चेरी-टेरीटरी') की भाषा फ्रांसीसी है। भले ही इस पांडिचेरी प्रदेश की भारतीय जनता की भाषा फ्रांसीसी न हो, लेकिन अगर एक यूरोपीय भाषा होने के नाते वहाँ उसे राजभाषा का पद मिल सकता है, तो सारे भारत में अंग्रेजी को राजभाषा—अथवा हिन्दी के साथ अतिरिक्त राजभाषा (और व्यवहार में एकमात्र राजभाषा)—का पद क्यों नहीं दिया जा सकता ?

प्रधानमन्त्री ने कहा कि जो प्रदेश पुर्तगालियों के अधिकार में है, एक दिन वह भी भारत राज्य में मिल जाएगा। तब पुर्तगाली भी 'ए लैंग्वेज ऑफ इंडिया' (भारत की एक भाषा) होगी।

इससे स्पष्ट परिणाम निबना कि संविधान में उल्लिखित भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी का नाम न होने पर भी वह है भारतीय भाषा ही ।

लोकसभा के एक दक्षिण भारतीय सदस्य ने श्री ऐन्टनी के समर्थन में कहा कि दो शताब्दियों में भारत का बुद्धिजीवी वर्ग अंग्रेजी को अपनी भाषा के रूप में अपनाये हुए है । देश की एकता के लिए यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम एक ही भाषा अर्थात् अंग्रेजी हो । प्रधान मंत्री ने माननीय सदस्य की बात की चर्चा करते हुए कहा कि वह स्वयं भी चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम एक ही भाषा अर्थात् अंग्रेजी रहे लेकिन उन्हें किसी तरह के दबाव से नफरत है; इन सब चीजों का सहज विकास हो वाछनीय है । उन्होंने कहा कि हिन्दी के हिमायती जब दूसरों पर हिन्दी लादना चाहते हैं, तो वह भी नापसन्द है ।

नतीजा यह कि इन दो नापसन्दगियों के बीच अंग्रेजी हमारी पसन्द से, बिना किसी पर लदे हुए, राजभाषा बनी रहती है ।

अंग्रेजी के राजभाषा न रहने में क्या होगा ? प्रधान मंत्री के अनुसार अंग्रेजी आधुनिक सत्तार की ओर खुलनेवासी बड़ी खिड़की है । 'थी डेयर नॉट क्लोज दैट विण्डो । इफ वी क्लोज इट, इट इज ऐट द पेरिल ऑफ अवर प्यूषर ।' (यह खिड़की हमें हर्गिज बन्द न करनी चाहिए । उसे बन्द किया तो हमारा भविष्य मकड़ में पड़ जाएगा ।)

भारत का भविष्य यहाँ की निग्यानवे फीसदी जनता पर निर्भर नहीं है । भविष्य निर्भर है डेढ़ फीसदी अंग्रेजी जाननेवालों पर, जो इस खिड़की से आधुनिक सत्तार की ओर झाँकते हैं । इन डेढ़ फीसदी में भी बहुतों को खिड़की तक पहुँचने और बाहर झाँकने का सौभाग्य नहीं मिलता । अंग्रेजी व्याकरण, उसके बाद उच्चारण और उससे भी बढ्तर शब्दों के लेखन की ऐसी बाधाएँ हैं जो उन्हें झाँकने से रोकती हैं । इसी कारण कुछ प्रदेशों के मन्त्री और उपमन्त्री तक बहुधा अपने अंग्रेजीवाँ सेक्रेटरियों की पीठ का सहारा लेकर ही खिड़की से झाँकते हैं । झाँककर वे क्या पाते हैं, यह कहना कठिन है क्योंकि जनता से अधिक भाषा-नक्षत्री पर भरोसा होने के कारण वे ज्योतिष-शास्त्र को आधुनिक विज्ञान की चरम उपलब्धि मानते हैं ।

प्रधानमन्त्री की युक्तिपूर्ण बातें कुछ समाचारपत्रों की सभ्य में नहीं आईं । इनमें ऐसे पक्ष भी हैं जो हिन्दी के समर्थकों की आलोचना करते हैं और जिनकी भाषा अंग्रेजी है । उदाहरण के लिए, 'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने १४ अगस्त की सम्पादकीय टिप्पणी में लिखा था, "राजभाषा के सम्बन्ध में लोकसभा की समिति ने अपने अत्यन्त तर्कसंगत विवरण में 'हिन्दी साम्राज्यवाद' के भय को निर्मूल कर दिया था । उसके बाद प्रधानमन्त्री द्वारा अधिक आश्वासन की अपेक्षा न थी । जो भय दूर हो चुके थे, उन्हें फिर से दूर करने के प्रयास में श्री नेहरू ने ऐसी बातें कही जो उन चरम-पणियों के हाथ मजबूत करती हैं जो इस स्थिति को अस्वीकार करते

हैं कि हिन्दी देश की राजभाषा हो।

यह अवधार मानता है कि आधुनिक समाज का देखने के लिए अंग्रेजी बिड़की आवश्यक है लेकिन उस सेद है कि श्री नहु आवश्यकता से अधिक आश्वामन दे गए। और हम नद है प्रमचद की बुद्ध पर जो अंग्रेजी का राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय महत्त्व न समझार उमे राष्ट्रभाषा माननेवाले देशभक्ता के लिए वह गए थे—' वे इतनी बुनदी पर पहुँच गए हैं कि नीचे का धून और गर्मी उन पर कोई असर नहीं कर सकती। वे मुअल्लक हवा में लटके रह सकते हैं। लेकिन हम सब तो हजार कोशिश करने पर भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। हम तो इसी धूल और गर्मी में जीना और मरना है। इटलीअँगिया में जो कुछ शक्ति और प्रभाव है वह जनता ही से आता है। उसमें अलग रहकर वे हाकिम की मूरत में ही रह सकते हैं। आदिम की मूरत में जनता के होकर नहीं रह सकते। उनके अरमान और मसूर उनके हैं जनता के नहीं। उनकी आवाज उनकी है उसमें जनममूह की आवाज की महुराई और गरिमा और गम्भीरता नहीं है। वह अपने प्रतिनिधि हैं जनता के प्रतिनिधि नहीं।

(१९५६)

सोवियत संघ में भाषा-समस्या-समाधान

तोल्स्तोय ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास 'युद्ध और शान्ति' में एक क्लब की चर्चा की है जिसकी स्थापना इस उद्देश्य में की गई थी कि उसके सदस्य रूसी बोलें, जो रूसी न बोलें वह जुर्माना दे। यह सस्था राष्ट्रीयता के आवेश में तब कायम की गई थी जब नैपोलियन मास्को के निकट पहुंच गया था। एक महिला सदस्य बीध में फ्रांसीसी बोलने लगती है और फिर भूल सुधारकर कहती है, आतुर इस बात को रूसी में कैसे व्यक्त करे। रूस के अभिजात वर्ग की यह फ्रांसीसी-भक्ति भारत के बहुत-से मौकरी-पेशा, नेता-पेशा भद्रजनों की अंग्रेजी-भक्ति से तुलनीय है। समाजवादी क्रान्ति ने यह विदेशी भाषा-भक्ति खत्म कर दी।

समाजवादी क्रान्ति के बाद साम्यवादी नेता इस बात का इन्तजार नहीं करते रहे कि रूसी भाषा विकसित होकर फ्रांसीसी या जर्मन के बराबर हो जाय तब उसे राजभाषा बनाएंगे। उन्होंने रूसी को ही राजभाषा नहीं बनाया, उक्रेनी, जार्जियाई, बेलोरूसी आदि भाषाओं को भी राजभाषा बनाया। सोवियत संघ गणराज्यों का संघ है और प्रत्येक गणराज्य की अपनी राजभाषा है। जो जातिमाँ पिछड़ी हुई थी, जिनकी भाषाओं की लिपि नहीं थी, उन्हें भी लिपि-व्याकरण आदि से दूरस्त करके स्वायत्त शासन के कार्यों के लिए चालू किया गया। जैसा कि गांधीजी ने कहा था, भारतीय भाषाओं के पिछड़ेपन की दुहाई देकर अंग्रेजी को बरकरार रखना आलस्य की निशानी है।

विभिन्न जातियों के बीच आपसी व्यवहार और केन्द्रीय राजकाज के लिए कोई भाषा हो या न हो? रूस में जातीय उत्पीड़न तीव्र था, इसलिए लेनिन ने यह नारा दिया कि कोई भी अनिवार्य केन्द्रीय राजभाषा न होनी चाहिए। साथ ही लेनिन ने अपने भाषा-सम्बन्धी लेखों में यह भी कहा कि सम्य देश में लोग उस जाति की भाषा को आपसी व्यवहार के लिए स्वीकार करेंगे जिसके बोलनेवालों की संख्या ज्यादा होगी। इस तरह केन्द्रीय पार्टियों और केन्द्रीय राजकाज के लिए रूसी भाषा का व्यवहार बराबर होता रहा।

पूँजीवादी बहुजातीय देशों और सोवियत संघ में केन्द्रीय भाषा की स्थिति में

अन्तर है। सोवियत सघ में कानून से रूसी को केन्द्रीय भाषा नहीं बनाया गया, वह स्वेच्छा से स्वीकृत हुई है। स्वेच्छा से स्वीकृत होने का सामाजिक आधार यह है कि किसी जाति के पूंजीपति दूसरी जाति के अधिकारों का दमन करने को नहीं वचे। इससे अलावा रूस में गैर-केन्द्रीय भाषाओं को जितने अधिकार प्राप्त हैं, उतने किसी भी बहुजातीय पूंजीवादी देश में गैर-केन्द्रीय भाषाओं को प्राप्त नहीं हैं। प्रत्येक गणराज्य (या रिपब्लिक) में उसकी अपनी राजभाषा है। स्वायत्त शासन क्षेत्रों में अन्य छोटी जातियों की भाषाओं में राजकाज होता है। मुद्रकाम में कालीनिन ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कहा था कि वे संनिकों से उन्हीं की भाषा में बातचीत करें, तभी उनका प्रचार-कार्य सफल होगा। यू० एन० ओ० तक में उर्ज़नी सदस्य अपनी भाषा का व्यवहार कर चुके हैं।

सोवियत सघ बहुजातीय देश है किन्तु वहाँ गणराज्यों की सरकारों के अलावा केन्द्रीय सरकार भी है। देश के राजकाज का संचालन करनेवाली पार्टी है जिसका सगठन-सिद्धान्त है जनवादी केन्द्रीयता। स्तालिन जाजिया के थे लेकिन केन्द्रीय शासन और पार्टी-कार्य के लिए रूसी बोलते और लिखते थे। ए० ए० उर्ज़नी हैं लेकिन पार्टी कांग्रेसों आदि में रूसी बोलते हैं। मिर्कोयान भार्मीनियन हैं। उनकी स्थिति भी वही है। रूसी जाने और उसका व्यवहार किये बिना वहाँ कोई राष्ट्रीय नेता नहीं बन सकता। इससे जो निष्कर्ष निकलते हैं, वे भारत के प्रगतिशील नेताओं के ध्यान देने योग्य हैं।

सोवियत सघ में सौ से ऊपर जातियाँ हैं लेकिन इनके सोलह प्रजातन्त्र या गणराज्य ही हैं। प्रत्येक भाषा को लेकर एक राज्य क्यों नहीं बना? इसका कारण यह है कि रूसी नेताओं ने भाषा समस्या को मूल सामाजिक समस्या के अधीन माना है, उससे स्वतन्त्र नहीं। मूल समस्या है, किसान-भूजदूरों की मुक्ति की, समाजवाद के विकास की। आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से यदि किसी जाति का गणराज्य निर्बल पड़ता है तो उसे दूसरे के साथ मिलकर रहना होगा, अतः उसका अपना स्वायत्त शासन-क्षेत्र होगा जिसमें उसकी अपनी भाषा का व्यवहार जायज होगा। भारत में प्रत्येक भाषा को लेकर एक राज्य बने या न बने—यह प्रश्न मूल सामाजिक समस्या से बलग रखकर हल नहीं किया जा सकता।

सोवियत सघ में प्रत्येक जाति की भाषा को विकास की सुविधाएँ प्राप्त हैं। फिर भी ये अधिकार और जातीय समानता हर जगह सौ फीसदी एक-से नहीं हैं। रूसी भाषा हर नागरिक को सीखनी होती है, रूसी-भाषियों को दूसरी भाषाएँ उसी तरह नहीं सीखनी पड़ती। गणराज्य की भाषा वहाँ के प्रत्येक नागरिक को सीखनी होती है। जिनकी वह मातृभाषा नहीं है, उन्हें भी वह सीखनी होती है। यथा उर्ज़नी गणराज्य में उर्ज़नी-भाषियों को मातृभाषा के अलावा रूसी सीखनी होगी; वहाँ उजबेक हो तो वे उजबेक के अलावा रूसी और उर्ज़नी सीखेंगे। इस तरह हर नागरिक को एक, किसी को दो, किसी को तीन या अधिक भाषाएँ परिस्थिति के अनुसार सीखनी होती हैं।

सोवियत संघ में हर भाषा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम नहीं है। निम्नस्तर के राजकाज और सांस्कृतिक कार्यवाही के लिए मातृभाषा का ही व्यवहार किया जाता है। उच्च शिक्षा का माध्यम बनानेवाली भाषाओं की समस्या सीमित है और इनमें भी जितना उच्च अनुसन्धान और शिक्षा-कार्य रुसी में होता है, उतना अन्य भाषाओं में नहीं। इस बात को ध्यान में रखने से राजस्थानी, पंजाबी आदि भाषाओं के प्रति न्याय करने की समस्या हल की जा सकती है। साथ ही इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि सभी सोवियत विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम रुसी नहीं है। उर्दू की विज्ञान अकादमी अपना विवरण आदि उर्दू में ही प्रकाशित करती है।

मुख्य बात यह है कि सोवियत-विज्ञान जनता की सेवा के लिए है, सोवियत शिक्षा जनता को सुसंस्कृत करके उसे साम्यवाद की ओर लाने के लिए है। पूँजीवादी शोषण को समाप्त कर देने से सोवियत संघ में भाषा और धर्म को लेकर दंगे नहीं होते, सभी जातियाँ परस्पर सहायता और सहयोग का जीवन बिताती हैं। इसलिए बड़ी भाँति संख्या भी संतोषजनक दंग से हल कर ली गई है।

(१६६१)

हिन्दी-उर्दू की बुनियादी एकता

किसी जाति की भाषा-समस्या पर विचार करते हुए हमें सबसे पहले उसके बोलचाल के रूप पर ध्यान देना चाहिए। क्या बोलचाल के रूप में भी हिन्दी-उर्दू दो भाषाएँ हैं? इसमें सन्देह नहीं कि बहुत बठिन हिन्दी और बहुत कठिन उर्दू बोली जा सकती है, लेकिन आम लोग उन्हें बोलते नहीं। इसलिए प्रेमचन्द का यह कहना ठीक था कि "बोलचाल की हिन्दी और उर्दू प्रायः एक ही है।" उर्दू हिन्दी के सर्वनाम एक है—वह, मैं, तू, हम इत्यादि। हिन्दी-उर्दू की क्रियाएँ एक ही हैं—जाना, सोना, खाना, पीना, करना, मरना, जीना, लिखना, पढ़ना इत्यादि। आजमाना, गुजरना, सरजना जैसी क्रियाएँ बहुत थोड़ी हैं, तुल्य मिलाकर एक वर्जन से बपादा नहीं, जो फारसी अरबी शब्दों के आधार पर बनी हैं। वे हिन्दी में मतरुक (उपेक्षित) नहीं हैं। बोलचाल में उनका प्रयोग बराबर होता है। हिन्दी-उर्दू के सम्बन्धवाचक शब्द—मे, पर, से, का आदि—वही हैं जो हिन्दी के। दोनों का मूल शब्द भण्डार भी एक है, लेकिन यही बहुत दिनों तक फारसी के राजभाषा रहने से हिन्दी शब्दों के फारसी या अरबी पर्यायवाची शब्द प्रचलित हो गए हैं—जैसे देश मुल्क, आकाश-आसमान, धरती जमीन, भाप जवान, किसान-कारतकार, नदी दरिया, रोगी बीमार इत्यादि।

इन शब्दों का व्यवहार बोलचाल की हिन्दी उर्दू में बिना किसी भेदभाव के होता है। देश, आकाश, धरती जैसे शब्द उर्दू-साहित्यकारों की रचनाओं में मिलेंगे और मुल्क, आसमान, जमीन जैसे शब्द हिन्दी साहित्यकारों की रचना में। इसके सिवा हस्त, बंस, खेत, खलिहान, बीज, जुताई, बुवाई, बारखाना, मजदूर, काम, छूटी आदि हजारों ऐसे शब्द हैं जिनके पर्यायवाची शब्द बोलचाल की भाषा में व्यवहृत नहीं होते, साहित्यिक भाषा में भले होते हों। लखनऊ और हैदराबाद के हिन्दू-मुसलमान बोलचाल की भाषा में फारसी शब्दों का व्यवहार ज्यादा करेंगे, उन्हीं फारसी शब्दों की जगह बिहार और मध्य प्रदेश के मुसलमान हिन्दी या संस्कृत शब्दों का प्रयोग करेंगे। यह स्थानीय भेद हुआ, इससे दो भाषाओं का निर्माण नहीं होता। हिन्दी उर्दू का व्याकरण

एक, वाक्यरचना एक-सी, शब्द-भण्डार और क्रियाएँ एक सी—इसीलिए हिन्दी-उर्दू-भाषियों की दो कौमे नहीं है। उनकी जाति एक है और बोलचाल की भाषा एक है।

हिन्दी-उर्दू में सबसे पहला भेद लिपि का है। लिपि लिखने के काम आती है न कि बोलने के। इसलिए लिपि-भेद को हम बुनियादी भेद नहीं मानते। हिन्दी-उर्दू में दूसरा भेद है शब्द भण्डार का। यह भेद साधारण लोगों की बोलचाल में बिल्कुल नहीं है, पढ़े-लिखे लोगों में बहुत थोड़ा है और भाषा के लिखित रूपों में बहुत ज्यादा है। बोलचाल में जो शब्द सामान्य सम्पत्ति हैं, लिखते समय उनमें भी अलग-अलग करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। परती, भाषा, किसान, नदी, भाषा, रोगी, देश जैसे शब्द उर्दू में कम मिलेंगे, काश्तदार, दरिया, आसमान, जवान जैसे शब्द साहित्यिक हिन्दी में कम मिलेंगे।

लेकिन मूल भेद दूसरा है। दर्शन, राजनीति, साहित्य आदि में जब हमें ऐसे शब्दों की जरूरत होती है, जो किसानों-मजदूरों की बोलचाल में नहीं हैं, तब उर्दू लेखक अरबी-फारसी से उधार लेते हैं, हिन्दी लेखक संस्कृत से। राजनीति-सिंघासत, साहित्य भद्र, लिपि-रसमुखत, भाषाविज्ञान-लसानीयात, आलोचना तनकीह, अन्तर्राष्ट्रीय वैयुक्तमन्त्रागामी, इतिहास-तारीख, जनतन्त्र-जम्हूरियत, कोश-लुगत—मुरयत इस तरह की शब्दावली हिन्दी-उर्दू में अलग-अलग उत्पन्न करती है।

पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि हिन्दी-उर्दू का यह अलग-अलग हमारे जातीय विपास के लिए घातक है। पढ़े-लिखे लोगों की शक्ति एक जगह सिमटकर पूरी जाति को आगे बढ़ाने के बदले बिखर जाती है और लिपि के आधार पर पाठक-वर्ग दो हिस्सों में बँट जाता है। यदि भाषा और साहित्य उच्च वर्गों के थोड़े-से पढ़े लिखे आदमियों के लिए ही हो, तो वे चाहे उर्दू में मनोरंजन करें, चाहे हिन्दी में, बाकी जनता इस मनोरंजन से दूर रहेगी। लेकिन सवाल है देश के साधारण लोगों का मेहनत से अन्न पैदा करनेवालों और पंचवर्षीय योजनाएँ पूरी करनेवालों का। भाषा और साहित्य इनके लिए हैं। समाजवादी व्यवस्था में सबसे पहले इन्हीं के लिए परिवर्तन होगा। तब यह भाषा और लिपि का बँटवारा बब तक चलेगा ?

समाजवादी व्यवस्था के निर्माण के लिए जनता का संगठन, उसकी शिक्षा और आन्दोलन जरूरी हैं। यदि एक ही कारखाने के मजदूर दो लिपियों से काम लेते हैं तो इससे उनकी शक्ति कम होगी, उनकी संस्कृति में दरारें पड़ेंगी। इसके सिवा हिन्दुस्तानी जाति दुनिया की सबसे बड़ी जातियों में है। अंग्रेजी बोलनेवाले बहुत हैं, लेकिन वे अनेक जातियों के हैं। एक ही भाषा बोलनेवालों की जाति हमसे संख्या में बड़ी हो सकती है, तो चीनी है। भारत की सभी जातियों में हमारी जाति सबसे बड़ी है, यह निर्विवाद है। ऐसी स्थिति में हमारी भाषा का राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है। स्पष्ट है कि हमारी भाषा अपनी

पूरी ताकत से तभी प्रगति कर सकती है, जब उसमें जाति के सभी तत्वों का सहयोग हो ।

हिन्दी उर्दू को एक होना चाहिए—यह हमारे ऐतिहासिक विकास की भाँति है । इसके लिए आवश्यक सांस्कृतिक आधार यह है कि साधारण जनता की बोलचाल की भाषा एक है । हमें इस एकता की ओर बढ़ने के लिए मजबूर करनेवाला सामाजिक कारण देश का पिछड़ापन, जनता की गरीबी, समाजवादी निर्माण की आवश्यकता है । इसके सिवा यह भी याद रखना चाहिए कि भारत के हर प्रदेश का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन अलग अलग रहकर विकसित नहीं होता, वह अखिल भारतीय जीवन प्रवाह की एक धारा है । और उस प्रवाह के साथ ही भाषे बढ़ता है । यंत्रों की भाषाएँ भी एक-दूसरे को प्रभावित करती रही हैं और करेंगी । भारत के हर जातीय प्रदेश की भाषा और लिपि एक हो, लेकिन हिन्द प्रदेश की दो लिपियाँ और दो भाषाएँ हो, यह सम्भव नहीं है ।

उर्दू अलग किसी कोम की भाषा नहीं है, इसलिए उसे इलाकाई ज़बान मनवाने के आन्दोलन का विरोध करना उचित है । किन्तु वह सांस्कृतिक अल्पसङ्ख्यकों की साहित्यिक भाषा है, इसलिए उसे पढ़ने-पढ़ाने और उसका व्यवहार करने की सुविधा मिलनी चाहिए । राजभाषा के रूप में हिन्दी होनी चाहिए, राजकाज के लिए दो लिपियाँ और उनमें लिखी हुई दो भाषाएँ नहीं हो सकती । हिन्दी-उर्दू के शब्द-भण्डार में काफी आदान प्रदान की गुंजाइश है । हिन्दी में बोलचाल के बहुत से शब्द साहित्यिक कृतियों में छोड़ दिये जाते हैं । बहुत से मुहावरे, कहावतें, बोलचाल के शब्द ऐसे हैं जो उर्दू में हैं, लेकिन जिनका प्रयोग हिन्दी में नहीं होना, कम होता है या गलत भी होता है । यह सब उर्दू से हिन्दी में आएगा । हमारी साहित्यिक भाषा ज्यादा सरल और मुहावरेदार होगी ।

उर्दू में संस्कृत शब्दों से जो परहेज है, उसे कम होना है । भारत की भाषाओं के लिए अरबी फारसी का वही महत्व नहीं है, जो संस्कृत का है । व्याकरण और मूल शब्द-भण्डार की दृष्टि से उर्दू संस्कृत परिवार की भाषा है, न कि अरबी-परिवार की । इसलिए अरबी में पारिभाषिक शब्द लेने की नीति गलत है, केवल अरबी से शब्द लेने और संस्कृत शब्दों को मनुष्यक समझन की नीति और भी गलत है । भारत की भाषाएँ प्रायः संस्कृत के आधार पर पारिभाषिक शब्दावली बनाती हैं । उर्दू इन सब भाषाओं से न्यायी रहकर अपनी उन्नति नहीं कर सकती । जहाँ तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, यह याद रखना चाहिए कि वहाँ की भाषाएँ सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बँगला आदि हैं । उर्दू उनके अधिकार छीननवाली राजभाषा है । पाकिस्तान में उर्दू का सामाजिक आधार बहुत ही सुकुचित है । इसमें जरा भी सन्देह न होना चाहिए कि सिंध, पंजाब, पूर्वी बंगाल आदि प्रदेशों की जनता अपनी भाषाओं की रक्षा करेगी

हिन्दी-उर्दू की बुनियादी एकता /

घोर उन्ही के माध्यम से अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति करेगी। इसलिए यदि कोई यह सोचे कि पाकिस्तान उर्दू की रक्षा करेगा, तो यह उसका भ्रम है। पाकिस्तान बनने से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की सामाजिक समस्याएँ हल हों, न उनकी भाषा-समस्या हल हो सकती है। इसीलिए उर्दू की समस्या का हल वही है, तो इसी हिन्द प्रदेश में है, जहाँ की जनता में उसका बोलचाल का रूप वापस है।

शब्द भण्डार में आदान प्रदान सम्भव है लेकिन लिपि में इसकी सम्भावना बिलकुल नहीं है। उर्दू से अलिफ और हिन्दी से 'इ' लेकर कोई नई लिपि नहीं बनाई जा सकती। रोमन लिपि का सवाल नहीं है। हम अपनी लिपि छोड़कर रोमन लिपि न अपनाएँगे। यदि रोमन लिपि कोई बहुत पूर्ण और वैज्ञानिक लिपि होती, तो उस पर विचार भी किया जाता। हिन्दी-उर्दू के लिपि-भेद को दूर करने के लिए रोमन लिपि को अपनाना बर्से ही है, जैसे हिन्दी तमिल, मराठी, गुजराती या बँगला अर्थात् भाषा के भगदो को दूर करने के लिए अंग्रेजी को महाराजभाषा बनाये रखना।

उर्दू लिपि के व्यवहार के लिए पूर्ण स्वाधीनता देते हुए प्रगतिशील विचारकों को चाहिए कि उर्दू-भाषियों को देवनागरी लिपि सिखाएँ। देवनागरी लिपि में उर्दू की जितनी किताबें छप रही हैं, उन्हें देखते हुए यह अनुमान होता है कि आगे चलकर देवनागरी लिपि में ही उर्दू के लेखकों की रचनाएँ छपेंगी। साक्षरता-प्रसार के साथ और दक्षिण में हिन्दी-प्रचार के साथ हिन्दी पुस्तकों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार तैयार हो गया है। यह नामुमकिन है कि उर्दू के होशियार पत्रकार लेखक इस स्थिति से फायदा न उठाएँ। सीधी मुनाफ की बात है उर्दू में किताबें छपेंगी कम बिकेंगी, हिन्दी में छपेंगी ज्यादा बिकेंगी। यह एक तरह का आर्थिक दबाव है जिससे देवनागरी लिपि को उर्दू लेखक अपनाएँगे।

इस प्रकार सामाजिक जीवन की परिस्थितियाँ हिन्दी उर्दू को बराबर एक दूसरे के नजदीक लाती रही हैं। सिनेमा और रंगमंच के लिए लिखनेवाले शुद्ध हिन्दी उर्दू का सवाल रखें तो उनकी रचनाएँ असफल हों। किसानों और मजदूरों में राजनीतिक काम करनेवालों को मजबूरन ऐसी सरल भाषा का प्रयोग करना पड़ता है जिसे हिन्दू-मुसलमान दोनों समझें। जन आन्दोलन की एकाता हिन्दी उर्दू के रूपों पर बराबर असर डाल रही है, और इसीलिए हमें यह दृढ़ विश्वास है कि ये दोनों रूप अपने अन्तर्गत तत्वों से एक ही साहित्यिक भाषा के विकास में सहायता करेंगे।

(१९६१)

राष्ट्रीय एकता और अंग्रेजी

राष्ट्रभाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे देश की बहुसंख्यक जनता जानती हो और जो लोग उसे न जानते हो, वे उसे आसानी से सीख सकें। यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय ही नहीं जनताधिक भी है क्योंकि बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली-समझी जानवाली भाषा के पक्ष में दिये जानेवाले सर्क के पीछे भावना यह है कि राष्ट्रीय यता मुट्ठी भर अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की धपौती नहीं है, उसका सम्बन्ध देश की बहुसंख्यक जनता से है।

५० जवाहरलाल नेहरू ने बीस-बाईस साल पहले लिखा था, 'प्रान्तीय भाषाभाषा के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का खरा भी उल्लंघन किये बिना हमारे लिए आवश्यक है कि विलिख भारतीय व्यवहार की एक सामान्य भाषा हो। कुछ लोग साचते हैं कि अंग्रेजी ऐसी भाषा बन सकती है, एक हद तक हमारे उच्च वर्गों के लिए और विलिख भारतीय राजनीतिक कार्यों के लिए अंग्रेजी ऐसी भाषा बनी भी है। किन्तु यदि हम आम जनता को ध्यान में रखकर सोचें तो यह बात स्पष्ट ही असम्भव प्रतीत होगी। हम करोड़ों लोगों को एक नितान्त विदेशी भाषा द्वारा शिक्षित नहीं कर सकते।' (नेशनल सेन्ट्रेज फॉर इंडिया—ए सिम्पोजियम, इलाहाबाद, १९४१, पृ० ४९-५०)

यदि राष्ट्रीयता उच्च वर्गों तक सीमित कर दी जाय, यदि जनतंत्र का उद्देश्य मुट्ठी भर लोगों का ऊँची सरकारी नौकरियाँ पाना हो, तो अवश्य अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा रहगी जैसे कि वह पिछले पन्द्रह वर्षों (या और भी पहले से) रही है। अंग्रेजी को हटाने और हिन्दी को व्यवहार में राष्ट्रभाषा बनाने का प्रश्न राष्ट्रीयता को व्यापक बनाने, राज्यसत्ता को जनताधिक रूप देने का प्रश्न है। जितने ही दिन अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित रहती है, उतने ही दिन राष्ट्रीयता का आधार नमश्च सुकुचित होता जाएगा, राज्य सत्ता जनता का विरुद्ध सम्पर्क और समर्थन खोती जाएगी। अनिश्चित काल के लिए अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाये रखने का अर्थ है, निश्चित रूप से जनतंत्र के आधार को सुकुचित करते जाना और अन्त में उसे निर्मूलक कर देना।

पराधीन भारत में ऊँची सरकारी नौकरियाँ पाने का अर्थ होता था, जनता पर हुकूमत करना। स्वाधीन भारत में सरकारी नौकरियों का अर्थ होना चाहिए जनता की सेवा करना। जिस भाषा को देश की जनता का एक प्रतिशत भाग समझता है, उससे विज्ञान जनता की सेवा कैसे हो सकती है ? आज भी बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में—पंजाब और ब्रह्मपूर की तो बात ही क्या—जितने लोग हिन्दी समझते हैं, उतने अंग्रेजी नहीं। अंग्रेजी न जाननेवाले इन करोड़ों अहिन्दी भाषियों की सेवा ऊँची सरकारी नौकरियाँ पानेवाले सज्जन हिन्दी के माध्यम से अधिक कर सकते हैं या अंग्रेजी द्वारा ?

कुछ लोग राष्ट्रीय एकता—या भावात्मक एकता—अंग्रेजी के माध्यम से दृढ़ करने का स्वप्न देखते हैं। यदि राष्ट्रीय एकता का अर्थ मुट्ठी-भर अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों की एकता है तो सम्भव है, वह अंग्रेजी से दृढ़ हो यद्यपि अंग्रेजीवादी नेताओं की कलह देखकर यह सम्भावना भी बहुत विष्वसनीय नहीं जान पड़ती। किन्तु यदि राष्ट्रीय एकता का अर्थ जनसाधारण की एकता है तो उसे दृढ़ करने में अंग्रेजी बाधक ही हो सकती है, साधक नहीं।

राष्ट्रीय गौरव की भावना के बिना भावात्मक एकता की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस राष्ट्र की अपनी भाषा न हो, जो राष्ट्र भाषा के पद पर एक विदेशी भाषा को बिठाये हो, उसके नागरिकों में राष्ट्रीय गौरव की भावना कैसे दृढ़ हो सकती है ?

अंग्रेजी के पक्ष में जो मुख्य तर्क दिया जाता है कि अंग्रेजी एक विकसित और समृद्ध भाषा है किन्तु हिन्दी तथा अन्य सभी भारतीय भाषाएँ अविकसित और दरिद्र हैं—वह राष्ट्रीय गौरव की भावना पर कुठाराघात है। अंग्रेजी के विकास और समृद्धि के गीत गाकर राष्ट्रीय गौरव को जगाने और भावात्मक एकता दृढ़ करनेवाले मेधावी लोग विषपान करके अमर होने का स्वप्न देख रहे हैं। यदि सुब्रह्मण्य भारती, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, बल्लत्तोल, प्रेमचन्द आदि साहित्यकार अंग्रेजी की समृद्धि से इसी तरह प्रभावित होते तो भारतीय साहित्य का वेडा मर्मधार में कभी का डूब चुका होता।

हम न दूसरों की तुलना में अपने को अकारण बड़ा बताकर डींग हाँकते हैं, न दीनभाव में अकारण अपने को सबसे पिछड़ा हुआ मानने को तैयार हैं। पश्चिमी यूरोप ने विज्ञान में अधिक उन्नति की है किन्तु साहित्य में हम यूरोप से बढ़कर नहीं तो घटकर भी नहीं हैं। विशेषकर पिछले सौ वर्षों में भारतीय साहित्य ने जो उन्नति की है, वह पश्चिमी यूरोप के किसी भी देश के लिए स्पर्हीय हो सकती है।

वास्तव में समस्या साहित्यिक समृद्धि की नहीं है, समस्या है राष्ट्रीय आत्मसम्मान और जनता की सेवा-भावना की। जिस देश हमसे अधिक विकसित नहीं है किन्तु वहाँ की राष्ट्रभाषा अरबी है। सोवियत संघ में कजाक, उजबेक, ताजिक आदि भी अपनी भाषाओं का शिक्षा, राजनीतिक कार्य आदि

के लिए प्रयुक्त करने हैं। चीन तक ने चीनी को राष्ट्रभाषा बना रखा है। ससार में सबसे प्राचीन संस्कृति का घनी भारत स्वाधीन होने पर भी अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाये रहे, इससे अधिक सज्जास्पद बात और क्या हो सकती है ?

यह ध्यान देने की बात है कि जो लोग अंग्रेजी को विकसित और समृद्ध बढ़कर उसे राष्ट्रभाषा बनाये रखना चाहते हैं, वे न केवल हिन्दी को, वरन् सभी भारतीय भाषाओं को न्यूनाधिक दरिद्र और अविकसित मानते हैं। हिन्दी के लिए हमारा सघर्ष, अंग्रेजी के विरुद्ध, सभी भारतीय भाषाओं के अधिनारों के लिए सघर्ष है। अंग्रेजी भारत में साम्राज्यवादी ढंग में प्रतिष्ठित है। वह प्रत्येक प्रदेश में वहाँ की भाषा के अधिकार छीनती है, उसे उच्च शिक्षा का माध्यम बनने से रोक्ती है; राजकाज में, उच्च न्यायालयों में वहाँ की भारतीय भाषा को अक्षय करती है। अंग्रेजी की यह साम्राज्यवादी स्थिति सारे देश में देखी जा सकती है; बाजार पर कुछ भी लिखा हो, व्यवहार की बात दूसरी ही है।

इसने विपरीत हिन्दी के समर्थकों का कहना है कि प्रत्येक प्रदेश में वहाँ की भाषा को उचित अधिकार मिले, वहाँ वे समस्त राजकाज में, शिक्षा-केन्द्रों, न्यायालयों आदि में वह प्रयुक्त हो, केवल विभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग व्यवहार के लिए, केन्द्रीय राज्यसत्ता और उसकी संस्थाओं के लिए हिन्दी का व्यवहार हो। यह स्थिति साम्राज्यवादी नहीं है, वरन् जनताधिकार और राष्ट्रीय है। प्रत्येक प्रदेश की भाषा को अंग्रेजी के स्थान पर राजनीतिक सांस्कृतिक कार्यवाही का माध्यम बनाना जनसंख्या की भावना के अनुकूल है। इन विभिन्न प्रदेशों के बीच तथा केन्द्र में हिन्दी का व्यवहार करना राष्ट्रीयता की भावना के अनुकूल है। भाषागत साम्राज्यवाद अंग्रेजी का है, न कि हिन्दी का। विभिन्न भारतीय भाषाओं के अधिकारों को इस समय पदचलित कर रही है अंग्रेजी, न कि हिन्दी। अंग्रेजी की वास्तविक साम्राज्यवादी स्थिति को भुलाकर जो लोग कल्पित हिन्दी-साम्राज्यवाद से जनता को आतंकित करते हैं, वे राष्ट्रीय एकता दुष्ट करने के बड़बुद राष्ट्रीय विघटन को जबर्दस्त प्रोत्साहन देते हैं।

अंग्रेजी से सभी भारतीय भाषाओं के हित टकराते हैं, हिन्दी से किसी भी भारतीय भाषा के हित नहीं टकराते, अंग्रेजी के जानने-समझनेवाले मुठ्ठी-भर हैं, हिन्दी बोलने समझनेवाले करोड़ों हैं; अंग्रेजी कायम रखने में जनता पर दुरुपयोग करनेवालों का निहित स्वार्थ है; हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने से विद्यालय जनता की सेवा करने का अवसर मिलता है; अंग्रेजी राष्ट्रीय शौर्य की भावना पर कुठाराघात करती है, हिन्दी राष्ट्रीय आत्मसम्मान को जाग्रत और पुष्ट करती है। इसलिए हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि अंग्रेजी अनिश्चित काल के लिए एवमात्र या सह-राष्ट्रभाषा नहीं रहेगी, निश्चित और सीमित अवधि में ही उसी अपना स्थान छोड़ना होगा।

राष्ट्रभाषा हिन्दी के विरुद्ध जितने तर्क दिये जाते हैं, उनमें जरा भी गौनियता नहीं है, वे पराधीन भारत में भी दिये जाते थे, अन्तर केवल इतना है कि तब ऐसे तर्क देनेवालों को अराष्ट्रीय कहा जाता था। अंग्रेजों के चले जाने पर मुसलमानों और अछूतों को सबर्ण हिन्दू या जाएंगे, दक्षिणवासी पर उत्तरवासी अपना आतंक फैलाएंगे, हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने से भारत की सांस्कृतिक उन्नति रुक जाएगी—ये सब तर्क ऊँची सरकारी नौकरियों के अंग्रेज-भक्त उम्मीदवार पहले भी दिया करते थे। अब इस तरह के तर्क अंग्रेजी-भक्त शासक या शासनपद के उम्मीदवार दिया करते हैं। इन सब तर्कों का सारतत्त्व यह है कि साहब का बेटा भी साहब होगा, कॉम्बेंट में पड़ेगा और अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोलेगा, वर्नक्युलर बोलनेवालों पर हुकूमत करेगा।

अंग्रेजी-प्रेमी शासकों को भय है कि अंग्रेजों के राजभाषा न रहने पर राज्य-सत्ता उनके हाथ में न रहेगी। यह बर्ग इस समय बाकी प्रभावशाली है किन्तु देश की विशाल जनता के सामने उसकी शक्ति नगण्य है। जो लोग भी अपनी मातृभाषा से प्रेम करते हैं, उनकी मातृभाषा चाहे हिन्दी हो, चाहे कोई अहिन्दी-भाषा, उनका कर्तव्य है कि विभिन्न प्रदेशों में अंग्रेजी की जगह वहाँ की प्रादेशिक भाषाओं को प्रतिष्ठित करें और केन्द्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी की जगह हिन्दी का व्यवहार करें।

हिन्दी पिछड़ी हुई भाषा है इसलिए उसे विवक्षित होने का अवसर देना चाहिए, यह भालसियों का तर्क है। हिन्दी में कितने आवश्यक शब्द हैं तथा कितने और होने चाहिए—इस समस्या की कोई वैज्ञानिक जाँच-पड़ताल अभी तक नहीं हुई। यदि भारत की किसी भी भाषा को समृद्ध माना जाय तो हम उससे पारिभाषिक शब्द लेने को तैयार हैं क्योंकि जो श्रोत हमारे पारिभाषिक शब्दों का है, वही उसके शब्दों का होगा—अर्थात् सस्कृत (उर्दू को छोड़कर)।

हिन्दी पिछड़ी हुई भाषा है, यह तर्क वे लोग देते हैं, जो भारत की प्रत्येक भाषा को पिछड़ा हुआ मानते हैं। राष्ट्र के लिए इससे अधिक अपमानजनक दूसरा दृष्टिकोण हो नहीं सकता। आज से पैंतीस वर्ष पहले अंग्रेज भाषाविद् प्रियर्सन ने हिन्दी के बारे में अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'लिंग्विस्टिक सर्वे' की भूमिका में लिखा था, "इट हैज ऐन एनारमस नेटिव वर्कबुलरी एण्ड ए कम्प्लीट अर्देन्ट फॉर ए एक्सप्लेन ऑफ़ ऐम्स्ट्रैक्ट टर्म्स," (देसी शब्दों का उसका विशाल शब्द-भण्डार है और सूक्ष्म धारणाएँ प्रकट करने के लिए पूर्ण पारिभाषिक शब्दावली है।) प्रियर्सन ने उन लोगों की आलोचना की थी, जो हिन्दी शब्द छोड़कर सस्कृत के कठिन और दुरूह शब्दों की ओर भागते थे और इसी प्रसंग में लिखा था—"थट इन्स्पाइट ऑफ़ हिन्दी पजेंसिंग सब ए वर्कबुलरी एण्ड ए पावर ऑफ़ एक्सप्रेसन नोट इन्फ़ीरियर टु इंग्लिश, इट हैज बिकम द फ़ैशन" (यद्यपि हिन्दी के पास ऐसा शब्द-भण्डार है और व्यञ्जना-शक्ति में वह अंग्रेजी से घटकर नहीं है, फिर भी यह फैशन हो गया है...)। जो लोग

अंग्रेजियत में अंग्रेजों के कान बाटते हैं, वे यह कभी न मानेंगे कि व्यजना-रावित में हिन्दी अंग्रेजी से घटकर नहीं है।

यूरोप और अमरीका में भारतीय सभ्यता के अग्रदूत महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने गुजराती साहित्य परिषद् के छठे अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था, "आपकी सेवा में खड़ा होकर विदेशीय भाषा वहाँ यह हम चाहते नहीं। पर जिस प्रान्त में मेरा घर है वहाँ सभा में बहने लायक हिन्दी का व्यवहार है नहीं। महात्मा गांधी महाराज की भी भाषा है हिन्दी में बहने के लिए। यदि हम समर्थ होता सब इससे बड़ा आनन्द और कुछ होता नहीं। असमर्थ होने पर भी आपकी सेवा में दो बात हिन्दी में बोलूंगा।" ('प्रभा', कानपुर, मार्च, १९२५)

जो लोग उठते-बैठते गांधीजी के नाम की माला जपते हैं और जिन्होंने प्रचलित भारतीय पैमाने पर रवीन्द्र-जयन्ती-समारोह सगठित किया था, वे हुए-विचार करें कि वे अपने व्यवहार में गांधी-रवीन्द्रनाथ के मार्ग से कितनी दूर था पड़े हैं। महाकवि ने अपनी असमर्थता प्रकट की, किसी भाषा को असमर्थ नहीं कहा, गांधीजी ने गुजरातियों के बीच उनसे अंग्रेजी में नहीं, हिन्दी में बोलने को कहा।

राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करने का यही एक मार्ग सन् '२५ में था, वही मार्ग अब सन् '६२ में भी है। और दूसरे रास्ते सब गलत हैं। (१९६२)

राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय प्रभुसत्ता

सन् '६५ में हिन्दी केन्द्रीय राजकाज की भाषा न बनेगी। बय बनेगी, यह अंग्रेजी-प्रेमी भारतवासियों की इच्छा पर निर्भर है। इस पर भी कुछ सज्जन असन्तुष्ट हैं। असन्तुष्ट इस बात पर है कि अंग्रेजी सदा-सर्वदा के लिए भारत की एकमात्र राष्ट्रभाषा घोषित नहीं की गई। हो सकता है दो-चार शताब्दियों बाद लोग हिन्दी को राष्ट्रभाषा बना दें। इस सम्भावना को रटने ही बयो दिया जाय ?

ऐसा सोचनेवाले सज्जन अंग्रेजी के माध्यम से शासनतन्त्र पर अपना इजारा हमेशा के लिए पक्का कर लेना चाहते हैं। वे और उनके भाई भतीजे तो इस युग में शासन की बागडोर संभाले ही हुए हैं, वे चाहते हैं कि युगो-युगो तक उन्हीं की तरह उनके वंशज भी—यानी मुट्ठी-भर विदेशी भाषा के उपासक—शासन की बागडोर इसी तरह मजबूती से थाम रहे। कुछ दिन हुए ऐसे लोगों को लक्ष्य करके मद्रास में प्रधान मन्त्री न प्रश्न किया था—क्या उनमें राष्ट्रीय आत्मसम्मान की भावना का एकदम लोप हो गया है ?

इस प्रश्न से नतीजा यह निकलता है कि जो लोग थोड़े समय के लिए अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा मानते हैं, उनमें उतने ही समय के लिए आत्मसम्मान का लोप होता है, जो लोग सदा के लिए अंग्रेजी का राष्ट्रभाषा बनाय रखना चाहते हैं, उनमें सदा के लिए आत्मसम्मान का लोप हो जाता है। सदा के लिए आत्मसम्मान खोने से अच्छा है उसे थोड़े समय के लिए खोया जाय। भले ही इस थोड़े समय की अवधि का क्रमशः विस्तार होता जाय—सन् '४६ से '६५ तक, '६५ से बीसवीं सदी के अन्त तक, बीसवीं सदी के बाद इक्कीसवीं सदी के अन्त तक, और इसी तरह अनिश्चित काल के लिए थाले भी। मुख्य बात यह है कि अनिश्चित काल को निश्चित न किया जाय, वरना राष्ट्रीय आत्मसम्मान का सापेक्ष अभाव शाश्वत और निरपेक्ष हो जाएगा।

एक बहुत दिलचस्प सवाल यह पैदा होता है कि राष्ट्रीय आत्मसम्मान का यह अभाव भाषा के क्षेत्र तक सीमित है या वह देश के राजनीतिक, आर्थिक

प्रादि अन्य क्षेत्रों में भी है। क्या आपने सत्तार के इतिहास में किसी ऐसे देश का नाम सुना है जो प्रायिक और राजनीतिक रूप से पूर्ण स्वाधीन रहा हो किन्तु जो भाषा के क्षेत्र में परमुखापेक्षी हो? क्या वर्तमान काल में कोई ऐसा देश है जो स्वाधीन होते हुए भी अपनी भाषा छोड़कर विदेशी भाषा का व्यवहार करता हो? इन स्वाधीन देशों में इस बात का लेकर पच-पत नहीं जुड़ती कि विश्व की सबसे समृद्ध भाषा चीन-सी है, देश की भाषा का हटाना उससे बढ़ने विदेश भाषा का व्यवहार अब तक किया जाय। प्रायिक जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, इतालवी, स्पेनी प्रादि भाषाएँ समान रूप में भी समृद्ध हो नहीं सकती। किन्तु जहाँ ये भाषाएँ होती जाती हैं, वहाँ यह प्रश्न कोई नहीं करता कि सबसे समृद्ध विदेश-भाषा को राजवाज की भाषा क्यों न बनाया जाय। यह प्रश्न केवल उन देशों में सामन होता है जो पश्चिमी राष्ट्रों के उपनिवेश हैं, या रहे चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हिन्दी में चिपके रहना और अंग्रेजी का विरोध करना रूप मण्डूकता है। भ्राम्य होता है कि अपनी भाषा से प्रेम करनेवाले तो कृषो में पड़ हैं, केवल भारत के अंग्रेजी-प्रेमी मण्डूक कुएँ से बाहर निकलकर अपनी अपनी अंग्रेजी-ध्वनि में दसों दिशाएँ गुंजरित कर रहे हैं।

प्रायिक स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए तो पैसा बीड़ी दरबार होता है, स्वर्ण की आवश्यकता होती है। किन्तु शब्द ब्रह्म तो अमूल्य है। बात करने में क्या लचक होता है? फिर भारत में सस्कृत की कृपा से किसी भी भाषा के शब्द-भण्डार में यथेच्छ भरने में विलम्ब नहीं होता। भाषा के क्षेत्र में परमुखापेक्षी होना परतों गिरे की मुलामी है। जो भाषा के क्षेत्र में स्वाधीन नहीं हो सकता, वह अन्य क्षेत्रों में क्या स्वाधीन होगा? भारतम्बु हरिद्वन्द्व, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सुब्रह्मण्य भारती, निराला, प्रेमचन्द प्रादि साहित्यकारों ने देश के पराधीन रहते हुए भी भाषा के क्षेत्र में अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा की। भाषा के क्षेत्र में भारतीय साहित्यकारों ने अंग्रेजी का प्रभुत्व कभी स्वीकार नहीं किया। स्वाधीनता मूर्ख की किरणों ने सबसे पहले भाषा के क्षेत्र को प्रकाशित किया। प्रायिक और राजनीतिक क्षेत्रों के नेता साहित्यकारों के अनुगामी रहे हैं, उनके पथ निर्देशक नहीं।

प्राये दिन जो राजनीतिज्ञ हिन्दी प्रेमियों को सबीर्ण और सङ्कुचित विचारवाला कहते हैं, जो हिन्दी से विमुख और अंग्रेजी के मुखापेक्षी असुखी बृट्टम्बकम् का उपदेश देते नहीं करते, उनसे पूछा जा सकता है—दश में अन्न का क्या हाल है? मुसमरी से बचने के लिए आपकी अन्य राष्ट्रों का दरवाजा तो सटखटाना नहीं पड़ता? अपनी पचवर्षीय योजनाओं की पूर्ति के लिए आपकी विदेशी बहीखातों में कर्जदार बनकर नाम लिखाना तो नहीं पड़ता? देश-रक्षा के लिए आप विदेशी अस्त्र-शस्त्रों के मोहताज तो नहीं हैं? आपके आयात-निर्यात व्यापार में विदेशी पूँजी का ताना बाना बुना हुआ तो नहीं है? आप विदेशी दबाव के कारण कश्मीर-जैसे किसी प्रदेश की भूमि का विनिमय

राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय प्रभुसत्ता /

करने की ओर तो मही बड़े ?

पुराने जमाने में लोग बहुत थे—अंग्रेजी हमारे गुलामी की निगानी है। ऊपर के प्रश्न पढ़कर बताइए, यह बात सही है या नहीं ? क्या आप समझते हैं कि दासता की मनोवृत्ति केवल भाषा के क्षेत्र में प्रतिबिम्बित होती है, अंग्रेजी की हटाने का प्रयास केवल एक भाषागत समस्या है ? गुलाम तो गुलाम। उमरी गुलामी न केवल उसके सोलने से प्रकट होगी बल्कि उसके हर तरह के धार्मिक और राजनीतिक व्यवहार से प्रकट होगी।

राष्ट्रभाषा की समस्या कोई विगुड़ भाषा विज्ञान की समस्या नहीं है। यह मूलतः देश की प्रभुसत्ता की समस्या है। यह तो सम्भव है कि केन्द्रीय राजराज के लिए एक सार्वजनिक भाषा का व्यवहार किया जाय, किन्तु देश की प्रभुसत्ता के लिए यह प्रसङ्ग है कि सभी भारतीय भाषाओं के अधिकारी की पैरी तले रौंदकर अंग्रेजी उन सबके ऊपर प्रतिष्ठित हो। जो लोग यह कहते हैं कि हिन्दी के माध्यम से बड़े-बड़े पूँजीपति छोटी छोटी अहिन्दीभाषी जातियों को दबाते हैं, वे यह अभी नहीं कहते कि अंग्रेजी के माध्यम से साम्राज्यवाद भारत की सभी जातियों को दबाता है, यहाँ की सभी भाषाओं के स्वतन्त्रता का अपहरण करता है।

हिन्दी को केन्द्रीय भाषा बनाने में कुछ बड़े पूँजीपतियों का स्वार्थ हो सकता है, यद्यपि ऐसा नहीं जाना है कि अंग्रेजी के दैनिक पत्रों की श्रृंखलाएँ इन्हीं बड़े पूँजीपतियों के हाथ में हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हिन्दी को केन्द्रीय भाषा बनाने में छोटे पूँजीपतियों तथा श्रमिक जनता का हित सबसे बड़ा है। हिन्दी के बिना सामान्य जनता सामन्ततन्त्र, केन्द्रीय राजराज में भाग नहीं ले सकती। यह राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यवाही का अन्तगोचर के समान दूर रहती जाती है। इस तरह हमारे जनतन्त्र का आधार सन्तुष्ट रहता है, हमारी राष्ट्रीयता मुट्ठी-भर अंग्रेजी पढ़े लोगों के हाथ का तिलोना बनी रहती है।

जो लोग अंग्रेजी को हटाना चाहते हैं, हिन्दी को केन्द्रीय भाषा बनाने के लिए जल्दी करते हैं, उन्हें 'हिन्दी एंथ्रॉपिस्ट' आदि उपाधियों से विभूषित किया जाता है। मानो अपनी भाषा का समर्थन करना गुनाह हो, 'अंग्रेजी एंथ्रॉपिस्ट' होना कोई बहुत बड़ा पुण्य हो। केन्द्रीय भाषा के पद से अंग्रेजी को हटाने में किसी एक भारतीय भाषा का स्वार्थ नहीं है। अंग्रेजी की वर्तमान स्थिति से सभी भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है, उनका अधिकार-मर्यादा नष्ट होती है। इसलिए अंग्रेजी के विरुद्ध संघर्ष आज सभी भारतीय भाषाओं की अधिकार रक्षा का संघर्ष है। इन भाषाओं के बीच परस्पर आदान प्रदान के लिए हम हिन्दी का व्यवहार चाहते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए, न कि उनके अधिकारों को रौंदकर। अधिकारों को रौंदने का काम अंग्रेजी कर रही है, न कि हिन्दी।

प्रत्येक जाति का यह जन्ममिद घटिकार है कि वह अपनी सांस्कृतिक, राजनीतिक, हर तरह की सामाजिक कार्यवाही अपनी भाषा के माध्यम से सम्पन्न करे। हर तरह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में अपनी भाषा का प्रयोग उसकी प्रभुता की उन्मुख घोषणा है। जातीय भाषा का व्यवहार राष्ट्र के स्वाधीन होने की पहचान है। भाषा के समृद्ध या दरिद्र होने से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। समार के किसी देश ने किसी समय यह नियम स्वीकार नहीं किया कि विद्वत् की सबसे समृद्ध भाषा को वह राष्ट्रभाषा बनायेगा। ऐसा नियम होता तो सारे समार में संस्कृत, ग्रीक या लैटिन का ही प्रभुत्व होता।

हिन्दी समृद्ध है या दरिद्र है, यह तय करने के लिए कोई वैज्ञानिक कसौटी नहीं अपनायी गई। उदाहरण के लिए, हिन्दी में राजनीतिक शब्दावली कम है या पर्याप्त है, यह जानने के लिए कोई शब्द-गणना नहीं की गई। एक प्रवाद कैना दीजिए, इस राजनीतिज्ञ उस प्रवाद को दोहरा दें, अंग्रेजी प्रत्यक्षारो में वह प्रवाद छप जाय, कम उसे प्रमाणित सत्य मान लिया जाएगा। देश में प्रचार के साधनों का इतना केन्द्रीकरण है कि मक्कारताने में हिन्दी सम्बन्धी सत्य की पुनरावृत्ति की भाषा से अधिक कारगर साबित नहीं होती।

शामनतन्त्र चलानेवाले बुद्धिजीवी अंग्रेजी में अथवा किसी देशी भाषा में अंग्रेजी शब्दों को मिलावट करके चिन्तन का काम पूरा करते हैं। उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम अंग्रेजी या वह खिचड़ी भाषा होती है। आप यह न समझें कि पारिभाषिक शब्दों के अभाव के कारण वे ऐसा करते हैं। उनके बच्चे बोलना सीखते हैं, पापा, डैडी, मम्मी, भगल, भाण्टी जैसे पारिभाषिक शब्दों के ज्ञान के साथ। 'जरा फादर को रिसीव करने जा रहा हूँ,' 'उसका रिमार्क ऐसा सिली था कि माई ब्लड बिगन टु बॉयल', 'भाजकस आप पोलिटिकल ऐक्टिविटी से इतने इण्टिफरेण्ट क्यों रहते हैं', 'एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि माडिनेरी एप्लीकेशन लिखने में एम० ए० पास लोग मिस्टेक करते हैं'—इस तरह के वाक्य उत्तर भारत के अनेक शहरों में आप सुन सकते हैं। इन वाक्यों में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग पारिभाषिक शब्दों की कमी के कारण नहीं है। मानसिक क्षमता, अंग्रेजी शब्दों का मोह, अपनी भाषा के प्रति अवज्ञा-सूचक दृष्टिकोण—इन कारणों से उस तरह के भोटे वाक्यों की रचना होती है। इन्हीं कारणों से अंग्रेजी प्रेमी बुद्धिजीवियों को यह तय करने में देर नहीं लगती कि अंग्रेजी समृद्ध है, हिन्दी दरिद्र है।

एक समिति में लोग आलोचना सम्बन्धी शब्द-सूची एवत्र कर रहे थे। समिति के अधिकांश सदस्य न हिन्दी के आलोचक थे, न हिन्दी आलोचना से परिचित थे। फिर भी वे इस काम में लगे हुए थे क्योंकि वे समिति के सदस्य बना दिये गए थे। शब्द संग्रह करने का तरीका क्या था? आप शायद सोचें कि हिन्दी की आलोचना पुरतकों से अथवा संस्कृत के सिद्धान्त ग्रन्थों से ऐसी शब्द-सूची मकलित की जा रही थी। समिति ने मामले का दूसरा था। काम हिन्दी-

शब्दों की सूची बनाना न था, काम था अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्याय निश्चित करना। इस तरह की सूची बनाने की जरूरत क्यों हुई? इसलिए कि अंग्रेजी का आलोचना-शास्त्र अधिक समृद्ध है, उसके शब्द-भण्डार के अनुरूप हिन्दी पर्याय स्थिर करके ही राष्ट्रभाषा को समृद्ध किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं, समिति में इस पद्धति का विरोध करनेवाले को किसी का समर्थन प्राप्त न हुआ होगा।

प्राकृतिक परिवेश, सामाजिक परिस्थितियाँ, दैनिक जीवन की आवश्यकताएँ विभिन्न देशों में बहुत-बहुत समान हैं। इसलिए उनके शब्द-भण्डार में अर्थ-सम्बन्धी बहुत बड़ी समानता है। किसी भी भाषा के हजारों शब्दों के लिए दूसरी भाषा में उन्हीं के समानार्थी शब्द मिल जाते हैं। यातायात के माधनों में प्रगति होने से, व्यापार, उद्योग धर्मों और विज्ञान में उन्नति होने से (और उन्नति करने के लिए) अनेक देश एक-दूसरे के अधिक निकट आये हैं। इसलिए ऐसे शब्दों की सख्या बहुत बड़ी है जो रूप में भिन्न होते हुए भी अर्थ में समान हैं। हिन्दी में भी उद्योग, व्यापार, राजनीति आदि से सम्बन्धित हजारों शब्द प्रचलित हैं जो उसी कोटि के अंग्रेजी या जर्मन शब्दों के समानार्थी हैं।

इसके साथ यह भी सही है कि प्रत्येक देश के प्राकृतिक परिवेश, सामाजिक परिस्थितियों, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की अपनी विशेषताएँ हैं। इसलिए प्रत्येक भाषा में हजारों शब्द ऐसे मिलेंगे जिनके ठीक समानार्थी शब्द दूसरी भाषाओं में दुर्लभ होंगे। किन्तु भाषा प्राकृतिक या सामाजिक परिवेश का दर्पण मात्र नहीं है। भाषा प्रत्येक जाति की विशिष्ट चिन्तन प्रक्रिया, उसके रसबोध, भाव-सम्बन्धी प्रतिक्रिया का दर्पण भी होती है, इस दृष्टि से विचार करने पर पता चलेगा कि कोई भी भाषा किसी से घटकर नहीं है, प्राणि-जगत् की प्रत्येक जीव यानि के समान ससार की प्रत्येक भाषा की अपनी विशेषता है।

इस देश के लोगो ने अनेक शताब्दियों तक मनुष्य के मन पर, उसकी चेतना पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। दर्शन और मनोविज्ञान के क्षेत्रों में अनेक धारणाओं का जैसा सूक्ष्म भेद संस्कृत शब्द प्रकट करते हैं, वैसा ससार की कोई भाषा प्रकट नहीं करती, कम-से-कम ग्रीक, लैटिन और इनसे प्रभावित यूरोप की भाषाएँ तो अवश्य नहीं करती। संस्कृत की वह शब्द-सम्पदा भारत की समस्त भाषाओं की सामान्य सम्पत्ति है। उन लोगो के सांस्कृतिक पतन का अनुमान कीजिए जो 'मेडिटेशन' के लिए अपनी शब्द-सूची में 'ध्यान' शब्द बिठाकर यह समझ लेते हैं और दूसरों को समझाते भी हैं कि 'ध्यान' अब 'स्टैण्डर्ड' शब्द हो गया, 'मेडिटेशन' का पर्याय बनकर। इसके बाद वे कहते हैं कि जो पुस्तकें लिखी जाएँ या अनुवादित की जाएँ, उनमें 'ध्यान' शब्द उसी अर्थ में प्रयुक्त होना चाहिए जिसमें अंग्रेजी का 'मेडिटेशन' शब्द प्रयुक्त होता है। और 'समाधि' के लिए अंग्रेजी का कोई पर्याय न हुआ तो वह बेचारा स्टैण्डर्ड-च्युत होकर शब्द-संग्रह के बाहर पड़ा रह गया।

भारतीय शब्द 'राष्ट्र' का ठीक समानार्थी अंग्रेजी शब्द 'नेशन' नहीं है। सोवियत सभ में एक से अधिक 'नेशन' हैं किन्तु वह 'राष्ट्र' एक है, अनेक नहीं। 'राष्ट्र' से केवल मनुष्यों का बोध नहीं होता जैसा कि 'नेशन' से होता है। 'नेशन' किसी देश की भूमि को नहीं वह सकता, किन्तु 'राष्ट्र' से भूमि का बोध भी होता है। जे० डी० वेट की 'ए दिक्शनरी ऑफ द हिन्दी लैंग्वेज' में राष्ट्र का भूमि वाला अर्थ दिया है—'ऐन इन्हेबिटेड कण्ट्री, ए रेलम, किंगडम, एम्पायर, रीजन।' अन्त में मनुष्यों से भी सम्भावित एक शब्द जोड़ दिया गया है, 'पब्लिक'। इससे उन कोशकारों की कठिनाइयों का अनुमान किया जा सकता है जिन्हें हिन्दी शब्दों के अंग्रेजी पर्याय ढूँढ़ने पड़ते हैं। बचारे 'राष्ट्र' के लिए 'पब्लिक' लिखकर सन्तोष कर लेते हैं। प्रसिद्ध कोशकार मोनियर विलियम्स को अपने महान् संस्कृत अंग्रेजी कोश की भूमिका में कैफियत देनी पड़ी थी कि उन्होंने एक एक संस्कृत शब्द के अनेक अंग्रेजी पर्याय क्यों दिये हैं। इसका एक कारण और भी था जिसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया। वह यह कि किसी एक संस्कृत शब्द का ठीक समानार्थी शब्द अंग्रेजी में मिलता न था; इसलिए उसके अर्थ के निकट पहुँचनेवाले अनेक शब्द देने पड़ते थे, जिससे अंग्रेजी जानने-वाला विद्यार्थी उन सभी की सहायता से अर्थ बोध कर सके। यथा 'समाधि' के लिए 'इण्टेन्स ब्रॉलीबेदान ऑर फिक्सिग द माइण्ड ऑन, इण्टेण्डनेस, अटेंशन, कन्सन्ट्रेशन ऑफ द थॉट्स, प्रोफाउण्ड ऑर ऐंस्टरैक्ट मेडिटेशन, इण्टेन्स कन्टेम्प्लेशन ऑफ ऐनी यर्टोबुलर ऑब्जेक्ट (सो एंज द्वाइवेण्टीफाई द कन्टेम्प्लेटर विद द ऑब्जेक्ट मेडिटेटेड अपॉन)'। 'समाधि' का समानार्थी शब्द ५ पंजी में है नहीं। यह भी स्पष्ट है कि 'अटेंशन', 'कन्टेम्प्लेशन', 'मेडिटेशन' आदि शब्द समाधि के निरिक्त अर्थ के निकट पहुँचते हैं किन्तु उसे प्रकट नहीं कर पाते। वास्तव में 'समाधि' की अपेक्षा वे 'ध्यान' के अधिक निकट हैं।

मोनियर विलियम्स ने भारतीय वाङ्मय के बारे में लिखा था, "कुछ विषयों में, विशेषकर प्रकृति और पारिवारिक प्रेम के कवित्वमय वर्णनों में वह ग्रीस और रोम की सर्वश्रेष्ठ कृतियों के मुकाबले हेठा नहीं सिद्ध होता और ज्ञान की गरिमा और नैतिक विचारों की सूक्ष्म सूक्ष्म में वह अद्वितीय है।" वैज्ञानिक विषयों का उल्लेख करते हुए उन्होंने आगे उसी भूमिका में लिखा था, "इससे भी बढ़कर यह कि हिन्दुओं ने खगोल विज्ञान, गणित, बीजगणित, वनस्पति-विज्ञान और औषध में काफी प्रगति की थी, व्याकरण में उनकी श्रेष्ठता का उल्लेख करना अनावश्यक है; और यह सब उस समय जब यूरोप की प्राचीनतम जातियों में भी इनमें से कुछ विज्ञान विकसित न हुए थे।" मोनियर विलियम्स ने संस्कृत के शब्द-भण्डार की बहुविध समृद्धि को लक्ष्य करके लिखा है कि उसका कोश बनानेवाले को लगभग सर्वज्ञ होना चाहिए। उनके अनुसार इम्बेड में यूनिवर्सिटी शिखा प्राप्त तरुण संस्कृत की "वैज्ञानिक शब्दावली की सही सही व्याख्या नहीं कर सकते।" मोनियर विलियम्स ने यह

घीर जोड़ दिया है कि यदा-कदा यह वैज्ञानिक शब्दावली संस्कृत में यूनानियों से उधार ली गई है। किन्तु यहाँ इस पर विवाद नहीं करना कि भारत में यूनान से पहले अनेक विज्ञान विवसित हुए, फिर भी यहाँ के शब्द यहाँ वालों ने क्यों उधार लिए। मुख्य बात यह है कि यूरोप की नवीन घीर प्राचीन भाषाओं के महापंडित कोशकार मोनियर विलियम्स को यह स्वीकार करना पड़ा था कि इंग्लैंड की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियों के सरुण ग्रेजुएट—भारत में जिनके रोबदाव की सीमा नहीं है—संस्कृत की वैज्ञानिक शब्दावली ('द साइटीफिक एक्सप्रेसन') की घारीवियों को समझने में असमर्थ थे। आज मालूम होता है, मोनियर विलियम्स प्रभृति विद्वानों द्वारा अभिनन्दित हमारा वह महान् रिषय वही लो गया है। सरकारी कोशकार हिन्दी में यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली से पारिभाषिक शब्द उधार लेने की बात करते हैं यद्यपि वे जो विदेशी शब्द लेते हैं, वे निरपवाद रूप से अंग्रेजी के ही होते हैं (अर्थात् ऐसे शब्द होते हैं जो ग्रीक लैटिन के आधार पर गढ़कर अंग्रेजी में अलाये गए हैं)। ये सम्मान्य सरकारी कोशकार वह अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली प्रकाशित कर दें तो यूरोप के भाषारमक एकीकरण में बड़ी सहायता मिले।

एक समय था जब स्वामी विवेकानन्द जैसे भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि गरजकर मदान्ध यूरोप से कहते थे, स्वार्थ-लिप्सा ने तुम्हें पतन के गर्त में ढकेल दिया है, भाषो, इस गर्त से बाहर निकलो, ज्ञान की दीक्षा भारत से लो।

विवेकानन्द घीर रवीन्द्रनाथ का वह भारत आज परमुलापेक्षी है, न केवल आर्थिक सहायता के लिए वह पश्चिमी राष्ट्रों का द्वार खटखटाता है वरन् शब्दावली के लिए भी वह उनका मुंह जोहता है, वह अंग्रेजी के बिना अपनी भाषा-समस्या हल नहीं कर सकता।

(१९६२)

हिन्दीभाषी प्रदेश में हिन्दी-प्रचार की आवश्यकता

हम हिन्दी-भाषियों में अधिकांश जनों की धारणा यही है कि हिन्दी यदि अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं हो पाई तो इसका मुख्य कारण अहिन्दी-भाषियों का अंग्रेजी-प्रेम अथवा हिन्दी विरोध है। हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में इस विषय पर जो लेख निकलते हैं, उनसे यह प्रकट नहीं होता कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का सर्वाधिक उत्तरदायित्व हमारा है और हम उसे निवाह नहीं रहे हैं।

हमारे देश में एक पूरा वर्ग है, जो राष्ट्रभाषा के पद पर अंग्रेजी की प्रतिष्ठित रायना चाहता है। यह वर्ग किसी प्रदेश-विशेष में सीमित नहीं है बल्कि हमारे देश में फैला हुआ है, अमर-जैन की तरह वह विशाल हिन्दीभाषी प्रदेश में भी फैला है। आधे दिन अपने प्रदेश के शिक्षित जनों के व्यवहार में हम अंग्रेजी का यह महत्व देख सकते हैं। हिन्दीभाषी प्रदेश में इस वर्ग के लोग उतने सुख नहीं हैं जितने उनके गृहयोगी अन्य प्रदेशों में हैं। फिर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रदेशों के अंग्रेजी प्रेमी एक-दूसरे की सहायता करते हैं।

पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अनेक नगरीय भावार्थक एकता पर राज नीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के नेताओं ने भाषण किये, अनेक मिथा-संस्थाओं में परिसंवाद आयोजित किये गए। आगरा और मेरठ की दो ऐसी गोष्ठियों में मैंने देखा कि अधिकांश भाषण अंग्रेजी में हुए। ये नेतागण अवश्य ही मन में सोचते होंगे कि अंग्रेजी ही उनके उच्च विभागों का वाहन हो सकती है अंग्रेजी द्वारा ही वे देश में राष्ट्रीय एकता दृढ़ कर सकते हैं। अभी पिछले महीने चीनी आक्रमण के विरोध में विद्यार्थियों की सभाओं में अध्यापकों के प्रोत्साहन-प्रद भाषण भी अंग्रेजी में हुए। यदि हमारे प्रदेश के शिक्षा-विचारद भी नवयुवकों की देश रक्षा का महत्व समझने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, तब अन्य प्रदेशों में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की माँग हम किम भूँह में कर सकते हैं ? सभी शिक्षित जनों का व्यवहार ऐसा नहीं होता, काफी लोग ऐसे हैं, जो ऐसे घर-बारों पर गनेत ढंग से हिन्दी का ही व्यवहार करते हैं। फिर भी यह मानना होगा कि हिन्दी क्षेत्र के शिक्षित जनों में अंग्रेजी का चयन आवश्यकता के

अधिक है।

हिन्दी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में शिक्षा का सामान्य माध्यम अंग्रेजी है। कुछ विषयों में जहाँ-तहाँ हिन्दी द्वारा शिक्षण भी होता है किन्तु कुल मिलाकर शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी का स्थान गौण है, अंग्रेजी का स्थान प्रमुख है। इसी प्रकार शासन-संस्थाओं की कार्यवाही के लिए अंग्रेजी का व्यवहार प्रचुर मात्रा में होता है। जब तक उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की शासन-संस्थाओं में अमली रूप से हिन्दी राजभाषा नहीं बन जाती, तब तक समूचे देश में उसका राष्ट्रभाषा बनना स्वप्नवत् ही रहेगा।

हिन्दी-भाषी प्रदेश के शिक्षित जन बंगाल या तमिलनाडु के लोगों पर अक्सर आधागत सखीर्णता या प्रान्तीयता का दोष लगाते हैं। वास्तविकता यह है कि बंगाल या तमिलनाडु के शिक्षित जन अपनी भाषा से जितना प्रेम करते हैं अपने सामाजिक जीवन में उसका जितना प्रयोग करते हैं, उतना हम नहीं करते। अन्य प्रदेशों के शिक्षित-जन यदि अपने यहाँ के साहित्य से अपरिचित हों तो उन्हें शर्म आयेगी। हमारे प्रदेश के शिक्षित जन हिन्दी-साहित्य से अपरिचित होने में गर्व का अनुभव करते हैं। अपने अज्ञान पर गर्व करते हुए वे पिछले तीस वर्षों से लगातार एक ही प्रश्न दोहराते चले आए हैं— हिन्दी में है ही क्या ?

हिन्दी-भाषी प्रदेश की जनता से थोटा लेना और उसकी भाषा और साहित्य को गालियाँ देना कुछ नेताओं का दैनिक व्यवसाय है। हमारे प्रदेश के शिक्षित जनों में जातीय भावना की कमी है। वे हिन्दी के प्रति उदासीन हैं, इसीलिए वे कुछ राजनीतिज्ञों की अपमानजनक बातों का समुचित उत्तर नहीं दे पाते। यहाँ का राजनीतिज्ञ राजनीति के अलावा अंग्रेजी-भक्ति में जनता का नेतृत्व करता है। अंग्रेजी में जितनी पुस्तकें केवल उत्तर प्रदेश के राजनीतिज्ञों ने लिखी हैं, उतनी शेष भारत के सारे राजनीतिज्ञों ने नहीं लिखी। अन्य प्रदेशों के नेताओं में एक पुस्तक अंग्रेजी में लिखी तो दो अपनी भाषा में भी लिखी। यहाँ का राजनीतिज्ञ यदि देवनागरी में हस्ताक्षर कर दे तो समझता है कि उसने हिन्दी को कृतार्थ कर दिया।

यह किसी नेता-विशेष का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है एक समूचे अंग्रेजी-प्रेमी वर्ग का, जो प्रदेश का शासक है या शासक बनना चाहता है। राजनीतिज्ञ इसी वर्ग का प्रतिनिधि है। एक नेता हट जाएगा तो दूसरा आ जाएगा क्योंकि उसे जन्म देनेवाला वर्ग मौजूद है। इसीलिए हिन्दी-भाषी प्रदेश में हिन्दी-प्रचार की आवश्यकता है, हिन्दी-प्रचार द्वारा शिक्षित जनों का दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है, उनके सामाजिक व्यवहार में, सांस्कृतिक जीवन में, शिक्षा-संस्थाओं के अन्तर्गत उनकी कार्यवाही में अंग्रेजी की जगह हिन्दी को प्रतिष्ठित कराने की आवश्यकता है।

मिथ्या जातीय अहंकार हानिकार होता है। अपनी भाषा और साहित्य को

ही ध्येष्ठ समझता और दूसरो की भाषा और साहित्य को सदा हीन समझता मूर्खता है। किन्तु जातीय भावना से हीन होकर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का मन्त्र जपना भी कोई बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता का चिह्न नहीं है। हमारा राष्ट्र अनेक भाषाएँ बोलनेवाली जातियों से मिलकर बना है। राष्ट्रीय एकता के लिए इन जातियाँ की एकता आवश्यक है। सभी जातियाँ मिलकर राष्ट्र को दृढ़ करें, इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक जाति अपने भीतर दृढ़ हो, अपने-आपमें एकताबद्ध हो। कोई भी जाति अपने भीतर शिथिल होकर राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने में उचित योग नहीं दे सकती।

हिन्दी भाषी जाति विभिन्न राज्यों में बँटी हुई है। हिन्दी-भाषी प्रदेश की सीमाएँ अनिश्चित हैं। यही नहीं, भाषागत विवाद जितने यहाँ हैं, उतने किसी अन्य प्रदेश में नहीं हैं। दूसरी जगह विवाद होना तो बँगला-असमिया या गुजराती-मराठी जैसी दो भिन्न भाषाओं को लेकर। यहाँ के विवाद एक ही भाषा-क्षेत्र के अन्तर्गत हैं।

मिथिला के कुछ राजनीतिज्ञ हिन्दी को अपनी जातीय भाषा नहीं मानते। पिछले चुनाव में उन्होंने अपने राजनीतिक प्रचार के पक्ष में मिली और उर्दू में छपाये। हिन्दी का बहिष्कार किया। भोजपुरी क्षेत्र में जन्म लेनेवाले कुछ हिन्दी के आचार्य भाषा-विज्ञान पर ग्रन्थ लिखकर यह सिद्ध करते हैं कि भोजपुरी हिन्दी से स्वतन्त्र भाषा है। जिन्हें हम हिन्दी की बोलियाँ कहते हैं, उनके क्षेत्रों में हिन्दी प्रचार आवश्यक है, जिससे वहाँ के शिक्षित-जन का वह भाग, जो अपनी बोली को स्वतन्त्र भाषा मानता है, जातीय भाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार करे। जब तक साधारण जनता के सामने यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि हिन्दी प्रदेश की सीमाएँ कौन-सी हैं, उसमें कौन-सी बोलियों का चलन है, उन्हें अब स्वतन्त्र भाषा न मानना चाहिए, तब तक मसूचे देश में तथा अपने ही प्रदेश में हिन्दी को उसका उचित स्थान दिमाने के लिए यह विज्ञान जनता सज्जिय नहीं हो सकती। हिन्दी प्रचार का एक लक्ष्य होना चाहिए जातीय प्रदेश का गठन, उसमें सर्वत्र जातीय भाषा के रूप में हिन्दी का धमन।

जातीय भाषा और राष्ट्रभाषा में अन्तर है। महाराष्ट्र, बंगाल या तमिल-नाडु के लोगों की जातीय भाषा मराठी, बँगला या तमिल है, हिन्दी नहीं। हिन्दी इन लोगों की राष्ट्रभाषा है, जो पारस्परिक आदान प्रदान का माध्यम बनती है। हिन्दी भाषियों के लिए हिन्दी जातीय भाषा है जैसे महाराष्ट्र के लोगों के लिए मराठी जातीय भाषा है। जातीय भाषा होने के साथ-साथ हम हिन्दी-भाषियों के लिए हिन्दी राष्ट्रभाषा भी है। मिथिला के कुछ शिक्षित-जन हिन्दी को राष्ट्रभाषा तो मानते हैं किन्तु अपनी जातीय भाषा नहीं मानते। मराठी के समान वे बँगाली को हिन्दी से स्वतन्त्र भाषा मानते हैं।

अनेक अहिन्दी भाषी अंग्रेजी-श्रेणी विद्वान् इसी तर्क का आश्रय लेते हैं और कहते हैं कि हिन्दी अपने ही क्षेत्र में दूसरों पर सारी गई भाषा है। यह प्रचार

करते हैं कि ब्रज, अवधी, बुन्देलखण्डी, भोजपुरी आदि सब स्वतन्त्र भाषाएँ हैं जिन पर कृत्रिम साहित्यिक हिन्दी जबरदस्ती लादी गई है। ये लोग भूल जाते हैं कि इंग्लैण्ड, रूस, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में अंग्रेज़ी, रूसी, फ्रांसीसी, जर्मन आदि भाषाओं की वैसे ही बोलियाँ हैं जैसे हिन्दी की। इन सब भ्रान्तियों के निवारण के लिए हिन्दी-भाषी प्रदेश में हिन्दी-प्रचार आवश्यक है।

हिन्दी-उर्दू समस्या को अधिर्वात हिन्दी-प्रेमी मूल-से गए थे। रेडिया द्वारा हिन्दी के सरलीकरण ने उन्हें नौद से जगा दिया। भारतेन्दु से लेकर प्रेमचन्द तक हिन्दी के तमाम लेखक अपनी भाषा को बठिन बनाते रहे, जिससे जनता उनका साहित्य समझ न पाये, अब उस हिन्दी को सरल बनाने का बीड़ा उठाया है आकाशवाणी ने। यह सरलीकरण का प्रश्न उस समय उठाया गया जिस समय अंग्रेज़ी को अनिश्चित बाल के लिए राजभाषा घोषित किया गया। हिन्दी-उर्दू के मामले में फिर मैं जान डालकर राष्ट्रभाषा के रूप में अंग्रेज़ी को नवजीवन दिया गया।

हिन्दी के कुछ विद्वान् मानते हैं कि मुसलमानों की भाषा उर्दू है, जो हिन्दी से स्वतन्त्र है। बंगाल के मुसलमानों की बँगला से स्वतन्त्र कोई भाषा क्यों नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर वे नहीं देते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हमारे देश की श्रमिक जनता में कहीं भी धर्म के आधार पर भाषागत विभाजन नहीं दिखाई देता। बानपुर, ससनऊ, पटना आदि के हिन्दू-मुसलमान मजदूर आपस में एक ही सामान्य भाषा का व्यवहार करते हैं। जो लोग हिन्दुओं और मुसलमानों की दो भाषाएँ मानते हैं, जो हिन्दी और उर्दू को मूलतः दो भाषाएँ मानते हैं, उन्हें यह समझाना चाहिए कि भाषा की आधारभूमि कोटि कोटि श्रमिक जनता है, न कि मुट्ठी-भर पढ़े-लिखे लोग।

उर्दू प्रेमियों में इस बात का प्रचार करना आवश्यक है कि उनकी अलग कीम नहीं है, वे विशाल हिन्दी भाषी जाति का अंग हैं, प्रत्येक जाति की एक ही भाषा होती है दो नहीं, हिन्दी-उर्दू मूलतः एक ही भाषा हैं, इसलिए उनका साहित्यिक रूप दो न होकर एक ही होगा, हिन्दी-उर्दू के अलग-अलग से हमारी जातीय सत्कृति पूरी शक्ति से विकसित नहीं हो पाती। उर्दू-प्रेमी कबीर, जयसी, रसखान, रहीम आदि की साहित्यिक परम्परा से अपना सम्बन्ध जोड़ें, भारत की अन्य भाषाओं के विकास के अनुकूल उर्दू को मोड़ें, इससे तुरन्त नहीं किन्तु कुछ समय बाद हमारी सामान्य साहित्यिक परम्परा विकसित होगी। उर्दू-प्रेमियों के साथ इस तरह का प्रचार उन हिन्दी-प्रेमियों में भी करना आवश्यक है, जो हिन्दुओं और मुसलमानों को दो भिन्न जातियाँ मानते हैं।

हिन्दी भाषी जनता की शक्ति अपार है किन्तु वह असंगठित और बिसरी हुई है। हिन्दी-भाषियों के जातीय हित में इस शक्ति को संगठित करना आवश्यक है। समूचे राष्ट्र को एकताबद्ध और दृढ़ करने के लिए हिन्दी भाषी जाति की एकता आवश्यक है। इस एकता के मार्ग में पहली बाधा है अंग्रेज़ी प्रेम।

दूसरी भाषा है आधिकारिक बोलियों को स्वतन्त्र भाषा मानने की भ्रान्ति । तीसरी भाषा है हिन्दी-उर्दू प्रेमियों का दो सेगो में बँटकर जातीय सस्कृति को बमजोर करना । इन तीनों भाषाओं के फलस्वरूप अपनी जातीय शक्ति के उपयोग द्वारा हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के अपने उत्तरदायित्व को हम निबाह नहीं पाते ।

यदि ममस्त हिन्दी-भाषी प्रदेश में शिक्षा-संस्थाओं, न्यायालयों, राजकीय कार्यों में हर स्तर पर हिन्दी का व्यवहार होने लगे, यदि विधान-परिषदों के सदस्य प्रतिज्ञा करें कि वे अपना सार्वजनिक कार्य हिन्दी में ही करेंगे, यदि लोकसभा के सदस्य तय कर लें कि वे राजभाषा के रूप में हिन्दी का ही व्यवहार करेंगे तो क्या इसमें किसी को मन्देह हो सकता है कि समूचे राष्ट्र का वातावरण बदल जाएगा और हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनते खरा भी देर न लगेगी ?

हम हिन्दी-भाषी किसी पर हिन्दी लादना नहीं चाहते । जो अंग्रेजी ही बोलना पसन्द करे उससे जबरदस्ती हिन्दी बुलवाना नहीं चाहते । किन्तु हमें भी अंग्रेजी बोलने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता । लोकसभा और राज्य-सभा के वे सदस्य और मंत्री, जो हिन्दी-भाषी प्रदेश से चुने गए हैं, जिस दिन तय कर लें कि अंग्रेजी के बदले हिन्दी का ही प्रयोग करेंगे, उसी दिन हिन्दी व्यवहारतः राष्ट्रभाषा बन जाएगी । यदि ऐसा नहीं होता तो कमजोरी हमारी है । हमें हिन्दी प्रचार द्वारा स्वयं अपने प्रदेश की जनता को जाग्रत करना है, अपने प्रदेश के नेताओं में हिन्दी की उम्मेद दूर करनी है, स्वयं अपने प्रति-निधियों को बाध्य करना है कि वे राजकाज में और सर्वत्र हिन्दी का व्यवहार करें । इस तरह के प्रचार और संगठन द्वारा ही अपनी जातीय शक्ति के अनुरूप हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का अपना गहन उत्तरदायित्व पूरा कर सकते हैं ।

(१९६२)

सरकारी कोशकार और राष्ट्रभाषा

तीस से अधिक वर्ष हुए, जनवरी, १९३२ की 'मुष्ठा' में अंग्रेजी-हिन्दी कोश-सम्बन्धी एक टिप्पणी प्रकाशित हुई थी। टिप्पणी के अनुसार श्री मुखसम्पति-राय भण्डारी ने 'विद्वान् और विशेषज्ञों की सहायता से' लगभग बीस हजार रुपये खर्च करके प्रायः डेढ़ लाख शब्दों का यह कोश तैयार किया था जिसकी प्रशंसा प्रयाग विश्वविद्यालय के बाइस चासलर डॉ० गगनाथ झा, पंजाब विश्व-विद्यालय के बाइस चासलर डॉ० ए० सी० बृसनर, डॉ० राधाकृष्ण मुक्जी, डॉ० बेनीप्रसाद, डॉ० सुनीलकुमार चटर्जी आदि विद्वानों ने की थी और सर पी० सी० राय ने इसे 'महान् प्रशसनीय साहित्यिक कार्य' कहते हुए, बंगाली, मराठी और गुजराती भाषा-भाषियों के लिए भी अत्यन्त उपयोगी बतलाया था।

हिन्दी-भाषी विद्वान् इस बात की ओर बहुत पहले से सचेत रहे हैं कि हमारी भाषा आधुनिक विज्ञान तथा सस्कृति से सम्बन्धित विचारों को प्रकट करने में सक्षम हो। सरकार की सहायता के अभाव में, अक्सर प्रच्छन्न सरकारी विरोध का सामना करते हुए मुखसम्पतिराय भण्डारी जैसे विद्वानों ने ओर परिश्रम करके पारिभाषिक शब्दों की कमी को पूरा किया। नागरी-प्रचारिणी सभा जैसी संस्थाओं ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। डॉ० सत्यप्रकाश जैसे विद्वानों ने वैज्ञानिक विषयों पर लेख लिखकर और दूसरों से लिखाकर पारिभाषिक शब्दों के प्रचार में सहायता की। भारत के स्वाधीन होने पर जब अंग्रेजी को हटाने, भारतीय भाषाओं को उनका स्वत्व देने और परस्पर व्यवहार तथा केन्द्रीय राज-काज के लिए हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का सवाल सामने आया तब हिन्दी से नितान्त अनभिज्ञ, देवनागरी में बठिनाई से हस्ताक्षर कर पानेवाले देश के अनेक सम्मान्य राजनीतिज्ञों ने धीपित किया कि हिन्दी को विकसित होने, आधुनिक विचारों की अभिव्यक्ति के योग्य बनने के लिए अभी ओर समय देना चाहिए। संविधान में इस बात को दर्ज कर दिया गया कि हिन्दी को विकसित किया जाय और सस्कृत तथा अन्य भाषाओं से आवश्यकतानुसार शब्द लेकर (या नये शब्द गढ़कर) उसे समृद्ध किया जाय।

भारत सरकार ने १९५० में विज्ञान-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्द-संग्रह के लिए एक समिति स्थापित की। शिक्षा मन्त्रालय के तत्वावधान में हिन्दी को विकासमान और समृद्ध करने का बृहत् कार्य बारह साल तक चलता रहा और १९६२ में 'पारिभाषिक शब्द-संग्रह' नामक सरकारी कोश प्रकाशित हो गया।

भूमिका में सरकारी नीति स्पष्ट कर दी गई है। शिक्षा मन्त्रालय के तत्वावधान में दस वर्षों की अवधि में जितने पारिभाषिक शब्द रचे गए, उन्हें कोशबद्ध किया गया। अंग्रेजी में श्री धार० पी० नायक लिखित इस भूमिका में 'इबोल्व' और 'इवोल्यूशन' शब्दों का अनेक बार प्रयोग किया गया है। इन शब्दों का आशय यही है कि हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों का अभाव था, इसलिए शिक्षा मन्त्रालय द्वारा संचालित हिन्दी निदेशालय में नवीन शब्दावली रची गई। एक जगह यह स्पष्ट लिखा है कि १९६१ के मध्य तक विशेषज्ञ-समितियों की संख्या २६ हो गई थी और 'नव-निर्मित' शब्दों की संख्या लगभग तीन लाख तक पहुँच गई थी (द टर्म्स क्वायण्ड बेम टु नियरली थी लैक्स)। ये शब्द 'क्वायन' किये गए थे, हिन्दी में ये नहीं, उसे विकसित करने के लिए निदेशालय में ये तीन लाख शब्द डाले गए थे।

अधिकांश भारतीय राजनीतिज्ञों के लिए जीवन के अनेक स्वीकृत मूल्यों के समान हिन्दी की दरिद्रता भी स्वयंसिद्ध मूल्य है जिसे प्रमाणित करने के लिए किसी आयोग या समिति की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी की समृद्धि उसी प्रकार दूसरा ध्रुव सत्य है जिसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध है। इन दो ध्रुवों की धुरी पर भारतीय जनतन्त्र की राजनीति अनवरत घावर्तन करती है।

यदि इस सरकारी कोश के सभी या अधिकांश शब्द नये सिरे से गढ़े गए हों, तो वे हिन्दी-भाषी बुद्धिजीवियों के लिए अपरिचित होंगे, कोश के पन्ने पलटने पर ऐसा लगेगा कि हम शब्दों की नई दुनिया में आ गए हैं, जिनमें रूप और अर्थ से हमारा पहली बार साक्षात्कार हो रहा है। वैसे तो किसी अपारिभाषिक कोश में भी साधारण पाठकों को हजारों शब्द मिल जाएँगे जिनसे वे परिचित न होंगे। इसलिए पारिभाषिक कोश में अजनबी लगनेवाले शब्दों का होना प्राक्चर्यजनक नहीं है। प्राक्चर्यजनक बात यह है कि हर पृष्ठ पर अनेक ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिनसे साधारण पाठक अच्छी तरह परिचित है और जिन्हें नायक साहब के अनुसार 'क्वायन' किया गया है।

एक निगाह इन शब्दों पर डालिए वायुमण्डल, उपलब्धि, आक्रमण, ध्यान, प्रायश्चित्त, मन्त्रिमण्डल, नैतिक, उपहास, त्वचा, बुद्धि, आशय, अभिप्राय, सौन्दर्यशास्त्र, रसायन, विनिमय, द्रव्य, पदार्थ, विषयवस्तु, मनोविज्ञान, मनो-विश्लेषण, सापेक्ष, नीतिशास्त्र, पुरातत्त्व, प्रतियोगिता, धनत्व, प्रत्याख्यान, प्रत्यक्ष, परोक्ष, उद्योग, सक्रमण, आकर्षण, विकर्षण इत्यादि। इस तरह के हजारों शब्द इस कोश में हैं जो हिन्दी में वर्षों से प्रचलित हैं और जिनके लिए कोई यह दावा भी नहीं कर सकता कि उन्हें नये सिरे से गढ़ा गया है। इनके

लिए यह दावा भी नहीं किया जा सकता कि वे अन्य कोशों में नहीं हैं। किन्तु हिन्दी को समृद्ध करने, उसे राष्ट्रभाषा पद के योग्य बनाने के लिए शिक्षा मन्त्रालय और विशेषज्ञ समितियों ने जो धीरे परिश्रम किया, उसमें इस तरह के शब्दों का संग्रह भी शामिल है।

इनके अलावा इस कोश में हिन्दी के ऐसे हजारों अतिप्रचलित शब्द हैं जिन्हें साधारण बुद्धि के लोग पारिभाषिक स्वीकार ही न करेंगे। प्रचलित शब्द भी पारिभाषिक हों, इस पर आपत्ति नहीं है। प्रश्न दूसरा है। क्या ये शब्द गढ़े गए हैं? क्या ये पहले से हिन्दी में या हिन्दी कोशों में थे नहीं? बपूर, झलाप, डेरा, कमरा, खरीदारी, सही, शताब्दी, छतरा निश्चित, जादू टोना, जादूगर, छपाई, जुड़ाई, उपाय, रोप, घाट, माफी, क्षमा पुनर्विवाह प्रभावित, विनाश भ्रजवायन, सौंफ, सुपारी, उधार, मोरा, मदिरा, अदली, चपरासी, विराया रोजगार, कार्यालय, दफ्तर, मुठभेड़, तैरना, घाघुनिक् बेइयासय चक्का, हिलका, मामलै, छितराना, मरम्मत करना, प्रयत्न करना, छिपकाना, पर्याप्त, काम रोकना, दापध दिलाना, स्तन, साँस, से, परे, ठीक है, धर्म, छूट देना, छट्टी पाना, जरा हट के, गिर गया, ढोड़ते हुए, इस हालत में, इत्यादि। इस तरह के शब्दों को देखकर यह प्रस्ताव करने की इच्छा होती है कि कोश के द्वितीय संस्करण में खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, सोना, घरती, आकाश, पानी हवा, घूस, झालू, मटर, टमाटर, बैंगन, गाजर, मकान, छत, फस, दरवाजा, सिडकी, पिता, पुत्र, बहन, भाई, चाचा, ताऊ आदि-आदि शब्दों को भी पारिभाषिकों में गिन लेना चाहिए और भूमिका में आगले दस वर्षों के समृद्धीकरण-प्रोग्राम की सफलता के रूप में उन्हें पेश कर देना चाहिए। किन्तु सम्भव है, इनमें और इन जैसे अनेक शब्द इस कोश में पहुँचे न ही हों और मैंने उन पर ध्यान न दिया हो। जो भी हो, जब तक ये शब्द सरकारी कोश में दर्ज नहीं हुए, तब तक हिन्दी दरिद्र थी। दर्ज होने के बाद भी हिन्दी समृद्ध होकर राष्ट्रभाषा नहीं बनी—वह प्रदर्शन प्रलभ है।

यह कहा जा सकता है कि ऊपर बिना तरह के शब्दों का उल्लेख किया गया है, ये हिन्दी में थे उद्धर किन्तु अर्थ निश्चित नहीं था, पारिभाषिक शब्द संग्रह परमेश्वरों ने हिन्दी को यह मेधा दी है कि अस्थिर अर्थवाले शब्दों को अग्रणी पर्यायों के माध्यम निश्चित रूप में नष्ट कर दिया है। भूमिका में भारतीय कोशकारों के प्रयत्नों का उल्लेख करते हुए शब्दों के अरथ की चर्चा की गई है जहाँ ऐम्बो घोर ग्राह्य जनो को शरत्ता नहीं भूमता। किन्तु इस कोश के पन्ने पलटने पर यह समझने में निम्नी को देर न लगेगी कि यहाँ हजार अग्रणी शब्द ऐसे हैं जिनके एक में अधिक हिन्दी-पर्याय दिये गए हैं। उदाहरण के लिए, ग्याय क्षेत्र में ऐम्बोई शब्द के लिए—विनियोग करना, प्रयोग करना, लागू करना, आवेदन करना, प्रार्थनापत्र देना, जीव विज्ञान के अन्तर्गत 'लैरिक्म' के लिए—कण्ड, स्वरयन्त्र, लैरिक्म। 'डम्क' शब्द के आगे यह नहीं

लिखा कि वह किस क्षेत्र का पारिभाषिक शब्द है, किन्तु उसने तीन पर्याय दिये गए हैं—गोधूलि, घुरी (?), सौम। धर्मशास्त्र के प्रचलित शब्द 'मर्चेन्ट' के लिए—सौदागर, सार्यवाह, व्यापारी, बणिक्। प्रचलित शब्द 'रिलीव' के लिए—छुट्टी देना, छुट्टी पाना (!), छुट्टी मिलना (नौकरी ५), भारमुक्त करना, भवमुक्त करना। 'यूनिट' शब्द के आगे भी सचेत नहीं है कि वह किस क्षेत्र का पारिभाषिक है। उसके पर्याय—मानक, एकक, (इ) काई, दल, एकाग, एकाश, यूनिट, एकाक !

सरकारी बोश के सरक्षकगण स्वयं देख सकते हैं कि शब्दों की बहुलता कम नहीं हुई, उसमें कुछ हजाफा ही हुआ है। पाठक प्रश्न कर सकते हैं कि इस शब्द-संग्रह में गोधूलि, सौम, सौदागर जैसे शब्द ही हैं तो उनसे संग्रह के लिए इतना परिश्रम क्यों ? नहीं, सौम, गोधूलि और सौदागर तो सरकारी सस्पर्श से पारिभाषिक बन गए हैं। इनके अलावा ऐसे भी हजारों शब्द हैं जिन्हें देखते ही कोई कह देगा कि वे पारिभाषिक हैं। उदाहरण के लिए, ससक्ति, नम्यता, अविलेयता, गलनाक, वाष्पायन, ऊष्मा, सघनन, विकिरण, प्रच्छाया, उपच्छाया, परावर्तन, अवतल, उत्तल, प्रक्ष, प्रच्छाशय, अपचय, प्रस्र, क्षार, ग्रन्थु, परमाणु, चाप, समीकरण, समापकी, अवशेषण, द्रव, ज्वलनशील, भौतिकी, भौतिकी इत्यादि—ये सब शब्द आपको इस बोश में मिलेंगे। किन्तु आप यदि थोड़ा-सा परिश्रम करें तो आप देखेंगे कि ये शब्द विद्यालयों की उन पाठ्य-पुस्तकों में भी प्रयुक्त हुए हैं जो इस बोश निर्माण से पहले प्रकाशित हुई थीं। इन्हें 'इचीत्व' करने या 'नवायन' करने का दावा इस बोश के सम्पादक लोग नहीं कर सकते।

इस सरकारी बोश में ऐसे भी हजारों शब्द हैं जिन्हें तीस वर्ष पहले ही श्री मुखसम्पतिराय भण्डारी और उनके सहयोगियों ने 'नवायन' या 'इचीत्व' कर लिया था। इनमें ग्रन्थ, परमाणु, धूमकेतु, निरपेक्ष, अमूर्त, सूत्र, मताधिकार, निर्वाचन-क्षेत्र, राष्ट्रीयकरण, समाजवाद, लोकतन्त्र जैसे शब्द हैं। ऐसे शब्द साधारण हिन्दी गद्य में बराबर प्रयुक्त होते रहे हैं। इनके अतिरिक्त विज्ञान-सम्बन्धी शब्द भी हैं, जिनका व्यवहार वैज्ञानिक पुस्तकों में होता है। 'डिफरेंशल इक्वेशन'—अवकल समीकरण; 'डिफ्रैक्शन'—विवर्तन; 'आइसोमेरिज्म'—समावयवता; 'लेटरल'—गतिविक, 'वेन'—क्षिरा, 'वर्टीका'—कक्षरुका; 'थूटेरस'—गर्भाशय; 'लैरिक्स'—स्वर-यन्त्र, 'अपेण्डिक्स'—परिशिष्ट; 'कार्टिलेज'—उपास्थि; 'क्लैविकल'—प्रक्षक; 'कोर्टेक्स'—वल्क; 'डक्ट'—वाहिनी; 'कोन'—शकु; 'कौपंस कैलोसम'—महासंयोजक; 'रेडिएशन'—विकिरण; 'मैग्नेटिज्म'—चुम्बकत्व; 'लोमैरियम'—लघुगणक; 'कैल्कुलस'—कलन; 'हिप्नोटिज्म'—सम्मोहन; 'इनहिबिशन'—अवरोध; 'साइको-एनैलिसिस'—मनोविश्लेषण; 'एनालोजी'—सादृश्य; 'एल्ड्र'—इरम—परायवाद; 'ऐनाबोलिज्म'—चय; 'आक्स्टिज्म'—गुहाविद्या; 'स्प्लीन'—प्लीहा, 'डेंसिटी'—घनत्व इत्यादि।

इस तरह के हजारों शब्द भण्डारी-बोश और उनके तीस साल बाद के

लिए यह दावा भी नहीं किया जा सकता कि वे धन्य बोधो में नहीं हैं।
किन्तु हिन्दी को समृद्ध करने, उसे राष्ट्रभाषा-पद के योग्य बनाने के लिए शिक्षा
मन्त्रालय और विशेषज्ञ समितियों ने जो धोर परिश्रम किया, उसमें इस तरह
के शब्दों का सग्रह भी शामिल है।

इनके अलावा इस कोश में हिन्दी के ऐसे हजारों अतिप्रचलित शब्द हैं जिन्हें
साधारण बुद्धि के लोग पारिभाषिक स्वीकार ही न करेंगे। प्रचलित शब्द भी
पारिभाषिक हो, इस पर आपत्ति नहीं है। प्रश्न दूसरा है। क्या ये शब्द गढ़े गए
हैं? क्या ये पहले से हिंदी में या हिन्दी बोधो में थे नहीं? कपूर, अलाप, डेरा,
कमरा, खरीदारी, सद्दी अताब्दी, खतरा निश्चित, जादू टोना, जादूगर, छपाई,
जुड़ाई, उपाय, रोप याद, भाफी, अमा पुनर्विवाह प्रभावित, विनाश भजवायन,
सीफ, सुपारी, उधार, शोरा, मदिरा, अदली, अपरासी, विराया रोजगार, बार्शालय,
दपतर, मुठभेड, तैरना, छाधुनिक वेध्यालय चकला, दिलवा, मामले, दितराना,
मरम्मत करना, प्रयत्न करना, चिपकाना, पर्याप्त, काम रोकना, क्षपथ दिलाना,
स्तन, सांस, से, परे, ठीक है, धर्म, छूट देना, छट्टी पाना, खरा हट के, गिर गया,
दीडते हुए, इस हालत में, इत्यादि। इस तरह के शब्दों को देखकर यह प्रस्ताव
करने की इच्छा होती है कि कोश के द्वितीय संस्करण में खाना, पीना, उठना,
बैठना, चलना, सोना, धरती, आकाश, पानी हरा, धूल, भालू, मटर, टमाटर,
बैंगन, गाजर, मकान, छत, फर्श, दरवाजा, खिडकी, पिता, पुत्र, बहन, भाई,
चाचा, ताऊ आदि-आदि शब्दों को भी पारिभाषिकों में गिन लेना चाहिए और
भूमिका में अगले दस वर्षों के समृद्धीकरण-प्रोग्राम की सफलता के रूप में उन्हें
पेश कर देना चाहिए। किन्तु सम्भव है, इनमें और इन जैसे अनेक शब्द इस
कोश में पहले से ही हो और मैंने उन पर ध्यान न दिया हो। जो भी हो, जब
तक ये शब्द सरकारी कोश में दर्ज नहीं हुए, तब तक हिन्दी दरिद्र थी।
दर्ज होने के बाद भी हिन्दी समृद्ध होकर राष्ट्रभाषा नहीं बनी—वह प्रश्न
अलग है।

यह कहा जा सकता है कि ऊपर जिस तरह के शब्दों का उल्लेख किया गया
है, वे हिन्दी में थे जरूर किन्तु अर्थ निश्चित नहीं था, पारिभाषिक शब्द-संग्रह
करनेवालों ने हिन्दी की यह सेवा की है कि अस्थिर अर्थवाले शब्दों को अंग्रेजी
पर्यायों के साथ निश्चित ढंग से जोड़ कर दिया है। भूमिका में भारतीय कोश-
कारों के प्रयत्नों का उल्लेख करते हुए शब्दों के अरथ की चर्चा की गई है,
जहाँ लेखकों और साधारण जनों को रास्ता नहीं भूलता। किन्तु इस कोश
के पन्ने पलटने पर यह समझने में किसी को देर न लगेगी कि यहाँ हजारों
अंग्रेजी शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक हिन्दी पर्याय दिये गए हैं। उदाहरण
के लिए, न्याय क्षेत्र में 'ऐप्पाई' शब्द के लिए—विनियोग करना, प्रयोग करना,
लागू करना, आवेदन करना, प्रार्थनापत्र देना, जीव विज्ञान के अन्तर्गत
'लैरिक्स' के लिए—कण्ठ, स्वरयन्त्र, लैरिक्स। 'डस्क' शब्द के आगे यह नहीं

लिखा कि वह किस क्षेत्र का पारिभाषिक शब्द है, किन्तु उसके तीन पर्याय दिये गए हैं—गोधूलि, धुरी (?) , सॉम । अर्थशास्त्र के प्रचलित शब्द 'भवेन्ट' के लिए—सौदागर, सार्यबाह, व्यापारी, वणिक् । प्रचलित शब्द 'रिलीव' के लिए—छुट्टी देना, छुट्टी पाना (1), छुट्टी मिलना (नौकरी छ), भारमुक्त करना, प्रवमुक्त करना । 'यूनिट' शब्द के आगे भी सकेत नहीं है कि वह किस क्षेत्र का पारिभाषिक है । उसके पर्याय—मात्रक, एकक, (इ) काई, दल, एकाग्र, एकाश, यूनिट, एकाक ।

सरकारी कोश के सशक्तवर्ण स्वयं देख सकते हैं कि शब्दों की बहुलता कम नहीं हुई, उसमें कुछ इजाफा हो हुआ है । पाठक प्रश्न कर सकते हैं कि इस शब्द-संग्रह में गोधूलि, सॉम, सौदागर जैसे शब्द ही हैं तो उनके संग्रह के लिए इतना परिश्रम क्यों ? नहीं, सॉम, गोधूलि और सौदागर तो सरकारी सम्पर्क से पारिभाषिक बन गए हैं । इनके अभाव में ऐसे भी हजारों शब्द हैं जिन्हें देखते ही कोई कह देगा कि वे पारिभाषिक हैं । उदाहरण के लिए, सन्नति, नम्यता, अविलेयता, गलनाक, वाष्पायन, ऊष्मा, सघनन, विचित्रण, प्रच्छाया, उपच्छाया, परावर्तन, प्रवतल, उत्तल, घस, अण्डाकार, अपचय, अम्ल, क्षार, भ्रू, परमाणु, चाप, समीकरण, समायोज, अवलोकन, द्रव, ज्वलनशील, भौतिकी, भौतिकी इत्यादि—ये सब शब्द आपका इस कोश में मिलेंगे । किन्तु आप यदि थोड़ा-सा परिश्रम करें तो आप देखेंगे कि ये शब्द विद्यापियों की उन पाठ्य-पुस्तकों में भी प्रयुक्त हुए हैं जो इस कोश निर्माण से पहले प्रकाशित हुई थी ! इन्हें 'इबोत्व' करने या 'बवायन' करने का दावा इस कोश के सम्पादक लोग नहीं कर सकते ।

इस सरकारी कोश में ऐसे भी हजारों शब्द हैं जिन्हें तीस वर्ष पहले ही श्री सुखसम्पतिराय भण्डारी और उनके सहयोगियों ने 'बवायन' या 'इबोत्व' कर लिया था । इनमें भ्रू, परमाणु, धूमकेतु, निरपेक्ष, अमूर्त, सूत्र, मताधिकार, निर्वाचन-क्षेत्र, राष्ट्रीयकरण, समाजवाद, लोकतन्त्र जैसे शब्द हैं । ऐसे शब्द साधारण हिन्दी गद्य में बराबर प्रयुक्त होते रहे हैं । इनके अतिरिक्त विज्ञान-सम्बन्धी शब्द भी हैं, जिनका व्यवहार वैज्ञानिक पुस्तकों में होता है । 'डिफरेंशल इन्वेंशन'—अवनम समीकरण, 'डिफ्रैक्शन'—विवर्तन; 'आइसोमेरिज्म'—समाव-धरता, 'लेटरल'—गतिवृत्त; 'वेन'—सिरा, 'बर्टीका'—वक्षेरुका; 'यूटेरस'—गर्भाशय; 'नैरिक्स'—स्वर-मन्त्र, 'अपेण्डिक्स'—परिशिष्ट; 'कार्टिलेज'—उपास्थि; 'क्लैविकल'—अक्षक; 'कर्टेक्स'—वृत्त; 'डक्ट'—वाहिनी; 'कोन'—शुक्र; 'कौपंस कोलोसम'—महासंयोजक, 'रैडिएशन'—विकिरण; 'मैग्नेटिज्म'—चुम्बकत्व; 'लोगैरिथम'—लघुगणक; 'कैल्कुलस'—कलन; 'हिप्नोटिज्म'—सम्मोहन; 'इनहिबिशन'—प्ररोध; 'साइको एनैलिसिस'—मनोविश्लेषण; 'एनालोजी'—सादृश्य; 'ऐल्ड्र-इज्म'—परायणवाद; 'एनाबोलिज्म'—वृद्धि; 'प्रोक्टिटिज्म'—गुहाविद्या; 'स्प्लीन'—प्लीहा, 'डेंसिटी'—घनत्व इत्यादि ।

इस तरह के हजारों शब्द भण्डारी-कोश और उसके तीस साल बाद के

सरकारी कोश में ज्यो-जे-त्यो विद्यमान हैं। इनके निवा ऐसे भी संवहो दण्ड हैं जिनमें सरकारी कोश में नाममात्र का परिवर्तन किया है। 'ढायतेदान' के लिए भण्डारी के 'विस्तारन' को यहाँ 'विस्तारण' कर दिया गया है, 'न' का 'ण' ! अथवा 'सिस्टोल' के लिए भण्डारी-श्रुत 'भानुवन' सरकारी कोश में 'प्रकुवन' हो गया। 'थोरेंसिक्' के लिए भण्डारी ने लिखा 'वडा-साम्बन्धी'; सरकारी कोश में उसे 'वक्षीय' कर दिया गया। 'माइसोटोप' के लिए भण्डारी ने लिखा 'समस्थानीय', सरकारी कोश में उसे किया 'समस्थानिक'।

इस सरकारी कोश के सम्पादकों-सरक्षकों से यह पूछना अनुचित न होगा कि धालिर के शब्द कौन-से हैं जिन्हें दस साल में आप लोगो ने 'हबोन्व' किया है, या 'क्वायन' किया है, जिनके प्रभाव में हिन्दी राष्ट्रभाषा न बन सकती थी, दरिद्र थी, माधुनिक जीवन से सम्बन्धित विचारों को प्रगट करने में अक्षम थी ? प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी को सरकार और उसके मुलाजिमों से यह प्रश्न करना चाहिए कि दस साल से लगातार हिन्दी के जिन प्रभावों की आप घोषणा कर रहे थे, वे कौन-से हैं, जिन शब्दों की रचना करके आपने उन प्रभावों की पूर्ति की है ? अपार धन व्यय करके आपने जिस कोश की रचना की है, स्पष्ट बताइए कि इसमें कितने शब्द ऐसे हैं जो हिन्दी में पहले से विद्यमान न थे ?

मेरा अनुमान है कि कोश में नये गढ़े हुए शब्दों को बहुत परिश्रम से ढूँढ़ निकाला जाय तो छपने पर वे पन्द्रह-बीस पृष्ठों से ज्यादा जगह न घेरेंगे। यह बात सही हो तो सरकार ने फी सान केवल डेढ़ या दो पृष्ठों की नवीन सामग्री प्रस्तुत की।

यदि किसी को विश्वास हो कि नवनिर्मित शब्दों की संख्या पन्द्रह-बीस पृष्ठों से अधिक परिमाण की होगी, तो उससे प्रार्थना है कि वह ऐम शब्दों का सयह कर डाले, उसे प्रकाशित कर दे, यह हिन्दी की बहुत बड़ी सेवा होगी, एकदम वैज्ञानिक ढंग से पता चल जाएगा कि हिन्दी की भाषागत समृद्धि में ठीक-ठीक कितने शब्दों का इजाफा किया गया है।

इस कोश निर्माण के लिए आई० सी० एस० आफिसर, शिक्षा मन्त्रालय के स्पेशल आफिसर भॉन ड्यूटी, मद्रास, मसूर, बेंगलोर, पूना, बलकत्ता, बम्बई, दिल्ली से निगट और दूर के, नगरो से बीसियों विधेपजो का पचासो धार धावा-गमन, उनके टी० ए० बिल, दिल्ली में ठहरने का भत्ता, एक स्थायी कार्यालय और उसके कर्मचारी—आप हिसाब लगाएँ, फी शब्द सो टके से कम नहीं पडा। पहले तीन लाख शब्द गढ़े या इकट्ठे किये गए। उनमें बहुत-से शब्द दुहराये-तिहराये गए थे। मनोविज्ञान के शब्द दर्शन में भी आ गए और भौतिकी के शब्द रसायन में। इन फालतू शब्दों की छँटाई के बाद इस कोश में एक लाख से कुछ ऊपर शब्द बच रहे हैं। कोश पर करोड़ों रुपये खर्च हुए। इतना धन व्यय करने के बाद भी पता नहीं चलता कि नवनिर्मित शब्द दरमसल कितने हैं। शिक्षा मन्त्रालय के उच्च अधिकारियों ने सम्भवत कोश को पन्ने पलट-

कर देता भी नहीं है। सरना श्री भार० पी० नायक तीन लाख 'नये शब्द गढ़ने' की बात न लिखते। बोध में प्रकाशित एक अन्य अंग्रेजी लेख में उन सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है जिनके अनुसार शब्द-संग्रह का कार्य सम्पादित किया गया है। इस लेख में बताया गया है कि सम्पादकों ने हिन्दी में पहले से प्रचलित शब्द-राशि से काम उठाया है। इस लेख में लाखों नये शब्द गढ़ने का दावा नहीं किया गया। इसमें प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय साहित्य से शब्द लेने की बात भी बड़ी गई है। सरकारी भूमिका में नये शब्द गढ़कर हिन्दी की दरिद्रता दूर करने का जो दावा किया गया है, वह इस लेख की बातों से बट जाता है।

इस लेख में शब्दों के अर्थ निश्चित करने के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, जो सत्य हैं। जिन प्राचीन शब्दों को खोज निकालने का दावा किया गया है, उनमें 'कैलकुलस' का पर्याय 'बलन' भी है। यह शब्द अण्डारीजी के कोश में विद्यमान है। इसी तरह 'होट' के लिए 'ऊष्मा' को निश्चित करने की जो बात कही गई है, वह सही नहीं है। भौतिकी-पुस्तकों में 'होट' के लिए ऊष्मा का प्रयोग काफ़ी पहले से होने लगा था। कोश में कुछ प्रचलित शब्दों को छोड़कर नये शब्द गढ़े गए हैं। यह गड़बड़ अक्सर भोली हो गई है। 'नर्व' के पर्याय-रूप में 'स्नायु' हिन्दी का प्रचलित शब्द था। उसे हटाकर 'तन्त्रिका' शब्द स्थापित किया गया है। 'स्नायु-तन्त्र' सुनने में अच्छा लगता है। उसने बदले इस कोश के अनुसार 'तन्त्रिका-तन्त्र' का जन्म होना चाहिए। 'डिप्लोमैसी' के लिए हिन्दी में 'कूटनीति' शब्द प्रचलित है। इन कारणों से उसने लिए नया शब्द दिया है—'राजनय'। 'अग्नीष्टीतिरम' का पर्याय दिया गया है 'अग्नीश्वरवाद,' जो असत्य है। इसके विपरीत अण्डारीजी ने कोश में सही शब्द दिया गया है—'अश्ववाद'। 'स्पेस' या 'आउटर स्पेस' का समानार्थी हमारा प्राचीन शब्द है 'अन्तरिक्ष'। उसे कोश में जगह नहीं मिली। 'नेशनैलिटी' का समानार्थी प्रचलित शब्द है—'जाति'। सरकारी कोश ने भोली गड़बड़ की है—'राष्ट्रवत्ता'।

एक विचित्र बात यह है कि एक ही शब्द से सम्बन्धित शब्द-समूह में पर्यायों की यथेष्ट भिन्नता दिखाई देगी। 'स्पेस टाइम' के लिए 'दिक् काल' किन्तु 'स्पेस टाइम नर्व' के लिए 'अवकाश समय बन्ध'। ऐसे भी सैकड़ों शब्द हैं जो कोश में नहीं आए—जथा 'एरजॉन्टेशन,' 'पैन्थीइजम,' 'ईस्थेसिया,' 'कोस्मोनॉट,' 'अनरल स्ट्राइक' इत्यादि।

ज्यादा अच्छा होता कि सरकार ज्ञान विज्ञान के समस्त क्षेत्रों में हिन्दी का समुद्ध करने का ठेका न लेती। वह शासन-व्यवस्था, न्याय, व्यापार आदि उन क्षेत्रों के शब्दों का ही संग्रह कराती जिससे उसे प्राप्त दिग्गज साबित पड़ता है। आखिर लोकसभा के सदस्य या मन्त्रीगण अपनी राजनीतिक हैसियत से भौतिकी, रसायन या जीवविज्ञान पर तो अन्य रचेंगे नहीं। हिन्दी की केन्द्रीय राजकाज की भाषा बनाने के लिए देखना यह चाहिए था कि उसमें राजकाज के शब्द हैं

या नहीं। यह सीधा-सादा छह महीने में खत्म होनेवाला काम न करके सरकार ने दो पचवर्षीय योजनाओं का समय लगा दिया, समस्त विषयों के इस शब्द-संग्रह में।

शब्द-संग्रह तैयार हो गया। धन, समय और शक्ति के अभाव में बावजूद यह लाख से ऊपर शब्दों का संग्रह प्रस्तुत है। भारत के डेढ़ फी सदी अंग्रेजीदाँ बुद्धिजीवी जो पहले अंग्रेजी में सोचते हैं, फिर अपने सोचने का फल किसी भारतीय भाषा में प्रकट करते हैं, इस कोश की सहायता से हिन्दी में अब अपने प्रमूल्य विचार प्रकट कर सकते हैं। क्या अब केन्द्रीय राजकाज अंग्रेजी के बदले हिन्दी में होने लगा है? नहीं, इसके विपरीत अनिश्चित काल के लिए अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा घोषित कर दी गई है।

दो निष्कर्ष स्पष्ट हैं—

(१) हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों के अभाव की बात राजनीतिकों का झूठा प्रचार है। सरकारी शब्द संग्रह के ६६ फी सदी शब्द हिन्दी पुस्तकों और कोश में पहले से विद्यमान हैं।

(२) कोश निर्माण द्वारा हिन्दी को समृद्ध करने, उग राजभाषा पद के योग्य बनाने की सारी प्रक्रिया एक राजनीतिक चाल है, जिसका उद्देश्य है हिन्दी भाषियों तथा समस्त राष्ट्रभाषा-प्रेमियों की घाँखों में धूल भोजना।

राष्ट्रीयता और जनतन्त्र का आधार सङ्कुचित करके अंग्रेजी पढ़े लिखे मुट्ठी-भर लोग जो भारत के शासन-तन्त्र का सवालन कर रहे हैं, अपना निहित स्वार्थ छोड़ने को तैयार नहीं हैं। उनकी धारणा है कि अंग्रेजी के बिदा होने पर उन्हें भी भारतीय रगमच से बिदा लेनी होगी। हिन्दी-भाषी तथा समस्त भारतीय जनता का हित इसी में है कि अंग्रेजीदाँ नौकरशाहों का यह वर्ग जल्दी-से-जल्दी शासन-तन्त्र से दूर हो, तभी देश की समस्त भाषाएँ जनता की सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति का साधन बनेंगी और भारत अपनी प्रभुसत्ता को पूरी तरह खरितार्थ करेगा।

(१९६१)

वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम का मसौदा (भाषा-सम्बन्धी नीति की प्रालोचना)

वामपंथियों के कार्यक्रम के मसौदे में भारतीय भाषाओं की समानता के बारे में बहुत-सी और बहुत अच्छी-अच्छी बातें बही गई हैं। लेकिन वहाँ यह नहीं बताया गया कि भारत की सभी भाषाओं पर अपना प्राधिपत्य जमाये हुए जो अंग्रेजी बंटी हुई है, उससे बारे में वामपंथी कम्युनिस्ट क्या करने जा रहे हैं। मसौदे में यह सराहनीय बात कही गई है कि विभिन्न राज्यों तथा वहाँ की जनता के बीच भाषिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देकर भविष्य में वाम होनेवाली जनता की जनवादी सरकार भारत की एकता को दृढ़ करेगी। यह एकाता दृढ़ करने का काम अंग्रेजी के द्वारा होगा या किसी भारतीय भाषा के द्वारा ?

जहाँ तक हिन्दी का सम्बन्ध है, मसौदे में कहा गया है कि अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी का व्यवहार अनिवार्य न होगा लेकिन विभिन्न राज्यों की सरकारों के बीच सम्पर्क भाषा बनने के लिए हिन्दी को प्रोत्साहन दिया जायगा।

हिन्दी का व्यवहार अनिवार्य न होगा। बहुत अच्छी बात है क्योंकि हिन्दी के व्यवहार को अनिवार्य बनाना जनतन्त्र-विरोधी कार्य होगा। लेकिन अंग्रेजी को हटाना अनिवार्य क्यों न कर दिया जाय ? मातृभाषाओं के व्यवहार पर सही जोर, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी के व्यवहार को लेकर आगा-पीछा—ऐसा क्यों ? जनता की जनवादी सरकार हिन्दी के व्यवहार को प्रोत्साहन देगी। मानो विभिन्न प्रदेशों की जनता ने अभी तक परस्पर आदान-प्रदान की आवश्यकता का अनुभव ही न किया हो। मानो वह अभी तक राह देख रही हो कि जनता की जनवादी सरकार बन जाय, तब वह आपसी सम्पर्क का काम शुरू करे। और विभिन्न राज्यों की सरकारों के हों परस्पर सम्पर्क के लिए हिन्दी को प्रोत्साहन क्यों दिया जायगा ? क्या अन्तर्प्रदेशिक सम्पर्क की आवश्यकता केवल सरकारों को पड़ती है ? जनता की जनवादी सरकार कायम होने पर जनता को इस सम्पर्क की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं ? भारत की

सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक एकता दृढ़ करने में जनता का भी कुछ हिस्सा होगा या नहीं ?

जनता के बाएँ और साम्राज्यवाद के दाएँ—वामपंथी मसौदे का सारतत्व यही है। जोरो से हिन्दी की अस्वीकृति और अंग्रेजी की स्वीकृति, भाज के लिए भी और बल के लिए भी—यह है मसौदे की नीति। सत्रह साल से कांग्रेस जिस नीति पर चन्तती आई है, उससे इस वामपंथी नीति में कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देता।

साम्राज्यवादी अंग्रेजी के प्रसार और शिक्षण पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। भारत के सबसे बड़े 'राष्ट्रीय' अखबार अंग्रेजी में निकलते हैं और उनके मालिक बड़े पूंजीपति हैं। इनमें अहिन्दी और हिन्दी दोनों तरह के पूंजीपति हैं। मध्यवर्ग के पढ़े-लिखे लोग नौकरशाही मशीन चलाते हैं और उन्हीं में से भारत की राजनीतिक पार्टियों के नेता भी बनते हैं। इन पार्टियों का राजनीतिक काम अंग्रेजी में होता है। इनमें से अनेक पार्टियाँ चाहती हैं कि अंग्रेजी जाय लेकिन वे अपना अन्तर्प्रदेशिक वाम करती हैं अंग्रेजी में सरकार से यह कहना कि यह करो, वह करो, तब तक बिलकुल फिजूल है जब तक राजनीतिक पार्टियाँ अखिल भारतीय कामों के लिए अंग्रेजी का सहारा सेना नहीं छोड़ती। वामपंथी कार्यक्रम के मसौदे में कहा गया है कि पार्लियामेंट के सदस्य अपनी-अपनी भाषा में बोल सकेंगे और भाषणों के सभी भाषाओं में अनुवादित होने की व्यवस्था होगी। वामपंथी कम्युनिस्ट अपनी पार्टी कांग्रेस में इस प्रस्ताव पर झगड़ करके खुद अपने अन्दर अंग्रेजी का व्यवहार खत्म क्यों नहीं कर देते ? भारतीय जनता के किसी भी हिस्से को अंग्रेजी के कायम रहने से लाभ नहीं है। श्रमिक आन्दोलन में विभिन्न जातियों के मजदूर परस्पर सम्पर्क के लिए हिन्दी का व्यवहार करते हैं।

भाज भारतीय जीवन में मुख्य अन्तर्विरोध हिन्दी और अहिन्दी भाषाओं में नहीं, अंग्रेजी तथा समस्त भारतीय भाषाओं में है। हिन्दी-अहिन्दी भाषाओं में जो भी अन्तर्विरोध हो, उसे गीण मानकर पहले मुख्य अन्तर्विरोध को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। बड़े समाचारपत्रों की भाषा अंग्रेजी, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में अंग्रेजी, विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी, विज्ञान-सम्बन्धी प्रकाशन के लिए अंग्रेजी, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर केन्द्रीय सरकार की व्यवहार-भाषा अंग्रेजी, राज्यों में सरकारी भाषा अंग्रेजी। अब बताइए, अहिन्दी जातियों की प्रगति के लिए खतरा हिन्दी साम्राज्यवाद से है या अंग्रेजी साम्राज्यवाद से ?

अहिन्दी जातियों के अधिकारों के लिए लड़ना और इस बात को भूल जाना कि अंग्रेजी सब पर हावी है, इस नीति का एक ही कारण है—भलगाव की भावना। आप प्रादेशिक स्तर पर जातियों के गठन की माँग करते हैं, उनकी भाषाओं के लिए समस्त अधिकारों की माँग करते हैं। लेकिन अखिल भारतीय

स्तर पर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए आप किसी भारतीय भाषा के लिए अधिकार नहीं मांगते। आप सहारा लेते हैं अंग्रेजी का जिसका मतलब है डेढ़ फी सदी भारतवासियों की एकता को सुदृढ़ करना। इसका मतलब है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को अखिल भारतीय धारा से तटस्थ हो जाना। आप इस विकास को अंग्रेजी तक सीमित कर देते हैं। आप अपने प्रदेश की ही भाषा और संस्कृति के विकास की बात सोचते हैं। यही है अलगवाव की भावना। अंग्रेजी का सूत्र बहुत कमजोर है और जरा से मटके से टूट सकता है। आपके लिए मजबूत सूत्र है प्रादेशिक भाषा जो आपको प्रदेश से बांधती है। लेकिन दूसरे प्रदेशों से जो आपको बांधे वह सूत्र कौन-सा है? तब क्या आश्चर्य कि ब्रिटिश बळगम अलग तमिल राज्य बनाने की मांग करता रहा है, नागा जनो के लिए फिजो महाशय अलग राज्य चाहते हैं, शेख अब्दुल्ला कश्मीर के लिए आरमनिर्णय का अधिकार चाहते हैं। राजाजी, फील्ड-मार्शल क्रयूब खाँ, चाऊ-एन-लाई और अंग्रेजी-भाषी जनबन्धों के ब्रिटिश अमरीकी नेता सभी आरमनिर्णय के अधिकार का समर्थन करते हैं।

भारत की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में अलगवाव से केवल साम्राज्यवाद का हित होता है। इसीलिए राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना सभी देश-प्रेमियों का सर्वोपरि कर्तव्य है।

आरमनिर्णय की मांग सार्थक तब होती है जब साम्राज्यवाद के विरुद्ध सघर्ष करती हुई जनता अपनी स्वाधीनता के लिए आरमनिर्णय की मांग करे। जारगाही रुस में यह मांग सार्थक थी क्योंकि रुसी पूँजीपति गैर-रुसी जातियों का उत्पीड़न करते थे। भारत में यह मांग निरर्थक है। जो लोग शेख अब्दुल्ला को मोरसाहन देते हैं या जमकर उमका विरोध नहीं करते, वे देश के प्रति विश्वासघात कर रहे हैं।

अंग्रेजी के कायम रहने से प्रादेशिक भाषाओं को ही नुकसान होता है। फिर किसी भी प्रदेश की भाषा और संस्कृति का विकास अलगवाव की हालत में नहीं हुआ। प्रत्येक भाषा में उसके साहित्य की विषयवस्तु का आधार है देशभक्ति, न कि अलगवाव-वादी प्रादेशिकता। इसलिए अपने प्रदेश और उसकी भाषा पर ही जोर देना और राष्ट्रीय एकता की बात मूल जाना हानिकार है।

वामपंथी कम्युनिस्ट राष्ट्र के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। मसौदे में कहा गया है कि छुटपुट सघर्ष बढ़ते-बढ़ते राष्ट्रीय (नेशनल) विद्रोह का रूप लेते, मसौदे में राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे आदि का उल्लेख है। इस राष्ट्र की एकता अंग्रेजी से दृढ़ नहीं हो सकती।

वामपंथी मसौदे में यह मांग की गई है कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी की जाय। राज्य का गठन इस बात को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि जनता के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में सुविधा हो। हर भाषा की लेकर केवल राज्य के लिए राज्य बनाना बचकानापन है।

“यह सम्राटो द्वारा शासित द्वीप”

यह मध्य प्रदेश, यह धरती, यह राज्य, यह इग्लड,

यह महाराजाधो का गर्भस्थल, यह उनवी धरित्री,

उनके जन्म लेने से प्रसिद्ध, उनके वक्ष के कारण शत्रु में भय उत्पन्न करने वाला ।’

फिर कोई भारतीय कवि किसी गुप्त-सम्राट् की प्रशस्ति के गीत क्यों गाये ? किन्तु महाभारत के कवि ने भारतवर्ष की प्रशस्ति लिखी है, राजाधो और सम्राटो की नहीं । राजाधो और सम्राटो के लिए लिखा है कि वे भूमि के लिए वैसे ही लड़ते हैं जैसे मास के लिए कुत्ते ।

देवमानुषकायानां काम भूमि परापणम् ।
अन्योन्यस्यावलुम्पन्ति सारमेया ययामिपम् ॥
राजानो भक्ष्यश्रेष्ठ भोक्तुकामा वसुधराम् ।
न चापि तृप्ति कामाना विद्यतेऽद्यापि कस्मचित् ॥
तस्मात् परिग्रहे भूमेर्यतन्ते कुरुपाण्डवा ।
साम्ना भेदेन दानेन दण्डेनैव च भारत ॥
पिता भ्राता च पुत्राश्च स्व शौश्व नरपुंगव ।
भूमिर्भवति भूताना सम्यगच्छिद्रदशना ॥

(देव-शरीरधारी प्राणियों के लिए और मानव-शरीरधारी जीवों के लिए मधेष्ट फल देनेवाली यह भूमि उनका परम आश्रय होती है । जैसे कुत्ते मास के टुकड़े के लिए परस्पर लड़ते और एक दूसरे को नोचते हैं, उसी प्रकार राजा लोग इस वसुधा को भोगने की इच्छा रखकर घापस में लड़ते और लूटमार करते हैं किन्तु भोज तक किसी को अपनी कामनाओं से तृप्ति नहीं हुई । इस अतृप्ति के ही कारण कौरव और पाण्डव साम, दाम, भेद और दण्ड के द्वारा सम्पूर्ण वसुधा पर अधिकार करने के लिए यत्न करते हैं । यदि भूमि के यथार्थ स्वरूप का सम्पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाय तो वह परमात्मा से अभिन्न होने के कारण प्राणियों के लिए पिता, भ्राता, पुत्र, भ्राताश्वर्त्ता पुण्यलोक तथा स्वर्ग भी बन जाती है ।)

यूरोप के प्राचीन साहित्य में इस मानवतावाद का जबाब नहीं है । शेक्सपियर की राष्ट्रीय गौरव-भावना से यह धरती-प्रेम बहुत ऊँचा है । इसलिए भारतवर्ष की प्रशस्ति सम्राटो की वन्दना नहीं, भारत-भूमि और उसकी जनता की वन्दना है वह हमारी प्राचीन राष्ट्रीय भावना की चोतक है । ‘रामायण’, ‘मेघदूत’ और ‘कुमारसम्भव’ में इसी प्रकार राष्ट्रीय चेतना के दर्शन होते हैं ।

माक्सवाद के अनुसार जातियाँ (नेशन) पूँजीवादी युग की देन हैं । लेकिन पूँजीवाद है क्या ? पूँजीवाद उत्पादन की एक पद्धति है । तब क्या शेक्सपियर के समय में उत्पादन की पद्धति बदल चुकी थी ? यदि हाँ, तो पगार पानेवाला सर्व-

द्वारा वर्ग नहीं था ? १८४४ में एंगेल्स ने अपने समय के इंग्लैंड के बारे में— 'इंग्लैंड के मजदूर-वर्ग की दशा' नामक पुस्तक में—लिखा था, "इंग्लैंड के सर्वहारावर्ग का इतिहास पिछली शताब्दी के उत्तरार्द्ध से आरम्भ होता है।" अठारहवीं सदी से पहले इंग्लैंड में सर्वहारा-वर्ग नहीं था। उत्पादन की पद्धति में कोई बुनियादी परिवर्तन न हुआ था। जुलाहे खेती भी करते थे। धरती से उनका सम्बन्ध टूटा न था। वे घुमन्तू सौदागरो को अपना माल बेचते थे। लेकिन वे अभी बाजार में अपनी श्रमशक्ति बेचने को बाध्य न थे। यदि पूँजीवाद केवल उत्पादन की पद्धति है, तो सोलहवीं सत्रहवीं सदी के अंग्रेज जाति के रूप में संगठित न हो सकते थे। लेकिन मिल्टन ने १६४४ ई० में क्रोमवेल की विजय के बाद लिखा था, "मुझे अपने मनोबल में दिखाई दे रहा है कि एक शक्तिशाली जाति (नेशन) नौद सउठे हुए मजदूर मानव के समान अपने बेश भटक रही है।"

हम में पूँजीवादी उत्पादन उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में आरम्भ हुआ, किन्तु लैनिन के अनुसार रूसी जाति का निर्माण सत्रहवीं सदी में हुआ। लैनिन ने रूस के सामाजिक विकास का विश्लेषण करके दिखाया था कि व्यापारियों ने रूस में एक देशव्यापी बाजार कायम किया था। यह समझना चाहिए कि पूँजीवाद केवल उत्पादन की पद्धति नहीं, वितरण की पद्धति भी है। मार्क्सवादी भारतीय इतिहास का नव तक सही तौर से न समझ सकेंगे जब तक वे सामाजिक विकास में वितरण की भूमिका का महत्व स्वीकार न करेंगे।

एंगेल्स ने एण्टी ड्यूयिंग में लिखा था कि उत्पादन और विनिमय अर्थात्तन्त्र की दो धुरी हैं दोनों के नियम बहुत-कुछ स्वतन्त्र हैं और वे दोनों एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। एंगेल्स ने इस बात पर जोर दिया था कि प्रत्येक समाज-व्यवस्था का आधार उत्पादन और वितरण दोनों हैं। पूँजी के तीमरे खण्ड में मार्क्स (अथवा एंगेल्स) ने बताया था कि औद्योगिक पूँजी का निर्माण तभी होता है जब उससे पहले सौदागरी पूँजी का निर्माण हो चुका हो। मार्क्स ने लिखा था कि सोलहवीं सत्रहवीं सदी में सौदागरी पूँजीवाद के विकास के साथ भारी क्रान्तियाँ हुईं और सामन्ती उत्पादन से पूँजीवादी उत्पादन के बीच सन्नमन की यह सबसे महत्वपूर्ण ऋद्धि थी। मार्क्स ने लिखा था, व्यापार में क्रान्ति होने से विश्व-बाजार कायम हुआ। आश्चर्य की बात होगी, विश्व-बाजार तो कायम हो जाय, जातीय बाजार (नेशनल मार्केट) कायम न हो।

सोलहवीं-सत्रहवीं सदियों में भारत विश्व-बाजार का बहुत महत्वपूर्ण अंग था। हमारे यहाँ यूरोप का माल बिकन आता था, यहाँ का माल वहाँ बिकने जाता था। एडम स्मिथ ने लिखा था कि उन दिनों यूरोप का मुख्य व्यापार यह था कि पश्चिमी देश अपनी घनगढ़ चीजें देकर अधिक सम्य देशों का बढ़िया माल लाते थे। आश्चर्य की बात होगी यदि असम्य देशों में तो राष्ट्रीय या जातीय चेतना फैल गई हो और सम्य देशों में उसका अभाव रहा हो।

मार्क्स ने लिखा था कि “प्राचीन काल की व्यापारी जातियाँ ऐपीक्यूरस के देवताओं की तरह ब्रह्माण्ड के मध्यलोक में रहती थीं। अथवा यों कहें जैसे पोलैंड में समाज में यहूदी भीतर पैठ गए थे।” मार्क्स ने व्यापारी जातियों (ट्रेडिंग नेशन्स) का उल्लेख किया है। इसका अर्थ यह है कि व्यापारी पूँजीवाद का विकास सोलहवीं सत्रहवीं सदी से पहले प्राचीन काल में भी हुआ था। जातियों का उद्भव आधुनिक पूँजीवाद के जन्म से बहुत पहले हो चुका था। ‘अर्थशास्त्र की आलोचना’ नामक ग्रन्थ में मार्क्स ने प्राचीन काल की जातियों की चर्चा की थी। उन्होंने लिखा था कि प्राचीन काल की व्यापारी जातियों में धन (मनी) की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

गुप्त-युग में भारत के जनपदों में परस्पर आर्थिक विनिमय बढ़ा, उस समय के व्यापारी भारतवर्ष से बाहर निकलकर दक्षिण पूर्वी एशिया और यूरोप तक अपना व्यापार करते रहे। जनपदों में परस्पर सांस्कृतिक सम्पर्क बढ़ा, संस्कृत द्वारा वे एक-दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते रहे। तब क्या आश्चर्य कि भारतवर्ष में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ और महाभारत में उसे अभिव्यक्ति मिली ?

प्राचीन यूनान का उदाहरण लीजिए। यह देश छोटे-छोटे राज्यों (जनपदों) में बँटा हुआ था। एथेन्स के लोगों में बड़े-बड़े व्यापारी थे। इन्होंने यूनानी लोगों में राष्ट्रीय चेतना उभारने में बड़ा योगदान दिया। यूनान के प्राचीन नाटकों—विशेषकर ईरानियों से सम्बन्धित ईस्किलस के नाटक में—यह चेतना उभरकर आई है। एथेन्स का नेता पेरिक्लीज अपने नगर को हेलास (यूनान) का शिक्षक कहता था। प्रसिद्ध इतिहासकार थ्यूसीडाइडीज ने पेलोपनीसस के युद्ध पर अपने ग्रन्थ में बारम्बार राष्ट्रीय भावना का उल्लेख किया है। ग्रन्थ के दूसरे खण्ड के छठे अध्याय में उसने लिखा है, “पेलोपनीसस और एथेन्स दोनों में ऐसे नौजवान भरे हुए थे जो भावहीनता के कारण हथियार उठाने को बड़े उत्साह से थे। बाकी हेलास अपने प्रमुख नगरों के सधर्म को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था।” यहाँ पेलोपनीसस और एथेन्स को एक ही राष्ट्र हेलास का अंग माना गया है। ये दोनों राज्य हैं, परस्पर स्वतन्त्र हैं, फिर भी जनता की चेतना में—विनिमय की बढ़ती के कारण और अन्य महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तत्त्वों के कारण—वे अपने से बड़ी इकाई के भाग हैं। लैंकेडिमोन (पेलोपनीसस) का राजदूत मेलेसिप्पस पेरिक्लीज से मिलने की अनुमति न पाकर कहता है, “यह दिन हेलास के महादुर्भाग्य के आरम्भ का दिन है।” ईसा से चार सौ साल पहले यूनान में यह राष्ट्रीय चेतना फैल सकती थी तो क्या ईसा से चार सौ साल बाद भारत में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार असम्भव माना जाएगा ?

बहस करनेवाले कह सकते हैं कि प्राचीन यूनानियों में राष्ट्रीय चेतना इसलिए फैली कि उन्हें ईरानियों से मुकाबला करना था। ऐसा ही सही। तब

प्राचीन भारत में राष्ट्रीय चेतना शक्ति और हूणों का मुकाबला करने के लिए पैदा हुई। कारण चाहे जो बताया जाय, प्राचीन यूनान और प्राचीन भारत में राष्ट्रीय चेतना के अस्तित्व से इन्कार नहीं किया जा सकता।

फिर भी रुढ़िवादी भावसंवादी कहेंगे, 'नेशन' उसे कहते हैं जिसकी भाषा एक हो। यूनान में मिलती जुलती बोलियाँ बोली जाती थी। लेकिन यहाँ तो भाषाएँ और द्रविड एकदम भिन्न भाषा-परिवार थे। फिर भारत राष्ट्र कैसे हुआ ?

प्राचीन भारत में अनेक भाषाएँ थी किन्तु शिक्षित-जन संस्कृत द्वारा मिलित भारतीय स्तर पर आपस में सम्पर्क बनाये हुए थे। आर्यावर्त से सबसे ज्यादा दूर बंगाल और केरल थे, फिर भी इनकी भाषाओं में संस्कृत के शब्द अपेक्षाकृत अधिक हैं। इससे संस्कृत के देशव्यापी प्रभाव का पता चलता है। प्रकाण्ड पंडित चक्रवर्त्य केरल ही के थे। बंगाल के न्यायशास्त्री दूर-दूर तक विख्यात हुए। फिर भी प्रश्न बना रहता है कि क्या एक से अधिक भाषाएँ बोलनेवालों को राष्ट्र की सजा दी जा सकती है ?

स्तालिन ने नेशन की जो प्रसिद्ध व्याख्या की थी, उसमें एक से अधिक भाषा की गुंजाइश नहीं है। ब्रिटिश जाति और फ्रांसीसी जातियों की एक-एक भाषा है अंग्रेजी और फ्रांसीसी। फिर भी भावसंवादी लेखक 'नेशनल फ्रीडम मूवमेंट' की बात करने हैं, सीमाव्य से वे उसे 'इंटरनेशनल फ्रीडम मूवमेंट' नहीं कहते।

अंग्रेजी का 'नेशन' शब्द बड़ा भ्रामक है। भारतीय भाषाओं में दो शब्द हैं—राष्ट्र और जाति। भारत राष्ट्र, हिन्दी भाषी जाति। ब्रिटेन राष्ट्र, ब्रिटिश जाति। ब्रिटेन राष्ट्र में एक ही भाषा है। भारत में अनेक भाषाएँ हैं। जाति की भाषा एक ही होती है। राष्ट्र में एक जाति, एक भाषा तथा अनेक जातियाँ, अनेक भाषाएँ हो सकती हैं। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 'जातीय संगीत' में जाति शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया था।

अंग्रेजी का 'पेट्रियोटिज्म' शब्द राष्ट्रीयता के बहुत निकट है किन्तु उसके मूल सेंटिन शब्द 'पात्रिष्मा' का अंग्रेजी में चलन नहीं है। राष्ट्र को पात्रिष्मा कह सकते हैं, नेशन नहीं। राष्ट्र के लिए 'नेशन' को पर्यायवाची मानें तो 'भारत बहु-जातीय राष्ट्र है'—इस वाक्य का अनुवाद होगा—'इंडिया इज ए मल्टीनेशनल नेशन'।

बहुजातीय राष्ट्र में राष्ट्रीयता का आधार क्या है ? उदाहरण के लिए, सोवियत राष्ट्रीयता (सोवियत पेट्रियोटिज्म) का आधार क्या है ? यह राष्ट्रीयता केवल भावजगत् की वस्तु नहीं है। भावसंवाद के अनुसार जाति की तरह बहु-जातीय राष्ट्रीयता का भी आर्थिक आधार होना चाहिए। क्या इसका आधार समाजवाद है ? सोवियत संघ के अनेक समाजवादी पक्षी हैं किन्तु उनकी राष्ट्रीयता या देशभक्ति सोवियत राष्ट्रीयता या सोवियत देशभक्ति से भिन्न है। राष्ट्र

की अनेक जातियाँ सामान्य आर्थिक सम्बन्धों, सामान्य देश में निवास, सामान्य ऐतिहासिक परम्पराओं और सामान्य सांस्कृतिक सूत्रों के कारण परस्पर सम्बद्ध होती हैं। भारत देश में निवास करनेवाली जातियों की भाषाएँ, प्रदेश, आर्थिक सम्बन्ध, साहित्य और संस्कृति अलग अलग हैं। फिर भी उन सबका देश एक है, उन सबका राष्ट्रीय इतिहास एक है, उनकी मिली-जुली परस्पर सम्बद्ध साहित्यिक परम्परा है, उनके आर्थिक सम्बन्ध पहले की अपेक्षा आज और भी दृढ़ हैं। इसलिए जो लोग भारत की तुलना यूरोप से करते हैं, जो देश को उप-महाद्वीप कहते हैं, वे एक ऐतिहासिक सत्य से इन्कार करते हैं। राष्ट्रीयता के विकास में केवल आर्थिक सम्बन्धों की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती। ऐसा होता तो चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया और पोलैंड सोवियत राष्ट्र के अन्तर्गत होते। उनकी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परम्पराएँ हैं जो उनकी राष्ट्रीयता निर्धारित करती हैं।

कहा जा सकता है कि इस तरह की बहुजातीय राष्ट्रीयता समाजवाद के अन्तर्गत ही सम्भव है, पूँजीवाद में तो जातियाँ, पूँजीपतियों के प्रभाव के कारण, परस्पर लड़ा करती हैं। यह बात सही नहीं है। पूँजीवाद ने अन्तर्गत 'जाति' का निर्माण होता है या नहीं? यह जाति सर्वहारा वर्ग और पूँजीपतियों के बीच संघर्ष के कारण विभाजित रहती है या नहीं? विभाजित रहती है किन्तु पूँजीपति और भजद्वार एक ही उत्पादन-वितरण व्यवस्था में काम करते हैं, इसलिए जाति सम्बद्ध भी रहती है। इसी तरह पूँजीवाद के अन्तर्गत एक ही राष्ट्र की अनेक जातियाँ आपस में स्पर्धा करती हैं, साथ ही राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था में एक-दूसरे से सम्बद्ध भी रहनी हैं। इससे अलावा सभी लोग मानते हैं कि देश की विभिन्न जातियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध 'राष्ट्रीय' आन्दोलन चलाया था। इसका अर्थ यह है कि विशेष परिस्थितियों में जातियों का आपसी तनाव कम हो जाता है और उनकी राष्ट्रीय एकता उभरकर सामने आ जाती है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि समाजवादी व्यवस्था में जातीय और राष्ट्रीय अलगाव की भावनाएँ कभी कभी बड़ा उग्र रूप धारण करती हैं। सोवियत संघ से यूगोस्लाविया, रूमानिया और चीन के सम्बन्ध इस सत्य की उजागर करते हैं।

भारत एक राष्ट्र है। हमारी राष्ट्रीयता केवल अंग्रेजों का विरोध करने के लिए—नकारात्मक रूप से—किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न नहीं हो गई। उसकी जड़ें हमारी ऐतिहासिक और आर्थिक परम्पराओं में बहुत गहरी पड़ी हुई हैं। आज की परिस्थिति में लोग चाहे जिस प्रदेश में रहते हों, उनकी आर्थिक, राजीनतिक और सांस्कृतिक प्रगति राष्ट्रीय एकता के बिना असम्भव है। किसी एक प्रदेश की उन्नति सारे देश की उन्नति पर निर्भर है।

भारत राष्ट्र से प्रेम है तो अंग्रेजी का मोह छोड़ना होगा। अंग्रेजी का प्रभुत्व राष्ट्र के लिए अपमानजनक है। विदेशी भाषाओं के साथ अंग्रेजी का अध्ययन भी किया जाएगा किन्तु वह भारतीय भाषाओं के हक भारकर यहाँ

नहीं रह सकती। सभी प्रदेशों की जनता को संग्रहीत हटाने के लिए मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। जो लोग हिन्दी साम्राज्यवाद का भय दिखाते हैं, वे अंग्रेजी का साम्राज्यवाद सुरक्षित रखते हैं।

१९६४

‘अन्तर्राष्ट्रीय’ वैज्ञानिक शब्दावली

बुद्धिजीवियों में, वे चाहे मार्क्सवादी हों चाहे गैर-मार्क्सवादी, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो समझते हैं कि विज्ञान में कोई अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली प्रचलित है। उनका तर्क यह है कि वर्तमान युग में विज्ञान अन्तर्राष्ट्रीय हो गया है, इसलिए उसकी शब्दावली भी अन्तर्राष्ट्रीय हो गई है। हिन्दी में यदि यह अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली अपना ली जाय, तो पारिभाषिक शब्दावली की समस्या हल हो जाय ।

स्थिति यह है कि यूरोप की भाषाओं में बहुत-से पारिभाषिक शब्द सामान्य हैं। सैंटिन-ग्रीक के आधार पर बनाये हुए ये शब्द एक ही रूप में या थोड़े से रूप-परिवर्तन के बाद विभिन्न यूरोपीय भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्दों को अपनाने में कोई हानि नहीं है। भारत सरकार की ओर से १९६२ में जो पारिभाषिक शब्दकोश प्रकाशित हुआ है, उसमें लगभग हर पृष्ठ पर इस श्रेणी के कुछ शब्द दिए हुए हैं। बोवास्ट, उरेनियम, उरेनस, उरेडियम, उरेमा, ऑक्सीजन, ऑक्सीनाइट्रेट, यूकलिप्टस, बलकोहल, एथिलीन आदि ऐसे ही शब्द हैं।

इस तरह की सामान्य शब्दावली सीमित है। सीमित सस्या में ही उससे शब्द लिये जा सकते हैं। यूरोप की भाषाओं में प्रयुक्त होनेवाले सभी वैज्ञानिक शब्द अन्तर्राष्ट्रीय नहीं हैं। मास्को से वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों के कई कोश प्रकाशित हुए हैं। जो लोग वैज्ञानिक शब्दावली की अन्तर्राष्ट्रीयता पर बड़ी दृढ़ता से विश्वास करते हैं, उन्हें ये कोश अवश्य देखने चाहिए।

उदाहरण के लिए, हवाई जहाजों की उड़ान से सम्बन्धित एक अंग्रेजी-रूसी कोश है। जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली की आवश्यकता अधिक हो। लेकिन अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द अक्सर प्रचलित शब्दों के आधार पर बनाये गए हैं और रूसी से भिन्न हैं। अंग्रेजी में एक प्रचलित शब्द है ‘कौक’। इसको आधार मानकर एयर कौक, एयर एस्केप कौक, बैलेंस कौक, कट्रोल कौक, ड्रेन कौक, पयूएल कौक, घोट-

लिंग कौक, आदि पारिभाषिक शब्दावली बनाई गई है। इसी कौक शब्द का प्रयोग नहीं करते। इसलिए वे दूसरी तरह के शब्दों का व्यवहार करते हैं। अंग्रेजी में प्रचलित शब्द है, कंट्रोल। इसे आधार मानकर सर्कुलेशन कंट्रोल, डेप्य कंट्रोल, डिस्टेन्स कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पलाइट कंट्रोल, ऐलिवेटर कंट्रोल, इमर्जेंसी कंट्रोल, पलाइट कंट्रोल, ग्राउंड कंट्रोल, आदि शब्दावली बनाई गई है। इसी तरह लेंडिंग के आधार पर त्रिसर्विड लेंडिंग, डेड-एजिन लेंडिंग, फोर्स लेंडिंग, रनअवे लेंडिंग आदि, एयरक्राफ्ट के आधार पर कर्बेट एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, सिविल एयरक्राफ्ट, जेट एयरक्राफ्ट आदि शब्दावली निमित्त हुई है। इनके इसी पर्यायवाची बिल्कुल भिन्न हैं जैसे कंट्रोल के लिए सभी शब्द हैं उप्रावलेनिय, एयरक्राफ्ट के लिए सामान्योत्त इत्यादि।

भास्को से कुछ पारिभाषिक शब्दकोश ऐसे प्रकाशित हुए हैं जिनमें सात भाषाओं के पर्यायवाची शब्द एक साथ दिए हुए हैं। इस तरह के कोशों का प्रकाशन ही मिट्टी करता है कि यूरोप में कोई सर्वमान्य अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावली नहीं है। अंग्रेजी में प्रयुक्त जो शब्द कुछ लोगों को बहुत अन्तर्राष्ट्रीय लग सकते हैं उनके लिए भी यूरोप की भाषाओं में भ्रमण शब्द हैं। जेट के लिए इसी में स्त्रूया शब्द है; कार्बन, कार्बन-डाईऑक्साइड, टॉन, योरेक्स, लेबियम, गैस्ट्रिक, प्रोबरी, ग्लेड, एस्कलो, और न्यूक्लिअर के लिए इसी में प्रमश, उल्गेरोद, उल्गेकीस्लुइ गाल, मुलोभीलिये, गूदा, गबा, ऊँ उदोन्बुइ, याइन्विच, ऊँ लेजा, श्वेलोच और यादेर्नाया शब्द हैं। ऑक्सीजन के लिए इसी और जर्मन के अपने शब्द किसेलरोद और जावर स्टोक हैं। नाइट्रोजन के लिए इतालवी, फ्रांसीसी और इसी में अजोत शब्द का प्रयोग होता है। फोस्फोर के लिए ल्यूमिनो-फोर सुस्तान्निमया, लायरटस्टीफ आदि शब्द हैं। डच और जर्मन भाषाएँ एक दूसरे से बहुत मिलती हैं। ग्रिड के लिए उनके भिन्न शब्द हैं—रोस्टर और गिटर। इनाइटर के लिए डच में ओटस्टेकर, जर्मन में ल्यूटस्टिपट शब्द हैं।

इस विवरण से स्पष्ट है कि भारतीय भाषाओं को अपने पारिभाषिक शब्दों का निर्माण और व्यवहार करने की पूर्ण स्वाधीनता है। वे सीमित संख्या में यूरोपीय भाषाओं से शब्द ले सकती हैं। सर्वमान्य वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का अस्तित्व कहीं नहीं है।

संस्कृति और भाषा.

भाषा को आप चाहे संस्कृति का ही अंग मान चाहे उससे भिन्न, दोनों के अनिष्ट सम्बन्ध को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वाक्य रचना की पद्धति हमारी चिन्तन पद्धति पर निर्भर होती है। आप अपनी भाषा में कर्म को क्रिया के पहले बिठाते हैं या बाद को, यह आपकी परम्परागत ज्ञानीय चिन्तन प्रक्रिया पर निर्भर है। आप अपनी भाषा में किस तरह के विदेशी शब्द कितने परिमाण में ग्रहण करते हैं, यह आपके जातीय चरित्र पर निर्भर है। आप अपनी भाषा का सम्मान करते हैं, दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करते हैं अथवा उसे पैरो तले रौंदते हैं और किसी अन्य भाषा को सिर चढ़ाते हैं, यह आपकी राष्ट्रीय सम्मान की भावना पर निर्भर है।

किसी भी देश में उसकी भाषा या भाषाओं की स्थिति विशुद्ध भाषा-विज्ञान के नियमों से सम्बन्ध में नहीं आ सकती। वह स्थिति देश की आन्तरिक और बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर है। आज ससार के बहुत बड़े हिस्से में अंग्रेजी का बोलचाल है। ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दो देश ऐसे हैं जो अन्य देशों को पूँजी का निर्यात करते हैं, जो प्रच्छन्न और प्रकट रूप से उपनिवेशवाद का पोषण करते हैं, जो अपने प्रभाव को साम-दाम-दण्ड-भेद की धूरणी नीति से सुरक्षित करके और व्यापक बनाने में लगे हुए हैं। राजनीति से लेकर शिक्षा और संस्कृति तक जिस देश में जैसे बल पड़ता है, वे घुसने बैठने, अपनी जड़ जमाने की कोशिश करते हैं। इनकी एक भाषा-सम्बन्धी स्पष्ट नीति है, पहले के समान यहाँ की भाषाओं का दबाकर रखना, उन सबके ऊपर शीर्ष स्थान पर अंग्रेजी को जमाकर रखना। इससे लाभ यह होता है कि आपके मर्मस्थल पर प्रहार करके आपको कमजोर बनाकर वे आपको अपनी स्वार्थ नीति की ओर आसानी से खींच सकते हैं। मर्मस्थल है, जातीय भाषा के प्रेम का स्थल, जातीय संस्कृति के प्रेम का स्थल, राष्ट्रीय आत्म गौरव का स्थल। आदमी को इस स्थल पर मारिए, उसे भीतर से निर्वीर्य कर दीजिए फिर उस बलि-पशु को चाहे जिस छूटे से बाँध कर उसका वध कर दीजिए।

भाषा उस देश की दशा पर विचार कीजिए जो घन्न से लेकर अस्थ-शस्त्र तक परमुखापेक्षी है, जो अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए उन्हीं लोगों का मुँह जोहता है जो अब तक उसे गुलाम बनाए हुए थे। इसी नीति के अनुरूप भाषाक्षेत्र में भी हमारे देश के नेता परमुखापेक्षी हैं। जिस अंग्रेजी भाषा ने विदेशी राज्यकाल में यहाँ की भाषाओं को पदमर्दित किया, यहाँ की संस्कृति और साहित्य के सहज विकास को कुण्ठित किया, अंग्रेजी के जिस आधिपत्य के विरुद्ध भारतीय मनोवियोग ने सतत संघर्ष किया, उस अंग्रेजी को हटाकर भारतीय भाषाओं को उनका स्वत्व देने में सामक और शिक्षामन्त्री हिचकिचा रहे हैं।

हमारी सांस्कृतिक पराधीनता भाषा के क्षेत्र में अनेक रूपों में प्रकट होती है। हमारे संविधान में लिखा है कि हिन्दी भाषा को विकसित होने के लिए समय दिया जाय। हिन्दी को विकसित करने के लिए एक विशाल निदेशालय बालू है। हिन्दी में क्या कमी है, कमी है या नहीं, है तो उसे कैसे पूरा किया जाय, हिन्दी और भारतीय भाषाओं को देखत 'विश्वभाषा' अंग्रेजी में भी कोई कमी है या नहीं, है तो उसे कैसे दूर किया जाय—इस सबका निदान करने के लिए कोई आयोग नहीं बनाया गया, भाषा की सिद्धि समृद्धि जाँचने का योग सत्रह साल में नहीं आया। करोड़ों रुपये इस स्वतः सिद्ध सत्य पर खर्च हो गए हैं कि 'विश्वभाषा' अंग्रेजी विकसित और समृद्ध है और भावी राष्ट्रभाषा हिन्दी अविकसित और दरिद्र है।

समृद्धि का कार्य कोष निर्माण द्वारा सम्पादित होता है। कोष निर्माण के लिए अंग्रेजी शब्द पहले हैं, हिन्दी बाद को। हमारी सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकता के लिए कौन सा शब्द आवश्यक है, यह विषय अग्रोचर ही रहता है। कोष निर्माताओं में अनेक जन अंग्रेजी से जितना प्राप्त करते हैं, उतना ही हिन्दी की प्रकृति से अनभिज्ञ भी। वे ऐसे 'स्थितित' और 'पतित' ऊर्जा वाले शब्द गढ़ते हैं कि 'तत्रिकात्र' भट्ट हो उठता है और उनकी 'शक्तिवृत्ता' को देखकर साधारण पठित जन यही सोचते हैं कि इससे तो अंग्रेजी भली। हिन्दी को समृद्ध करने के नाम पर अस्वाभाविक, उच्चारण में दुष्कर शब्दों का निर्माण भाषा के प्रति अवज्ञा का परिचायक है, अज्ञान का तो है ही।

सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में जहाँ हिन्दी बोलना चाहिए, वहाँ हम अंग्रेजी से काम लेते हैं। परिवार के भीतर बचपन से अपनी सन्तान को हम डंडी, मम्मी, अबस कहना सिखाते हैं माना यहाँ भी पाठ्यापिब शब्दों की कमी हो। हमारे उच्च मध्यम वर्ग के लोगों की बहुत बड़ी आकांक्षा यह रहती है कि बेटा कॉन्वेंट में पढ़े, परीटे से अंग्रेजी बोले, मजिस्ट्रेट बनकर लोगों पर हुकूमत करे। जिसका सिवाभाव, जिसके गांधी और बुद्ध। खाने के दाँत और, दिखाने के और।

जहाँ तक मुझे मालूम है, इस देश की राजनीतिक परिस्थिति अपना केन्द्रीय

राजनीतिक कार्य, अपने वैश्वीय मुखपत्र अंग्रेजी में चलाती हैं। हम विश्वभाषा के नाम पर अंग्रेजी पढ़ने पर जोर देते हैं। जहाँ फ्रांस का राज्य था या है, वहाँ विश्वभाषा का दर्जा फ्रांसीसी को मिला है। किस पिछड़े हुए देश ने यूरोप की किस भाषा को विश्वभाषा माना है, यह इस पर निर्भर है कि उस पर यूरोप के किस देश का प्राधिपत्य था या है।

हमारे अनेक युगान्तरकारी साहित्यकार अपनी वाक्य-रचना में अंग्रेजी शब्दों की ऐसी भरमार करते हैं मानो हिन्दी में सोचना उन्होंने बन्द कर दिया है। वे न हिन्दी में सोचते हैं, न अंग्रेजी में वरन् इन दोनों से मिली हुई एक नई इंग्लिस्तानी भाषा में, जो उनके लिए बहुत स्वाभाविक है किन्तु जो देश की जनता के लिए, हमारे समग्र सामाजिक विकास के लिए घातक है। अनेक लेखक अंग्रेजी मुहावरों का अनुवाद करके अपनी जातीय भाषा की सजाते हैं। अंग्रेजी के शब्दों, उद्धरणों और अनुवादित मुहावरों से वे अपनी—भाव-विचार-अनुभव की—दरिद्रता छिपाते हैं। अपनी सांस्कृतिक परम्परा के लिए, भारतीय भाषाओं और उनके साहित्य के लिए उनके हृदय में घनादर की भावना है। उनमें बड़ी उत्सुकता होती है कि नई अंग्रेजी पुस्तकों की खर्चा करके अपने सुसज्जित होने का परिचय दें। वे साधारणतः यूरोप की भाषाओं से प्रभावित होते हैं और यूरोप के साहित्य को अंग्रेजी निगाहों से ही देखते हैं।

हिन्दी के अनेक समर्थ साहित्यकार इस भाषा-सम्बन्धी पराधीनता से मुक्त हैं। कुल मिलाकर हिन्दी साहित्य अपने स्वस्थ जातीय मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि छात्रों की सुविधा से लाभ उठाकर बहुत से लेखक ऐसी भाषा का प्रयोग करने लगे हैं जो हिन्दी के सहज विकास के लिए घातक है।

इनमें भिन्न श्रेणी का एक लेखक समुदाय और है जो अंग्रेजी के माध्यम से ही अपनी कलात्मक प्रतिभा का परिचय देता है। वे किसान-वैद्य की संस्कृति का उद्धार कर रहे हैं, अंग्रेजी में उपन्यास, कहानियाँ, कविताएँ लिखकर। माना कि अंग्रेजी विश्वभाषा है और उसमें लिखने से अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति जल्दी मिलती है किन्तु नाबें, डेनमार्क, इटली, स्पेन, जैसे छोटे देशों के लेखक इस विश्वभाषा को नहीं अपनाते, उसे अपनाने का ठेका हमारे महान् देश के लेखकों ने लिया है।

हमें अपनी भाषा के जातीय रूप की रक्षा करनी चाहिए। उसमें अघाघुग्ध अंग्रेजी शब्दों की भर्ती हमारे राष्ट्रीय सम्मान के विपरीत है। हिन्दी की शक्ति उसे अपनाने, धार करनेवाली जनता की शक्ति है। दुर्बोध, उच्चारण के लिए विकट शब्दावली से उसे भरसक बचाना चाहिए अर्थात् हमें भरसक अपनी गैली सुगम बनानी चाहिए और वैज्ञानिक शब्दावली में भी भरसक हिन्दी की शक्ति का ध्यान रखना चाहिए। हमारा साहित्य इस देश की जनता के लिए है। इसलिए इंग्लिस्तानी के बड़े हिन्दी का ही प्रयोग करना चाहिए। अंग्रेजी !

के माध्यम से प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति अस्थायी है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर प्रमोद
ने अपनी भाषाओं के माध्यम से जो ख्याति पाई, वही स्थायी है। जातीय
संस्कृति से भाषा का घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह ध्यान में रखकर हमें अपने
व्यवहार में सतर्क रहना चाहिए। (१९६४)

भाषा की समस्या—अति आवश्यक

देश की राजनीतिक परिस्थिति की एक विशेषता यह है कि कांग्रेस को मिलनेवाले बोट दिन-पर-दिन कम होते जा रहे हैं और उसी परिणाम में वाम-पक्षी पार्टियाँ और उनका संयुक्त मोर्चा समर्थ होकर जनता के सामने नहीं आ रहे। पिछले दिनों कम्युनिस्ट पार्टी में विघटन के कारण वामपक्ष और भी कमजोर हो गया है। हिन्दी-भाषी प्रदेश में विशेष रूप से दक्षिणपक्षी दल शहजोर है। चूँकि भारत में हर समस्या अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल ही हल नहीं होती, इसलिए हर जागरूक नागरिक को फासिस्ट तानाशाही की संभावना के प्रति सतर्क रहना चाहिए।

जर्मनी के अनुभव से हमें मालूम है और अपने देश का अनुभव भी यही बतलाता है कि फासिस्ट दल संस्कृति के प्रश्न लेकर जनता को गुमराह करते हैं। हिटलर मध्यवर्ग ही नहीं, मजदूर वर्ग के भी एक भाग को गुमराह करने में सफल हुआ था। हमारे देश में साम्प्रदायिक दल संस्कृति के प्रश्न विशेष रूप से जनता के सामने रखते हैं। वे अपने को भारतीय संस्कृति का एकमात्र रक्षक मानते हैं। संस्कृति को ढाल बनाकर वे अपनी गलत राजनीति के अस्थिर जनता पर चलाते हैं।

कुछ प्रगतिशील लोग समझते हैं कि यदि वे भी संस्कृति की बात करेंगे तो उनमें और साम्प्रदायिक दलों में कोई अन्तर न रह जायगा। आजकल हिन्दी भाषा के सवाल को लेकर हिन्दीभाषी क्षेत्रों में बड़ी सरगर्मी है। कुछ प्रगतिशील नेता समझते हैं कि अंग्रेजी को व्यवहार में लाना, अंग्रेजी में अपने दस्तावेज तैयार करना, अंग्रेजी में अपने राजनीतिक सम्मेलनों की कार्यवाही सम्पन्न करना, व्यावहारिक राष्ट्रभाषा के रूप में अंग्रेजी को प्रतिष्ठित रखना बहुत बड़ा साम्राज्यवाद-विरोध है, राष्ट्रियता और जनतंत्र के हित में है और साम्यवाद के अनुकूल है। इसके विपरीत अखिल भारतीय स्तर से अंग्रेजी को हटाने की माँग करना, हिन्दी को केन्द्रीय राजकाज की भाषा बनाने के लिए आन्दोलन करना साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन देना है।

कोई भी प्रगतिशील दल भाषा और संस्कृति के मामलों में कितना दखल देता है, यह उसके व्यवहार से जाना जाता है। मिसाल के लिए यह विचारणीय है कि मैपिलीशरण गुप्त के निधन पर किन राजनीतिक दलों ने कहाँ कहाँ शोक प्रस्ताव पास किये। व्यवहार के अलावा विभिन्न दलों के कार्यक्रम प्रस्ताव आदि दर्शनीय हैं यह जानने के लिए कि उन्होंने सांस्कृतिक समस्याओं पर कितना विचार किया है।

माना कि सांस्कृतिक समस्याएँ बहुत उसलभी हुई हैं। यह भी माना कि राजनीतिक समस्याएँ सुलझाने में ही बहुत से नेताओं की सारी ताकत खर्च हो जाती है। किन्तु भाषा की समस्या बरौड़ों आदमियों को प्रभावित करती है। यह व्यापक सामाजिक समस्या बन गई है। उस पर सही दृष्टिकोण अपनाना और सही नीति के अनुसार आन्दोलन करना प्रगतिशील जनों का कर्तव्य है।

सवाल यह नहीं है कि जब कांग्रेसी सरकार के बदले हमारे मन-मुताबिक दूसरी हुकूमत बनेगी तब हम अंग्रेजी को जल्दी हटायेंगे या धीरे-धीरे, देर में हटायेंगे। सवाल यह है कि अभी हम क्या करने जा रहे हैं। और अभी जो कुछ करते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर है कि भविष्य में यहाँ जनता की सरकार बनेगी या फासिस्ट तानाशाही की।

जब अंग्रेजी राज कायम था तब भाषा की समस्या सभी साम्राज्य-विरोधी दलों और उनके नेताओं के सामने उसलभी हुई नहीं थी। एक बात पर सभी सहमत थे कि अंग्रेजी जाय, उसके बने रहने से देश की शक्ति और धन का नाश होता है। आजकल अनेक साम्राज्यविरोधी मोढ़ा इस बात पर एकमत दिखाई देते हैं कि कामज पर चाहे जो छपा रहे, व्यवहार में अंग्रेजी ही राष्ट्रीय भाषा बनी रहे।

हिन्दी भाषी प्रदेश में कोई भी दल भाषा के सवाल को नजरअंदाज करके सकलशास्त्री नहीं बन सकता। अंग्रेजी को हटाने और हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की माँग जनता की न्यायपूर्ण साम्राज्यविरोधी राष्ट्रीय माँग है। प्रगतिशील नेताओं को उसका समर्थन ही न करना चाहिए, आगे बढ़कर उसके लिए आन्दोलन करना चाहिए। वे लोग ही विभिन्न भाषाओं के उचित अधिकारों की रक्षा करते हुए हिन्दी के लिए सही आन्दोलन कर सकते हैं। वे अपना उत्तरदायित्व न निवाहें तो दक्षिणपथी ताकतों को अवसर मिलेगा कि वे सही माँग के लिए गलत ढंग से आन्दोलन चलाएँ, जातीय और साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाएँ और जनवादी पार्टियों के दमन के लिए आवश्यक तैयारी करें। जो प्रगतिशील नेता अब भी बेखबर रहते हैं, वे वस्तुगत रूप से जनतंत्र का नाश करने और तानाशाही को साने के लिए जिम्मेदार होंगे। (१९६५)

शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहेगी। क्या यह भारतीय भाषाओं पर अंग्रेजी लादना नहीं है? अंग्रेजी को लादना तो राष्ट्रीय एकता के लिए हितकर बताया जाता है, अंग्रेजी की जगह हिन्दी के चलन की बात भी करना साम्राज्यवाद है! तमिल की जगह तमिलनाडु में ही अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनी रहता तो इससे राष्ट्र का विकास होता है, यदि केन्द्रीय राजकाज के लिए—तमिलनाडु में नहीं, केवल केन्द्रीय राजकाज के किसी अत्यन्त सीमित दायरे में—हिन्दी चलन की बात की जाय तो साम्राज्यवाद हो जाता है।

देश का भला चाहनेवाले अनेक नेताओं और पत्रकारों ने लिखा है, वक्तव्य दिये हैं कि दक्षिणवालों का भय जायज है और उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह भय क्या है? भय यह है कि हिन्दी के राजभाषा होने से अखिल भारतीय सरकारी नौकरियाँ हिन्दीवाले हाथों में, दक्षिणवाले टापटें रह जाएँगी। राष्ट्रीय एकता और तमिल-प्रेम का सम टूटता है नौकरियों के मसल पर। किसी समय भारत का उच्च वर्ग अंग्रेजों से माँग करता था कि सरकारी नौकरियाँ उस भी दी जाएँ, अंग्रेजों के लिए सुरक्षित न रह। इस उच्च-वर्ग का भारत की स्वाधीनता की चिन्ता नहीं थी, उसकी सहाई थी सरकारी नौकरियों के लिए। तमिलनाडु और अन्य प्रदेशों के अंग्रेजी-प्रेमी नेताओं को रोटी रोख का मसला हल करने की, देश के आर्थिक विकास की चिन्ता नहीं है। उनमें सबसे बड़ी चिन्ता है सरकारी नौकरियों की। ठीक है। सरकारी नौकरियों की चिन्ता कीजिए। लेकिन राष्ट्रीय एकता के सबादे से इस स्वार्थ को मत रोकिए। मातृभाषा-प्रेम की पवित्र भावना जगाकर नौकरियों के इस सभ्यता में भोली-भाली जनता को पुलिस-फौज की गोतियों का शिकार न बनाइए।

अखिल भारतीय नौकरियों के लिए जो परीक्षाएँ होती हैं, उनमें अंग्रेजी और हिन्दी की स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि अभी तक इन परीक्षाओं का एकमात्र माध्यम है अंग्रेजी। इस माध्यम का हटाने की कोई भी योजना नहीं है, कागजों और पत्रों पर भी नहीं है। सबकुछ केवल यह है कि केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों की राय से एक प्रयोग करने का निश्चय किया है। वह प्रयोग यह है कि यदि हिन्दी को भी अंग्रेजी के साथ—अंग्रेजी की जगह नहीं—कुछ विषयों में (सभी विषयों में नहीं) परीक्षा का माध्यम बनाया जाय तो इससे अंग्रेजी माध्यमवाले घाटे में तो नहीं रहेंगे। यह प्रयोग हुआ नहीं है। उसने होने की बात है। उस प्रयोग से जब अहिन्दी-भाषी भी सन्तुष्ट हो जायेंगे निश्चय ही अंग्रेजी का व्यवहार करने पर उन्हें थोड़ा न होगा, तब उन्हें सहमत होने पर कुछ विषयों में अंग्रेजी के साथ हिन्दी भी एक ऐच्छिक माध्यम हो सकती है। अंग्रेजी के लिए इतना ही सकट उत्पन्न हुआ है।

प्रधानमन्त्री ने कहा है कि हिन्दी-प्रेमियों का अंग्रेजी हटाने में जल्दी न करना चाहिए। स्वराष्ट्र-मन्त्री ने कहा है, हमें इस मामले में जल्दी न करना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने सरकार को सलाह दी है कि हिन्दी को

राजभाषा बनाने में जल्दी न करनी चाहिए। आखिर वह बौन-सी तब रफ्तार की और किस क्षेत्र में थी, जिससे हिन्दी राजभाषा बनी जा रही थी? आजादी पाने के छठारह साल बाद जो सरकार मिली भारतीय नौकरियों के लिए हिन्दी को केवल ऐच्छिक माध्यम बनाने के प्रयोग की बात करती है, उसमें भी कुछ बुद्धिमानों को तेज रफ्तार की सिखायत होती है।

हिन्दी तो एक दिन राजभाषा होगी, लेकिन धीरे-धीरे—ऐसा कहनेवाले वास्तव में अंग्रेजी की हिमायत करते हैं। इसका प्रमाण यह है कि अपना मिलित भारतीय राजनीतिक कार्य में नेता और उनकी पार्टियाँ अंग्रेजी में करती हैं। व्यवहार में अंग्रेजी, हिन्दीभाषी जनता के बोट लेने के लिए भविष्य में हिन्दी की राजभाषा बनाने के बाड़े। यह दुरभी नीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी।

कुछ दूसरे लोग हैं जो माँग करते हैं कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी के सम्बन्ध में जो वादे किये थे, वे सविधान में दर्ज हो जान चाहिए। यद्यपि वर्तमान प्रधानमंत्री ने उन आश्वासनों को दुहराया है, किन्तु बहुत-से दशमकतों के लिए इतना काफी नहीं है। वे चाहते हैं कि सविधान में उन आश्वासनों को दर्ज कर दिया जाय।

अनेक स्थानों में यह नया नारा सुनने को मिला है—‘हिन्दी नेयर, इग्लिश एवर।’ हिन्दी कभी न आग, अंग्रेजी हमेशा बनी रह। दक्षिण में जो उच्छ्वाटि के प्रतिक्रियावादी नेता हैं, वे यही नारा दे रहे हैं कि भारत की एकमात्र राजभाषा अंग्रेजी ही। अपने आन्दोलन के जरिये वे सबसे पहले तमिल की जड़ काट रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से तमिलनाडु में तमिल उच्छ्वाटि का माध्यम नहीं बनी। इसके बाद वे विशाल हिन्दीभाषी प्रदेश पर—तथा अन्य अहिन्दी राष्ट्रभाषा प्रेमी जनता पर—सदा के लिए अंग्रेजी का प्रभुत्व स्थापित करने का पड्यन्त्र कर रहे हैं। अंग्रेजी के इस वास्तविक साम्राज्यवाद को देश की जनता कभी सहन न करेगी।

यह ध्यान देने की बात है, हिन्दी विरोधी आन्दोलन ने भयानक उल्लास का रूप केवल तमिलनाडु में लिया है। अंग्रेजी प्रेमी नेता अन्य प्रदेशों में भी हैं, किन्तु उन्होंने कोई उग्र आन्दोलन नहीं चलाया। इसके दो कारण हैं। पहला यह कि अंग्रेजी प्रेमी नेता जानते हैं कि वास्तव में अंग्रेजी के लिए कोई खतरा नहीं है, हिन्दी को व्यावहारिक राजभाषा होने में बहुत देर है। इसलिए गर्म या गर्म किसी तरह के आन्दोलन को वे अनावश्यक समझते हैं। दूसरा कारण यह है कि तमिलनाडु का भारत से अलग करने के लिए जैसा आन्दोलन उस प्रदेश में हुआ है, वैसा आन्दोलन अन्य किसी प्रदेश को अलग करने के लिए नहीं हुआ। विघटन के इस प्रचार की राजनीतिक दलों ने सगठित किया। भाषाशास्त्र और इतिहास की भूठी गवाही से उस विघटन की भावना को वहाँ तक फैलाया। केन्द्रीय या तमिलनाडु का शासन अथवा कोई भी राजनीतिक दल उसका समर्थन प्रतिवाद नहीं कर पाया। यही कारण है कि हिन्दी-विरोधी

ग्रान्दोलन ऐसा विनाशक रूप केवल तमिलनाडु में ले सका । । । ।

इसका अर्थ यह है कि हिन्दी विरोध एक नकाब है, जिसके नीचे विघटन का देव छिपा हुआ है । नीकरी न मिलेगी यह भय दिखसाकर स्वार्थी नेताओं ने छात्रों को उभारा है और स्वतन्त्र द्विदि राज्य कायम करने के नक्ष के लिए उनका उपयोग किया है । देश की स्थिति ऐसी है कि कश्मीर, नागालैण्ड या तमिलनाडु कोई भी प्रदेश अलग होता है, तो उसकी हिमायन के लिए साम्राज्यवादी आगे आते हैं । वे अपने फौजी अड्डा का स्वप्न देखते हैं, भारत का जो हिस्सा मिले उसका उपयोग अपनी समर योजनाओं के लिए करना चाहते हैं । कुछ विदेशी पक्षों ने तमिलनाडु के हिन्दी-विरोधी ग्रान्दोलन को लेकर तमिल की लिपि, तमिल भाषा की व्यञ्जना शक्ति की बड़ी प्रशंसा की है और हिन्दी को तमिल से नीचा ठहराया है । इस प्रकार का उद्देश्य भारत में गृहयुद्ध की आग सुलगाना है ।

भारत से अलग होकर तमिलनाडु या कोई भी प्रदेश न तो साम्राज्यवाद से मुक्त रह सकता है, न अपना आर्थिक और सांस्कृतिक विकास कर सकता है । विप्लवकारी ग्रान्दोलन से सर्वप्रथम उन प्रदेश का ग्रहित होता है जहाँ ऐसा ग्रान्दोलन चलाया जाता है । उसके बाद समूचे देश का ग्रहित होता है । अंग्रेजी की सुरक्षा का यह ग्रान्दोलन देश के विघटन का ग्रान्दोलन है । समस्या हिन्दी और तमिल की नहीं है, समस्या तमिलनाडु को भारत का अभिन्न अंग बनाये रखने की है ।

यह सम्भव है कि भारत सरकार अंग्रेजी प्रेमियों के दबाव से अंग्रेजी की सुरक्षा के लिए कुछ और नियम कायदे बना दे या सविधान में तब्दीली कर दे । इससे अंग्रेजी की वास्तविक स्थिति में कोई अंतर न पड़ेगा । अंग्रेजी तो राज भाषा के रूप में सुरक्षित है ही । भारतीय भाषाओं को उनके उचित अधिकार दिलाने के लिए यह जरूरी है कि सबसे पहले हिन्दीभाषी प्रदेश में अंग्रेजी को राजभाषा और सांस्कृतिक भाषा के पद से पूर्णतः हटा दिया जाय, विश्वविद्यालयों में पूर्णतः हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाय, यहाँ के न्यायालयों का सारा काम हिन्दी में हो, सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में अंग्रेजी का व्यवहार खत्म किया जाय । इसके बाद जिस दिन हिन्दीभाषी जनता संगठित होकर अपने लोक-सभा के प्रतिनिधियों को हिन्दी में बोलने और सारा राजकाज हिन्दी में करने के लिए बाध्य करेगी, उस दिन अंग्रेजी का साम्राज्यवाद खत्म हो जाएगा, उस दिन तमिलनाडु में तमिल भी अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त करेगी और राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करने में हिन्दीभाषी जनता अपनी भूमिका पूरी करेगी । अंग्रेजी को हटाने और राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करने का भार अब हिन्दीभाषी प्रदेश पर है ।

(१९६५)

भाषा की समस्या और राष्ट्रीय विघटन

जिस समय भारत की संविधान सभा ने यह निश्चय किया कि राष्ट्रभाषा हिन्दी हो और तुरन्त नहीं, पन्द्रह साल बाद सन् '६५ में हो, उस समय इस फैसले के पक्ष में बोट देनेवाले उत्तर के लोग भी थे, दक्षिण के भी, हिन्दी-भाषी इलाकों के नेता भी थे और अहिन्दी-भाषी प्रदेशों के भी। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह फैसला हिन्दीवालों ने दक्षिण या बंगाल पर लाया था।

जैसे-जैसे सन् '६५ निकट आता गया वैसे-वैसे उस फैसले को टालने के लिए भी कोशिशें होने लगीं। संसद ने एक कानून बना दिया जिसके अनुसार सन् '६५ के बाद भी अंग्रेजी सह-राजभाषा बनी रह सकती है। इस फैसले से हिन्दी को धक्का लगा, यह माना जा सकता है। किन्तु उससे किसी अहिन्दी भाषा को हानि हुई यह दावा कोई नहीं करता।

इसके बाद भी स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि अहिन्दी-भाषियों की भर्जों के बिना अंग्रेजी को नहीं हटाया जाएगा। इस साल २६ जनवरी से दिल्ली सरकार ने अपना राजकाज हिन्दी में नहीं शुरू किया, किसी अफसर को हिन्दी न जानने के कारण निकाला नहीं गया, प्रखिल भारतीय नीतिरियों के लिए परीक्षाएँ हिन्दी में नहीं होने लगीं, न अंग्रेजी को हटाकर उन परीक्षाओं के लिए हिन्दी को एकमात्र माध्यम बनाने का फैसला किया गया, उत्तर-दक्षिण के विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी नहीं बनी, किसी भी केन्द्रीय मंत्रालय में अपने कामकाज-पत्र हिन्दी में तैयार करना नहीं शुरू किया, न इस तरह के कामकाज-पत्र केन्द्र से राज्यों को भेजे गए, तमिलनाडु या बंगाल से अंग्रेजी में लिखकर भेजा हुआ कोई कागज दिल्ली से वापस नहीं किया गया, कांग्रेस के प्रधान श्री कामराज के तमिल में ही बोलने पर कहीं हिन्दी-जनता ने प्रदर्शन नहीं किया, फिर भी तमिलनाडु में उत्पात मड़ा हो गया।

केन्द्रीय सरकार में उत्तर-दक्षिण, हिन्दी-अहिन्दी सभी प्रदेशों के लोग हैं। इस सरकार का कोई भी नाम नहिं हिन्दीभाषी जनता का नाम नहीं माना

जाना। फिर भी अगर कोई ऐसा काम हुआ हो जिससे अंग्रेजी की गौरवमय स्थिति को धक्का लगा हो तो मैं जानना चाहता हूँ कि वह काम कौन-सा है। सन् '६५ में हिन्दी को—बागज पर, दिक्षावे के लिए—राष्ट्रभाषा बनाने का फैसला सोतह सात पहले किया गया था। फैसला करनेवाले उत्तर-दक्षिणवाले दोनों थे। फिर अचानक अहिन्दी भाषियों पर हिन्दी भाषा कैसे लाद दी गई?

कुछ लोगों का कहना है कि भारत ने सभी राज्यों की भाषाओं को बराबरी का दर्जा दे दिया जाय। मैं कहता हूँ सौक से दीजिए। लेकिन भाषा जिस पार्टी में भी हो, उसका राजनीतिक काम दस बारह भाषाओं में करके दिखाइए। जो पार्टियाँ अपना केन्द्रीय काम एक भाषा में करती हो, उन्हें कोई हक नहीं है कि वे केन्द्र में दस भाषाएँ चलाने की बात करें।

कुछ बुद्धिमान नेता यह राय देते हैं कि राज्यों में वही की भाषाएँ चलें लेकिन केन्द्र में अंग्रेजी चने क्योंकि हिन्दी को अभी और विकसित होना है। इनका मतलब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि के राजकाज के लिए तो हिन्दी विकसित है, केवल केन्द्रीय राजकाज के लिए वह अविकसित है। मैं जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश और केन्द्र के राजकाज में वह कौन-सा गुणात्मक अन्तर है जिससे हिन्दी एक जगह विकसित मानी जाती है और दूसरी जगह अविकसित।

अमलियत यह है कि अंग्रेजी को देश में कायम रखने के लिए हर दलील जायज है। अंग्रेजी के जरिये हमारा अफसर वर्ग साहब बनकर जनता पर हुकूमत करता है। और हर पार्टी के अन्दर अंग्रेजी के कारण एक ऊँचे पाये का नेता है जिसे अपने महान् विचार प्रकट करने में किसी भारतीय भाषा को माध्यम बनाते हुए बड़ी कठिनाई होती है। दूसरा नेता छोटे दर्जे का केवल भारतीय भाषाएँ जाननेवाला है। अंग्रेजी के जरिये अफसर और जनता, साहब और गुलाम, बड़ा आदमी और छोटा आदमी—दो वर्गों में सारे देश को बाँटने में सहायक होती है। जो लोग कहते हैं कि अंग्रेजी के रहने से राष्ट्रीय एकता कायम रहती है, उनका मतलब यही होता है कि उसके जरिये काले साहबों की एकता कायम रहती है। इस एकता के कारण ग्राम जनता और हुकूमत के बीच कितना बड़ा फासला कायम रहता है, इसकी चिन्ता उन्हें नहीं होती।

अब यह बिलकुल स्पष्ट है कि तट्टाई तमिल या बंगला के अधिकारों के लिए नहीं है। तट्टाई है अंग्रेजी के बेजा अधिकारों की रक्षा के लिए। तमिलनाडु के जिन विद्यार्थियों में तमिल की शिक्षा का माध्यम बनाया गया उन्हें बन्द कर देना पड़ा। आंध्र के शासकों का कहना है कि तेलुगु को राजभाषा बनाने में दस साल लगेंगे। इसमें क्या सारबिंत होता है? क्या हिन्दी राष्ट्रभाषा बनकर तमिल और तेलुगु के अधिकार छीने ले रही है? एकीकृत यह है कि आंध्र और तमिलनाडु में राजभाषा अंग्रेजी है और उम्र हटाने के बदले प्रदेश प्रेमी सज्जन हिन्दी-विरोधी आन्दोलन चला रहे हैं।

केन्द्र में अंग्रेजी और प्रदेश में अंग्रेजी—दोनों जगह के तार आपस में जुड़े हुए हैं। जो केन्द्र में अंग्रेजी हटाने का विरोधी है वह प्रदेश में भी उसे नहीं हटाना चाहता। बात बिलकुल स्वाभाविक है। तमिलनाडु में रहनेवाला जो मूढ़स्थ अपने बेटे को धीरे-धीरे इडिया सविम में अफसर बनाना चाहता है वह उसके लिए तमिल की शिक्षा का माध्यम क्यों बनाए ? प्रदेश में हर स्तर पर वहीं की भाषा चालू हो जाय तो होनहार नौजवानों को अंग्रेजी निखने-बोलने में कठिनाई न होगी ? अंग्रेजी क्यों ज्यादा अच्छी बोलेंगे—वह जिसकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रही है या वह जो शिक्षा प्रादेशिक भाषा में पाता रहा है ? इसीलिए गुजरात में आन्दोलन हो रहा है कि अंग्रेजी की शिक्षा को बड़ी दर्जा दिया जाय जो और राज्यों में उसे प्राप्त है।

जब तक केन्द्र की राजभाषा अंग्रेजी है तब तक प्रदेशों में वहाँ की भाषाएँ पूरी तरह राजभाषा बन नहीं सकनी। बेटा हजीनियर बनेगा, लोकसभा का सदस्य बनेगा, बही का राज्यपाल बनेगा, कंसवटर या कमिश्नर बनेगा। यह सब बनने-बनाने का काम अंग्रेजी से होगा या तमिल और मराठी ? होनहार नौजवानों के माता-पिता क्या मुर्ख हैं जो प्रादेशिक भाषा में शिक्षा देकर उनका अखिल भारतीय भविष्य नष्ट करेंगे ?

इसलिए वे नेकदिन नेता, जो भाषा-समस्या सुलझाने के लिए यह सुझाव देना करते हैं कि राज्यों में तुरन्त वहाँ की भाषाओं को राजभाषा बनाया जाय और केन्द्र में अंग्रेजी को बहुत धीरे-धीरे हटाया जाय, बहुत भारी भ्रम में हैं। स्वाधीन भारत में शिक्षा का महान् उद्देश्य अब भी अखिल भारतीय नौकरियों प्राप्त करना है। बेटों का ब्याह भाई० ए० एस० अफसर से हो, मध्यवर्गीय बाप की यह सबसे बड़ी समस्या होती है। प्रदेशों में शिक्षा का संगठन इन्हीं अखिल भारतीय नौकरियों को लक्ष्य बनाकर होता है। इसलिए जब तक केन्द्र में अंग्रेजी रहेगी जब तक अखिल भारतीय स्तर पर अंग्रेजी का मौजूदा रोबदार रहेगा, तब तक प्रदेशों में भी अंग्रेजी हटाई न जाएगी। जो सचमुच अंग्रेजी हटाकर प्रादेशिक भाषाओं को राजभाषा बनाना चाहते हैं, वे केन्द्र में अंग्रेजी के समर्थक ही ही नहीं सकते।

सरकार की बात जाने दीजिए। मैं उन अखिल भारतीय पार्टियों का नाम जानना चाहता हूँ जिसकी प्रादेशिक भाषाएँ अपना सारा काम भारतीय भाषाओं में करती हैं और जो केन्द्र में अंग्रेजी हटाकर धीरे-धीरे हिन्दी लाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

भाषावार राज्यों के पुनर्गठन का आन्दोलन चला। इस आन्दोलन में यह जोरदार आवाज नहीं सुनाई दी कि प्रदेशों में अंग्रेजी हटाई जाय, प्रादेशिक भाषा को राजभाषा बनाया जाय। इसका क्या कारण है ? कारण यह है कि भाषावार राज्य बनाने में प्रादेशिक पूँजीपतियों का भी स्वार्थ था, वे अपने लिए भव्य बाजार कायम करना चाहते थे, उन्हें प्रादेशिक भाषाओं के बड़े बाजार

मोहब्बत न थी। प्रगतिशील नेताओं ने उनका साथ दिया, ठीक विया। लेकिन प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाय, इसके लिए वे कोई सशक्त आन्दोलन नहीं कर सके। क्यों? आज भी प्रस्ताव पास करने के बलावा प्रदेशों में अंग्रेजी हटाने के लिए कोई आन्दोलन नहीं चलाया जा रहा, न कोई आन्दोलन चलाने का कार्यक्रम है। क्यों? प्रदेशों में अंग्रेजी हटाने के लिए भाषावार प्रान्त आन्दोलन जैसी कोई चीज सामने क्यों नहीं है? इसलिए कि प्रादेशिक पूँजीपतियों का साथ देते हुए बहुत से प्रगतिशील नेता भी भटकाव के शिकार हो गए हैं। उन्होंने प्रादेशिक भाषाओं के लिए आन्दोलन नहीं किया, राज्यों की भौगोलिक सीमाओं के लिए मरे सपने। उन्होंने प्रादेशिकता के आन्दोलन में राष्ट्रीय एकता की भावाज वृत्ति नहीं की। उसी का नतीजा है कि आज वे प्रदेशों में तो अंग्रेजी हटाने की बात करते हैं लेकिन केन्द्र में काफी दिन तक अंग्रेजी कायम रखने की बात सोचते हैं। नतीजा यह होता है कि अंग्रेजी न केन्द्र से हटती है, न प्रदेशों से। हिन्दी के लिए जो सही मार्ग हैं उन्हें पेश करने का काम उन्होंने श्री मुरारजी भाई और जनसंघ के नेताओं को सौंप दिया है। उनकी ढिलाई से प्रतिक्रियावादी नेता फायदा उठा रहे हैं, यह देखने के बदले वे प्रसन्न होकर फतवा देते हैं—तुरन्त अंग्रेजी हटाने का नारा मुरारजी और सधियों का है। आश्चर्य की बात है कि संयुक्त महाराष्ट्र आन्दोलन में जनसंघ के साथ काम करते हुए अनेक प्रगतिशील नेताओं को जरा भी तकलीफ नहीं हुई। जब केन्द्र से अंग्रेजी हटाने के सवाल पर वे जनसंघ का ढीवा खड़ा करते हैं।

कुछ दिन पहले बंगाल में प्रगतिशील और अप्रगतिशील सभी दलों ने हिन्दी चालू न करने के लिए एकमत होकर प्रस्ताव पास किया। तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम से लेकर केन्द्र-मन्त्रियों तक अंग्रेजी की सुरक्षा के लिए एकमत हैं। केरल में 'राइवन कम्युनिस्ट' श्री नम्बूद्रीपाद मुस्लिम लीग से साँठ गाँठ करने में दक्षिण हैं। भाषा के प्रश्न पर जहर उगलनेवाले श्री फ्रैंक ऐन्टनी के साथ कुछ प्रगतिशील नेताओं ने एक ही बयान पर हस्ताक्षर किये हैं। प्रदेशों में अंग्रेजी के पक्ष में प्रगतिशील अप्रगतिशील एक हो सकते हैं। केवल केन्द्र में अंग्रेजी हटाने के सवाल पर मुरारजी भाई और जनसंघ में सावधान रहना चाहिए।

तमिलनाडु में भाषा का आन्दोलन प्रतिक्रियावादियों के हाथ में था। उन्होंने जनता के तमिल प्रेम से लाभ उठाकर पुस्तकालयों, स्टेशनों और डाकखानों में धाग लगाई। खूब समझ लीजिए यह गृहयुद्ध की भाँति है। उत्तर में मुरारजी भाई आदि अंग्रेजी हटाने का आन्दोलन अपने हाथ में ले रहे हैं। प्रगतिशील नेता टुकुर-टुकुर देख रहे हैं। अंग्रेजी हटाने का आन्दोलन अपने हाथ में लेकर वे उसे प्रतिक्रियावादियों को सौंप रहे हैं।

प्रगतिशील नेता बहुत नैक सर्लाह देते हैं कि हिन्दी भाषी जनता को अन्य राष्ट्रवाद का शिकार न होना चाहिए। सही बात है। हिन्दी जनता का राष्ट्रवाद कैसे जाहिर होता है? जो लोग समझते हैं कि सारे देश में हिन्दी वैसे ही

चलेगी जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी चलती है, यानी जो भारतीय भाषाओं को मिटाना चाहते हैं और राष्ट्रीय एकता का मतलब यह लगाते हैं कि और सब भारतीय भाषाएँ मिट जाएँ, उनकी जगह हिन्दी ही रहे, वे अन्ध राष्ट्रवादी हैं। किन्तु हिन्दी प्रदेशों में किसी ने यह माँग नहीं की कि तमिलनाडु में तमिल को शिक्षा का माध्यम न बनाया जाय, यह माँग नहीं की कि वहाँ या बंगाल या महाराष्ट्र में हर स्तर पर हिन्दी चलाई जाय। इसके विपरीत हुआ यह है कि सभी दलों के नेता प्रादेशिक भाषाओं को उनसे पूर्ण अधिकार देने के पक्ष में हैं। माँग है अंग्रेजी को हटाने की, न कि अहिन्दी भाषाओं को दबाने की। इसलिए केन्द्र से अंग्रेजी को हटाने के सवाल पर हिन्दी साम्राज्यवाद का भय दिखाना वास्तव में अंग्रेजी की सुरक्षा के लिए बहुत घटिया किस्म की कालत करना है।

सरकार क्या करेगी और दूसरी पार्टियाँ क्या करेंगी, ये बड़ी-बड़ी बातें हैं जिन पर इस लेख में कुछ नहीं कहना। मेरी माँग भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से है। आप अपना सारा प्रादेशिक काम भारतीय भाषाओं में कीजिए, एक महीने के अन्दर प्रदेशों में अंग्रेजी भी जड़ काट दीजिए। केन्द्र में अपना काम चाहे हिन्दी में कीजिए चाहे हिन्दी को बिल्कुल न रखिए बल्कि वह काम दस बारह-चौदह अहिन्दी भाषाओं में कीजिए, अगले छह महीनों में अपने केन्द्र से अंग्रेजी का पूर्ण बहिष्कार कीजिए। ऐसा आप कर लें तो मैं समझूँगा कि भारत की भाषा-समस्या हल करने में आपन बहुत बड़ी सक्रिय सहायता दी है। वरना देश जिस विघटन की ओर बढ़ रहा है, उसमें सबसे पहली चोट आप पर होगी और आप यह कहने की हालत में भी न होयें कि चोट गसत पड़ी।

मध्यवर्ग का सहारा लेने के लिए फासिस्टवाद भाषा और संस्कृति का रक्षक बनकर सामने आता है। हिटलर जर्मन भाषा और जर्मन संस्कृति का बहुत बड़ा समर्थक बनकर रंगमंच पर आया था। तमिलनाडु में तमिल-रक्षा का भार द्रविड मुन्नेत्र कळगम पर, उत्तर में हिन्दी-रक्षा का भार जनसंघ पर और दोनों की रक्षा का भार महान् गणराज्य संयुक्त राष्ट्र अमरीका पर। भारत का भावी मानचित्र आपको कैसा दिखाई देता है ?

पहले एक देश में दो देश बने, भारत और पाकिस्तान। अब भारत में दो नये राष्ट्रों का निर्माण होगा, एक हिन्दी राज्य, दूसरा अहिन्दी-राज्य। लेकिन विघटन यही समाप्त न होगा। असम में दूने हिन्दी-भाषियों के खिलाफ न हुए थे। बम्बई में संयुक्त महाराष्ट्र आन्दोलन के दौरान अन्ध राष्ट्रवादियों का क्रोध हिन्दी भाषियों पर न बरसा था। मारे गये वे बंगाली और गुजराती, दोनों अहिन्दी भाषी। तमिलनाडु और आन्ध्र के अनेक शिक्षित जनो में एक-दूसरे के प्रति वही भाव है, जो असमी-बंगालियों, गुजराती-मराठी-भाषियों में है। कश्मीर और नागा प्रदेश में अलगाव के आन्दोलन से सभी लोग परिचित हैं। द्रविड मुन्नेत्र कळगम मूलतः तमिलनाडु को अलग करने का आन्दोलन करता रहा है, हिन्दी विरोध को गहकाने और उससे लाभ उठाने की सूझ-बाद की है। मुस्लिम

लीग के 'डायरेक्ट ऐक्शन' से त्रस्त होकर देशप्रेमी नेताओं ने देश का विभाजन स्वीकार किया। उससे साम्प्रदायिक समस्या सुलभ गई? साम्राज्यवाद को अपने पोजी ग्रंडे बनाने का मौका नहीं मिला? दोजिए तमिलनाडु को भारत-निर्णय का अधिकार! कीजिए कश्मीर और नागा प्रदेश को भारत में मेल। कहिए कि भारत की अखंडता का नारा जनसंघ का नारा है। आपके शासन-निर्णय के अधिकार से साम्राज्यवाद को लाभ होता है या भारत की जनता को?

भारत के मजदूर वर्ग का संगठन प्रदेशों में घट्टेगा नहीं, वह अग्रिम भारतीय स्तर पर होगा। विकास की पंचवर्षीय योजनाएँ अखिल भारतीय स्तर पर बनेंगी और उसी पर सफल होगी। केरल में अन्न की कमी या बेकारी अन्य राज्यों और केन्द्र के सहयोग से ही दूर होगी। राष्ट्रीय विघटन का अर्थ है सबकी हानि, साम्राज्यवाद का लाभ। राष्ट्रीय एकाता का अर्थ है सबका लाभ, साम्राज्यवाद की हानि।

यह राष्ट्रीय एकाता अब अंग्रेजी जाननेवाले डेढ़ फीसदी लोगों के सहारे कायम नहीं रह सकती। अगर केन्द्र में हिन्दी खलाना साम्राज्यवाद है तो अंग्रेजी कायम रखना और भी बड़ा अन्याय है। हिन्दी भाषी जनता इसे कभी सहन न करेगी। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के चाहे जितने आश्वामनो को कानून का रूप दे दीजिए, वे अंग्रेजी की रक्षा नहीं कर सकते।

हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का आन्दोलन यहाँ उन्नीसवीं सदी से हो रहा है। गांधीजी ने हिन्दी-प्रचार को राष्ट्रीय आन्दोलन का अभिन्न भग बनाया। भारत की स्वाधीन हुए अठारह साल हो गए। अब और कितने धीरे? कुछ रफतार निश्चित कर दीजिए। मालूम तो हो जाय कि अठ्ठाईस कोस भी दिन में सँ करने हैं या अठारह दिन में।

एक अजीब बात हिन्दी के पिछड़ेपन के बारे में है। लेनिन ने जारशाही रूस की भाषाओं को पिछड़ा हुआ न पाया। उन्होंने रूसी भाषाओं को राजकाज के लिए माध्यम बनने दिया। चीनी भाषा पिछड़ी हुई नहीं है, माओत्से तुंग और चीनी सरकार के काम आती है। सिर्फ हिन्दी ऐसी पिछड़ी हुई भाषा है और भारत के बुद्धिजीवी ऐसे महान् चिन्तक हैं कि अंग्रेजी के बिना न तो केन्द्रीय सरकार का काम चल सकता है, न किसी पार्टी का अपना राजनीतिक कार्य, विशेषकर उसका केन्द्रीय राजनीतिक कार्य। यह पिछड़ेपन की दलील न केवल हिन्दी भाषी जाति का अपमान है बल्कि अंग्रेजी की गुलामी का सजीव प्रमाणपत्र है।

राज्यों में प्रादेशिक भाषाएँ और केन्द्र में हिन्दी—ये दोनों लक्ष्य एक ही साथ सिद्ध होंगे। ये दोनों लक्ष्य आज सिद्ध हो सकते हैं यदि राजनीतिक पार्टियाँ अपने व्यवहार में इस नीति को अपना लें। बयनी और करनी में भेद होने में कोई समस्या हल नहीं हो सकती। जितना ही विलम्ब होगा, उतना ही विघटन

बढ़ेगा। इसलिए सही नीति के लिए हिम्मत से ग्रान्दोलन करने का समय अभी है, कल न रहेगा।

हिन्दी के लिए धीरे चलो, यह श्रुत है। कहना चाहिए, धीरे तेज चलो। केन्द्र और राज्यों से एक साथ अंग्रेजी हटाओ—यही नारा सही है।

केन्द्र में आप हिन्दी नहीं चाहते, न रखिए। लेकिन अंग्रेजी न चलेगी। उसकी जगह भारत की एक भाषा चलाइए, चाहे दस भाषाएँ। केन्द्रीय सरकार में जो भाषा-नीति आप चनाना चाहते हों, उसे अपनी पार्टी के व्यवहार में लाइए। इसी से हमें विश्वास होगा कि आप ईमानदारी से भाषा-समस्या हल करना चाहते हैं। बरना बातें बनानेवाले नेताओं की हम देश में कमी नहीं है।

(१९६५)

भाषा की समस्या और मजदूर वर्ग

समाज की और दूसरी समस्याओं की तरह भाषा की समस्या पर भी साम्राज्यवादियों, भारतीय पूँजीपतियों और मजदूर वर्ग के विचार अलग-अलग हैं।

अंग्रेजों ने इस देश को जीता। लोगों की इच्छा के विरुद्ध शिक्षा और शासन में अंग्रेजी चलाई। भारतीय भाषाएँ पिछड़ी हुई हैं, वे न शासनतन्त्र के योग्य हैं, न उनमें आधुनिक शिक्षा दी जा सकती है—यह स्थापना ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के प्रतिनिधि लार्ड मैकाले ने शिक्षा सम्बन्धी अपने प्रसिद्ध लेख में की। अंग्रेजों ने विभिन्न भाषाएँ बोलनेवाली जातियों को आपस में लड़ाया। इस लड़ाई से लाभ उठाकर उन्होंने सभी के ऊपर अंग्रेजी का प्रभुत्व कायम रखा। अंग्रेजी की यह गुलामी राजनीतिक पराधीनता का ही एक हिस्सा थी।

राष्ट्रीय आन्दोलन के आरम्भ काल से अंग्रेजी हटाने की माँग स्वाधीनता आन्दोलन का अभिन्न अंग बन गई। गांधीजी ने सितम्बर, १९२१ के 'यंग इंडिया' में लिखा था कि उनके हाथ में तानाशाह की ताकत होती तो वह उसी दिन अंग्रेजी में शिक्षा देना बन्द करा देते और जो अध्यापक इस हुक्म को न मानता, उसे वह नौकरी से हटा देते।

अंग्रेजी से किसी एक भाषा का नहीं, सारे राष्ट्र का ग्रहित होता है। इस बारे में गांधीजी ने ५ जुलाई, १९२८ के 'यंग इंडिया' में लिखा था कि अंग्रेजी ने राष्ट्र की शक्ति का नाश कर दिया है और अंग्रेजी बनी रही तो राष्ट्र की आत्मा का नाश हो जायगा।

भारत में प्रगतिशील साहित्यिक आन्दोलन के जन्मदाता महान् उपन्यासकार प्रेमचन्द्र ने भाषा की गुलामी के बारे में लिखा था, 'जवान की गुलामी ही मसली गुलामी है।' (प्रेमचन्द्र, कुछ विचार, पृ० २२१)।

भारत विभाजित हुआ और स्वाधीन हुआ। आज़ादी मिले एक ही महीना हुआ था कि गांधीजी ने केन्द्र और प्रान्तों से एक साथ अंग्रेजी हटाने की माँग की। २१ सितम्बर, १९४७ के 'हरिजन' में उन्होंने लिखा कि "प्रान्तीय सरकारों २१२/भारत की भाषा-समस्या -

के लिए ऐसे कर्मचारी रखना विलंबित आसान होना चाहिए जो प्रान्तीय भाषाओं और नागरी या उर्दू लिपि में लिखी जानेवाली अन्तर्प्रान्तीय भाषा हिन्दुस्तानी में सारा काम कर सकें।”

गांधीजी की नीति थी कि केन्द्र और राज्यों से तुरन्त और एक साथ अंग्रेजी हटाई जाय। इसलिए उन्होंने प्रान्तीय सरकारों को सलाह दी थी कि वे ऐसे कर्मचारी रखें जो प्रान्तीय भाषा के साथ हिन्दुस्तानी में भी काम कर सकें।

अंग्रेजी हटाने का काम पन्द्रह साल के लिए टाल दिया जाय, इस नीति के वह विरुद्ध थे। जब अंग्रेजी से नुकसान होता है, तब उस क्यों मालमर भी चलने दिया जाय? उनकी राय थी, “इस आवश्यक तब्दीली में, जो एक-एक दिन बीतता है, उससे राष्ट्र की सांस्कृतिक हानि होती है।”

जो लोग कहते थे कि तुरन्त परिवर्तन अमम्भव है उनके बारे में गांधीजी का मत यह था, “हमारे सेक्टेरियटों में भी, कुछ समय बीतने पर तब्दीली होगी, दिमागी काहिली के अलावा और कुछ नहीं है।”

गांधीजी की सलाह थी—दिमागी काहिली खत्म करो, प्रान्तों और दिल्ली से अंग्रेजी को निवालो, भारतीय भाषाओं का व्यवहार करो।

प्रान्तीय सरकारों केन्द्र से अंग्रेजी द्वारा सम्पर्क कायम न रखेंगी, इस बारे में उन्होंने लिखा था, “प्रान्तों का केन्द्र से काम पड़ेगा। यह काम के अंग्रेजी में करने की हिम्मत न करेंगे। केन्द्र में यह जल्द समझने की बुद्धि होती चाहिए कि वह सांस्कृतिक रूप में राष्ट्र पर मुट्ठी भर भारतवासियों का बोझ न डालेगा। ये लोग इसमें आसानी हैं कि उस भाषा को सोखते नहीं जो आसानी से सारे भारत की आम भाषा बन सकती है और जिससे जनता के किसी हिस्से या पार्टी को नाखुशी न होगी।”

गांधीजी की भाषा-सम्बन्धी नीति का निचोड़ यह था, “अंग्रेजी ने जो सांस्कृतिक डकैती की है, उसे खत्म किया जाय।”

केन्द्र और प्रान्तों से तुरन्त अंग्रेजी हटाने के बारे में गांधीजी की जोरदार आवाज हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की सच्ची और सही आवाज थी। वह मजदूर वर्ग के हित में थी।

लेकिन सांस्कृतिक डकैती जारी रही सकती थी जब एक और जनता की तसल्ली दी जाय कि अंग्रेजी हटा दी जाएगी, दूसरी ओर कुछ ऐसे कारण बूढ़ निकाले जाएँ जिससे अंग्रेजी कायम रहे। भारतीय पूँजीवाद एक और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक और राजनीतिक दबाव का विरोध करता था, दूसरी ओर अपने विकास के लिए उससे सहायता भी चाहता था। भारत में ब्रिटिश पूँजी की आमद और ज्यादा हुई, मुनाफा गया वित्तियत को, साथ ही देश में उद्योग धन्यो का निर्माण भी हुआ। पूँजीवाद की इस दुर्गति नीति के अनुरूप उसकी भाषा नीति थी। भारतीय पूँजीवाद की प्रमुख पार्टी—कांग्रेस

भाषा की समस्या और मजदूर वर्ग

—नै यह नीति निकाली कि अंग्रेजी हटाने का बराबर दम भरते रहो लेकिन अमल में किसी-न-किसी बहाने अंग्रेजी कायम रखो ।

पहला बहाना यह था कि हिन्दी पिछड़ी हुई भाषा है । वह अंग्रेजी की जगह ले, इसके लिए उसे विकसित होने का अवसर देना चाहिए । विकास के लिए पन्द्रह साल का अवसर दिया गया ।

यह शुद्ध बहाना था । लोकसभा में सदस्यों को जीव-विज्ञान या भौतिकी पर बहस न करनी थी । लेकिन हिन्दी को समृद्ध करने के लिए बड़े-बड़े कोश रचे जाने लगे । किसी ने यह न देखा कि इन कोशों में बितने पुराने ऐसे शब्द दोहराए जा रहे हैं जो हिन्दी में सन् '४७ से पहले ही प्रचलित थे । किसी ने लोकसभा में यह माँग नहीं की कि हिन्दी कितनी पिछड़ी हुई है, इसकी जाँच के लिए कम-से-कम एक बमौदान तो बिठा दिया जाय ।

अंग्रेजी कायम रखने के लिए दूसरा कारण यह खोज निकाला गया कि वह प्राधुनिक ज्ञान-विज्ञान की भाषा है । अंग्रेजी चली गई तो देश प्राथमिक और वैज्ञानिक प्रगति में पिछड़ जाएगा ।

अंग्रेजी कायम रखने के पीछे एक जानी-बूझी वर्ग-नीति थी । इसे जनता के गले उतारने का काम किया भारत के लोकप्रिय नेता स्वर्गीय प० जवाहरलाल नेहरू ने । अंग्रेजी को निकालने और साथ ही कायम रखने की नीति उन्होंने सितम्बर, १९४६ में संविधान सभा में इस तरह पेश की

“अंग्रेजी चाहे जितनी महत्वपूर्ण भाषा हो, हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे देश में कुछ तो अंग्रेजी पढ़े-लिखे शरीफ लोग हों और आम जनता अंग्रेजी से महकम रहे । इसलिए हमारी अपनी भाषा होनी चाहिए । लेकिन आप इस बात को प्रस्ताव में चाहे लिखें, चाहे न लिखें, अंग्रेजी लाजमी तौर से भारत में बहुत महत्वपूर्ण भाषा बनकर रहेगी जिसे बहुत-से लोग सीखेंगे और शायद उन्हें उसे जबरन सीखना होगा ।”

पाठक १५ सितम्बर, १९४६ के अखबारों में नेहरूजी का यह भाषण पढ़ सकते हैं ।

नेहरूजी ने अपने भाषण में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के भाषा-सम्बन्धी विचारों की भूरि-भूरि प्रशंसा की । फिर अंग्रेजी हटाने की गाँधी-नीति से ठीक उल्टी दिशा में चल दिए ।

नेहरूजी भारी जनतन्त्रवादी थे । बेरल की जनताधिक सार्ववादी सरकार के खिलाफ बेहाद की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी ।

नेहरूवाद और मार्क्सवाद पर्यापवाची शब्द नहीं हैं ।

भारतीय पूँजीवाद की पार्टी—कांग्रेस—न तो राज्यों से, और न केन्द्र से अंग्रेजी हटाने में समर्थ हुई । उल्टा उसकी नीति स अंग्रेजी और अंग्रेजियत की जड़ें पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गईं ।

भारत में भाषावार राज्य बनाने का आन्दोलन चला, हर प्रदेश में उसकी

शिक्षा और संस्कृति का विकास उमड़ी भाषा के माध्यम में हो, यह माँग सही थी। लेकिन आन्दोलन में जितना जोर राज्यों की सीमाओं और क्षेत्रफल पर दिया गया, उतना प्रादेशिक भाषाओं पर नहीं। यह भी पूँजीवादी नीति का ही फल था। नतीजा यह हुआ कि भाषावार राज्य बन गए और इन राज्यों में अंग्रेजी कायम रही।

भाषावार राज्यों का आन्दोलन इस तरह चला कि लोगों के सामने प्रादेशिकता मुख्य और राष्ट्रीय एकता गौण हो गई। इस असमाव की भावना से लाभ हुआ अंग्रेजी को। गुजराती और मराठी-भाषी भाषा में लड़े, अंग्रेजी के समर्थन में दोनों के नेता—विशेष रूप से कामपदा नता—एक साथ रहे। असम में भाषा के सवाल को लेकर भयानक दंग हुए। लड़ाई हुई असमिया-बंगला में। दोनों के ऊपर कायम रही अंग्रेजी।

अंग्रेजी कायम रखने के लिए एक नया बहाना और मिला हिन्दीवाले अहिन्दीवालों को दबाना चाहते हैं। द्रविड़ बळगम ने मारा दिया कि तमिलनाडु भारत से अलग हो। उसने प्रचार किया कि २६ जनवरी, १९६५ से हिन्दी राष्ट्रभाषा हो जाएगी और तमिल का नाश कर देगी। तमिलनाडु के प्रति-विस्थावादी नेताओं ने जनता के सहज तमिलप्रेम से लाभ उठाकर आपत्त बरपा कर दी। जनतन्त्र और राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए अंग्रेजी को कायम रखना आवश्यक हो गया।

सन् '६५ में अंग्रेजी हट न जाय, इसलिये दिल्ली सरकार ने यह कानून बना दिया था कि अंग्रेजी का भी चलन रहेगा। व्यवहार में देखा यह गया कि अंग्रेजी का ही चलन रहेगा। इस तरह भारत की माँवधान सभा के फैसले को बड़े वैधानिक ढंग में भारत के जनतन्त्र-प्रेमियों ने पीरो तले रोड़ा।

पूँजीपतियों ने अलग, अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों के अनुकूल, भाषासमस्या पर मजदूर वर्ग का अपना दृष्टिकोण होना चाहिए। मजदूर वर्ग समाज का सबसे आन्तिमकारी वर्ग है। उसे साम्राज्यवादी विरासत और हमारी गुलामी की प्रतीक अंग्रेजी के खिलाफ सबसे आगे बढ़कर लड़ना चाहिए। अंग्रेजी को हटाने के मामले में वह पूँजीपतियों की टालमटोल नीति का अनुसरण नहीं कर सकता। वह इस दुरंगी नीति पर नहीं चल सकता कि मुँह से कह, 'अंग्रेजी हटाओ', अमल में उस कायम रखे। वह इस दलील को नहीं मान सकता कि भारत की भाषाएँ पिछड़ी हुई हैं, इसलिये अंग्रेजी कायम रहनी चाहिए। उसके सामने लेनिन की मिसाल है जिन्होंने रूसी साम्राज्यवाद का दबाव खत्म करने के लिए खुद अपनी मातृभाषा रूसी को राजभाषा पद से हटा दिया था। फिर विदेशी भाषा अंग्रेजी को हटाने में किसी को सकोच क्यों हो?

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी ने किसी जाति की भाषा को पिछड़ा हुआ न माना। उसने सोवियत प्रजातन्त्रों में और रूसी भाषाओं को राजभाषा

बनाया। हिन्दी पिछड़ी हुई है, उसे अभी विकसित होना है या जनता के निक्ट पहुँचना है, यह माक्सवादियों का तर्क नहीं हो सकता।

मजदूर वर्ग अखिल भारतीय स्तर पर अपनी एकता अंग्रेजी के माध्यम से कायम नहीं कर सकता। यह एकता किसी भारतीय भाषा के द्वारा ही कायम हो सकती है। यह भारतीय भाषा मजदूर वर्ग के नेताओं के अनुसार हिन्दी है। मजदूर वर्ग की एकता खुद उसके लिए ही नहीं, सारे राष्ट्र के लिए जरूरी है। बंगाल-असम में भगड़े बराते हैं पूँजीपति। उनमें एकता स्थापित करता है मजदूर वर्ग। हिन्दी-अहिन्दी के संपर्क को रोक्ने की ताकत मजदूर वर्ग में ही है।

मजदूर वर्ग के साथी हैं किसान। किसान-मजदूर-एकता ही वह शक्तिवारी शक्ति है जो देश को सामाजिक प्रगति की राह पर आगे बढ़ा सकती है। किसान अपना अखिल भारतीय संगठन अंग्रेजी के द्वारा मजबूत नहीं कर सकते। कम्युनिस्ट पार्टी खुद अपने अन्दर बहुत-से किसान-मजदूरों को जगह नहीं दे सकती, क्योंकि अंग्रेजी का प्रभुत्व रहने पर वे न तो पार्टी की ऊँची समितियों के सदस्य हो सकेंगे, न उनकी बहस में ठीक से भाग ले सकेंगे।

इसीलिए मजदूर वर्ग के हित में एक ही भाषा-नीति हो सकती है—राज्यो से और बन्द से, दानो जगह से एक साथ अंग्रेजी हटाओ।

इस नीति पर मजदूर वर्ग सारे देश को लम्बी चला सकता है, जब उसकी अपनी पार्टी—कम्युनिस्ट पार्टी—के दफ्तरों से अंग्रेजी निकले। अंग्रेजी का जुझा खुद अपने बन्धों पर सादकर कम्युनिस्ट पार्टी देश को अंग्रेजी की गुलामी से आजाद नहीं करा सकती।

अब देखना चाहिए कि मजदूर वर्ग की पार्टी और उसके द्वारा संचालित जन-संगठनों में अंग्रेजी की हैसियत क्या है।

स्वर्गीय कामरेड अजय घोष ने सरकारी भाषा-आयोग की रिपोर्ट पर एक नोट लिखा था। उसमें उन्होंने अंग्रेजी की हैसियत के बारे में ये बातें लिखी थीं—

“भाज अधिकांश अखिल भारतीय संगठनों का काम अंग्रेजी में होता है। इनमें किसानों और मजदूरों के संगठन भी शामिल हैं। इसका लाजमी नतीजा यह होता है कि मध्यवर्ग और उच्च मध्यवर्ग के सुशिक्षित लोग ही अखिल भारतीय स्तर पर इन संगठनों के बहस-मुवाहसे में भाग ले सकते हैं। अमल में यही लोग इन संगठनों की अखिल भारतीय कार्य-समितियों के सदस्य बन सकते हैं। जिस किसी को भी जन आन्दोलन का जरा भी तजुर्बा होगा, वह जानता होगा, इससे कितनी कठिनाई पैदा होती है।”

इससे स्पष्ट है कि अंग्रेजी के रहते न तो मजदूर संगठन शक्तिशाली हो सकते हैं, न किसान-मजदूर एकता दृढ़ की जा सकती है।

सांस्कृतिक क्षेत्र में पार्टी के वर्तमान बसलात हुए अजय घोष ने लिखा था,

“देश के सभी भाषों में जनता को किसी एक भारतीय भाषा का अल्पतम आवश्यक ज्ञान कराना होगा जिससे वह भाषा जल्दी-से-जल्दी केन्द्र (यूनिफन) की भाषा बन सके और विभिन्न प्रदेशों की जनता के बीच भी परस्पर आदान-प्रदान का साधन बने। भारत की भाषाओं में जो भाषा सबसे अधिक बोली और समझी जाती है, वह हिन्दी है और इसी के द्वारा यह काम हो सकता है।”

मजदूर वर्ग और उसकी पार्टी का हित इस बात में है कि केन्द्र और प्रदेशों से अंग्रेजी को निवाला जाय। जल्दी-से-जल्दी हिन्दी को भारत सरकार की भाषा तथा पार्टी द्वारा संचालित प्रचलित भारतीय जन संगठनों की भाषा बनाया जाय।

दो वर्ग, दो उद्देश्य, दो भाषा-नीतियाँ स्पष्ट हो जाती हैं। उनका भेद आसानी से देखा जा सकता है।

इस समय कम्युनिस्ट पार्टी की नीति क्या है? राज्यों से अंग्रेजी हटाओ, केन्द्र में आगे चलकर हिन्दी होगी लेकिन फिलहाल वहाँ अंग्रेजी चलने दो।

मालवहादुर शास्त्रीजी और गुलजारीमाल नन्दाजी क्या कहते हैं? वे भी यही कहते हैं। हिन्दी धीरे धीरे आएगी। आएगी जरूर लेकिन अभी तो अंग्रेजी चलने दो। राज्यों में प्रादेशिक भाषाओं के व्यवहार के लिए उन्होंने संविधान बनने के समय से ही पूरी छूट दे रखी है। अब राज्य उस सुविधा का उपयोग न करे तो इसमें शास्त्रीजी और नन्दाजी का क्या दोष।

इस समय भाषा के सवाल पर कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी कोई स्वतन्त्र नीति नहीं है। वह पूँजीवादी पार्टी—काप्रेस—का पिछलगुआ बनकर चल रही है। मोतीलाल शर्माजी जैसे कम्युनिस्ट नेता इस पिछलगुएपन की नीति की पार्टी की स्वतन्त्र नीति कहकर हमस उस पर खूब करने-करो कहते हैं। मुझे तो अंग्रेजी बामम रखने की इस मजदूर-विरोधी, राष्ट्र-विरोधी नीति पर गर्म आती है, उसमें खूब करने की कोई बात नहीं दिखाई देती।

इसके विपरीत अपने एक लेख में मैंने यह नीति रखी है कि पार्टी को केन्द्र और राज्य दोनों से अंग्रेजी हटाने का आन्दोलन करना चाहिए।

मोतीलाल शर्माजी का कहना है कि यह जोर-अबंदस्ती वाला हिन्दी राष्ट्रवादी नारा है। वह कहते हैं कि भाषा की समस्या का जनैतांत्रिक समाधान होना चाहिए।

जनैतांत्रिक समाधान वही है जिसे सन् '४६ में भारत सरकार ने धमल में लाती रही है। यानी भविष्य में हिन्दी, वर्तमान में अंग्रेजी। मोतीलाल शर्माजी भी कहते हैं, भविष्य में हिन्दी ही केन्द्रीय राजभाषा होगी लेकिन अभी अंग्रेजी चलने दो। वह प० जवाहरमाल नेहरू की तरह अंग्रेजी की निन्दा भी करते हैं। कहते हैं—अंग्रेजी के जरिये जो राष्ट्रीय एकता कायम की जाती है, वह अंग्रेजी के समय की औपनिवेशिक एकता से बढ़कर नहीं है। लेकिन उनका धमल

नारा है अंग्रेजी के जरिये अभी यह एकता कायम रहने दो !

जैसे सन् '४७ से पहले सर तेजबहादुर सप्रू बहते थे कि अंग्रेजी राज तो खत्म होना चाहिए लेकिन राजे महाराजे नहीं मानते, अछूत और मुसलमान नहीं मानते, एंग्लोइंडियन नहीं मानते, इसलिए फिलहाल तो अंग्रेजी राज रहेगा ही—वैसे ही सन् '६५ में यह 'फिलहाल' अंग्रेजी चलाने की नीति है।

यदि यह मान लें कि अहिन्दी भाषी जनता अंग्रेजी को नहीं छोड़ना चाहती, तो भी अंग्रेजी का कायम रहना जनतात्रिक नहीं कहा जा सकता। यदि अंग्रेजी को हटाना अहिन्दी-भाषियों के साथ अन्याय है, तो उसे कायम रखना हिन्दी-भाषियों के साथ अन्याय है। जनतन्त्र का मतलब यह नहीं है कि अहिन्दी भाषियों की राय सी जाय और हिन्दी-भाषियों को पूछा ही न जाय।

अहिन्दी भाषियों की राय भी किस जनतात्रिक उपाय से मालूम की गई ? क्या बसें तोड़ना और स्टेशन जलाना लाकमत्त सप्रह का बहुत कारगर तरीका है ?

ब्रिटिश कलमग और स्वतन्त्र पार्टी के लोगो ने धुमांधार प्रचार किया कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा हिन्दी में है। हिन्दी साम्राज्यवाद का होया खडा करके कौशल से उन्होने अंग्रेजी के साम्राज्यवाद की रक्षा की। लेकिन भारतीय भाषाओं को दबानेवाली भाषा हिन्दी नहीं अंग्रेजी है।

इस सम्बन्ध में अजय घोष ने अपने उसी नोट में लिखा था "भाज जब लोग कहते हैं कि इस या उस भाषा से खतरा पैदा हो गया है, तब वे भूल जाते हैं कि देश में जिस भाषा का सचमुच प्रभुत्व रहा है, वह अंग्रेजी है। यह प्रभुत्व न केवल राजनीतिक क्षेत्र में रहा है, वरन् सांस्कृतिक क्षेत्र में भी रहा है। वे भूल जाते हैं कि सांस्कृतिक क्षेत्र में यह प्रभुत्व अब भी बना हुआ है। वे भूल जाते हैं कि भारत के सांस्कृतिक विकास में, हर भारतीय भाषा के विकास में यह प्रभुत्व ही सबसे बड़ी बाधा है और इसलिए उसे दूर करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है।"

इससे ठीक उल्टी राय योगीन्द्र शर्माजी की है। उनकी दलील है कि अंग्रेजी की जगह हिन्दी आई तो भारतीय भाषाओं का दमन होगा। उन्होंने जोशीले ढंग से अपने लेख में पूछा है—

"क्या कोई भी सच्चा देशभक्त, सच्चा जनतन्त्र प्रेमी इसको स्वीकार कर सकता है जिस तरह अभी तक—अंग्रेजी भारत की तमाम भाषाओं का दमन और दहन करती रही, उसी तरह उस काम को अब हिन्दी करे ?"

उन्होंने यह नहीं बताया कि सविधान की किस धारा के अनुसार हिन्दी तमिलनाडु से तमिल को बाहर कर देगी।

उनकी राय है कि अंग्रेजी की तरह हिन्दी भी तमाम भाषाओं का दमन न करे, इसलिए अंग्रेजी को ही यह दमन करने दिया जाय।

हिन्दी से भारतीय भाषाओं को खतरा है, यह साबित करने के लिए उन्होंने

‘कम्युनिस्ट’ में प्रवासित सन् ‘४६’ वाले मेरे पुराने लेख को ढूँढ़ निवाला है। इस लेख को उन्होंने अतिवादी और अराजकतावादी कहा है और उसी से उन्होंने हिन्दी का खतरा भी साबित कर दिया है !

सन् ‘४८’ में कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी कांग्रेस ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में भारत के बड़े पूँजीपतियों को उत्पीड़न वर्ग कहा था। उस स्थापना से यही नतीजा निकलता था कि बड़े पूँजीपतियों की सरकार केन्द्रीय राजभाषा के जरिये प्रदेशों का दबाना चाहती है। कम्युनिस्ट पार्टी ने यह मान्यता बदल दी है। क्या योगीन्द्र शर्माजी अभी भी समझते हैं कि सरकार बड़े पूँजीपतियों की सरकार है और ये बड़े पूँजीपति साम्राज्यवादी हैं ? यदि नहीं तो बतलाएँ कि हिन्दी के खतरे का ठोस सामाजिक आधार क्या है।

अंग्रेजी हटाने का विरोध साम्राज्यवाद के खुले और छिपे समर्थक स्वतन्त्र पार्टी और द्रविड़ कळगम के नेता करते हैं। हिन्दी द्वारा अहिन्दी भाषाओं के दमन का होना वे लक्षा में रखते हैं। योगीन्द्र शर्माजी भी उनमें प्रचार में शामिल हो गए हैं।

अंग्रेजी कायम रखने के लिए एक विभिन्न ढंग से विशाल राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा बन गया है। इस मोर्चे में स्वतन्त्र दल के नेता हैं, द्रविड़ कळगम वाले हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के अनेक नेता भी इसमें हैं। लेकिन यह मोर्चा बना है बालू की भीत पर। उसमें पीछे भारत के किसानों और मजदूरों की ताकत नहीं है। वह ज्यादातर बाबू लोगों का संयुक्त मोर्चा है। इनमें कुछ तो अंग्रेजी पढ़े हैं और बाकी बिना पढ़े ही उसका समर्थन करते हैं। खास बात यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी की दोनों शाखाएँ इस संयुक्त मोर्चे में शामिल हैं।

अहिन्दी-भाषी क्षेत्र के बाबूओं का डर है कि अंग्रेजी खो गई तो अखिल भारतीय नौकरियाँ हिन्दीवाले हाथों लेंगे। अखिल भारतीय नौकरियों की समस्या पूरे मध्यवर्ग की समस्या नहीं है। कुछ थोड़े-से तेज लोग—जो हर मानी में तेज होते हैं—ये नौकरियाँ पाते हैं। बाकी उम्मीदवार नाउम्मीद होकर कहीं मास्टरी या क्लर्क करते हैं या बेकारी में जपसँ चटवाते हुए घूमते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी अपनी भाषा नीति इन मुट्ठी-भर पढ़े-लिखे बाबूओं की राय से निर्धारित नहीं करती। उसके सामने होना चाहिए किसानों और मजदूरों का हित।

वास्तव में मध्यवर्ग का हित भी अंग्रेजी कायम रखने में नहीं है। निम्नान्वे की सदी अंग्रेजी-पढ़े बाबूओं को छोटी मोटी नौकरियों से ही संतोष करना पड़ता है। लाखों की तादाद में वे हर साल अंग्रेजी के कारण फेल होते हैं। अंग्रेजी के कारण शिक्षा उनके लिए हर तरह से महँगी पड़ती है। अखिल भारतीय नौकरियों के लिए अंग्रेजी आवश्यक है, इसलिए राज्यों में भी अंग्रेजी चलती है। पल भुगतना पड़ता है तमाम निम्न मध्यवर्ग की गरीब जनता को।

भाषा की समस्या और मजदूर वर्ग ।

जब तक केन्द्र में अंग्रेजी चलती है, तब तक राज्यों से अंग्रेजी की जड़ नहीं कट सकती। राज्यों में अंग्रेजी की पतियाँ मोचने से उसकी केन्द्रीय जड़ पर कोई असर न पड़ेगा। पिछले सोलह साल का अनुभव यही सिद्ध करता है। केन्द्र के कारण ही राज्यों में अंग्रेजी का प्रभुत्व है। इससे तमिलनाडु में अभी तक तमिल उच्च शिक्षा का माध्यम नहीं बन पाई।

जो लोग अखिल भारतीय नीकरियों के उम्मीदवार हैं, उनका भय भाषानी से दूर किया जा सकता है। यह नियम बनाना चाहिए कि अखिल भारतीय नीकरियों के लिए एक अहिन्दी भाषा सीखना अनिवार्य होगा। अहिन्दी भाषा का समुचित ज्ञान अनिवार्य कर देने से हिन्दीवालों को कोई विशेष सुविधा न मिलेगी। पार्टी इस नियम के लिए और अंग्रेजी हटाने के लिए एक साथ आन्दोलन कर सकती है। लेकिन नीकरियों की समस्या हल न कर पाने के कारण केन्द्र में अंग्रेजी कायम रखने की बात करना मार्क्सवाद को ठुकराकर मध्यवर्ग के बाबुओं का दृष्टिबोध प्रदाना है।

अंग्रेजी कायम रखने में भारत के किसी वर्ग का हित नहीं है—न मजदूर वर्ग का, न किसानों का, न शहरों के मध्यवर्ग का। अंग्रेजी से न अहिन्दी प्रदेश का हित होता है, न हिन्दी प्रदेश का। उससे केवल साम्राज्यवादियों का हित होता है। ब्रिटिश और अमरीकी पूंजीपति हमारे अर्थतन्त्र पर हर तरह से प्रभाव डालते हैं। उनके आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव को रद्द करने का साधन है—अंग्रेजी का प्रभुत्व। वे करोड़ों रुपये तब तक तरह से यहाँ अंग्रेजी के प्रचार और प्रसार पर खर्च करते हैं। अंग्रेजी को कायम रखना 'जनतन्त्र' के नाम पर साम्राज्यवाद की सेवा करना है।

अंग्रेजी हटाने का सवाल राष्ट्रीय एकता के प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है। भारत बहुजातीय राष्ट्र है। भारतीय भाषाएँ बोलनेवाली विभिन्न जातियाँ ब्रिटेन और फ्रांस की तरह एक-दूसरे से अलग स्वतन्त्र जातियाँ नहीं हैं। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक सूत्रों से बंधी हुई वे एक ही राष्ट्र का अविभाज्य अंग हैं। जिस तरह हर प्रदेश में उसकी अपनी भाषा को सभी अधिकार मिलने चाहिए, वैसे ही इन सबको जोड़नेवाली राष्ट्रभाषा हिन्दी को भी केन्द्र में पूर्ण अधिकार मिलने चाहिए।

जो लोग अंग्रेजी हटाने का विरोध करते हैं, वे राष्ट्रीय एकता का विरोध करते हैं। विभिन्न प्रदेशों की जनता एक-दूसरे के नजदीक हिन्दी के जरिये ही आ सकती है। अंग्रेजी के जरिये पढ़-लिखा बाबूवर्ग दिन-पर-दिन साधारण जनता से दूर होता जा रहा है।

पिछले पन्द्रह साल में अंग्रेजियत बढ़ी है और उसके साथ भारतीय भाषाओं की उपेक्षा आम तौर से, और हिन्दी की उपेक्षा खास तौर से, बढ़ी है। यह उपेक्षा हिन्दी और अहिन्दी दोनों क्षेत्रों में है। डेंडी, मम्मी और अकलजी का चलन हिन्दी बाबुओं के घर में पिछले वर्षों ज्यादा हुआ है। अमरीकी-

साहित्य के नक्कालों की हिन्दी में अंग्रेजी के अप्रच शब्दों की बाढ भा गई है।

हिन्दी की उपेक्षा कांग्रेस में ही नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी में भी है—हमें इस कटु सत्य का सामना करना चाहिए। आज से इक्तीस साल पहले प्रेमचन्द ने हमारे नेताओं के अंग्रेजी-प्रेम की अच्छी तरह परखा था और उसकी तीखी आलोचना की थी। बम्बई के राष्ट्रभाषा-सम्मेलन में उन्होंने कहा था—

“हमारी बीबी सभाओं में सारी कार्रवाई अंग्रेजी में होती है, अंग्रेजी में भाषण दिये जाते हैं, लेख लिखे जाते हैं, प्रस्ताव पेश किये जाते हैं, सारी लिखा-पढ़ी अंग्रेजी में होती है, उस सभा में भी, जो अपने को जनता की सभा कहती है। यहाँ तक कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट भी, जो जनता के आमुलजात फंडे-बंददार हैं, सभी कार्रवाई अंग्रेजी में करते हैं।”

प्रेमचन्द की आलोचना का कोई असर कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं पर नहीं हुआ। वे जहाँ सन् '३४ में थे, वहीं सन् '६५ में हैं। इस स्थिति पर कौन गवें कर सकता है ?

प्रेमचन्द ने बहुत सही सवाल उठाया था कि पार्टियाँ अपनी कार्रवाई किस भाषा में करती हैं। यही सवाल अपने एक लेख में मैंने भी उठाया था।

मेरा अनुभव है कि राज्यों में कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता अपने मसौदे अंग्रेजी में तैयार करते हैं। अक्सर राज्यों के पत्रों में उनके अंग्रेजी लेखों के अनुवाद छपते हैं। योगीन्द्र शर्माजी का कहना है कि राज्यों में पार्टी का सारा काम प्रादेशिक भाषाओं में होता है। उसका स्वागत करता हूँ। पार्टी के नेताओं को यथाई देता हूँ कि कम-से-कम राज्यों में उन्होंने पहल की और दूसरी पार्टियों के सामने एक आदर्श रखा।

लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी अपने केन्द्रीय दफ्तर से अंग्रेजी क्यों नहीं निकाल पाती ? इसका मूल कारण है, स्वयं पार्टी के नेताओं में हिन्दी के प्रति उपेक्षा का भाव।

यदि प्रकृति भारतीय स्तर पर मजदूर वर्ग की एकता हिन्दी के जरिये ही कायम हो सकती है, तो हिन्दी की यह उपेक्षा मजदूर वर्ग की ही उपेक्षा है।

बामरेड गोपालन लोकसभा से बाहर चले गए क्योंकि कोई मन्त्री हिन्दी में बोला था। उनका मजदूर-प्रेम हिन्दी से चिढ़ता है, अंग्रेजी को सिर धड़ता है। बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की दोनों शाखाओं ने विधान सभा में कांग्रेस के साथ मिलकर हिन्दी के विरुद्ध प्रस्ताव पास किया, केन्द्र में अंग्रेजी उन्हें सप्रेम स्वीकार है !

पार्टी के नेता जो सिर्फ राज्यों से अंग्रेजी हटाने की बात करते हैं, इसका नाराण हिन्दी के प्रति यही उपेक्षा-भाव है। मराठी, बंगला, तमिल के चलन की बात तो वे कर सकते हैं, हिन्दी के चलन की बात कैसे करें ?

कहा जा सकता है कि हिन्दीभाषी क्षेत्र में कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर है, इसलिए पार्टी-केन्द्र में हिन्दी का चलन नहीं है।

लेकिन भारत का वह अंग्रेजी भाषी क्षेत्र कौन सा है जहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलन मजबूत होने से पार्टी केन्द्र में अंग्रेजी चलती है ? वह अंग्रेजी-भाषी क्षेत्र ऊपर के कुछ नेताओं तक सीमित है । भारत की घरती से उखड़ा हुआ यह क्षेत्र त्रिशकु की तरह आसमान में लटका हुआ है । इस हवाई क्षेत्र की भाषा—अंग्रेजी—पार्टी केन्द्र में चल सकती है । भारत की एक तिहाई जनता की भाषा हिन्दी नहीं चल सकती ।

कम्युनिस्ट पार्टी के वोटरो म जो पिछतर की सदी अहिन्दी भाषी हैं, उनमें अंग्रेजी जाननेवाले एक की सदी भी नहीं हैं । फिर भी पार्टी केन्द्र में चलेगी अंग्रेजी !

हमारे आन्दोलन के विकास और फैलाव की वह कौन-सी विशेषता है जिससे अंग्रेजी भाषी न होते हुए भी हमारे नेता बंदरिया के मुँह बच्चे की तरह अंग्रेजी को छाती से चिपकाये हुए हैं ? वह विशेष अवस्था है, हिन्दी की उपेक्षा ।

इस स्थिति से लाभ उठाते हैं जनसभ के नेता । वे जनता की सही माँगों का समर्थन करके अपनी जन-विरोधी नीति के लिए लोकप्रियता हासिल करते हैं । उनका उद्देश्य होता है, पूँजीवाद को मजबूत करना, तटस्थता की नीति खत्म करके भारत को साम्राज्यवादी खेमे में ढकेस देना ।

केन्द्र में अंग्रेजी कायम रखना समस्त भारतीय जनता के साथ अन्याय है, हिन्दी भाषी जनता के साथ विशेष अन्याय है । अंग्रेजी चालू रखने की नीति का समर्थन करके कम्युनिस्ट पार्टी हिन्दी-भाषी जनता में अपना प्रभाव बढ़ाएगी, कम्युनिस्ट आन्दोलन को आवश्यकतानुसार शक्तिशाली नहीं बना सकती ।

पिछले वर्षों का अनुभव बतलाता है कि जनता के असन्तोष से लाभ उठाकर प्रतिक्रियावादी दलों ने अपनी ताकत जितना बढ़ाई है, उतना कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं । तब कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त थी, अब विभक्त है । सोच लीजिए, क्या नतीजा होगा ।

अंग्रेजी के विरुद्ध हिन्दी जनता के असन्तोष को दक्षिण और बंगाल की ओर मोड़ना बहुत आसान है । जैसे कुछ लोग तमिल-प्रेम को हिन्दी विरोध का रूप देते हैं, वैसे ही हिन्दी प्रेम को तमिल विरोध का रूप देना मुश्किल नहीं है । गृहयुद्ध की इस परिस्थिति में अंग्रेजी के बल पर राष्ट्रीय एकता की रक्षा नहीं की जा सकती ।

समस्या का एक ही हल है केन्द्र में हिन्दी हो, राज्यों में प्रादेशिक भाषाएँ ।

इस पर भी यदि कोई कहे कि अंग्रेजी हटाने से अहिन्दी भाषाओं का दमन होता है तो निवेदन है, लोकसभा में सभी भाषाएँ चलाइए । हमें इस बात का भ्रम नहीं है कि भारत सरकार का काम हिन्दी में हो । घुणा इस बात से है कि उसका काम अंग्रेजी में होता है । केन्द्र में चाहे एक भारतीय भाषा चलाइए, चाहे दस, विदेशी भाषा अंग्रेजी को निकालिए ।

मैंने योगीन्द्र शर्माजी से पूछा था, 'पार्टी दफ्तर में सभी भारतीय भाषाओं

का चलन करने में क्या व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं ?”

उन्होंने उत्तर दिया है, “पार्टी के केन्द्रीय दफ्तर में अंग्रेजी की जगह सभी भारतीय भाषाओं को बराबर जगह देने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ अवश्य हैं। व्यावहारिक कठिनाइयों में मुख्य कठिनाई है बहुभाषी स्टाफ तैयार करने की—तमाम भारतीय भाषाओं से अनुवाद करने की व्यवस्था की।”

पार्टी-केन्द्र में हिन्दी इसलिए नहीं चलती कि हिन्दी-प्रदेश में कम्युनिस्ट भ्रान्दोलन कमजोर है। अनेक भारतीय भाषाएँ इसलिए नहीं चल सकती कि उपयुक्त स्टाफ नहीं है। इसलिए अंग्रेजी की गुलामी से पार्टी-केन्द्र मुक्त नहीं हो सकता।

योगीन्द्रजी ने मुझे आश्वासन दिया है कि लोगों को तमाम भाषाओं में बोलने की आजादी है। केन्द्रीय दफ्तर में तमाम भाषाओं में चिट्ठियाँ, रिपोर्टें आदि आती हैं। अविध्य में पार्टी केन्द्र की भाषा हिन्दी ही होगी लेकिन जहाँ तक वर्तमान का सम्बन्ध है, उन्हीं के शब्दों में—“तमाम भारतीय भाषाओं की इस आजादी और बराबरी के बावजूद ‘फिलहाल’ अंग्रेजी प्रधान और सम्पर्क-भाषा है।”

असली समस्या इसी ‘फिलहाल’ की है।

पार्टी के जो नेता अपने केन्द्र से अंग्रेजी निकालने में असमर्थ हैं, वे भारत में अंग्रेजी का प्रभुत्व कभी खत्म नहीं कर सकते।

हिन्दी-भाषी जनता से भड़कानेवाले कहते हैं, यह उत्तर और दक्षिण की लड़ाई है। दक्षिणवाले हिन्दी नहीं चाहते तो उन्हें उत्तर भारत से निकाल दो।

इस गृहयुद्ध की नीति के खिलाफ ‘धर्मयुग’ ने अपने लेखों में मैंने हिन्दी-भाषी जनता के सामने यह कार्यक्रम रखा है लड़ाई तमिल हिन्दी की नहीं है, लड़ाई तमाम भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी की है। इस संघर्ष में हम हिन्दी-भाषियों को पहले करनी चाहिए। हम अपने हिन्दी भाषी राज्यों में हर जगह, हर स्तर पर हिन्दी को प्रमत्त में राजभाषा बनाना चाहिए। हमें अपने नेताओं को बाध्य करना चाहिए कि वे लोकसभा में हिन्दी में बोलें। भारत की एक-तिहाई जनता के प्रतिनिधि केन्द्र और राज्यों में अपना सारा काम हिन्दी में करेंगे तो हिन्दी बहुत जल्दी राष्ट्रभाषा बन जाएगी।

इस कार्यक्रम के विपरीत हिन्दीभाषी जनता से कहना कि केन्द्र में अंग्रेजी कायम रहने दो, उसे तमिल-विरोध की ओर बढ़ने की राह देना है। कांग्रेस सरकार की भाषा-नीति से दुरूप हिन्दी-भाषी जनता के सामने जब अंग्रेजी से लड़ने की नीति न रहेगी, तब वह अहिन्दी-भाषियों के खिलाफ जरूर भड़काई जाएगी।

मैं हिन्दी क्षेत्र के नेताओं से भी लोकसभा में हिन्दी बोलने को कहता हूँ तो योगीन्द्र शर्माजी को लगता है कि मैं अहिन्दी भाषियों पर हिन्दी लादने की बात कर रहा हूँ। अंग्रेजी को हटाने की सलाहकार उन्हें गृहयुद्ध की सलाहकार

मालूम होती है !

लोकसभा में अहिन्दी-भाषी नेता शौक से अपनी अपनी भाषाएँ बोल । हिन्दी-भाषी नेता हिन्दी में बोलें । कम्युनिस्ट सदस्य लोकसभा में अपने व्यवहार से इस नीति की मिसाल कायम करें ।

लेकिन हमारे पार्टी-नेता अंग्रेजी में बोलना पसन्द करते हैं । लोकसभा में सभी भारतीय भाषाओं में बोलने की सुविधा के लिए नहीं लड़ते । लड़ें कैसे जब उनके अपने केन्द्र में अंग्रेजी चलती है ।

साम्राज्यवादी प्रचारक कहते थे कि भारतीय भाषाएँ पिछड़ी हुई हैं, इसलिए अंग्रेजी चलेगी । इस प्रचार का नया रूप यह है हिन्दी जनता से दूर चली गई है, पड़िताऊ हो गई है, रघुवीरो है, इसलिए अंग्रेजी चलेगी ।

यदि मान भी लें कि डॉ० रघुवीर इतने बड़े सूरमा थे कि भारतेन्दु से लेकर प्रमोदलाल नागर तक चली आती हिन्दी की प्रशस्त धारा को मोड़कर उन्होंने उसे पड़िताऊ बना दिया तो क्या इससे अंग्रेजी का कायम रहना उचित हो जाएगा ?

मजे की बात यह है कि राज्यों में हिन्दी चल सकती है । कठिनाई पैदा होती है, उसके दिल्लीवाले दफ्तरों में घुसने पर ।

साम्राज्यवादी प्रचारक हिन्दी-उर्दू को लड़ाकर अंग्रेजी का पाया मजबूत करते थे । उस नीति का नया रूप यह है हिन्दी ने अपनी बहन और सहेली उर्दू का दमन किया है, उसे अपने ही घर से निकाल दिया है । इसलिए केन्द्र में अंग्रेजी चलनी चाहिए ।

'जनशक्ति' और 'जनयुग' के उर्दू-संस्करण निकालिए । इच्छा हो तो दोनों में एक ही भाषा 'हिन्दुस्तानी' चलाइए । पटना और लखनऊ के पार्टी-दफ्तरों में हिन्दी-उर्दू दोनों को बराबर जगह दीजिए । लेकिन उर्दू-दमन के विरोध के नाम पर अंग्रेजी चलाने की कोशिश मत कीजिए ।

केन्द्र और राज्यों से एक साथ अंग्रेजी हटाने की माँग करना उग्र हिन्दी राष्ट्रवाद के उन्माद में आत्मविभोर होना नहीं है । उग्र हिन्दी राष्ट्रवाद का नारा है एक भाषा, एक राष्ट्र । मेरी नीति इससे बिल्कुल उल्टी है । उस नीति का मूल सूत्र यह है भारत बहुजातीय राष्ट्र है । बहुजातीय है, इसलिए राज्यों में वहीं की भाषाएँ राजभाषा होंगी, राष्ट्र है, इसलिए सब जातियों को मिलानेवाली केन्द्रीय भाषा हिन्दी होगी । इन दोनों बातों में किसी एक को भूल जाना राष्ट्रीय विघटन को बुलावा देना होगा । (१९६५)

भारत की राजभाषा अंग्रेजी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा

योगीन्द्र शर्माजी ने ठीक लिखा है कि सिद्धान्त और नीति की जो बातें मैंने उठाई हैं, उनकी व्यवहेतना नहीं की जा सकती और वे बातें अपने-आप में भी महत्वपूर्ण हैं। इस विषय पर मैं जो कुछ भागे लिख रहा हूँ, पाठक उसे नीति और सिद्धान्त का आवश्यक विवेचन समझकर पढ़ेंगे।

अंग्रेजी के प्रभुत्व से हानियाँ

योगीन्द्र शर्माजी मानते हैं कि अंग्रेजी का प्रभुत्व कायम रहने से हानि होती है। इस हानि से देश को बितने बड़े सकट का सामना करना पड़ सकता है, मजदूर वर्ग और कम्युनिस्ट पार्टी से इस हानि का सम्बन्ध क्या है, इस बारे में उनका और मेरा विस्तरेण एक-सा नहीं है।

उनका कहना है, "अंग्रेजी के आधार पर भारत की एकता वैसी ही होगी जैसी अंग्रेजी सामन के मातहत थी।"

इतना कहना काफी नहीं है। अंग्रेजी के आधार पर आज भारतीय पूँजीवाद औपनिवेशिक एकता भी कायम नहीं रख सकता।

साम्राज्यवाद फौज, पुलिस और अंग्रेजी जाननेवाले नौकरसाह वर्ग के द्वारा जनता का शोषण करने के लिए उपनिवेश भारत की एकता कायम किये हुए था। अब नौकरसाह वर्ग का मानिक है भारतीय पूँजीवाद जिसमें बाजारों के लिए सहनेवाले विभिन्न प्रदेशों के पूँजीपति हैं तथा इनमें कुछ इजारेदार हैं, शेष ग़ैर-इजारेदार पूँजीपति हैं। इन अन्तर्विरोधों से पीड़ित पूँजीवाद औपनिवेशिक एकता की रक्षा नहीं कर पा रहा है। उसकी अस्तित्व भारतीय पार्टी में भयानक गुटबन्दी है और उसका सामाजिक आधार दिन-पर-दिन सङ्कुचित होता जा रहा है।

योगीन्द्र शर्माजी जानते हैं कि भारत का पूँजीपति वर्ग "विभिन्न भाषा-समूहों में बँटा हुआ है, विभिन्न जातियों में विभक्त है। वह एक-दूसरे की नीमत पर अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है।" इसीलिए वह अंग्रेजी के सहारे

देश की पुरानी औपनिवेशिक एकता को भी बचा नहीं पा रहा ।

देश की एकता पूँजीपति वर्ग के हित में है । योगीन्द्रजी का कहना है, "पूरे देश के बाजार और राजशक्ति की आवश्यकता उनको राष्ट्रीय एकता का हिमायती बनाती है ।" भारतीय इतिहास के अनुभव को सभी लोग जानते हैं कि यहाँ के पूँजीपति वर्ग ने साम्राज्यवादी योजना स्वीकार की और 'पूरे देश के बाजार' को अपने वर्ग-हितो के विरुद्ध, बँट जाने दिया ।

देश की एकता की रक्षा के लिए पूँजीपति वर्ग की एकता का भरोसा न करके श्रमिक जनता की एकता दृढ़ करनी चाहिए । यह एकता अंग्रेजी के जरिये दृढ़ नहीं की जा सकती । अंग्रेजी का प्रभुत्व इस एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है । अंग्रेजी के बाधम रहने से भारतीय जनतन्त्र का आधार सङ्कुचित होता है और फासिस्टवाद का खतरा बढ़ता है ।

'भाषा और समाज' में मैंने लिखा था •

"एक छोटा सा वर्ग जो अंग्रेजी आधार पढ़ता है, अंग्रेजी के माध्यम से मौकरी पाता है अंग्रेजी के माध्यम से पार्लामेण्टरी डिमोक्रेसी और सोशलिस्ट पैटर्न के प्रयोग करता है वही 'नेहरू के बाद क्या होगा'—यह समस्या उठाकर परेशान भी हो लेता है" जनतन्त्र का यह सङ्कुचित वर्ग-आधार खुद तो नष्ट होगा ही, खतरा यह है कि अपने विनाश के साथ वह देश की बागडोर किसी अशुभ शक्ति को न सौंप दे ।" (पृ० ४१५)

इस देश में हर चीज के लिए आन्दोलन होते हैं । भाषावार राज्यों के आन्दोलन में कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी । केवल केन्द्र से अंग्रेजी हटाने का आन्दोलन नहीं होता, केवल इस तरह का आन्दोलन पार्टी के नेताओं को पसन्द नहीं है । इसका कारण यह है कि संयुक्त महाराष्ट्र या विशाल आन्ध्र के निर्माण को वे जितना आवश्यक समझते थे, उतना अंग्रेजी के प्रभुत्व को खरम करना नहीं ।

मैंने लिखा था, "अंग्रेजी सीखना और बात है, उसे सीखकर लाभ उठाया जा सकता है लेकिन उसे सभी भारतीय भाषाओं के ऊपर केन्द्रीय और सांस्कृतिक भाषा बनाने से ऐसे वर्ग का ही सृजन होगा जो जनता से दूर होगा, जो अंग्रेजी ज्ञान के बल पर—न कि ईमानदारी, देशभक्ति, कार्यक्षमता के बल पर—शासनकार्य चलाएगा । इससे देश की अपार क्षति होगी और हो रही है ।" (उप०, पृ० ४५३)

स्पष्ट है, अंग्रेजी से होनेवाली हानि के बारे में योगीन्द्रजी के और मेरे विचारों में अन्तर है ।

कांग्रेस और अंग्रेजी

दश में जो भाषा-सम्बन्धी द्वेषभाव फैला है, उसके लिए सबसे पहले कांग्रेसी नेता जिम्मेदार हैं । उन्होंने भाषावार राज्यों का विरोध किया और अपने वक्तव्यों

मे प्रादेशिक भाषाओं को उचित महत्त्व नहीं दिया—यह स्थिति का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि सन् '४६ से अब तक तरह-तरह के बहाने करके वे अंग्रेजी का प्रमुख कायम किये हुए हैं। इस दूसरे पहलू पर योगीन्द्रजी का ध्यान कम जाता है।

मुख्य अन्तर्विरोध हिन्दी और अहिन्दी भाषाओं में नहीं, अंग्रेजी तथा समस्त भारतीय भाषाओं में है। कांग्रेसी नेताओं ने जहाँ भी केन्द्र में हिन्दी चलाने की बात की, योगीन्द्रजी उनकी सख्त आलोचना करते हैं। वे अठारह साल से अंग्रेजी चला रहे हैं, इसकी मस्त आलोचना वह नहीं करते।

उन्होंने लिखा है, “केन्द्रीय सरकार ने २६ जनवरी से हिन्दी को ‘राष्ट्रभाषा’ बनाने की जो पालख और चक्रवाते की घोषणा की, उससे गैर-हिन्दीभाषी लोगों में, विशेषकर तमिलनाडु में विरोध का तूफान पैदा हो गया।”

कांग्रेस के वर्णधार चाहते हैं कि अंग्रेजी न भाज हटे, न कल। हिन्दी-भाषी जनता से ही कांग्रेस को सबसे ज्यादा बोट मिलते हैं। उसे खुश करने के लिए वे राष्ट्रभाषा की बातें करते हैं, हिन्दी को समृद्ध करने के लिए लाखों रुपये खर्च करते हैं। उनके इस पालख पर योगीन्द्रजी को विशेष क्रोध नहीं आता।

योगीन्द्र शर्माजी के विपरीत हर मजिल पर मैंने कांग्रेसी नेताओं के इस पालख की बराबर आलोचना की है।

सन् '४६ में मैंने लिखा था -

“भारतीय जनता न माँग की थी कि शिक्षा, अदालत-कचहरी शासन इत्यादि में अंग्रेजी की जगह उसकी अपनी भाषा चल। यह बिल्कुल न्यायपूर्ण माँग थी। राष्ट्रीय नेताओं से आशा की जाती थी कि सन् '४७ में आजादी पाने के बाद इस माँग को वे पूरा करेंगे। लेकिन विभिन्न कारणों में वे उसे पूरा नहीं कर सके—दस साल तक उद्योग-धन्यो का राष्ट्रीयकरण न होगा। वैसे ही पाँच या दस साल तक ग्राम जनता की उच्च शिक्षा, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यवाही उसकी अपनी भाषा में न होगी” (‘कम्पुनिस्ट’)

पाँच साल बाद राजभाषा के सवाल पर मैंने एक पुस्तिका लिखी जो पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित हुई। उसमें कांग्रेसी नेताओं की दुरगति नीति के बारे में मैंने लिखा था, ‘कांग्रेसी नेताओं की कोई मशा नहीं थी कि अंग्रेजी हटाने के लिए जमकर कोशिश करें। उन्होंने स्पष्ट ही अपने सामने यह सभावना रखी थी कि पन्द्रह साल के बाद भी अंग्रेजी जारी रहेगी, शायद उसके अगले पन्द्रह साल तक जारी रहेगी, हो सकता है इसके आगे भी जारी रहे।”

सन् '६५ में बिल्कुल यही स्थिति हमारे सामने है।

नेहरूजी के अंग्रेजी समर्थन की चर्चा करते हुए उसी पुस्तिका में लिखा था, “सविधान सभा में बहुमती तमाम सरगर्मियों के पीछे यह निर्णय निश्चय साफ दिखाई देता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की हानि करते हुए अंग्रेजी को अनिवार्य राजभाषा के रूप में चालू रखा जाय। श्री नेहरू ने बड़ी स्पष्टता से

कहा है कि 'भाषा इस बात को प्रस्ताव में लिखें, चाहे न लिखें, अंग्रेजी लाजमी तौर से भारत में बहुत महत्वपूर्ण भाषा बनकर रहेगी जिसे बहुत लोग सीखेंगे और शायद उन्हें उसे जबरन सीखना होगा।' लोग इन तमाम वपों में अंग्रेजी जबरन सीखते आए हैं। अब उनके सामने एकमात्र यह सम्भावना पेश की गई है कि अंग्रेजी के बिना हमारी कला और विज्ञान का पतन हो जाएगा और देश का विघटन होगा, उसका नाश हो जाएगा।"

'भाषा और समाज' में मैंने जहाँ भाषावार राज्य आन्दोलन के दमन की निन्दा की है, वहाँ अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाये रखने की कांग्रेसी नीति की आलोचना भी की है। लिखा था :

"अंग्रेजी भारत की राष्ट्रभाषा रहे तो सबसे अच्छा। दूसरे देशों के सामने शर्म के मारे उसे राष्ट्रभाषा न बहू सकें और भूल मारकर हिन्दी का व्यवहार करना पड़े तो अंग्रेजी और हिन्दी दोनों को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहिए। यदि हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा रखने की प्रतिज्ञा करनी पड़े तो भी जहाँ तक हो सके, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यों के लिए अंग्रेजी का व्यवहार होना ही चाहिए" भारत को आजाद करने की मुख्य प्रेरणा अंग्रेजी से ही मिली लेकिन आजादी पाने के लिए भी अंग्रेजी की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अब समाजवादी भारत के निर्माण के लिए है।" (पृ० ४१३)

पिछले अठारह साल में कांग्रेस की जो नीति रही है, उसी का अनुसरण करते हुए उसके नेताओं ने नया प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव के अनुसार प्रादेशिक भाषाएँ पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं का ऐच्छिक माध्यम बनेंगी, अखिल भारतीय नौकरियों का अनिवार्य माध्यम रहेगी अंग्रेजी।

गांधीजी भाषाओं के आधार पर प्रान्तों के नवनिर्माण के पक्ष में थे। नेहरू जी भाषावार राज्य बनाने के प्रबल विरोधी थे। गांधीजी केन्द्र से अंग्रेजी हटाने के पक्ष में थे, नेहरूजी उसे वहाँ अमाये रखने के पक्ष में थे। केन्द्र और राज्य—दोनों जगह गांधीजी और नेहरूजी की भाषा-नीति में अन्तर था। नेहरूजी ने देश के लिए बहुत से अच्छे काम किए लेकिन उनकी अंग्रेजी कायम रखने की नीति गलत थी। देश में अंग्रेजी कायम रखने के लिए जिम्मेदार है कांग्रेस।

भाषागत द्वेष और गृहयुद्ध की सम्भावना

ज़ारशाही रूस में रूसी पूँजीवाद ने साम्राज्यवाद का रूप ले लिया था। रूसी पूँजीपति गैर-रूसी इलाकों का शोषण करते थे, वहाँ की भाषाओं का दमन करते थे। सन् '४८ में कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी कांग्रेस ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में भारत को भी ज़ारशाही रूस की तरह जातियों का कारागार मान लिया था। इसीलिए उत्पीड़क पूँजीवादी गुट के विरुद्ध केरल, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों के लिए आत्मनिर्णय की माँग की गई थी।

प्रस्ताव में कहा गया था, 'कांग्रेसी नेतृत्व ने अपनी समझौतावादी नीति

के कारण आत्मनिर्णय के अधिकार का विरोध करने की वजह से देश का घातक विभाजन करा दिया है। आज इंडियन यूनियन में वह फिर वही अपराध कर रहा है, उत्पीड़क पूंजीपति वर्ग के हित में वह महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु आदि जातीय प्रदेशों के आत्मनिर्णय का अधिकार अस्वीकार करता है।"

भारतीय परिस्थितियों में आत्मनिर्णय की यह बात गलत थी और आज भी है। आत्मनिर्णय की मांग की जाती है साम्राज्यवाद के खिलाफ, उन प्रदेशों के लिए जहाँ विदेशी पूंजीपतियों ने अपने उपनिवेश कायम किये हो।

भारत में अहिन्दी भाषाओं के दमन की आशंका कुछ लोगों के मन में है, लेकिन दमन का कोई ठोस सामाजिक आधार नहीं है। यदि हिन्दीभाषी क्षेत्र का पूंजीवाद साम्राज्यवाद का रूप ले रहा हो, यदि किसी एक प्रदेश के पूंजीपतियों ने अन्य प्रदेशों को अपना उपनिवेश बनाना प्रारम्भ कर दिया हो तो मानना होगा कि अहिन्दी भाषाओं के दमन का वास्तविक स्रोत है। ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए शक शुद्ध की बात की जा सकती है, भाषाओं के दमन की बात करना जनता में हिन्दी के प्रति द्वेष फैलाना है।

योगीन्द्रजी ने शक-शुद्धे और वास्तविक स्रोतों को मिलाकर एक कर दिया है। उन्होंने आरशाही रूप और भारत के पूंजीवाद का फकें नहीं देखा। वह अहिन्दी भाषाओं के दमन की बात इस तरह करते हैं मानो दिल्ली सरकार केवल हिन्दी क्षेत्र के पूंजीपतियों की सरकार हो। उन्होंने पूछा है, "१९४६ में दक्षिण भारत की जनता हिन्दी को एव दबानेवाली भाषा के रूप में देखती थी या नहीं?" इसका उत्तर है कि कुछ लोग दक्षिण में हिन्दी को दबानेवाली भाषा के रूप में देखते थे। यह उनकी आशंका थी। उस आशंका के कारण थे। लेकिन हिन्दी दबानेवाली भाषा न तब थी, न आज है। दबानेवाली भाषा वास्तव में अंग्रेजी थी, आज भी है।

योगीन्द्रजी ने पूछा है कि पार्टी ने अपनी जनत नीति सुधार ली, तब सन् '६१ में मैंने वही गलत बात क्यों दुहराई।

उन्हे भ्रम है कि सन् '६१ में मैंने सन् '४६ की बातें दुहराई हैं। सन् '४६ में मैंने केन्द्रीय राजभाषा का विरोध किया था, सन् '६१ में उसका समर्थन किया था। सन् '४६ में जातीय उत्पीड़न का वास्तविक स्रोत है, मैं यह मानता था। सन् '६१ में शक-शुद्धे की बात थी, भाषाओं के वास्तविक दमन की बात नहीं थी। इन शक-शुद्धे का सम्बन्ध मुख्यतः नौकरीपेशा मध्यवर्ग के लोगों से है। इनके बारे में 'भाषा और समाज' में मैंने लिखा था

'देश के विभिन्न वर्गों का जैसा सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, उसी के अनुकूल वे भाषा समस्या का समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। इनमें सबसे पहले वह वर्ग है जो साम्राज्यवादी व्यवस्था में शिक्षा के कारण ऊँची नौकरियाँ पा सका था और अब स्वाधीन भारत में वह उसी शिक्षा के आधार पर अपने लिए उन नौकरियों को बरकरार रखना चाहता है। इनमें विभिन्न प्रदेशों के उच्च मध्य-

वर्गीय शिक्षित लोग हैं जो समझते हैं कि अंग्रेजी के न रहने से हिन्दीवाले बाजो मार ले जाएंगे। इनकी तो मातृभाषा हिन्दी है, दूसरो को उसी को सीखना पड़ेगा। इस तरह के तर्क साम्राज्यवादी अवशेषों को जाहिर करते हैं।”

(पृ० ४४३)

इस भय को दूर करने का उपाय मैंने यह बताया था ‘ऊँची नौकरियों के लिए हिन्दी-भाषियों को तभी लेना चाहिए जब उन्हें एक अहिन्दी भाषा का अच्छा ज्ञान हो।’

(पृ० ४५७)

‘जनशक्ति’ में यही प्रस्ताव मैंने दोहराया था, “अहिन्द भाषा का समुचित ज्ञान अनिवार्य कर देने से हिन्दीवालों को कोई विशेष सुविधा न मिलेगी।”

जो लोग सचमुच अंग्रेजी का प्रमुख स्रोत बनना चाहते हैं, वे इस प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार करेंगे। जो हठ धर्मी से केन्द्र में अंग्रेजी बंते रहने के पक्ष में हैं, वे उससे बारे में चुप रहेंगे।

तमिलनाडु में जो आन्दोलन चला उसमें शक-शुबहो से लाभ उठाया गया, तिल का ताड़ बनाकर जनता को गुमराह किया गया। आन्दोलन के सूत्रधार वे थे जो द्रविड भारत या तमिलनाडु का अलगवा चाहते हैं, जो कश्मीर से लेकर नागालैंड तक अलगवा के हर आन्दोलन का साथ देते हैं।

भारत में गृहयुद्ध का खतरा पैदा होता है उन लोगों से जो देश के नये विभाजन के लिए प्रयत्नशील हैं। भाषाओं के दमन की बात वे अपना असली उद्देश्य छिपाने के लिए करते हैं। उनकी इस नीति का पर्दाफाश करके जनता को उनके प्रभाव से निकालना चाहिए, न कि उनके सुर में सुर मिलाकर बहना चाहिए कि हिन्दी भाषा अहिन्दी भाषाओं का दमन कर रही है।

अपने धर्म से प्रेम करना गुरा नहीं है। मुस्लिम लीग ने कहा—इस्लाम खतरे में है। मुसलमानों को हिन्दू खा जाएंगे। लीग ने ‘डायरेक्ट ऐक्शन’ का रास्ता अपनाया। आत्मनिर्णय के नाम पर देश का विभाजन हुआ।

अपनी भाषा से प्रेम करना गुरा नहीं है। द्रविड मुन्नेत्र कळगम ने कहा—तमिल खतरे में है; तमिल-भाषियों को हिन्दीवाले गुलाम बना लेंगे। कळगम ने ‘डायरेक्ट ऐक्शन’ का रास्ता अपनाया। हिन्दी तमिल का दमन न करे इसलिए केन्द्र में अनिश्चित काल के लिए अंग्रेजी कायम रहेगी।

केन्द्र और राज्य—पहले और बाद का सवाल

योगीन्द्रजी ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि पहले राज्यों से अंग्रेजी हटाना जरूरी है। राज्यों के विश्वविद्यालयों, सरकारी दफतरो आदि में पूरी तरह प्रादेशिक भाषाओं का चलन हो जाने के बाद ही केन्द्र से अंग्रेजी हटाने की बात की जा सकेगी। उन्होंने गांधीजी का यह कथन उद्धृत किया है, “सबसे पहले उन समृद्ध प्रादेशिक भाषाओं को पुनर्जीवित करना है जो भारत को सुलभ हैं।”

इसका अर्थ उन्होंने यह लगाया है कि जब तक राज्यों से अंग्रेजी निकल

न जाय, तब तक केन्द्र में अंग्रेजी चलती रहे !' इसके विपरीत गांधीजी ने प्रस्ताव किया था कि प्रान्तों में ऐसे नम्रचारी रहे जाएँ जो प्रान्तीय भाषा के साथ केन्द्रीय भाषा भी जानते हों। इसीलिए उन्होंने लिखा था कि "प्रान्तों को केन्द्र से काम पड़ेगा। यह काम वे अंग्रेजी में करने की हिम्मत न करेंगे।"

'भाषा और समाज' में गांधीजी के बारे में मैंने लिखा था, "वह भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। वह न इन भाषाओं पर हिन्दी सादना चाहते थे, न हिन्दी सादने का हीवा खटा करके अंग्रेजी बनाये रखने के पक्ष में थे।" (पृ० ४१३) गांधीजी की भाषा-नीति की यही व्याख्या मैं अब भी करता हूँ।

योगीन्द्रजी ने 'भाषा और समाज' से वे अक्ष उद्धृत किये हैं जहाँ भाषावार राज्यों के विरोध की निन्दा की गई है, जहाँ इस विरोध के कारण कुछ अहिन्दी-भाषी लोगों में हिन्दी के प्रति भय उत्पन्न होने की बात कही गई है, जहाँ राज्यों से अंग्रेजी हटाकर इस भय को दूर करने की बात की गई है। उन्होंने वे अक्ष छोड़ दिये हैं जहाँ मैंने लिखा था कि इस भय को बहाना बनाकर केन्द्र में अंग्रेजी कायम रखना गलत है।

मैंने स्पष्ट लिखा था, "भाषावार राज्यों के निर्माण का विरोध करके कांग्रेसी नेतृत्व ने काफी हद तक यह भय उत्पन्न किया है। इसका यह अर्थ नहीं कि अहिन्दी-भाषी अंग्रेजी की कारण लें।" (पृ० ४६९-७०)

मातृभाषाओं की दुहाई देकर अंग्रेजी की कारण लेनेवालों के बारे में मैंने लिखा था, "अहिन्दी क्षेत्रों के लोग अंग्रेजी से चिपके रहना चाहते हैं, वे मातृभाषाओं की सेवा नहीं करते। उन्हें हर बात में अंग्रेजी अपनी मातृभाषाओं से श्रेष्ठ लगती है। इसलिए उसे वे केन्द्र में ही नहीं अपने यहाँ भी सबसे ऊँचे आसन पर बिठाये रखना चाहते हैं—मातृभाषाओं की दुहाई देकर अंग्रेजी का प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता।" (पृ० ४५५)

गांधीजी के लेख को प्रकाशित हुए अठारह साल हो गये। योगीन्द्रजी के लिए अभी 'समृद्ध' प्रादेशिक भाषाओं को 'पुनर्जीवित' करने का सवाल बना हुआ है। तमिल, तेलुगु, मराठी आदि भाषाओं के आधार पर तमिलनाडु, आन्ध्र, महाराष्ट्र आदि राज्य कभी के बन गये। योगीन्द्रजी समझते हैं कि भाषावार राज्यों के विरोध से जो भय उत्पन्न हुआ था, उसे दूर करना अभी बाकी है। तमिलनाडु में तमिल माध्यमवाले विद्यालय खोले गये। छात्रों के अभाव में उन्हें बन्द कर देना पड़ा। इसलिए कि दिल्ली सरकार हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहती थी !

ध्यान देने की बात है कि तमिलनाडु में भाषावार राज्य बनाने के लिए कोई आन्दोलन नहीं हुआ। आन्दोलन हुआ आन्ध्र और बेरल में जहाँ तमिलनाड की तरह तोड़-फोड़ की कोई आवश्यकता नहीं हुई। भाषावार राज्य-आन्दोलन का दमन किया गया महाराष्ट्र और गुजरात में जहाँ हिन्दी-विरोधी

ग्रान्दोलन का प्रभाव है। ग्रहिन्दी-भाषी प्रदेशों में महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहाँ हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए जोरदार आवाज उठी है।

भाषावार राज्यों के ग्रान्दोलन में कम्युनिस्ट पार्टी ने सक्रिय भाग लिया था। तमिलनाडु के हिन्दी-विरोधी ग्रान्दोलन को प्रेरणा देनेवाले दो मुख्य दल थे—स्वतन्त्र पार्टी और द्रविड कळमम। भाषावार राज्यों के ग्रान्दोलन के दमन से ग्रहिन्दी भाषियों में हिन्दी के प्रति भय उत्पन्न हुआ है, इस सूत्र का भाज की परिस्थितिसे कोई भी सम्बन्ध नहीं है।

भाज यह बिलकुल स्पष्ट है कि राज्यों की सरकारों के सामने प्रादेशिक भाषाओं के व्यवहार को रोकनेवाली कोई भी वैधानिक कठिनाई नहीं है। केन्द्रीय नौकरियों में अंग्रेजी चलती है। इनके प्रभाव से राज्यों के शिक्षाक्रम में अंग्रेजी की पढाई अनिवार्य हो जाती है।

‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ के विशेष सवाददाता ने उस पत्र के ७ जुलाई के अंक में लिखा है कि राजस्थान सरकार ने अनेक विभागों में हिन्दी के व्यवहार का निर्देश किया है किन्तु योजना सचिवालय जैसे विभागों को छोड़ दिया गया है। “जब तक योजना आयोग (प्लानिंग कमीशन) ही हिन्दी के व्यवहार का फैसला नहीं करता, तब तक राज्य को मजबूर होकर अंग्रेजी का व्यवहार जारी रखना पड़ेगा। इस पृष्ठभूमि में यह महसूस किया जा रहा है कि यदि अंग्रेजी की पढाई पर जोर कम दिया जाएगा तो राजस्थान और उसके नौजवानों के हितों की हानि होगी।”

जब राजस्थान का यह हाल है तब ग्रहिन्दीभाषी राज्यों की स्थिति की कल्पना की जा सकती है। कौन राज्य नहीं चाहता कि उसके नौजवान क्यादा-से-क्यादा सहाय में केन्द्रीय सेवाओं में लिये जाएँ? इन केन्द्रीय सेवाओं के लिए अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य है। इसलिए केन्द्रीय सेवाओं का मेवा लूटने के लिए राज्य एक-दूसरे से होड़ करते हैं कि कौन अंग्रेजी क्यादा पढाता है।

इसीलिए भाज की परिस्थिति में केन्द्र से अंग्रेजी हटाये बिना राज्यों में अंग्रेजी का प्रभुत्व खत्म नहीं किया जा सकता।

यद्यपि योगीन्द्र शर्माजी ने अपने लेख में राज्यों में पहले अंग्रेजी हटाने पर बहुत जोर दिया है किन्तु केन्द्र में उतने परिवर्तन की बात उन्होंने मान ली है जितना कांग्रेस को स्वीकार है। कांग्रेस का कहना है कि केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं में प्रादेशिक भाषाओं को ऐच्छिक माध्यम बनाया जाय। योगीन्द्रजी इसे स्वीकार करते हैं। जब तक राज्यों से अंग्रेजी हट न जाय तब तक केन्द्र में कोई परिवर्तन न हो—यह सिद्धान्त उन्होंने खुद काट दिया। मेरा भी कहना है, केन्द्र और राज्य—दोनों जगह ■ अंग्रेजी हटाई जाय।

योगीन्द्रजी जब केन्द्र में इतना परिवर्तन मान लेते हैं—कि परीक्षाओं में प्रादेशिक भाषाएँ ऐच्छिक माध्यम हो, तब दो बंदम आगे और बढ़ें और यह माँग करें—केन्द्र में अंग्रेजी की जगह भारतीय भाषाओं का व्यवहार हो, अंग्रेजी

की चलन सत्य करने की अवधि निश्चित हो ।

केन्द्र में अंग्रेजी चलती है, इस कारण राज्यों में भी उसकी जड़ जमी हुई है। जो भी प्रादेशिक भाषाओं का हित चाहता है, वह केन्द्र से अंग्रेजी हटाने की मांग का समर्थन करेगा ।

कम्युनिस्ट पार्टी और अंग्रेजी

कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को कोई मालूम नहीं है कि केन्द्रीय सरकारी नौकरियाँ उन्हें भी मिल जाएँ । उन्हें कोई भय नहीं है कि पार्टी केन्द्र में हिन्दी का चलन हुआ तो राज्यों में पार्टी कार्य के लिए प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार न हो पाएगा । फिर भी पार्टी-केन्द्र की भाषा अंग्रेजी है ।

योगीन्द्र फार्माजी के अनुसार राज्यों का मातृ पार्टी-कार्य प्रादेशिक भाषाओं में होता है । जहाँ तक पार्टी का सम्बन्ध है, राज्यों में अंग्रेजी हटाने का कार्यक्रम पूरा हो गया है । फिर भी पार्टी केन्द्र से अंग्रेजी नहीं निकाली जा रही । इसके कारण ज़रूर होंगे लेकिन जो कारण कम्युनिस्ट पार्टी के सामने हैं उनमें तगड़े कारण काफ़ी हैं । राज्यों में अंग्रेजी विराधी क्रान्ति घायल पूरी कर लेंगे और उससे बाद उस क्रान्ति का मण्डा केन्द्र में गड़ेंगे—यह बात मैं कैसे मान लूँ ?

ब्रिटिश राज में कम्युनिस्ट पार्टी पर यह पाकन्दी न थी कि वह अपना काम अंग्रेजी में करे । ब्राज़ील में भी उस पर कोई ऐसी पाकन्दी नहीं रही । उसका जन्म हुए बीसवीं वर्ष हो गये, फातूनी जीवन बिताते हुए बीस साल में ऊपर हुए । वह गरीब जनता की पार्टी है, श्रमिकबर्ग की पार्टी है । योगीन्द्र फार्माजी के अनुसार वह सांस्कृतिक क्रान्ति की पार्टी है । लेकिन पार्टी के नेता अभी तक अपनी केन्द्र भूमि में इस सांस्कृतिक क्रान्ति का बीजारोपण नहीं कर सके । वे पार्टी केन्द्र से अंग्रेजी की वियचना की जड़ नहीं खोद पाये । तब पूँजीवादी पार्टियों से क्या आशा की जाय ?

भारत की राजभाषा हिन्दी और राष्ट्रीय जनताधिक मोर्चा । मुन्ने में बहुत प्रच्छन्न लगता है । लेकिन सोचन की बात है जब पार्टी के नेता खुद अपने लिए हिन्दी को सम्पूर्ण भाषा नहीं बना पाये, तब राष्ट्रीय जनताधिक मोर्चे में उसका प्रवेश के बिना द्वार से कराएँगे ? मोर्चा घोषित करेगा कि भविष्य में भारत की राजभाषा होगी हिन्दी लेकिन वर्तमान काल में खुद मोर्चे की भाषा होगी—अंग्रेजी ।

अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत चलाने के लिए भाई० सी० एस० फफतरो के लिए हिन्दुस्तानी सीखना अनिवार्य कर दिया था । मेरा प्रस्ताव है कि देश की सेवा के लिए—मजदूर वर्ग की एकता दृढ़ करने के लिए—कम्युनिस्ट पार्टी को नेशनल कौंसिल के सदस्य हिन्दी सीखें । यह नियम बना दिया जाय कि जिसे हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान न होगा, वह राष्ट्रीय कौंसिल का सदस्य न

भारत की राजभाषा अंग्रेजी और राष्ट्रीय जनताधिक मोर्चा ।

हो सकेगा ।

योगीन्द्रजी ने 'भाषा और समाज' से एक वाक्य उद्धृत किया है जिसमें पार्टी के नेताओं द्वारा हिन्दी बोलने की तारीफ है । वाक्य है, "भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि मास्को और पेरिस के कम्युनिस्ट सम्मेलनों में हिन्दी का व्यवहार कर चुके हैं ।"

यह तारीफ मैं वापस नहीं ले रहा हूँ । निवेदन यह है कि मास्को और पेरिस में ही नहीं, पार्टी के नेता दिल्ली में भी हिन्दी बोलें ।

योगीन्द्र शर्माजी 'भाषा और समाज' के इन वाक्यों पर विचार करें "जब हम बाहर जायेंगे, किसी अन्य राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे, तब (कभी कभी, हमेशा नहीं) हम हिन्दी का व्यवहार करेंगे । लेकिन अपने घर में हमारे मुलपत्र अंग्रेजी में प्रकाशित होंगे, हमारी कार्यकारिणी का अधिवेशन होगा तो उसमें विचार-विनिमय अंग्रेजी में होगा, नेताओं का अन्य नेताओं और उपनेताओं से पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में होगा ।" (पृ० ४१३)

यह प्रालोचना कांग्रेसी नेताओं पर ही नहीं, कम्युनिस्ट नेताओं पर भी लागू होती है ।

स्तालिन, लुइसिय और मिकोयान की मातृभाषा रूसी नहीं थी । फिर भी सारे देश में राजनीतिक कार्यवाही के प्रसार और सगठन के लिए उन्होंने रूसी भाषा को अपनाया, इस तथ्य का उल्लेख करते हुए मैंने 'भाषा और समाज' में लिखा था, "भारत में हिन्दी का व्यवहार किये बिना कोई प्रखिल भारतीय नेता नहीं बन सकता ।" (पृ० ४१४)

और भी—'लोग कहते हैं, नेहरू के बाद कोई ऐसा नेता नहीं दिखाई देता जिसकी बात सारा देश ध्यान से सुने । इसका कारण जहाँ हिन्दीभाषी प्रदेश का राजनीतिक पिछड़ापन है, वहाँ हिन्दीभाषी नेताओं द्वारा हिन्दी के प्रति उदासीनता भी है । वे हिन्दी के माध्यम से जन-वाधारण में राजनीतिक कार्य-वाही का महत्त्व नहीं समझ पायें ।' (पृ० ४१४)

यही उदासीनता का भाव जनक अहिन्दीभाषी नेताओं में तीव्र उपेक्षा का भाव बन जाता है । इसी उपेक्षा की निन्दा मैंने अपने एक लेख में की थी ।

कम्युनिस्ट पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल श्रमिक जनता की एकात्मता का है । यह एकात्मता अंग्रेजी के माध्यम से दृढ़ नहीं हो सकती । अंग्रेजी की प्रधानता होने से खुद कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर गरीब किसान और मजदूर जिम्मेदारी के पद नहीं संभाल सकते । यह इतिहास का व्यंग्य है कि कुछ समय के लिए केन्द्र में अंग्रेजी कायम रखकर योगीन्द्रजी देश को गृहयुद्ध से बचाना चाहते हैं । लेकिन गृहयुद्ध की सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर । पार्टी बीच में टूटी, उसके दो हिस्से हो गये । इस परिस्थिति के लिए एक हद तक पार्टी के अन्दर के मध्यवर्गी तत्त्व भी जिम्मेदार हैं जो अपनी अंग्रेजियत के कारण पार्टी-नेतृत्व का दरवाजा मजदूरों के लिए बन्द किये हैं ।

यह परिस्थिति अब बदलनी चाहिए ।

कांग्रेस सरकार ने केन्द्र से अंग्रेजी हटाने के लिए पन्द्रह साल की मियाद रखी थी । उसने अपना वादा तोड़ दिया । कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने अपने केन्द्र से अंग्रेजी हटाने के लिए कोई मियाद नहीं रखी थी । इसलिए उन पर वादा तोड़ने का आरोप भी नहीं लगाया जा सकता ।

नेहरूजी ने कहा—हिन्दी अविवर्धित भाषा है, पहले उसे विकसित करो । फिर यह राजभाषा बनगी । पार्टी के नेताओं ने कहा—ठीक । हिन्दी को विकसित होने दो । दूसरी प्रादेशिक भाषाएँ हैं, उनके विकास पर भी रुपये खर्च होने दो । नेहरूजी ने कहा—अहिन्दी-भाषी नहीं चाहते कि अंग्रेजी हटाई जाय । पार्टी के नेताओं ने कहा—ठीक । चार ही क्या है ? फिलहाल केन्द्र में अंग्रेजी ही चले ।

कांग्रेस कार्यसमिति ने प्रस्ताव पास किया कि पञ्चिक सचिव कमीशन की परीक्षाओं के लिए प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार भी हो सकता है । पार्टी के नेताओं ने कहा—बहुत अच्छा, यही तो हम भी चाहते थे ।

इन अखिल भारतीय रोषाओं में अंग्रेजी का व्यवहार अनिवार्य होगा—इस बारे में वे चुप रहें । अपने पिछने सेल में इस प्रस्ताव की कैफियत देते हुए योगीन्द्रजी ने अंग्रेजी का नाम ही नहीं लिया, माना अंग्रेजी से उसका कोई सम्बन्ध ही न हो ।

हमें माँग करनी चाहिए कि हर स्वाधीन देश की तरह भारत के शिक्षाक्रम में भी अंग्रेजी की पढ़ाई वैकल्पिक हो । हम माँग करनी चाहिए कि सरकार केन्द्र और राज्यों से अंग्रेजी हटाने की अवधि निर्दिष्ट करे । हिन्दी को अभी और समृद्ध करने प्रादेशिक भाषाओं को समृद्ध करने के बाद अंग्रेजी हटाने के कांग्रेसी पाखण्ड का नीम खण्डन करना चाहिए । यह न करके योगीन्द्रजी उसका समर्थन करते हैं । उनकी स्वतन्त्र नीति केवल इस बात में प्रकट होती है कि वे इस गलत प्रस्ताव को मनी मही भ्रमण में लाने पर जोर देंगे ।

पार्टी-केन्द्र में अंग्रेजी हटाने का सवाल अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इस सवाल के जवाब से ही मालूम होगा कि आन्तिका की लफकाजी और आन्तिकारी भ्रमण में क्या फर्क है ।

लेकिन की सीख—फिलहाल अंग्रेजी

लेनिनवाद के अनेक भाष्य, अनेक व्याख्याएँ समार में प्रचलित हैं । स्तालिन ने जो कुछ किया लेनिनवाद के नाम पर । स्ट्रुइव ने उनकी वज्र सोदी—लेनिनवादी नीति की रक्षा के नाम पर । वे अनेक और कोसीगन ने स्ट्रुइव को हराया—लेनिनवाद को ही भ्रमण में लाने के लिए । पेरिग के नेता सोवियत संघ को अमरीकी साम्राज्यवाद का समर्थक कहते हैं—महान् आन्तिकारी लेनिन की विरासत की रक्षा करने के नाम पर । इसलिए यदि कोई भारत में कहे कि

लेनिन की यह सोख है कि फिलहाल केन्द्र में अंग्रेजी कायम रहे तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है।

जारसाही रुस के अभिजात वर्ग में फ्रांसीसी भाषा का बहुत व्यवहार होता था। यूरोप की अन्तर्जातीय भाषा फ्रांसीसी थी। लेनिन ने यह नहीं कहा कि लोग केन्द्र में रुसी भाषा नहीं चाहते, इसलिए फिलहाल वहाँ फ्रांसीसी भाषा चल दी जाय।

लेनिन का समाधान यह था कि किसी भी भाषा को अनिवार्य केन्द्रीय राजभाषा का पद न दिया जाय। इस समाधान को यदि भारत में लागू किया जाय तो अंग्रेजी को हटाकर उसकी जगह सभी प्रादेशिक भाषाओं को बराबरी की जगह देनी होगी।

योगीन्द्रजी इस बात की कल्पना ही नहीं करते कि केन्द्रीय राजभाषा के बिना भी काम चल सकता है। इसीलिए उन्होंने मेरे बारे में लिखा है, "किसी भाषा के शोर जबर्दस्ती लादे जाने के वे ऐसे कट्टर विरोधी थे कि उस समय के कानूनी राजभाषा के सिद्धान्त का ही विरोध करते थे...वे १९५०-५५ में भाषा के सवाल पर अराजकतावादी छोर पर थे

केन्द्र में अनेक राजभाषाएँ चलाने का सिद्धान्त अराजकतावादी नहीं है। लेनिन ने समाजवादी प्रान्ति के बाद न तो रुसी को केन्द्रीय राजभाषा बनाया न और किसी भाषा को। यह अराजकतावाद नहीं था।

यदि भारत के लिए हम कहे कि केन्द्रीय राजकर्मचारियों को समस्त प्रादेशिक भाषाएँ सीखनी हानी तो यह अराजकतावादी बात होगी। किन्तु केन्द्र में सभी भारतीय भाषाओं को समानता के अधिकार देने के और भी उपाय हैं। इनमें मुख्य उपाय है अनुवाद की व्यवस्था का।

४ जुलाई के जनयुग में श्री राही मामूम रजा ने यह प्रस्ताव रखा है, "केन्द्रीय सरकार के पास एक अनुवाद-विभाग हो। अन्य प्रान्तों से होनेवाले पत्रव्यवहार की भाषा तो हिन्दी हो जाय और प्रान्तीय सरकारों की भाषा उस समय तक उस क्षेत्र की भाषा बनी रहे जब तक कि वह क्षेत्र हिन्दी को स्वीकार न कर ले।"

यदि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एक बार यह तय कर लें कि अंग्रेजी की जगह केन्द्र में भारतीय भाषाएँ चलानी हैं तो अनुवाद की समुचित व्यवस्था क्या हो, वे यह तय कर लेंगे। केन्द्र में सभी भाषाओं को बराबरी का दर्जा देने से वे शक-शुद्धे बहुत जल्दी दूर हो जाएँगे जिनके मारे योगीन्द्रजी परेशान हैं। अभी उनके पास कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिससे हिन्दी भाषा को केन्द्र में चालू करने की स्वेच्छा अहिन्दीभाषी नेताओं में उत्पन्न हो। मेरा प्रस्ताव उस 'स्वेच्छा' को उत्पन्न करने में सहायक होगा।

केन्द्र में अनेक भाषाओं के चलन का सिद्धान्त बीजरूप में कांग्रेस ने स्वीकार किया है। उसने केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं के लिए प्रादेशिक भाषाओं

की माध्यम रूप में मान्यता दी है। योगीन्द्रजी बाग्रेम के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। बीजरूप में अनेक राजभाषाओं के चलन की बात यह भी मानते हैं। इसलिए अंग्रेजी को हटाकर प्रादेशिक भाषाओं को केन्द्र में जगह देने की बात उन्हें प्रमान्य न होनी चाहिए।

इस समय अनेक दलों के नेताओं ने यह प्रचार कर रखा है कि केन्द्र में अंग्रेजी हटाते ही गृहयुद्ध छिड़ जायगा। इनमें कुछ लोग कहते हैं अंग्रेजी अनन्त काल तक रहनी चाहिए। दूसरे कहते हैं, अनन्त काल तक नहीं, अनिश्चित काल तक रहनी चाहिए यानी तब तक जब तक अहिन्दीभाषी लोग हिन्दी को स्वीकार न कर लें।

आन्ध्र के मन्त्री श्री चलपति वेंकटरामैया ने कहा है कि "हिन्दी को अंग्रेजी की जगह लेने में पचास साल लगेंगे।" (नादैनं इडिया पत्रिका, १६ फरवरी, '६५)

ये औरो से फिर अच्छे हैं। पचास साल की निश्चित अवधि की बात तो करते हैं। अनिश्चित काल वालों का राम ही मातृक है।

जनतांत्रिक समाधान ऐसा होना चाहिए जो हिन्दीभाषियों को भी स्वीकार हो। कुछ लोगों को हिन्दी पसन्द नहीं है, औरो को अंग्रेजी पसन्द नहीं है। हिन्दी अंग्रेजी के इस संघर्ष में तैनिनवाद का फंमला अंग्रेजी के पक्ष में न होना चाहिए। फंमला होना चाहिए भारतीय भाषाओं के पक्ष में।

योगीन्द्र शर्माजी की निगाह गृहयुद्ध की सम्भावना के एक पक्ष पर है। वह यह कि हिन्दी को राजभाषा बनाने में अहिन्दी भाषी विद्रोह कर देंगे। उन्होंने गृहयुद्ध की सम्भावना के दूसरे पक्ष पर विचार नहीं किया। हिन्दी-भाषियों की इच्छा के विरुद्ध केन्द्र में अंग्रेजी बनाते रहना अन्याय है। ये भी अंग्रेजी के चलने के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं।

स्थिति यह है कि अंग्रेजी के प्रभुत्व के कारण दक्षिण में द्रविड़ कळगम और उत्तर में जनसंघ शक्तिशाली होते जा रहे हैं। इनके शक्तिशाली होने के कारण अलग अलग हैं लेकिन भाषा समस्या से उनका गहरा सम्बन्ध है। यदि केन्द्र में तमिल को हिन्दी के बराबर जगह दी जाय तो द्रविड़ कळगम को समित प्रेम का भण्डा उठाने का मौका न मिले।

बाग्रेमी और कम्युनिस्ट नेता जितने दिन केन्द्र में अंग्रेजी खालू रखने की नीति का समर्थन करते हैं, उतने ही दिन वे द्रविड़ कळगम और जनसंघ की भाषा विवाद से फायदा उठाकर शक्तिशाली बनने का मौका देते हैं। जनता में इन प्रतिनिध्यावादी दलों के प्रभाव की खतरा करने का एक अच्छा उपाय है, केन्द्र में अंग्रेजी की जगह प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार।

यह अस्थायी समाधान है। जब तक अहिन्दीभाषी केन्द्र में हिन्दी का चलन स्वीकार न करें, तब तक यह समाधान लागू करना चाहिए।

तर्क-पद्धति और निष्कर्ष

मैं समझता हूँ कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य जनवादी पार्टियाँ मिल-कर प्रयत्न करें तो अगले पाँच वर्षों में वे हिन्दी को केन्द्रीय राजभाषा बना सकती हैं। द्रविड कळगम और स्वतन्त्र पार्टी इतनी समर्थ नहीं हैं जितनी वे मालूम होती हैं। उन्होंने जनता के मातृभाषा-प्रेम से लाभ उठाकर उसे बरगसाया है। यदि उस जनता को बताया जाय कि केन्द्रीय सेवाओं के लिए अहिन्दी-भाषियों को हिन्दी सीखनी होगी और हिन्दीभाषी अफसरों को वैसे ही एक अहिन्दीभाषा का ज्ञान प्राप्त करना होगा, तो जनता के गुमराह अशो को राह पर लाया जा सकता है।

लेकिन केन्द्रीय सेवाओं के हिन्दीभाषी उम्मीदवार एक अहिन्दीभाषा का ज्ञान प्राप्त करें—मेरे इस प्रस्ताव पर योगीन्द्रजी ने ध्यान ही नहीं दिया, उस पर एक शब्द भी नहीं कहा। तब कांग्रेसी नेताओं से मैं क्या आशा करूँ ?

इसलिए मैंने अपने लेख में यह विकल्प रखा है कि केन्द्र में हिन्दी के साथ अन्य भाषाओं का व्यवहार भी हो। इससे पहले भी मैंने 'जनशक्ति' में लिखा था, 'समस्या का एक ही हल है केन्द्र में हिन्दी हो, राज्यों में प्रादेशिक भाषाएँ। इस पर भी यदि कोई कहे कि अंग्रेजी हटाने से अहिन्दी भाषाओं का दमन हुआ तो निवेदन है, लोकसभा में सभी भाषाएँ चलाइए। हम इस बात का मोह नहीं है कि भारत सरकार का काम हिन्दी में हो। घृणा इस बात से है कि उसका काम अंग्रेजी में होता है। केन्द्र में चाहे एक भारतीय भाषा चलाइए, चाहे दस विदेशी भाषा अंग्रेजी को निकालिए।'

लोकसभा के लिए मैंने विशेष रूप में लिखा था, 'लोकसभा में अहिन्दी-भाषी नेता मौक से अपनी अपनी भाषाएँ बोलें। हिन्दी भाषी नेता हिन्दी में बोलें। कम्युनिस्ट सदस्य अपने व्यवहार से इस नीति की मिसाल कायम करें।'

मेरे यह सब लिखने पर भी योगीन्द्र शर्माजी ने बड़े आग्रह से यही सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मैं अहिन्दी भाषाओं को दवाना और केन्द्र में जबरदस्ती हिन्दी चलाना चाहता हूँ।

उन्होंने १४ मार्च के भर्तृयुग में प्रकाशित मेरे लेख का दो बार हवाला दिया है। यह लेख उन्हें विशेष उपयोगी जान पड़ता है, उसमें गृहयुद्ध की ललकार उन्हें ज्यादा स्पष्ट सुनाई पड़ती है।

मैंने लिखा था "यह सघर्ष हिन्दी-तमिल का नहीं है, अंग्रेजी और समस्त भारतीय भाषाओं का है। हिन्दी-तमिल-विरोध के बड़े घातक परिणाम हो सकते हैं। एक बार गृहयुद्ध की आग भड़कने पर उसे रोकना गम्भीर हो जाएगा।"

गृहयुद्ध की ललकार का इससे अधिक पुष्ट प्रमाण और क्या होगा ?

मैंने लिखा था, 'भारतीय भाषाओं को उनके उचित अधिकार दिलाने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हिन्दी-भाषी प्रदेश में अंग्रेजी को राजभाषा और सांस्कृतिक भाषा के पद से हटा दिया जाय।'

योगीन्द्रजी का विचार है कि मैं भारतीय भाषाओं के अधिकारों को कुचल-कर हिन्दी को राजभाषा बनाने के पक्ष में हूँ !

मैंने लिखा था, “इसके बाद जिस दिन हिन्दीभाषी जनता संगठित होकर अपने लोकसभा के प्रतिनिधियों को हिन्दी में बोलने और सारा राजकाज हिन्दी में करने के लिए बाध्य करेगी, उस दिन अंग्रेजी का साम्राज्यवाद खत्म होगा, उस दिन तमिलनाडु में तमिल भी अपना पूर्ण स्वत्व प्राप्त करेगी और राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करने में हिन्दीभाषी जनता अपनी भूमिका पूरी करेगी।”

यह वाक्य उन्होंने उद्धृत किया है लेकिन उसका बहु टुकड़ा निकालकर जिसमें तमिल के पूर्ण स्वत्व प्राप्त करने की बात है। कारण स्पष्ट है। पूरा वाक्य उद्धृत करने से मुझ पर तमिल-दमन का आरोप लगाने में असुविधा होती।

वह भ्रम निकाल देने पर भी गृहयुद्ध की लसकार का आरोप लगाना सरल नहीं था। इसलिए उन्होंने ‘लेकिन यदि’ का सहारा लिया—“लेकिन यदि यही बात पूरे देश के लिए कही जाय तो...” इस तरह ‘लेकिन यदि’ लगाकर किसी भी वाक्य से कोई भी नतीजा निकाला जा सकता है।

योगीन्द्रजी ने मुझ पर यह आरोप लगाया है कि अजय घोष के लेख में मैंने वे बातें छोड़ दी हैं जो मेरी नीतियों के विरुद्ध हैं। ये कौन-सी बातें हैं ? अजय घोष के लेख से उन्होंने जो अंश उद्धृत किया है उसमें कहा गया है भाषा-भाषियों के सदस्य प्रादेशिक भाषाओं को एक अभिगम के रूप में देखते हैं। वे नहीं मानते कि भारत बहुभाषी देश है। उन्होंने जनसन्त्र के इस प्रारम्भिक सिद्धान्त को विचार में बाहर रखा है कि शासन, विधि न्याय की भाषा, प्रत्येक क्षेत्र में सभी स्तरों पर वह भाषा होनी चाहिए जिसको जनता आम तौर पर बोलती और समझती है।

योगीन्द्रजी का विचार है कि मैं अजय घोष की उपर्युक्त नीति का विरोधी हूँ यानी प्रदेशों में वहाँ की भाषाओं के बदले हिन्दी का ही चलन करना चाहता हूँ।

‘जनशक्ति’ में मैंने लिखा था—

(क) “भारत में भाषावार राज्य बनाने का आन्दोलन चला। हर प्रदेश में उसकी शिक्षा और संस्कृति का विकास उसकी भाषा के माध्यम से हो, यह माँग रही थी।”

(ख) “जिस तरह हर प्रदेश में उसकी अपनी भाषा की सभी अधिकार मिलने चाहिए, वैसे ही इन सबको जोड़नेवाली राष्ट्रभाषा हिन्दी को भी केन्द्र में पूर्ण अधिकार मिलने चाहिए।”

(ग) “इस पर भी यदि कोई बहे कि अंग्रेजी हटाने से अहिन्दी भाषाओं का रमन होता है तो निवेदन है, लोगसभा में सभी भाषाएँ चलाइए।”

अजय घोष ने अहिन्दी भाषाओं को केवल प्रदेशों में पूर्ण अधिकार देने की

बात कही थी। मैं उन्हें केन्द्र में हिन्दी के बराबर स्थान देने की बात कहता हूँ। लेकिन विरोधी आलोचकों का मुँह बन्द करने के लिए योगीन्द्र शर्माजी ने सीधी रणनीति निकाली है। उन पर ग्रन्थ हिन्दी राष्ट्रवाद का आरोप लगा दो, केन्द्र में फिलहाल अंग्रेजी चलाने की नीति अपने आप सही साबित हो जाएगी।

मैंने लिखा था, “अंग्रेजी कायम रखने के लिए जो विशाल समुक्त मोर्चा बना है, उसमें स्वतन्त्र दल के नेता हैं, द्रविड़ कळगम वाले हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के अनेक नेता भी इसमें हैं।” योगीन्द्रजी ने अनेक का अर्थ किया सम्पूर्ण और नाराज होकर लिखा, “इन्हीं की पक़्त में सम्पूर्ण कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को खड़ा कर देना भारतीय राष्ट्रीयता और जनतन्त्र की कलकित करना है, सच्चाई के मुँह पर समाचा मारना है।”

१७ फरवरी, '६५ को पी० टी० आई० द्वारा नई दिल्ली से प्रसारित समाचार के अनुसार ३४ सदस्य-सदस्यों ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया था कि संविधान की यह धारा बदल देनी चाहिए जिसमें हिन्दी को राजभाषा घोषित किया गया है। पी० टी० आई० के अनुसार इन सदस्य-सदस्यों में कम्युनिस्ट पार्टी, द्रविड़ कळगम, स्वतन्त्र पार्टी, धार० एस० पी० तथा मुस्लिम लीग के नेता थे।

योगीन्द्र शर्माजी विचार करें, भारतीय राष्ट्रीयता और जनतन्त्र को कौन कलकित करता है, सच्चाई के मुँह पर समाचा कौन मारता है।

मैंने कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की भाषा नीति की आलाचना की थी। इसे उन्होंने ‘हिन्दी भाषा और भारत देश को शाप’ देना कहा है।

गद्य में प्रतिशयोक्ति अलंकार उन्हें बहुत प्रिय है और उसके व्यवहार पर वह कोई भी प्रतिबन्ध लगाना अनुचित समझते हैं।

‘भाषा और समाज’ से सम्बा उद्धरण देकर उन्होंने यह नतीजा निकाला है कि पहले मैं पड़िताऊ हिन्दी का विरोधी था, अब उसका समर्थक हो गया हूँ। अपनी रणनीति के अनुसार मेरी पुस्तक के वे अंश उन्होंने छोड़ दिए हैं जहाँ मैंने सुगठ पारिभाषिक शब्दों के निर्माण की प्रशंसा की थी। मैंने लिखा था—

‘लेकिन पारिभाषिक शब्दावली में ऐसे भी बहुत से शब्द हैं जो धोलने में हिन्दी प्रवृत्ति का उत्प्रेरण नहीं करते और जिनके लिए विश्वास से कहा जा सकता है कि वे अवश्य लोकप्रिय होंगे। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित कृपि सम्बन्धी शब्दावली से हम कुछ शब्द ले सकते हैं।’ (पृ० ४३३)

छास बात यह है कि मैंने उन लोगों का विरोध किया था जो पारिभाषिक शब्दावली को असन्तोषजनक बताकर केन्द्र में अंग्रेजी चलाने रहने का समर्थन करते थे। मैंने लिखा था—

‘हिन्दी में काफी पारिभाषिक शब्दों का निर्माण हो चुका है। इनमें बहुत से अपने-अपने विषय की हिन्दी पुस्तकों में व्यवहृत भी होते हैं। जहाँ तक राजकाज

का सम्बन्ध है, इस विषय के शब्दों का निर्माण विज्ञान की सन्दावली बनाने से प्राप्त है। इसलिए विज्ञान में चाहे हिन्दी का प्रयोग कुछ दिन खा भी रहे, राजभाषा के रूप में हिन्दी का व्यवहार रके, इसका कोई कारण नहीं है।”
(पृ० ४३३)

योगीन्द्रजी ने इससे उल्टा निष्कर्ष निवाला है।

इस तरह की तर्क-पद्धति वे अपनाते हैं जो हठधर्मों से गलत नीति को भी सही साबित करने के लिए कसर कम सेत हैं। इस तरह विरोधी भाषावकों की बातों को तोड़-मरोड़कर पेश करने से जनवादी तत्त्वों में एकता स्थापित नहीं की जा सकती।

योगीन्द्रजी ने ग्रन्थ-राष्ट्रवाद की बात बहुत बार की है। वह 'भाषा और समाज' के इस वाक्य पर भी गौर करें—

“वर्तमान ग्रन्थ राष्ट्रवाद की विशेषता यह है कि वह दूसरी भारतीय भाषाओं के प्रति घृणा फैलाता है और अंग्रेज़ों को गले लगाता है।” (पृ० ४२५)

मैं चाहता हूँ कि पार्टी के नेताओं में हिन्दी के प्रति जो खेद-भाव है, वह खत्म हो। वे अपने सिद्धांत और व्यवहार में एकता स्थापित करें। सामन-केन्द्र में चाहे एक भाषा चलाएँ चाहे अनेक, निश्चित अर्थात् में अंग्रेज़ी का चलन बन्द हो—यह माँग करें। अंग्रेज़ी को अनिश्चित काल के लिए भारत की राज-भाषा बनाकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चे का निर्माण नहीं हो सकता।

(१९६५)

देश का विघटन और अंग्रेजी

एक जमाना था जब लोग समझते थे कि अंग्रेजी सभी भारतीय भाषाओं पर साम्राज्यवादियों द्वारा लादी हुई भाषा है। राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान किसी भी देशभक्त को इस बारे में शक नहीं था कि अंग्रेजी की गुलामी अंग्रेजों की ही गुलामी का एक भग है। उस समय राष्ट्रीय नेता मानते थे कि अंग्रेजी का प्रमुख राष्ट्रों के लिए अपमानजनक है। वे जानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा के कारण देश की शक्ति और धन का अपार अपव्यय होता है। वे कहते थे कि देश पर मुट्ठी-भर अंग्रेजी-पढ़े हुकूमत करें, यह जनतन्त्र का मजाक है। उस जमाने में राष्ट्र के नेता भाषा की समस्या पर आम जनता के दृष्टिकोण से विचार करते थे। वे घोषित करते थे कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ है भारत के करोड़ों श्रमिक जनो की एकता। यह एकता हिन्दी और केवल हिन्दी के द्वारा कायम हो सकती है।

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद वे बातें अब पुरानी हो गईं। जो अंग्रेजी की हिमायत करता है, वह उदार और प्रगतिशील माना जाता है। जो अंग्रेजी हटाने की बात करता है, वह पुराणपन्थी और हिन्दी उन्मादी कहलाता है। राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे आवश्यक है अंग्रेजी। अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क के लिए एकमात्र विश्वभाषा है अंग्रेजी। ज्ञान-विज्ञान के लिए अनिवार्य माध्यम है अंग्रेजी।

अब राष्ट्रीय एकता का अर्थ जन-साधारण की एकता नहीं है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है अंग्रेजी-पढ़े नेताओं और नौकरशाहों की एकता। अब राष्ट्रीय एकता का प्रश्न जुड़ा हुआ है प्रखिल भारतीय नौकरियों के साथ।

तमिलनाडु में इतना उत्पात हुआ, तमिल की रक्षा के लिए ? नहीं, लोगों को भय दिखाया गया कि सरकारी नौकरियाँ हथिया लेंगे हिन्दीवाने, दक्षिण-वाले टापटे रह जाएंगे। हिन्दी के अत्याचार ने बचने के लिए कुछ लोगो ने सुझाव दिया कि हर राज्य के लिए नौकरियों का 'कोटा' निश्चित कर दिया जाय।

पिछले छह: महीने से यह नीवरियो का मवात अंग्रेजी-पढे बाबुओं के सामने है । उनके लिए यह सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्या है । अंग्रेजी-पढा नीवरसाह वर्ग आम जनता से कितनी दूर है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इस समुदाय के सामने भाषा-समस्या का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है—नौकरी !

देश की राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस के नेता भाषा-समस्या पर विचार करते हैं तो उनके सामने मुख्य प्रश्न होता है : अखिल भारतीय नौकरियों की परीक्षाएँ कितनी भाषाओं में होगी !

यह मानते हुए कि अपनी जगह नौकरियों की समस्या का भी महत्व है, हमें राष्ट्रीय एकता के प्रश्न को सरकारी नौकरियों के दायरे में बन्द न कर देना चाहिए । विभिन्न प्रदेशों की श्रमिक जनता की एकता किस तरह कायम की जाय, शासन-तन्त्र में आम जनता किस तरह भाग ले, राज्यसत्ता कुछ ऊपरवाले निहित स्वार्थों के हाथ में बठपुतली बनकर न रह जाय—भाषा की समस्या पर विचार करते हुए इन प्रश्नों को हमेशा सामने रखना चाहिए ।

कांग्रेस कार्यसमिति ने फैसला किया है कि अखिल भारतीय नौकरियों की परीक्षाएँ अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में होंगी । कुछ वर्ष अंग्रेजी और हिन्दी में अनिवार्य होंगी । जिन उम्मीदवारों की भाषा हिन्दी होगी, उनके लिए एक वर्ष किसी अहिन्दी भाषा में होगा । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक राज्य की भाषा, शासन और शिक्षा का माध्यम बनेगी । हिन्दी-शिक्षण के स्तर को ऊँचा किया जाएगा । “अंग्रेजी ऐसी भाषा के रूप में पढाई जाती रहेगी, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है ।” तीन भाषाएँ सीखने की नीति दृढ़ता से लागू की जाएगी । हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं का विकास किया जाएगा ।

जिन लोगों ने कांग्रेस कार्यसमिति के फैसले का स्वागत किया है, उनका विचार है कि अब अंग्रेजी की जगह प्रादेशिक भाषाओं का चलन हो जाएगा ।

इस आशा का आधार क्या है ?

प्रादेशिक भाषाएँ केवल परीक्षाओं का माध्यम बनेंगी, केन्द्रीय राजकाज का माध्यम नहीं । राजकाज होगा अंग्रेजी में । अखिल भारतीय सेवाओं में यह तो होगा नहीं कि परीक्षा में जिसका माध्यम तमिल है, उसे नौकरी तमिलनाडु में ही करनी होगी । अखिल भारतीय नौकरियों का मतलब ही यह है कि किसी भी अफसर की एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा सकता है । तब यह विभिन्न प्रदेशों में कार्य किस भाषा में होगा ? क्या तमिलभाषी अफसर दिल्ली में अपना दफतर तमिल में चलाएगा ? या बंगलाभाषी अफसर मद्रास में अपना काम बंगला में करेगा ?

स्पष्ट है कि अखिल भारतीय नौकरियों का माध्यम अंग्रेजी ही रहेगी ।

कांग्रेस कार्यसमिति ने यह फैसला नहीं किया कि केन्द्रीय सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी की जगह प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार होगा । फैसला यह किया है कि परीक्षाओं में अंग्रेजी के साथ प्रादेशिक भाषाएँ भी माध्यम बन सकती हैं ।

इसलिए यह भाषा सगाना व्यर्थ है कि केन्द्रीय राजराज में अंग्रेजी की जगह प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार होने लगेगा, या अंग्रेजी के साथ उन्हें ही बालिश भर जगह भी मिल जाएगी।

परीक्षाओं के लिए भी प्रादेशिक भाषाओं को अनिवार्य माध्यम नहीं बनाया गया। माध्यम बनने के लिए उन्हें विकसित होना है, अपने प्रदेश में राजभाषा बनना है, विश्वविद्यालयों में उच्चतम शिक्षा का माध्यम बनना है। बनने-बनाने का यह साग क्रम बब समाप्त होगा, इसकी कोई श्रवण निश्चित नहीं की गई।

भारत सरकार पन्द्रह साल से हिन्दी के विकास में लगी है, लेकिन अभी वही उस विकास का छोर नहीं दिखाई देता। बड़े-बड़े कोश बन जाने के बाद भी कार्यसमिति के प्रस्ताव में हिन्दी को अभी और विकसित करने की बात वही गई है।

यह अदभुत राष्ट्रभाषा प्रेम है ! हिन्दी के विकास से वह अभी सन्तुष्ट नहीं होता ! विकास के अपूर्ण हान से वह अंग्रेजी को ही राष्ट्रभाषा बनाए रहता है।

प्रादेशिक भाषाओं के प्रमी समझ लें, उन्हें अपनी भाषाओं के विकास के लिए बितनी लम्बी प्रतीक्षा करनी होगी।

प्रादेशिक भाषाओं को पन्द्रह साल से यह अधिकार प्राप्त है कि वे उच्च शिक्षा का माध्यम बनें, प्रदेशों की राजभाषा बनें। लेकिन इस अधिकार का उपयोग क्यों नहीं हुआ ? कांग्रेस के प्रस्ताव में वही इस बात की कैफियत नहीं दी गई कि, हर राज्य में शासन की भाग्य और कांग्रेस के हाथ में होने पर भी, उस अधिकार का पूरी तरह उपयोग क्यों नहीं किया गया।

जिस अधिकार का उपयोग पन्द्रह साल में नहीं हुआ, इस प्रस्ताव के बाद उसका उपयोग होगा ही, इसका क्या प्रमाण है ? इसके विपरीत उसका उपयोग भागे भी न होगा, इसका प्रमाण है।

केन्द्र में जब तक अंग्रेजी का बोलवाला रहेगा, तब तक राज्यों में प्रादेशिक भाषाओं को पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं हो सकतः। अंग्रेजी पढ़ा उम्मीदवार पढ़ने प्रशिक्षित भारतीय अधिकार बनने की कोशिश करता है। इस वाशिश में असफल होता है तब प्रादेशिक अधिकार बनने का प्रयत्न करता है। यहाँ भी नाकामयाब रहा तो मास्टरी या क्लर्की करता है। स्थिति यह है कि रेल, बैंक, डाक, तार, फीज, पुलिस, प्राइवेट फर्म—वहीं भी मामूली वरुँ अंग्रेजी के बिना नहीं मिलती। लाखों नौजवान हर साल फेंक होत हैं, अंग्रेजी की बजह से। देश में शिक्षा बेहद महंगी है अंग्रेजी के कारण।

इसलिए जो लोग धन और श्रम शक्ति के इस अव्यय को बन्द करना चाहते हैं, जो राज्यों में प्रादेशिक भाषाओं को उनके पूर्ण अधिकार दिलाना चाहते हैं उनके सामने एक ही वर्तव्य हो सकता है—केन्द्र में अंग्रेजी के प्रभुत्व को खत्म करना।

जो लोग सोचते हैं कि केन्द्र में अंग्रेजी के हटाने से नौकरियाँ हिन्दीवालों को ज्यादा मिल जाएंगी, उनका भय दूर करना कठिन नहीं है। हिन्दीभाषी उम्मीद-वारी के लिए एक प्राधुनिक अहिन्दी भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर देना चाहिए। कांग्रेस कार्यसमिति के प्रस्ताव में यह नियम शामिल किया गया है कि हिन्दी-भाषियों के लिए एक पचास अहिन्दी भाषा का होगा। देश की भावात्मक एकता के लिए मुख्य जोर प्राधुनिक प्रादेशिक भाषाएँ सीखने पर होना चाहिए।

किन्तु कांग्रेस के तीन भाषा वाले सूत्र में मुख्य जोर है अंग्रेजी पर। इसी-लिए उस सूत्र को प्रमत्त में माना कठिन होता है। वह जिस तरह प्रमत्त में लाया गया है, उससे किसी को सन्तोष नहीं है। सन्तोष इसलिए नहीं है कि प्रमत्त में लानेवालों की निगाह अंग्रेजी पर पहले है, हिन्दी और भारतीय भाषाओं पर बाद की।

श्री सार्धक प्रसी कांग्रेस के जाने माने नेता है। कांग्रेस के संगठन-कार्य से उनका विशेष सम्बन्ध रहा है। उन्होंने कार्यसमिति के प्रस्ताव को व्याख्या करते हुए ७ जून के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में एक लेख लिखा है। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि तीन भाषाओं वाला फार्मूला लागू करने से अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार और भी अधिक होगा।

लिखा है "सन्देहवादी लोग कह सकते हैं कि तीन भाषाओं वाले फार्मूले को कारगर तरीके से लागू करने की गुंजाइश कम है। इसके धारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि तीन भाषाओं वाले फार्मूले में अंग्रेजी वाला हिस्सा कारगर तरीके से जल्द लागू किया जाएगा।"

अंग्रेजी, और अधिक अंग्रेजी—यह है हमारे राष्ट्रीय नेताओं का दृष्टिकोण।

श्री सार्धक प्रसी का विचार है, 'यह अच्छी बात है कि हमारे विद्यार्थियों में अंग्रेजी जानने की व्यापक इच्छा है।'

ऐसा है तो अंग्रेजी वैकल्पिक कर दीजिए। फिर देखिए, कितने लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। आगरा विश्वविद्यालय में जब मेरी बी० ए० की परीक्षाओं में अंग्रेजी को वैकल्पिक कर दिया है, तब से लगभग नब्बे फी सदी विद्यार्थियों ने 'जनरल इनिश' की परीक्षा देना बन्द कर दिया है।

श्री सार्धक प्रसी का मत है, "सही दृष्टिकोण यह है कि अंग्रेजी को उसका न्यायोचित स्थान (राइटफुन प्लेस) दिया जाय जिसमें देश की सम्मिलित इच्छा सक्रिय व सहारे वह फूले-फूले। इस तरह उसने सामने ज्यादा सुन्दर, ज्यादा महान, ज्यादा रचनात्मक भविष्य होगा।"

न्यायोचित स्थान देना है अंग्रेजी को। रचनात्मक भविष्य है अंग्रेजी का। देश की सम्मिलित इच्छासक्रिय सहारा दोगे अंग्रेजी को।

शायक वर्ग अपनी भाषा-नीति जिस उद्देश्य से निर्धारित कर रहा है, यह श्री सार्धक प्रसी के बक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है।

सार्धक भीम सत्ता होंगी अंग्रेजी की। प्रादेशिक भाषाएँ होंगी उसकी शक्ति।

उद्देश्य और इच्छाओं के अलावा हिन्दी अहिन्दीभाषी राज्यों को यह अधिकार प्राप्त है कि जब तक विधान-सभा, लोक सभा तथा राज्य सभा में उनके प्रतिनिधि अपने भारी बहुमत से अंग्रेजी हटाने का प्रस्ताव पास न करें तब तक—यानी अनिश्चित काल के लिए—अंग्रेजी ही भारत की राष्ट्रभाषा रहेगी।

इस पर भी कुछ लोगों को यह दुस्वप्न होता है कि कांग्रेस के प्रस्ताव ॥ हिन्दी साम्राज्यवाद के लिए रास्ता साफ हो गया है। यदि लोकसभा यह प्रस्ताव पास कर दे कि भारत में सदा-सर्वदा के लिए अंग्रेजी एकमात्र राजभाषा रहेगी, तब भी ये लोग कहेंगे, उत्तरवाले दक्षिणवालों पर राज्य कर रहे हैं। जिन लोगों की नीति है कि हर बहाने 'द्रविड-भारत' को 'आर्य-भारत' से अलग कर दिया जाय, वे अंग्रेजी के बारे में किसी भी आश्वासन से सन्तुष्ट नहीं हो सकते।

अंग्रेजी की जड़ मजबूती से जमी है। कांग्रेस कार्यसमिति के प्रस्ताव की कानूनी रूप देने से वह और भी पुस्ता हो जाएगी। किसी को यह भय न होना चाहिए कि प्रादेशिक भाषाओं को नये अधिकार मिल गए हैं और अब अंग्रेजी के अभाव में राष्ट्रीय एकता छिन्न भिन्न हो जाएगी।

यदि अंग्रेजी से राष्ट्रीय एकता दृढ़ होती थी तो भविष्य में वह और भी सुदृढ़ हो जाएगी।

किन्तु क्या सचमुच अंग्रेजी से राष्ट्रीय एकता दृढ़ होती है ?

सन '४७ में जब एक राष्ट्र से दो राष्ट्र बने, तब अंग्रेजी-पढ़े लोग ही विघटनकारी प्रकार के समुदाय थे। बम्बई में संयुक्त महाराष्ट्र आन्दोलन के दौरान गुजरातियों और मराठी-भाषियों में संघर्ष हुआ। उसके नेता भी अंग्रेजी पढ़े लोग थे। असम में बंगालियों और असमियों के बीच दंगे हुए। वहाँ भी भाषा सम्बन्धी आन्दोलन के नेता थे अंग्रेजी पढ़े भद्र लोग। तमिलनाडु में जो उत्पात हुआ, उसके सूत्रधार अंग्रेजी-प्रेमी सज्जन थे। कश्मीर में अलगाव के नेता विलायत जाकर अंग्रेजी में भाषण देनेवाले लोग हैं। नागालैण्ड के अलगाव पन्थी नेता विलायत ही में निवास करते हैं।

अंग्रेजी पढ़ा वर्ग भारत में विघटन प्रक्रिया रोकने में असमर्थ है। दिवालिये राजनीतिज्ञ राष्ट्रीय एकता कायम रखन के लिए जितना ही इस समुदाय का भरोसा करते हैं उतना ही विघटनकारी शक्तियाँ प्रबल होती जाती हैं।

राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करने का दूसरा तरीका है जन-साधारण का भरोसा करना, फौलाद ढालनेवालों और अन्न पैदा करनेवालों की एकता के बल पर राष्ट्र को मजबूत करना। इस तरह की स्थायी और अपराजेय एकता हिन्दी से कायम हो सकती है, अंग्रेजी से नहीं।

कांग्रेस कार्यसमिति के प्रस्ताव में इस तरह की एकता पर ध्यान नहीं दिया गया। उसमें भरोसा किया गया है अखिल भारतीय सेवाओं में लग हुए नौकर-शाहों का। प्रस्ताव में एकता का माध्यम हिन्दी नहीं, अंग्रेजी है। अंग्रेजी को हटाने के लिए कोई अवधि निश्चित नहीं की गई। इसलिए इस प्रस्ताव का विरोध

ही किया जा सकता है, स्वागत नहीं।

समस्त प्रादेशिक भाषाओं को अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त करने के दो उपाय हैं—

(१) केन्द्र में अंग्रेजी की जगह हिन्दी हो, राज्यों में प्रादेशिक भाषाएँ राजभाषा हो,

(२) राज्यों में तो प्रादेशिक भाषाएँ राजभाषा हो ही, केन्द्र में भी अंग्रेजी की जगह उन सबका व्यवहार हो।

पहला उपाय ज्यादा व्यावहारिक है, मविधान के अनुबल है। लोक-राज-नीतिक दल उसका समर्थन भी करते हैं। किन्तु जब प्रश्न उठता है, कब तक अंग्रेजी हटाई जाएगी, सब परिवर्तन की अवधि अनिश्चित हो जाती है। नेताओं के सामने सीधा-सा बहाना है। अहिन्दीभाषी नहीं चाहते कि हिन्दी केन्द्रीय राजभाषा हो, इसलिए किलहास अंग्रेजी ही चलेगी।

ऐसी स्थिति में अंग्रेजी हटाने के दूसरे उपाय पर भी विचार करना चाहिए। यह उपाय कठिन है, व्यय-साध्य है, किन्तु असम्भव नहीं है। स्विट्जरलैण्ड में जर्मन, फ्रांसीसी और इतालवी को समान अधिकार प्राप्त हैं। हमारे यहाँ भी केन्द्र में सभी भारतीय भाषाओं का चलन हो सकता है।

कांग्रेस के नेता कहते हैं जब तक अहिन्दीभाषी राज्य हिन्दी को स्वीकार नहीं करते, तब तक केन्द्र में अंग्रेजी चलेगी।

हिन्दीभाषी जनता उनसे कह सकती है जब तक अहिन्दीभाषी राज्य हिन्दी को स्वीकार नहीं करते, तब तक केन्द्र में सभी भारतीय भाषाओं का व्यवहार होने दीजिए।

यदि देश के नेताओं को प्रादेशिक भाषाओं से सच्चा प्रेम है तो वे केन्द्र में अंग्रेजी की जगह उनका व्यवहार क्यों नहीं करते?

यदि भाषाओं के अवि सित होने का सवाल हो, तो कमीशन बिठाकर इस बात की जाँच कराएँ कि भारतीय भाषाओं के विकास में कौन-सी कमी रह गई है।

जो नेता भारतीय भाषाओं के अविकसित होने से परेशान हैं, उन्हें अपनी शिक्षा के स्तर पर भी ध्यान देना चाहिए।

विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दों से सम्बन्धित कठिनाई हो सकती है। लेकिन यहाँ सवाल राजकाज के लिए भारतीय भाषाओं के व्यवहार का है। क्या लोकसभा में आज तक कोई ऐसा भाषण हुआ है जिसके लिए अंग्रेजी ही माध्यम बन सकती थी, जिसकी विषयवस्तु प्रकट करने की क्षमता भारतीय भाषाओं में नहीं थी? क्या इस बात पर विश्वास किया जा सकता है कि जिन भाषाओं में रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सुब्रह्मण्य भारती, बल्लत्तोल, प्रेमचन्द आदि ने अपनी महान् साहित्यिक रचनाएँ की हैं, उनमें श्री लालबहादुर शास्त्री या श्री हीरेन मुर्जो या अन्य राजनीतिज्ञ अपना मन्तव्य प्रकट नहीं कर सकते?

असल में बात यह है कि अधिकांश राजनीतिक पार्टियाँ अपने जन्मबाल से अब तक अपना अखिल भारतीय राजनीतिक कार्य अंग्रेजी में ही करती रही हैं। इनके नेता तरह-तरह के बहाने करते हैं, अपने अनुयायियों को तरह-तरह से बहकाते हैं। वे अपने दफ्तरों में अंग्रेजी निकाल नहीं पाते। जब तक जनता इनके दफ्तरों के सामने प्रदर्शन न करेगी, इनके केन्द्रीय भवनों से अंग्रेजी निकालने के लिए इन पर दबाव न डालेगी, तब तक वे नेता अपनी नीति से बाज न आएँगे। भारतीय जनतन्त्र के मंचालक ये ही लोग हैं। वे अपने पार्टी-कार्यों में अंग्रेजी से चिपके हुए हैं। सब सरकारी दफ्तरों और विश्व-विद्यालयों से अंग्रेजी क्या खाकर निकालेंगे ?

इस समय नेता सोग देश में हवा बाँधे हैं कि अंग्रेजी के बिना न राष्ट्रीय काम चल सकता है, न अन्तर्राष्ट्रीय। यह हवा सिर्फ ऊपर-ऊपर है। गरीब जनता का काम तो अंग्रेजी के बिना ही चलता है। ऐसी हालत में जो राजनीतिक पार्टी अपने केन्द्रीय राजकाज में अंग्रेजी का चतान खरम करती है, वह देश की बहुत बड़ी सेवा करती है। वह लोगों में आत्मनिर्भरता की चेतना दृढ़ करती है। वह अंग्रेजी प्रेमियों को दिखता देती है कि अंग्रेजी के बिना भी काम चल सकता है।

श्री कामराज नाडार कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए भी तमिल में भाषण करते हैं। इसका देश में विघटन पैदा नहीं हो गया। क्या ही अच्छा हो यदि राष्ट्रसंघ में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता एक बार श्री कामराज हो और वहाँ जाकर तमिल में भाषण करें।

सोवियत संघ के प्रतिनिधि मन्थुल्स्की ने एक बार राष्ट्रसंघ के सामने उकैनी में भाषण किया था। तब श्री कामराज वहाँ तमिल में भाषण क्यों नहीं कर सकते ? मिस्र के अध्यक्ष श्री नासिर राष्ट्रसंघ के सामने अरबी में भाषण कर सकते हैं तो हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन के सामने हिन्दी में भाषण क्यों नहीं कर सकते ? भारतीय भाषाओं के व्यवहार में अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारा कमजोर नहीं होता, वरन् मित्र-देशों में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री सोवियत संघ गए, तब जगह-जगह हिन्दी वाक्यों से सजे हुए बन्दनधारों से उनका स्वागत किया गया। इससे सोवियत-भारत मैत्री कमजोर नहीं हो गई।

क्या ही अच्छा होता यदि काग्रस कार्यसमिति स्वयं अपने लिए एक प्रस्ताव पास करती कि भविष्य में उसका काम अंग्रेजी में न होगा, भारतीय भाषाओं में ही होगा।

भारतीय जनतन्त्र के कर्णधार हमारे सीमित साहित्यिक अनुभव की ओर भी दृष्टिपान कर लें।

भारतीय भाषाओं ने एक-दूसरे को प्रभावित किया है, विभिन्न प्रदेश सांस्कृतिक स्तर पर एक-दूसरे के निरुद्ध आए हैं; रवीन्द्रनाथ ठाकुर से लगभग

सभी प्राधुनिक भाषाओं के लेखक न्यूनाधिक प्रभावित हुए हैं, सरत्चन्द्र और प्रेमचन्द की रचनाओं से करोड़ों पाठक परिचित हैं—यह सब अंग्रेजी के कारण सम्भव नहीं हुआ। जो गीत श्रीनगर से कन्याकुमारी तक—और देश की सीमाएँ पार करके वेरावल से सिंदल तक—गूँजे हैं, वे अंग्रेजी के सम्पर्क-भाषा होने के कारण नहीं।

अंग्रेजी के बिना भी काम चल सकता है। अंग्रेजी के बिना ही काम चलेगा। स्वाधीन भारत में अंग्रेजी नहीं चलेगी।

भारत सरकार लोकसभा में सभी भाषाओं में बोलने और भाषणों के अनुवाद की व्यवस्था करे। लोकसभा, राज्यसभा की कार्यवाही, कानून, मसौदे—सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हों, अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय भाषाओं का व्यवहार हो। बाप्रेस की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि इस सारे परिवर्तन का भार उठाये। अहि-दीमायी जनता हिन्दी नहीं चाहती, यह कहकर वह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

एक बार लोकसभा में जब हमारे प्रतिनिधि भारतीय भाषाओं में बोलेंगे, तब उनका अंग्रेजी मोह कम होगा। तब उन्हें बाध होगा कि हिन्दी से अन्य भाषाओं का दमन नहीं होता, वरन् उनसे राष्ट्रीय एकता दृढ़ होती है। एक बार जब उन्हें विश्वास हो जाएगा कि उनकी भाषा को वही अधिकार प्राप्त है, जो हिन्दी को है, तब वे स्वेच्छा से हिन्दी बोलेंगे। जब तक अंग्रेजी अनिवार्य राजभाषा बनी हुई है, तब तक स्वेच्छा से हिन्दी बोलने की बात उनकी समझ में न आएगी।

जो लोग सचमुच चाहते हैं कि अहिन्दीभाषी राजनीतिज्ञ स्वेच्छा से हिन्दी को केन्द्रीय भाषा मानें, वे अब तक जनता के सामने कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं रख सके जिससे इस उद्देश्य की पूर्ति हो। वे समझते हैं कि 'कलहाल' अंग्रेजी कायम रखने से अपने प्रायः अहिन्दीभाषियों में 'स्वेच्छा' उत्पन्न हो जाएगी। पिछले पन्द्रह साल का अनुभव कुछ दूसरा है। अंग्रेजी की जड़ें और मजबूत हुई हैं। शिक्षित वर्ग के सामने से स्वेच्छापूर्वक हिन्दी अपनाने की बात दूर चली गई है। इस स्थिति का मूल कारण है अंग्रेजी की पालपोतकर मजबूत करने की नीति। अहिन्दीमायी राजनीतिज्ञों के हिन्दी विरोध का कारण यह नहीं है कि उन पर जबदस्ती हिन्दी लादी गई है। हिन्दी विरोध का कारण यह है कि वे 'स्वेच्छा' से अपने ऊपर अंग्रेजी लादे रखना चाहते हैं।

इसी समझ का बदला है।

सभी भारतीय भाषाओं को केन्द्र में समान अधिकार प्राप्त हो—इस आधार पर अंग्रेजी के विरुद्ध सभी सच्चे भारतीय भाषा प्रेमियों की एकता स्थापित की जा सकती है।

राष्ट्र के नेताओं से निवेदन है जब तक अहिन्दीभाषी नेता केन्द्रीय राज-भाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार नहीं करते, तब तक सभी भारतीय भाषाओं

को केन्द्रीय राजभाषा बनाए रहिए। अंग्रेजी हटाने का यह कार्यक्रम अगले पांच वर्ष में पूरा कीजिए। पूर्व-निश्चित अवधि के पन्द्रह वर्ष पहले ही बीत चुके हैं। पांच वर्ष की प्रतिरिक्त अवधि काफी है। शिक्षाक्रम में अंग्रेजी को वैकल्पिक बनाइए। केन्द्रीय सेवाओं तथा विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी की अनिवार्यता पांच साल में खत्म कीजिए।

अंग्रेजी की दासता से भारतीय भाषाओं को मुक्त करना हर देशभक्त का पवित्र कर्तव्य है। इस कर्तव्य को पूरा करके राष्ट्र के नेता जन्ता के श्रद्धाभाजन बनेंगे। इसके विपरीत यदि उन्होंने अंग्रेजी को राजभाषा बने रहने दिया तो भावी विघटन के लिए उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। (१९६५)

प्रगतिशील साहित्यकार और भाषा-समस्या के जनतांत्रिक समाधान

प्रगतिशील साहित्यिक आन्दोलन के आरम्भ में उसकी भाषा-सम्बन्धी मान्यताएँ वही थीं जो गांधीजी के नेतृत्व में चलनेवाले राष्ट्रीय आन्दोलन की थीं। अंग्रेजी की जगह हिन्दी या हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा होगी, हिन्दी-उर्दू मूलतः एक ही भाषा हैं और उन्हें मिलाना प्रगतिशील लेखकों का कर्तव्य है, ये मान्यताएँ प्रेमचन्द के भाषणों में थीं। उस समय हिन्दी-उर्दू हिन्दुस्तानी का लेखक जोरदार बहस हाँती थी। हिन्दी-उर्दू बुनियादी तौर से एक ही भाषा हैं, इस बात को प्रायः सभी लेखक मानते थे। यह मान्यता नयी नहीं थी। बालमुकुन्द गुप्त जैसे लेखक बहुत पहले इस मान्यता को स्पष्ट शब्दों में प्रकट कर चुके थे। बहुत इस चीज को लेकर भी कि हिन्दुस्तानी भाषा बन चुकी है या बनाई जाय, उसका रूप उर्दू के अधिक निकट है या हिन्दी के, हिन्दी-उर्दू को मिलाने के लिए निम्न दोन-सीं हैं।

हिन्दीभाषी प्रदेश में उस समय प्रगतिशील साहित्यिक आन्दोलन के संगठनकर्ता और समोजक ज्यादातर उर्दू के लेखक थे। प्रेमचन्द हिन्दी-उर्दू दोनों के लेखक माने जाते थे। सन् '३६ में, इस नये साहित्यिक आन्दोलन के आरम्भ में ही, उनका देहान्त हो गया। अब इसके नेतृत्व में ऐसा लोग रह गये जो या तो उदीयमान साहित्यकार थे जैसे श्री अली सरदार जाफरी या साहित्यकार कम और आन्दोलनकारी ज्यादा थे जैसे डॉ० अब्दुल अल्लम और श्री संमद सज्जाद जहीर।

'३३८ में बलवत्ते में दूसरा अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक-सम्मेलन हुआ। इसमें डॉ० अब्दुल ग़नीम ने 'हिन्दुस्तानी की समस्या' नाम से अंग्रेजी में एक निबन्ध पढ़ा। इसमें उन्होंने कहा कि हिन्दी-उर्दू दो भाषाएँ नहीं हैं बरन् वे एक ही भाषा के दो साहित्यिक रूप हैं। हिन्दुस्तानी उस प्रदेश की भाषा है जिसे पुराने जमाने में लोग हिन्दुस्तानी कहते थे। इस प्रदेश के उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में विन्ध्याचल, पश्चिम में पञ्जाब और पूर्व में बंगाल है। मुगल छावनीयों की ज़बान को ज़बान ए उर्दू-ए-मुग़ल्ला, संक्षेप में उर्दू, कहा जाता था।

“इसका प्रचलित नाम हिन्दी था जो प्रारम्भिक मुस्लिम विद्वानों का दिया हुआ था और जिसका अर्थ था हिन्द की भाषा।” अक्बर के जमाने में प्राकृतों पर फारसी का असर पड़ने लगा। “यह असर डालनेवाले खत्री और कायस्थ थे जिन्होंने फारसी सीखी। फारसी राजभाषा थी। वे अपनी धाम बोलचाल में फारसी के लफ्ज जैसे ही इस्तेमाल करने लगे जैसे कि ज्यादातर पढ़े-लिखे लोग आजकल अंग्रेज़ी के शब्द इस्तेमाल करते हैं।” १७१६ ई० में दक्खिन के शाहजहाँ की काव्य-संग्रह दिल्ली पहुँचा। उत्तर के प्रारम्भिक मुस्लिम कवियों ने ज्यादातर पुराने भारतीय छन्दों का प्रयोग किया था। दक्खिन के कवि फारसी की बहरे इस्तेमाल करते थे। “आश्चर्य की बात है कि उत्तर के शाहजहाँ की कविता का यह नया ढंग इतना अच्छा लगा कि वे दिल्ली की ज्यादा कुछ भाषा में (यानी उस भाषा में जो ज्यादा फारसी-मिश्रित नहीं थी) बली के रंग-ढंग की नकल करने लगे। तभी से दोनों में भेद शुरू हुआ जो अब बढ़ते-बढ़ते बहुत चौड़ी खाई बन गया है।”

डॉ० अलीम की ये स्थापनाएँ बहुत महत्वपूर्ण थी। वह एक खास प्रदेश की भाषा को हिन्दुस्तानी कहते थे। इस प्रदेश का पुराना नाम हिन्दुस्तान था, यह उन्होंने ठीक कहा था। तुर्क लेखकों शासकों इतिहासकारों ने हिन्दुस्तान शब्द का बराबर प्रयोग किया है। डॉ० अलीम ने भाषा का सम्बन्ध किसी धर्म से नहीं जोड़ा। उन्होंने बोलचाल की भाषा में फारसी शब्दों की घामद का बहुत सही कारण बतलाया। उन्होंने हिन्दू मुस्लिम संस्कृतियों के मिल से नयी भाषा बनने की बात नहीं की। फारसी के शब्द बोलचाल की भाषा में इसलिए नहीं आ गए कि वे हिन्दू-मुस्लिम-मिलन के लिए आवश्यक थे। वे इसलिए आए कि फारसी राजभाषा थी और इस राजनीतिक-सांस्कृतिक प्रभाव के कारण बोलचाल की भाषा में बहुत से फारसी शब्द घुल मिल गए। लेकिन बोलचाल की भाषा का साहित्यिक रूप एक ही था। उसके दो रूप तब हुए जब बली की नकल करने-वाले उत्तर के कवियों की रचनाओं में फारसीयत का रंग गाढ़ा होने लगा। उर्दू का यह साहित्यिक विकास अठारहवीं सदी की घटना है और मुसलमानों के भारत आने में, भारत में हिन्दू-मुस्लिम संस्कृतियों के मिलन से या इस्लाम से उसका कोई सम्बन्ध न था।

यह एक सही वैज्ञानिक और साम्राज्य विरोधी दृष्टिकोण था। गिलक्रिस्ट और ग्रियर्सन उर्दू-हिन्दी का सम्बन्ध धर्म से जोड़ चुके थे। डॉ० अलीम ने उस सम्बन्ध को अस्वीकार करके भाषा-समस्या के वैज्ञानिक विवेचन और सही समाधान की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाया था। धर्म को आधार मानकर कोई समस्या हल नहीं की जा सकती, न लिपि की, न शब्दों के चुनाव की। हिन्दी-उर्दू समस्या पर जो भी विचार करे, उसे शुद्धता इस सूत्र से करना चाहिए कि वे एक ही जाति की भाषा हैं, धर्म के आधार पर हिन्दू-मुस्लिम दो कोमें नहीं हैं, उर्दू और हिन्दी का बुनियादी बोलचाल का रूप एक है।

हिन्दी-उर्दू में भेद होते हुए भी उनके साहित्य में बहुत बड़ी समानता है। डॉ० अलीम के लेख में इस समानता पर जोर नहीं है। उन्होंने हिन्दी और उर्दू को कृत्रिम रूप कहकर घटा बटा दी। इससे हिन्दी और उर्दू के प्रगतिशील लेखक हिन्दी-उर्दू साहित्य को प्रभावित करने के बदले उससे अपने को प्रलग कर सकते थे। उन्होंने भीर भ्रमन और सल्लूजी लाल के बाद नमाम साहित्यिक विकास को हिन्दुस्तान के विकास के लिए घातक बनाया। उन्होंने कांग्रेस को फटकारा कि इतने दिन से हिन्दुस्तानी की माना जपने के बाद भी उसके विकास के लिए उसने कुछ नहीं किया। उन्होंने इसाहावाद की हिन्दुस्तानी प्रकारभी को सुझाया कि वह हिन्दुस्तानी के विकास की योजना बनाए। उन्होंने 'हिन्दी प्रथवा हिन्दुस्तानी' शब्दों का व्यवहार हानिकारक बताया (क्योंकि इसमें हिन्दुस्तानी का सम्बन्ध हिन्दी से जुड़ता था)। प्रगतिशील लेखकों से उन्होंने कहा, मुख्य समस्या यह है कि हिन्दुस्तानी अभी विकसित साहित्यिक भाषा नहीं है; आप लोगों को उसे विकसित कर देना चाहिए। पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी से लेने की सलाह दी जो उनकी समझ में अधिकांश सम्य दलों की भाषाओं में सामान्य थे। लिपि की समस्या, डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी की राय का समर्थन करते हुए उन्होंने रोमन लिपि अपनाकर हल करने की सलाह दी।

रोमन लिपि अपनाने में उन्हें सबसे बड़ा लाभ यह दिखाई दिया, "इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि अपनी लिपियों को छोड़ देने से अपने बहुत से पुराने साहित्य से हमारा सम्बन्ध अपने घाप टूट जाएगा। धार्मिक पुनरुत्थानवादी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं के प्रामाण्य परिवर्तन में विद्वान् करते हैं। हम अपने साहित्य की बुद्धिसंगत बनाने में (इन रैशनलाइजिंग भवर लिटरेचर) विद्वान् करते हैं। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसी लिपि अपनाएँ जो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक हो और जिसे अपनाकर हम आधुनिक ससार की आवश्यकताएँ पूरी कर सकें।"

इस प्रकार डॉ० अलीम का दृष्टिकोण पुरानी साहित्यिक विरासत की तरफ बिल्कुल अस्वीकृति का था। यह दृष्टिकोण वास्तव में साम्राज्यवादी लेखकों का रहा है जो भारत की सांस्कृतिक उपनदियों की झुमेला अपनाय कर रहे हैं। सार्द मैकाले ने कुछ ऐसी ही बातें अपने प्रसिद्ध निबन्ध में कही थीं। डॉ० अलीम भारत की अन्य भाषाओं के साहित्य से अपरिचित थे; वह हिन्दी पढ़ लेते हैं लेकिन कम-से-कम सन् '३८ में जब उन्होंने यह निबन्ध लिखा था, तब वह हिन्दी साहित्य के विकास से अपरिचित थे। उनके मुख्य सहायकार श्री मुल्कराज धानन्द भारतीय साहित्य की प्रगति से और भी कोरे थे। प्रेमचन्द के प्रभाव में ऐसा कोई लेखक नहीं था जो इन्हें सर्वांगतावाद में बंधाता। राष्ट्रीय आन्दोलन में आधुनिक साहित्य का सम्बन्ध न समझने के कारण उन्होंने हिन्दी-उर्दू के साहित्य के प्रति यह सर्वांग दृष्टिकोण अपनाया। राष्ट्रीय आन्दोलन और भारतीय साहित्य में नव-जागरण की न समझने के कारण वे बहुत जल्दी ऐसे

प्रगतिशील साहित्यकार और भाषा-समस्या के जनतांत्रिक समाधान / ९

नेताओं के प्रभाव में था यह जो आत्मनिर्णय के नाम पर मुस्लिम लीग और पाकिस्तान का समर्थन करते थे।

इन नये नेताओं में श्री सैयद सज्जाद जहीर मुख्य थे। सन् '३८ में प्रखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री डॉ० अब्दुल मलीम थे, द्वितीय महा-युद्ध के दौरान उसके मंत्री हुए सज्जाद जहीर साहब। डॉ० मलीम की तुलना में वह साहित्यकार कुछ ज्यादा थे। उनका 'लन्दन की एक रात' उपन्यास सन् '३८ के आस पास छप चुका था। सन् '४३ से सन् '४६ तक वह कम्युनिस्ट पार्टी के भूतपूर्व नेता श्री पूरन जोशी के दाहने हाथ रहे। मुस्लिम समस्या पर उन्हें सलाह देने के अलावा श्री जोशी की आत्मनिर्णय वाली नीति को वह मुसलमानों में लागू भी करते थे। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का नारा था, कांग्रेस लीग एक हो। यह नारा इस समय के आधार पर दिया गया था कि भारत में दो राष्ट्र या दो तरह की राष्ट्रियता विकसित होती रही हैं—एक हिन्दुओं की, दूसरी मुसलमानों की। इन दोनों को मिलकर अंग्रेजों से सत्ता देने की माँग करना चाहिए।

मुसलमानों की अलग कीम है, उसे आत्मनिर्णय का अधिकार दानी देश से अलग होकर अपना राज्य बनाने का हक मिलना चाहिए, इस सिद्धान्त को भाषा-क्षेत्र में लागू किया जाय तो यह नतीजा निकलेगा ही कि हिन्दुओं की भाषा हिन्दी है, मुसलमानों की भाषा उर्दू है।

हिन्दी-उर्दू में भेद क्यों हुआ ? इसलिए कि हिन्दुओं ने उर्दू का ढाँचा लेकर उसमें उन शब्दों को भरा जिनका सम्बन्ध हिन्दू संस्कृति से था।

हिन्दी-उर्दू-हिन्दुस्तानी समस्या का हल' नाम के निबन्ध में श्री सज्जाद जहीर ने लिखा, "आधुनिक हिन्दी ने कभी बोली का ढाँचा उर्दू से लिया और उसमें उसने उन शब्द-योजनाओं और परम्पराओं से उसे अनुप्राणित किया, जो हिन्दू संस्कृति के अभिन्न अंग थे।"

आधुनिक युग में राष्ट्रीयता का अन्वेषण कैसे हुआ ? राजा राममोहन राय ने 'अंग्रेज ईसाई मिशनरियों के हमले से हिन्दू धर्म को बचाने के लिए' ब्राह्म-समाज की नींव डाली। इसका प्रभाव आधुनिक बंगाली संस्कृति के विकास पर पड़ा और बंगाल के 'इसी आन्दोलन से प्रभावित होकर हिन्दी साहित्य के प्रथम मजारफी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपना आन्दोलन शुरू किया। उनकी रचनाओं में 'मध्यवर्ग के शिक्षित हिन्दुओं के हृदय में वह नैराश्य और धिपाई दूर कर दिया जो पराधीनता के कारण देश में छा गया था।' भारतेन्दु ने 'प्राचीन हिन्दू महापुरुषों और देवताओं को रंगमंच पर लाकर हिन्दुओं को उनके विगत वैभव' की याद दिलाई, 'हिन्दू-समाज की बुराइयों' की आलोचना की।

इस प्रकार 'हिन्दी उत्तर भारत में (विशेषकर मुक्त प्रान्त, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रान्त के हिन्दुस्तानी भाग में) हिन्दू राष्ट्रीय जागरण का—जिम्मे विभिन्न पक्ष अथवा रूप धर्मोद्धार, धर्म-सुधार, समाज सुधार और नवीन

निष्ठा-प्रचार है—एक शक्तिशाली माध्यम बन गई।”

श्री मज्जाद जहीर ने भारतेन्दु युग के साहित्य में जो साम्राज्य-विरोधी तत्त्व थे, जिनका सम्बन्ध हिन्दू-समाज से ही नहीं, सारे भारत से था, उन्हें नज़र-आज किया। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि भारतेन्दु, प्रताप-नारायण पन्थ और बालमुकुन्द गुप्त जैसे हिन्दी लेखक उर्दू में भी लिखते थे। उन्होंने गिलक्रिस्ट और ग्रिमसन से दो कदम आगे बढ़कर धर्म के आधार पर साहित्य और भाषा का बँटवारा कर दिया। जो धार्मिक भावनाएँ पुराने साहित्य में रही हैं, उन्हें उस साहित्य का एक पक्ष न मानकर, उन्होंने उन भावनाओं को राष्ट्रीय जागरण का मुख्य चिह्न मान लिया।

कही उनके दिमाग में एक पुराना बीजा भी रेंग रहा था। यह मुस्लिमों जवान का बीजा था। हिन्दुओं और मुसलमानों के मेल-जोल से उर्दू का जन्म और विकास हुआ। हम मम्मिनित विकास को खत्म कर दिया सम्प्रदायवादी हिन्दुओं ने।

“उर्दू अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में उत्तर और मध्य भारत के मम्मिनित सामाजिक जीवन के सांस्कृतिक आदान-प्रदान की स्वाभाविक माध्यम बन गई थी।” उर्दू लेखकों में रतननाथ सप्यार जैसे हिन्दू थे। पुराने पश्चिमोत्तर प्रान्त—घाज के उत्तर प्रदेश—में १८६६ में चौबीस पक्ष निकलते थे, उन्नीस उर्दू में, तीन हिन्दी-उर्दू दोनों में। इनमें अधिकांश के मालिक और सम्पादक हिन्दू थे। १८७१ में प्रथम में जो विचारों उर्दू पड़ते थे, उनमें ज्यादातर हिन्दू थे। “अतः उर्दू भाषा और उसकी लिपि के विरोध और बहिष्कार को लेकर जो हिन्दी नागरी आन्दोलन आरम्भ हुआ, इसको अपने समाज और संस्कृति पर हिन्दुओं की ओर से अन्यायपूर्ण, संवृद्धित, साम्प्रदायिक प्रहार समझना मुसलमानों के लिए स्वाभाविक था।”

हिन्दुओं और मुसलमानों के सांस्कृतिक आदान-प्रदान का माध्यम उर्दू बनी। यह कार्य भी स्वाभाविक था। हिन्दी-आन्दोलन को मुसलमानों ने अन्यायपूर्ण समझा, यह भी स्वाभाविक था। हिन्दी हिन्दुओं की सांस्कृतिक भाषा बनी, यह भी स्वाभाविक था।

ये तीन स्वाभाविक त्रियाएँ एक साथ कैसे हो गईं? जहीर साहब के अनुसार हिन्दुओं और मुसलमानों की मूलन दो संस्कृतियाँ हैं। इनकी प्रागे चलन चलन विकसित होना ही था। “आरम्भ से ही मुसलमानों के निकट हिन्दी और देव-नागरी लिपि आन्दोलन हिन्दुओं की बट्टर साम्प्रदायिकता और मुस्लिम संस्कृति-विरोध का द्योतक रहा है।” इसलिए “१९०० से जब देवनागरी भी उर्दू के समान प्रचलन में जारी हो गई, तो मर सैयद को विश्वास हो गया कि ‘अध हिन्दुओं और मुसलमानों का एक राष्ट्र होकर अपने धर्ममुत्थान के लिए मम्मिनित प्रयत्न करना असम्भव हो गया है।’ उसी समय उर्दू-रक्षा-मिति मर सैयद के तत्वावधान में कायम हुई।”

मुसलमानों का मतलब राष्ट्र हो, उर्दू की रक्षा का प्रयत्न किया जाय—दोनों बातों का उल्लेख साथ-साथ किया गया है। श्री सज्जाद जहीर के पास हिन्दी-उर्दू विरोध का हल क्या है? या अठारह साल पहले उनके पास कौन-सा हल था? उनके पास वही हल था जो सर सैयद अहमद खाँ ने बताया था और जिसका सर मुहम्मद इक्बाल ने नये सिरे से प्रचार किया था।

उर्दू हिन्दुओं और मुसलमानों की एकमात्र मिली-जुली भाषा न रह सकी। कारण था हिन्दुओं की साम्प्रदायिक कट्टरता। इसलिए हिन्दू अलग, मुसलमान अलग, एक राष्ट्र की भाषा हिन्दी, दूसरे की उर्दू।

जिसे राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान साम्प्रदायिकता कहा जाता था, उसी को श्री सज्जाद जहीर और उनके सहयोगी श्री पूरनचन्द ओशी राष्ट्रीयता कहने लगे। हिन्दू राष्ट्रवाद, मुस्लिम राष्ट्रवाद—ये दो नये ढंग के राष्ट्रवाद सामने आए। एक का प्रचार मुस्लिम लीग ने किया, दूसरे का, उससे पीछे, उसके चरणधिल्लों पर चलकर, हिन्दू महासभा और जनसंघ ने। इन्हे मार्क्सवाद के नाम पर वैज्ञानिक ठहराया श्री सज्जाद जहीर ने।

मुसलमानों ने हिन्दी-आन्दोलन का विरोध किया। 'इस व्यापक विरोध को समझने के लिए हमें यह जानना चाहिए कि मुसलमानों के लिए उस समय यह समझना कठिन था कि हिन्दी नागरी आन्दोलन हिन्दुओं के देशव्यापी सांस्कृतिक नवोत्थान का ही एक अंग था।' यह हिन्दुओं का नवोत्थान जारी रहा और उसे आगे बढ़ाया महात्मा गांधी ने।

चीकने की बात नहीं है। गांधीजी के राष्ट्रीय आन्दोलन को जिन्ना साहब हिन्दू आन्दोलन कहते थे या नहीं? फील्ड मार्शल अम्बेडकर खाँ हिन्दू भारत से मुस्लिम कश्मीर को आजाद कराने का जेहाद शुरू कर चुके हैं या नहीं? ब्रिटिश प्रचारक कहते हैं या नहीं कि श्री लालबहादुर शास्त्री पाकिस्तान से इसलिए लड़ रहे हैं कि वह हिन्दू हैं?

जहीर साहब के वैज्ञानिक विवेचन के अनुसार "सन् १९२० में जब राष्ट्रीय आन्दोलन की एक नयी लहर कांग्रेस और महात्मा गांधी के नेतृत्व में उठी, तो इसके बाद हिन्दुओं में हिन्दी का और भी अधिक प्रासंगिकता मिली। बाबू मैथिली-शरण गुप्त ने अपना सुप्रसिद्ध काव्य 'भारत-भारती' इसी युग के आस पास (सन् १९१३) में लिखा। यह कविता उन गांधीवादी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो इस समय उत्तरी भारत के हिन्दुओं को आन्दोलित कर रही थी।"

सन् '२० में जो राष्ट्रीय आन्दोलन की नयी लहर उठी, उसने सात साल पहले की रचना 'भारत-भारती' को प्रभावित किया और इसमें वे गांधीवादी भावनाएँ हैं जो उस समय के हिन्दुओं को आन्दोलित कर रही थी।

उधर 'हिन्दुओं के ही समान उत्तरी भारत के मुसलमानों में 'राष्ट्रीय आन्दोलन' की लहर उठ रही थी। इस राष्ट्रीय आन्दोलन का सम्बन्ध गांधीजी के आन्दोलन से नहीं है। बीसवीं सदी के आरम्भ में 'राजनीति' आन्दोलन के

साथ साथ स्वतन्त्रता का भाव भी मुसलमानों में जागने लगा ।" राजनीतिक जागरण ? क्या यह गांधीजी के आन्दोलन का बाहर कोई जागरण था ? स्वतन्त्रता का भाव ? किससे ? अंग्रेजों से या हिन्दुओं से या दोनों से ? उर्दू साहित्य ने नई करवट ली "और शिवली जफर अली खाँ, अबुल कलाम और अन्त में इकबाल ने मुसलमानों के नवीन जागरण को व्यक्त किया ।"

अबुल कलाम आजाद मुसलमानों के 'राष्ट्रीय' जागरण के नेता कंसे बने, यह नहीं बताया गया । मुझे याद है, सन् '४७ के आस-पास इस तरह के 'राष्ट्रीय' जागरण की चर्चा करनेवाले समझते थे कि कांग्रेस और गांधीजी का साथ देने-वाले मुसलमान गुमराह हैं, वे मुस्लिम इतहाद को तोड़नेवाले लोग हैं । मुसलमानों के असली नेता कायदे आज़म जिन्ना और अन्य मुस्लिम लीगो हैं । किंतु इकबाल ने राष्ट्रियता के साथ पहचानी करके साम्प्रदायिकता को अपनाया, स्वभावतः उसकी आलोचना थी ज़हीर के लेख में नहीं है यद्यपि बहुत से उर्दू लेखकों ने इसके लिए इकबाल की आलोचना की थी ।

नतीजा यह कि "आधुनिक उर्दू की तरक्की हिन्दुस्तानी मुसलमानों के विगत सौ वर्षों के राष्ट्रीय जागरण से सम्बद्ध है ।" राष्ट्रीय जागरण से सम्बद्ध है तो नया राष्ट्र बनेगा ही, ज़हीर साहब के अनुसार उर्दू का सारा विकास पाकिस्तान की ओर—भारत के विभाजन की ओर—संबंधित करता था । हिन्दू सम्प्रदायवादी भी उर्दू के दमन के पक्ष में यही सब देते थे । मुश्किल यह थी कि उर्दू के लेखकों में प्रेमचन्द भी थे, वह दाना राष्ट्रीय जागरणों में हिस्सा बँटा रहे थे । क्या कारण है कि किसान जीवन के अमर चित्रकार प्रेमचन्द के सामने होते हुए भी सज़ाद ज़हीर जैम मार्क्सवादी हिन्दी उर्दू साहित्य का सम्बन्ध हिन्दू और मुस्लिम राष्ट्रवाद यानी सम्प्रदायवाद से जोड़ने लगे ? कारण है ग्राम जनता से अलगत्व । उनका जन्म अभिजात वर्ग में हुआ । अपने वर्ग के संस्कार मिटाने के लिए उन्हें ग्राम जनता से जैसा सम्पर्क कायम करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया । ग्राम जनता में काम किए बिना ही वह बहुत जल्दी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बन गए । श्री पूरनचन्द जोशी हमेशा ऐसे लोगों की तलाश में रहे हैं जो ग्राम स्वतन्त्रता के हो, बिलामत जाकर पड़े हो, दिमाग के बच्चे हो जिसमें कि उनकी नयी-नयी स्थापनाएँ आसानी से मान लें । श्री सज़ाद ज़हीर बहुत अच्छे लेखक, बहुत अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता बन सकते थे यदि श्रीमान् पूरनचन्द जोशी ने उन्हें बिगाड़ा न होता ।

इसलिए 'गोदान' की तारीफ करने के बाद इस सम्प्रदाय के तरक्की पसन्द प्रदीप कहते थे कि जब प्रेमचन्द तरक्की पसन्द बन रहे थे, तभी वह स्वर्गवासी हो गए । प्रेमचन्द के विवास को वे बिलकुल न समझते थे । उनका साहित्य हर तरह के सम्प्रदायवाद पर कितना अवदस्त प्रहार है यह उन्हें बिलकुल दिखाई न देता था । एक मित्र ने छह-सात साल पहले अपने एक भाषण में कहा था कि प्रेमचन्द हिन्दुओं की आलोचना तो कर लेते थे, मुसलमानों की आलोचना करते

जैसे उन्हें डर लगता था। मैंने 'समानोचक' में इन हिन्दी लेखक मित्र के आरोप का विस्तार से जवाब दिया था। उन्हीं की तरह '४३-'४७ में बम्बई के कुछ राज-नीतिज्ञ प्रेमचन्द के बारे में कहते थे कि वह महज हिन्दू समाज-सुधारक थे।

दिलचस्प बात है कि 'भारत-भारती' पर जहीर साहब ने स्वर्गीय रामचन्द्र शुक्ल की सम्मति उद्धृत की है। इस सम्मति में कहा गया है, "सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यतावाद, विश्वप्रेम, किसानों और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम और सम्मान, सबकी भद्रक हम पाते हैं।"

इमें भी उन्होंने हिन्दुओं को आन्दोलित करनेवाली बाधीवादी भावनाओं के प्रमाणस्वरूप पेश किया है।

आधुनिक उर्दू साहित्य में फिराक गोरखपुरी, कृष्णचन्दर, राजेन्द्रसिंह बेदी जैसे गैर-मुसलमान लेखक भी हैं। सम्प्रदायवादी बहते हैं कि ये आधे मुसलमान हैं। जहीर साहब की राय यह थी कि "उर्दू साहित्य का अधिकांश पहले भी, और आज और भी अधिकतर मुसलमानों से सम्बन्ध रखता है, और इसी कारण उर्दू साहित्य के अधिकांश भाग पर मुसलमानों की सम्यता और संस्कृति की छाप है। बिल्कुल ऐसा ही हिन्दी के अधिकांश भाग पर हिन्दू सम्यता के प्रभाव स्पष्ट हैं।" इस तरह प्रेमचन्द, फिराक, बेदी, कृष्णचन्दर वगैरह-वगैरह के बाव-जूद श्री सज्जाद जहीर ने साहित्य को हिन्दू-मुस्लिम सम्यता के आधार पर दो हिस्सों में बांट दिया।

उनके दिमाग पर धार्मिक पुनरुत्थानवाद का इतना गहरा रंग चढ़ा हुआ था कि हिन्दी-उर्दू साहित्य में उन्हें हिन्दू-मुस्लिम सम्यता के अलावा और कुछ दिखाई ही न देता था।

हिन्दू सम्प्रदायवादियों से जब कोई कहता है कि आप हिन्दू धर्म का प्रचार करते हैं, धार्मिक सकीर्णता फैलाते हैं, तो वे जवाब देते हैं कि हमारा तात्पर्य धर्म से नहीं है, हिन्दुत्व एक जीवन-पद्धति है, वह इस देश की जीवन-पद्धति है, जो उसे माने वह हिन्दू।

जहीर ग्राह्य ने लिखा था, "जब मैं हिन्दू संस्कृति या मुस्लिम संस्कृति का नाम लेता हूँ तो मेरा तात्पर्य उनके धार्मिक भेदों से नहीं है। भारतीय सम्यता को हम देश के विभिन्न भागों में विभिन्न रूप से देखते हैं, और इनमें हमें अनगिनत समानताएँ मिलती हैं। फिर भी उन इलाकों में जहाँ उर्दू या हिन्दी आम तौर से बोली जाती है, हिन्दू और मुस्लिम संस्कृति का भेद, हमें उर्दू और अंग्रेजी के साहित्यिक रूपों में स्पष्ट दिखाई देता है।"

हिन्दू सम्प्रदायवादी बहते हैं कि सारे भारत में एक ही संस्कृति है, हिन्दू संस्कृति। जहीर साहब बहते हैं, एक नहीं, दो संस्कृतियाँ हैं। हिन्दू संस्कृति तो है ही, एक मुस्लिम संस्कृति भी है।

मुस्लिम संस्कृति किन इलाकों में है? उन इलाकों में जहाँ उर्दू बोली जाती है। क्या सिन्ध और पूर्वी बंगाल की भाषा उर्दू है? नहीं। फिर भी मुस्लिम

संस्कृति के नाम पर भारत का वह सारा हिस्सा बलम किया गया जहाँ किसी की भी मातृभाषा उर्दू नहीं है। जिनकी मातृभाषा उर्दू है वे भारत में ही हैं, इसलिए इलाकाई जवानों की समस्या फिर भी बनी रह गई।

उर्दू में अब भी बहुत से अक्षरों का निकलते हैं जिनमें धूर्वाधार हिन्दू सम्प्रदायवाद का प्रचार होता है। जो उर्दू में लिखे वह भाषा मुसलमान हो जाय, यह आवश्यक नहीं है। एक ही भाषा में हर तरह के विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। भाषा और धर्म दो अलग चीजें हैं। उर्दू में फारसी के जो शब्द आए हैं वे ईरान के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण, धर्म के कारण नहीं। फारसी मुसलमानों की धार्मिक भाषा नहीं है। उनका धर्मग्रन्थ अरबी में है। वह अरबी इस्लाम में पहले भी थी, उसका जन्म इस्लाम के साथ नहीं हुआ। और धर्मग्रन्थ बपति ही धर्म के साथ भाषा का सम्बन्ध जोड़ सकता है। उर्दू के इन रक्षकों को यह नहीं दिखाई देता कि कश्मीरी, सिन्धी, बंगला आदि भाषाएँ बोलनेवाले लाखों मुसलमान हैं जिनका उर्दू से कोई सम्बन्ध नहीं है।

और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जिन्होंने हिन्दी आन्दोलन और हिन्दू राष्ट्रवाद को जन्म दिया, कैसी हिन्दी लिखते थे? क्या उनकी भाषा में सभी शब्द हिन्दी होते थे?

जकीर साहब ने भारतेन्दु की भाषा शैली का बहुत सही वर्णन किया है। लिखा है "भारतेन्दुजी की भाषा पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो उसमें प्रवाह और ओज के साथ साथ यह भी देखते हैं कि वह अपनी हिन्दी में अरबी और फारसी के प्रचलित शब्द निरसकोच प्रयोग करते हैं। उनकी रचना हिन्दी होती है उसमें संस्कृत का मिश्रण होना है, और यह सब और अवधी की परम्पराओं का भी दायन नहीं छोड़ती। इस दृष्टि में हमें और सप्रति प्रचलित उर्दू गद्य की शैली में काफी अन्तर है।"

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अरबी-फारसी के प्रचलित शब्दों को छोड़ा नहीं, उनकी भाषा में संस्कृत शब्द भी होते हैं सब, अवधी आदि की जनपदीय और साहित्यिक परम्पराएँ हमें जुड़ी हुई हैं—क्या हिन्दी-उर्दू की मिनी जुली साहित्यिक परम्परा इस ग्लिन्जिमी और तरह की भाषा अपना सकती है? इस तरह की भाषा पर हिन्दू राष्ट्रवाद का कौन-सा ठप्पा लगा हुआ है? इस भाषा में उर्दू की रक्षा का मतलब क्या होना है? संस्कृत शब्दों का चिह्नकार, सांस्कृतिक शब्दावली केवल अरबी-फारसी से नीचा, जनपदीय शब्दों और हिन्दी की पुरानी साहित्यिक परम्परा के अन्तर्गत। यह उर्दू की रक्षा का नहीं, उसके विनाश का मार्ग है।

दो तरह की संस्कृतियों, दो तरह के 'राष्ट्रीय' जागरणों की मान्यताएँ प्रस्तुत करने के बाद भी जकीर साहब ने फिस्मो में और मजदूर नेताओं के भाषणों में हिन्दी उर्दू का मिना-जुमा रूप देखा, यह उनकी धरापत थी। जब संस्कृतियाँ हिन्दू और मुस्लिम दोनों में विभाजित थीं, तब यह मिनी-जुली भाषा

बोली-भाषा संस्कृति को प्रतिबिम्बित करती थी, जो न हिन्दी थी, न मुगलमान—यह उन्होंने नहीं बनाया।

बाप्रेस सींग एक हो, यह नारा भाषा के क्षेत्र में लागू करते हुए उन्होंने राय दी—“भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी और उर्दू दोनों हों।”

उन्होंने उदारता से लिखा, “उर्दू और हिन्दी के धाज के पारंपरिक को स्वीकार करते हुए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि यह पारंपरिक बम हो।

“इसलिए आवश्यक है कि इन समय हिन्दी और उर्दू का यह भाषा-क्षेत्र जो समान रूप से दोनों का एक है, जिसे सरस उर्दू, सरस हिन्दी या हिन्दुस्तानी का नाम दिया जाता है, कायम रहे और उसकी सीमा बराबर बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय।”

हिन्दी और उर्दू बुनियादी रूप में एक हैं; उनके साहित्यिक, शिष्ट रूप में धाज भेद है, उसे दूर करना चाहिए। दोनों का भाषा क्षेत्र एक है। दोनों का सामाजिक परिवेष्टन एक है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि श्री जहीर ने जानि की मार्क्सवादी व्याख्या पर विचार किया होता तो वह इस मनीषे पर अवश्य पहुँचते कि हिन्दी-उर्दू एक ही जानि की भाषा है, दोनों का साहित्य एक ही जानि का साहित्य है, उनमें एक ही राष्ट्रीय जागरण की भ्रमक है, दो राष्ट्रों के जागरण की नहीं। मार्क्सवाद में वही भी इसका प्रमाण नहीं है कि धर्म के आधार पर भाषा या जानि का निर्माण स्वीकार किया गया हो।

यदि हिन्दी-उर्दू का इलाका एक था, तो बंगाल और सिन्ध में आरामनिर्णय का अधिकार किसके लिए? फिर पाकिस्तान का समर्थन क्यों?

इन प्रश्नों का उत्तर यह है इलाका तो एक है लेकिन “उसकी सीमा बराबर बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय”।

जहीर साहब के दिमाग में नक्शा यह है कि मुसलमानों की एक भाषा है उर्दू। जो मुसलमान उर्दू नहीं बोलते, वे भी आगे चलकर उर्दू बोलने लगेंगे। मुस्लिम संस्कृति में उर्दू का सम्बन्ध जोड़ने का एक ही मतीबा होगा। भारत के सभी मुसलमानों की भाषा उर्दू हो। इसीलिए धीरे धीरे इलाका बढ़ाते जाओ, एक दिन सब मुसलमान उसमें सिमट आएँगे। उधर हिन्दुओं की राष्ट्रभाषा होगी हिन्दी। हिन्दू संस्कृति से हिन्दी का सम्बन्ध है, इसलिए हिन्दू मात्र की एक भाषा होगी हिन्दी। हिन्दू राष्ट्र में बंगला, मराठी तमिल आदि भाषाएँ कायम रहें तो वे राष्ट्र को सङ्घटित करेंगी—यही सम्प्रदायवादियों का दृष्टिकोण रहा है।

श्री सज्जाद जहीर की भाव्यताओं को श्री शिवदानसिंह चौहान ने और भी पुष्पित और पल्लवित किया।

‘राष्ट्रभाषा विवाद और समाधान’ नाम के निबन्ध में शिवदानसिंहजी ने पहले तो सम्प्रदायवादियों को फटकार बताई, कहा कि १४० साल से यह हिन्दी-उर्दू की बहस राजनीतिक उत्तेजना और ‘धार्मिक-साम्प्रदायिक उन्माद के वाता-’

बना रखा है', उन्होंने सावधान किया कि वे दिन गये जब "आर्य-भाषा' हिन्दी के समर्थक उसे हिन्दुओं की परम्परागत भाषा कहकर' उसका चलन बचहरियो और दफ्तरो मे कराना चाहते थे, उन्होंने किंचित् खेद प्रकट किया कि "हिन्दी का नेतृत्व विशेषकर हिन्दू राष्ट्रवादियों के हाथ मे है," उधर "उर्दू का नेतृत्व विशेषकर मुस्लिम राष्ट्रवादियों के हाथ मे है।" इसके बाद उन्होंने प्रगतिवादियों की सखर ली जिन्होंने मिली-जुली भाषा हिन्दुस्तानी का समर्थन किया, "इससे उन्हें राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर गहराई से सोचने से जैसे छुट्टी मिल गई और सरल समाधानों को ही स्वीकार कर उन्होंने अपनी इतिकर्तव्यता मान ली।"

भाषा-समस्या पर गहराई से विचार करके, सरल समाधानों को रास्ते से हटाकर सखिल्ट समाधानों को और साहम से कदम उठाते हुए श्री चौहान ने अपनी ये मान्यताएँ प्रस्तुत की—

—"सर्वप्रथम यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि हिन्दी और उर्दू दो भिन्न भाषाएँ हैं।"

—"हिन्दी और उर्दूवालों को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये दोनों भलग भलग स्वतन्त्र भाषाएँ हैं।"

—"ये दोनों पृथक् भाषाएँ खड़ी बोली की जमीन पर संस्कृत और फारसी के खाद बीज से उत्पन्न दो पौधों के समान हैं, भत दो भिन्न संस्कृतियों हिन्दू और मुस्लिम की प्रतीक हैं।"

ये मान्यताएँ नई नहीं हैं। हिन्दू और मुस्लिम सम्प्रदायवादी यही बातें कहते रहे हैं। लेकिन यह श्री शिवदानमिह चौहान का ही वृत्ता था कि वह हिन्दू राष्ट्रवादियों की निन्दा करते हुए उन्हीं की स्थापनाओं को अपने जनवाद के नाम पर दोहराते चले।

उनका जनवाद धन्य है क्योंकि "हम जनवाद के उन सिद्धान्तों के आधार पर इस प्रश्न का समाधान करना चाहते हैं जिनका आधार भलख हिन्दुस्तान भयवा विभाजित हिन्दुस्तान की केन्द्रीय-सरकारों को भी लेना पड़ेगा।"

श्री चौहान ने जनवाद पर इतनी गहराई से विचार किया था कि उन्होंने भलख और ललित दोनों तरह के देश के लिए अपना भलूक समाधान प्रस्तुत किया था—

"इस समय देश मे 'पाकिस्तान' और 'भलख हिन्दुस्तान' का विवाद छिडा हुआ है। हमने अपने विवेचन मे भलख भयवा विभाजित भारत को सख्य मे रखकर कोई समाधान निकासने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि हमारी दृष्टि मे भलख हिन्दुस्तान हो भयवा पाकिस्तान और हिन्दुस्तान भलग-भलग हो, दोनों दशाओं मे राष्ट्रभाषा का वही समाधान होगा जिस पर हम अभी विचार करेंगे।"

भलली चीज है जनवादी दृष्टि प्राप्त करना। गुरु-गुरु के लिये वह दृष्टि

प्रगतिनील साहित्यकार और भाषा-समस्या ने

प्राप्त हो जाती है, उससे लिए जैसे पाकिस्तान, वैसे अखंड भारत। गुरु श्री गजराज जहोर की कृपा से यह दृष्टि मुरीद श्री चौहान को प्राप्त हो गई।

“इस जनवादी उदार दृष्टि को प्राप्त करने पर राष्ट्रभाषा के प्रश्न का समाधान स्वतः स्पष्ट हो जाता है।”

अब देखिए इस उदार दृष्टि के प्राप्त होने से भूत, भविष्यत् और वर्तमान तीनो कालो मे सत्य कैसा स्पष्ट दिखाई देने लगता है।

पहले अतीत के दृश्य देखिए। भारत मे मुसलमान आए। जब साजे थे, जब तो हिन्दू-मुस्लिम सस्कृतियों का मेल हा गया, जब यहाँ रहते रहते यही वे हो गये, तब उनकी सस्कृतियों मे भेद हा गया। और यह भेद करनेवाले थे ब्रज और अवधी के दो कवि—सूरदास और तुलसीदास।

मुनिए हिन्दी साहित्य के विकास का यह अभिनव जनवादी विश्लेषण।

“इसमे सन्देह नहीं कि भारत मे मुसलमानों के आगमन के पश्चात् हिन्दू-मुस्लिम सस्कृतियों मे एक लम्बी अवधि तक सुन्न घासान प्रदान और मिश्रण होता रहा।”

ईरानियों की सस्कृति, अरबो, पठानो, उजबको की सस्कृति—सब एक-सी, सब इस्लामी सस्कृति।

निर्गुणपथिया और प्रेम मार्गियों ने हिन्दू और मुस्लिम सस्कृतियों को मिलाया। ‘इस समुक्त विचार-परम्परा की कविताएँ यद्यपि सत्रहवीं शताब्दी तक होती रही परन्तु स्वामी रामानुजाचार्य के अनुयायी रामानन्द और श्री चल्लभाचार्य ने राम और कृष्ण की भगुणोपासना की जो परिपाटी चलाई उसने तुलसी और सूर जैसे महाकवियों को जन्म दिया जिन्होंने अवधी और ब्रज की काव्यधारा को बड़ी और जायसी की हिन्दू-मुस्लिम सस्कृतियों की सम्मिलित परम्परा से एकदम अलग कर दिया। अवधी और ब्रज की काव्य परम्परा हिन्दू सस्कृति की प्राचीन काव्य-परम्पराओं की उत्तराधिकारिणी बन गई। यह हिन्दू जातीयता की नवचेतना का परिणाम था।”

मुसलमानों के आने पर पहले तो सम्मिलित सस्कृति की धारा चली, फिर उसे सूरदास और तुलसीदास ने तोड़ दिया। यह भी अच्छा हुआ क्योंकि सत्रहवीं सदी से हिन्दू जातीयता का अस्तित्वान्धारम्भ हो गया था। इन महाकवियों ने उसे पहचाना और उसे अपने साहित्य मे अभिव्यक्त किया।

रीति और भक्ति की काव्यधाराओं मे भले ही बहुत से मुसलमानों ने योग दिया हो, श्री चौहान के अनुसार “ये काव्यधाराएँ हिन्दू जातीयता के नवोन्मेष की प्रतीक हैं।” इनके भाव-विचार ही नहीं, “सौन्दर्य मूल्य, छन्द रचना, ध्वनि-योजना, अलंकार-विधान” भी “संस्कृत साहित्य और हिन्दू-ग्राम्य सस्कृति से प्रभावित और निरूपित हैं।” चौहान ने यह नहीं बताया कि जिन कवियों ने हिन्दू-मुस्लिम सस्कृतियों का मेल किया था, उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम छन्दों का मेल कैसे किया था।

धार्मिक हिन्दी के युग में आये। हिन्दू सस्कृति की यह परम्परा आगे भी बरकरार रही। लिखा है— सूरदास और तुलसीदास के समय में भारतभर का तब ब्रज और मथुरा की वास्तविक परम्परा में यह विचारधारा ही सर्वप्रथम बनी रही।”

आधुनिक खड़ी बोली ने अपने से पहले की सांस्कृतिक परम्पराओं से सम्बन्ध बना जोड़ा—“खड़ी बोली हिन्दी ने सम्पूर्ण, प्राकृत और अपभ्रंशों में अपना सीधा सम्बन्ध जोड़कर शीतल, भाग्य, आदि अपभ्रंशों की अन्य भाषाओं के प्राचीन साहित्य को अपना प्राचीन साहित्य घोषित करके अपने को आर्य-हिन्दू परम्परा का उत्तराधिकारी सिद्ध किया। इस प्रकार हिन्दू जातीयता और तदनन्तर हिन्दू राष्ट्रियता ने अपनी जायति, मजबूत और विकास के लिए खड़ी बोली हिन्दी के द्वारा अपना मार्ग प्रशस्त किया अथवा वही कि इस पुनरुत्थान और राष्ट्रिय चेतना में हिन्दुओं के लिए खड़ी बोली हिन्दी माध्यम और वाहक बनी। हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने इस तथ्य को मुख्य बतला रखा है।”

शिवदानसिंहजी ने उदात्ततायुक्त हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों का जल्लेख कर दिया है। वरना पहले हिन्दू जातीयता, तदनन्तर हिन्दू राष्ट्रियता के विकास का मुख्य भेद किसने किया है? साधारण पाठक इस भेद को समझ भी नहीं सकते। हिन्दू जातीयता हिन्दी-भाषी क्षेत्र तक सीमित थी, इसके प्रचारक-प्रसारक सूरदास और तुलसीदास थे। खड़ी बोली सारे भारत में फैल गई, यह हिन्दुओं की नयी भारतव्यापी राष्ट्रियता का चोटक हुई। इसलिए लिखा कि पहले हिन्दू जातीयता, तदनन्तर हिन्दू राष्ट्रियता का विकास हुआ। यदि यह व्याख्या गलत हो तो भाई शिवदानसिंह उस दुरुस्त करके अपनी व्याख्या प्रस्तुत करें।

लेकिन ‘अपभ्रंशों की अन्य भाषाओं’ से उनका क्या तात्पर्य है, यह मैं बहुत बौद्धिक करने पर भी नहीं समझ पाया। खैर, अर्थ जो कुछ भी हो, “अपभ्रंशों की अन्य भाषाओं के प्राचीन साहित्य को अपना प्राचीन साहित्य”—यह दुकड़ा अपनी ‘ध्वनि-योजना’ में निश्चय ही हिन्दू राष्ट्रवादी है।

हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों ने उदात्ततर भारतीय साहित्य, भारतीय सस्कृति की बात की है। जोहान ने भारतीय शब्द की व्याख्या करके उसका शक्तिशाली अर्थ स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने लिखा है—“आधुनिक हिन्दी के साहित्य के यदि सभी अंग उपांगों का निरीक्षण करें (जितना धैर्य चाहिए इस कार्य के लिए। सराहिये उस मर्मभेदी दृष्टि को जो अंगों ही नहीं, उपांगों तक का निरीक्षण कर लेती है।) तो उससे निर्विवाद मिल्न हो जायगा कि हिन्दी साहित्य में भारतीय साहित्य, सस्कृति, विचारधारा तथा राष्ट्रियता आदि जिन शब्दों के आगे ‘भारतीय’ विशेषण निर्वाण प्रयोग होता है वह वास्तव में सुसंगत—मानों के योग से विवक्षित एक समुक्त अवित भारतीय सस्कृति अथवा विचार-

धारा का द्योतन नहीं करता। इन प्रयोगों में 'भारतीय' केवल हिन्दू-धर्म सस्कृति और हिन्दू राष्ट्रियता का अर्थवाची है।"

भाषाविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों ही की दृष्टि से श्री चौहान की यह खोज अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि हिन्दी लेखक भारतीय शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में करते हैं जिसमें भारतीय जनसंघ के नेता करते हैं।

जिन निर्गुणपथी सन्तों के बारे में चौहानजी की राय है कि उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम सस्कृतियों का मेल किया था, उनके लिए हजारीप्रसाद द्विवेदीजी ने लिखा है कि उनके काव्य की बाहरी रूपरेखा 'सम्पूर्णतः भारतीय' है ('हिन्दी साहित्य की भूमिका,' पृ० ३१)। शायद उनका मतलब है कि बाहर से पूरे हिन्दू हैं, भीतर से आधे मुसलमान। लेकिन उसी वाक्य में बौद्धों को भी लाकर 'भारतीय' के विषुद्ध अर्थ को खड़ित कर दिया है—“बौद्ध धर्म के अन्तिम सिद्धों और नाथपथी योगियों के पदादि से उसका सीधा सम्बन्ध है।"

'काव्य में प्राकृतिक दृश्य' नाम के अपने निबन्ध में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा था "आजकल के पार्कों में हम भारतीय आदर्श की छाया देखते हैं।" अर्थात् ये पार्क हिन्दू हैं, मुस्लिम नहीं।

श्री हरिशंकर शर्मा ने उर्दू-साहित्य के इतिहास में जोश मलीहाबादी की राष्ट्रीय कविताओं का उल्लेख किया है; श्री गोपीनाथ अग्रवाल ने 'उर्दू और उसका साहित्य' में चकबस्त की राष्ट्रीय कविताओं की चर्चा की है। चकबस्त तो हिन्दू थे ही, जोश भी कुछ समय के लिए हिन्दू राष्ट्रियता के गीत गान लगे, बरना धर्मसमाजी विद्वान् श्री हरिशंकर शर्मा उनकी राष्ट्रियता की प्रशंसा कैसे करते।

फिराक साहब ने उर्दू की प्रगतिशील कविताओं के संग्रह 'जजीरें टूटती हैं' की भूमिका में इनके रचयिताओं के लिए दावा किया है कि 'आदिकाल से अब तक की भारतीय सस्कृति उनकी जागीर है।' चूंकि यह जागीर हिन्दुओं की है, इसलिए फिराक गोरखपुरी का तो उसमें थोड़ा-बहुत हिस्सा हो भी सकता है, लेकिन मखदूम मुहीउद्दीन, राही मासूम रजा, बामिक जौनपुरी, अली सरदार आफरी घग्गैरह भी हिस्सेदार हो जायें, यह बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

बंगालियों ने शब्दों का अर्थ अलग भ्रष्ट कर दिया है। प्राचीन सस्कृति के सबसे बड़े जागीरदार श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कबीर, नानक, दादू आदि को पहले तो भारतीय साधक कहा, फिर उनका सम्बन्ध राममोहन राय से जोड़ा, राममोहन राय का सम्बन्ध आधुनिक साहित्य से जोड़कर हिन्दू-मुस्लिम विवास के तमाम इतिहास का ही सत्यानाश कर दिया। (देखिए दादू ग्रन्थावली की भूमिका)

भारत के आधुनिक विकास की विशेषता क्या है? श्री चौहान कहते हैं, "वस्तुतः हमारे देश के ऐतिहासिक विकास-क्रम की ही यह विशिष्टता है कि

राष्ट्रीय चेतना ने हिन्दू राष्ट्रीयता और मुस्लिम राष्ट्रवादिता का रूप ग्रहण किया ।”

जिसे राष्ट्रवादी लोग साम्प्रदायिकता कहते थे, वही सच्ची राष्ट्रीयता है; जिसे वे राष्ट्रीयता कहते थे, वह “बीब-सात सौ वर्ष के ऐतिहासिक जीवन की स्मृतियों तक की उन्मूलन करने की असम्भव चेष्टा” है ।

हिन्दुओं और मुसलमानों की एक राष्ट्रीयता ? असम्भव । यह सम्प्रदायवाद है, जनतंत्र की हत्या है । उदार जनवादी दृष्टि ने विचार कीजिए तो पता चल जाएगा कि इस ‘द्वैत को स्थायित्व प्रदान’ करने में अंग्रेजी शासन का भी हाथ भले रहा हो, “राष्ट्रीय जागरण ने इस भेद चैतन्य को और भी निखारा है ।” चैतन्य महाप्रभु के बाद गौरांग महाप्रभु की कृपा से ये नये भेद चैतन्यजी प्रकट हुए ।

इन भेद चैतन्यजी के प्रकट होने का फल यह हुआ कि एक ओर हिन्दू संस्कृति को प्रतिबिम्बित करनेवाला हिन्दी साहित्य विकसित हुआ, उसी तरह मुस्लिम संस्कृति को प्रतिबिम्बित करनेवाला उर्दू-साहित्य भी संवर्धित हुआ ।

‘हिन्दी (संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक बोली) के समानान्तर (अरबी-फारसी-निष्ठ) साहित्यिक खड़ी बोली का विकास मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव में हुआ ।”

संस्कृत के शब्द आर्य हिन्दू हैं, फारसी के शब्द मुसलमान हैं, इसलिये जहाँ संस्कृत के शब्द ज्यादा हो वहाँ हिन्दू संस्कृति जीती, जहाँ अरबी-फारसी के शब्द ज्यादा हो वहाँ इस्लाम जीता ।

“राष्ट्रीय जाग्रति के साथ-साथ हिन्दी और उर्दू का भेद और भी बढ गया ।” पहले प्रगतिशील लेखक यह भेद देखकर परेशान होते थे, उसे दूर करने की कोशिश करते थे । बीहान ने बताया कि परेशानी की कोई बात नहीं है, “दोनों भाषाओं ने अपनी प्रकृति के अनुकूल पर्याप्त विकास किया” और “राष्ट्रीय जाग्रति के बिना इन दोनों भाषाओं का ऐसा अपूर्व विकास असम्भव होता ।”

इस राष्ट्रीय जाग्रति से शायद गांधीजी का भी कुछ सम्बन्ध था । उन्होंने जीवन-भर प्रयत्न किया कि यह भेद मिटे और हिन्दी-उर्दू एक-दूसरे के नजदीक आएँ । वे हिन्दू-मुसलमानों तथा हिन्दी-उर्दू के भेदभाव से दुःख थे । इसका कारण यह था कि उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आधुनिक इतिहास को समझा न था, उसका निर्माण भले ही किया हो । श्री बीहान के शब्दों में “हिन्दी और उर्दू के स्वतन्त्र विकास से केवल ऐसे ही लोग विदुग्ध हैं जो अपने अतिहासिक दृष्टिकोण और इस बढभूल धारणा के कारण कि हिन्दू मुस्लिम एकता ग्रथवा समस्त भारत की अखण्डता के लिए एक ही राष्ट्रभाषा का होना अनिवार्य है, भारत की विनिष्ट वस्तुस्थिति को समझ नहीं पाते ।”

यह हुई विशुद्ध समाजशास्त्र की बात । भाष पूछ सकते हैं, किसी भाषा के शब्द-भण्डार या व्याकरण-व्यवस्था से धर्म का क्या सम्बन्ध है । भाष न जानते।

होगे कि ससार के तमाम ईसाइयों की भाषाओं का व्याकरण एक सा है, तमाम मुसलमानों की भाषाओं का व्याकरण एक सा है। जब इस्लाम भारत में आया तब उसने न केवल यहाँ की भाषाओं के शब्द-भण्डार में भारी उथल-पुथल की, उसने इन भाषाओं के व्याकरण में भी राष्ट्रीय और जनवादी क्रांति कर दी।

चौहान ने लिखा—“हिन्दी और उर्दू की भिन्नता केवल शब्दों के संस्कृत या फारसी प्रयोग तक ही सीमित नहीं है। उनके व्याकरण, पिगल वाक्य-विन्यास आदि में भी मौलिक भेद उत्पन्न हो गया है।” क्लिष्ट शब्द तो दोनों में होते ही हैं, “परन्तु इसमें भी अधिक खड़ी बोली के व्याकरण का शुद्ध पालन न हिन्दी में किया जाता है, न उर्दू में। हिन्दी व्याकरण पर संस्कृत व्याकरण का प्रभाव स्पष्ट लक्षित है और उर्दू व्याकरण पर फारसी और अरबी व्याकरण की गहरी छाप पड़ गई है।”

सम्भवतः अरबी और फारसी—दो भिन्न कुलों की भाषाओं—का व्याकरण एक-सा है क्योंकि दोनों का प्रभाव मुसलमानों की खड़ी बोली पर पड़ा है। आश्चर्य की बात है कि मराठी, हिन्दी और बँगला—तीनों के व्याकरण पर संस्कृत का प्रभाव पड़ा लेकिन मराठी में तीन लिंग हैं, हिन्दी में दो, बँगला में एक भी नहीं। गम्भीरता से विचार कीजिए तो आपको ज्ञात हो जायगा कि मराठी पर संस्कृत का प्रभाव सबसे ज्यादा है, इसलिए उसके बोलनेवाले सब हिन्दू हैं या हिन्दू राष्ट्रवादी हैं, हिन्दी में दो ही लिंग हैं, इसलिए यहाँ हिन्दुत्व कमजोर रहा, मुसलमान हिन्दू राष्ट्रवादी न हुए, उरुटा अपना राष्ट्रवाद विकसित करते रहे। बँगला में एक भी लिंग नहीं, संस्कृत का प्रभाव सबसे कम, इसलिए बंगाल के दो टुकड़े हो गए।

यहाँ तक तो हुई भूत और वर्तमान की बात।

अब लीजिए भविष्य की बात। चौहानजी ने गुरुजी को समझाया कि आप यह भ्रम त्याग दीजिए कि भविष्य में कभी हिन्दी-उर्दू मिलकर एक हो जाएंगी। “यह कहना कि राष्ट्रीय भावना ज्यो-ज्यो व्यापक होती जाएगी त्यो त्यो हिन्दी-उर्दू का भेद कम होता जाएगा, केवल भ्रात धारणा है। यद्यपि सत्य तो यह है कि ज्यो-ज्यो राष्ट्रीय भावना व्यापक होती गई है, दोनों भाषाओं के पृथक् विकास की गति भी उतनी ही तीव्र होती गई है।”

अन्त में समाधान यह रहा कि “मुस्लिम-प्रधान प्रान्तों में राजकीय कार्यों में उर्दू भाषा का प्रयोग होगा,” इसी प्रकार “मध्यदेश (हिन्दू-प्रधान प्रान्तों) में राजकीय कार्यों में हिन्दी भाषा का प्रयोग होगा।” दोनों इलाकों के अल्प-संख्यक अपनी-अपनी भाषा का व्यवहार भी कर सकेंगे। चौहानजी यह मानकर चले थे कि पूर्वी बंगाल के मुसलमान उर्दू का व्यवहार करने को बहुत उत्सुक हैं। हिन्दू भारत में एक द्विविध प्रदेश है। उनके बारे में वह अधिक सतर्क थे। उन्होंने अवरन राष्ट्रभाषा लागू करने का विरोध करते हुए सुझाया—“सम्भव है कि वे अपनी ही किसी भाषा को अपने प्रान्तों की राष्ट्रभाषा बनाना चाहें।”

इस तरह भाषा समस्या का जनवादी समाधान यह हुआ कि द्रविड प्रान्तों की अपनी राष्ट्रभाषा, मुस्लिम प्रान्तों की राष्ट्रभाषा उर्दू, द्रविड़ों से भिन्न धार्य-हिन्दू भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी । तीन राष्ट्र और राष्ट्रभाषाएँ ।

यह तो राष्ट्रभाषा की समस्या का समाधान हुआ । हिन्दी प्रान्तों की एक विशेष समस्या की ओर भी उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया । हिन्दी प्रान्तों में "सगमग बीस भाषाएँ और बड़ी बोलियाँ बोलती जाती हैं ।" उनके आधार पर "हिन्दी प्रान्तों का भी पुनर्विभाजन करना होगा ।" इस तरह हिन्दीभाषी प्रदेश को मिलान के बदले चौहानजी ने बीस नये प्रान्त बनाने की नकाह दी ।

'जनपदीय भाषाओं का प्रश्न' नामक सम्बन्ध निबन्ध में उन्होंने गहनभी की मातृभाषा-सम्बन्धी माग्यनाओं का और भी संवारकर पक्ष किया । ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अंग्रेजों को अनिवार्य राजभाषा बनाकर यहाँ की भाषाओं का दमन किस तरह किया इसका विवेचन न करके, साम्राज्यवाद की भूमिका को मूलावर श्री विधदानसिंह ने खड़ी बोली हिन्दी के साम्राज्यवाद पर आश्रय दिया । यह साम्राज्यवाद हिन्दी क्षेत्र की बोलियों का दमन कर रहा था ।

उन्होंने लिखा, "अकेली खड़ी (हिन्दी-उर्दू) ने सगमग पन्द्रह करोड़ ब्यासी लाख व्यक्तियों को अपनी मातृभाषाओं में शिक्षा पाने से वंचित कर रखा है । इससे सिद्ध है कि भारत भी 'भाषाओं का विनाश कारागार' है ।"

भारत कारागार ब्रिटिश साम्राज्य के कारण नहीं है, यहाँ की भाषाएँ अंग्रेजों के कारण कारागार में बंदी नहीं हैं, उन्हें कारागार में डाला है खड़ी बोली ने ।

भारत को उपनिवेश ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने नहीं बनाया, यही उपनिवेश कायम किये हैं हिन्दी साम्राज्य ने ।

चौहान अपने अद्भुत भाषाशास्त्र की दृष्टि " 'हिन्दी-साम्राज्य' के विभिन्न 'भाषा-उपनिवेशों' की क्रान्तिपर परिस्थिति पर" डालते हैं । वह इस नतीजे पर पहुँचते हैं, "हिन्दी का वर्तमान साम्राज्य 'हाथ के घर' से अधिक मजबूत नहीं है ।" बोलियों के उपनिवेश टूट जाएँगे, "किर खड़ी बोली को अपने साम्राज्य का पश्चिमी हिन्दी के क्षेत्र में भी विघटन करके अपने जनपद में ही सन्तोष करना पड़ेगा ।"

चौहान का विचार था कि अंग्रेजों और अंग्रेजी का साम्राज्य चाहे बाद में खरम हो, हिन्दी का साम्राज्य पराधीन भारत में ही खरम हो जाना चाहिए । "यदि वर्तमान आधार को हटाकर न्याय, समानता और स्वतन्त्रता का नया आधार न प्रदान किया गया तो भारत के स्वयन्त्र होने पर हिन्दी के साम्राज्य को टूटते देर न लगेगी ।"

भारत स्वतन्त्र हो गया; हिन्दी का 'साम्राज्य' न टूटा । बोलियों के उपनिवेश न टूटे । हिन्दी प्रान्तों में नये बीस प्रान्त न बने । इसी तरह अठारह लाख तक हिन्दी-साम्राज्य के टूटने की राह देखने के बाद चौहानजी ने स्वयं

उठाये और घालोचना न० ३४ (जुलाई, '६५; सितम्बर में प्रकाशित) में भारत की एकता के नाम पर इस साम्राज्य पर हल्का बोल दिया।

चौहान के पहले के लेखों में जैसे अंग्रेजी का प्रभुत्व खत्म करने पर जोर नहीं है, वैसे ही इस लेख में अंग्रेजी को अनिवार्य राजभाषा के पद से हटाने का आग्रह नहीं है। श्री सज्जाद जहीर ने आत्मनिर्णय के सिद्धान्त को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध, सारे देश की स्वाधीनता के लिए न लागू करके, उमें राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध, जनतन्त्र के नाम पर, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हित में लागू किया था। इस समय उन्हें उर्दू के संरक्षण की जितनी चिन्ता है, उतनी अंग्रेजी हटाने की नहीं। उन्हीं की तरह श्री चौहान ने उर्दू की रक्षा का नारा लगाया है लेकिन वह दूसरों की स्थापनाओं को दोहराते-भर नहीं हैं। वह योग्य शिष्य हैं, इस नाते उन्होंने आत्मनिर्णय का अधिकार हिन्दी के उपनिवेशों पर लागू किया है।

अवध, बुन्देलखण्ड, वज, भोजपुरी क्षेत्रों के जो लेखक हिन्दी को अपनी मातृभाषा कहते हैं, उनकी निन्दा करते हुए श्री चौहान ने प्रश्न किया है कि जब अंग्रेजी में साहित्य रचनेवाले मुल्कराज आनन्द, भवानी भट्टाचार्य, और के० नारायणन अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा नहीं कहते, सब प्रेमचन्द, प्रसाद, निराला, बृन्दावनलाल वर्मा, रामचन्द्र शुक्ल ही हिन्दी को अपनी मातृभाषा क्यों बहे? हिन्दी साहित्य का सारा इतिहास चौहानजी को विकृत दिखाई देता है; इसके रचनेवालों की मातृभाषा हिन्दी थी ही नहीं, जैसे मुल्कराज आनन्द और भवानी भट्टाचार्य की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। यशपालजी की मातृभाषा हिन्दी नहीं है। “इस दृष्टि से उनकी और डा० मुल्कराज आनन्द की स्थिति में विशेष फर्क नहीं है। यह बात भारतेन्दु से लेकर मोहन राकेश तक की नई पीढ़ी के निम्नानवे फी सदी हिन्दी लेखकों और हिन्दी-आन्दोलन के सुभट योद्धाओं के बारे में भी सच है।”

मुल्कराज और यशपाल की स्थिति में विशेष फर्क न हो, थोड़ा बहुत फर्क तो है ही। चौहान हिन्दी के निम्नानवे फी सदी लेखकों को मातृभाषाती कहते हैं क्योंकि उनकी समझ में इन लेखकों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में उपन्यास-कहानियाँ लिखनेवाले मुल्कराज आनन्द को मातृभाषाती कहने का साहस उनमें नहीं है। कारण, इससे विश्वभाषा अंग्रेजी के प्रति सकीर्णता प्रकट होती है और ‘ऐम्बो-एशियन-सौलिडैरिटी’ को धक्का लगता है। भारत में इस सौलिडैरिटी के तीन स्तम्भ हैं—मुल्कराज आनन्द, सैयद सज्जाद जहीर और शिवदान-सिंह चौहान।

भारतेन्दु से लेकर मोहन राकेश तक हिन्दी के निम्नानवे फी सदी लेखक अपनी मातृभाषाएँ छोड़कर हिन्दी की सेवा क्यों करते रहे हैं? अर्थ और यश-लाभ के लिए! देशभक्त बनने का सुख अलग से! इन मातृभाषातियों से मातृभाषाओं की रक्षा करने के लिए खड्ग लेकर उठ खड़े हुए हैं, श्री शिवदानसिंह

चौहान।

जनतांत्रिकता की होड़ में सभी भारतीय लेखकों को पछाड़ते हुए उन्होंने लिखा है, “भाज की ‘हिन्दी’ हम सबने अपनी मातृभाषाओं को त्यागकर स्कूलों में किताबों में ही सीखी-पढ़ी है, जिस तरह अंग्रेजी स्कूलों में किताबों से सीखी-पढ़ी है। इसे आप क्या कहेंगे, मातृघात या कुछ और, मैं यह तो नहीं जानता, क्योंकि जब हम लोगों ने शिखरालयों में प्रवेश किया, उस समय हिन्दी या उर्दू के अलावा अपनी मातृभाषाओं में पढ़ने का कोई विकल्प ही नहीं था। भाज भी नहीं है। लेकिन यह सच है कि एक समय जो विद्यार्थी था, वह बालिश होने पर अर्थ और यशस्वी और देशभक्ति के रूप में प्रसिद्धि पाने का नुस्खा साबित हुई, इसलिए अपनी मातृभाषाओं के प्रति अपना कर्तव्य भुला देना ही हम सबके भाग्य सबसे सुविधाजनक मार्ग था।”

सुबह का भूला शाम को घर नीट पाए तो उसे भूला हुआ नहीं करते। चौहान अब समझ गए हैं कि अर्थ और यश के लिए हिन्दी-सेवा करना अनुचित है। उन्होंने स्वयं बाकी यश अर्जित कर लिया है, अर्थ भी ‘मालोचना’ से ऐसा क्या मिलता होगा? उन्हें चाहिए कि वह हिन्दी के मातृघाती लेखकों के सामने अपने स्थान से एक मिसाल कायम करें। अब उन्हें हिन्दी लिखना बन्द कर देना चाहिए और हिन्दी के बाकी दिन मातृभाषा की सेवा में लगाने चाहिए। सम्भवतः उनकी मातृभाषा ब्रज है, उसकी सेवा करें। अभी तो उनका कोई लेख, कोई पुस्तक ब्रजभाषा में नहीं देखने को नहीं मिली। ब्रजभाषा में अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय देकर वह ब्रज और हिन्दी दोनों का उपकार करेंगे। मातृभाषा ब्रज न हो तो जो भी मातृभाषा हो, उसकी सेवा करें। उनके पिताजी ने एक बार आगरे में दर्शन दिए थे। पुलिस के आदमी थे। उन्होंने अपने पुत्रों की खर्चा करते हुए बहुत मुहावरेदार खड़ी बोली का व्यवहार किया था। उनके धाराप्रवाह वाक्य मुझे अभी तक याद हैं यद्यपि उन्हें लिखकर प्रकाशित करने का साहस मुझमें नहीं है। बहरहाल सवाल मातृभाषा का है, पितृभाषा का नहीं।

फायद ने ईहोपम काम्प्लेक्स ईजाद करके सभी विश्वीय और शिशुओं को सम्भाव्य पितृघाती सिद्ध कर दिया था। शिवदानसिंहजी ने पितृघात की बात पुरानी पड़ जाने से उसे त्यागकर अधिक वैज्ञानिक इस मातृघाती काम्प्लेक्स का आविष्कार किया है। अब देखिए, इससे बंभी जटिल ग्रन्थियाँ लोगों के मन में पढ़ जाती हैं।

कहते हैं, “अपनी मातृभाषाओं के प्रति अपनी उपेक्षा को हम मातृघात कहें या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इनका जानना है कि हिन्दी के अलावा और आन्दोलनकारी नेताओं के अन्तर्गत में कहीं कोई अपराध-भावना की ग्रन्थ जरूर पड़ गई है जिसका कारण वे अपने अपराध पर परदा डालने के लिए इतिहास को तोड़-मोड़कर यह सिद्ध करने की काशिश करते रहते हैं कि मविश्वी,

राजस्थानी अवधी वगैरे प्रादि वस्तुतः स्वतन्त्र भाषाएँ नहीं हैं 'हिन्दी' (संस्कृत-निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली) ही स्थानीय बोलियाँ हैं और जनगणना प्रादि के मोक्षों पर हिन्दी प्रचारक और जनसंघ के अन्ध-हिन्दूराष्ट्रवाद से प्रभावित सरकारी अमला इन भाषाओं का बोलतवाली जनता पर दबाव डालते हैं कि वे मातृभाषा के स्थान में राजस्थानी या मैथिली न लिखवाकर हिन्दी लिखवाएँ, यानी वे उत्तर भारत की समूची जनता का अपन अपराध में साक्षीदार बना लेना चाहते हैं।

इस अपराध भावा का सब लग्न मुक्त हैं जिन्होंने खड़ी बोली के उर्दू रूप का अपनाया है। खड़ी बोली यदि मातृभाषा है तो उर्दू-रूप में, हिन्दी रूप में नहीं। यह नहीं मान्यता है जाँची चौहान के पुराने निबन्धा की मान्यता से बहुत घाग बढ़ गई है। अब उन्होंने सीधे-सीधे उर्दू को मुस्लिम राष्ट्रवाद की भाषा कहना छाड़ दिया है, अब वे हिन्दी का ही सम्बन्ध हिन्दू राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं। उर्दू हिन्दुओं और मुसलमानों की मुस्तरा जवान है।

लिखा है, 'मैं के घटनों पर बैठकर हम में से किसी ने 'हिन्दी नहीं सीखी जिस तरह कि अधिक पुरानी शब्दों (१) उर्दू को दिल्ली लखनऊ, हैदराबाद अनेक सांस्कृतिक केन्द्रों के बीच हजारों हिन्दू और मुसलमान परिवारों में पुन-दर पुन से अपनी माताओं की गोद में ही सीखते आए हैं।

यही कारण है कि दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद के हिन्दू मुसलमान तो पुन-दर-पुन से अपनी माताओं की गोद में ही उर्दू सीखते आए हैं लेकिन इलाहाबाद, बनारस और पटना के हिन्दू मुसलमान अपनी माँ की गोद में हिन्दी नहीं सीख पाए ? कारण यह है कि चौहान की समझ में उर्दू मुख्यतः मुसलमानों की भाषा है, दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद में मुसलमान काफी बड़ी संख्या में हैं, बनारस पटना और इलाहाबाद में वे इतनी बड़ी संख्या में नहीं हैं इसलिए खड़ी बोली के प्रसार का एक नियम लागू होता है मुस्लिम प्रधान शहरों में दूसरा नियम लागू होता है हिन्दू प्रधान शहरों में—इस कारण खड़ी बोली का उर्दू-रूप तो मातृभाषा है उसका हिन्दी रूप नहीं है। शिवदानसिंह चौहान ने भाषाओं का विभाजन कर उसी पुराने साम्प्रदायिक आधार पर किया है। उनके जनतांत्रिक आडम्बर के नीचे वही साम्प्रदायिकता का चोर छिपा हुआ है।

यदि यह मान भी लें कि दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद के हिन्दुओं और मुसलमानों की मातृभाषा उर्दू है तो भी यह बात साफ नहीं होती कि चौहान उर्दू के उन तमाम लखवों को मातृभाषा क्यों नहीं कहते जो इन शहरों में दूर ब्रज अवध, पंजाब या भोजपुरी क्षेत्रों के रहनेवाले थे। उर्दू के दो सवने बड़े शायर गालिब और मीर आशरेफ़ में पैदा हुए थे। सैदा के साथ ईरानी थे। इकबाल पंजाबी थे। सादिक जुधियानवी, हफीज जालन्धरी, ओश मलसियानी, जगन्नाथ आजाद अहमद नदीम कासिमी फ़ख़्र, राजेन्द्रसिंह बेदी, कृष्ण चन्दर आदि पंजाबी हैं। ये सब मातृभाषा है या नहीं ? जोश मसौदाबादी, किराक

गोरखपुरी, मजरूह मुल्तानपुरी, फानी वदायूनी, शाद अजीमाबादी, अक्बर इलाहाबादी वगैरह मातृघाती क्यों नहीं हैं ?

दरअसल चौहान अंग्रेजी और उर्दूवालों के सामने खोखे निपोरते हैं, अर्थ और यशस्वी के लिए नहीं, विगुद जनतन्त्र की रक्षा के लिए, हिन्दीवालों पर गुराँते हैं क्योंकि जिस पत्तल में खाना, उमी में छेद करना उनकी न्यायप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण होया। इसलिए भारतेन्दु में लेकर मोहन राकेश तक के हिन्दी-लेखकों को दोसने में उन्हें जरा भी फिक्र नहीं होती, लेकिन उर्दू भाषा और साहित्य के लिए वह नियम-ब्यादे दूसरे बना लेते हैं।

उन्हें यह नहीं मालूम कि उर्दू के बहुत से लेखक आज भी अपने घरों में घबघी या भोजपुरी बोलते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि उर्दू के बहुत से कवियों की भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव नज़ीर की कविताओं में सबसे ज्यादा स्पष्ट है। उन्हें यह तो जरूर मालूम होना कि उर्दू के पंजाबी लेखक प्रायः में पंजाबी बोलते हैं। पंजाब, अवध और ब्रज के उर्दू लेखकों को निकास दीजिए। तीन-चौपाई उर्दू-साहित्य का सफाया हो जाएगा। चौहान को यह नहीं मालूम कि हैदराबाद में हिन्दुओं और मुसलमानों की जो बोलचाल की भाषा है, व पुरानी खड़ी बोली का वह रूप है जिसे उत्तर भारत के लोग यहाँ से अपने साथ ले गए थे और जिस पर मराठी-तेलुगु आदि भाषाओं का प्रभाव पड़ा है।

बोलचाल की दकनी में 'भूमना' नको, 'नामई च नहीं लेते', 'साठे नौ बज कूँ घाए' जैसे प्रयोग होते हैं। (देखिए, श्रीराम शर्मा का सबलन 'द्विखनी में गद्य और पद्य', पृ० ४३६)। हैदराबादी बन्धु 'क' या 'क' की जगह 'ख' काँ बोलते हैं, इससे बहुत स सतीके मसहूर हैं। चौहानजी इन सब बातों से बेखबर हैं। 'उल्टा घोर कौतवाल को डाटे' की मसल चरितार्थ करते हुए फर्माते "जब कोई व्यक्ति, वर्ग या समुदाय जीवन की वास्तविक परिस्थिति को ख़ास प्राँवों में देखने में असमर्थ हो जाता है और इस तरह की अमूर्त मिथिक पारंपरणाएँ गढ़कर उनसे चश्मे से जीवन-वास्तव को देखने लगता है, तब उस तर्क, विवेक और औदार्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती।"

वास्तविक परिस्थिति क्या है ? हैदराबाद में लोगों की बोलचाल की ज़बान दिल्ली की उर्दू है या उससे भिन्न दकनी ? उर्दू के पंजाबी लेखकों की घर की भाषा उर्दू है ? मलीहाबाद, अजीमाबाद, गोरखपुर, इलाहाबाद के लोगों की बोलचाल की भाषा साहित्यिक उर्दू है ? तथ्यों में कौन प्राँवें खुराता है ?

वास्तविक स्थिति यह है कि हर भाषा की अपनी बोलियाँ होती हैं। अंग्रेजी, फ़ारसी, रंगी की तरह बंगला, मराठी, हिन्दी, तमिल आदि भाषाओं की भी अपनी बोलियाँ हैं। इस बारे में बहस हो सकती है कि कोई बोली स्वतन्त्र भाषा है या बाली, लेकिन किसी भाषा की बोलियाँ ही न हो, ऐसा नहीं होता। पूँजीवाद के विकास के साथ जब विनिमय के बड़े-बड़े केन्द्र नगरों के रूप में स्थापित होते हैं, तब उनमें अनेक बोलियों के क्षेत्रों—अनेक जनपदों—में सिमटकर लोग

प्रगतिशील साहित्यकार और भाषा-समस्या के जनतांत्रिक **अपवाद** *

घाते हैं। दिल्ली और आगरा में बहुत से परिवार पूरब से आकर बस गए। इनके यहाँ लोग अब भी घर में अवधी बोलते हैं। इनमें मुस्लिम परिवार भी हैं।

हिन्दी-भाषी जाति के विकास और गठन में दिल्ली, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद और पटना मुख्य सांस्कृतिक केन्द्र बने। यहाँ खड़ी बोली का प्रसार हिन्दुआ और मुसलमानों दोनों ने किया। इनकी बोलचाल की भाषा में धार्मिक आधार पर कोई फर्क नहीं है। साथ ही इन शहरों के बहुत से हिन्दू और मुसलमान अपने घरों में खड़ी बोली से भिन्न अपनी पुरानी बोली का भी व्यवहार करते रहते हैं। इसलिए यह कहना कि उर्दू तो मातृभाषा है, हिन्दी नहीं है, गलत है। दिल्ली, आगरा, लखनऊ आदि शहरों में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने माँ की बोद में खड़ी बोली सीखी है और हजारों ऐसे हैं जिन्होंने मोहल्ले के दोस्तों से खड़ी बोली सीखी है। कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत कोपिला करने पर भी खड़ी बोली नहीं सीख पाए, न उसका हिन्दी रूप, न उर्दू रूप।

कानपुर, लखनऊ, पटना आदि शहरों में मजदूरी और नौकरी के लिए जो अवधी, भोजपुरी बुन्देलखण्डी आदि बोलियों का व्यवहार करने वाले लोग एकत्र होते हैं, अपने सामाजिक कार्यों के लिए वे खड़ी बोली अपनाते हैं। इसे हम जातीय निर्माण की प्रक्रिया समझें या बोलियों के दमन की प्रक्रिया। दिल्ली से पटना तक और पटना से भोपाल जर्जन तक कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें विभिन्न जनपदों के लोग एकत्र न हुए हों। इन लोगों ने अपने राजनीतिक-सांस्कृतिक कार्यों के लिए खड़ी बोली को अपनाया है। अब छोटे छोटे कस्बों तक में एक ही देहाती बोलनेवाले नहीं रह गए हैं। लेकिन जातीय निर्माण की यह सारी प्रक्रिया न समझकर, बोली और भाषा का भेद न समझकर, जातीय प्रदेश और सामन्ती युग के जनपदों का भेद न समझकर, स्तानिन की 'नशन' की परिभाषा आसि मूँदकर जनपदों पर लागू करके, भाषावार प्रान्त निर्माण की माँग को हास्यास्पद बनाते हुए श्री चौहान ने माँग की है कि हिन्दी क्षेत्र में 'दस पन्द्रह नये राज्यों का निर्माण' कर दिया जाय। 'सोलह-सत्रह तो इस समय भी हैं। और इससे देश का विघटन नहीं हुआ तो दस-पन्द्रह और भाषावार राज्य बना देने से 'आसमान नहीं फट पड़ेगा।'

अहिन्दी प्रदेशों में जो लोग हिन्दी के विराधी हैं, वे यह तर्क देते हैं कि हिन्दी कृत्रिम भाषा है। उसकी कृत्रिमता सिद्ध करने के लिए वे हिन्दी की बोलियों का हवाला देते हैं, उन्हें स्वतन्त्र भाषाएँ कहकर हिन्दी को साम्राज्यवादी उत्पीड़क भाषा मानते हैं। यदि कोई हिन्दी प्रेमी मराठी, बंगला या तमिल के लिए कहे कि वे हिन्दी की बोलियाँ हैं या यह कि भारत में एक राष्ट्रभाषा रहेगी, और सब भाषाएँ मिटा दी जाएँगी, तो यह जरूर साम्राज्यवादी उत्पीड़न की बात होगी। लेकिन लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली में जो लोग मेहनत मजदूरी करने आते हैं, वे खड़ी बोली का व्यवहार

न करें तो बेमौत भरें। दिल्ली और वानपुर के सूती मिल-मजदूर लड़ी बोली का व्यवहार न करें तो उनका ट्रेड यूनियन आन्दोलन ठप हो जाय। मजदूर वर्ग को अपने संगठन के लिए जातीय भाषा की जरूरत होती है जो अलग-अलग बोलियाँ बोलनेवाले मजदूरों को एकजुट करे। चौहान के मार्क्सवाद में मजदूर वर्ग को स्थान नहीं है। यदि हो तो एक भी मिल, एक भी कारखाने, एक भी उद्योग का नाम बतान की कृपा करें जहाँ सिर्फ मैथिली, सिर्फ भोजपुरी, सिर्फ अवधी या अन्य कोई जनपदीय बोली बोलनेवाले ही काम करते हों।

चौहान ने क्रूरित समाजशास्त्र की काफी निन्दा की है। लेकिन उनके बुद्धिहीन विषुद्ध समाजशास्त्र में कहीं पूँजीवादी विकास के अन्तर्गत नये विविध वर्गों में विभिन्न जनपदों में एकत्र होनेवाले मध्यम और श्रमिक वर्गों का उल्लेख नहीं है।

जातीय भाषा का प्रसार सामाजिक विकास का परिणाम है, इसलिए उसका विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होता। भारतीय बुद्धिजीवियों पर अंग्रेजी का प्रभाव है, वे 'मिथिक' परिवर्तनाओं की बात करते हैं अंग्रेजी शब्दों और मुहावरों का शलत अनुवाद करके अपनी हिन्दी को सजाते हैं (जैसे 'कौस्टली' के लिए 'कीमती' शब्द का व्यवहार—'कीमती किन्तु अनुपयोगी प्रयोग', 'यह प्रयोग शायद बहुत कीमती भी साबित हो।') तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे ईसाई हो गए हैं या उन पर ईसाइयत का प्रभाव है। बोलचाल की लड़ी बोली में हिन्दू और मुसलमान साधारणजन घर-बार-आरोग्य या ससृष्ट के कठिन शब्दों का व्यवहार नहीं करते। यह है बुनियादी बात। यहाँ धर्म के आधार पर कोई विभाजन नहीं है। लोग फारसी या ससृष्ट के शब्दों का ब्यादा प्रयोग करते हैं तो इसका प्रधान कारण भास्कृतिक है, धार्मिक नहीं।

उस विशाल क्षेत्र में, जिसके नगरीय हिन्दू और मुसलमान, विभिन्न जनपदों में पाये हुए मजदूर और नीचरीपेना लोग, लिप्य भाषा के रूप में लड़ी बोली का व्यवहार करते हैं सभी की जाति, काम या मेहनत एक है, यहाँ दस या पन्द्रह प्रांत बनाने की बात करना हिन्दीभाषी जनता की जातीय एकता को तोड़ने का प्रयास करना है। इस क्षेत्र की बोलचाल की भाषा में हिन्दी-उर्दू का भेद नहीं है, इसलिए उर्दू को क्षेत्रीय भाषा कहना गलत है। यदि बोलचाल की उर्दू और हिन्दी में एक ही बोल-आस्मान में काम करने वाले मजदूर भेद करते तो उर्दू को क्षेत्रीय भाषा मानना उचित होता। लेकिन आम जनता बोलचाल में ऐसा कोई भेद नहीं करती। यह भेद लिप्य भाषा के रूप और लिपि को लेकर है। अधिकांश जनता देवनागरी लिपि का व्यवहार करती है और लिप्य भाषा के लिए अधिकतर शब्द संस्कृत में लेती है। एक अल्पमध्यम समुदाय ऐसा है जो फारसी लिपि का व्यवहार करता है और अपनी लिप्य भाषा में अरबी फारसी से शब्द लेता है। इस समुदाय में मुसलमानों के साथ हिन्दू भी हैं, इसलिए उस भास्कृतिक अल्पमत बढ़ना चाहिए। इन भास्कृतिक

अल्पसंख्यकों की भावनाओं का आदर करते हुए उनकी लिपि और शिष्ट भाषा की रक्षा करनी चाहिए लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम दो कौमो के सिद्धान्त के आधार पर दो भाषाएँ स्वीकार कर लें। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ साहित्यिक उर्दू बोलचाल की भाषा हो या जहाँ उर्दू की बोलचाल का रूप वही की हिन्दी के बोलचाल के रूप से भिन्न हो। बोलचाल की खड़ी बोली के दो साहित्यिक रूप हैं—हिन्दी और उर्दू। उर्दू को हिन्दी की शैली कहने से बुरा लगता हो तो उस खड़ी बोली की शैली कहिए, हिन्दी को भी खड़ी बोली की एक शैली कहिए। लेकिन सांस्कृतिक बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों का भेद याद रखिए। यह जान लीजिए कि बहुत से उर्दू लेखक और लेखिकाएँ—जिनमें श्रीमती रजिया सज्जाद जी भी हैं—अपनी रचनाएँ उर्दू की इमरत में कोई फेर बदल किये बिना, देवनागरी में छपवाती हैं। यह रवाज बढ़ता जा रहा है कि प्रसिद्ध उर्दू लेखकों की रचनाएँ देवनागरी लिपि में पहले छपें, फारसी लिपि में बाद की। इससे हिन्दी उर्दू साहित्य को देवनागरी के माध्यम से पठने-वालों की एक मिली जुली जमात बनती है। यह जमात अपनी एकता, अपनी रूचि का असर लेखकों पर, उनकी हिन्दी उर्दू शैली पर डालकर एक ही शैली के विकास में सहायक होती है। जो लोग दो कौमो के सिद्धान्त पर विश्वास नहीं करते, वे इस एकता के मर्म मिलसिलसे से खुश होंगे।

राजपाल एण्ड मन्ज ने लोकप्रिय उर्दू शायरों की निरीज निकालकर लाखों हिन्दी-भाषियों तक इनकी रचनाएँ पहुँचाईं उन्हें दरअसल लोकप्रिय शायर बनाया। इससे उर्दू का नाश नहीं हो गया। देवनागरी लिपि में 'उर्दू साहित्य', 'डगर' जैसे पत्र निकलते हैं जिनमें उर्दू की रचनाएँ देवनागरी लिपि में छपती हैं। एजाजा महमद अब्बास और उनके साथियों ने 'सरगम' निकाला था जिसमें देवनागरी लिपि सरल उर्दू रचनाएँ छपती थी। हिन्दी 'डिलटूज' की भाषा, 'जनयुग' और 'आलोचना' में भिन्न, आसान उर्दू होती है जिसमें बहुत थोड़े पारिभाषिक शब्द संस्कृत के होते हैं। इस तरह हिन्दी-भाषियों ने उर्दू को अपनाया है, उसका दमन नहीं किया। देवनागरी के माध्यम से उन लोगों तक उर्दू साहित्य पहुँचा है जो पहले उससे बौंसो दूर थे। जो लोग अपने को मार्क्सवादी कहते हैं, बोलचाल की भाषा और उसके साहित्यिक रूप में बुनियादी भेद नहीं मानते, उन्हें सांस्कृतिक विकास के इस मिलसिलसे में खुश होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा मुहरंभी मूरतें वही लागू बनाय हुए हैं जो अपने को मार्क्सवादी लेखकों का रहनुमा समझते हैं। कोई भूल हड़ताल की धमकी देता है तो कोई नरसों देखकर वह इलाका तय करने में लगा है जहाँ हिन्दी से अलग लोगों की मातृभाषा उर्दू है। कुछ अन्य मित्र सांस्कृतिक बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक का भेद न समझकर दिल्ली या अन्य राज्यों में हिन्दी के बराबर उर्दू को राजभाषा बनाने का स्वागत् देख रहे हैं। और इन सबमें कोई भी यह माँग नहीं करता कि भारत की सभी भाषाओं का दमन करनेवाली विदेशी भाषा अंग्रेजी

का प्रभुत्व प्राप्त हो ।

जहाँ तब राजस्थानी और पञ्जाबी का सम्बन्ध है, उनके लिखने ढोलने-वाले तब करें कि वे हिन्दी अपनाएँगे या पञ्जाबी राजस्थानी का स्वतन्त्र विकास करेंगे । यदि उत्तर प्रदेश की सरकार या दिल्ली सरकार उन पर किसी तरह का दबाव डालेगी कि वे हिन्दी का ही व्यवहार करें, तो मैं इसका विरोध करूँगा । माय ही उपेन्द्रनाथ भट्ट और यशपाल हिन्दी लिखते हैं तो मैं इसे मातृभाषा न कहूँगा ।

हिन्दी भाषा जातीय विकास के परिणामस्वरूप विद्यालय हिन्दी क्षेत्र की भाषा बनी है । इस विकास को न समझने से भारतेन्दु से लेकर मोहन रावदा तक हिन्दी के सैकड़ों लेखक साम्राज्यवादी या पक्षधरवादी दिखाई देते हैं । इस विद्यालय क्षेत्र में बानियों के दमन की बात वे कहते हैं जो भारत में अंग्रेज़ी को राजभूषण या बलाय रखना चाहते हैं । अंग्रेज़ी की रक्षा उस 'जनतन्त्र' का यह दुर्कर्म पहचानकर नहीं की जा सकती ।

जैसे-जैसे अंग्रेज़ी का हटाने का समय नजदीक आया, वैसे-वैसे उर्दू के संरक्षण की माँग भी जोर पकड़ती गई । छेद की बात है कि कुछ गुमराह भाषासंवादी नेता हिन्दी पर उर्दू के दमन का अपराध लगाकर 'किलहाल' अंग्रेज़ी कायम रखने की नीति का प्रचार करते हैं । उर्दू के लेखक और उर्दू साहित्य के प्रेमी पाठक उनकी रक्षा हिन्दी लेखकों और हिन्दीभाषी जनता के सहयोग में ही कर सकते हैं । उन्हें इस हिन्दीभाषी जनता के साथ मिलकर अंग्रेज़ी को हटाने और सभी भारतीय भाषाओं को अंग्रेज़ी की दामनी से मुक्त कराने के लिए सघर्ष करना चाहिए । वस्तुस्थिति को पहचानते हुए वे सांस्कृतिक सम्पत्तियों के रूप में अधिकारों के बिना लड़ें, हिन्दी-भाषी जनता उनका साथ देगी । उनका अलगवाह या रत्नवा सम्प्रदायवाद की उपज है और उन्हीं के लिए हानिकारक है ।

बोहान न फातिशम और हिटलर की उच्चतर धार्मिक जाति-सम्बन्धी परिवर्तन' की निन्दा की है । यह कृपा करके अपने पुराने राष्ट्रभाषा बाने निबन्ध में देकर जाएँ, उन्होंने कितनी बार धार्मिक हिन्दूमा और हिन्दू राष्ट्रवाद की चर्चा की है और उमक आधार पर हिन्दी के विकास का विक्षेपण किया है । उन्होंने यह हिन्दू राष्ट्रवाद का नाम लेना बन्द कर दिया है लेकिन हिन्दू-मुस्लिम सस्वृत्तियों अभी बरकरार है । उन्होंने लिखा है कि "विभिन्न बोमा की जनता (विशेषकर उत्तर भारत की जनता) ने हिन्दू और मुस्लिम सस्वृत्तियों के योगदान से दिल्ली के आग पान बोनी जनेवाली लड़ी वाली की भूमि पर एक अपनी ही सम्पूर्ण भाषा उर्दू का विकास किया ।"

बोहान ने यह नहीं बताया कि बंगाल, कश्मीर, सिन्ध आदि में हिन्दू-मुस्लिम सस्वृत्तियों के योगदान से किसी नयी सम्पूर्ण भाषा का विकास क्यों नहीं हुआ । वह यह नहीं जानते कि ईरानी, अरब, पठान, उजबेक मुसलमानों की

संस्कृति एक नहीं है, न तमिलनाडु, बंगाल और गुजरात की संस्कृति एक है। और सारे हिन्दुओं की एक संस्कृति हो भी तो उनकी एक भाषा कैसे हो जायगी ? भारत में आनेवाले तुर्क, पठान और ईरानी मुसलमानों की भाषा कैसे एक हो जायगी ?

गुप्ती वही पुरानी है। वह समझते हैं कि संस्कृत के शब्द हिन्दू हैं और फारसी के शब्द मुसलमान ! दोनों के मिलने से उर्दू का विकास हुआ।

और हिन्दी का विकास कैसे हुआ ?

“हिन्दू समाज में उठे सुधार-आन्दोलनों और कई दूसरी ऐतिहासिक परिस्थितियों के प्रभाव से उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में खड़ी बोली की ही जमीन पर उर्दू के मुकाबले में एक संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक रूप हिन्दी का विकास हुआ।”

वही बात है जो श्री सज्जाद ज़हीर ने अपने निबन्ध में लिखी थी और जिसे चौहानजी ने अपने पुराने निबन्ध में पल्लवित किया था। हिन्दी का विकास हिन्दू-समाज में उठे सुधार आन्दोलनों के कारण हुआ। वह हिन्दुओं की भाषा है। उर्दू मुख्यतः मुसलमानों की भाषा है जिनके साथ कुछ शरीफ हिन्दू भी हैं।

चौहान को यह नहीं मालूम कि जितनी संस्कृतनिष्ठ हिन्दी (उन्हे छोड़कर) हिन्दी के भीतर मिलकर लिखते हैं, उसमें ज्यादा संस्कृतनिष्ठ बंगला पूर्वी पाकिस्तान के ढाका रेडियो से बोली जाती है वैसे ही संस्कृतनिष्ठ मलयालम केरल के ईसाई लिखते और बोलते हैं। भाषा में घर्ष का घट्टट सम्बन्ध होता तो हर प्रदेश में नयी-नयी सम्पर्क भाषाएँ बन गई होती।

चौहान के विचार से “संस्कृतनिष्ठ हान के कारण ‘‘हिन्दी ने उर्दू के मुकाबले में ‘ राष्ट्रीय आन्दोलन को एकजुट करने में अधिक व्यापक योग दिया।” होना यह चाहिए था कि जो सहज सम्पर्क भाषा बनी थी, वही राष्ट्रीय आन्दोलन को एकजुट करती। लेकिन यह काम किया संस्कृतनिष्ठ—हिन्दू समाज की भाषा—हिन्दी ने। यह भी उसी पुरानी स्थापना का नया रूप है; गांधीजी ने जो राष्ट्रीय आन्दोलन चलाया, वह मूलतः हिन्दू राष्ट्रवाद का आन्दोलन था।

अब बच गए मुसलमान। वे असल राष्ट्र की माँग तो कर चुके। अब उर्दू को क्षेत्रीय भाषा बनाने के बलावा और किम चीज की माँग करें ?

इस प्रकार चौहान का यह नया लेख भी उनकी पुरानी हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति की सम्प्रदायवादी—भाकर्मवाद-विरोधी—समझ के आधार पर लिखा गया है। वह वस्तुगत रूप में अंग्रेज़ों का समर्थन करता है, अंग्रेज़ों को राजभाषा बनाये रखनेवालों के तर्क दोहराता है। उनकी एक भी स्थापना हिन्दी के लेखक और पाठक न मानें तो यह स्वाभाविक है, इस तरह उन्हें बका न होना चाहिए।

(१९६५)

हिन्दी के आधुनिक विकास-सन्दर्भ में ब्रजभाषा की भूमिका

भारत की अन्य भाषाओं की तरह हिन्दी भी विकासमान भाषा है।

पिछले पच्चीस वर्षों में हिन्दी भाषी प्रदेश के नगरों का रूप काफी बदल गया है। अवध के प्रसिद्ध नगर सखनऊ पर भोजपुरी छाप है। दिल्ली तीन चौथाई पंजाबी शहर है। फरीदाबाद जैसे व्यापार और उद्योग धन्धों के नये केन्द्र कायम हो गये हैं। कलकत्ता और बम्बई जैसे महानगरों में लाखों नये आदमी निमग्न-कर इकट्ठा हो गये हैं। इन सब केन्द्रों में जिस भाषा का व्यवहार होता है, वह छापे की परिनिष्ठित हिन्दी नहीं है।

इस हिन्दी की विशेषता है, उस पर अनपदीय बोलियों अथवा हिन्दी की पड़ोसी भाषाओं का प्रभाव। दिल्ली की हिन्दी पंजाबी प्रभावित है, बनारस की हिन्दी भोजपुरी प्रभावित, कलकत्ते की हिन्दी बंगला-प्रभावित, बम्बई की हिन्दी मराठी-प्रभावित। ध्यान देने की बात है कि हिन्दी दूसरों पर लादी गई होती तो दूसरों का प्रभाव ग्रहण करके नये नये स्थानीय रूप धारण न करती। उसका प्रसार और विकास सहज है, इसीलिए वह स्थानीय प्रभाव से अपना रूप बदल लेती है। यह भी ध्यान देने की बात है कि इस विकासमान भाषा को हिन्दी-उर्दू की विभाजन रेखा खींचकर दो हिस्सों में बाँटा नहीं जा सकता।

हिन्दी प्रदेश में ब्रज एक प्रसिद्ध जनपद की बोली है। ब्रजभाषा का खनि-तत्र इस ढंग का है कि ग्रामों से पटना तक उसके शब्दों को मुँह से निकालने में किसी को कठिनाई नहीं होती। कोई भाषा अपने क्षेत्र में और पड़ोसी प्रदेशों में लोकप्रिय हो, इसने लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह लोगों की बोलने में सुगम जान पड़े। जिन कवियों ने शताब्दियों तक ब्रजभाषा को सँवारा, उसे गुजरात से बंगाल तक, पंजाब में केरल तक संगीत और साहित्य के माध्यम से लोकप्रिय बनाया, वे इस बात की अच्छी तरह समझते थे। वे ब्रजभाषा का स्वभाव पहचानते थे, उन्हें यह भ्रम न था कि ब्रजभाषा संस्कृत की बेटी है, इसलिए उसमें जितना ही उत्तम शब्द होंगे, उनका ही लोक-प्रिय होकर वह सारे भारत की राष्ट्रभाषा बन जायेगी। उन्होंने ब्रजभाषा में

वैसे शब्द लिये जैसे उसमें खप जाते थे। इसलिए रेडियो और समाचार पत्रों की सहायता के बिना, किसी केन्द्रीय निदेशालय द्वारा मूत्र-मदानन के बिना, विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम का अङ्ग हुए बिना यह हमारी प्रिय व्रजभाषा जनता का कठहार बन गई। आज का हिन्दी लेखक उस मारे विकास को देखकर विनम्रता से सर झुका ले तो अच्छा है, स्पर्धाभाव से उस विकास को तुच्छ ठहराने का फल उसी के लिए अतिशय होगा।

पिछले पच्चीस वर्षों में हिन्दी का तेजी से प्रसार हुआ है, इस प्रसार के साथ उस पर जनपदीय बोलियों और पड़ोसी भाषाओं का गहरा असर पड़ा है। बोलचाल की हिन्दी का यह प्रसार, उस पर जनपदीय बोलियों और पड़ोसी भाषाओं का गहरा प्रभाव उसका विकास है, उसका ह्रास या उसके रूप का बिगड़ना नहीं है। यह बोलचाल की हिन्दी हमारी जातीय भाषा है, वही सारे देश के लोगों की राष्ट्रभाषा है। उसके विकास और प्रसार को रोकना किसी राजनीतिज्ञ के वश में नहीं है, उस हिन्दी-उर्दू के दो रूपों में बाँटना किसी संप्रदायवादी के हाथ में नहीं है।

हिन्दी का यह आधुनिक विकास उसे व्रजभाषा के समीप लाता है और संस्कृत-गर्भित परिनिष्ठित हिन्दी (तथा फारसी-अरबी-गर्भित उर्दू) से दूर ले जाता है। ऐसा होना स्वाभाविक है। मगधी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, मैथिली आदि व्रजभाषा की तरह तद्भव रूप ग्रहणाती है, संयुक्त वर्णों वाले, उच्चारण में किष्ट, सत्सम रूप नहीं। जनपदीय बोलियों के तद्भव रूपों में आज की हिन्दी जितना ही प्रभावित होगी, उतना ही वह व्रजभाषा के अनुरूप बनेगी; क्योंकि यह व्रजभाषा भी तद्भव प्रधान है। व्रज व्रजभाषा चाहे साहित्य की हो, चाहे बोलचाल की, उसके रूप में विशेष अन्तर नहीं पड़ता। कुछ विद्वान् कहते हैं, साहित्य की भाषा और बोलचाल की भाषा में हमेशा बड़ा अन्तर रहता है। वे व्रजभाषा का विशाल साहित्य देखें और बतायें कि यह बोलचाल की व्रजभाषा से मूलतः कहीं भिन्न है। आज की हिन्दी अंग्रेजी मुहावरों, अंग्रेजी वाक्य विन्यास से निरन्तर प्रभावित होकर अपना रूप बिगाड़ रही है, फारसी से प्रभावित होकर व्रजभाषा ने अपना रूप नहीं बिगड़ने दिया। अपनी शिष्टता और विद्वत्ता प्रकट करने के लिए हम आज की हिन्दी में ज़िम डग से नये गढ़े हुए शब्द भरते हैं, उस तरह व्रजभाषा के कवियों ने नहीं भरे। व्रजभाषा की ध्वनियाँ, उनके शब्द रचने का ढंग बोलचाल में वही है जो साहित्य में है। साहित्य की व्रजभाषा और बोलचाल की व्रजभाषा में वैसे अन्तर नहीं है जैसा बोलचाल की हिन्दी और साहित्य की हिन्दी में आज है।

यह दुर्भाग्य की वान है कि व्रजभाषा और खड़ी बोली के विवाद में पढ़कर बहुत स लेखकों ने अपनी हिन्दी की व्रजभाषा की राह से हटाकर संस्कृत की ओर मोड़ा। यदि हम भारनेन्दु, प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुन्द गुप्त जैसे पुराने लेखकों के गद्य पर ध्यान दें तो विदित होगा कि उनका

खड़ी बोली गद्य व्रजभाषा में प्रभावित है, या उसके अनुरूप है। उसकी मर-
मना और सजीवता का यह बहुत बड़ा कारण है। प्रेमचन्द या घमनमाल नागर
का बहुत-सा गद्य-लेखन जनपदीय बोलियों में प्रभावित हान के कारण उसी पर-
परा में जुड़ा हुआ है। हिन्दी लेखकों के लिए भाषा और साहित्य की मजसे बड़ी
विरामत व्रजभाषा में सुरक्षित है। वह विरासत घर बैठे मुलभ है, उस अपना-
कर हम अपनी भाषा को समर्थ बनायें, बमजोर नहीं। अनक विषापद जनपदीय
बोलियों के तित व्यवहार की चीज हैं, अपनी परिणिष्ठित हिन्दी में हम उन उन्हें
निकाल दिया है। वे सब व्रज साहित्य में सुरक्षित हैं। उनके लिए हिन्दी का
द्वार खोल देना चाहिए। हिन्दी में नये तद्भव रूपों का बनना बन्द हो गया
है, नये रूप बनाना दूर, पुराने तद्भवों से हम अपने को भरमर बचाते हैं। उर्दू
की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह जनपदीय बोलियों से दूर होती गई,
इस बात में हिन्दी उसका अनुसरण क्यों करे? हिन्दी की शक्ति इस बात में
थी कि वह जनपदीय बोलियों से जुड़ी हुई थी। उस अपनी शक्ति का यह
आधार न छोड़ना चाहिए।

जनपदीय बोलियों में व्रजभाषा पर ही विशेष ध्यान क्यों दिया जाय, इसके
बड़े कारण हैं। पहला कारण यह कि भाषा को निखारने, सँभारने का काम
जिनका व्रज में हुआ है, उतना अन्य किसी बोली में नहीं। यहाँ लेखकों के लिए
वे आदर्श रूप तैयार कर दिये गये हैं, जिनके अनुकरण से वे खड़ी बोली को
अधिक लोकप्रिय बना सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि साहित्य की व्रजभाषा
ने सीमित व्रज क्षेत्र की भाषा मपदा से ही अपना ठाठ नहीं रचा है, उसमें अनेक
जनपदों के महत्वपूर्ण भाषा तत्व भी समेट लिये गये हैं। ऐसा होना अनिवार्य
था क्योंकि व्रजभाषा के अधिकांश ब्रज प्रदेश के रहने वाले नहीं थे। नये
मिरे से मेहनत करके विभिन्न जनपदों से भाषातत्व समेटकर अपनी जातीय
भाषा को पुष्ट करने के बदले हिन्दी लेखक व्रजभाषा-साहित्य के अध्ययन से ही
अपनी खड़ी बोली में उन बहुत से भाषातत्वों का समावेश कर सकते हैं। तीसरा
और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हरियाणा की खड़ी बोली ने आधुनिक
हिन्दी उर्दू का रूप ही व्रजभाषा के प्रभाव से ग्रहण किया है। व्रजभाषा का रस
उसकी धृष्टी में उसे पिनाया गया था। इसलिए व्रजभाषा की अनुकूलता हिन्दी
के विकास का ऐसा नियम है जो निमग्न-सिद्ध है और उसका आधुनिक रूप की
पसोटी है।

इस तीसरे कारण पर थोड़ा और विचार करना उचित होगा।

कहते हैं कि उर्दू देहली की जवान है। इस जवान का देहली ने आसपास
के गाँवों से क्या सम्बन्ध है?

कहते हैं कि हिन्दी दिल्ली और मेरठ की भाषा है। दिल्ली और मेरठ के
जनपद घर्षात् हरियाणा से इस भाषा का क्या सम्बन्ध है?

हिन्दी और उर्दू का व्याकरण तब मूलतः वही है जो हरियाणा की बोली

हिन्दी के आधुनिक विकास मन्दज में व्रजभाषा की भूमिका / ३३३-

का है। ब्रजभाषा की तरह 'खाऊगो' या भवषी की तरह 'खाब,' 'खइवे' रूप हिन्दी में नहीं चसते। 'खाऊगा' रूप हरियाणा की देन है। हिन्दी-उर्दू ने अपना व्याकरण-तन्त्र हरियाणा की जनपदीय खड़ी बोली (भयवा बांगरू) से पाया है, उसका ध्वनितन्त्र ब्रजभाषा की देन है। दीर्घ स्वर के बाद सयुक्त व्यंजनो का प्रयोग बांगरू की विशेषता है। रोट्टी, टेस्सण, वेल्लण (वेसन) जैसे ध्वनिबन्ध हिन्दी-उर्दू के लिए (और ब्रज से लेकर मैथिली तक जनपदीय बोलियों के लिए) अस्वाभाविक हैं। बांगरू में ठकार की भरमार है। थाली, हथेली, बाळक; हिन्दी-उर्दू (तथा ब्रज से लेकर मैथिली तक जनपदीय बोलियों) में इसका पूर्ण बहिष्कार है। बांगरू के ध्वनितन्त्र की ऐसी घनेक विशेषताएँ हैं जिनका हिन्दी में अभाव है। उन सब की चर्चा करना यहाँ अनावश्यक है। एक अन्य विशेषता की ओर ध्यान दिलाना बाकी होगा। अपनापण, निगापन, दाणा, पाणी, जाना, आणा, कितना, सुनना जैसे रूपों में मूर्धन्य अनुनासिको की बहुतायत ब्रज तथा अन्य पूर्वी जनपदीय बोलियों को अग्राह्य है। हिन्दी में तो संस्कृत के प्रभाव से तत्सम रूपों में णकार लिखा भी जाना है (बोलने में उसकी निरन्तर अवहेलना होती है) किन्तु उर्दू में तो उसे पँठने की अनुमति ही नहीं मिली। है न आश्चर्य की बात! बांगरू जनपद का मुख्य नगर दिल्ली और उसकी भाषा में णकार का अभाव। दिल्ली के उत्तर और पश्चिम में णकार प्रेमी पंजाबी और राजस्थानी बोलियों का प्रसार, पूरब और दक्खिन में बांगरू, फिर भी णकार का अभाव। अपने चारों ओर विरोधी ध्वनितन्त्र के समुद्र में दिल्ली शहर एक द्वीप के समान था जिस पर ब्रजभाषा के ध्वनि-तन्त्र की पताका फहराती थी। जातीय भाषा के रूप में हिन्दी के प्रसार का एक प्रमुख कारण उसमें हरियाणा के व्याकरण तन्त्र और ब्रजभाषा के ध्वनितन्त्र का समन्वय है। व्याकरण तन्त्र से हिन्दी पछाही बोलियों को अपनी ओर खींचती है, ध्वनितन्त्र से (बुन्देलखण्ड-बघेली आदि के साथ) पूर्वी बोलियों को। यूरप और भारत की आधुनिक भाषाओं ने प्रायः किसी एक बोली के आधार पर ही अपना आधुनिक रूप विकसित किया है। व्याकरण तन्त्र एक बोली का, ध्वनितन्त्र दूसरी बोली का, ऐसा सामञ्जस्य अन्यत्र दुर्लभ है। हिन्दी जो पूर्वी और उत्तर पश्चिमी जनपदों को सामान्य जातीय जीवन में बाध सकती है, उसका एक ऐतिहासिक कारण यह अनुपम सामञ्जस्य है।

दिल्ली से भिन्न आगरा नगर ब्रज जनपद का प्रमुख केन्द्र है। इस नगर के उत्तर, दक्खिन, पूरब, पच्छिम चारों ओर ब्रजभाषा को छोड़कर दूसरी बोली की पँठ नहीं है। खड़ी बोली की एक टकसाल आगरे में भी थी। अकबर और शाहजहाँ के जमाने में आगरा एशिया में व्यापार की सबसे बड़ी मंडी था। दिल्ली और हरियाणा समेत अनेक नगरों और जनपदों के व्यापारी और कारीगर यहाँ इकट्ठे हुए थे। ब्रजभाषा के परिवेश में ये खड़ी बोली का व्यवहार करते थे, इसलिए यह स्वाभाविक था कि वे रोट्टी को रोटी कहें, टेस्सण को

टेसन, बाळक को बालक, घाणा-जाणा को घाना-जाना ।

१६०० से १८०० ई० तक खड़ी बोली के विकास का यह स्वर्ण युग है जब उस पर ब्रजभाषा का गहरा असर पड़ा। इस खड़ी बोली पर आगरे की छाप है। आगरे की खड़ी बोली का एक खास सर्वनाम रूप है— विस, 'इसका बहुवचन हुआ—विन। सल्लूजी साल आगरे के, उनकी खड़ी बोली में 'विस' का घाना लाजमी था। "विसका सार ले, यामनी भाषा छोड़, दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में वह नाम प्रेमसागर धरा" (दिल्ली भरठ की खड़ी बोली नहीं, दिल्ली आगरे की खड़ी बोली।), "बिन्हें देख परीछित मन में कहने लगे"। राजा शिवप्रसाद ने 'गुटका' में 'सल्लू जी की बोली' के जो नमूने इकट्ठे किये, उनमें 'विस' और 'विन' भी थे। किन्तु इनका सम्बन्ध सल्लूजी की किसी व्यक्तिगत बोली से नहीं, आगरे की बोली से था। ये रूप सदल मिथ के नासिबेती-पाख्यान में भी हैं, "और वेद की भाषा से सतान के लिए पत्नी सो भोग करना उचित है, नहीं तो विस विन क्या कभी क्रिया सिद्ध होती है", "और जिस जिस के लाने को धर्मराज विन को बरजते हैं"। गिनक्रिस्ट के हिन्दुस्तानी भाषा के व्याकरण (सन् १७९६) में एक मसिया है जिसमें विस और विन का प्रयोग किया गया है।

दिलला के विन बच्चों को विस के लहू की नाली

लेगे को लाके विन पर बच्चे को फिर सँभाला।

यह मसिया गोपीचंद नारग न अपनी छोटी किन्तु सारगर्भित पुस्तक "करखन्दारी डायनेक्ट ऑव डेलही" में उद्धृत किया है। करखन्दारी डायनेक्ट यानी कारखाने के मजदूरों की बोली। इन मजदूरों की बोली में—दिल्ली की परिनिष्ठित उर्दू से भिन्न—आगरे की खड़ी बोली के वे रूप आज भी कायम हैं जिन्हें उनके बाप दादे अपने साथ दिल्ली ले गये थे। "विसी की तो बान कर रिया हू", "विनो ने लुटिया भर के विन के भागे करी"—यह दिल्ली के जनसाधारण की खड़ी बोली है और यह आगरे की खड़ी बोली भी है। अमृतलाल नागर ने आगरे के लोगों से सुनकर और सीखकर इस बोली का प्रयोग 'सेठ बांकेमल' में किया है : "विन्ने रो-रो के बही कि प्यारी रो मती। हाय, तेरी भावो का मुरमा बहा जाय है। जे बहूके विसि कलेजे से लगा लीना", "इत्ता बहना या भयो कि विसकी भाखें उलटने लगी। विन्ने दो बार भल्ला भल्ला करके धोला छोड़ दीना।"

हिन्दी के पुराने व्याकरणों और कोशों में ये रूप बराबर मिलते हैं। हिन्दी-उर्दू के विकास में आगरे के महत्वपूर्ण योगदान का यह प्रमाण है।

पुरानी हिन्दी में देखियो, बरियो, लाइयो जैसे क्रिया रूपों की भरमार है। ये कविता में, भाषा को आकर्षक बनाने के लिए ब्रजभाषा से उधार लेकर नहीं रख दिये गये। ये दिल्ली और आगरे की ब्रजभाषा प्रभावित खड़ी बोली के अपने रूप हैं। नजीर अकबरावादी ने कन्हैया जी के जन्म का वर्णन करते हुए

हिन्दी के आधुनिक विकास-सन्दर्भ में ब्रजभाषा की मूलिकाँ

लिखा :

ये सोच हुआ मन बीच उन्हें पर इस जल में कैसे धरिये ।

है रैन धोंधेरी सँग बालक इस विपत्ता में अब क्या करिये ।

मीर का शेर है

दादो करियाद जावजा करिये,

घायद उसके भी दिल में जा करिए ।

और गालिब •

पढिये गर बीमार तो कोई न हो तीमारदार,

और अगर मर जाइये तो नौहस्वा कोई न हो ।

गालिब और मीर दोनों आगरे के थे, आगरे से आकर दिल्ली बसे थे ।

फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने शिक्षा-विभाग के माध्यम से हिन्दी-उर्दू को दो दिशाओं में विकसित करने का संगठित प्रयास किया । हिन्दुओं के बच्चे चाहे एक बार उर्दू पढ़ लें, मुसलमानों के बच्चे हिन्दी नहीं पढ़ेंगे; इतिहास और भूगोल की स्कूली किताबों में हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली भलग, उर्दू की असल । फोर्ट विलियम कालेज से पहले मुसलमानों ने चाहे पंजाबी लिखी हो, चाहे ब्रजभाषा या बँगला, उसमें अरबी-फारसी के लिए वह प्राप्रह नहीं है जो उर्दू में है । फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना से पहले खड़ी बोली में जो भी साहित्य लिखा गया है, वह शब्दावली के आधार पर हिन्दी-उर्दू के दो भिन्न रूपों में नहीं बाँटा जा सकता । दिल्ली और आगरे के मुसलमानों की इस पुरानी खड़ी बोली पर ब्रज 'भाषा' का ही नहीं, उसकी साहित्यिक परंपरा का भी गहरा असर है । मेरठ-निवासी मुहम्मद अफ़जल उर्फ़ शाह अफ़जल ने "विकट कहानी-बारह मासा" में जिस भाषा का प्रयोग किया है, उसे डा. समूद हुसैन खा और डा. विद्यासागर ने अपनी भूमिका में उचित ही सोलहवीं सदी की खड़ी बोली हिन्दी का समूना स्वीकार किया है ।

किनारे लग रही पिउ विन प्रेसी,

भई है जियी मुझ पर दुहेली ।

तुम्ही टुक कर पकड़ समझाय कहियो,

पगल पर सीस घर कर लाय कहियो ।

अगर मैं जानती यह बेवफ़ाई,

खुदा की सौं न करती आशनाई ।

अरे ऊँघो सुनो यह दुस हमन सूं,

कहो टुक जाय परदेसी सजन सूं ।

सोलहवीं सदी में—फारसी ने राजभाषा बने रहने पर भी—हिन्दुओं और मुसलमानों की जातीय भाषा को साहित्य में जो सहज सरस रूप मिला था, वह ऐसा था । मुगल साम्राज्य के विघटन के समय, और फोर्ट विलियम कालेज

की स्थापना के बाद विकास का यह सहज क्रम टूट गया। जहाँ से यह क्रम टूटा था, सन ४७ में फिर से उसे जोड़ना था। किन्तु राजनीतिज्ञों ने स्वराज्य आन्दोलन के समय किये हुए और वादों की तरह हिन्दी-उर्दू की एकता वाली पुरानी बात भी उठाकर ताक पर रख दी। वे कहते हैं, हिन्दी वाले एक और उर्दू को दबाते हैं, दूसरी ओर हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के उत्साह में दक्षिण के लोगों के मन में भय उत्पन्न करते हैं। एक राजनीतिज्ञ ने पिछले महीने लखनऊ की एक सभा में यहाँ तक कहा—याहिया खाँ ने पाकिस्तान में उर्दू को राष्ट्रभाषा बनाना चाहा, क्या नतीजा हुआ? पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गये। क्या आप चाहते हैं कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हम दक्षिण में फौज भेजें और भारत के दो टुकड़े हो जाने दें?

सुना है स्वाधीन बंगला देश में वहाँ की राजभाषा बंगला है। पश्चिमी बंगाल की राजभाषा अंग्रेजी है। यदि कोई कहे कि पूर्वी बंगाल की तरह पश्चिमी बंगाल में भी बंगला को राजभाषा बनाइये तो राजनीतिज्ञ कहेंगे, पूर्वी बंगाल जैसे पाकिस्तान से अलग हुआ, वैसे ही पश्चिमी बंगाल को तुम भारत से अलग करना चाहते हो?

यानी हर परिस्थिति में, हर तर्क-योजना के अंत में आप पहुँचेंगे एक ही लक्ष्य तक—भारत में अंग्रेजी बरतनी चाहिए।

इस लक्ष्य सिद्धि के लिए इनके पास तीन दाँव हैं।

पहला—हिन्दी और अहिन्दी भाषियों को एक दूसरे से लड़ाना, इनके परस्पर भय और रागद्वेष से नाम उठाकर समस्त भारतीय भाषाओं को दबाकर रखना,

दूसरा—हिन्दी और उर्दू के भेद को गहरा करना, हिन्दी उर्दू को दबाये है, एक महत्वपूर्ण भाषा नेस्तनाबूद होने को है, इसलिये हिन्दी भाषी प्रदेश में भी हिन्दी को अपना स्वतन्त्र न मिलना चाहिए।

तीसरा—हिन्दी और उसकी जनपदीय बोलियों की एक दूसरे से लड़ाना, साहित्य प्रकाशनी द्वारा अनेक बोलियों का मान्यता दिलाकर उनको हिन्दी से स्वतन्त्र भाषा करार देना, क्षेत्रीयता की भावना को बढ़ावा देकर पहले से ही बँटे हुए हिन्दी प्रदेश को और भी छोटे-छोटे टुकड़ों में बाटना।

दिवालिवा दासक वर्ग इस कूटनीति द्वारा जनता को ठगने के बलावा और कर ही क्या सकता है?

किसे फुसंत है यह देखने की कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से पहले हिन्दी उर्दू का भेद था या नहीं और उस समय की खड़ी बोली पर प्रजभाषा का प्रभाव गहरा था या उबला?

हिन्दी लेखकों का कोई जातीय भय नहीं है। इसलिए उपर्युक्त कूटनीति का कोई उत्तर हिन्दी की ओर से नहीं दिया जा रहा है। किन्तु भारत की जनता अपने ढंग से, परिस्थितियों को साफ-साफ न पहचानते हुए, फिर भी निरन्तर

हिन्दी के भाषुनिन विकास-मन्दर्भ में प्रजभाषा की भूमिका / ३३३

उनसे प्रेरित और प्रभावित होकर, इस कूटनीति का उत्तर दे रही है।

पहले दांव का उत्तर यह है कि अहिन्दी प्रदेशों में हिन्दी का प्रसार ही नहीं हो रहा, वह अहिन्दी भाषाओं से प्रभावित होकर नये-नये स्थानीय रूप भी ग्रहण कर रही है। अंग्रेजों ने अठारहवीं सदी में मद्रास की सेना के अंग्रेज अफसरों के लिए दक्कनी हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य कर दिया था, उस समय हैदराबाद की हिन्दी दक्षिण भारत में प्रचलित हिन्दी का एक मात्र रूप थी। इस समय हैदराबादी दक्कनी के अलावा, चार प्रमुख द्रविड़ भाषाओं का प्रभाव ग्रहण करती हुई हैदराबाद के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, हिन्दी के एक नये रूप का चलन हो रहा है, जिसे हम द्राविडी हिन्दी कह सकते हैं। इसका व्यवहार द्रविड़ भाषा भाषी सामान्य जन उत्तर भारत के भाष्य भाषा भाषियों से संपर्क होने पर ही करें, यह आवश्यक नहीं है, स्वयं आपस में एक दूसरे की बात समझ पाने के लिए, अंग्रेजी का ज्ञान न होने पर, उन्हें हिन्दी का सहारा लेना पड़ता है। हिन्दी का व्यवहार सबसे पहले और सबसे अधिक अहिन्दी भाषियों के आपसी संपर्क के लिए जरूरी है। हिन्दी के प्रसार का यह वस्तुगत कारण है। इसके लिए हिन्दी भाषी उत्तरदायी नहीं है। दरअसल पिछले बीस वर्षों में हिन्दी का प्रसार कार्य बिल्कुल ढीला हो गया है, जनता का पैसा सरकार के माध्यम से चाहे जितना बाँटा गया हो, पर यह सच है कि प्रचार जितना ही कम हुआ, प्रसार उतना ही ज्यादा हुआ। कारण वही है, स्वाधीन भारत की अहिन्दी भाषी जनता के आपसी संपर्क की उत्कट आवश्यकता। विदेशी राज्या द्वारा करोड़ों रुपये (भारतीय शासन द्वारा लाखों रुपये) अंग्रेजी पढ़ने पढ़ाने पर खर्च किये जाने पर भी संपर्क की इस आवश्यकता को अंग्रेजी पूरा नहीं कर सकती।

द्राविडी हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा का दक्षिणी रूप है, नये स्वाधीन भारत का प्रकाश्य यथार्थ है। इस यथार्थ को देखने के लिए मद्रास जाना आवश्यक नहीं है, दिल्ली या आगरे में भी उसके दर्शन हो सकते हैं।

दूसरे दांव का उत्तर यह है कि हिन्दी भाषी प्रदेश के हिन्दू और मुसलमान, गाँवों के करोड़ों किसान और नये औद्योगिक विकास के साथ नये नये लाखों मजदूर—हिन्दू और मुसलमान—एक सा जातीय जीवन बिता रहे हैं। उन्हें आपसी व्यवहार के लिए दुभाषिये की जरूरत नहीं पड़ती, न वे राष्ट्र के सूत्रधारों की तरह देश-जनता-राजनीति जैसे शब्द कहकर मुक्त अवाम सियासत के द्वारा अपनी बात का अनुवाद करते हैं। बंगला और तमिल फिल्म बंगाल और तमिल-नाडु के बाहर दिखाना हो तो उसके सबादों का हिन्दी रूपान्तर जरूरी होता है। किसी हिन्दी फिल्म का उर्दू रूपान्तर या उर्दू फिल्म का हिन्दी रूपान्तर अभी तक देखने-सुनने में नहीं आया। जनता की इस सामान्य भाषाई एकता का आधार छोड़कर जो भी भ्रमराज का हवामहल बनायगा, वह उस हवामहल की तरह खुद भी एक दिन इस धरती से हवा हो जायगा।

तीसरे दौर के उत्तर में हिन्दी प्रवेश के जनपदों ने आपसी एकता को और दृढ़ किया है। जयपुर, मथुरा, करीदाबाद, झाँसी, पटना—कहीं कोई ऐसा कारखाना, कोई भी औद्योगिक प्रतिष्ठान ऐसा नहीं है जिसमें एक ही जनपद के लोग काम करते हों, जिसमें वे आपस में किसी एक जनपदीय बोली का ही व्यवहार करते हों। दैनिक जनता की यह एकता हमारी जातीय एकता की धुरी है। जो लोग जनपदीय अलगवाव को बढ़ावा देते हैं, वे इस धुरी पर ही प्रहार करते हैं। इससे उन्हीं के सर में चोट लगेगी। जनपदीय बोलियाँ हिन्दी को निरन्तर प्रभावित करती हुई उस क्षेत्रीय रूप देकर उसे स्थानीय जनता के अनुरूप बना रही हैं।

इस परिस्थिति में—हिन्दी के इस आधुनिक विकास सन्दर्भ में—हमें ब्रजभाषा की भूमिका पर विचार करना चाहिए। हिन्दी प्रदेश के सभी जनपदों में ब्रजभाषा का साहित्य ही सबसे विस्तृत है, अन्य जनपदों में यह साहित्य भाषा भी लोकप्रिय है, नये तद्भव गढ़ने और तद्भवों में तत्समों को खपाने की कला के श्रेष्ठ उदाहरण इसके साहित्य में हैं, अन्य जनपदों की बहुत सी भाषा-संपदा साहित्यिक ब्रजभाषा में पहले ही सिमट आई है, हरियाणा की खड़ी बोली को हिन्दी-उर्दू का सरस, सामान्य रूप देने का श्रेय ब्रजभाषा की है, हिन्दी से उसका सम्बन्ध जन्मजान है, तब उसके विकास में ब्रजभाषा का योगदान ऐतिहासिक रूप से भावश्यक है। आज की लिखित हिन्दी के स्वभाव को ब्रजभाषा के अनुकूल बनाना विकास की उन कड़ियों को फिर से जोड़ना है जो फोटे बिलियम कालेज की स्थापना के बाद टूट गई थी।

आज की लिखित हिन्दी जितना ही ब्रजभाषा के अनुकूल होगी, उतना ही वह हिन्दी जनपदों में लोकप्रिय होगी, उतना ही वह हिन्दी-उर्दू का भेद मिटाने में समर्थ होगी, उतना ही वह अहिन्दी प्रदेशों, विशेषकर दक्षिण भारत में, लोकप्रिय होगी। यदि रचना चाहिए कि द्रविड भाषाएँ सबकी सस्कृत रूपों को निरन्तर तद्भव बनाती रही हैं। तमिल 'वच्चा' हिन्दी 'बच्चा' के अनुरूप है, सस्कृत 'कट्या' के नहीं, बन्नड 'वट्टि' हिन्दी 'भट्टा' के अनुरूप है, सस्कृत 'आप्प' के नहीं, 'श्री' का तत्सम उच्चारण द्रविड भाषियों के लिए बैसा ही कठिन है जैसा ब्रजवासियों के लिए, निरूपति' से लेकर 'तिरमन्तपुरम्' (दिवेन्द्रम्)। तब तक सब कही 'श्री' के तदभव रूप 'तिह' की ही शोभा है। वर्ष नहीं, मरुम्, आचार्य नहीं, आचार्यर, अहंत नहीं, मरहन, दोय नहीं, चेमम्, स्पान नहीं, तानम्; ऐसी सबकी मिसालें हैं जिनसे यह समझते देर न लगेगी कि अक्षत तमिल भाषी के लिए ब्रजभाषा के तद्भव रूप ही सुगम हैं, लिखित हिन्दी (खास तौर से सरकारी हिन्दी) के तत्सम रूप नहीं।

चाहे जनपदीय स्तर पर विचार करें, चाहे भाषास्तर पर, यह निष्कर्ष अनिवार्य है कि आज की लिखित हिन्दी जिस को ब्रजभाषा के अनुरूप ढालकर ही अपने ऐतिहासिक विकास की मजिल तक पहुँच सकती है। १९७५

हिन्दी के आधुनिक विकास सन्दर्भ में ब्रजभाषा की भूमिका

हिन्दीभाषी प्रदेश—बहुभाषाभाषी प्रदेश ?

कुछ दिन पहले एक भारतमित्र विदेशी विद्वान् व० मु० विद्यापीठ आगरा पधारे थे। वह भारत में काफी दिन रह चुके हैं, बहुत अच्छी हिन्दी बोलते हैं और हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में बहुत कुछ ज्ञान भी चुके हैं। इस समय वह हिन्दी भाषी प्रदेश की भाषाई स्थिति पर शोध कार्य कर रहे थे। उनकी धारणा यह थी कि हिन्दी प्रदेश बहुभाषाभाषी प्रदेश है और इस प्रकार भारत या यूँ कहें कि भाषाई क्षेत्रों से इसकी स्थिति भिन्न है। अपनी धारणा के प्रमाणस्वरूप उन्होंने इन तथ्यों का हवाला दिया। हिन्दी प्रदेश में काफी लोग सामाजिक और पारिवारिक जीवन में अंग्रेजी भाषा का व्यवहार करते हैं। भाषा में हिन्दी बोलते हुए भी बीच-बीच में अंग्रेजी का व्यवहार करते हैं। इसके अनिश्चित हिन्दी और उर्दू दो भिन्न भाषाएँ हैं, इसमें सन्देह ही क्या है, और इन दोनों का मुख्य व्यवहार क्षेत्र एक ही प्रदेश यानी हिन्दी भाषी प्रदेश है। उर्दू के अलावा अनेक सांस्कृतिक कार्यों में, विशेष अवसरों पर धार्मिक कृत्यों में, संस्कृत का व्यवहार होता है। मुसलमान लोग अरबी का व्यवहार करते हैं। संभव है, कुछ लोग फारसी का व्यवहार भी करते हों। धर्म-विशेष के लोग पालि और प्राकृत में पवित्र वचनों का पाठ करते हैं। हिन्दी प्रदेश में जहाँ भी जाते हैं वहाँ देहात में हिन्दी में अलग-अलग बोली सुनाई देती है। कहीं लोग भोजपुरी बोलते हैं कहीं मैथिली, वही ब्रजभाषा कहीं कोई अन्य बोली। व्याकरण उच्चारण आदि के विचार से ये बोलियाँ एक-दूसरे से बहुत भिन्न हैं और स्वतंत्र भाषाओं जैसी लगती हैं। देहात के अलावा शहरों में भी अलग-अलग ढंग की हिन्दी सुनाई देती है। कलकत्ता, मम्बई, हैदराबाद, पटना और दिल्ली की हिन्दी में काफी अन्तर है। हिन्दी प्रदेश में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहाँ द्रविड़ और मुंडा परिवारों की भाषाएँ बोली जाती हैं। इन सारे तथ्यों को देखने से यह प्रमाणित होता है कि हिन्दी-भाषी प्रदेश एक भाषा का प्रदेश नहीं है, यहाँ अनेक भाषाओं का व्यवहार होता है। उस बहुभाषाभाषी प्रदेश कहना अधिक युक्तिसंगत है।

उस गोष्ठी में उक्त स्थापना के सम्बन्ध में मैंने जो कुछ कहा, उसका सारांश

इस प्रकार है।

प्रादरणीय विद्वान् ने हिन्दी प्रदेश की भाषाई स्थिति के बारे में जो कुछ कहा है, वह सभी लोगों के ध्यान देने योग्य है। उन्होंने हिन्दी-भाषी प्रदेश की चर्चा करते हिन्दी के जातीय क्षेत्र को स्वीकार किया है। जहाँ की भाषा-समस्या का अध्ययन वह कर रहे हैं, वह हिन्दी प्रदेश है, वह हिन्दी भाषा का जातीय क्षेत्र है, हिन्दी जाति का अपना प्रदेश है, वह हिन्दी-उर्दू-अंग्रेजी-संस्कृत-भारवी प्रदेश नहीं कहलाता। मूल बात यह है कि हिन्दी बोलने वालों की एक जाति है, यह जाति अनेक भाषाओं के व्यवहार के कारण विभाजित नहीं है, इस जाति के सदस्यों को जोड़ने वाली भाषा हिन्दी है, हिन्दी छोड़कर अन्य कोई भाषा यह कार्य नहीं करती। मुख्य स्थान इसी हिन्दी भाषा का है, अन्य भाषाएँ, उपभाषाएँ, बोलियाँ, विदेशी भाषाएँ, प्राचीन भाषाएँ आदि गौण स्थान पर हैं। वे विभाजित भले करती हों, जोड़ती नहीं हैं, जोड़ने का काम केवल हिन्दी करती है। यह भी स्पष्ट है कि जोड़ने की प्रक्रिया ऊपर है, अधिक शक्तिसायी है, तोड़ने की प्रक्रिया नीचे है और निर्बल है। ऐसी बात न हो तो हिन्दी भाषी प्रदेश जैसे किसी प्रदेश की कल्पना ही न की जाय, उसकी भाषाई स्थिति की चर्चा का अवसर ही न पाये। हिन्दी प्रदेश वैसे ही यथार्थ इकाई है जैसे अंग्रेजी भाषा या किसी भाषा का प्रदेश यथार्थ इकाई है। राजनीतिक रूप से यह प्रदेश अनेक राज्यों में बँटा हुआ है। जर्मनी, कोरिया, वियतनाम, बंगाल दो राज्यों में बँटे हुए हैं, इससे जर्मन, कोरियाई, वियतनामी, बंगाली जातियाँ और भाषाएँ विभाजित नहीं हो जातीं। प्रादरणीय विद्वान् हिन्दी प्रदेश का अस्तिव स्वीकार करते हैं, उनकी और मेरी स्थापनाओं की यह सामान्य आधारभूमि है।

अब देवना चाहिए कि इस तरह की स्थिति केवल हिन्दी प्रदेश में उत्पन्न हुई है या इससे मिलती जुलती स्थिति अन्य देशों में भी है अथवा कभी रही है।

विदेश में जो भी विद्वान् हमारे प्रदेश में आता है, उसे यहाँ के पढ़े-लिखे लोगों में अंग्रेजी का व्यापक व्यवहार देखकर आश्चर्य होता है। अंग्रेजी का व्यवहार इसलिए नहीं होता कि यहाँ तमिल या तेलुगु बोलने वालों से हिन्दी-भाषियों को सम्पर्क काममें करना है, और वे हिन्दी नहीं जानते, इसलिए अंग्रेजी का व्यवहार करना है। हिन्दी-भाषी लोग ही आपस में अंग्रेजी का व्यवहार करते हैं, विश्वविद्यालयों में इसी प्रदेश के अध्यापक इसी प्रदेश के छात्रों को अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देते हैं, यहाँ के राजकीय अराजकीय कार्यालयों में अंग्रेजी का काफी व्यवहार होता है। इसका कारण हमारी राजनीतिक और सांस्कृतिक पराधीनता के अवशेष हैं। किन्तु इस तरह की स्थिति हमारे प्रदेश अथवा समस्त भारत देश के लिए बुरा नहीं है। किसी समय इंग्लैंड पर नार्मन लोगों का प्रभुत्व था। उस समय इंग्लैंड का अभिजात वर्ग साम्राज्य और पारिवारिक जीवन में अत्यधिक रूप से फ्रांसीसी भाषा का व्यवहार करता था। १६वीं सदी में इस का अभिजात वर्ग इसी फ्रांसीसी भाषा का व्यवहार करता था।

यद्यपि नपोलियन और उसकी फ्रांसीसी सेना की हस्तियों ने पराजित किया था, फिर भी सांस्कृतिक रूप से रूसी अभिजात वर्ग पर फ्रांस की भाषा और संस्कृति का बड़ा गहरा प्रभाव था। यह स्थिति तात्स्तोय के उपन्यासों में बहुत अच्छी तरह चित्रित की गई है। फ्रांसीसी भाषा के धलावा रूसी अभिजात वर्ग जर्मन भाषा का व्यवहार भी करता था। मध्य यूरोप के देशों में जर्मन का व्यवहार और भी व्यापक था जैसे कि चेकोस्लोवाकिया में। मानस के समय में यह प्रभाव इतना अधिक था कि माक्स समझते थे कि चेक और स्लोवाक भाषाओं का अस्तित्व न रहेगा और उनकी जगह जर्मन भाषा का ही व्यवहार होगा। इन तथ्यों पर ध्यान देने से विदित होता है कि विशेष सामाजिक कारणों से अनेक देशों में जातीय भाषा के साथ उच्चवर्गों में विजातीय भाषा का व्यवहार भी हो सकता है और हुआ है। जब कोई जाति अपना सामाजिक सांस्कृतिक विकास करती है, अपनी आन्तरिक एकता सुदृढ़ करती है, तब वह विजातीय भाषा का प्रभाव उतार फेंकती है। ऐसा इंग्लैंड और रूस में हुआ है, चेकोस्लोवाकिया में हुआ है। हिन्दी प्रदेश और भारत में अंग्रेजी का जो व्यवहार दिखाई देता है, वह अस्पाई है। जब हिन्दी जाति सुगठित होगी, अपना सामाजिक सांस्कृतिक विकास करेगी, तब अंग्रेजी का व्यापक व्यवहार बन्द हो जायेगा। जब सारा देश राष्ट्रीय स्तर पर सुगठित होगा, तब अंग्रेजी का यह अखिल भारतीय महत्व समाप्त होगा। अभी यह अखिल भारतीय महत्व अन्य प्रदेशों की तरह हमारे प्रदेश को भी प्रभावित करता है। यह बात याद रखनी चाहिए कि अंग्रेजी का व्यापक प्रभाव भारत के बहुत थोड़े से पढ़े-लिखे लोगों के समुदाय में सीमित है उसकी व्यापकता अत्यन्त सापेक्ष है। हिन्दी प्रदेश में जनसाधारण के बीच व्यापक रूप से हिन्दी का ही व्यवहार होता है।

हिन्दी के साथ उर्दू का व्यवहार हमारे यहाँ का एक अनोखा व्यापार प्रतीत होता है। किन्तु हिन्दी उर्दू दो भिन्न भाषाएँ नहीं हैं, वे मूलतः एक ही भाषा है। इनके सर्वनाम, क्रियापद, मूल-शब्दभण्डार एक ही हैं। सत्तार में कोई दो भाषाएँ ऐसी नहीं हैं जिनके सर्वनाम और क्रियापद सीपीसदी सामान्य हों। रूसी और उर्दू की भाषाएँ एक-दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं पर उनमें भी ऐसी समानता नहीं है। उर्दू की भिन्नता का कारण उसकी सरचना, उसकी मूल भाषाई सम्पदा नहीं है। उसकी भिन्नता का कारण अरबी फारसी शब्दावली का विशिष्ट व्यवहार है।

बहुत समय से जर्मनी में यहूदी लोग रहते आए हैं। इनकी धर्मभाषा हीब्रू है। हीब्रू उनकी बोलचाल की भाषा नहीं है, वह उनकी धार्मिक अथवा सांस्कृतिक भाषा है। जर्मन भाषा में यहूदिया ने हीब्रू शब्दावली मिलाकर एक भाषा गढ़ी जो यिद्दिश कहलायी। आन्स्टाइन और फ्रायड जैसे यहूदियों ने अपनी जातीय भाषा जर्मन का ही व्यवहार किया, फिर भी बहुत से यहूदी अपने धर्म से हीब्रू भाषा का विशेष सम्बन्ध जोड़ने के कारण यिद्दिश को अपनाए

रहे। बहुत से जर्मन यहूदी रुस में जा बसे। वहाँ भी उन्होंने यहिदा चलाई। इस भाषा में उन्होंने अपने समाचार पत्र निकामे। मौस्को में इस भाषा में रचे जाने वाले नाटक खेलने के लिए एक विशेष नाट्यशाला बनायी गई। रुमी भाषा के विशाल जातीय प्रदेश में यहिदा का व्यवहार करने वाले यहूदियों का एक स्वायत्त क्षेत्र भी है। पर यहूदियों की कोई जाति नहीं है। रूसी, पासीसी, जर्मन आदि की तरह कोई यहूदी जाति नहीं है। धर्म अलग-अलग हैं पर ईसाई और यहूदी जर्मनो, ईसाई और यहूदी अंग्रेजों, ईसाई-यहूदी-ता-मजहब सभी तरह के रूसियों की जाति एक ही है। यहिदा में जैसे हीब्रू के बहुत से शब्द मिला दिये गये हैं, वैसे ही उर्दू में बहुत से अरबी-फ़ारसी शब्द मिला देने से उर्दू का अलगवर्ग पैदा हुआ है। जैसे बंगाल के हिन्दुओं और मुसलमानों की एक ही भाषा बँगला है, वैसे ही हिन्दी प्रदेश के हिन्दुओं और मुसलमानों की एक ही भाषा हिन्दी है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होने तक हमारे प्रदेश के मुसलमान अपनी भाषा को हिन्दी ही कहते थे। दोनों के बीच का फासला अंग्रेजी राज्य में ही बढ़ा है। उस राज्य के खत्म होने पर वह फासला कम हो गया है। जब हिन्दी प्रदेश की बहुसंख्यक किसान जनता साक्षर होगी, उसमें शिक्षा-प्रसार होगा, तब यह फासला पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। कबीर, मलिक मुहम्मद जायसी, दादू, रज्जब, रहीम, रसखान की परंपरा फिर जीवित होगी और वहाँ के हिन्दू और मुसलमान एक ही साहित्यिक भाषा के माध्यम से अपनी जातीय संस्कृति और साहित्य को समृद्ध करेंगे। जनसाधारण के निरक्षर और पिछड़े होने से, पुरानी रूढ़ियों के प्रभाव से, धर्म-विशेष के लोग अपनी जातीयता न पहचानकर उस धर्म-विशेष की भाषा से अपना सम्बन्ध जोड़ लेते हैं, उस भाषा का व्यवहार दैनिक जीवन में सम्भव नहीं होता, अतः उसके अधिक से अधिक शब्द जातीय भाषा में ठूँसकर वे अपना अलगवर्ग कायम रखना चाहते हैं। हिन्दू-उर्दू का मुख्य भेद फारसी शब्दों के कारण नहीं है, अरबी शब्दों का लेकर है। फ़ारसी धार्मिकपरिवार की भाषा है, इसके संबन्धी शब्द संस्कृत के तद्भव रूपों जैसे हैं। किन्तु अरबी सामी परिवार की भाषा है। इसके बहुत से शब्द तुर्की में आ गये थे। क़मालपाशा के समय में, और उसके बाद, तुर्कों ने अपनी भाषा को अरबी प्रभाव में मुक्त किया। उसी प्रकार नवजाग्रत ईरान के लोग धार्मिक फारसी को अरबीप्रभाव में मुक्त कर रहे हैं। इसलिए मेरा विश्वास है कि हिन्दी प्रदेश में भी अरबी प्रभाव के कारण हिन्दी-उर्दू में जो भेद पैदा हुआ है वह अस्थायी है और कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा।

हिन्दी प्रदेश में विशेष अवसरों पर धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यों में संस्कृत, अरबी आदि प्राचीन भाषाओं का व्यवहार होता है। यह व्यवहार क्षेत्र अत्यन्त सीमित है और इससे जातीय भाषा का अस्तित्व अक्षत नहीं होता। यूरप के देशों में जहाँ ईसाइयों का रोमन कैथलिक सम्प्रदाय है, वहाँ गिरजाघर में

लैटिन का व्यवहार होता है। आगरे के एक गिरजाघर में अपने एक हिन्दी-भाषी रोमन कैथलिक बन्धु की बहन के विवाह में मैं उपस्थित था। वहाँ मैंने देखा कि जैसे हिन्दू विवाह में संस्कृत मंत्र पढ़े जाते हैं, वैसे ही यहाँ प्रार्थना या मंत्र पाठ लैटिन में हो रहा है। इंग्लैंड में ईसाइयों का प्रोटेस्टेंट मत फैलने पर अंग्रेजी का व्यवहार होने लगा, फिर भी अनेक पवित्र कार्यों के लिए लैटिन का स्थान सुरक्षित रहा। सन्दन का वेस्टमिनिस्टर गिरजाघर बड़ा पवित्र स्थान है। वहाँ देश के महान् पुरुष दफनाये जाते हैं। १८वीं सदी के प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक डा० जानसन से उनके मित्रों ने मज़ाक किया, उनके सामने एक प्रार्थना-पत्र रखा कि वह कवि मोल्डस्मिथ का समाधि लेख अंग्रेजी में लिख दें तो उसे उनकी कब्र पर पत्थर में अंकित कराया जाय। डा० जानसन ने स्पष्ट होकर कहा कि समाधि-लेख लैटिन में ही होगा, वेस्टमिनिस्टर गिरजाघर को अंग्रेजी के व्यवहार से अपवित्र नहीं किया जा सकता।

अंग्रेज जॉब चौसर ने एक पादरी का वर्णन किया है कि जब वह होश में होता था, तब अंग्रेजी बोलता था, जब नशे में होता था तब केवल लैटिन बोलता था। नशा कई तरह का होता है। बहुत से लोग अब भी समझते हैं, ईश्वर उनके धर्म-विशेष की भाषा बोलता था और उसका व्यवहार न करने पर धार्मिक-सांस्कृतिक अनुष्ठानों की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। जहाँ धर्म में ईश्वर की जगह नहीं मिली, वहाँ उसकी जगह कोई सिद्ध पुरुष प्रतिष्ठित हुआ। उसकी मयार्थ या कल्पित वाणी को लोग धर्म की पवित्र भाषा मानने लगे। स्पष्ट है कि धर्म-भाषाओं का व्यवहार हिन्दी प्रदेश की विशेषता नहीं है। अन्यत्र भी ऐसा होता है और हुआ है किन्तु जातीय भाषाओं से भिन्न ऐसी धर्म-भाषाओं का व्यवहार-क्षेत्र निरन्तर संकुचित होना गया है।

यह बात सही है कि हिन्दी प्रदेश में बहुत सी बोलियों का व्यवहार होता है। यह स्थिति हिन्दी प्रदेश के लिए अनोखी नहीं है। भारत या पूरप की कोई भाषा ऐसी नहीं है जिनकी अनेक बोलियाँ न हों। इंग्लैंड में उत्तर और दक्खिन के गाँवों की बोलियों में बड़ा अन्तर है। सन्दन शहर की अपनी बोली है जो परिनिष्ठित अंग्रेजी से भिन्न है। कुछ लोग वेल्स और स्कॉटलैंड की भाषाओं को अंग्रेजी की बोली मानते हैं पर वे अंग्रेजी से उतना ही भिन्न हैं जितना हिन्दी से तमिल। आधुनिक जातीय प्रदेश पुराने जनपदों के आधार पर बनते हैं, जातीय भाषा का निर्माण और प्रसार इन्हीं जनपदों की भाषाओं के बीच होता है। इस विकास की यह विशेषता होती है कि उद्योग-धन्यो और व्यापार के केन्द्रों में जातीय भाषा का व्यवहार होता है, विभिन्न जनपदों के लोग परस्पर सम्पर्क के लिए उसी जातीय भाषा का व्यवहार करते हैं। हिन्दी प्रदेश में कोई ऐसा नगर नहीं है जहाँ हिन्दी से घलग किमी जनपदीय भाषा का ही व्यवहार होता हो। कानपुर एक बड़ा औद्योगिक नगर है। यहाँ दूर-दूर के जनपदों से आकर मजदूर काम करते हैं। इनकी सम्पर्क भाषा हिन्दी है, अपने घर में वे चाहे

कनोजी बोलें चाहे बुन्देलखण्डी । ब्रज प्रदेश के नगर आगरे की सामान्य भाषा ब्रज नहीं है बुन्देलखण्ड के नगर भामो की सामान्य भाषा बुन्देलखण्डी नहीं है, भोजपुरी क्षेत्र के नगर बनारस की सामान्य भाषा भोजपुरी नहीं है । हर जगह मजदूरों, व्यापारियों, नौकरीपेशा लोगों की भाषा हिन्दी है । अब मान लीजिए, बनारस के किसी कारखाने में केवल भोजपुरी का व्यवहार हो, कानपुर में केवल कनोजी का व्यवहार हो, दिल्ली में बंगाल का व्यवहार हो, तो सामाजिक विकास की सारी प्रक्रिया ठप हो जाएगी । सामाजिक विकास-प्रक्रिया के अनुरूप सारे प्रदेश में शिक्षा का माध्यम हिन्दी है । यदि शिक्षा के जनपदीय माध्यम बनाये जायें, भाँसी में शिक्षा का माध्यम बुन्देलखण्डी हो, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम भोजपुरी हो, अलीगढ़ विश्वविद्यालय में शिक्षा ब्रजभाषा के माध्यम से दी जाय, लखनऊ विश्वविद्यालय में अवधी के माध्यम से दी जाय, तो यह सम्भवे देर न लगेगी कि भारत सांस्कृतिक विकास तहसलहस हो जाएगा । इसके अलावा यथार्थ जीवन में भाषाओं की जो स्थिति है, यह कार्य उससे मिलकुल उठता होगा ।

हिन्दी प्रदेश की एकता, इस प्रदेश में हिन्दी के व्यवहार का प्रश्न, राष्ट्रीय एकता के प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है । जो लोग यह चाहते हैं कि भारत में अंग्रेजी का पुराना गौरवपूर्ण स्थान बना रहे, वे हिन्दी के कृत्रिम होने का शोर सबसे ज्यादा मचाते हैं । वे कहते हैं, देखो, हिन्दी न ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी आदि आदि स्वतंत्र भाषाओं को दबा रहा है । उत्तर भारत में ही हिन्दी ने अपना साम्राज्यवाद कायम कर रखा है, उसी का प्रसार हिन्दी वाले बंगाल, महाराष्ट्र, दक्षिण के प्रदेशों में भी करना चाहते हैं । इसलिए अंग्रेजी का व्यवहार निरन्तर करते जाना चाहिए ।

हिन्दी प्रदेश वैसे ही अनक राज्यों में बँटा हुआ है । अन्य प्रदेशों में भारत के राजनीतिक दम भाषावर राज्य बनाने का आन्दोलन चला चुके हैं । हिन्दी प्रदेश में राज्य न तो जनपदीय भाषाओं के आधार पर बने हैं और न जातीय भाषा के आधार पर । यहाँ राज्यनिर्माण का कोई भी सिद्धान्त लागू नहीं होता और राजनीति-विशारद इस समस्या की चर्चा भी नहीं करते । इसलिए जनपदी की भाषाएँ हिन्दी से स्वतंत्र भाषाएँ हैं, यह स्थापना हमारी जातीय एकता को खण्डित करती है, यह राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती है, और अंग्रेजी के प्रमुख को कायम रखती है । इस स्थापना को दोहराते समय बहुत सतर्क रहना आवश्यक है ।

हिन्दी में लिखा हुआ बहुत-सा साहित्य अब गाँवों में किसान पढ़ते हैं । कचहरी अदालत में उनका काम हिन्दी से चलता है । पाठशालाओं में उनके बच्चे हिन्दी पढ़ते हैं । बहुत से विमान गरीबों के कारण गाँव छोड़कर शहर में मजदूरी करने आते हैं । उनका काम हिन्दी में चलता है । इस तरह जिन आर्थिक और सांस्कृतिक सूत्रों से शहर के लोग बँधे हुए हैं, उनमें पूर्णतः नहीं

सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करने की पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए। बड़े जातीय क्षेत्रों में जहाँ पुराने कबीले या लघुमुख्यक जातियाँ रहती हैं वहाँ उनके सामाजिक विकास की समस्याएँ हल करने में दो तरीके महत्वपूर्ण होते हैं। एक तरीका यह है कि बड़े जातीय क्षेत्रों के अन्तर्गत इन्हें स्वायत्त शासन की सुविधा प्रदान की जाय। दूसरा तरीका यह है कि जहाँ अधिक रूप से इनका राज्य आत्मनिर्भर हो सके, वहाँ उनका राज्य बना दिया जाय। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक आदिवासियों के क्षेत्र फैले हुए हैं। ये लोग सामाजिक विकास की विभिन्न मजिलों में हैं। इनका प्रदेश किसी एक ही जाति या एक ही भाषा का प्रदेश नहीं है। यहाँ द्रविड़ और कोल परिवारों की अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। इनके अलावा छोटा नागपुर में आदिवासियों की भाषा से प्रभावित हिन्दी का व्यवहार भी व्यापक रूप से होता है। जैसे शहरों में हिन्दी के अनेक रूप हैं, वैसे ही छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्र में हिन्दी का अपना बोली रूप है। इससे मिलती-जुलती स्थिति भारत के अन्य प्रदेशों में भी है। केरल, तमिल-नाडु आदि के द्रविड़ प्रदेशों में तो अन्य द्रविड़ भाषाएँ बोलने वालों के ही विशेष क्षेत्र हैं। इन्हें स्वायत्त शासन का अधिकार मिलना चाहिए। सोवियत संघ में सो से अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं, वहाँ सो से अधिक जातियाँ निवास करती हैं। वहाँ केवल सोलह प्रजातन्त्र हैं। सोवियत संघ इन्हीं राज्यों का संघ है। प्रत्येक राज्य में अनेक स्वायत्तशासन के क्षेत्र हैं, सबसे अधिक रूसी प्रजातन्त्र में है। ब्रिटेन में एक ही राज्य है परन्तु यहाँ भी वेल्श और गैलिक के अलग क्षेत्र हैं।

हिन्दी प्रदेश की भाषाई स्थिति के बारे में जो विशेषताएँ बतायी गयी हैं, उनमें कुछ ऐसी हैं जो सभी भाषाक्षेत्रों में पाई जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो थोड़े से भाषा-क्षेत्रों में मिलती हैं पर ऐसी कोई विशेषता नहीं है जो कहीं भी न मिलती हो। कहा जा सकता है, दो चार विशेषताएँ इधर-उधर मिल सकती हैं पर ऐसा भाषा क्षेत्र कौन सा है जहाँ ये सभी विशेषताएँ एक साथ मिलती हों? मेरा उत्तर है, ऐसा भाषा क्षेत्र इस है, वहाँ तथाकथित बहुभाषा भाषी हिन्दी प्रदेश की सभी विशेषताएँ प्राप्त हुई हैं।

सबसे पहले विजातीय भाषा का व्यवहार। हिन्दी प्रदेश में अंग्रेजी का व्यवहार होता है, रूस में फ्रांसीसी भाषा का व्यवहार होता था। अब वहाँ नहीं होता क्योंकि समाजवाद की एक उपलब्धि विजातीय भाषा का प्रभाव समाप्त करना है। पूंजीवादी रूस में बीसवीं सदी के प्रथम चरण तक फ्रांसीसी भाषा को गौरव का स्थान प्राप्त था। भाषाई स्थिति का सम्बन्ध समाज-व्यवस्था से बड़ा गहरा है। जब हिन्दी प्रदेश में समाजवादी व्यवस्था कायम होगी, तब अंग्रेजी का यह गौरवपूर्ण स्थान भी समाप्त हो जाएगा। विजातीय भाषा का प्रभाव एक विरल विशेषता है क्योंकि इसका कारण किसी अन्य जाति का राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक प्रभाव है। विरल होने पर भी यह विशेषता बहुत से देशों में मिलती

है क्योंकि विश्वसाम्राज्यवादी व्यवस्था के अन्तर्गत एशिया और अफ्रीका के बीमियों देन इस तरह के प्रभाव में रहे हैं। इनमें यह भी सम्मिलित चाहिए कि हिन्दी प्रदेश की यह विशेषता धर्म्याई है जैसे कि वह रूस में अस्थाई सिद्ध हो चुकी है। एशिया के देशों में वियतनाम फ्रांस का उपनिवेश रह चुका है। वहाँ कभी फ्रांसीसी भाषा का वैसे ही व्यवहार होता था जैसे भारत में अंग्रेजी का होना है। अब वहाँ सर्वोपरि स्थान वियतनामी भाषा का है।

हिन्दी-उर्दू का भेद हिन्दी प्रदेश की अपनी विशेषता माना जाता है। रूस में विद्दिश भाषा का व्यवहार वैसे ही होता है जैसे वहाँ उर्दू का। यहूदी एक धर्म है, जाति नहीं है जैसे कि ईसाई एक धर्म है, जाति नहीं है। रूस में यहूदी हीब्रू की अपनी धर्मभाषा मानते हैं, हीब्रू मिश्रित भाषा को अपनी सात भाषा मानते हैं। इस भाषा में जर्मनभाषातत्त्व इसलिए हैं कि रूस के यहूदी वहाँ जर्मनी से पहुँचे हैं। जैसे आगरे का कोई मुसलमान कसकत्त में जाकर उर्दू बोले, वैसे ही जर्मनी के यहूदी रूस में जाकर हीब्रू मिश्रित जर्मन धर्मात् विद्दिश का व्यवहार करते हैं। न तो रूस में सभी यहूदी विद्दिश का व्यवहार करते हैं, न हिन्दी प्रदेश में सभी मुसलमान उर्दू का व्यवहार करते हैं। कुछ शहरो को छोड़कर गाँवों के मुसलमान, खासकर बिहार और मध्यप्रदेश के मुसलमान, हिन्दी या स्थानीय जनपदीय बोली का व्यवहार करते हैं। रूस के बाहर विद्दिश का व्यवहार बहुत कम होता है, यद्यपि ब्रिटेन और अमरीका में यहूदी भरे पड़े हैं। वैसे ही हिन्दी प्रदेश के बाहर, कश्मीर, बंगाल या सिन्ध में, धर्म के कारण हिन्दुओं से मुसलमानों की कोई अलग भाषा नहीं है। अतः हिन्दी प्रदेश की इस विशेषता को भी धर्म्याई मानना चाहिए।

अब रही परिनिष्ठित भाषा के साथ जनपदीय उपभाषाओं के व्यवहार की बात। यह एक व्यापक विशेषता है जो हर भाषा क्षेत्र में मिलती है। इसका कारण यह है कि जनपदीय का अन्वय खरम जाने पर जातीय प्रदेश निमित्त होता है, कोई एक जनपदीय भाषा जातीय भाषा बनती है और अन्य जनपदीय भाषाओं के तत्त्व अपने भीतर समेटती है। प्राधुनिक उद्योगधन्धा के विकास के साथ, साक्षरता और शिक्षाप्रसार के कारण, जनपदीय भाषाओं का व्यवहार निरन्तर कम होता जाता है परन्तु पूरी तरह समाप्त नहीं होता। परिनिष्ठित कृषी भाषा, की बोलियाँ पूँजीवादी व्यवस्था में भी, समाजवादी व्यवस्था में भी हैं। हिन्दी प्रदेश में अनेक जनपदीय भाषाओं में विपुल साहित्य-राशि है। ऐसा रूस में नहीं है पर इससे वहाँ जनपदीय भाषाओं का अस्तित्व अक्षिप्त नहीं होता। -

जनपदीय उपभाषाओं के अलावा परिनिष्ठित भाषा के ही बोली-रूप होते हैं। जनपदीय उपभाषाएँ सामन्ती व्यवस्था के युग की स्वतन्त्र भाषाएँ हैं, परिनिष्ठित भाषा के बोली-रूप उन स्वतन्त्र भाषाओं के अवशेष नहीं हैं। ये रूप जातीय भाषा पर जनपदीय उपभाषाओं अथवा अन्य जातीय भाषाओं का प्रभाव

पड़ने से बनते हैं। जनपदीय उपभाषाओं का मुख्य व्यवहार क्षेत्र गाँव होते हैं; परिनिष्ठित भाषा के मुख्य व्यवहार क्षेत्र शहर होते हैं। ऊपर दिन्नी, बम्बई-कलकत्ता आदि शहरों की जिस हिन्दी का जल्नेल है, उसमें यह तथ्य प्रमाणित होता है। परिनिष्ठित भाषा के बोली रूपों के व्यवहार के व्यापक सामाजिक कारण हैं। घट यह विशेषता चाहे रूसी हो, चाहे अंग्रेजी, चाहे तमिल हो, चाहे बंगला, सर्वत्र दिखाई देनी है।

अनेक भाषा-क्षेत्रों में विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों में किसी धर्म-भाषा का व्यवहार होता है अथवा ऐसी रिक्त भाषा का व्यवहार होता है जिसे लागू अपनी सांस्कृतिक विरासत से विशेष रूप में सम्बद्ध मानते हैं। हिन्दी प्रदेश में इस स्तर पर संस्कृत का व्यवहार होता है। रूस में एक धर्मभाषा का व्यवहार होता था जिसे पश्चिम के भाषा वैज्ञानिक 'चर्चस्लावोनिक्' कहते हैं। यह गिरजाघरों की पुरोहित-भाषा है जो अब ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों का स्रोत है। वास्तव में यह पुरानी बुल्गार भाषा है। वह रूसी से भिन्न है। आधुनिक रूस में उसका व्यवहार बहुत कम हो गया है किन्तु पुरानी धार्मिक रूढ़ियाँ मानने वाले लोग वहाँ अब भी हैं, इसलिए उसका थोड़ा बहुत व्यवहार वहाँ अब भी होता होगा। पहले होता था, इसमें संदेह नहीं। रूस में ईसाइयों के अनेक सम्प्रदाय हैं। इनमें एक ग्रीक ग्रीगोरीयन चर्च अथवा सनातनपन्थी यूनानी सम्प्रदाय है जो दायद ग्रीक भाषा का व्यवहार करता होगा। ईसाइयों के अलावा रूस में लाला मुसलमान हैं। इनमें काफी लोग अभी नमाज पढ़ते हैं और उनकी नमाज अरबी में ही होती है। यहूदियों के अपने उपासना-स्थान हैं। उनमें नि सन्देश हीब्रू का व्यवहार होता होगा। कुछ थोड़े मंदिर भी हैं। अवश्य ही ये लोग पालि भाषा में धर्मपद का पाठ करते होंगे। कुल मिलाकर धर्मभाषाओं या रिक्त भाषाओं की स्थिति रूस में वैसी ही है जैसी हिन्दी प्रदेश में। यह विशेषता सर्वत्र समान रूप से व्यापक नहीं है। इसका एक कारण यह है कि सामाजिक जीवन में धार्मिक रूढ़ियाँ का स्थान निरन्तर गौण होता जाता है। दूसरा कारण यह है कि अनेक देशों में समाज सुधारकों ने धार्मिक कार्यों में जातीय भाषा के व्यवहार पर खोर दिया और इस जातीय भाषा में पुरानी धर्मभाषा का स्थान ले लिया। धर्म से भिन्न अन्य सांस्कृतिक कार्यों में रिक्त भाषा का व्यवहार निरन्तर क्षीण होता गया है। कुल मिलाकर जातीय भाषा का स्थान सर्वोपरि होता है, अन्य सभी भाषाएँ गौण स्थान प्राप्त करती हैं। यही स्थिति हिन्दी प्रदेश की है।

जातीय भाषा के साथ विजातीय भाषा का व्यवहार केवल उच्चवर्गों और शिक्षित जनो में होता है जनसाधारण में नहीं। जातीय भाषा के साथ रिक्त भाषा या धर्म भाषा का व्यवहार पुरोहित वर्ग के लोग विशेष अवसरों पर ही करते हैं। इसका व्यवहार क्षेत्र विजातीय भाषा की तुलना में और भी संकुचित होता है। रिक्त भाषा या धर्मभाषा के कुछ तत्व जातीय भाषा में मिलाकर

उर्दू या पश्चिमी जैसी मिश्रित भाषा बनती है। इसे जातीय भाषा की एक बोली विशेष कह सकते हैं। इसका व्यवहार अधिकतर धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय करते हैं। जातीय गठन और विकास के साथ इसके व्यवहार का अल्पसंख्यक क्षेत्र क्रमशः जातीय भाषा के वृहत्तर व्यवहार क्षेत्र में विलीन हो जाता है।

जातीय भाषा के साथ जनपदीय उपभाषाओं का व्यवहार शहरी की अपेक्षा गाँवों में अधिक होता है। उक्त तीन कोटि की भाषाओं की तुलना में इनका व्यवहार क्षेत्र अधिक टिकाऊ और व्यापक होता है। साथ ही ये उपभाषाएँ जातीय भाषा को समृद्ध करने का साधन भी हैं। जातीय भाषा के परिनिष्ठित रूपों के साथ उसके बोली-रूपों का व्यवहार और भी टिकाऊ, और भी व्यापक होता है। ये बोली रूप जातीय भाषा के प्रसार के अनिवार्य परिणाम होते हैं।

हिन्दी प्रदेश में अनेक भाषाओं का प्रयोग इस प्रदेश की विलक्षणता नहीं है। ऐसा अल्पसंख्यक भी हुआ है और हो रहा है। मुख्य बात यह है कि हिन्दी के माध्यम से एक विशाल प्रदेश में भारत की एक महान् जाति सुगठित हो गई है और उसके धार्मिक सांस्कृतिक विकास को रोक रखना संभव नहीं है। बहु-भाषावाद की समस्या पर इसी परिप्रेक्ष्य में विचार करना उचित है। १९७७

परिशिष्ट-१

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और उन्नीसवीं सदी में हिन्दी-आन्दोलन

"हिन्दी नई बाल में बनी, सन् १८७३ ई०।"
इस नई बाल की हिन्दी ने एक ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति की।
उसने हिन्द प्रदेश की जनता को राजनीतिक और सांस्कृतिक जागरण की बाणी
नी।

गिलगाइस्ट और ग्रियर्सन आदि अंग्रेज विद्वानों की फँसाई हुई एक भ्रान्त
धारणा अब भी लोगों में मिल जाती है कि उर्दू से अरबी फारसी के शब्द निकाल-
कर और उनकी जगह सस्कृत शब्द डालकर इस भाषा का निर्माण हुआ।
भारतेन्दु का गद्य देखने से यह धारणा निर्मूल सिद्ध होती है। उनके निबन्धों
में हुज्जत, जमाना, बयान, सफर, मुर्द, बलम, रिवाज, तलाश, दरस्त, सबूत,
गरज आदि जैसे शब्द निहायत बेतकल्फ़ी से इस्तेमाल किये गए हैं। यही
हाल बालवृष्ण भट्ट, बालमुकुन्द गुप्त, राधाचरण गोस्वामी आदि लेखकों का
भी है। कुछ लेखक ऐसे जरूर थे जो प्रचलित अरबी फारसी के शब्द निकालकर
उनकी जगह सस्कृत-शब्दावली रखकर शुद्ध हिन्दी लिखने के पक्षपाती थे।
लेकिन भाषा की समस्या प्रचलित शब्दों की न थी।

समस्या यह थी कि जहाँ अप्रचलित शब्दों की जरूरत पड़े, यानी साधारण
बोलचाल से अलग जहाँ गैर-युनियादी शब्द-मण्डार की जरूरत पड़े, यहाँ अरबी-
फारसी से शब्द लिये जाएँ या सस्कृत में। बोलचाल की भाषा के आधार पर
जिस साहित्यिक उर्दू का विकास हुआ, उसका इमान गैर-युनियादी शब्द-
मण्डार के लिए सस्कृत के बदले अरबी फारसी की तरफ जाने का था। उर्दू
की भी दो धँलियाँ थी, एक यह जिसमें बोलचाल की हिन्दी के शब्द निश्चलकर
उनकी जगह भी अरबी-फारसी के शब्द डाले जाते थे, गैर युनियादी हिस्से में
तो उनकी भरमार रहती ही थी। दूसरी नैली यह थी जिसमें बोलचाल की
हिन्दी के शब्दों का बायबाट न किया जाता था और गैर युनियादी हिस्से में भी
अरबी-फारसी की बेजा भरमार न की जाती थी।
बोलचाल की भाषा एव ही थी, हिन्दी उर्दू का युनियादी शब्द-मण्डार एव

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और उन्नीसवीं सदी में हिन्दी प्राचीन / १०१

ही था। लेकिन साहित्यिक शैली का निर्माण उन लोगों के हाथों हुआ जो अरबी-फारसी के विद्वान् थे ही, संस्कृत के भी विद्वान् थे। इन लोगों ने गैर-बुनियादी शब्द-भण्डार के लिए अरबी-फारसी या संस्कृत का सहारा लिया।

यदि गैर-बुनियादी शब्द-भण्डार के लिए अरबी-फारसी का सहारा लेने की नीति हमारे जातीय विकास की ऐतिहासिक आवश्यकताएँ पूरी कर सकती तो 'नई हिन्दी' के चलन का सवाल न उठता, सवाल उठने पर भी उसमें सफलता न मिलती। कचहरियो, पुलिस विभाग आदि में उर्दू चालू थी। जनता का समर्थन मिलने पर उसका प्रचार इतना व्यापक हो जाता कि कोई भाषा-शैली उससे होड़ करने की जुरत न करती। लेकिन गैर-बुनियादी शब्द-भण्डार के लिए सिर्फ अरबी फारसी का सहारा लेने की नीति भारत की किसी भाषा में न अपनायी थी। कारण यह था कि यहाँ की भाषाओं का जो सम्बन्ध संस्कृत से था, वह अरबी-फारसी से न था। हिन्दी की क्रियाएँ—चलना, लिखना, हँसना, रोना, खाना, पीना, मरना, जीना, आदि आदि—संस्कृत की क्रियाएँ भी हैं। इस तरह अरबी-फारसी की क्रियाएँ बोलचाल की हिन्दी में बहुत कम हैं। इसलिए इस तरह की क्रियाओं से बननेवाले शब्द भी अरबी-फारसी की क्रियाओं से बननेवाले शब्दों की अपेक्षा बोलचाल की हिन्दी में कहीं ज्यादा हैं। बोलचाल की हिन्दी में तद्भवों की भरमार है। उतने तद्भव अरबी-फारसी से नहीं बने, यद्यपि बोलचाल की भाषा में आये हुए अरबी-फारसी के शब्दों का रूप और कभी-कभी अर्थ भी एक हद तक बदला है।

बोलचाल की हिन्दी की तरह भारत की अन्य भाषाओं में भी अरबी-फारसी के सैकड़ों शब्द घुल-मिल गए। इसका सबब यह नहीं था कि मुसलमानों की भाषा अरबी-फारसी थी और हिन्दुओं की भाषा संस्कृत, प्राकृत या अपभ्रंश थी। बाबर वगैरह की ज़बान दरअसल तुर्की थी। कुछ ईरानियों के अलावा उच्च वर्ग के मुसलमानों के घरों में भी फारसी न बोली जाती थी। लेकिन सैकड़ों साल तक फारसी उत्तर भारत की राजभाषा रही थी। सैकड़ों अरबी के शब्द फारसी के जरिये यहाँ आये। इसके अलावा शिक्षित मुसलमानों के लिए धर्मग्रन्थ की भाषा अरबी थी। बोलचाल की हिन्दी में फारसी शब्दों के घुलने-मिलने का मुख्य कारण फारसी का राजभाषा होना था।

फिर भी हिन्दी-भाषी प्रदेश की-सी समस्या कश्मीरी, बँगला, मराठी आदि भाषाओं में नहीं पैदा हुई। इसके कई कारण थे। राजभाषा फारसी के केन्द्र हिन्द प्रदेश ही में थे। अगर और दिल्ली मुगलों की राजधानी रह चुके थे। यहाँ के शिक्षित वर्ग में फारसी का प्रचार भारत के दूसरे नगरों और प्रान्तों के मुकाबले में ज्यादा था। १८३६ ई० तक यहाँ राजभाषा फारसी रही और उसके बाद कचहरियो, पुलिस विभाग आदि में जो भाषा चली, वह अरबी-फारसी शब्दों से लदी हुई थी।

अंग्रेजों ने यहाँ की सामन्तशाही को अपना मित्र और चाकर बनाया।

नवाबों के दरबार जन-संस्कृति के केन्द्र न थे। जनता से उनका भलगाव उनके सरक्षण में चलनेवाली भाषा-नीति पर भी पड़ा। सखनऊ, रामपुर, हैदराबाद के दरबार एक खास तरह की शैली और कविता के केन्द्र बन गये। अंग्रेजों ने दो लिपियों और दो शैलियों के चलन को प्रोत्साहन दिया और भाषा-सम्बन्धी विवाद उनकी 'फूट डालो और राज करो' नीति का बहरी हिस्सा बन गया। लेकिन यह समझना बहुत बड़ी भूल होगी कि समूचा उर्दू साहित्य सामन्ती संस्कृति में प्रभावित है। उर्दू का एक बहुत बड़ा हिस्सा सामन्त-विरोधी और राष्ट्रीय है। उससे हिन्दी के लेखक बहुत कुछ सीख सकते हैं और पिछले हिन्दी लेखकों ने बहुत कुछ सीखा है। उसमें बोलचाल की हिन्दी का बहुत ही सुन्दर और सँवारा हुआ रूप मिलता है।

भारतेन्दु के समय तक—और एक हद तक अब भी—शिक्षा पर पठितों और मीलवियों का इजारा था। इसका एक फल यह हुआ कि हिन्दी-उर्दू की दो लिपियों का चलन हुआ। इससे साहित्य के पाठक दो हिस्सों में बँट गये और अक्सर उन्हें पता न रहता था कि दूसरी लिपि में क्या लिखा जा रहा है। जनसाधारण की भाषागत एकता साहित्य की शैली पर अपना असर न डाल पाई। फिर भी लिपि-भेद से ही हिन्दी-उर्दू का भेद इस हद तक नहीं बढ़ा। जायसी के 'पद्यावत' के फारसी लिपि में लिखे जाने से वह उर्दू का ग्रन्थ नहीं हो गया। मूल प्रश्न गैर-बुनियादी शब्द-भण्डार का था। उन्नीसवीं सदी के अनेक उर्दू-लेखक अपनी भाषा को सरल करने का प्रयत्न कर रहे थे और उसमें अरबी-फारसी की अनावश्यक भरमार कम कर रहे थे। फिर भी ज़रूरत पड़ने पर बोलचाल की शब्दावली से बाहर के अरबी-फारसी का ही सहारा लेते थे।

भारतेन्दु ने कोई नयी भाषा नहीं चलाई। उन्होंने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया। उनके पक्ष में तीन बातें महत्वपूर्ण थीं। उनकी भाषा-सम्बन्धी नीति वही थी जो अवधी और ब्रज के पुराने हिन्दू-मुसलमान कवियों की थी। उर्दू के बड़े कवि—कुछ अपवाद छोड़कर—तुलसी, मूर, मीरा, रहीम, रसखान, झलम, शेख, पजनेस, जायसी, पद्याकर, भूषण आदि की परम्परा से प्रभावित थे। इस परम्परा और उसकी भाषानीति को भारतेन्दु ने अपनाया। यह भाषा-नीति यह थी कि उत्तम संस्कृत के मुकामसे वे सद्भव शब्दों का प्रयोग करना, बोलचाल के अरबी फारसी शब्दों का बहिष्कार न करना, गैर-बुनियादी शब्द-भण्डार के लिए संस्कृत का सहारा लेना। दूसरी बात उनके पक्ष में यह थी कि उन्होंने ग्रामीण या जनपदीय बोलियों का स्वभाव पहचाना और अपनी हिन्दी को गाँव के साधारण पढ़े लिखे लोगों के लिए सुलभ बनाने की कोशिश की। तीसरी बात उनके पक्ष में नागरी लिपि थी। सैंकड़ों साल तक फारसी के राजभाषा बने रहने पर भी नागरी का सोप न हुआ। गाँव के लोग ज्यादातर नागरी ही काम में लाते थे। इस लिपि के जरिये भारतेन्दु जनता के

उस तमाम हिस्से को बटोर सके जो उर्दू न जानता था या जिसकी जातीय आवश्यकताएँ उर्दू से पूरी न होती थी ।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में भाषा-सम्बन्धी बहस में हिस्सा लेनेवालों ने यह सब विकास-क्रम न समझा था । उर्दू के समर्थकों को हिन्दी प्रतिद्वन्द्वी के रूप में दिखाई दी । कुछ मूसलमान लेखकों को यह अपनी सस्कृति पर ही हमला दिखाई दिया । अंग्रेजों ने अपनी भाषा-नीति से बहस को बढ़ावा दिया और उसमें दोनों तरफ से ऐसी बातें कही गईं जो उचित न थीं । इसी बहस की गर्मी में भारतेन्दु ने 'उर्दू का स्यापा' लिखा था ।

हे हे उर्दू हाय हाय ! कहां सिधारी हाय हाय ॥

और भागे चलकर बालमुकुन्द गुप्त ने 'उर्दू को उत्तर' लिखा था ।

न बोधी बहुत जो में धबराइये,

सम्हलिये जरा होश में आइये ।

लेकिन उर्दू सिधारी नहीं । इसका कारण उसका बुनियादी शब्द-भण्डार था जो बोलचाल की हिन्दी का ही था । वह दूसरी लिपि के माध्यम से— दरबारी और दरबारी साहित्य के अलावा—साधारण जनता के एक हिस्से की सेवा करती रही । इसलिए प्रेमचन्द, पद्मसिंह शर्मा आदि लेखकों का मत था कि क्रमशः साहित्य में एक मिली-जुली शैली का विकास होगा और वह उर्दू को हटाकर या दबाकर न होगा बल्कि उससे बहुत कुछ लेकर होगा ।

भारतेन्दु ने बहस के दौरान कुछ तेज बातें उद्धृत लिखी, लेकिन वह न उर्दू से मफरत करते थे, न उर्दू के प्रचलित शब्दों का बहिष्कार करते थे । यही नहीं, वह उर्दू में मद्य-पद्य खुद भी लिखते थे । भारतेन्दु को जब ध्याख्यान देने के लिए बलिया बुलाया गया था, तब विज्ञापन में उन्हें 'शायरे मारुफ बुलबुले हिन्दुस्तान' कहा गया था । वाजिद अली धाह के शायर मिर्जा आबिद ने 'बागे आलम में मोतदिल है हवा' आदि उन पर कसीदा लिखकर भेजा था । श्री रामशंकर व्यास ने लिखा था कि उन्हें बजीर और अनीस का काव्य विशेष प्रिय था । १७ सितम्बर, १८७२ की 'कविवचन-मुघा' में एक दिलचस्प विज्ञापन छपा था । यह विज्ञापन उर्दू के साप्ताहिक पत्र 'कासिद' के बारे में था जिसे भारतेन्दु निकालनेवाले थे ।

“कासिद !

सातएँ दिन आवेगा ॥

नये हितकारी और विचित्र समाचार कहेंगा ॥ १

यह एक साप्ताहिक उर्दू पत्र निकलेंगा इसमें अनेक हित की, नये उद्गार की, साम्प्रत समयानुसार लोक वृद्धि की और अनेक शुभ समाचार की बातें

रहेंगी—यह पत्र बहुत उत्तम बढ-बढे पृष्ठों में स्वच्छ अक्षरों में छपेगा मूल्य—
१०) बापिक ।

हरिश्चन्द्र

उद्यमकर्ता ।"

भारतेन्दु ने उर्दू के प्रति द्वेषभाव होता तो वह 'कासिद' निकालने की बात कभी न सोचते ।

भारतेन्दु ने हिन्दी के माध्यम से जिस जातीय संगठन में योग दिया, उसमें अवध, ब्रज, मुन्देलखण्ड, भोजपुर आदि जनपदों की जनता शामिल थी । यदि महाप्रबुद्ध राहुल साहूत्यायन की यह स्थापना सच मानी जाय कि अवध, ब्रज, मुन्देलखण्ड, भोजपुरी बोलनेवाले अलग-अलग जानियों के लोग हैं, तो भारतेन्दु का यह काम इतिहास-विरोधी ठहरेगा । भारतेन्दु भोजपुरी क्षेत्र के निवासी थे । भोजपुरी जानते भी अच्छी तरह थे । लेकिन उन्होंने भोजपुरी में न लिखकर हिन्दी को अपना साहित्यिक माध्यम बनाया जैसे कि आगे प्रेमचन्द और प्रसाद ने किया । इतिहास-विरोधी काम भारतेन्दु का नहीं था, इतिहास-विरोधी स्थापना महाप्रबुद्ध राहुल और उन जैसे विचारकों को है । यद्यपि राहुलजी स्वयं हिन्दी के लेखक हैं—और अपना जीवनचरित उन्होंने भोजपुरी में लिखना उचित नहीं समझा—फिर भी वह हिन्दीभाषी जनता का एक प्रान्त बनाने की माँग करने के बदले बोलियों के व्यापार पर हिन्द प्रदेश के तरह टुकड़े करने का सुझाव पेश करते हैं । सन् १९५३ की 'भालोचना' (दिल्ली) में इस भाषण का उनका एक लेख छपा था । सोलहवीं सदी के आस पास ही व्यापार के प्रसार के साथ भोजपुरी आदि के क्षेत्रों में खड़ी बोली फैलने लगी थी । व्यापार के केन्द्रों में एक ही बोली बोलनेवाले लोग इकट्ठा हों, ऐसा नहीं होता । उद्योग-व्यापार और व्यापार महलों में विभिन्न बोलियाँ बोलनेवाले लोगों को बटोरते हैं और उनमें किसी एक बोली का व्यवहार 'शिष्ट' लोग करते हैं । बनारस आदि पूर्वी नगरों में खड़ी बोली व्यापारी वर्गों के साथ आई । २ अक्टूबर, १८७२ की 'कविवचन-सुधा' में भारतेन्दु का 'हिन्दी भाषा' नाम का निबन्ध छपा था । यह निबन्ध ऐतिहासिक महत्व का है । इसमें भारतेन्दु ने बनारस की बोलियों का अध्ययन किया है और यह दिखाया है कि शिष्टजनों की भाषा हिन्दी है ।

बनारस के लोगों की बोली के बारे में वह कहते हैं, "हमी बनारस में जो बनारस के पुर्ने कहाये हैं उनके घर में विचित्र-विचित्र बोनियाँ बोली जाती हैं जैसा पुरखियों की बोनी तो भाइला जाइला प्रसिद्ध ही है परन्तु यहाँ के पुराने निवासी कसरे लोग 'वाट' शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं जैसा 'भावत हूँ' के स्थान पर 'भावत बाटी', 'का करन होय' वा 'का करल' के स्थान पर 'का करत बाटय' वा 'बाटो' वा 'वाट' ।"

बनारस में इन बोणियों के एकत्र होने और उन सबके ऊपर हिन्दी के

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और उन्नीसवीं सदी में हिन्दी-प्रादेशिक / ३३३

चलन का कारण क्या है ? इसका कारण व्यापार का प्रसार, भौद्योगिक और व्यापारी केंद्रों का निर्माण, सामन्ती सम्बन्धों के भीतर पूँजीवादी सम्बन्धों का पनपना और विभिन्न बोलियाँ बोलनेवालों का जातीय गठन है । 'प्रेमजोगिनी' में भूपटिया 'मिसरो नहीं आए' कहता है लेकिन जलघरिया 'सुतल थोड़े रहली' और 'कधा छिला जाला' कहता है । और शिष्ट लोग खड़ी बोली का व्यवहार करते हैं ।

बनारस की विभिन्न बोलियों का उत्सृष्ट करने के बाद भारतेन्दु 'हिन्दी भाषा' वाले निबन्ध में कहते हैं, "जो हो यह तो सिद्धान्त है कि जो यहाँ के शिष्ट लोग बोलते हैं यह परदेसी भाषा है और यहाँ पश्चिम से आई है ।"

पछाँह से यह बोली किसके साथ आई, इस प्रश्न का उत्तर भारतेन्दु के इस वाक्य से मिलता है . "अब पश्चिमोत्तर देश में घर में बोलने की भाषा कौन है यह निश्चय नहीं होता क्योंकि दिल्ली प्रान्त के वा अन्य नगरों में भी खानियों वा पछाँही घरवालों वा और पछाँही जातियों के अतिरिक्त घर में हिन्दी कोई नहीं बोलते वरन् यहाँ तो कोस-कोस पर भाषा बदलती है ।" दिल्ली के अलावा अन्य नगरों में भी खड़ी बोली खानियों, पछाँही घरवालों आदि के जरिये फैली जिनका मुख्य पेशा व्यापार था । आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि मुगल-साम्राज्य के ध्वंस के बाद "दिल्ली के आस-पास के प्रदेशों की हिन्दू व्यापारी जानियाँ (अगरवाले, खत्री आदि) जीविका के लिए सखनऊ, फैजाबाद, प्रयाग, काशी, पटना आदि पूरबी शहरों में फैलने लगी । उनके साथ-साथ उनकी बोलचाल की भाषा खड़ी बोली भी लगी चलती थी ।"

वास्तव में यह क्रम मुगल-साम्राज्य के ध्वंस से पहले ही शुरू हो चुका था । शुक्लजी ने व्यापारियों द्वारा खड़ी बोली के प्रसार का तथ्य बहुत सही दिया है । इन व्यापारियों में मुसलमान भी थे । इसके सिवा सोलहवीं से उन्नीसवीं सदी तक एक बोली बोलनेवालों का दूसरी बोली के क्षेत्र में जाकर बसने का क्रम बराबर चलता रहा । अवध के जो मुसलमान मिथिला में जाकर बस गए और वहाँ एक नये ढंग की हिन्दुस्तानी का व्यवहार करने लगे, वह कार्य भी इसी क्रम का अन्तर्गत हुआ ।

जो लोग समझते हैं कि खड़ी बोली केवल सम्य व्यवहार या साहित्य की भाषा है, उन्हें इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि दिल्ली के अलावा अन्य नगरों में वह बहुत से लोगों की मातृभाषा थी और है । इस सिलसिले में भारतेन्दु ने लिखा था, "ऐसे ही पश्चिमोत्तर देश में अनेक भाषा है पर उनमें ऐसे नगर थोड़े हैं जिनमें अन्ध-बुद्ध-बन्धिता सब खड़ी भाषा बोलते हो अतएव यद्यपि काशी में पूर्वं प्रदेशों की मातृभाषा वा घर के बोलचाल की भाषा हिन्दी है यह तो हम नहीं कह सकते पर हाँ यह कह सकते हैं कि इसी पश्चिमोत्तर

देश में कई नगर ऐसे हैं जहाँ यही खड़ी बोली मातृभाषा है।"

इस बोलचाल की भाषा में हिन्दी उर्दू का भेद न था। यह विभिन्न बोलियाँ बोलनेवाली जनता की नई जातीय भाषा थी जो उसे एक सूत्र में बाँध रही थी। गिलग्राइस्ट से ही इस बात का सूत्रपात हो चुका था कि मुसलमानों की शिष्ट बोली घोर होगी और हिन्दुओं की घोर। लेकिन भारतेन्दु बोलचाल की भाषा में भेद न मानते थे। हिन्दी-उर्दू का भेद भरबी फारसी या संस्कृत से शब्द लेने के कारण था। ८ सितम्बर, १८७३ की 'कविवचन सुधा' में हिन्दी-उर्दू के बारे में एक लेख छपा था जिसका अंग्रेजी में शीर्षक है, "Hindi Versus Urdu, Philologically Hindi और उर्दू।" इसमें हिन्दी उर्दू के भेद के बारे में यह स्थापना है, "हिन्दी और उर्दू में अन्तर क्या है हम बिना संकोच के उत्तर देते हैं कि भाषाओं में कुछ अन्तर नहीं है क्योंकि व्याकरण की विभक्तियाँ और नियम दोनों के एक हैं पर इतना ही अन्तर है कि हिन्दी में जिसके लिए हिन्दी शब्द नहीं मिलता वहाँ संस्कृत शब्द काम में आते हैं और उर्दू में सहज हिन्दी शब्द होने पर भी और जहाँ शब्द नहीं मिलते हैं वहाँ तो अवश्य ही भरबी और फारसी के शब्द लिखे जाते हैं, यही दोनों में अन्तर है।"

भारतेन्दु ने हिन्दी के नई चाल में ढलने का वर्ष १८७३ लिखा था। वास्तव में १८६८ में ही 'विद्यासुन्दर' के प्रकाशन और कविवचन सुधा के निकलने से हरिश्चन्द्री हिन्दी का चलन शुरू हो गया था। लेकिन हरिश्चन्द्र ने न तो कोई नई भाषा चलाई थी, न व्याकरण आदि में ही कोई क्रांतिकारी परिवर्तन किया था। उनकी हिन्दी की विशेषता उनकी शैली थी। 'विद्यासुन्दर' में 'समाचार लेने के हेतु', 'यह पौन हमारी प्राणधारी त्रिभुवनमोहनी का अग्न स्वर्ण करके आता है', 'पुरस्कार के हेतु', 'बस अब बहुत भई', 'सब काम सिद्ध भया', 'बिना कुछ भए', ऐसी दशा शत्रु की होय', 'और जो वह सन्पासी हमी होय', 'जो यह बात सच होय' आदि प्रयोग मिलते हैं। 'कर्पूरमञ्जरी' में "महाराज, कहिये और क्या होय?" 'मुद्राराक्षस' में "जो कोई सुननेवाला और समझने-वाला होय।" 'वैदिकी हिसा' में "बड़ा आनन्द भया"। 'सरय हरिश्चन्द्र' में "बेटा, साँफ़ भई", "ठीक है, लेव सोना"। 'विपश्य विपभीषणम्' में "तो क्या हुआ है, होय।" 'वैष्णवता और भारतवर्ष' में "स्नान आदि भी यहीं तक रहें", "भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है" में "खराबी जो बीच में भई है।"

भाषा के परिवार की दृष्टि से भारतेन्दु का काम युगान्तरकारी नहीं कहा जा सकता। उनके पहले—उर्दू गद्य को छोड़ भी दें तो—रामप्रसाद निरञ्जी, सदानुसलाल, राजा सधर्मामह आदि समर्थ हिन्दी-लेखक हो चुके थे। जल्लूजी सागरी भाषा की तुलना में भारतेन्दु की भाषा युगान्तरकारी मालूम हो सकती है लेकिन हिन्दी गद्य के विकास में जल्लूजीलाल का जो महत्व प्रियसंग ने घोषित किया है, वह इतिहास में सिद्ध नहीं होता।

बोली को माध्यम बनाने के लिए एक सम्बन्ध मंथन चलता । 'हिन्दी भाषा' वाले निबन्ध में उन्होंने अपना यह मत प्रकट किया है कि "पश्चिमोत्तर देश की कविता की भाषा ब्रजभाषा है यह निर्णीत हो चुकी है ।" अपने अनुभव के बारे में लिखा है - "मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊँ पर वह मेरे चिन्तानुसार नहीं बनी, इससे यह निश्चय होता है कि ब्रजभाषा में ही कविता करना उत्तम होता है और इसी से सब कविता ब्रजभाषा में ही उत्तम होती हैं ।" खड़ी बोली में कविता मोठी क्यों नहीं होती, इसका "सबसे बड़ा कारण यह जान पड़ा कि इसमें क्रिया इत्यादि में प्रायः दीर्घ मात्रा होती है इससे कविता अच्छी नहीं बनती ।"

वास्तव में खड़ी बोली की कविता में मिठास के अभाव के लिए कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है । कारण कवियों में अभ्यास की कमी ही हो सकता है । ब्रजभाषा में पद्य का एक बना-बनाया रास्ता था, कविता की अपनी शब्दावली थी । खड़ी बोली में यह सब गड़ना था ।

खड़ी बोली बनारस और दूसरे पूर्वी जिलों में शिष्ट लोगो की बोलचाल की भाषा के रूप में फैल रही थी । इसलिए भारतेंदु जैसे कवि का उससे प्रभावित न होना असम्भव था । उनकी एक तरह की शैली वह है जिसमें ब्रजभाषा खड़ी बोली के साथ घुलती मिलती दिखाई देती है । जैसे 'प्रेमतरंग' के इस गीत में—

किन वे रूठाया मेरा प्यार ।

कहाँ गया, क्यों छोड़ गया मोहि, तोड़ गया क्यों प्यार ।

या

नशीली छाँखोवालो सोए रहो अभी है बड़ी रात ।

मगरी रैन मेरे सग जागत रहे करत रगीली बात ॥

दूसरी तरह की शैली उनकी लावनियों की है जिसमें प्रचलित फारसी के शब्द भी आते हैं और जिसकी भाषा धामतीर से शुद्ध खड़ी बोली होती है । सूफी कवियों के रंग में भारतेंदु खड़ी बोली की कितनी सरस कविता कर सकते थे, इसका सबूत इन पक्तियों में मिलेगा—

श्री राधा माधव जुगल चरन रस का अपने को मस्त बना ।

पी प्रेम पियाला भर भर कर कुछ इस में का भी देख मजा ॥

यह वह मैं है जिसके पीने से और ध्यान छूट जाता है ।

अपने में भी दिलवर में फिर कुछ भेद नहीं दिखलाता है ॥

इसके मुरूर से मस्त हरेक अपने को नजर बस आता है ।

फिर और हवस रहती न जरा कुछ ऐमा मजा दिखाता है ॥

टुक मान मेरा कहना दिल को इस मँखाने की तर्फ भुका ।

पी प्रेम पियाला भर भर कर कुछ इस में का भी देख मजा ॥

लावनीबाजो ने खड़ी बोली कविता की एक सजीव परम्परा कायम की थी ।

उनके लिए दीर्घ ह्रस्व मात्राओं से खड़ी बोली ने सीठे, बड़े बनाने का सवाल न था। उनके यहाँ खड़ी बोली एक बहुत ही खबीला माध्यम बन गई थी और भारतेन्दु ने जब उस परम्परा का सहारा लिया, तब उन्होंने खड़ी बोली में बहुत ही सरस कविता की। यह सही है कि यह कविता पत प्रसाद की शैली से बहुत दूर है लेकिन वह जन-काव्य की परम्परा के बहुत निकट है।

जनसाधारण के कवियों ने पद्य में खड़ी बोली की परम्परा बहुत दिन से चला रखी थी। उन्हें यह विदवास दिलाने की जरूरत न थी कि ब्रजभाषा छोड़कर खड़ी बोली में लिखने से साहित्य और जल्दी उन्नति करेगा। कवियों के सामने प्रश्न यह था कि वे इस सजीव परम्परा से नाता जोड़ेंगे या नहीं। भारतेन्दु के तालूके में खड़ी बोली के गीतों आदि का घाना यह साबित करता है कि जनता में खड़ी बोली के पद्य प्रचलित थे। 'बँदिकी हिला' में राजा गाता है: 'पीले अबधू के मतवाले प्याना प्रेम हरी रस का रे।' 'सत्य हरिश्चन्द्र' में धर्म कहता है—

हम चौधरी होम सरदार ! भ्रमल हमारा दोनों पार ।
और पिशाचों-डाकिनियों का भीत—

हम सजसे बजके बजके चलेंगे चमकेंगे चम चम चम ।
'भारत-दुर्दशा' में भालस्य का गीत है—

दुनिया में हाथ-पैर हिलाना नहीं अच्छा ।
'अधेर-नगरी' में घासीराम का 'बने जोर गरम' खड़ी बोली की अपनी चना-जोर शैली में है। ऐसे ही चूरनवाले का लटका है—

चूरन भजनबंद का आगी । जिसको खाते कृष्णपुरारी ।
मेरा पापक है पचलोना । जिसको खाता श्याममलोना ॥

भाम जनता में खड़ी बोली के पद्यों के चलन का मतलब यह था कि कविता में भी खड़ी बोली की माध्यम बनाने की ऐतिहासिक आवश्यकता पैदा हो गई थी।

भारतेन्दु की उपर्युक्त शैलियों के अलावा उनकी उर्दू शैली की रचनाएँ हैं। 'रसा' नाम की वह गायत्री करते थे और आमतौर पर उनकी भाषा सरल उर्दू होती है। यथा—

दिल मेरा ने गया दिया करने ।
बेवफा हो गया वफा करने ॥

शेस्तो बीन मेरी तुबंत पर,
रो रहा है 'रमा रमा' करने ।

भारतेन्दु की गमूकी खड़ी बोली की कविता परियान में कम नहीं है। उन्होंने खड़ी बोली की सरस भोजप्रिय कविता से सहृदयता पाई थी। लेकिन ब्रजभाषा में त्रिम पुरानी शैली पर वह शृंगार-रस के पद्य बनाते थे, उस शैली

भाषा के परिष्कार की दृष्टि से भारतेन्दु के गद्य में बहुत सी खामियाँ थीं, लेकिन उनका युगान्तरकारी काम यह था कि उन्होंने बोलचाल की भाषा की प्रकृति पहचानी, उसकी मिठास को साहित्य में जगह दी, उस भाषा को सभी तरह के साहित्य का समर्थ माध्यम बनाया। यह समझते थे कि गद्य के लिए ब्रजभाषा ही उपयुक्त है, फिर भी उन्होंने स्वयं खड़ी बोली में कम गद्य नहीं रचा जो उनके ब्रजभाषा में लिखे हुए गद्य में बढ़कर है। जनता में खड़ी बोली बहिष्कार की अपनी एक परम्परा कायम हो चुकी थी। भारतेन्दु ने इसे पहचाना और उसके अनुकूल गद्य भी रचे। वास्तव में खड़ी बोली (हिन्दी) में गद्यरचना के लिए ऐतिहासिक आवश्यकता अभी की पैदा हो चुकी थी।

भारतेन्दु ने उन लोगो का विरोध किया जो यह दावा करते थे कि हिन्दी में विज्ञान की किताबें लिखी ही नहीं जा सकती या हिन्दी में विज्ञान की शिक्षा न देनी चाहिए। उनके सामने शिक्षा और विज्ञान का उद्देश्य समूचे देश की उन्नति करना था और यह काम देशी भाषाओं द्वारा ही हो सकता था।

इस तरह भारतेन्दु ने हिन्दी को नई चाल में ही नहीं ढाला वरन् उसके बीमुखी विकास के लिए सघर्ष भी किया।

(१९५३)

गांधीजी और भाषा-समस्या

अपने राजनीतिक जीवन के आरम्भ से ही गांधीजी ने भाषा-समस्या पर सोचना और लिखना आरम्भ कर दिया था। सत्य, अहिंसा, स्वराज्य, सर्वोद्यम—किसी भी अन्य विषय पर उनके विचार आज के लिए इतने उपादेय नहीं हैं, जितने भाषा-समस्या पर। अंग्रेजी, भारतीय भाषाओं, राष्ट्रभाषा हिन्दी और हिन्दी-उर्दू की समस्या पर उन्होंने जितनी बातें कही हैं, वे बहुत ही मूल्यवान हैं। किसी राजनीतिक नेता ने इन समस्याओं पर इतनी गहराई से नहीं सोचा, किसी पार्टी और उसके नेताओं ने भाषा-समस्या के सैद्धान्तिक समाधान को अपनी निरपेक्षता की दायेंबाही में इस तरह धमकी जामा नहीं पहनाया, जैसे गांधीजी ने। उनकी नीति के मूल सूत्र छोड़ देने से यह समस्या दिन-पर-दिन खलबली जा रही है। जो लोग उसे उलझा रहे हैं, वे गांधीजी की जय बोलते हुए, गांधीवाद की जय बोलते हुए, गांधीवाद की दुहाई देते हुए ऐसा कर रहे हैं।

गांधीजी का भाषा नीति का पहला सूत्र है, भाषा-समस्या का समाधान जनता के हित में हो।

नेता अंग्रेजी में भाषण दें, जनता समझे नहीं। ऐसे नेता न तो देश में कोई बड़ा परिवर्तन कर सकते थे, न उनकी राजनीति जनता की राजनीति बन सकती थी। जो नेता अंग्रेजी में ही बोलने की जिद करते थे और हिन्दी सीखने से इन्कार करते थे, उनके लिए गांधीजी ने मई '२७ में लिखा था, "वास्तव में ये अंग्रेजी में बोलनेवाले नेता हैं जो आम जनता में हमारा काम जल्दी भागे बढ़ने नहीं देते। वे हिन्दी सीखने से इन्कार करते हैं जबकि हिन्दी द्विविध प्रदेश में भी तीन महीने के अन्दर सीखी जा सकती है, अगर सीखनेवाले इसके लिए तीन घंटे हर रोज दें।" (पोस्टमॉन नेशनल संग्रेज, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, पृ० २३)।

गांधीजी ने नेताओं का अंग्रेजी बोलना छुड़ाया। उनके सबके फलस्वरूप कम-से-कम अब अपने प्रदेशों में वे जनता के सामने अंग्रेजी में ~~बोलना नहीं~~ बोलते।

लेकिन उनका राजनीतिक-सांस्कृतिक कार्य भव भी बहुत कुछ अंग्रेजी में होता है। भव 'राज्यसत्ता कांग्रेसी नेताओं के हाथ में है। यह राज्यसत्ता, उसे चलाने-वाला नौकरशाही वर्ग किसके लिए है ? स्वराज्य किसके लिए है ? सन् '३१ में गांधीजी ने लिखा था, "यदि स्वराज्य अंग्रेजी-पढ़े भारतवासियों का है और केवल उनके लिए है, तो सम्पर्क भाषा अवश्य अंग्रेजी होगी। यदि वह करोड़ों भूखे लोगों, करोड़ों निरक्षर लोगों, निरक्षर स्त्रियों, सताये हुए भ्रष्टों के लिए है तो सम्पर्क भाषा केवल हिन्दी हो सकती है।" (उप० पृ० ३१)

इसलिए यदि जनतन्त्र जनता का है और जनता के लिए है तो उसमें अंग्रेजी के लिए जगह न होनी चाहिए। अंग्रेजी को अपनानेवाले वे लोग हैं जो भाषा-समस्या पर जनता के हितों को ध्यान में रखकर विचार नहीं करते। उन्होंने लिखा था, 'कुछ लोग जो अपने दिमाग से जनता की बात एकदम निहाल देते हैं, वे यही नहीं कहते कि अंग्रेजी भी सम्पर्क भाषा हो सकती है, वे कहते हैं कि अंग्रेजी ही एकमात्र सम्पर्क भाषा हो सकती है।' (उप० पृ० ३०)

जो राजनीतिज्ञ जनता-जनता सबसे ज्यादा चिन्ताते हैं, वे अपनी राजनीतिक कार्यवाही में इसी जनता की उपेक्षा करते हैं। गांधीजी मार्क्सवादी-लेनिनवादी नहीं थे लेकिन लेनिन की भाषा सम्बन्धी नीति का सारस्वत उन्होंने ग्रहण कर लिया था। उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अंग्रेजी के व्यवहार की आलोचना करते हुए सन् '३७ में लिखा था, उनके लेख अंग्रेजी न जाननेवालों के लिए गुप्त खजाना (सील्ड बुक) हैं। लेकिन इस का हाल देखिए। वहाँ क्रान्ति से पहले ही तमाम पाठ्य पुस्तकें (वैज्ञानिक पुस्तकों समेत) रूसी में छपती थी। दरअसल इसी बात ने लेनिन की क्रान्ति के लिए मार्ग तैयार किया। हम ग्राम जनता से सच्चा सम्पर्क तब तक कायम नहीं कर सकते, जब तक कांग्रेस यह फैसला नहीं करती कि उसका सारा विचार-विमर्श हिन्दी में होगा और उसके प्रान्तीय सगठनों का काम प्रान्तीय भाषाओं में होगा।" (उप० पृ० ५३)

विभिन्न प्रदेशों के बीच विदेशी भाषा को अपनी सम्पर्क-भाषा बनाकर कोई भी देश जन-क्रान्ति नहीं कर सकता। क्रान्ति का अर्थ मुट्ठी भर घादमियों द्वारा खूनखराबी करना नहीं होता। क्रान्ति का अर्थ है, समाज-व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाना। इस तरह के परिवर्तन ग्राम जनता के सहयोग के बिना कभी नहीं लाये जा सकते। जो देश पराधीन हैं, वे ग्राम जनता के संघर्ष के बिना स्वाधीन नहीं हो सकते, और जो देश स्वाधीन हैं, वे ग्राम जनता की दृढ़ एकता और समर्थ राजनीतिक कार्यवाही के बिना अपनी स्वाधीनता की रक्षा नहीं कर सकते।

कुछ लोग समझते हैं कि सम्पर्क भाषा तो मन्त्रियों, नेताओं, बड़े बड़े अफसरों वर्ग के लिए ही जरूरी है। ग्राम जनता अपनी प्रादेशिक भाषाएँ बोलती ही है; उसे सम्पर्क भाषा से क्या लेना-देना है ? ऐसा सोचनेवाले अपने को शासक और जनता को शासित समझते हैं। उनके लिए नौकरशाह

जनता के नोकर नहीं हैं, वे उससे बादशाह हैं। जिन पार्टियों के हाथ में राज्य-सत्ता नहीं है जिनके नेता निवृत्त अविप्य में मन्त्री बनने के उम्मीदवार हैं, वे भी जनता के अपने को जनता का मेवर नहीं हुकमरान समझने लगे हैं। इसलिए वे अंग्रेजी को सम्पर्क भाषा बनाकर चैन से अपनी गद्दियों पर बैठे हुए हैं।

इन सबसे भिन्न गांधीजी का मत था कि सम्पर्क नेताओं में ही नहीं, विभिन्न प्रदेशों की आम जनता में होना चाहिए। उन्होंने लिखा था, "आप और हम चाहते हैं कि करोड़ों आदमी अन्तर्प्रान्तीय सम्पर्क कायम करें। स्पष्ट है कि अंग्रेजी के द्वारा, कई पीढ़ियाँ गुजर जाने पर भी वे परस्पर सम्पर्क स्थापित न कर सकेंगे।" (१९२७, ३५० पृ० ४८)। यदि हमारे देश के जनवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी-लेनिनवादी राजनीतिज्ञ गांधीजी की इस बात को मानें कि करोड़ों जनता को आपस में राष्ट्रीय स्तर पर सम्पर्क कायम करना है, तो वे सबसे आगे बढ़कर हिन्दी प्रचार के काम में हिस्सा बँटाएँ, वे अंग्रेजी की छतरी के नीचे बैठकर दूर से हिन्दी की नुक्ताचीनी न करते रहें।

देशव्यापी सम्पर्क जनता का, स्वराज्य करोड़ों अनिश्चित और निर्धन लोगों के लिए, नेता और जनता के बीच सबसे बड़ी दीवार अंग्रेजी—यह हुआ गांधीजी की भाषानीति का पहला सूत्र।

गांधीजी के लिए भाषा-समस्या कोई छुट्टा भाषा विज्ञान की समस्या नहीं थी। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन के सन्दर्भ में ही उस पर विचार किया था। अंग्रेज़ों ने भारतीय जनता को गुलाम बनाने के साथ उसकी भाषाओं का दमन किया उस पर अंग्रेज़ी लादी। अंग्रेज़ों का चलन राजनीतिक सांस्कृतिक पराधीनता का अंग था, उसे सम्पर्क भाषा के पद से हटाना राजनीतिक-सांस्कृतिक स्वाधीनता के लिए आवश्यक था। अंग्रेज़ी की जगह भारतीय भाषाओं का व्यवहार राष्ट्रीय आत्मसम्मान की रक्षा का प्रश्न था।

उनकी भाषा नीति का दूसरा सूत्र है राष्ट्रीय आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अंग्रेज़ी का प्रभाव ख़त्म करो।

१९०६ में गांधीजी ने लिखा था, 'क्या वे लोग जो अपनी मातृभाषा का अपमान करते हैं, वही देश का भला कर सकते हैं? मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता कि गुजरात के लोग अपनी मातृभाषा छोड़कर अन्य कोई भाषा अपना लें। ऐसा ही तो यह करने में ज़रा भी प्रतिशयोक्ति न होगी कि जो लोग अपनी भाषा छोड़ देते हैं वे देशद्रोही हैं और जनता के प्रति विश्वासघात करते हैं।' (३५० पृ० १८६)

जा लोग अंग्रेज़ी में उपन्यास और कहानियाँ लिखकर अन्तर्राष्ट्रीय श्रद्धा अर्जित करते रहे हैं, वे गांधीजी ने इन बातों पर गम्भीरता से विचार करें।

गांधीजी ने गुजराती भाषी निश्चित जनता में मातृभाषा का प्रेम जगाया, अंग्रेज़ी बोलने पर उनकी सानत मलामत की। गुजरात के नवीन साहित्यिक अग्रगण्य में उनका योगदान अनुपम है। दिसम्बर, १९१४ में सद्रामपुर, मूरत

के जैन विद्यार्थियों ने गांधीजी को अपने पुस्तकालय का उद्घाटन करने के लिए बुलाया। गांधीजी के बोलने की बात सुनकर वहाँ बड़ा जन-समुदाय एकत्र हो गया। एक विद्यार्थी ने अंग्रेजी में भाषण किया। दूसरा खड़ा हुआ, उसने अंग्रेजी में निबन्ध पढ़ा। गांधीजी ने इन अंग्रेजी बोलनेवालों को लक्ष्य करके कहा, “यदि अंग्रेजी जाननेवाले मुट्ठीभर लोगो को हम देश मान लें तो कहना होगा कि देश शब्द का अर्थ नहीं समझा।” उन्होंने उन लोगो को फटकारा जो कहते थे कि ये मातृभाषा में अपने विचार अच्छी तरह प्रकट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, “जो युवक यह कहते हैं कि हम अपने विचार मातृभाषा द्वारा नहीं प्रकट कर सकते, उनमें मैं यही निवेदन करूँगा कि आप मातृभाषा के लिए भार-रूप है। मातृभाषा की अपूर्णता दूर करने के बदले उसका अन्यास करना—उसमें हाथ ही धो बैठना—किसी सच्चे सपूत की शोभादायक नहीं।”

यह फैसला अभी तक बना हुआ है कि जिनके पास रहने की कुछ नहीं है वे भी करण कठ संक्षमा याचना करत हुए जनता न कहते हैं, हम हिन्दी में अपने विचार पलुएटली प्रकट नहीं कर सकते। मातृभाषा की अपूर्णता दूर करना इनके मन की बात नहीं, वे अंग्रेजी के भारवाही बनकर मातृभाषा और मातृ-भूमि के लिए केवल भार-रूप है।

गांधीजी गुजराती के, समस्त भारतीय भाषाओं के सम्मान के लिए लड़े। उनके इस संघर्ष का आदर करनेवालों में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी भी थे। उन्होंने गांधीजी का उपयुक्त भाषण मार्च, १९१६ की ‘सरस्वती’ में छपा था। भाषण को हिन्दी में अनुवादित करने भेजा था गुजराती राजन श्री मणिभाई व्यास ने।

दिसम्बर, १९१६ में गांधीजी ने देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा के प्रचार पर लखनऊ में भाषण दिया। आठ-दस हजार श्रोताओं के बीच उन्होंने यह भाषण हिन्दी में दिया। अपने हिन्दी सीखने और हिन्दी के लिए अपमानित होने के बारे में उन्होंने ये मर्मस्पर्शी शब्द कहे थे—

“जिन प्रान्तों में हिन्दी का प्रचार कम है वहाँ हिन्दी पढ़नेवालों की बड़ी कमी है। मैं स्वयं हिन्दी सीखना चाहता था। पर अहमदाबाद में कोई हिन्दी-ज्ञाता शिक्षक न मिला। मिला बेवारा एक गुजराती भाषाभाषी, जिसने पन्द्रह-बीस वर्ष काशी में रहकर टूटी-फूटी हिन्दी सीखी थी। उसी से मैंने हिन्दी सीखी। सम्मेलन यदि अन्य भाषा-भाषी प्रान्तों में आदमी भेजे तो बहुत से लोग हिन्दी सीख जाएँ।”

हिन्दी की दरिद्रता के भीत गाते अंग्रेजी-प्रेमी भारतवासी थकते नहीं हैं। पता नहीं इनकी संख्या पहले ज्यादा थी या अब है। गांधीजी ने इन लोगों को लक्ष्य करके कहा था, “लोग कहते हैं कि हिन्दी में कुछ नहीं है—हिन्दी साहित्य खोखला है—अतएव अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता। कभी-कभी तो अंग्रेजी न जानने के कारण लोगों को वृथा ही बहुत कष्ट उठाना पड़ता है।

यह मैं भी मानता हूँ। यहाँ तक कि मुझ-जैसे लोगों को, हिन्दी का व्यवहार करने के कारण—हिन्दी बोलने के कारण—रेलवे इत्यादि में घबके भी खाने पड़ते हैं। अंग्रेज़ों से हिन्दी कितना ही पीछे क्यों न हो, हमें उसका गौरव बढ़ाना ही पड़ेगा।”

राष्ट्र के जो नेता आज हवाई जहाज़ों और ‘एयर कंडीशन्ड’ गाड़ियों में सफर करते हुए अंग्रेज़ों को सम्पर्क भाषा का गौरव प्रदान करते हैं, क्या वे कभी याद करते हैं कि अंग्रेज़ी रेलों के यात्री मोहनदास करमचन्द गांधी को हिन्दी बोलने के कारण घबके खाने पड़े थे? वे राष्ट्रपति की जय बोलते हैं, राष्ट्रपिता के नाम पर जनता को अघ्यात्मवाद के उपदेश देते हैं, राष्ट्र के नाम पर सन्देश प्रसारित करते हैं, उस भाषा में जिसका व्यवहार गांधीजी राष्ट्र-सम्मान के प्रतिकूल समझते थे।

गांधीजी न अंग्रेज़ों के सामने, उच्चतम अंग्रेज़ पदाधिकारियों के सामने, महा-प्रतापी ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि वाइसराय के सामने भारतीय भाषाओं के गौरव की रक्षा की। उसी भाषण में उन्होंने कहा था, “सरकारी कमिशनरों में अंग्रेज़ों की पूछ है—उसी का विशेष आदर है। लोग कहते हैं कि वाइसराय इत्यादि अंग्रेज़ों के अतिरिक्त और कोई भाषा नहीं समझते। अतएव अंग्रेज़ों का ही उपयोग करना आवश्यक है। पर मैं कहता हूँ कि यदि मैं बोलना जानता हूँ और मेरे कथन में कोई बात ऐसी है जिससे वाइसराय लाभ उठा सकें तो अवश्य मेरी बातें, हिन्दी में होने पर भी, सुनें। आपको जरा दृढ़ता और मनोयोग से काम लेना चाहिए। आत्मबलमय किए बिना कोई काम मिट नहीं होता।”

अब अंग्रेज़ वाइसराय नहीं हैं। लेकिन मनोबृत्ति वही है। अंग्रेज़ों बोलने में लोग गौरव का अनुभव करते हैं। इसमें राष्ट्रीय धारमसम्मान की भावना क्षीण होती है। अंग्रेज़ वाइसराय एक बार किसी को हिन्दी में बोलने की अनुमति भी दे दे लेकिन यदि स्वाधीन भारत की लोकसभा में कोई मंत्री हिन्दी में बोलें तो महाक्रान्तिकारी कामरेड गोपानन ‘वाक आउट’ कर देते हैं। गांधीजी ने केवल दूमरों को वाइसराय के सामने हिन्दी बोलने का उपदेश न दिया था; उन्होंने साहम से अपने उपदेश के अनुसार आचरण भी किया था।

१९३१ में मधुबन भारत के चेम्बर ऑफ कॉमर्स का अधिवेशन कराची में हुआ। उसमें विभिन्न प्रान्तों के सेठ और व्यापारी मौजूद थे। अंग्रेज़ भी थे। किन्तु गांधीजी ने अपना भाषण हिन्दी में दिया। इस भाषण में उन्होंने बताया कि सन् ‘१८ में वाइसराय के सामने वह हिन्दी में बोले थे। सन् ‘१८! अंग्रेज़ वाइसराय! अंग्रेज़ और अंग्रेज़ियत का वह आतंक! उन बातोंवरण में वाइसराय के सामने हिन्दी बोलने खड़े हुए कर्मवीर गायी।

कराचीवाले भाषण में उन्होंने कहा था, “मेरे अंग्रेज़ मित्र मुझे क्षमा करेंगे कि जो कुछ मुझे कहना है, वह मैं राष्ट्रभाषा में कहूँगा। इस अवसर पर मुझे उस समय की याद आती है जो यही १९१८ में मुनाई गई थी। बहुत बहस-मुवाहसे के

वाद जब मैं इस सभा में आने को तैयार हुआ तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे हिन्दी या हिन्दुस्तानी में बोलने की अनुमति दी जाय। मैं जानता हूँ कि इसके लिए प्रार्थना करना जरूरी नहीं था, फिर भी सम्यता का तकाजा था; वरना वाइसराय को बुरा लगता। उन्होंने तुरन्त मुझे अनुमति दे दी और तब से इस मामले में मेरी हिम्मत और खुल गई है। और आज फिर मैं उसी जगह अपने उस अमल को दोहराने जा रहा हूँ। और इस चेम्बर के सदस्यों से मैं विनम्र कहूँगा कि आपका यह कर्तव्य है कि अपना सारा काम राष्ट्रभाषा में करें। इस सगठन में आपको अपनी जनता से ही वास्ता पड़ता है। देश का आतावरण भी इस समय ऐसा है कि उसका प्रभाव आप पर भी जरूर पड़ेगा।” (उप० पृ० २४)

आज किसी अखिल भारतीय सगठन में लोगों से कहा जाय कि अपना काम राष्ट्रभाषा में कीजिए तो बहुत से देशभक्त कह उठेंगे—हम पर हिन्दी लादी जा रही है। उन पर अंग्रेजी पहले से लदी हुई है, यह वे भूल जाते हैं। अंग्रेजी के लिए स्वेच्छा, हिन्दी के लिए अनिच्छा—यह है उनकी देशभक्ति।

५ जुलाई, १९२८ के ‘यश इंडिया’ में गांधीजी ने अंग्रेजी के प्रभुत्व से होनेवाली देश की हानि के बारे में लिखा था, हजारों नवयुवक अपना कीमती समय इस विदेशी भाषा को सीखने में नष्ट करने हैं जब कि उनके दैनिक जीवन में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, अंग्रेजी सीखने में समय लगाते हुए वे मातृभाषा की उपेक्षा करते हैं, वे इस अल्पविश्वास के शिकार होते हैं कि ऊँचे दर्जे का विचार अंग्रेजी ही में प्रकट किए जा सकते हैं, अंग्रेजी के सादे जाने से राष्ट्र की शक्ति सूख गई है, विद्यार्थियों की धारु क्षीण हो गई है, ग्राम जनता से वे दूर जा पड़े हैं, शिक्षा पाना बड़े खर्च का काम हो गया है। ‘यदि यही सिलसिला जारी रहा तो बहुत सम्भव है कि राष्ट्र की आत्मा का नाश हो जाय।’

और सब तरह की हानि तो होती ही है, खर्च ज्यादा होता है, उन्नत कम होती है, मातृभाषा की उपेक्षा होती है, गांधीजी के लिए सबसे बड़ा खतरा यह था कि अंग्रेजी का प्रभुत्व राष्ट्र की आत्मा का नाश कर देगा। वह ऐसा क्यों सोचते थे? इसलिए सोचते थे कि वह स्वाधीनता-आन्दोलन के सन्दर्भ में भाषा-समस्या पर विचार करते थे। उनके लिए प्रश्न यह नहीं था कि अंग्रेजी विश्व-भाषा है और हिन्दी दलित है, प्रश्न यह था कि विदेशी भाषा के व्यवहार से राष्ट्रीय चरित्र पर असर क्या पड़ता है। इसलिए वह तुरन्त अंग्रेजी को विदा करने के पक्ष में थे। लेकिन जिसे गांधीजी राष्ट्र की आत्मा कहते थे, उसे अंग्रेजी-प्रेमी नेता मानसिक सर्वाणता कहते हैं।

गांधीजी अंग्रेजी पढ़ने के विरुद्ध नहीं थे। वह उसे वाणिज्य और कूटनीति की भाषा मानते थे। किन्तु वह यह सहन न कर सकते थे कि वह किसी भारतीय भाषा के हक मारे। वह बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अंग्रेजी का विश्व-महत्त्व ब्रिटिश साम्राज्य के कारण है। उन्होंने १९१८ में ही घोषित किया

था, "हमें ऐसी हालत पैदा कर देनी चाहिए कि हमारे राजनीतिक या सामा-
जिक सम्मेलनों में, कांग्रेस तथा प्रांतीय सभाओं आदि में अंग्रेजी का एक शब्द
भी न सुना जाय। अंग्रेजी का व्यवहार हमें पूरी तरह बन्द कर देना चाहिए।
अंग्रेजी ने विश्वभाषा की जगह पा ली है लेकिन यह इसलिए कि अंग्रेज सारी
दुनिया में फैल गए हैं और हर जगह अपने पैर उन्होंने जमा लिये हैं। जब
उनकी यह स्थिति नहीं रहेगी, तब अंग्रेजी का प्रसार भी संकुचित हो जाएगा।"
(७५० पृ० ६)

साम्राज्यवाद के पतन के साथ अंग्रेजी के प्रसार का दायरा कम हो गया
है। प्रायः भाषाएँ विश्व स्तर पर अंग्रेजी से स्पर्धा करती हैं। बोलनेवालों की
संख्या की दृष्टि से संसार की तीसरी भाषा हिन्दी भी विश्वभाषा के रूप में
अंग्रेजी का महत्व कम कर सकती है, विश्वभाषा के रूप में उससे स्पर्धा कर
सकती है यदि अंग्रेजी प्रेमी भारतवासी अपने देश को अंग्रेजी की गुलामी से
आजाद कर दें।

सन् '४७ से पहले हर देशभक्त मानता था कि अंग्रेजी का व्यवहार,
शिक्षा संस्थाओं, राजनीतिक संगठनों आदि में अंग्रेजी का चलन मानसिक
पराधीनता का लक्षण है। राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारक समझते थे
कि भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी हो जाएगी। ६ जून, १९६५ के 'न्यू एज'
(माप्ताहिक) में डी० सी० होम नाम के संपन्न ने लिखा है कि उन्नीसवीं
सदी के मध्य में जब भारत में नया औद्योगिक युग शुरू हो रहा था, तब भारत
के प्रमुख नागरिकों ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए खूब खो-
दार घाड़ोलन किया। राजा राममोहन राय ने इनका नेतृत्व किया।

दिलचस्प बात है कि जो भी अंग्रेजी को भारत की प्रमूख राष्ट्रभाषा
मानता है, वह किसी-न-किसी रूप में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की प्रगतिशील
भूमिका भी मानता है। डी० सी० होम के अनुसार "प्लासी के सत्तर वर्ष बाद,
यानी जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद की वस्तुगत रूप से प्रगतिशील भूमिका का एक
चक्कर पूरा हो गया था तब क्या हमसे यह पता नहीं चलना कि समाज में नये
कार्य पूरा करने की उत्सुकता पैदा हो गई थी?"

जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हर देश में समाजवाद अपने ढंग से आना है
और उसका अपना रूप होता है वैसे ही क्या अजब जो हर देश में पूंजीवाद
भी अपने ढंग से आए और उसका अपना रूप हो। भारतीय पूंजीवाद की
विशेषताएँ क्या हैं? इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह प्रारम्भ से ही
अंग्रेजी बोलता रहा है। आखिर देश की एकता तो कायम रखनी ही थी, यहाँ
संस्कृत राष्ट्रभाषा बन न सकती थी। प्रादेशिक भाषाएँ बोलियाँ थीं नहीं कि
वे किसी एक राष्ट्रभाषा के नीचे दब जाती। द्विदि और संस्कृत भाषा-परिवारों
का भेद अलग। अंग्रेजी के बिना भारतीय पूंजीवाद कौन-सी भाषा बोलता?
इसलिए जिन लोगों ने लाठ मँवाले के लिए रास्ता साफ किया, जिन्होंने मँका

की भाषानीति का समर्थन किया, वे सब प्रगतिशील थे ! जिन्होंने अंग्रेजी का विरोध किया, वे सब दक्षिणानूसी और प्रतिक्रियावादी थे !

संस्कृत और द्रविड परिवारों में ऐसी भयानक शत्रुता है तो मलयालम, तेलुगु आदि भाषाओं में संस्कृत के इतने शब्द कैसे पहुँच गए ? द्रविड देश के शंकराचार्य ने संस्कृत में अपने विचार क्यों प्रकट किए ? क्या उस समय तक कोई द्रविड भाषा उत्पन्न ही न हुई थी ? वह तमिल वहाँ थी जो प्राचीनता में समक्ष नहीं जाती है ?

वास्तव में यहाँ तमिल भी थी, अनेक द्रविड और गैर द्रविड भाषाएँ भी थीं। फिर भी शिक्षितजन संस्कृत का व्यवहार करते थे क्योंकि सामन्ती व्यवस्था के बावजूद, डी० सी० होम सम्प्रदाय की अपेक्षा उनमें राष्ट्रीयता का बोध ज्यादा था।

जनता के दृष्टिगोचर सन मोचन पर आज के गुमराह प्रगतिशील विचारकों को पूँजीवाद और समाजवाद दोनों के विकास के लिए अंग्रेजी आवश्यक दिखाई देती है।

श्री मोहनकुमार मगलम ने भारत का भाषा-संकट नामक पुस्तक में लिखा है, 'हम यह याद किये बिना नहीं रह सकते कि महान् राजा राममोहन राम उस दिन का स्वप्न देखते थे, जब भारत की भाषाएँ रंगमंच से हट जाएँगी और अंग्रेजी यहाँ की करोड़ों जनता की सामान्य भाषा हो जाएगी।' (पृ० ४)

लार्ड मैकाले और इन महान् समाज सुधारकों का सम्बन्ध इस प्रकार है, "इस तरह इन प्रारम्भिक समाज सुधारकों ने भी अंग्रेजी को उठाने और भारतीय भाषाओं का विकास रोकने में लार्ड मैकाले के प्रयत्न में मदद दी।" (पृ० ५)

भारत की भाषाओं और संस्कृति की हालत उस समय क्या थी ? "भारत और पूर्व की संस्कृति अधिक प्राचीन थी परन्तु इस समय वह ठहराव की हालत में (स्टैगनेंट) थी। वह पश्चिम के शक्तिशाली सांस्कृतिक उभार के सम्पर्क में आई।"

भले ही डोली, मैथ्यू आर्नेल्ड, वेल्स आदि लेखक भारतीय संस्कृति से प्रभावित रहे हों, श्री मोहनकुमार मगलम के लिए यहाँ की संस्कृति गतिरुद्ध ही थी। इसलिए आज राजभाषा के पद के लिए तमिल को योग्य बनाना उन्हें हिमालय पहाड़ उठाने जैसा लगता है। (उप० पृ० ६८)

होम और मोहन कुमारमगलम दोनों का मत है कि भारत में संस्कृत के बाद कोई भी सम्पर्क भाषा नहीं थी। इसलिए अंग्रेजी सम्पर्क भाषा के रूप में स्वाधीनता-प्राप्ति के पहले भी जरूरी थी और आज भी जरूरी है। भारतीय इतिहास के ये विरोधज्ञ भूल जाते हैं कि अंग्रेजों का राज कायम होने से पहले यहाँ सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का प्रचार और प्रसार सर्वत्र था। इसीलिए अंग्रेजों ने अपने अफसरों के लिए हिन्दुस्तानी का ज्ञान अनिवार्य कर दिया था।

दिल्ली के असिस्टेंट रेजिडेंट मेटकाफ ने २६ अगस्त, १८०६ को हिन्दुस्तानी

वे अपने शिक्षक गिलक्रिस्ट के नाम एक पत्र में लिखा था, "भारत के जिस भाग में भी मुझे काम करना पड़ा है, कलकत्ता से लेकर लाहौर तक, कुमाऊँ के पहाड़ों से नमदा तक, ब्रकमनो, मराठो, राजपूतो, जाटो, सिखो और उन प्रदेशों के सभी कबीलो में जहाँ मैंने भाया की है, मैंने उस भाया का ग्राम व्यवहार देखा है जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी थी। अपने अनुभव से और दूसरों से सुनी हुई बातों के बल पर मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक या आवा से मिथु के मुहाने तक इस विश्वास से यात्रा करने की हिम्मत कर सकता हूँ कि मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हिन्दुस्तानी बोल बोलें होंगे।" (जे० बी० गिलक्रिस्ट, ए बार्बुलरो, हिन्दुस्तानी एण्ड इग्निटा, इग्निज एण्ड हिन्दुस्तानी, एकिनवरा में उद्धृत)

राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए मैमोरेण्डम पेश किया, होम-सम्प्रदाय को यह तो दिखाई देता है लेकिन जिस भाया को कश्मीर में कन्याकुमारी तक भारत की करोड़ों जनता अपनी सम्पर्क भाया बना रही थी, वह उन्हें बहुत आँखें गड़ाकर देखने पर भी नहीं दिखाई देती।

गांधीजी न लाहं मैकाले के रोब में थे, न राजा राममोहन राय के। उन्होंने सन् '२० में लिखा था, "हम अपने विचार में अपने राष्ट्रीय जीवन में प्रादेशिक भायाभा (वनीक्युमस) को उनका उचित स्थान दे रहे हैं। भाग्य राजा राममोहन राय की हम भविष्यवाणी का साथ नहीं दे रहा कि भारत एक दिन अंग्रेजी भाषी देश हो जाएगा। लेकिन उन महान् समाज-सुधारक का भूत अब भी कुछ लोग पर सवार है। कुछ प्रमिद्ध आदमी बहुत जल्दी यह पंमता दे देते हैं कि राष्ट्र की सम्पर्क भाया अंग्रेजी होगी।" (थॉट्स ऑन नेशनल लैंग्वेज, पृ० १७)

गांधीजी का सम्बन्ध भी भारतीय पूँजीवाद के विकास से रहा है। उनके स्वदेशी आन्दोलन में भारतीय पूँजीपतियों को अपने उद्योग-धन्धे विकसित करने में सहायता मिली। बिड़ला जैसे उद्योगपति गांधीजी के नज़दीकी लोगों में थे। होम महाशय को सन् बीस के बाद का पूँजीवादी विकास नहीं दिखाई देता क्योंकि तब अंग्रेजी का विराध और भारतीय भायाभा का समर्थन होने लगा था।

गांधीजी को ज़रूर मैकाले-भक्तों से बराबर साबका पड़ा होगा। ये लोग सीधे मैकाले का नाम न लेकर राजा राममोहन राय की दुहाई देते रहे होंगे। इसीलिए राममोहन राय का नाम अक्सर उनके लेखों में आता है। सन् २१ में उन्होंने इस बात पर दुःख प्रकट किया था कि अंग्रेजी ने प्रांतीय भायाभा की जगह ले ली है। उन्होंने कहा था कि राजा राममोहन राय और भी बड़े समाज-सुधारक हात यदि उन्हें अंग्रेजी में साबने और उसी में अपने विचार प्रकट करने की अस्वाभाविक क्रिया न करनी पड़ती। (उप० पृ० २०१)

अंग्रेजा न आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका आदि

भरसक वहाँ की भाषाओं का नाश किया। लाखों नीग्रोजन अपनी भाषाएँ छोड़कर—गुलाम बनाए जाकर—अंग्रेजी-भाषी हो गए। भारतीय जनता ने १८५७ में अंग्रेजों को इस जन-घाती, भाषा घाती नीति पर चलने का मजा चला दिया। सन् १८५७ से पहले भी महाराष्ट्र के शिक्षा-शास्त्रियों ने जमकर मँकाले की भाषा नीति का विरोध किया। वहाँ के समाज-सुधारक डी० सी० होम एण्ड कम्पनी को नहीं दिखाई देते। 'दिये लोभ चसमा चखनि लघु पुनि बडो दिखाय।' अंग्रेजियत के चश्मे से अंग्रेजी परस्त तो बहुत बड़े समाज-सुधारक मालूम होते हैं, अंग्रेजी के विरोधी इतने छोटे हो जाते हैं कि उनके अस्तित्व का उल्लेख भी आवश्यक नहीं होता।

गांधीजी ने राजा राममोहन राय के साथ लोकमान्य तिलक का नाम भी लिया था और कहा था कि यदि उनकी शिक्षा-दीक्षा कम अस्वाभाविक व्यवस्था में हुई होती तो जनता पर उनका प्रभाव और भी गहरा पड़ा होता।

लोकमान्य तिलक मराठी के समर्थ लेखक थे। वह भारतीय भाषाओं का स्थान अंग्रेजी को देने के पक्ष में नहीं थे। इसके अलावा राजा राममोहन राय के विपरीत वह हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानत थे। कानपुर में जनता ने उनका स्वागत किया तो उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया कि वह हिन्दी में भाषण नहीं कर सकते। "यद्यपि मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिन्दी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। मैं हिन्दी समझ सकता हूँ और टूटी फूटी बोल भी सकता हूँ, व्याख्यान नहीं दे सकता।" ('सरस्वती', फरवरी, १९१७)

इस विचार को अमली रूप देने के लिए उन्होंने 'केसरी' का एक हिस्सा हिन्दी में प्रकाशित करना शुरू कर दिया था।

लोकमान्य तिलक जैसे समाज सुधारक होम-जैसे अंग्रेजी प्रेमियों की दृष्टि से अशुभल रहते हैं।

स्वाधीनता प्राप्ति के साल भर पहले गांधीजी ने उस दिमागी गुलामी की निन्दा की थी जो अंग्रेजी को अपनी राजभाषा बनाने के लिए नेताओं को मजबूर करती है। मोक्षियन सच भी मिमांश देते हुए उन्होंने लिखा था, "हम ने अपनी सारी वैज्ञानिक प्रगति अंग्रेजी के बिना ही की है। यह हमारी दिमागी गुलामी है जो हम कहते हैं कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता। मैं इस पराजयवादी मत को कभी स्वीकार नहीं कर सकता।" (उप० पृ० २०१)

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद गांधीजी ने २१ सितम्बर, १९४७ के 'हरिजन' में 'दिमागी बाहिनी' की निन्दा की जिसमें प्रेरित होकर अफमर और नेता कहते थे कि शिक्षा और धामन में अंग्रेजी ही चलेगी।

गांधीजी ने अपने राजनीतिक जीवन के आरम्भ में लेकर भारत के स्वाधीन होन के बाद तक, अपने जीवन की साखिरी घड़ियों तक अंग्रेजी का विरोध किया, अंग्रेजी के ऊपर निर्भर रहन की आदत को राष्ट्र के लिए हानिकार

बताया, अंग्रेजी की हिमायत को राष्ट्रीय चरित्र के लिए घातक बताया। जो लोग अंग्रेजी कायम रखकर भाषा-समस्या का समाधान खोजते रहे हैं, उनमें राष्ट्रीय धारममम्मान की कमी है।

राष्ट्रभाषा की समस्या राष्ट्रीय चेतना के आधार पर ही हल हो सकती है। जो लोग भाषा-समस्या को साम्राज्य-विरोधी सघर्ष के मन्दर्म से ग्रन्थग हटाकर हल करना चाहते हैं, वे समस्या को बराबर उमझाते जाएंगे, उसे मुलभाना उनके लिए सम्भव न होगा। यह गांधीजी का दूसरा सूत्र हुआ।

गांधीजी का तीसरा सूत्र है—भारतीय जनता की धमनी राष्ट्रभाषा हिन्दी है।

यदि राजनीतिज्ञ जनता के व्यवहार को देखें, इस बात को समझें कि अंग्रेजी न जाननेवाले साधारण जनो को भी परस्पर सम्पर्क के लिए एक सामान्य भाषा की जरूरत होती है, तो उन्हें यह दिखाई देने लगे कि जनता के अन्तर्प्रार्थित सम्पर्क की भाषा कौन-सी है। महा-राष्ट्र-गुजरात पंजाब के लोग आपस में हिन्दी को सम्पर्क भाषा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसे बहुत से लोग मानते हैं। सवाल है दक्षिण भारत का। क्या वहाँ के साधारण लोग भी हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में अपनाते हैं?

गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका के अपने इस अनुभव का उल्लेख किया था कि वहाँ तमिल और तेलुगु बोलनेवाले लोग परस्पर सम्पर्क के लिए हिन्दी काम में लाते हैं। जो कार्य वे दक्षिण अफ्रीका में करते थे, उस वे दक्षिण भारत में भी प्रबल्य करते रहे होंगे। वास्तव में तमिल-तेलुगु-भाषियों को उत्तर भारत से सम्पर्क कायम करने के लिए ही हिन्दी की जरूरत नहीं होती, उन्हें आपस में सम्पर्क-भाषा के लिए भी जरूरत हिन्दी की होती है।

एक मित्र ने अद्यमान से मुझे वहाँ की भाषा-स्थिति के बारे में यह लिखा है, "अधिकतर वहाँ बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड और मलयालम बोली जाती है। आपस में व्यवहार की भाषा हिन्दी है जो 'हम बोलता है, आप करना माँगता है' पद्धति से बोली जाती है। हिन्दी ही राष्ट्रभाषा है यहाँ स्वतः सिद्ध हो जाता है। तमिल तेलुगु से हिन्दी में ही बात कर पाता है। इसी प्रकार अन्य भाषा-भाषी।"

दक्षिण भारत में गांधीजी का अनुभव ऐसा ही था, "यह कहना सही नहीं है कि मद्रास में अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलता। मैंने अपने सारे कामों के लिए वहाँ सफलतापूर्वक हिन्दी का व्यवहार किया है। मैंने रेल में मद्रासी मुसाफिरों को दूसरों से हिन्दी में बातें करते सुना है।" (उप० पृ० ६)

सी० एफ० एण्ड्रूज का अनुभव भी यही था। उनकी मातृभाषा अंग्रेजी थी लेकिन उन्हें हिन्दी बोलने में उतना कष्ट न होता था जितना राज्यसभा या लोकसभा के कुछ भारतीय सदस्यों को। 'द टू इंडिया (१९३६) पुस्तक में उन्होंने लिखा था, "कल एक व्यक्ति मुझसे मिलने आया था, उसने जब मैंने

अंग्रेजी में बातचीत करने की कोशिश की तो उसने कहा, 'कृपा करके हिन्दुस्तानी में बातचीत कीजिए।' और जब मैं उस भाषा में बोला तो वह मेरी बात आसानी से समझ गया।"

राजनीतिज्ञों को उत्तर-दक्षिण में सम्पर्क के लिए नई भाषा गढ़ना नहीं है, वह भाषा जनता में पहले से प्रचलित है, उसे केवल सरकारी स्तर पर सम्पर्क-भाषा के रूप में स्वीकार करना है। जहाँ तक बंगाल का सम्बन्ध है, वहाँ की भाषा हिन्दी के बहुत ही नजदीक है। इस नजदीकीपन के भलावा कलकत्ता की लगभग आधी आबादी हिन्दुस्तानी है। इस आबादी में ज्यादातर लोग मेहनत-मजदूरी करके गुजर करनेवाले हैं। उनके मालिकों का उनसे हिन्दी में ही बात करनी होती है। गांधीजी ने लिखा था कि "उत्तर भारत का जो भ्रष्टा वर्ग के सेठ के यहाँ दरबानगरी करता है, वह गुजगानी नहीं बोलता, उसका मालिक सेठ ही मजदूर होकर उससे टूटी-फूटी हिन्दी में बातचीत करता है" (उप० पृ० ६)। यही स्थिति बंगाल की है। वहाँ न जाने कितने 'हिन्दुस्तानी' दरबान का काम करते रहे हैं। उनके मालिक उनसे टूटी-फूटी हिन्दी में ही बातें करने को बाध्य हुए हैं।

डॉ० सुनीतिकुमार बटर्जी ने पहले हिन्दी इसी तरह के लोगों से सीखी थी। "कलकत्ता में अपने वचन में ही लेखक ने हाट गल्लारी में तथा घर के बिहारी नौकरों से बंगाल में प्रयुक्त 'बाजार हिन्दी' कहलाना पाया भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था।" (भारतीय ग्राम्य भाषा और हिन्दी, पृ० २४५)। यद्यपि डॉ० सुनीतिकुमार भाषा को धर्म में और धर्म का सङ्घटित से जोड़कर यह नतीजा निकालते हैं कि 'हिन्दी के संस्कृत उपादान को श्रमण कम करने की प्रवृत्ति भारतीय परम्परा एवं भारतीय सङ्घटित पर प्रत्यक्ष आघात-मा है" (उप० पृ० २३८), फिर भी वह मानते हैं कि "हिन्दी (हिन्दुस्तानी) के साठे चौबीस करोड़ बोलने या समझनेवालों में से लगभग बीस करोड़ हिन्दुस्तानी का यही महज रूप बोलते हैं" (उप० पृ० २०६), मोनवी, मुंशी और मुल्ला लोग "फारसी भरी उर्दू का निर्माण एवं बढान करते रहे। उसी प्रकार पंडित लोग तथा ग्रन्थ लेखक लोग संस्कृत भरी हिन्दी का निर्माण करते रहे। परन्तु साधारण जनो का हिन्दुस्तानी के विषय में एक ही रुख रहा, इनमें पश्चिमी पंजाब से लगाकर पूर्वी बंगाल तक के हिन्दू मुसलमान सभी थे। वे अब भी, साधारण जीवन में अपने-अपने-अपने भाषावाला से बातचीत करना चाहते हैं तो प्रचलित हिन्दुस्तानी का ही व्यवहार करते हैं।" (उप० पृ० २०६)

पश्चिमी पंजाब से पूर्वी बंगाल तक, जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जन-सम्पर्क की भाषा बोलचाल की हिन्दी है। व्याकरण के अनुसार शुद्ध रूप में, संस्कृत शब्दों से सजाकर जनता इसे नहीं बोलती। उसके स्थानीय भेद हैं जैसे ब्रिटेन, अमेरिका और आस्ट्रेलिया की अंग्रेजी में भेद हैं। बोलचाल की हिन्दी बंगाल में भी समझी जाती है और जनता के व्यवहार में आती है। फिर भी

बंगाल में हिन्दी का तीव्र विरोध है, सभी लोगो में नहीं किन्तु मध्यवर्ग और पढ़े-लिखे लोगो में है इसमें कोई सन्देह नहीं।

गांधीजी ने सन् २१ में 'यंग इंडिया' में लिखा था कि बंगाल के लोग अपने पूर्वाग्रह के कारण भारत की और कोई भाषा सीखना नहीं चाहते (याँट्स ऑन नेशनल लैंग्वेज, पृ० १६)। हिन्दी-प्रचार के काम में बंगाली विद्वानों ने महत्वपूर्ण योग दिया है। हिन्दी के समर्थकों में डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी जैसे भाषाविद् रहे हैं। उन्होंने भारतीय भाषाओं के लिए—विशेषकर बंगला और हिन्दी के लिए—बहुत काम किया है। आज वह हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के विरुद्ध अंग्रेजी का समर्थन करते हैं, इससे उनका पहले किया हुआ काम निरर्थक नहीं हो जाता। उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करना धर्म है। उनसे पहले बकिमचन्द्र चटर्जी के समय में 'बगदर्शन' पत्र में लिखा था, "हिन्दी भाषा साहाय्ये भारतवर्षे विभिन्न प्रदेशे मध्य जाहारा ऐक्यवन्धन स्थापन करिते पारिवेन ताहाराईप्रकृत भारतवन्धु नामे अभिहित हइवार योग्य।" (बालमुकुन्द गुप्त द्वारा उद्धृत, बालमुकुन्द गुप्त निबन्धावली, कलकत्ता, पृ० १५६)

फिर भी बंगाल में ऐसे बुद्धिजीवी बहुतायत से हैं जो किसी भी भारतीय भाषा को सीखना अपने लिए हेठी की बात समझते हैं। डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी ने ही लिखा है, "कोई भी महाराष्ट्रीय या बंगाली व्यक्ति इस बात का अनुभव नहीं करता कि अपनी मातृभाषा की अपेक्षा नागरी हिन्दी या उर्दू के माध्यम द्वारा उच्चतर सृष्टि की प्राप्ति हा सकती है, बाज़ाफ़ हिन्दी का तो प्रश्न ही दूर है।" (भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी, पृ० २१५)

इसी तरह तमिलनाडु के श्री मोहनकुमार मगलम न यह राय जाहिर की है कि "स्वाधीनता-प्राप्ति के समय हिन्दी शायद सबसे कम विकसित भाषा थी।" (भारत का भाषा-मकट, पृ० ३१)। दाव्य में शायद उन्होंने मालीनतावश लगा दिया है, वरना हिन्दी का पिछड़ी हुई भाषा कहना प्रत्येक भारतवासी का नावैधानिक अधिकार है।

तमिलनाडु और बंगाल के अंग्रेजी प्रेमी बुद्धिजीवियों को एक विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति ध्यान में रखनी चाहिए। किसी समय प्रसन्न, उड़ीसा, बिहार आदि प्रदेश समुक्त बंगाल के अन्तर्गत थे। इसी प्रकार केरल और आंध्र तमिलनाडु के भाग जुड़े हुए थे। इन बड़े बड़े प्रान्तों में तमिल और बंगाली बुद्धिजीवी अंग्रेजी के कारण सरकारी नौकरियाँ पाते थे, अफसर बनकर दूसरों पर हुकूम करते थे, बकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि के पेशों में इन्हीं का बोलबाला था। मद्रास प्रेसीडेन्सी टूट गई, रह गया तमिलनाडु। उड़ीसा, प्रसन्न और बिहार अलग हो गए, रह गया विभाजित बंगाल। प्रसन्न में बंगालियों और प्रसन्नियों के बीच दंगे हुए। पौरो कारणों के अलावा दंगों के पीछे दोनों जातियों के बीच पुराना सनातन भी काम कर रहा था। तमिलनाडु और आंध्र के शिक्षितजनों में उससे

कार्यवाही की भाषा हिन्दी होनी चाहिए ।

यह बात देखने में बहुत साधारण मालूम होती है लेकिन वास्तव में है सबसे महत्वपूर्ण । भारत की राजनीतिक पाटियाँ भाषा-समस्या पर प्रस्ताव करके दूसरी को सिलवाती रही हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए । वे स्वयं अंग्रेजी हटाने के लिए क्या करने जा रही हैं, इसकी सूचना वे दूसरों को कम देती हैं । आप कल्पना कीजिए, यदि कांग्रेस का सारा राजकाज हिन्दी में हुमा करता तो क्या हुकूमत की बागडोर सँभालते ही अंग्रेजी हटाने में कांग्रेसी नेताओं को साल-भर से ज्यादा देर लगती ? ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट नेता जो पहले कांग्रेस के ही सदस्य थे, स्वाधीनता-प्राप्ति के दो साल पहले तक जो कांग्रेस में थे, क्या उससे प्रलग होने पर अपने यहाँ भी हिन्दी का व्यवहार न करते ? यदि ये विभिन्न पार्टियों के नेता अंग्रेजी के बिना अपना काम चलाने के आदी होते, तो क्या संविधान सभा में हिन्दी अंग्रेजी को लेकर इतनी बहस होती ? क्या संविधान सभा हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने के बाद पन्द्रह साल तक अंग्रेजी को चालू रखने का नियम बनाती ? क्या पन्द्रह साल बीतने से पहले अंग्रेजी को आगे भी सह-राजभाषा—असल में एकमात्र केन्द्रीय राजभाषा—बनाए रखने का कानून पास होता ? क्या पन्द्रह साल बीतने पर अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक कायम रखने की नीबट आती ?

इसमें आप समझ लीजिए कि कांग्रेस के अन्दर से अंग्रेजी हटाने का सघर्ष कितना महत्वपूर्ण था और यह सघर्ष चलाकर गांधीजी में कितनी बड़ी वीरता और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था । उन्हें अपने सघर्ष में सफलता नहीं मिली, इसमें यह भी समझ लीजिए कि अंग्रेजी के हिमायती इस देश में कितने शक्तिशाली हैं । गांधीजी को हिन्दू-मुस्लिम सम्प्रदायवाद खत्म करने में सफलता नहीं मिली, उन्हें देश का विभाजन रोकने में सफलता नहीं मिली, उन्हें सरकार और कांग्रेस के अन्दर से अंग्रेजी हटाने में सफलता नहीं मिली । इन तमाम असफलताओं को लिए हुए वह भारतीय प्रतिक्रियावाद की गोली खाकर सत्तार से चले गए । लेकिन रास्ता वही है जिस पर वह चले थे और उस रास्ते पर चलकर भारत एक दिन अवश्य विजयी होगा ।

दिसम्बर, १९१६ । तखनऊ में कांग्रेस का इकतीसवाँ अधिवेशन । गांधीजी हिन्दी में बोलना शुरू करते हैं । 'इम्पिज प्लीज' की आवाजें आती हैं । वह सदस्यों से कहते हैं—साल-भर में हिन्दी अवश्य सीख लीजिए । अगले साल की कांग्रेस में अंग्रेजी न चलनी चाहिए ।

१९१८ । वह कहते हैं, "हमारी राष्ट्रीय सस्थाओं में हिन्दी का ही व्यवहार होना चाहिए । कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस दिशा में बहुत-कुछ कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए । मैं चाहता हूँ कि यह सम्मेलन (हिन्दी साहित्य-सम्मेलन) कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के समय उसके सामने इस आशय का प्रस्ताव रखे ।" (वॉट्स, पृ० १२)

१९२१ वह बंगाल और दक्षिण के लोगों से खास तौर से कहते हैं, "मैं माया करता हूँ कि बंगाली और द्रविड़ लोग दूसरी कांग्रेस में (यानी कांग्रेस के अगले अधिवेशन में) काम लायक हिन्दी सीखकर आएँगे। हमारी यह महान् सभा जनता की शिक्षक तब तक नहीं बन सकती जब तक वह ऐसी भाषा में न बोले, जिसे ज्यादा-से-ज्यादा जनता समझती हो।" (उप०, पृ० १६)

१९२५. कांग्रेस का नया विधान धारा ३३—"जहाँ तक सम्भव होगा कांग्रेस की कार्यवाही हिन्दुस्तानी में होगी। यदि कोई हिन्दुस्तानी न बोल सके या जरूरत पड़े तो अंग्रेजी तथा प्रान्तीय भाषा का व्यवहार भी किया जा सकेगा।" इस प्रस्ताव में अंग्रेजी-प्रेमियों पर तगड़ी पाबन्दी न लगाई गई थी, फिर भी जो लोग हिन्दी-हिन्दुस्तानी का व्यवहार करना चाहें, उनके लिए छूट थी।

१९२८ : गांधीजी ने श्री विजयरामवाचारी के इस कथन का उल्लेख किया कि "हम लोग उत्सुकता से उस दिन की राह देख रहे हैं जब हम हिन्दुस्तानी पहले होंगे, मद्रासी या बंगाली बाद को। वह दिन जल्दी आएगा यदि मद्रासी, जो इस मामले में सबसे ज्यादा गायित हैं, बड़ी तादाद में हिन्दी सीखने लगे।" इसके बाद गांधीजी ने 'यंग इंडिया' में लिखा, "दक्षिण के लोगों को हिन्दी-प्रचार सभा के कारण हिन्दी सीखने के लिए हर तरह की सुविधा है। यदि भारत के लिए हमारे हृदय में वैसे ही मरुवा प्यार है जैसे अपने प्रान्तों के लिए है तो हम अवश्य ही जल्दी सीख लेंगे और हमें यह अपमानजनक दृश्य न देखना पड़ेगा कि अल्पमत भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यवाही—पूरी-की-पूरी नहीं तो अधिकांश—अंग्रेजी में हो रही है।" (उप०, पृ० २६)

१९३१ : "दक्षिण के लोग वादा कर चुके हैं कि अगले साल की कांग्रेस के लिए वे ऐसे प्रतिनिधि भेजेंगे जो हिन्दी में बोलेंगे और हिन्दी समझेंगे। हम अस्वाभाविक परिस्थितियों में न रहते होते तो दक्षिण के लोगों को हिन्दी सीखना बिल्कुल न मान्य होता, व्यर्थ की बात तो और भी नहीं।" (उप०, पृ० ३०)

१९३७ : मद्रास में हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के भब से उन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया कि सम्मेलन कांग्रेस में हिन्दी का व्यवहार करने की प्रार्थना करता है। उन्होंने प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा, "हम राष्ट्रभाषा हिन्दी के समर्थन में प्रस्ताव पास करते रहे और कांग्रेस पुरानी सीक पर चलती रहे तो हमारे काम की रचना बहुत धीमी होगी। इस प्रस्ताव में कांग्रेस से अपील की गई है कि वह अन्तर्प्रान्तीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का बहिष्कार करे। इसके अनुसार अंग्रेजी को न तो प्रान्तीय भाषा, न हिन्दी की जगह देनी चाहिए।" (उप०, पृ० ५२)

अन्त में अपने और अन्य गहनयोगियों के सुदीर्घ प्रयत्नों का परिणाम स्वरूप करते हुए उन्होंने अपने जीवन के अन्तिम चरण में लिखा-

गांधीजी

ने अपने बानपुर-अधिवेशन के प्रसिद्ध प्रस्ताव में इस अखिल भारतीय भाषा को हिन्दुस्तानी कहा। तब से कम से-कम कहने-भर को हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा हो गई है। कहने-भर को इसलिए कि कांग्रेसियों ने भी उस प्रस्ताव पर उस तरह अमल नहीं किया जैसे उन्हें करना चाहिए था। १९२० में जबकि यह बोधिशुरू हुई कि आम जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं का महत्व पहचाना जाय, साथ ही एक अखिल भारतीय सामान्य भाषा का महत्व पहचाना जाय, जिसे राजनीति में प्रबुद्ध भारत प्रासानी से बोल सके और जिसे विभिन्न प्रान्तों के सदस्य कांग्रेस के अखिल भारतीय अधिवेशनों में सम्मिलित सकें। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि बहुत से कांग्रेसी जनो ने उस प्रस्ताव पर अमल नहीं किया। और इसलिए यह दुःख उपस्थित होता है जो मेरी समझ में शामिल है कि कांग्रेसमें अंग्रेजी बोलने की जिद करत हैं और दूसरों को भी अपनी खातिर अंग्रेजी बोलने पर मजबूर करते हैं। अंग्रेजी का जादू अभी खत्म नहीं हुआ। उस जादू के असर से हम देश को अपने सत्य की ओर बढ़ने से रोकते हैं। जनता के लिए हमारा प्रेम एकदम सतही है यदि हम हिन्दुस्तानी सीखने के लिए उतने महीने भी नहीं देना चाहते जितने साल हम अंग्रेजी सीखने में लगाते हैं।" (उप०, पृ० ६२)

भारत स्वाधीन हुआ। गांधीजी ने चेतावनी दी कि "सरकार और सेक्रेटैरियट सावधान न रहे तो सम्भव है कि अंग्रेजी हिन्दुस्तानी की जगह ले ले। इससे भारत की करोड़ों जनता का बेहद नुकसान होगा जो अंग्रेजी समझ न पाएगी।" (उप०, पृ० १६८)। उन्होंने प्रान्तीय भाषाओं को पुनर्जीवित करने की सलाह दी, साथ ही यह सुझाव रखा कि प्रान्तीय सरकारें ऐसे कर्मचारी रखें जो प्रान्तीय भाषा के साथ अन्तर्प्रान्तीय भाषा हिन्दुस्तानी भी जानते हों।

यह सब न हुआ क्योंकि जिन लोगों के हाथ में शासन की बागडोर थी, वे अपने राजनीतिक समूहों में अंग्रेजी का व्यवहार करते थे। जो विरोधी दल ससद् में भारतीय लोकतन्त्र के संचालन में शामिल हुए, वे भी अखिल भारतीय सम्पर्क के लिए अंग्रेजी का ही व्यवहार करते थे।

इसलिए जो लोग चाहते हैं कि स्वाधीन भारत में अंग्रेजी का प्रभुत्व खत्म हो, उन्हें पहला कदम यह उठाना चाहिए कि भारत के राजनीतिक दलों के केन्द्रीय दफ्तरों से अंग्रेजी निकालें, इनके अखिल भारतीय अधिवेशनों में अंग्रेजी का व्यवहार बन्द कराएँ, उनका अखिल भारतीय प्रचार कार्य अंग्रेजी के माध्यम से बन्द कराएँ। सबसे मुश्किल यह पहला कदम ही है। यदि एक बार भारतीय जनता यह कदम उठाने के लिए पार्टियों के नेताओं को बाध्य करे तो दूसरे कदम उठाना बहुत आसान हो जाएगा।

पहले पार्टियों के अन्दर से अंग्रेजी की जड़ काटिए।

फिर लोकसभा में अपने प्रतिनिधियों को भारतीय भाषाओं में बोलने—
और अंग्रेजी छोड़ने—पर मजबूर कीजिए।

इसके बाद नौकरशाही पर दबाव डालिए कि वे दफ्तरो से अंग्रेजी निकालें। जब नेता लोग अंग्रेजी का बहिष्कार कर देंगे तब मन्त्रीजी के सामने कोई फाइल अंग्रेजी में न आएगी। अफसर लोग लोकसभा का अनुसरण करेंगे। इस समय विश्वविद्यालय अखिल भारतीय मेधावी से नरथी हैं। शिक्षा का एक उद्देश्य और मुख्य उद्देश्य अफसर तैयार करना है। जब आई० ए० एस० में अंग्रेजी का चलन न होगा, तब विश्वविद्यालयों में भी अंग्रेजी का प्रभुत्व न रहेगा।

पार्टी—लोकसभा—नौकरशाही—युनिवर्सिटियाँ, इस क्रम से अंग्रेजी के त्रिलो पर हमला करना चाहिए।

गांधीजी की भाषा-नीति का पाँचवाँ सूत्र है—भारत का विकास और राष्ट्रीय एकता की रक्षा प्रादेशिक भाषाओं को दबाकर नहीं, उनके पूर्ण विकास से ही सम्भव है।

गांधीजी ने अपने राजनीतिक जीवन के आरम्भ से ही अंग्रेजी का विरोध किया और प्रांतीय भाषाओं की हिमायत की। १९०६ में ही उन्होंने प्रांतीय भाषाओं और राष्ट्रभाषा का सम्बन्ध अच्छी तरह समझ लिया था। उन्होंने लिखा था, “हिन्दुस्तान में आजकल हिन्दू, मुसलमान, पारसी वगैरह ‘अपने देश’ की बात करने लगे हैं। इस समय मैं इस बात पर राजनीतिक दृष्टि से विचार नहीं कर रहा हूँ। भाषा की दृष्टि से यह जरूरी है कि इसके पहले कि हम अपने देश को अपना कहें, हमारे दिलों में अपनी भाषाओं के लिए प्रेम और आदर पैदा होना चाहिए। ऐसा मासूम होता है कि सारे भारत में लोग अपनी भाषाओं की ओर ध्यान देने लगे हैं। यह प्रगति की बात है।” (उप०, पृ० १-८)

इस तैल में गुजरातियों को अंग्रेजी बोलने पर उन्होंने फटकारा। उन्होंने इस बात पर हर्ष प्रकट किया कि लोग गुजराती, मराठी, बँगला, उर्दू आदि की प्रगति के लिए संस्कार बना रहे हैं।

सन् '१५ में सभागपुर के विद्यार्थियों के सामने भाषण (जिसका उल्लेख पहले हो चुका है) करते हुए उन्होंने मानुभाषा की अवज्ञा करनेवालों की निन्दा की।

सन् '२७ में जब हिन्दी प्रचार आन्दोलन सक्रियताशी होने लगा था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि “हिन्दी या हिन्दुस्तानी का उद्देश्य यह नहीं है कि वह प्रांतीय भाषाओं की जगह ले ले। वह अनिश्चित भाषा होगी और अन्तराष्ट्रीय सम्पर्क के काम आएगी।” (उप०, पृ० २६)

१९३५ में जब बारा बानेलकर ने गांधीजी को बताया कि लोग यह कहने लगे हैं कि हिन्दी प्रचार का उद्देश्य प्रांतीय भाषाओं का दमन है तब गांधीजी ने साहित्य-भारतमेलन के मंच पर घोषित किया, “मगर कहना बराबर गलती रहा है कि प्रांतीय भाषाओं का जरा भी बहिष्कार हम नहीं करना चाहते, उनका दमन या

नाश करना तो दूर की बात है।" (उप०, पृ० ३८)

गांधीजी स्वयं गुजराती के थोड़े लेखक थे। उनकी प्रेरणा से गुजराती बुद्धि-जीवियों ने अंग्रेजी का मोह छोड़ा और मातृभाषा की सेवा की। गुजराती भाषा के सेवक अंग्रेजी की गुलामी में मुक्त होने के कारण हिन्दी के समर्थक हुए। हिन्दी भाषी प्रदेशों के नेता, विशेषकर उत्तर प्रदेश (भूतपूर्व संयुक्त प्रान्त) के अधिकांश कांग्रेसी और कम्युनिस्ट नेता गांधीजी की तरह मातृभाषा के सेवक नहीं थे। अंग्रेजी का प्रभुत्व कायम रखने में उनका बहुत हाथ रहा है। गांधीजी स्वयं गुजराती के समर्थ लेखक थे, इसलिए वह प्रान्तीय भाषाओं और हिन्दी का सम्बन्ध अच्छी तरह समझते थे।

सन '३६ में उन्होंने बंगलोर में कहा था, "लोगों ने एक हीवा खड़ा कर रखा है जिसे मैं आप लोगों के दिमाग में निवास देना चाहता हूँ। क्या हिन्दी की शिक्षा कन्नड़ को हटाकर दी जाएगी? क्या यह सम्भावना है कि वह कन्नड़ की जगह ले ले? इसके विपरीत मेरा कहना है कि हम जितना ही हिन्दी प्रचार करेंगे उतना ही अपनी मातृभाषाओं के अध्ययन का और मशकत बनाएँगे, इन भाषाओं की शक्ति और सामर्थ्य को और भी बढ़ा सकेंगे। मैं विभिन्न प्रान्तों में अपने अनुभव के आधार पर यह कहता हूँ।" (उप०, पृ० ५०)

गांधीजी खूब जानते थे कि प्रादेशिक भाषाओं का मुख्य अन्तर्विरोध अंग्रेजी से है, न कि हिन्दी से। उन्होंने मद्रास में कहा था, 'अगर अंग्रेजी ने जनता की भाषाओं की जगह न ले ली होती तो आज वे अत्यन्त समृद्ध अवस्था में होती।' (१९३७, पृ० ५२)

गांधीजी की नीति स्पष्ट थी किन्तु कांग्रेस के कुछ नेता, विशेषकर उत्तर प्रदेश के नेता, यह कहते थे कि उच्च शिक्षा और सामन्य व्यवस्था में अंग्रेजी की तरह हिन्दी भी प्रादेशिक भाषाओं की जगह लेगी। इससे अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं का मुख्य अन्तर्विरोध गौण हो जाता था, और हिन्दी प्रहिन्दी भाषाओं का नया अन्तर्विरोध सामने आ जाता था। हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के जो हिमायती प्रादेशिक भाषाओं के हक मारकर उसे अंग्रेजी की जगह देने की बात कहते रहे हैं, वे हिन्दी के मार्ग में बाँटे बिछाते रहे हैं और इससे लाभ हुआ है अंग्रेजी को।

गांधीजी जानते थे कि भारत ऐसा राष्ट्र है जिसमें अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। वह ब्रिटेन या फ्रांस की तरह एक भाषावाला राष्ट्र नहीं है। इसलिए वह इस पक्ष में थे कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो जिससे प्रदेशों का राजकाज वहाँ की भाषाओं में हो सके। गांधीजी के कहने से जातीय इलाकों के आधार पर कांग्रेस कमेटीयों का संगठन किया गया था। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद गांधीजी ने लिखा, 'प्रान्तीय भाषाओं को अपना पूर्ण विकास करना है तो भाषा के आधार पर प्रान्तों का पुनर्गठन आवश्यक है। हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा हमी लेकिन वह प्रान्तीय भाषाओं की जगह न लेगी। वह प्रान्तों में

शिक्षा का माध्यम न होगी—अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम हो, इसका मकाल नहीं है। हिन्दुस्तानी का उद्देश्य यह होगा कि वह लोगों को महसूस कराए कि वे भारत के अभिन्न भग हैं। बाहर के लोग हमें गुजराती, महाराष्ट्री, तमिल आदि कहकर नहीं जानते हैं। उनके लिए हम सब हिन्दुस्तानी हैं। इसलिए हमें सभी विघटनकारी प्रवृत्तियों को दृढ़ता से रोकना चाहिए। इस मुख्य बात को ध्यान में रखते हुए हम मानेंगे कि भाषावार प्रान्त बनाने से शिक्षा और व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा।" (१९४८, उप०, पृ० २०२)

केन्द्रीय सरकार ने भाषावार प्रान्त बनाने का प्रबल विरोध किया। तमिलनाडु और गुजरात के बड़े पूंजीपति यह नहीं चाहते थे कि उनके विभाज्य प्रान्त खण्डित हो। इनके अंग्रेजी भ्रष्टाचारों ने भाषावार प्रान्त-निर्माण का जोरों से विरोध किया। गांधीजी ने कहा था कि भाषावार प्रान्त बनाने से शिक्षा और व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। गांधीजी की निगाह छोटे व्यापारियों और पूंजीपतियों पर थी जो बड़े प्रान्त में उदीयमान इजारेदारों से पीड़ित थे। लेकिन दिल्ली की सरकार इन इजारेदारों की बात ज्यादा सुनती थी, गांधीजी और मध्यम पूंजीपतियों की कम। यही कारण है कि उसने प्राणपन से महाराष्ट्र और आंध्र के नये प्रान्त बनाने के आन्दोलन का विरोध किया।

गांधीजी के नाम पर जनता में घोट सेनेवात्रा, गांधीवाद विरोधी दिल्ली का सरकारी कांग्रेस-नेतृत्व भाषावार प्रान्त-निर्माण का विरोध करके हिन्दी का अहित और अंग्रेजी का हित कर रहा था। कुछ अहिन्दी-भाषियों में यह भय उत्पन्न हुआ कि उनकी भाषाओं का दमन किया जाएगा और उन पर हिन्दी लादी जाएगी। इधर दिल्ली सरकार के नेता जानते थे कि अंग्रेजी न भाज जाने-वाली है न बल। फिर भी वे बराबर हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का दावा करते जाते थे क्योंकि इसके बिना विभाज्य हिन्दी-भाषी क्षेत्र में उन्हें घोट न मिल सके थे।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भाषावार प्रान्त-निर्माण का विरोध करने में दिल्ली सरकार ने बड़े पूंजीपतियों के दबाव में सरकार अपनी नीति निर्धारित की। इन बड़े पूंजीपतियों की माँठ गाँठ ब्रिटेन के इजारेदारों से भी थी। दिल्ली सरकार भारत के बड़े पूंजीपतियों के अनावाजब-तब ब्रिटेन के इजारेदारों का हल देखकर भी काम करती थी। ब्रिटिश पूंजीपति चाहते थे कि भारत में अंग्रेजी रहे। इसमें एक तो भारत सांस्कृतिक रूप से ब्रिटेन के साथ नट्यो रहता है, दूसरे अंग्रेजी किताबों की बिक्री के लिए इतना बड़ा बाजार ब्रिटिश प्रकाशकों के हाथ में बना रहता है। इसीलिए जो लोग भाषावार प्रान्त बनाने के विरोधी थे, वे अंग्रेजी का बहुत बड़े समर्थक थे। दिल्ली सरकार ने तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की दनाल थी, न वह केवल भारत के बड़े पूंजीपतियों की प्रतिनिधि थी। उसने भारत के उद्योगीकरण में, विद्योपकरण सरकारी उद्योग-धन्यो के निर्माण में, भारत की स्वतन्त्र विदेश-नीति निर्धारित करने में और

समाजवादी देशों से मंत्री-सम्बन्ध कायम करने में बहुत बड़ा योग दिया। फिर भी उसने भारत और ब्रिटेन के बड़े पूंजीपतियों के हित में कुछ गलत कदम उठाए।

कुछ प्रगतिशील विचारक भाषावार प्रान्त-निर्माण के पक्ष में गांधीजी के विचार बड़े गर्व से उद्धृत करते हैं किन्तु गांधीजी ने अंग्रेजी हटाने के बारे में जो कुछ कहा था, उसे वे बड़े प्रेम से नजरअन्दाज कर देते हैं। ये विचारक उन मध्यवर्गी बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधि हैं जो केन्द्र में अंग्रेजी चालू रखकर प्रखिल भारतीय नीकरियों के उम्मीदवार हैं।

गांधीजी के नाम की दुहाई देकर केन्द्र में 'फिलहाल' अंग्रेजी चलाते रहने की बात करना हास्यास्पद है।

प्रान्तीय भाषाओं के सम्बन्ध में गांधीजी का यह उदार दृष्टिकोण ध्यान देने योग्य है कि अंग्रेजी की जगह जहाँ अन्तर्प्रान्तीय सम्पर्क के लिए लोग हिन्दी न बोल सकें, वहाँ वे प्रान्तीय भाषा का ही व्यवहार करें।

१९४२ में बनारस विश्वविद्यालय में गांधीजी ने हिन्दी में भाषण करते हुए कहा था, 'यहाँ मध्द पर एक के बाद दूसरा वक्ता भाषा और मैं अधीरता से राह देखता रहा कि कोई हिन्दी या उर्दू या हिन्दुस्तानी म, या संस्कृत में ही भाषण करे, यह न सही तो मराठी में या और किसी भारतीय भाषा में बोले। लेकिन मुझे यह सीमाध्य प्राप्त न हुआ। क्यों? इसलिए कि हम गुलाम हैं और उन्हीं की भाषा को छाती से चिपकाये हुए हैं जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा है।'

विद्यार्थियों को लक्ष्य करके उन्होंने कहा, "ये जरा-जरा-सी बात पर हड़ताल कर देते हैं, भूल हड़ताल कर देते हैं। ये राष्ट्रभाषा में शिक्षा पाने के लिए क्यों नहीं लड़ते? मुझे बताया गया है कि घाघ्र प्रदेश के ठाई सी विद्यार्थी हैं। उन्हें सर राधाकृष्णन् के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए कि विश्व-विद्यालय में एक आन्ध्र विभाग खोला जाय। वे राष्ट्रभाषा नहीं सीखना चाहते तो तेलुगु के माध्यम से शिक्षा पाने की माँग करें।" (उप० पृ० ६२-६३)

"राष्ट्रभाषा नहीं सीखना चाहते तो तेलुगु के माध्यम से शिक्षा पाने की माँग करें", इस सूत्र की आज की परिस्थितियाँ में लागू करें तो हम नेताओं में कहेंगे कि भाषा हिन्दी नहीं बोल सकते तो अपनी मातृभाषा में भाषण कीजिए। श्री कामराज नाडार इसी नीति का पालन करते हैं और तमिल में बोलते हैं। अनुवाद की व्यवस्था करके उन लोगों की कठिनाई दूर की जा सकती है जो हिन्दी का व्यवहार नहीं कर सकते या जान बूझकर नहीं करना चाहते।

गांधीजी भरिया गए। सभा में हज़ारों मजदूर थे। गांधीजी का अभिनन्दन अंग्रेजी में किया गया। इस पर उन्होंने 'यंग इंडिया' में लिखा, 'अधिकांश श्रोता आसानी से हिन्दी समझ लेते और काफी लोग बँगला समझ लेते। उस सभ के

पदाधिकारी बगाली थे। अगर उन्होंने अंग्रेजी का व्यवहार मेरे लिए किया तो बिल्कुल अनावश्यक था। वे अभिनन्दन (या भाषण) बंगला में लिख सकते थे और मुझे उसका हिन्दी-अनुवाद दे देते। अंग्रेजी में भी अनुवाद करके दे सकते थे। लेकिन उत्तरी बड़ी सभा पर अंग्रेजी घोषणा उसका अपमान करना था।”

इसके आगे दक्षिण भारत को लक्ष्य करके उन्होंने लिखा, “यह घटना सभाएं संगठित करनेवालों के लिए हर जगह चेतावनी का काम करे, खास तौर से आंध्र, तमिलनाडु, केरल और बर्माटन के सभा-संयोजकों को सावधान कर दे, यह मैं चाहता हूँ। मैं उनकी कठिनाई समझता हूँ। लेकिन छह साल से उनके बीच हिन्दी-प्रचार सभा (जोरो) से काम कर रही है। उनके भाषण प्रांतीय भाषाओं में होने चाहिए और मेरी सुविधा के लिए उनके हिन्दी अनुवाद दे देने चाहिए।” (अप०, पृ० २२-२३)

गांधीजी ने यह सब सन् '२७ में लिखा। तब से अब तक हिन्दी-प्रचार सभा लाखों छात्रमियों को हिन्दी सिखा चुकी है। फिर भी वे या अन्य अहिन्दी-भाषी राष्ट्रभाषा का व्यवहार न कर सकें या न करना चाहें तो उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलना चाहिए और उनके भाषण के अनुवाद की व्यवस्था होनी चाहिए।

२७-२८ जून को इस सत्र बरेली में माहित्य-सम्मेलन का जो अधिवेशन हुआ, उसके प्रस्ताव में कहा गया है, “केन्द्रीय सरकार और हिन्दी-भाषी राज्य-सरकारों से उत्तर प्रदेश सरकार केवल हिन्दी में सम्पूर्ण पत्र-व्यवहार करे तथा इतर भाषी राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार मूल रूप से हिन्दी में करे और साथ में तत्कालीन भाषा में रूपान्तर सलभ कर दिया करे।” (राष्ट्रभाषा सन्देश, इलाहाबाद, ८ जुलाई, १९६५)

गांधीजी की नीति को वर्तमान परिस्थिति में कैसे धमली रूप दिया जाय, सम्मेलन का सुझाव इसकी बहुत अच्छी मिसाल है। प्रस्ताव में यह मही कहा गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार अन्य प्रदेशों की सरकार से केवल हिन्दी में पत्र-व्यवहार करे, या हिन्दी के साथ अंग्रेजी में अनुवाद भेजे, प्रस्ताव में अंग्रेजी के मुकाबले प्रांतीय भाषाओं को ऊँचा आसन दिया गया है। इस प्रकार अनुवाद की व्यवस्था करके अन्य प्रदेशों की सुविधा का ध्यान रखते हुए अंग्रेजी को हटाया जा सकता है।

गांधीजी ने कहा था कि आंध्र के विद्यार्थी राष्ट्रभाषा के माध्यम से शिक्षा पाना नहीं चाहते तो वे तेलुगु में शिक्षा पाने की माँग करें। वे उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक केन्द्र काशी में प्रादेशिक भाषा तेलुगु और हिन्दी की समान अधिकार देने के लिए तैयार थे। पाठक विचार करें, समुक्त राष्ट्र सघ का काम कैसे चलता है। वह विश्व सस्था है। उसके सेक्रेटेरियट में न जाने कितनी भाषाओं में बोलनेवालों की बातों का हिसाब-किताब रखना पड़ता है। सेक्रेटेरियट में

दुनिया की सभी भाषाओं में कारंवाई नहीं दर्ज की जाती; न संयुक्त राष्ट्रमण्डल ने अंग्रेजी को विश्व-भाषा मानकर केवल उसी में दफ्तर चलाने का नियम बनाया है। उसने अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, चीनी और स्पेनी को बराबर अधिकार देकर उन्हें अपने काम-काज की भाषा बनाया है। हर भाषण का अनुवाद इन भाषाओं में एवं साथ किया जाता है।

भारत में जब तक अहिन्दी प्रदेशों के नेता स्वेच्छा से हिन्दी स्वीकार नहीं करते, तब तक यदि हिन्दी, बंगला, तमिल, तेलुगु और मराठी को समान हथ से केन्द्रीय भाषा मान लिया जाय, तो क्या यह समाधान हिन्दी-अहिन्दी नेताओं को मान्य न होना चाहिए ?

यदि विश्व-मन्त्रालय का दफ्तर एक से अधिक भाषाओं में चल सकता है तो क्या हम लोकसभा में एक से अधिक भाषाओं में बोलने और राज स्वीकृत भाषाओं में भाषण के अनुवाद की व्यवस्था नहीं कर सकते ? इसी तरह केन्द्रीय सरकारी दफ्तरों का काम एक से अधिक भाषाओं में हो सकता है।

गांधीजी ने लिखा था, 'दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में अंग्रेजी और डच भाषाओं को टक्कर थी। अन्त में फैसला यह हुआ कि दोनों भाषाओं को बराबरी का दर्जा देना चाहिए।' (गोट्स, पृ० २४)

इसी तरह कनाडा में अंग्रेजी-फ्रांसीसी, बेल्जियम में फ्रांसीसी-फ्लेमिश, पाकिस्तान में उर्दू-बंगला, लद्दाख में सिंहली-तमिल भाषाओं की टक्कर है। इन देशों में भाषा-समस्या का एक ही समाधान है कि दो भाषाओं को बराबर अधिकार देकर उन्हें केन्द्रीय भाषाएँ माना जाय।

जो लोग यह समझते हैं कि अंग्रेजी हटाने की माँग दूसरी भाषाओं पर जबर्दस्ती हिन्दी ला देने की माँग है, उनके विचार और चिन्तन के लिए मेरा उपर्युक्त प्रस्ताव है। इसमें न तो केन्द्रीय सेवाओं के लिए सभी से एक भाषा सीखने का आग्रह है, न भारत की सभी भाषाओं को केन्द्रीय भाषा बना देने की माँग है। यह मध्यमार्गी प्रस्ताव है और अमल में लाया जा सकता है वशतः कि पहले कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य दल अपने केन्द्रीय दफ्तरों से अंग्रेजी निकास दें।

गांधीजी की भाषा-नीति का अन्तिम सूत्र है—हिन्दी-उर्दू बुनियादी तौर से एक ही भाषा है और भाषे चलकर उनका एक ही सम्मिलित साहित्यिक रूप होगा।

हिन्दी-उर्दू की बुनियादी एकता के बारे में उन्होंने लिखा था, 'हिन्दी और उर्दू या हिन्दुस्तानी में कोई भी फर्क नहीं है। दोनों का व्याकरण एक है। फर्क केवल लिपि का है। विचार कीजिए तो मालूम होगा कि हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी—इन तीन शब्दों से एक ही भाषा का बोध होता है। इनके शब्दकोश देखें तो पता चलेगा कि अधिकांश शब्द एक-से हैं।' (उप०, पृ० ५०)

गांधीजी ने जो कुछ लिखा था, वह बोलचाल की भाषा की दृष्टि से सही

था। हिन्दी-उर्दू मूलतः एक ही भाषा है और ग्राम जनता उनके व्यवहार में कोई भेद नहीं करती।

गांधीजी ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि उर्दू भाषा और लिपि केवल मुसलमानों की सम्पत्ति नहीं है। "ऐसे काफी हिन्दू और अन्य धर्मों के लोग भी हैं जिनकी मातृभाषा उर्दू है और जो केवल उर्दू लिपि जानते हैं।" (उप०, पृ० १७५)

इससे जो नतीजा निकलता है, वह यह कि उर्दू धार्मिक अल्पसंख्यकों की भाषा न होकर सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की भाषा है। वह स्वतन्त्र भाषा नहीं, इसलिए उसकी रक्षा रक्षित करनी चाहिए जब तक एक ही बोलचाल की भाषा के दोनो निष्ठ रूप मूल-मिश्रण एक न हो जाएं।

देश में हिन्दू-मुस्लिम समस्या अंग्रेजों के हाथ में बहुत बड़ा हथियार थी जिसे वे राष्ट्रीय आन्दोलन को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। उर्दू का सम्बन्ध मुसलमानों के विशेषाधिकारों से जुड़ गया। उर्दू की रक्षा का प्रश्न—विशेष रूप से उसकी लिपि की रक्षा का प्रश्न—धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा का प्रश्न बन गया। गांधीजी ने हिन्दी-हिन्दुस्तानी का नारा देकर हिन्दुओं और मुसलमानों को मिलाते का भरोसा प्रयत्न किया। किन्तु भाषा केवल बहाना थी; घनगाव के कारण दूमे थे। बंगाल में उर्दू लिपि की रक्षा का प्रश्न न था; फिर उसका विभाजन हुआ। मिथी भाषा के लिए कार्मों लिपि का ही संगोषित रूप काम में आता था। फिर भी मिथी पाकिस्तान में गया। जिनकी भाषा उर्दू थी, वे वहीं रहे। उर्दू के दमन का नारा लगाकर मुस्लिम जनता को मड़काया गया, साम्राज्यवादियों और उनके माध्यमिक सहायकों ने भाषा समस्या में काम उठाकर राष्ट्रीय आन्दोलन को कमजोर किया।

इस परिस्थिति को बदलने का एक ही तरीका था, साम्राज्यवाद के खिलाफ ग्राम जनता का संगठन किया जाए। उत्तर भारत में किसान-मजदूरों और मजदूर-मजदूरों में एक ही भाषा का व्यवहार किया जाए, इन जन-संगठनों में फारसी, मस्तूत गारों के व्यवहार पर रोक न लगाकर एक ही लिपि देवनागरी के व्यवहार पर जोर दिया जाए। एक लिपि के माध्यम से जो किसान-मजदूर अपनी राजनीतिक-सांस्कृतिक काम करते, वे सरकारी-मस्तूत के गारों की छेदाई खुद कर लेते। वे लेखक जो मार्क्सवाद में प्रभावित थे, हिन्दी-उर्दू साहित्य का प्रकाशन एक ही लिपि देवनागरी में करने दोनो के बीच का कामना काम करने में मदद दे सकते थे। गांधीजी गुजराती थे। वह धार्मिक हिन्दी साहित्य से बहुत काम परिचित थे, उर्दू-साहित्य के विज्ञान से और भी कम परिचित थे। उत्तर प्रदेश के प्रगतिशील लेखक गांधीजी को बहुत बड़ी मदद कर सकते थे। लेकिन इन लेखकों को भाषा-नीति में शामिल थीं जिनकी चर्चा अन्य निबन्ध में है।

हिन्दी उर्दू का भेद महत्व नहीं था। बलिताऊ हिन्दी और मौनबिजाना उर्दू

की शिक्षा करके वह भेद समाप्त न किया जा सकता था। दोनों में एक चुन-कर मान-की भाषा में एक सामान्य लिखत बना ली न जा सकती थी। गांधीजी भारत की समाज भाषाओं के लिए एक विधि के व्यवहार पर जोर देने में हिन्दु राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी के लिए यह दोषा निम्नो का व्यवहार आवश्यक समझते थे। यह जानने के लिए बहुत से विद्वानों की विधि अधिक प्रस्तावित है। और हमें समझ करती होती है। उर्दू लिख और उर्दू-भाषा को सुरक्षित रखने की भाषा लही थी। हिन्दु यदि एक ही विमान-भाषा में अपना भाषा हिन्दी में अपना काम करने है और हम चाहते हैं उर्दू में, तो हमें विमानों का बर्तन-महल कमजोर होता है। यदि देश में राष्ट्रभाषा की वांछिनी है, तो हमें यदि देश का काम बहिन हो जाता है। यदि देश व शिक्षा लोग दोनों विविध लोगों, राष्ट्रभाषा दोनों ही विविधों में मिली जाय, वह बात सामान्य-कारिणी थी।

व्यावहारिक बात यह भी कि हिन्दी-उर्दू की विविधों को बराबरी का दर्जा न देकर एक की प्रमाण और प्रादेशिक व्यवहार के लिए स्वीकार किया जाय और दूसरी को अल्पगण्यकों के लिए आवश्यक मात्रा परमाण प्रमाण दिया जाय। यदि उर्दू की सुगमताओं की विधि दात ही किया जाय तो भी वह अल्पगण्यकों की विधि होगी, उसे देवनागरी का दर्जा देना समझ था।

हिन्दू और मुस्लिम साम्राज्यवादियों में भिन्न गांधीजी हिन्दी-उर्दू की बुनियादी एकता में विश्वास करने के और समझने के कि जब साम्राज्यवाद समाप्त कम हो जाएगा, तब दोनों धर्मों का युग मिलकर एक हो जाएगी। उन्होंने मनु '२७' में लिखा था, "जब तक हिन्दू-मुस्लिम समाप्त बना हुआ है, तब तक वह कभी पारसी-घरकी दादों से लड़ी हुई पारसी विधि में मिली जानेवाली उर्दू का रूप लेता है, कभी मल्लूय दादों से लड़ी हुई देवनागरी विधि में मिली जानेवाली हिन्दी का रूप लेता है। जब दोनों के दिल मिलेंगे तब एक ही भाषा के दो रूप युग मिलकर एक हो जाएंगे और हम भाषा में संस्कृत, पारसी, घरकी या अन्य भाषाओं के उतने ही दाद होने किने उनके पूर्ण विभाग और पूर्ण व्यक्तता-कारिणी के लिए दरबार होंगे।" (उप०, पृ० २६-२७)

इन बातों में जोर भाषा की मूल प्रवृत्ति पर है। किने दाद कि भाषा में मिले जाएंगे, यह भाषा के अपने विभाग पर, उनके सोचनेवालों के विश्वास पर निर्भर है, इसका फैसला कोषकार नहीं कर सकते। लेकिन दोनों मिलेंगी जरूर, गांधीजी का यह दृढ़ विश्वास था। उनका यह विश्वास निमकुल लही था। बंगाल के विभाजन का खैला के दो रूप नहीं हो गए, पञ्जाब के बंटवारे से दो पञ्जाबी भाषाएँ नहीं बन गईं। भाषाओं के विभाग के नियम साम्राज्यवादी योजनाओं से ज्यादा शक्तिशाली हैं। उर्दू पाकिस्तान की नहीं हिन्दुस्तान की है। हम उसका संरक्षण करेंगे, साथ ही हिन्दी-उर्दू का भेद मिटाने का भी करेंगे। हिन्दी-उर्दू लिखने सोचनेवालों का प्रदेस एक, जाति एक,

आर्थिक सम्बन्ध एक । बोलचाल की भाषा के दोनों साहित्यिक रूपों को एक दिन मिलना ही होगा ।

गांधीजी की भाषा-नीति के ये छह महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिन्हें आज की परिस्थितियों में विवेक से लागू करके हम भाषा-समस्या के यही समाधान की ओर बढ़ सकते हैं ।

(१९६५)

सबका है।

ग्रन्थ भाषा-भाषियों की मुन्नता के लिए, कृपित के दायरे बढ़ाना चाहते थे परन्तु वह ऐसे छन्द देने के लिए जिनके लिये लिखे न रहे। नवम्बर, ३५ के 'दृष्ट' में उन्होंने लिखा था, "इनका छन्द रखने से तो कि ग्रन्थ को बड़ाने की धुन में वह ग्रन्थ बन ही न जाये, बड़े-छोटे की एक मर्यादा है, और उनका चाहे बिना भी विस्तार है, इनको इस ग्रन्थ को रखा होनी आवश्यक है।" इन शब्दों में उन्होंने अपने अर्थ-व्यञ्जक के अनुभव और चिन्तन का सार रख दिया है।

सरन भाषा निखने के पक्षपाती होते हुए भी प्रेमबन्ध साहित्यिक की कठिनाइयों को जानते थे। उन्होंने स्वीकार किया है, ज्ञान, विज्ञान आदि में और क्या-साहित्य में भी जहाँ वह विवेचनात्मक हो जाता है, जन-साधारण की भाषा से ग्रन्थ कठिन शब्द ग्रन्थाने पड़ते हैं। भाषा-काव्य के विरुद्ध कुछ लोगों की तरह भाषा न उठाकर प्रेमबन्ध ने जन-साधारण में ही अधिकारिक भाषा और साहित्य के प्रचार पर और दिया है। जो सोय उच्चकोटि का सम्मौर साहित्य रचनेवालों की भाषा-सम्बन्धी कठिनाइयों को न समझकर उस पर गुरज ही बुराहता, अस्वामाविकता आदि का आरोप कर बैठते हैं, उन्हें प्रेमबन्ध के इन शब्दों को ध्यान में रखना चाहिए—'जब तक जनता में शिक्षा का प्रचलन प्रचार नहीं हो जाता, उसकी व्यावहारिक शब्दावली बड़ नहीं जाती, हम उसके समझने लायक भाषा में तात्त्विक विवेचनाएँ नहीं लिख सकते।' शिक्षा का प्रचार होने पर वही कठिन शब्द "जिन्हें देखकर धात्र हम भयभीत हो जाते हैं, जब ग्रन्थास में आ जायेंगे तो उनका हीवापन जाता रहेगा।" ('हम, जनवरी, १९३५)

राष्ट्रभाषा के राजनीतिक महत्व को वह पूरी तरह स्वीकार करते थे और इसके लिए उन्होंने नेताओं पर यह बोध भी लगाया है कि वे इस सम्बन्ध में अधिक सचेष्ट नहीं रहे। "जब हमारे नेता हिन्दी-साहित्य से बेखबर से हैं, जब हम लोग बोझी-सी भाषाएँ लिखने की सामर्थ्य होते ही हिन्दी को कुछ और प्रामीणी की भाषा समझने लगते हैं, तब यह कैसे भाषा की जा सकती है कि हिन्दी में जैसे दर्ज के साहित्य का निर्माण हो।" ('हम', जनवरी, १९३६) फिर भी उनका विचार या देश का साहित्य यदि उन्नति कर सकता है तो राष्ट्रभाषा के द्वारा ही, अन्य उपभाषाओं से नहीं, राष्ट्रभाषा का साहित्य प्रत्यक्ष में उभर सवेगा, दूसरा नहीं। "यह स्वप्न देखना कि भारत की समुन्नत भाषाओं के बराबर हो सकती है, केवल अन्तर्राष्ट्रीय संधों के सामने सदा

प्रेमबन्ध कितना महत्वपूर्ण

प्रेमचन्द और भाषा-समस्या

प्रेमचन्द ने भाषा के सम्बन्ध में काफी विचार किया था और उसके सम्बन्ध में जिज्ञा भी काफी है। जब उन्होंने उर्दू छोड़कर हिन्दी में लिखना शुरू किया था तब भी उनके सामने भाषा का प्रश्न महत्वपूर्ण होकर आया था। इसी-लिए 'सेवासदन' में भी हम उन्हें इस विषय पर सोचते-विचारते देखते हैं। डॉ० श्यामाधरण मोटार से उतरकर अंग्रेजी में अपने देर होने की क्षमा चाहते हैं, तब कुँवर साहब उन्हें पाद दिलाते हैं, "डॉक्टर साहब, आप भूलते हैं, यह बाले प्रादमियों का समाज है।" डॉक्टर साहब अंग्रेजी की देश की सिमुद्रा फाका मानते हैं, परन्तु कुँवर साहब इसका कारण देश के कुछ अंग्रेजी-मक्ती को बताने हैं। अंग्रेजी से कुँवर साहब को "ऐसी ही घुणा होती है जैसी किसी अंग्रेज के उदारे कपड़े पहनने में।"

उर्दू और हिन्दी का प्रश्न प्रेमचन्द के सामने खड़ा था। उसके बाद में कुँवर साहब कहते हैं—"फारस और बाबुल के पूर्व सिपाहियों और हिन्दू श्या-पाठियों के समागम से उर्दू जैसी भाषा का प्रादुर्भाव हो गया। अगर हमारे देश के मिल-मिल प्रान्तों के विद्वज्जन अपनी ही भाषा में सम्भाषण करते तो अब तक कभी एक सार्वदेशिक भाषा बन गई होती।" दिसम्बर, १९३१ के 'हंस' में एक पुस्तक की आलोचना करते हुए प्रेमचन्द ने लिखा था, "साहित्य-मंडल ने उर्दू के केन्द्र दिल्ली में हिन्दी-प्रकाशन का भार उठाया है, यह उद्योग प्रशंसनीय है।" प्रेमचन्द हिन्दी-उर्दू का भेद मिटाने के पक्ष में थे क्योंकि बाल्य में मायाएँ दोनों एक हैं। इसके लिए वह बाज़ी उदारता से काम लेना चाहते थे, भाषा शुद्ध ही हो, इसके वह कामत न थे। परन्तु राष्ट्रभाषा को कुछ दिने-बुने प्रादमियों की न होकर देश के समूह की समझ में आनीवासी होना चाहिए। जैसा उन्होंने 'हंस' में लिखा था, "राष्ट्रभाषा केवल रईमों और अमीरों की भाषा नहीं हो सकती। उसे विमानों और मजदूरों की भाषा बनना पड़ेगा।" बीजली भाषा विमानों और मजदूरों की भाषा बन सकेगी—इसी-लिए कहानियों और उपन्यासों में ही विमान-मजदूरों की भाषा है।

सबता है।

अन्य भाषा-भाषियों की सुममता के लिए वह हिन्दी का शब्दकोश बढ़ाना चाहते थे परन्तु वह ऐसे शब्द लेने के पक्ष में न थे जिनसे हिन्दी हिन्दी न रहे। नवम्बर, '३५ के 'हस' में उन्होंने लिखा था, "इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना कोष बढ़ाने की धुन में वह अपना रूप ही न खो बैठे...हिन्दी की एक मर्यादा है, और उसका चाहे जितना भी विस्तार हो, उसकी इस मर्यादा की रक्षा होनी आवश्यक है।" इन शब्दों में उन्होंने अपने जीवन-पर्यन्त के अनुभव और चिन्तन का सार रख दिया है।

सरल भाषा लिखने के पक्षपाती होते हुए भी प्रेमचन्द साहित्यिक की कठिनाइयों को जानते थे। उन्होंने स्वीकार किया है, दर्शन, विज्ञान आदि में और कथा-साहित्य में भी जहाँ वह विवेचनात्मक हो जाता है, जन-साधारण की भाषा से अलग कठिन शब्द अपनाने पड़ते हैं। भाषा-काठिन्ध के विरुद्ध कुछ लोगों की तरह आकाश न उठाकर प्रेमचन्द ने जन-साधारण में ही अधिकाधिक भाषा और साहित्य के प्रचार पर जोर दिया है। जो लोग उच्चकोटि का गम्भीर साहित्य रचनेवालों की भाषा-सम्बन्धी कठिनाइयों को न समझकर उस पर तुरन्त ही दुरुहता, अस्वाभाविकता आदि का आरोप कर बैठते हैं, उन्हें प्रेमचन्द ने इन शब्दों को ध्यान में रखना चाहिए— 'जब तक जनता में शिक्षा का अच्छा प्रचार नहीं हो जाता, उसकी व्यावहारिक शब्दावली बढ़ नहीं जाती, हम उसके समझने लायक भाषा में तार्किक विवेचनाएँ नहीं लिख सकते।' शिक्षा का प्रचार होने पर वही कठिन शब्द "जिन्हें देखकर धाज हम भयभीत हो जाते हैं, जब अभ्यास में आ जाएंगे तो उनका होवापन जाता रहेगा।' ('हस, जनवरी, १९३५)

राष्ट्रभाषा के राजनीतिक महत्त्व को वह पूरी तरह स्वीकार करते थे और इसके लिए उन्होंने नेताओं पर यह दोष भी लगाया है कि वे इस सम्बन्ध में अधिक सचेष्ट नहीं रहे। "जब हमारे नेता हिन्दी-साहित्य से ब्रेखबर से हैं, जब हम लोग थोड़ी-सी अंग्रेजी लिखने की सामर्थ्य होते ही हिन्दी को तुच्छ और ग्रामीणों की भाषा समझने लगते हैं, तब यह कैसे भाषा की जा सकती है कि हिन्दी में ऊँचे दर्जे के साहित्य का निर्माण हो।' ('हस', जनवरी, १९३६)

फिर भी उनका विचार था देश का साहित्य यदि उन्नति कर सकता है तो राष्ट्रभाषा के द्वारा ही, अन्य उपभाषाओं से नहीं, राष्ट्रभाषा का साहित्य अन्त-राष्ट्रीय प्रतिद्वन्द्विता में ठहर सकेगा, दूसरा नहीं। "यह स्वप्न देखना कि भारत की सभी प्रान्तीय-भाषाएँ ससार की समुन्नत भाषाओं के बराबर हो सकती हैं, भूल है। एक राष्ट्र एक ही भाषा को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय सभा के सामने खड़ा हो सकता है।' ('हस', नवम्बर, १९३५)

इससे मालूम होता है, राष्ट्रभाषा के प्रश्न को प्रेमचन्द कितना महत्वपूर्ण समझते थे और उसके साहित्य की उन्नति के लिए उनमें कौसी उत्कट अभिलाषा

थी। उसी लगन से साहित्य रचकर उन्होंने राष्ट्रभाषा का भस्तव भी ऊँचा किया है।

लिपि के सम्बन्ध में उन्होंने विशेष कुछ विवेचनात्मक नहीं लिखा, परन्तु जैसे भाषा के सम्बन्ध में उनकी पहली कसौटी बोधगम्यता की है, उसी प्रकार लिपि के लिए उन्होंने पहले पहल उसका सरल और सुबोध होना आवश्यक समझा है। इसलिए उन्होंने देवनागरी लिपि का ही मर्मर्षन किया था, "हिन्दुस्तानी भाषा के लिए हिन्दी लिपि रखना ही सुविधा की बात है।" ('हंस', नवम्बर, १९३५) (१९४०)

२

प्रेमचन्द ने साहित्यकारों के लिए लिखा था कि उन्होंने कौम की तारीख बनाई है, उसकी संस्कृति बनाई है। प्रेमचन्द किस कौम की तारीख बनानेवाले साहित्यकार थे? वैसे तो उनके साहित्य का आधार सारे हिन्दुस्तान में हुआ है लेकिन वह खास तौर से हिन्दीभाषी जाति के लेखक थे। वह हिन्दुस्तानी कौम की तारीख बनानेवाले साहित्यकार थे। उन्होंने हिन्दी और उर्दू दोनों ही में रचनाएँ कीं। हिन्दी और उर्दू के लेखकों को नज़दीक लाने में, हिन्दी और उर्दू के सामन्ती साहित्य का मुकाबला करने में, हिन्दी और उर्दू के नये साहित्य में आजादी और जनतन्त्र का भाव और विचार भरने में प्रेमचन्द ने हमारी जाति की अद्वितीय सेवा की है। तुलसीदास के बाद हिन्दी के यह सबसे बड़े साहित्यकार थे जिन्होंने हमारी किसान जनता से अपनाया। जहाँ-जहाँ हिन्दी-उर्दू पढ़नेवालों ने प्रेमचन्द की रचनाओं को मर्म लिया, वहाँ-वहाँ जातीय एकता का भाव और मजबूत हुआ।

हिन्दुस्तानी कौम की एकता में हिन्दी-उर्दू का विवाद एक बहुत बड़ी बाधा बना हुआ था। प्रेमचन्द इसके लिसनेवालों को दो कौमों का लेखक न मानते थे। वह उन्हें नज़दीक लाना चाहते थे जिससे कि एक मिली-जुली साहित्यिक भाषा का चलन हो सके। दिल्ली में हिन्दुस्तानी सभा के स्थापित होने पर उन्होंने उसका स्वागत किया था क्योंकि उसमें हिन्दी और उर्दू के लेखक एक साथ बैठते और बहस करते थे। हिन्दी उर्दू के लेखकों का परस्पर मिलना जुलना और एक साथ भाषा और साहित्य की समस्याओं पर विचार करना उनकी नज़र में कितना जरूरी था यह 'हिन्दुस्तानी सभा' पर उनकी टिप्पणी से जाहिर होता है। इसमें उन्होंने लिखा था, "जब उर्दू का अदीब अपनी कोई रचना ऐसी समाज के सामने पढ़ेगा, जिसमें हिन्दी के लेखक भी शरीक हैं, तो वह ऐसी भाषा लिखने को प्रोत्साहित करेगा जो हिन्दीवालों की समझ में आए। इसी तरह हिन्दी का लेखक उर्दू के अदीबों की मण्डली में अपनी भाषा को सुबोध रखने पर मजबूर होगा।" इस तरह के परस्पर प्रभाव और आदान-प्रदान से वह एक मिली जुली साहित्यिक मंडली के विकास की धारा बरते थे।

इस तरह के प्रयोग की सफलता एक दूसरी बात पर भी निर्भर है और वह

यह कि इस तरह की समाग्रो में शामिल होनेवाले लेखक किस हद तक जनता के लिए लिखते हैं और किस हद तक अपने जीवन में जनता के नज़दीक हैं। जनता के लिए न लिखने पर साहित्यकार उसी पुरानी सफाजी और उन्हीं पुराने धलकारों की दुनिया में चक्कर लगाता रहता है और तब हिन्दी और उर्दू के लेखक एक-दूसरे से सीखने के बदले एक-दूसरे के कठिन शब्दों को ढूँढ़ने में लग जाते हैं। एक मिली-जुली साहित्यिक भाषा के जरिये काम की सेवा करने और उसको संगठित करने का सवाल पीछे पड़ जाता है। जहाँ पर हिन्दी-उर्दू लेखकों के मिलकर काम करने और सभाएं चलाने के काम पूरी तरह सफल नहीं हुए वहाँ असफलता का मुख्य कारण जनता से लेखकों के असंगत को समझना चाहिए।

एक साहित्यिक शैली गढ़ने के पक्ष में होते हुए भी प्रेमचन्द उसे गढ़ने की कठिनाइयों को जानते थे। 'भारतीय साहित्य परिषद्' में हिन्दुस्तानी को जगह न देने पर मौलाना अब्दुल हक की आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने जून, सन् '३६ के 'हस' में लिखा था, "और जो हिन्दुस्तानी अभी व्यवहार में नहीं आई, उसके और पयादा हिमायती नहीं निकले तो कोई तारुज नहीं। जो लोग हिन्दुस्तानी का कालतनामा लिये हुए हैं, और उनमें एक इन पक्तियों का लेखक भी है वे भी अभी तक हिन्दुस्तानी का कोई रूप खड़ा नहीं कर सके। केवल उसकी कल्पना-मात्र कर सके हैं, यानी वह ऐसी भाषा हो जो उर्दू और हिन्दी दोनों ही के सगम की सूरत में हो जो सुबोध हो और आम बोलचाल की हो।"

इससे नतीजा यही निकलता था कि एक मिली जुली साहित्यिक शैली के लिए बक्त की जरूरत थी। हिन्दी को बहुत ज्यादा सस्कृतमय और उर्दू को फारसी-अरबीमय बनाने का विरोध करना सही था लेकिन हिन्दी और उर्दू की जो दो शैलियाँ चल रही थी, उन्हें एकाएक छोड़ा नहीं जा सकता था। प्रेमचन्द हिन्दी और उर्दू दोनों में लिखते थे और उनकी हिन्दी उर्दू में भेद भी रहता था। इस पर कुछ लोगों ने उन पर यह तोहमत लगाई कि वह भूँह से तो हिन्दुस्तानी की हिमायत करते हैं, असल में हिन्दी का प्रचार करते हैं।

'हस' के 'प्रेमचन्द स्मृति भक्त' में श्री अशफाक हुसैन ने एक दिलचस्प घटना का जिक्र किया है। "अलीगढ़ से 'मुहल' नाम का एक उर्दू अखबार निकलता है। उसमें छापने के लिए प्रेमचन्दजी ने अपनी दो रचनाएँ भेजी थी जिनमें एक तो हिन्दी में थी और दूसरी उर्दू में। इसके लिए एक साहब ने प्रेमचन्द के बारे में बहुत-सी उल्टी-सीधी बातें लिख डाली थी। उनकी हिन्दीवाली रचना में तो सस्कृत के कई शब्द थे और उर्दूवाली रचना में उससे भी अधिक फारसी के शब्द थे। इसकी आलोचना जिस तरह के लोगों को करनी चाहिए थी, उसी तरह के लोगों ने की थी और कहा था कि 'प्रेमचन्दजी दोरखी चालें चलते हैं, दोनों तरफ मिले रहना चाहते हैं और दोनों तरफ से अच्छे बन रहना चाहते

हैं।"

भगर प्रेमचन्द का यह दावा होता कि हिन्दी-उर्दू का बायकाट करके, तुरन्त हिन्दुस्तानी रायज की जा सकती है, तो घायद इस आलोचना में कुछ तथ्य होता। लेकिन जैसा कि हम देख चुके हैं, प्रेमचन्द हवाई सिद्धान्तकार नहीं थे; वह भ्रमन में तुरन्त एक मिली-जुली भाषा-शैली ईजाद करने की बठिनाइयो की जानते थे। इसलिए हिन्दी और उर्दू दोनों में कुछ हेर-फेर के साथ लिखने की उनकी नीति सही थी; बोलचाल की बोली जबान हिन्दुस्तानी का समर्थन करना भी ठीक था।

‘प्रेमचन्द-स्मृति अंक’ में श्री मोहम्मद आकिस ने इस तरह की दूसरी घटना का जिक्र किया है। ‘इस सिलसिले में देहली के रिसाले ‘साकी’ ने जो तनवीद की थी कि प्रेमचन्दजी उर्दू के लिए मरहूम हो चुके हैं, उसके बारे में हँसकर कहने लगे कि ‘साकी’ के एडीटर को मैंने लिखा है कि मैं उर्दू के लिए न सिर्फ जिन्दा हूँ बल्कि रयादा खोरो से जी रहा हूँ।’ प्रेमचन्द उन थोड़े से लेखकों में थे जिनमें हिन्दी-उर्दू को लेकर बड़ा-बड़ी का भाव नहीं था। यह भाव तब पैदा होता है जब लेखक के दिमाग में हिन्दी-उर्दू के पीछे हिन्दुस्तानी कीम नहीं होनी बल्कि हिन्दू धर्म और इस्लाम होता है। प्रेमचन्द ने अपने भ्रमल से दिखलाया कि साहित्य का जातीय रूप समूझ करने से, उसमें जनवादी विचारों का समावेश करने से भाषा की समस्या हल करने में मदद मिलती है। प्रेमचन्द के जल्दबाज आलोचक, जो तुरन्त हिन्दुस्तानी रायज करना चाहते थे, इस दिशा में ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर पाए।

प्रेमचन्द ने राष्ट्रभाषा और हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में जो भाषण दिए थे, उनमें एक तरफ तो साम्राज्यवादियों की गुलामी के हर रूप से बेहद नफरत जाहिर होती है दूसरी तरफ हर जगह उनका यह दृढ़ विश्वास भी जाहिर होता है कि हिन्दी और उर्दू एक ही कीम की जवान हैं और इनका एक होना लाजमी है।

प्रेमचन्द को देश के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अंग्रेजी भाषा की प्रभुता खलती थी। यह उनकी साम्राज्य-विरोधी राष्ट्रीय चेतना, उनके आत्म-सम्मान की भावना का अवर्द्धत सबूत था। किसी ने साम्राज्यवादियों की अंग्रेजी सादने की नीति के खिलाफ, बुद्धिजीवियों में इस नीति के सामने सिर झुकाने की नीति के खिलाफ इतने रोष और तर्कों के साथ बगावत न की थी जैसे प्रेमचन्द ने। सन् ‘३४ में बम्बई के राष्ट्रभाषा-सम्मेलन में उन्होंने पशुओं और मनुष्यों में यह भेद बतलाया कि मनुष्य भाषा इस्तेमाल करते हैं, पशु नहीं करते। “समाज की बुनियाद भाषा है।” इस महत्व की जगह से अंग्रेजी यहाँ की भाषाओं को हटाने की कोशिश करती रही थी। सारे देश के लोग आपस में जिस भाषा का व्यवहार करें, इस बारे में नेताओं काँटू की उदासीनता का जिक्र करत हुए उन्होंने इस सम्मेलन में कहा था—‘इस नाररवाही का खास सबब है—अंग्रेजी जवान का बढ़ता हुआ प्रचार और हमारे आत्म-सम्मान की

वह बमी, जो गुलामी की शर्म को नहीं महसूस करती ।”

किसी भी देश और जाति की उन्नति में वह आत्म सम्मान की भावना जनता में जोश भर देती है, उसे सशक्ति होकर नए-नए मोर्चे फटह करने में बेहद मदद देती है । प्रेमचन्द का स्वामिमान यह देशपर तिलमिला उठता था कि गुलाम देश के बुद्धिजीवी अपने मालिकों की भाषा पर अभिमान करते हैं । अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व को उन्होंने साम्राज्यवादी प्रभुत्व का ही घट्टट हिस्सा बतलाते हुए कहा था—“अंग्रेजी राजनीति का, व्यापार का, साम्राज्यवाद का हमारे ऊपर जैसा घातक है, उससे बही ज्यादा अंग्रेजी भाषा का है । अंग्रेजी राजनीति से, व्यापार से, साम्राज्यवाद से तो घायल बगावन करते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा को घायल गुलामी के तोंक की तरह गर्दन में डाले हुए हैं ।”

प्रेमचन्द के इन उचित कोष से भरे हुए वाक्यों के सामने कोई दलील कारगर नहीं हो सकती । सवाल है राष्ट्रीय आत्म-सम्मान का । कौन सा देश, जो स्वाधीन है या स्वाधीनता के लिए लड़ रहा है, हमारी तरह दूसरों की ज़बान को अपने राजकाज की ज़बान बनाए हुए है ? प्रेमचन्द ने उन लोगों को कड़ी फटकार बताई जो इस गुलामी पर नाज करते थे । उन्होंने तमाम अंग्रेजी-मक्कियों पर घड़ी पानी उड़ेलते हुए कहा था—‘अंग्रेजी राज्य की जगह आप स्वराज्य चाहते हैं । उनके व्यापार की जगह अपना व्यापार चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा का सिक्का हमारे दिलों पर बैठ गया है, उसके बिना हमारा पढ़ा लिखा समाज अनाथ हो जाएगा । पुराने समय में धर्म और धनार्थ का भेद था, आज अंग्रेजीदा और गैर अंग्रेजीदा का भेद है । अंग्रेजीदा धर्म है । उसके हाथ में, अपने स्वामियों की कृपा दृष्टि की बदौलत कुछ भ्रष्टियार ॥ रोव है, सम्मान है, गैर-अंग्रेजीदा धनार्थ है और उसका काम केवल धायों की सेवा टहल करना है और उनके भोग-विलास और भोजन के लिए सामग्री जुटाना है ।’ प्रेमचन्द ने भारत के अंग्रेजी प्रेमी शायों के लिए ये शब्द गूँथारह साल पहले कहे थे । उनका महत्व आज भी कम नहीं हुआ ।

प्रेमचन्द हिन्दी-उर्दू को एक ज़बान मानते थे । राष्ट्रभाषा सम्मेलन वाले भाषण में उन्होंने हिन्दी-उर्दू का भेद संस्कृत और फारसी शब्दों के प्रयोग पर निर्भर बतलाया था । इस भाषण में उन्होंने हिन्दी की बोलियों के स्वभाव की तरफ़ ध्यान दिलाया था, कि किस तरह वे संस्कृत शब्दों को ण्यो-का-र्यो नहीं लेती । उन्होंने इस कुतर्क का जोरो से खण्डन किया कि हिन्दी में संस्कृत शब्दों की भरमार करने से वह सभी प्रान्तों के लोगों के लिए आसान हो जाएगी ।

हिन्दी-उर्दू की बुनियादी एकरा के बारे में प्रेमचन्द कहते हैं—‘हमारे सूबे के देहातों में रहनेवाले मुसलमान प्रायः देहातियों की भाषा ही बोलते हैं । जो बहुत से मुसलमान देहातों से जाकर शहरों में आवाह हो गए हैं वे भी अपने घरों में देहाती ज़बान ही बोलते हैं । बोलचाल की हिन्दी समझने में न तो आधारण मुसलमानों को ही कोई कठिनाई होती है और न बोलचाल की उर्दू

समझने में साधारण हिन्दुओं को ही। जोनबान की हिन्दी और उर्दू भाषा: एक-ही है।”

यहाँ पर प्रेमचन्द ने इस ध्वनिज्ञानिक मिथ्यात्व का गन्धन किया है कि भाषा का साधारण धर्म है और इसलिए हिन्दुओं की भाषा हिन्दी है और मुसलमानों की भाषा उर्दू है। उन्होंने धर्म के नाम पर भाषा और बोध का बंटवारा करने-वाले साम्राज्यवादी और सामन्ती भाषा-वैज्ञानिकों का गन्धन किया और हिन्दुस्थानी जाति की भाषा और संस्कृति के विषय में बहुत बड़ी मदद की। इस जाति की भाषा की विधि के लिए बड़ देवनागरी लिपि के पक्षपाती थे। राष्ट्रभाषा-सम्मेलन में उन्होंने कहा था—“प्रांतीय भाषाओं को हम प्रांतीय लिपियों में लिखते जाते, कोई ऐतराज नहीं; लेकिन हिन्दुस्थानी भाषा के लिए हिन्दी लिपि रचना ही सुविधा की बात है, इसलिए नहीं कि हमें हिन्दी लिपि से लाभ मोह है; बल्कि हिन्दी लिपि का प्रचार बहुत ज्यादा है और उसके सीखने में भी किसी को दिक्कत नहीं हो सकती। और जो भाषा उर्दू लिपि के प्राचीन है, उन्हें हिन्दी लिपि का व्यवहार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर उबान एक हो जाय, तो लिपि का भेद कोई महत्व नहीं रखता।”

हिन्दी उर्दू को एक करने, बोधी भाषा और संस्कृति का नया विकास करने की जिम्मेदारी प्रेमचन्द घमसी पीढ़ी पर छोड़ गए थे। उनके बताये हुए रास्ते पर चलकर ही हम उस जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं। (१९५२)

उत्तर प्रदेश की सरकार और हिन्दी

१५ अगस्त, १९६५ की 'उत्तर प्रदेश पचायती राज्य' नामक पत्रिका में श्रीमती सुचेता कृपालानी का एक लेख छपा है 'उत्तर प्रदेश और राष्ट्रभाषा।' इसमें उन्होंने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के सिलसिले में जो बातें कही हैं, उनका सम्बन्ध राजनीतिकों से अधिक साहित्यकारों से है। भाषा है, हिन्दी लेखक उन पर उचित ध्यान देंगे।

पहले तो उन्होंने यह बताया कि हिन्दी का प्रचार गलत ढंग से किया गया और वह गलत ढंग छोड़ देना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का सही तरीका क्या है।

जिस तरीके से हिन्दी का प्रचार हुआ, उससे अहिन्दी जनता के मन में यह प्रतिक्रिया पैदा हुई—“हम क्यों हिन्दी सीखें?”

“भाषा का प्रचार तलवार से नहीं होता।”

बिल्कुल सही बात है। राज्यसत्ता कांग्रेस के हाथ में है। तलवार का किसी ने प्रयोग किया होगा तो वह कांग्रेसी नेता ही होगा। उत्तर भारत में तमिल के विरोध में या अंग्रेज़ी के विरोध में स्टेशनो, ठाकलानो बगैरह पर हमला नहीं हुआ। इस तरह की कार्रवाई तमिलनाडु में हुई। इसे तलवार का प्रयोग कहा जाय या प्रेम-प्रदर्शन, यह कांग्रेसी नेता तय करें। एक बात निश्चित है कि तलवार का प्रयोग हिन्दी जनता या हिन्दी प्रचारकों ने नहीं किया।

हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का सही तरीका उन्होंने यह बताया—

“हिन्दी भाषा को प्रगति पर लाएँ। हिन्दी को उस स्तर पर लाएँ कि हरेक हिन्दी को खुशी से सीखें।”

“अगर भाषा उन्नत हो, भाषा मधुर हो, भाषा सुन्दर हो, भाषा में इतने शब्द हो या भाषा इस स्तर में पहुँची हो कि हमारी हरेक जरूरियात को पूरी कर सके तब लोग आप-से-आप भाषा को सीख लेते हैं।”

“हिन्दी को अगर भारत की भाषा बनाना है, भारत की राष्ट्रभाषा बनाना है, तो हिन्दी-प्रेमी बैठकर खोज करें, अनुसन्धान करें, किताबें लिखें, लोगों को

बैठकर हिन्दी सिखाएँ। ऐसी सुन्दर किताबें लिखी जाएँ, ऐसी भाषा में किताबें लिखी जाएँ कि लोग उसे ग्रहण करने के लिए भाग्यवद् करें।"

'हिन्दी को लोगों द्वारा ग्राह्य बनाने के लिए तलवार से नहीं बल्कि साहित्य के महत्व से, साहित्य की उच्चता और सुन्दरता से और प्रचार और प्रसार करने के सुन्दर तरीके से यह होगा।'

जहाँ तक भाषा के सुन्दर और मधुर होने का सम्बन्ध है, हिन्दी जैसी है, वैसी है। हर व्यक्ति को अपनी भाषा सबसे ज्यादा मीठी लगती है। यदि वह कहे कि दूसरे की भाषा ज्यादा मीठी है तो समझना चाहिए कि उसके मस्तरों में वहीं कोई दोष है। मिठास के कारण कोई अपनी भाषा के मुकाबले दूसरी भाषा को महत्व नहीं देता।

जहाँ तक भाषा में 'हरेक ज़रूरियात' के शब्द होने का सवाल है, हम मानें कि कांग्रेसी सरकार का शिक्षा-मन्त्रालय और उसके विरोध यह काम करते रहे हैं। यदि हिन्दी अभी तक आवश्यक शब्द इकट्ठे न कर पाई, तो इसमें दोष सुचेताजी की पार्टी के नेताओं का है। लेकिन राजकाज के लिए उन तमाम शब्दों की ज़रूरत नहीं होती जिन्हें गढ़ने या इकट्ठा करने में दस साल में विरोध तग रहे हैं। राजकाज की ज़रूरियात-भर को तो हिन्दी में शब्द हैं, भन्ने ही हरेक ज़रूरियात के लिए न हो।

जहाँ तक साहित्य की उच्चता का सम्बन्ध है, अंग्रेजी बाज़ी उच्च भाषा है। लेकिन आगरा विश्वविद्यालय की बी० एम०-बी० परीक्षाओं में अब से अंग्रेजी ऐच्छिक विषय हो गई है, तब से अंग्रेजी लेनेवाले छात्रों की संख्या लगभग आठवीं सदी कम हो गई है। जो बी० ए० में अंग्रेजी पढ़ते हैं, उनका हाल मत पूछिये। किताबें पढ़े बिना ही बाज़ार से या ऑनलाइन के ज़िस्वाद् हुए नोट पढ़कर पास होना चाहते हैं। जो छात्र एम० ए० में अंग्रेजी पढ़ते हैं, उनमें निग्यामवे की सदी ऐसे होते हैं जो किसी तरह पास होना चाहते हैं या डिग्रीशन बनाना चाहते हैं। साहित्य प्रेम से उन्हें कोई बाला नहीं है।

अंग्रेजी के अलावा भारत की जो दूसरी मधुर भाषाएँ हैं, उन्हें साहित्य को वे फूटी धौली भी नहीं देखते। आगरा और लगनूर में ऐसी हिन्दी-भाषी छात्र कम मिलेंगे जिन्होंने रवीन्द्रनाथ की रचनाएँ बँगला में पढ़ी हों। जनकता के पढ़ते हो, ऐसा भी मेरे देखने में नहीं आया।

भारत की शिक्षा व्यवस्था नौकरियों में तृतीया और नौकरियों की भाषा है अंग्रेजी। इसने लिए सुचेताजी की पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं, हिन्दी साहित्य-कार नहीं।

मान लिया कि हिन्दी भाषा सुन्दर नहीं है और उसका साहित्य बनना किस्म का है। भारत की जिन भाषाओं का साहित्य—अनुवादित हुए हिन्दी—अन्य प्रदेशों में बहुतायत से पढ़ा जाता है? अंग्रेजी को भारतीय जीवन में जो

उन प्रदेशों की सरकार

महत्व दिया गया है, उससे समस्त भारतीय भाषाओं के पठन-पाठन में बाधा पड़ती है, हिन्दी के प्रचार-प्रसार में ही नहीं।

मान लिया, हिन्दी-प्रचारकों के अक्षत उत्साह के कारण लोग अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी से नाखुश हो गए। बंगाल में बंगला राजभाषा क्यों नहीं है? वहाँ बंगला के व्यवहार पर किन लोगों ने प्रतिबन्ध लगाया है? तमिलनाडु में तमिल के व्यवहार पर किसने रोक लगाई है?

हिन्दी प्रचारकों को दोष देना एवं बहाना है जिससे केन्द्र और प्रान्तों में अंग्रेजी का चलन बना रहे।

खुद उत्तर प्रदेश में राजभाषा हिन्दी का क्या हाल है?

'राष्ट्रभाषा सन्देश' (प्रयाग) ने २ सितम्बर, १९६५ के अंक में लिखा है, "वास्तविक स्थिति कम-से-कम उत्तर प्रदेश में यह है कि यहाँ निग्यानवे प्रतिशत से अधिक सरकारी काम अंग्रेजी में किया जाता है।"

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा हिन्दीभाषी राज्य है। सारे देश में हिन्दी की स्थिति क्या होती है, यह बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में हिन्दी की स्थिति पर निर्भर है।

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपालानी ने हिन्दी भाषा में उच्च साहित्य की आवश्यकता पर जो विचार प्रकट किये हैं, वैसे विचार सन् '३६-४० में कांग्रेसी नेता पहले भी प्रकट किया करते थे। लेकिन वे हिन्दी लिख-पढ़ लेते थे। सुचेताजी ने अपने उपर्युक्त लेख में बताया है कि उन्होंने "मर-मर-कर रोख सुबह एक घंटा लगाकर 'रामचरितमानस' पढ़ा। उसमें उन्हें कोई चीज मिली। लेकिन मालूम होता है, लिखने में उन्हें अब भी कठिनाई होती है।

'मैं हिन्दी लिख नहीं सकती'—श्रीमती सुचेता कृपालानी का यह वाक्य पढ़कर किसे दुःख न होगा? आशा है अगले चुनाव तक वह अपनी यह कठिनाई भी दूर कर लेंगी। तब शायद हिन्दी साहित्यकारों को वह जो उपदेश देंगी, वे भीर भी मधुर और लाभप्रद होंगे।

(१९६५)

भारत का भाषा-संकट

श्री मोहनकुमार मंगलम ने अंग्रेजी में एक बहुत सुन्दर पुस्तक लिखी है जिसका नाम है—'भारत का भाषा-संकट'। जो लोग चाहते हैं कि भारत में अंग्रेजी का प्रभुत्व खत्म हो, उन्हें यह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। उत्तर भारत में लाखों आदमी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हिन्दी राष्ट्रभाषा हो। वे चाहते हैं कि विभिन्न प्रदेशों में वहाँ की भाषाएँ राजभाषा के गौरवमय आसन पर प्रतिष्ठित हो। प्रश्न यह है कि वे राजभाषा क्यों नहीं बन पाती? कौन-सी शक्ति उन्हें अपने उचित आसन पर बैठने से रोकती है?

श्री मोहनकुमार मंगलम की पुस्तक के छठे अध्याय में इस विषय का विवेचन किया गया है कि तमिलनाडु में तमिल धामी तक क्यों राजभाषा नहीं बन पाई। तमिल को सरकारी तौर पर सन् '५७-५८ में राजभाषा बना दिया गया था किन्तु इसने बाद मद्रास में अंग्रेजी का रुनवा बड़ा है, कम नहीं हुआ। अधिकांश विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। कुछ साल पहले अंग्रेजी की शिक्षा छठे दर्जे में शुरू होती थी, अब वह तीसरे दर्जे से शुरू होती है। शिक्षा-केन्द्रों में अंग्रेजी का प्रभुत्व घटल है। "माता-पिता सोचते हैं कि बेटे को तरक्की करनी है तो बढ़िया अंग्रेजी सीखकर ही वह भागे बड़ सकता है। इसलिए जिन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम तमिल थी, उनमें छात्रों की सख्या लगातार कम होती गई और वे अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा पाने लगे।"

तमिलनाडु की जनता अपने मातृभाषा-प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। उसे अपनी भाषा की प्राचीनता और साहित्य की समृद्धि पर उचित गर्व है। फिर क्या कारण है कि स्कूलों और कॉलेजों में तमिल शिक्षा का माध्यम नहीं हो पाती?

इस प्रश्न का उत्तर श्री मोहनकुमार मंगलम ने बहुत स्पष्ट शब्दों में दिया है। उन्होंने लिखा है : "ऐसा इसलिए होता है कि सरकार और यूनिवर्सिटी अधिकारियों ने छात्रों के सामने सदैव यह रखा है—'अंग्रेजी खूब अच्छी तरह सीखो

जिसमें प्रखिल भारतीय स्तर पर ऊँची नौकरियों के लिए होठ कर मकी और युनियसिटी में भी कारगर दम से शिक्षा प्राप्त कर सके।”

हमारे देश में शिक्षा-मंस्थाएँ नौकरियों से जुड़ी हुई हैं। अंग्रेजों ने शासन-तन्त्र चलाने के लिए वर्कर्स से लेकर कमिशनर तक के लिए अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य कर दी थी। वही स्थिति आज भी है।

श्री मोहनकुमार मंगलम ने दो साल पहले दिया हुआ श्री भवनवरसलम का भाषण उद्धृत किया है। इसमें उन्होंने कहा था, “भाता-विता चाहते हैं कि उनके बच्चे सरकारी नौकरियाँ पाएँ। राज्य की नौकरियों के मुकाबले में केन्द्रीय नौकरियाँ ज्यादा आकर्षक होती हैं। इसलिए माता पिता और छात्रों की भी पहली तम-ना यह होती है कि वे आई० ए० एस० और आई० पी० एम० जैसी केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षा में बैठें।” यही कारण है कि तमिलनाडु में तमिल राजभाषा नहीं बन पाती। उस जागजी तौर पर राजभाषा बना दिया जाता है लेकिन वास्तविक प्रभुसत्ता रहती है अंग्रेजी के हाथ में। श्री मोहनकुमार मंगलम के शब्दों में—“अंग्रेजी की शिक्षा पाये बिना किसी भी तमिलभाषी के लिए केन्द्रीय नौकरी पान का सवाल नहीं उठता।”

कांग्रेसी नेताओं ने केन्द्र में अंग्रेजी का प्रभुत्व कायम रखकर राज्यों में वहाँ की भाषाओं को पददलित कर दिया है। तमिल जैसी प्राचीन और सम्पन्न भाषा अंग्रेजी की दासी बनी हुई है। मद्रास में तमिल राजभाषा नहीं बन पाई, इसका कारण यह नहीं है कि हिन्दी उसका दमन कर रही है, इसका कारण यह है कि कांग्रेसी नेताओं ने साम्राज्यवादियों की चलाई हुई—शासन-तन्त्र और शिक्षा के बारे में अंग्रेजी के व्यवहार की—नीति को बरकरार रखा है। इस नीति के लिए केवल हिन्दी क्षेत्र के नेता जिम्मेदार नहीं हैं—यद्यपि उन्हें ज्यादा शर्म आनी चाहिए क्योंकि वे हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का दावा भी करते हैं—अहिन्दी क्षेत्रों के नेता भी उतने ही जिम्मेदार हैं।

भारतीय भाषाओं में मुख्य अन्तर्बिरोध हिन्दी अहिन्दी का नहीं है, मुख्य अन्तर्बिरोध अंग्रेजी और समस्त भारतीय भाषाओं का है। राज्यों में अंग्रेजी के प्रभुत्व का कारण है—केन्द्रीय सेवाओं में उसका व्यवहार।

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब तक केन्द्रीय सेवाओं में अंग्रेजी न हटेगी, तब तक तमिल भी मद्रास में व्यावहारिक रूप में राजभाषा न बनेगी। इसलिए समाधान ऐसा होना चाहिए जिससे केन्द्रीय सेवाओं में अंग्रेजी का चलन खत्म हो।

श्री मोहनकुमार मंगलम ने कांग्रेस के पुराने प्रस्ताव का हवाला देते हुए सभी भारतीय भाषाओं को प्रखिल भारतीय परीक्षाओं का माध्यम बनाने की बात कही है। उनका सुझाव सही है। कमी इतनी है कि उन्होंने केन्द्रीय सेवाओं में केवल परीक्षाओं के लिए भारतीय भाषाओं के ऐच्छिक माध्यम होने का सवाल उठाया है। जब मद्रास के छात्र तमिल में परीक्षा देकर प्रफ़्तर बनेंगे,

तब वे अंग्रेजी का व्यवहार करेंगे, या भारतीय भाषाओं का—इन प्रश्न पर उन्होंने विचार नहीं किया। अतिल भारतीय सेवाओं का भाष्यम अंग्रेजी ही रखी—इसलिए सफ्ट ज्यों-वा त्यों बना रहता है। परीक्षा भाषा चाहे जिसमें दे लें, काम अंग्रेजी में ही करना पड़ेगा।

श्री मोहनकुमार मंगलम ने तीन भाषाओं वाले फार्मूले का समर्थन रिया है। इस फार्मूल में अंग्रेजी का स्थान सुरक्षित है। अंग्रेजी का स्थान सुरक्षित रखकर अंग्रेजी का प्रभुत्व नहीं खत्म किया जा सकता। फलतः तमिलनाडु में भी तमिल को राजभाषा और उच्च शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता।

अंग्रेजी की शिक्षा बिकल्पक हो—यह माँग करनी चाहिए। किसी भी स्वाधीन देश के विद्यालयों में किसी विद्यार्थी को अपनी भाषा का अध्ययन सभी छात्रों के लिए अनिवार्य नहीं होता। केन्द्र में अंग्रेजी का प्रभुत्व खत्म करना चाहिए। उसकी जगह हिन्दी चले या अनेक भारतीय भाषाओं का व्यवहार हो—श्री मोहनकुमार मंगलम जो फंसला करेंगे, मैं उसका समर्थन करूँगा। लेकिन केन्द्र में अंग्रेजी चलाते रहने से भारत का भाषा-संकट हम न होगा, उल्टे वह और गहरा होगा और इससे तमिल की उतनी ही हानि होगी जितनी हिन्दी की।

भारतीय भाषाओं को प्रदेशों में राजभाषा का पद न दिया जाय—इसके लिए अंग्रेजी प्रेमी विद्वान सफ़ देते हैं कि वे भाषाएँ पिछड़ी हुई हैं। पर्याप्त किसी ने भारतीय भाषाओं में एक भाषा लेकर वैज्ञानिक परीक्षा करके यह नहीं दिखाया कि पिछड़ापन किस बात में है—फिर भी यह सर्वमान्य सत्य बन गया है कि अंग्रेजी के मुकाबले में भारतीय भाषाएँ धाम खीर से—और हिन्दी खास खीर से—पिछड़ी हुई हैं।

तमिल विकसित भाषा है या नहीं? उसमें मद्रास राज्य का सरकारी काम हो सकता है या नहीं? उसमें उच्च शिक्षा दी जा सकती है या नहीं?

श्री मोहनकुमार मंगलम ने इन प्रश्नों के परस्पर-विरोधी उत्तर दिये हैं। उनकी समझ में भारत के भाषा संकट का मुख्य कारण यह है कि सरकारी परवरिश के कारण हिन्दी को विकसित होने का मौका मिला लेकिन अहिन्दी भाषाएँ अविकसित रह गईं। इसलिए समस्या का समाधान यह है कि पहले इन भाषाओं को राजभाषा बना दिया जाय, उन्हें विकसित होन दिया जाय, इसके बाद ही केन्द्र से अंग्रेजी हटाने का सवाल उठेगा।

उन्होंने लिखा है, 'हमें यह न भूलना चाहिए कि अपनी प्राचीनता, अपनी देन, अपने सत्कृत साहित्य आदि गुणों के बावजूद वे किसी भी समय, बहुत से बहुत, एक संकुचित गुट के विचारों का वाहन हो रही हैं।'

इसका अर्थ है कि वे वर्तमान सम्य समाज की शिक्षा-संस्कृति राजनीति का माध्यम बनने के योग्य नहीं हैं।

उनके विचार से अंग्रेजी के आने से पहले भारत की संस्कृति प्राचीन होते

हुए भी गतिरुद्ध (स्टैगनेन्ट कल्चर ऑफ इंडिया) हो चुकी थी। अंग्रेजी के प्रभुत्व से भारतीय भाषाओं की प्रगति रुक गई थी, “अर्थात् आधुनिक भाषाओं के रूप में, आधुनिक विचारों को प्रकट करनेवाले माध्यम के रूप में विकसित होने से रोका गया।”

मैं नहीं जानता कि वे आधुनिक विचार कौन से हैं जो तमिल या हिन्दी के माध्यम से प्रकट नहीं किए जा सकते। इतना जरूर कह सकता हूँ कि प्रादरणीय बन्धु मोहनकुमार मगलम ने जो विचार इस पुस्तक में प्रकट किये हैं, वे किसी भी भारतीय भाषा में बखूबी प्रकट किए जा सकते हैं।

कुमारमगलमजी ने यह मत भी बड़ी स्पष्टता से प्रकट किया है कि भारतीय भाषाएँ सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्णतः विकसित हैं। उन्होंने पुस्तक के पृष्ठ ४० पर लिखा है—

“हकीकत यह है कि (घाठवीं अनुसूची में उल्लिखित) सभी भाषाएँ विकसित भाषाएँ हैं। इन्हे करोड़ों प्रादमी बोलते हैं और मानते हैं कि उच्च शिक्षा का माध्यम बनने के लिए वे पूरी तरह विकसित हैं।”

यदि भारतीय भाषाएँ विकसित हैं तो भाषा-संकट इसलिए नहीं पैदा हो गया कि सरकार ने हिन्दी को ज्यादा विकसित कर दिया है और तमिल पीछे रह गई है। भाषाएँ अविकसित हैं—यह एक बहाना है जो हिन्दी और तमिल, सभी भारतीय भाषाओं के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। संकट का असली कारण है केन्द्र में अंग्रेजी का प्रभुत्व। इसी प्रभुत्व के कारण तमिल अपने प्रदेश में राजभाषा नहीं बनी, इसी कारण वह शिक्षा का माध्यम नहीं बनी। जो भी केन्द्र में अंग्रेजी कायम रखकर राज्यों से अंग्रेजी हटाने का सपना देखता है, वह अपने को और दूसरों को धोखा देता है। जब तक केन्द्रीय संघात्मक अंग्रेजी का चलन रहेगा, तब तक मद्रास का विद्यार्थी कभी अंग्रेजी छोड़ने को राजी न होगा।

श्री मोहन कुमारमगलम कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। श्रमिक जनता के आन्दोलन से उनका गहरा सम्बन्ध रहा है। उनसे हम आशा कर सकते हैं कि वे मजदूर वर्ग की एकता और भाषा समस्या पर भी कुछ कहेंगे। लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा।

अखिल भारतीय स्तर पर मजदूरों के संगठन की भाषा अंग्रेजी क्यों है? अखिल भारतीय किसान-सभा के केन्द्रीय दफ्तर की कार्यवाही अंग्रेजी में क्यों होती है (या होती थी)? कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सम्पर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी का व्यवहार क्यों करते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी के केन्द्रीय दफ्तर में अंग्रेजी का व्यवहार क्यों होता है? पार्टी और जन-संगठनों में अंग्रेजी के इस प्रभुत्व से हानि होती है या लाभ? श्री मोहनकुमार मगलम ने ऐसा एक भी सवाल अपनी पुस्तक में नहीं उठाया। यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है।

इस देश में जब अंग्रेज आए, तब यहाँ के राजा और नवाब, मिलकर उनसे लड़ने के बजाय, आपस में लड़ते रहे। आपस में लड़ने के लिए वे बारी-बारी

से अंग्रेजों की मदद लेते रहे और अंग्रेज बारी-बारी से उन्हें सत्प करके उनका राज्य हड़पते रहे ।

वर्तमान काल में जातीय विद्वेष और स बढ़ा है । गोधा को लेकर मंसूर के मुख्यमंत्री ने जितनी सरगर्मी महाराष्ट्र के विरुद्ध दिखाई है, उतनी सरगर्मी पुर्तगाल के खिलाफ न दिखाई थी । भाषा की समस्या जातीय समस्या का अंग है । भारतीय भाषाओं के हिमायती भाषस में लड़ते हैं और अंग्रेजी की जय बोलते हैं । जातीय विद्वेष का एक रूप भाषागत विद्वेष है । इस तरह का द्वेष पूँजीपतियों के लिए स्वाभाविक है, पूँजीवादी विचारधारा से प्रभावित मध्यवर्ग श्रेणियों के बुद्धिजीवियों के लिए यह विद्वेष बहुत कुछ मुखर और जीवन की मुख्य प्रेरणा है । केवल मजदूर वर्ग में यह क्षमता है कि वह इस विद्वेष से ऊपर उठकर अन्तर्जातीय भाईचारे के आधार पर राष्ट्रीय एकता दृढ़ करे । इसीलिए अंग्रेजी और मजदूर वर्ग की अखिल भारतीय एकता का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

भाषा सक्क क्यों पैदा हुआ, मद्रास में अंग्रेजी क्यों कायम रहती है, सविधान के निर्माताओं की किन गलतियों से प्रादेशिक भाषाभाषा का चलन न हुआ, यह समस्त सूक्ष्म विद्वेषण, कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर अंग्रेजी के व्यवहार पर नजर डालते ही, घकीलों की जिरह की तरह कानूनी तौर पर सही परन्तु न्याय के प्रतिकूल मालूम होने लगता है । भला भाषाओं के विकास में 'इम्बैलेन्स' पैदा हो जाने से कम्युनिस्ट पार्टी में अंग्रेजी का चलन क्यों हो ?

भारतीय जनतन्त्र को चलाने के लिए आसमान से फिरस्ते नहीं आते । वर्तमान युग में जनतन्त्र को चलानी हैं पार्टियाँ और पार्टियों के नेता । जब तक देश की राजनीतिक पार्टियाँ अपना अखिल भारतीय काम अंग्रेजी में करती हैं, तब तब न तो वे देश की भाषा समस्या हल कर सकती हैं, न दरअसल उन्हें इस समस्या पर बोलने का नैतिक अधिकार है ।

श्री मोहनकुमार मगलम ने लिखा है कि हर नागरिक का यह अधिकार होना चाहिए कि वह लोकसभा में अपनी मातृभाषा में बोल सके ।

मैं इस भाँग का समर्थन करता हूँ । हमारे साथी बोलें जो भारतीय भाषाभाषा में । फिर देखें, हिन्दी और अहिंदी भाषियों का कंसा ज़बरदस्त अंग्रेजी विरोधी मोर्चा बनता है । लेकिन वे खुद बोलेंगे अंग्रेजी में, दूसरा के लिए मातृभाषा में बोलने का अधिकार माँगेंगे । इस तरह सात जन्म में अंग्रेजी का प्रभुत्व दूर न होगा ।

लोकसभा में भारतीय भाषाओं का व्यवहार कीजिए । जन-संगठनों का अखिल भारतीय काम देशी भाषाओं में कीजिए । अपने केन्द्रीय दफ्तर से अंग्रेजी निकालिए । भारत का भाषा सक्क हल करने का यही नगरग तरीका है ।

